

विषय-सूची

खंड २८

विषय	पृष्ठ-संख्या
कौंसिल के पदाधिकारी	५
सरकार	७
सदस्यों की वर्णात्मक सूची तथा उनके निर्वाचन-क्षेत्र ...	३-४
उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौंसिल की कार्यवाही की अनुक्रमणिका खंड २८ ..	१-१२

सोमवार, २७ अक्तूबर, सन् १९५२ ई०

उपस्थित सदस्यों की सूची	१
प्रश्नोत्तर	२-९
सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारों के ऋण कम करने का विधेयक (सेक्रेटरी, लेजिस्लेटिव कौंसिल—मेज पर रखा) ..	
सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन) विधेयक (सेक्रेटरी, लेजिस्लेटिव कौंसिल—मेज पर रखा) ...	९
सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश फायर सर्विस (संशोधन) विधेयक (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—पुरःस्थापित किया) ...	९
सन् १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कंट्रोल) (संशोधन) विधेयक पर राष्ट्रपति की स्वीकृति की घोषणा	९
सन् १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी एकोमोडेशन) रिकवीजेशन (संशोधन) विधेयक पर राष्ट्रपति की स्वीकृति की घोषणा ..	१०
सन् १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ सप्लाईज (कन्टीन्यु—एन्स आर, पावर्स) (संशोधन) विधेयक पर राष्ट्रपति की स्वीकृति की घोषणा	१०
सन् १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश (अस्थायी) कंट्रोल आफ रेंट एण्ड इविकेशन (संशोधन) विधेयक पर राष्ट्रपति की स्वीकृति की घोषणा	१०
सदन का कार्यक्रम	१०-१२

मंगलवार, २८ अक्तूबर, सन् १९५२ ई०

उपस्थित सदस्यों की सूची	१३
प्रश्नोत्तर	१४-१९
संकल्प कि उत्तर प्रदेश में अनाथालयों तथा विधवा आश्रमों का प्रबन्ध सरकार अपने हाथ में ले ले (श्रीमती शिवराजवती नेहरू—वापस लिया गया)	१९-२४

विषय	पृष्ठ-संख्या
संकल्प कि प्रदेश में माध्यमिक कक्षाओं में सैनिक शिक्षा अनिवार्य कर दी जाय—(श्री कुंवर गुरु नारायण—अस्वीकृत हुआ) ...	२५-५३
संकल्प कि काशी के घाटों के सम्बन्ध में शीघ्र कार्य आरम्भ किया जाय—(श्री सभापति उपाध्याय—वापस लिया गया) ...	३५-६१
सदन का कार्यक्रम ...	६१

बुधवार, २९ अक्टूबर, सन् १९५२ ई०

प्रश्नोत्तर ...	६४-६६
सन् १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारों के ऋण कम करने का विधेयक (माल मंत्री—पारित हुआ) ...	६६-११२
सन् १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक (स्वशासन मंत्री—पुरःस्थापित किया) ...	११२

गुरुवार, ३० अक्टूबर, सन् १९५२ ई०

प्रश्नोत्तर ...	११४-११७
आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट को संशोधित करने के विषय में श्री कुंवर गुरु नारायण द्वारा जानकारी की प्रार्थना—(अनुमति नहीं दी गई) ...	११७
सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश विक्री-कर (संशोधन) विधेयक—(वित्त मंत्री—विचार किया गया और पारित हुआ) ...	११७-१३३
सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश फायर सर्विस (संशोधन) विधेयक—(वित्त मंत्री—विचार किया गया और पारित हुआ) ...	१३३-१३६
इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कोर्ट के लिये दो सदस्यों के चुनाव का प्रस्ताव—(वित्त मंत्री—स्वीकृत हुआ) ...	१३६-१३७
सदन का कार्यक्रम ...	१३७
नित्तियां ...	१३८-१४०

सोमवार, ३ नवम्बर, सन् १९५२ ई०

प्रश्नोत्तर ...	१४२-१४५
आगरा विश्वविद्यालय के उप-कुलपति का चुनाव आर्डिनेंस द्वारा स्थगित किये जाने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना—(श्री राजा राम शास्त्री—विचार स्थगित) ...	१४५-१४६
सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक (स्वशासन मंत्री—विचार जारी) ...	१४६-१८७

गलवार, ४ नवम्बर, सन् १९५२ ई०

प्रश्नोत्तर ...	१९०-१९५
आगरा विश्वविद्यालय के उप-कुलपति का चुनाव आर्डिनेंस द्वारा स्थगित किये जाने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव—(श्री राजा राम शास्त्री—प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गई)। ...	१९५-१९६
सन् १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक (स्वशासन मंत्री—विचार जारी) ...	१९७-१५३
सदन का कार्यक्रम ...	२५४

विषय	पृष्ठ-संख्या
इलाहाबाद यूनीवर्सिटी कोर्ट के लिये चुनाव...	२५४
आगरा यूनीवर्सिटी (पूरक) विधेयक १९५२ ई०—(शिक्षा मंत्री—पुरः स्थापित किया) ...	२५४
सदन का कार्यक्रम ..	२५४-२५५

बुधवार, ५ नवम्बर, सन् १९५२ ई०

प्रश्नोत्तर ...	२५८-२६६
उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक, १९५२—(स्वशासन मंत्री—पारित हुआ) ...	२६६-३१९

गुरुवार, ६ नवम्बर, सन् १९५२ ई०

आगरा यूनिवर्सिटी (अनुपूरक) विधेयक, १९५२ ई०—(शिक्षा मंत्री— विचार किया गया—पारित हुआ)। ...	३२२-३५८
सत्रावसान ...	३५८
नत्थी ...	३५९-३६०

उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौंसिल

के

पदाधिकारी

चेयरमैन "

श्री चन्द्र भाल ।

डिप्टी चेयरमैन

श्री निजामुद्दीन ।

सेक्रेटरी

श्री श्याम लाल गोविल, एम० ए०, एल-ए० बी० ।

सरकार

गवर्नर

श्री कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी

मंत्री परिषद्

हित गोविन्द बल्लभ पन्त, बी० ए०, एल-एल० बी०, मुख्य मंत्री, सामान्य प्रशासन तथा नियोजन मंत्री।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम, बी० ए०, एल-एल० बी०, वित्त तथा विद्युत् मंत्री।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द, बी० एस-सी०, गृह तथा श्रम मंत्री।

श्री हुकुम सिंह, बी० ए०, एल-एल० बी०, पुनर्वास तथा उद्योग मंत्री।

श्री गिरधारी लाल, एम० ए०, सार्वजनिक निर्माण मंत्री।

श्री चन्द्र भानु गुप्त, एम० ए०, एल-एल० बी०, खाद्य तथा स्वास्थ्य मंत्री।

श्री चरण सिंह, एम० ए०, बी० एस-सी०, एल-एल० बी०, माल तथा कृषि मंत्री।

श्री तैयब अली जहीर, बार-एट-ला, न्याय तथा आबकारी मंत्री।

श्री हर गोविन्द सिंह, बी० एस-सी०, एल-एल० बी०, शिक्षा तथा हरिजन सहायक मंत्री।

श्री मोहन लाल गौतम, बी० ए० (आनर्स), स्वशासन मंत्री।

श्री कमला पति त्रिपाठी, सूचना तथा सिंचाई मंत्री।

श्री विचित्र नारायण शर्मा, परिवहन तथा सहकारी मंत्री।

उप-मंत्री

श्री मंगला प्रसाद, बी० ए०, एल-एल० बी०, विधान सभा सदस्य, संसदीय प्रक्रिया तथा सहकारी उप-मंत्री।

श्री जग मोहन सिंह नेगी, बी० ए०, एल-एल० बी०, विधान सभा सदस्य, वन उप-मंत्री।

श्री फूल सिंह, बी० ए०, एल-एल० बी०, विधान सभा सदस्य, नियोजन उप-मंत्री।

श्री जगन प्रसाद रावत, बी० एस-सी०, एल-एल० बी०, विधान सभा सदस्य, कृषि उप-मंत्री।

श्री मुजफ्फर हुसन, विधान सभा सदस्य, जेल उप-मंत्री।

श्री चतुर्भुज शर्मा, बी० ए०, एल-एल० बी०, विधान सभा सदस्य, सार्वजनिक निर्माण उप-मंत्री।

श्री राम मूर्ति, एम० ए०, एल-एल० बी०, विधान सभा सदस्य, सिंचाई उप-मंत्री।

सभा सचिव

मुख्य मंत्री के सभा-सचिव

श्री कृपा शंकर, विधान सभा सदस्य।

(ज)

खाद्य तथा स्वास्थ्य मंत्री के सभा-सचिव

१--श्री बनारसी दास, विधान सभा सदस्य ।

२--श्री बलदेव सिंह आर्य, विधान सभा सदस्य ।

शिक्षा मंत्री के सभा-सचिव

डाक्टर सीताराम, एम० एस-सी० (विस०), पी० एच० डी०, विधान सभा सदस्य ।

माल तथा कृषि मंत्री के सभा-सचिव

श्रीद्वारिका प्रसाद मौर्य, विधान सभा सदस्य ।

उद्योग तथा पुनर्वासि मंत्री के सभा-सचिव

श्री रऊफ जाफरी, एम० २०, विधान सभा सदस्य ।

सदस्यों की वणत्तिक सूची तथा उनके निर्वाचन-क्षेत्र

अब्दुल शकूर नजमी, श्री	...	स्थानीय संस्थायें निर्वाचन-क्षेत्र
अम्बिका प्रसाद बाजपेयी, श्री	...	नाम निर्देशित ।
इन्द्र सिंह नयाल, श्री	...	स्थानीय संस्थायें निर्वाचन-क्षेत्र ।
ईश्वरी प्रसाद, डाक्टर	...	स्नातक निर्वाचन-क्षेत्र ।
उमानाथ बली, श्री	...	नाम निर्देशित ।
एम० जे० सुकर्जी, श्री	...	विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र ।
कन्हैया लाल गुप्त, श्री	...	अध्यापक निर्वाचन-क्षेत्र ।
कुंवर गुरु नारायण, श्री	...	विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र ।
कुंवर माहवीर सिंह, श्री	...	"
केदार नाथ खेतान, श्री	...	"
कृष्ण चन्द्र जोशी, श्री	...	"
खुशाल सिंह, श्री	...	"
गोविन्द सहाय, श्री	...	स्नातक निर्वाचन-क्षेत्र ।
चन्द्र भाल, श्री (चेयरमैन)	...	विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र ।
जगन्नाथ आचार्य, श्री	...	स्थानीय संस्थायें निर्वाचन-क्षेत्र ।
जमीलुर्रहमान क़िदवाई, श्री	...	"
ज्योति प्रसाद गुप्त, श्री	...	"
तारा अग्रवाल, श्रीमती	...	नाम निर्देशित ।
तेलू राम, श्री	...	स्थानीय संस्थायें निर्वाचन-क्षेत्र ।
दीप चन्द्र, श्री	...	"
नरोत्तम दास टन्डन, श्री	...	"
निजामुद्दीन, श्री (डिप्टी चेयरमैन)	...	"
निर्मल चन्द्र चतुर्वेदी, श्री	...	स्नातक निर्वाचन-क्षेत्र ।
प्रताप चन्द्र आजाद, श्री	...	विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र ।
प्रभु नारायण सिंह, श्री	...	स्थानीय संस्थायें निर्वाचन-क्षेत्र ।
प्रसिद्ध नारायण अनंद, श्री	...	"
प्रेम चन्द्र शर्मा, श्री	...	"
पन्ना लाल गुप्त, श्री	...	"
परमात्मानन्द सिंह, श्री	...	"
पूर्ण चन्द्र विद्यालंकार, श्री	...	विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र ।
प्यारेलाल श्रीवास्तव, डाक्टर	...	अध्यापक निर्वाचन-क्षेत्र ।
बद्री प्रसाद कक्कड़, श्री	...	विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र ।
बशीर अहमद, श्री	...	"
बालक राम वैश्य, श्री	...	"
बाबू अब्दुल मजीद, श्री	...	स्थानीय संस्थायें निर्वाचन-क्षेत्र ।
बलभद्र प्रसाद बाजपेयी, श्री	...	अध्यापक निर्वाचन-क्षेत्र ।
बीर भान भाटिया, डाक्टर	...	नाम निर्देशित ।
वेणी प्रसाद टंडन, श्री	...	स्नातक निर्वाचन-क्षेत्र ।
वंशीधर शुक्ल, श्री	...	स्थानीय संस्थायें निर्वाचन-क्षेत्र ।
झज लाल वर्मान (हकीम), श्री	...	"
ब्रजेंद्र स्वरूप, डाक्टर	...	स्नातक निर्वाचन-क्षेत्र ।
महमूद अस्लम खां, श्री	...	स्थानीय संस्थायें निर्वाचन-क्षेत्र ।
महादेवी वर्मा, श्रीमती	...	नाम निर्देशित ।

मानपाल गुप्त, श्री
 मुकुट बिहारी लाल, प्रोफेसर
 राजाराम शास्त्री, श्री
 राना शिव अम्बर सिंह, श्री
 राम किशोर रस्तोगी, श्री
 राम किशोर शर्मा, श्री
 राम नन्दन सिंह, श्री
 राम लखन, श्री
 राम लगन सिंह, श्री
 राय बजरंग बहादुर सिंह, श्री
 रक्तुद्दीन खां, श्री
 लल्लू राम द्विवेदी, श्री
 लालता प्रसाद सोनकर, श्री
 लाल सुरेश सिंह, श्री
 विजय आफ विज्ञाननगरम्, डाक्टर,
 महाराज कुमार
 विद्वनाथ, श्री
 शान्ति स्वरूप अग्रवाल, श्री
 शान्ति देवी अग्रवाल, श्रीमती
 शान्ति देवी, श्रीमती
 शिवराजवती नेहरू, श्रीमती
 शिव सुमिरन लाल जौहरी, श्री
 श्याम सुन्दर लाल, श्री
 सत्य प्रेमी उपनाम हरि प्रसाद, श्री
 सभापति उपाध्याय, श्री
 सरदार सन्तोष सिंह, श्री
 सैयद मुहम्मद नसोर, श्री
 हृदय नारायण सिंह, श्री
 हयातुल्ला अन्सारी, श्री
 हर गोविन्द मिश्र, श्री

... स्थानीय संस्थायें निर्वाचन-क्षेत्र ।
 .. स्नातक निर्वाचन-क्षेत्र ।
 ... विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र ।
 ... ”
 .. स्थानीय संस्थायें निर्वाचन-क्षेत्र ।
 ... अध्यापक निर्वाचन-क्षेत्र ।
 ... विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र ।
 ... स्थानीय संस्थायें निर्वाचन-क्षेत्र ।
 ... विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र ।
 ... नाम निर्देशित ।
 ... विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र ।
 .. स्थानीय संस्थायें निर्वाचन-क्षेत्र ।
 ... विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र ।
 ... स्थानीय संस्थायें निर्वाचन-क्षेत्र ।
 ... नाम निर्देशित ।
 ... विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र ।
 ... अध्यापक निर्वाचन-क्षेत्र ।
 ... विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र ।
 ... ”
 ... ”
 ... स्थानीय संस्थायें निर्वाचन-क्षेत्र ।
 .. विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र ।
 ... नाम निर्देशित ।
 ... ”
 ... ”
 ... अध्यापक निर्वाचन-क्षेत्र ।
 ... नाम निर्देशित ।
 ...

उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौंसिल

—o—

उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौंसिल की बैठक, विधान भवन, लखनऊ में ११ बजे दिन के चेयरमैन (श्री चन्द्रभाल) के सभापतित्व में हुई।

—o—

उपस्थित सदस्य (५०)

अब्दुल शकूर नजमी, श्री
ईश्वरी प्रसाद, डाक्टर
उमानाथ बली, श्री
एम० जे० मुकर्जी, श्री
कुंवर गुरु नारायण, श्री
कुंवर महावीर सिंह, श्री
जगन्नाथ आचार्य, श्री
जमीलुर्रहमान क़िदवई, श्री
ज्योति प्रसाद गुप्त, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेल राम, श्री
नरोत्तम दास टण्डन, श्री
निजामुद्दीन, श्री
निर्मल चन्द्र चतुर्वेदी, श्री
प्रताप चन्द्र आज़ाद, श्री
प्रभू नारायण सिंह, श्री
प्रसिद्ध नारायण अनन्द, श्री
प्रेम चन्द्र शर्मा, श्री
पन्ना लाल गुप्त, श्री
परमात्मा नन्द सिंह, श्री
पूर्ण चन्द्र विद्यालंकार, श्री
प्यारेलाल श्रीवास्तव, डाक्टर
बशीर अहमद, श्री
बलभद्र प्रसाद वाजपेयी, श्री
बालक राम वैश्य, श्री
बाबू अब्दुल मजीद, श्री

बंशीधर शुक्ल, श्री
ब्रजलाल वर्मन, श्री (हकीम)
ब्रजेन्द्र स्वरूप, डाक्टर
महमूद अस्लम खां, श्री
मान पाल गुप्त, श्री
मुकुट बिहारी लाल, प्रोफ़ेसर
राजा राम शास्त्री, श्री
राना शिवशम्बर सिंह, श्री
राम किशोर शर्मा, श्री
राम नन्दन सिंह, श्री
राम लगन सिंह, श्री
राय बजरंग बहादुर सिंह, श्री
लालता प्रसाद सोनकर, श्री
लाल मुरेश सिंह, श्री
विजय आनन्द आफ़ विज्ञाननगरम,
डाक्टर, महाराजकुमार
विश्वनाथ, श्री
शान्ति देवी अग्रवाल, श्रीमती
शान्ति देवी, श्रीमती
शिवराजवती नेहरू, श्रीमती
शिव सुमरन लाल जौहरी, श्री
श्याम सुन्दर लाल, श्री
सत्य-प्रेमी उपनाम हरिप्रसाद, श्री
सरदार सन्तोष सिंह, श्री
सैयद मोहम्मद नसीर, श्री

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम (वित्त मंत्री) भी उपस्थित थे।

—o—

प्रश्नोत्तर

सन् १९४९ से बिना पब्लिक सर्विस कमीशन को सूचित किये हुये की गई नियुक्तिया

१—श्री कुंवर गुरु नारायण (विधान-सभा निर्वाचन क्षेत्र)—क्या सरकार १९४९ ई० से की गई उन नियुक्तियों की एक सूची मेज पर रखने की कृपा करेगी जो बिना पब्लिक सर्विस कमीशन को सूचित किये हुये की गई ?

1. Sri Kunwar Guru Narain—(*Lagislative Assembly Constituency*)—Will the Government place on the table of the House a list of appointments made by them since 1949 without referring to the Public Service Commission ?

श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम (वित्त मंत्री)—नियुक्तियों के विषय में कमीशन के साथ परामर्श यू० पी० पब्लिक सर्विस कमीशन (लिमिटेशन ऑफ फंक्शन्स) रेगुलेशन्स के अधीन किया जाता है, जिसकी एक प्रति मेज पर रख दी गई है। इन रेगुलेशनों (विनियमों) के अनुसार कुछ प्रकार की नियुक्तियां कमीशन से कोई संबंध नहीं रखती और इसलिये इन नियुक्तियों के बारे में कमीशन से परामर्श करना आवश्यक नहीं है। माननीय सदस्य का ध्यान कमीशन के वार्षिक रिपोर्ट की ओर आकर्षित किया जाता है जिससे ऐसे विषयों पर हर साल विचार किया गया है।

Sri Hafiz Mohammad Ibrahim—(*Minister for Finance*)—Consultation with the Commission in the matter of appointments is governed by the U. P. Public Service Commission (Limitation of Functions) Regulations, a copy of which is placed on the table. According to these Regulations, certain types of appointments fall outside the purview of the Commission, and consultation with the latter about these appointments is not, therefore, necessary. The Hon'ble Member is referred to the annual reports of the Commission in which such matters have been dealt with every year.

Sri Kunwar Guru Narain—The reply given is not clear to me. I want to ask the Minister what are the appointments in which the Public Service Commission should have been necessarily consulted, but it was not consulted ?

Sri Hafiz Mohammad Ibrahim—Does the Hon'ble Member ask for the law or any case ?

Sri Kunwar Guru Narain—Sir, my question is this. Will the Govt. place on the table of the House a list of appointments made by them since 1949 without referring to the Public Service Commission ? I want the list of such appointments. Ordinarily, appointments made by the Government should have been made after referring to the Commission, but some appointments were made without reference to the Commission. I want to know what are those appointments ?

Sri Hafiz Mohammad Ibrahim—The answer is already there in the reply given by me. Certain types of appointments are outside the purview of the Commission and appointments are made without reference to the Public Service Commission. The question is not this that those cases in which a reference was necessary to the Public Service Commission, but were not referred to the Commission.

Sri Kumar Guru Narain—My question was quite clear and it was this, will the Government please lay on the table a list of appointments made by them since 1949 without referring to the Public Service Commission ? There is nothing in the question which asks the appointments which are outside the purview of the Commission. The question does not ask such cases which should or should not have been referred to the Public Service Commission. It asks the list of appointments which should have been referred to the Commission but was not referred.

Chairman—We cannot discuss the reply. We must take the reply as it is given.

२—श्री कुंवर गुरु नारायण—क्या सरकार ने कोई ऐसा समय निश्चित किया है जिससे पहले कर्मचारी को, जिसको सरकार ने अपनी तुरन्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये रखती है मुस्तकिल होने के लिये पब्लिक सर्विस कमिशन के सामने जाना पड़े ?

३—यदि नहीं, तो क्यों ?

2. Sri Kunwar Guru Narain—Have the Government fixed any period before which the incumbent employed by them to meet their immediate needs has to appear before the Public Service Commission for confirmation?

3—If not, why not ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम (२-३)—सदस्य का ध्यान पब्लिक सर्विस कमिशन (लिमिटेशन ऑफ फंक्शन्स) रेगुलेशन्स के रेगुलेशन ३ के वाक्यखंड (१) की मद (जी) और (एच) की ओर आकर्षित किया जाता है।

3. Sri Hafiz Mohammad Ibrahim (2-3)—The attention of the Member is invited to items (g) and (h) of clause (1) of Regulation 3 of the Public Service Commission (Limitation of Functions) Regulations.

४—श्री कुंवर गुरु नारायण—क्या पब्लिक सर्विस कमिशन ने हाल ही में सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है कि एक विशेष मामले में सरकार द्वारा की गई नियुक्ति को ४ वर्ष के बाद भी कमिशन को सूचित नहीं किया गया ?

4. Sri Kunwar Guru Narain—Has the Public Service Commission recently brought to the notice of the Government that in one particular case an appointment made by the Government was not referred to the Commission even after four years?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—सदस्य के ध्यान में जो विशेष मामला है उसके बारे में स्पष्ट विवरण न होने के कारण किसी ऐसे मामले का पता लगाना संभव नहीं हुआ।

Sri Hafiz Mohammad Ibrahim—It has not been possible to locate any such case in the absence of specific details about the particular case which the Member has in view.

Sri Kunwar Guru Narain—In the answer it has been suggested that it has not been possible to locate any such case in the absence of any specific details but in the annual report of the Public Service Commission it has been mentioned that the case has been there and the appointment was made by the Government and it was referred to the Public Service Commission afterwards. I want to know what is that particular case which has been mentioned in the annual report of the Public Service Commission.

Sri Hafiz Mohammad Ibrahim—Probably to answer this question the report of the Commission was not seen by those who had to answer the question. They may not be knowing what particular question is referred to in the report. They have not followed it. It has not been possible to locate the particular case which the member wants to know.

Sri Kunwar Guru Narain—Sir, in the report the case has not been mentioned. I want to enquire from Government what is that case which is mentioned in the annual report.

Sri Hafiz Mohammad Ibrahim—I do not know myself what is there without referring to the Report itself.

५—श्री कुंवर गुरु नारायण—स्थगित ।

मिनिस्ट्रीयल जगहों पर भर्ती के लिये परीक्षा

६—श्री कुंवर गुरु नारायण—क्या सरकार मिनिस्ट्रीयल जगहों की भर्ती के लिये एक मुकाबले का इम्तहान लेने के औचित्य पर विचार करना चाहती है जैसा कि कुछ दूसरे राज्यों में होता है ?

6. **Sri Kunwar Guru Narain**—Do the Government propose to consider the advisability of holding a competitive examination annually for recruitment to the ministerial posts as is done in some other States ?

श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम—सेक्रेटरीयट और सबऑर्डिनेट आफिसों दोनों ही में, मिनिस्ट्रीयल जगहों पर भर्ती के लिये प्रतियोगिता परीक्षाएँ लेने की प्रथा पहले ही से जारी है ।

Sri Hafiz Mohammad Ibrahim—The system of holding competitive examinations for recruitment to ministerial posts, both in the Secretariat and in the subordinate offices, is already in force.

Sri Kunwar Guru Narain—Does the Government propose to ask the Public Service Commission to hold a competitive examination among the legislators for the purpose of recruiting candidates for the Cabinet posts ?

Chairman—I cannot allow this question. Only questions seeking information can be asked. There should be no insinuation on the Government.

७—८—श्री कुंवर गुरु नारायण—स्थगित ।

९-२२—श्री इन्द्र सिंह नयाल (स्थानीय संस्थाएँ निर्वाचन क्षेत्र)—स्थगित ।

पन्चकियों की नालियों से बिजली पैदा होना

२३—श्री इन्द्र सिंह नयाल—क्या सरकार ने इस बात को निश्चित रूप से मालूम कर लिया है कि पहाड़ियों में पन्चकियों की नालियों से पानी के बहाव से उत्पन्न होने वाली शक्ति या उसमें और किसी प्रकार की रद्दीकरण करने से बिजली पैदा हो सकती है ?

23. Sri Indra Singh Nayal—Has the Government ascertained whether electricity can be generated by the water-power afforded by the channels of the water-mills in the hills or by a modification of the same ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—पन्चकियों की नालियों से काफी बिजली उत्पन्न नहीं की जा सकती क्योंकि नाली के सिर (head) में पानी बहुत कम होता है।

Sri Hafiz Mohammad Ibrahim—It is not possible to generate sufficient electricity from the channels of the water mills as the amount of the water in the head is far too low.

२४—श्री इन्द्र सिंह नयाल—यदि हां, तो क्या सरकार ने या उसके किसी अधिकारी ने इस प्रश्न को अच्छी तरह अध्ययन किया है और इस बात का भी शुमार लगाया कि इस प्रकार कितनी बिजली की शक्ति पैदा हो सकती है ?

24. Sri Indra Singh Nayal—If so, has the Government or any of its officials studied the question and calculated the amount of electric energy that can thus be generated ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—पन्चकियों की नालियों से सिर्फ एक एच० पी० बिजली पैदा की जा सकती है ?

Sri Hafiz Mohammad Ibrahim—The amount of electric energy which can be generated from these water mills is about 1 H. P.

२५—श्री इन्द्र सिंह नयाल—यदि हां, तो क्या सरकार कृपा करके इसके संबंध में की गई छान-बीन का परिणाम बताने की कृपा करेगी।

25. Sri Indra Singh Nayal.—If so, will the Government please state the result of the investigation ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—यह सवाल पैदा नहीं होता।

Sri Hafiz Mohammad Ibrahim—The question does not arise.

२६—श्री इन्द्र सिंह नयाल—यदि नहीं, तो क्या सरकार इस प्रश्न की छान-बीन करने के लिये कार्यवाही करने का इरादा रखती है ?

26. Sri Indra Singh Nayal—If not, do the Government intend to take steps to investigate the question ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—यह सवाल पैदा नहीं होता।

Sri Hafiz Mohammad Ibrahim—The question does not arise.

२७—श्री इन्द्र सिंह नयाल—क्या सरकार ने यह भी निश्चित रूप से मालूम कर लिया है कि इस प्रकार जो बिजली की शक्ति पैदा होगी वह कुटीर उद्योगों में तैयार और चरखों के चलाने और अन्य प्रकार से इस्तेमाल की जा सकती है ?

Sri Indra Singh Nayal—Has the Government also ascertained whether the electric energy thus generated can be utilised cottage industries for operating handlooms, *Charkhas* and also in various other ways ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—बिजली की मात्रा बहुत कम होने की वजह से वह हैंडलूम चरखा वगैरह चलाने के लिये काफी नहीं है।

Sri Hafiz Mohammad Ibrahim—The amount of energy is too small and not sufficient for operating handlooms, *charkhas* etc.

२८—श्री इन्द्र सिंह नयाल—यदि नहीं, तो क्यों ?

28. Sri Indra Singh Nayal—If not, why ?

हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—यह सवाल पैदा नहीं होता।

Sri Hafiz Mohammad Ibrahim—The question does not arise.

२९—श्री इन्द्र सिंह नयाल—यदि प्रश्न संख्या २७ का उत्तर हां में है, तो क्या सरकार पहाड़ियों पर इस प्रकार के कुटीर उद्योगों के तरीके को रायज करने के लिये कार्यवाही करने का इरादा रखती है ?

29. Sir Indra Singh—If the answer to question no. 27 be in the affirmative, do the Government intend to take steps to introduce this system of cottage industries in the hills ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—यह सवाल पैदा नहीं होता।

Sri Hafiz Mohammad Ibrahim—The question does not arise.

३०—३४—श्री राम नन्दन सिंह (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—स्थगित।

नये मकान बनाने वालों को बिजली का कनेक्शन

प्रा० सं० ता० ३५—श्री हकीम बजलाल वर्मन—(क) क्या सरकार ने नये मकान की नीति को ४-६-१०-५२ प्रोत्साहन देने के लिये कभी कोई ऐसी आज्ञा निकाली थी कि नये मकान बनाने वालों को बिजली का कनेक्शन (Connection) दिया जावेगा ?

(ख) यदि निकाली थी, तो कब ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—(क) जी हां। एक आजा निकाली गई थी लेकिन यह आजा सिर्फ हाइडल एरिया के बाहर वाले क्षेत्रों के वास्ते थी।

(ख) १८ जून, १९४८।

३६—श्री हकीम ब्रजलाल वर्मन—(क) क्या सरकार ने बिजली के कनेक्शन्स (Connections) के कुछ तबादले (shiftings) एक मकान से दूसरे मकान में मथुरा शहर में मंजूर और कुछ नामंजूर किये हैं?

(ख) किन-किन लोगों के तबादले नामंजूर किये हैं और किन आधार पर?

(ग) किन-किन लोगों के मंजूर किये हैं और किन आधार पर?

(घ) क्या श्री रामनाथ मुख्तार, मेम्बर, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को ऐसा तबादला दो बार जनवरी सन् १९५१ और ५-५-५१ को अस्वीकार किया गया है? यदि किया गया है, तो किस आधार पर?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—(क) बिजली के कनेक्शनों के तबादले की सब अर्जियां इधर हाल के सालों में मंजूर कर दी गयी थीं।

(ख) कनेक्शनों के तबादले की सभी दरखास्तें इधर हाल के सालों में नामंजूर कर दी गई हैं, चूंकि यह तबादले कानूनी पेचीदगियां पैदा करते हैं।

(ग) इधर हाल के सालों में कोई भी दरखास्त मंजूर नहीं हुई। चूंकि यह तबादले कानूनी पेचीदगियां पैदा करते हैं।

(घ) जी हां, नामंजूरी की वजह यह थी कि बिजली के कनेक्शनों के तबादले के वास्ते कानूनन इजाजत नहीं दी जा सकती थी।

श्री हकीम ब्रजलाल वर्मन—यह जो कानूनी पेचीदगियां इसमें पैदा हो गई हैं कि जिन लोगों ने टेम्पोरेरी कनेक्शन्स की दरखास्तें दी हैं उनके लिये ही कानूनी पेचीदगियां आईं, मगर जिन्होंने परमानेंट कनेक्शन्स के लिये दरखास्तें दी थीं, उनके लिये कानूनी पेचीदगियां क्यों आईं?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जो टेम्पोरेरी कनेक्शन्स हैं उनको मुस्तकिल करना या न करना गवर्नमेंट के अख्तियार में है मगर एक जगह से दूसरे जगह कनेक्शन हटाने में ये पेचीदगियां पैदा हो गई हैं। गवर्नमेंट ने आर्डर दिये हैं। एक दफ्ता एक साहब ने उस पर मुकदमा दायर किया, अदालत ने तय किया है कि जितने कनेक्शन्स इस तरह के हों, उनको हटा कर के दूसरी जगह के लिये इजाजत दे दे। इसीलिये ये कानूनी पेचीदगियां आ गई हैं।

३७—श्री हकीम ब्रजलाल वर्मन—(क) क्या सरकार कृपा कर बतलायेगी कि मथुरा से एक साल के अन्दर १९५१ में बिजली के नये कनेक्शन्स (Connections) की कितनी दरखास्तें सरकार के पास आईं।

(ख) उनमें से कितनी स्वीकार हुई और कितनी अस्वीकार हुई और किस नीति से यह स्वीकार और अस्वीकार हुई?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—(क) लगभग २८०।

(ख) १२१ आर्जी (Temporary) कनेक्शन्स मंजूर किये गये थे चूँकि इनकी दरखास्तों के साथ माकूल डाक्टरी सर्टिफिकेट मौजूद थे। इस क्रिस्म की ३७ दरखास्तें नामंजूर कर दी गईं चूँकि इनके साथ माकूल सर्टिफिकेट नहीं थे। बिजली की कमी की वजह से मुस्तक़िल (Permanent) कनेक्शनों की १२२ दरखास्तें मंजूर नहीं की जा सकीं।

श्री हकीम ब्रजलाल वर्मन—क्या सरकार की कोई ऐसी नीति है कि पहले अस्थायी कनेक्शन (Connection) दिया जावे और फिर स्थायी दिया जावे ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जी नहीं।

३६—श्री हकीम ब्रजलाल वर्मन—यदि नहीं, तो मथुरा में लगभग ६० कनेक्शन्स (Connections) एक दम किस आधार पर स्थायी कर दिये गये ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—मोहम्मद पुर पावर हाउस से बिजली मिलने के सबब से हाइड्रिल ग्रिड एरिया में सब आर्जी कनेक्शन जिनमें मथुरा के भी आर्जी कनेक्शन शामिल हैं मुस्तक़िल कर दिये गये हैं।

४०—श्री हकीम ब्रजलाल वर्मन—किस आधार पर सरकार वेट्स (Watts) नियत करती है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—वाट्स (Watts) नियत करने के लिये कोई खास क़ायदे नहीं हैं। इनका निश्चय कनेक्शन मंजूर करने वाले अधिकारी, दरखास्तों में दी गयी सूचना पर अपने फ़ैसले के मुताबिक़ करते हैं।

श्री हकीम ब्रजलाल वर्मन—इस प्रश्न के संबंध में यह फरमाया गया कि उसके लिये कोई क़ायदा नहीं है। तो क्या गवर्नमेंट मुनासिब समझती है कि उनके लिये कोई खास क़ायदे बना लिये जायें और उसमें यह मुनासिब समझा जाय कि जो आफीसर कन्सर्न हैं, उनके डिसक्रिप्शन पर यह छोड़ दिया जाय।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—यह चीज़ ऐसी है कि क़ायदों से गवर्न नहीं हो सकती है, मौके पर लोगों को इस पर अपना डिसक्रिप्शन इस्तेमाल करना पड़ता है।

४१—श्री हकीम ब्रजलाल वर्मन—(क) क्या यह ठीक है कि बुन्दावन में केवल ५८ K. W. A. की बिजली स्वीकृत है किन्तु कार्यरूप में १२५ K. W. A. तक बिजली का प्रयोग होता है ?

(ख) क्या यह ठीक है कि मथुरा में ५०० K. W. A. स्वीकृत है और ६०० K. W. A. तक का प्रयोग होता है।

(ग) यदि भाग (क) और (ख) का उत्तर हाँ में है, तो मथुरा को बुन्दावन की अपेक्षा अधिक बिजली क्यों नहीं दी जाती है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—(क) बुन्दावन के वास्ते मंजूरशुदा मांग ५८ किलोवाट है लेकिन कभी-कभी यह ११० किलोवाट तक पहुँच गई है।

(ख) मथुरा के वास्ते मंजूरशुदा मांग ५०० के० डब्ल्यू० ए० है, लेकिन कभी-कभी यह ५७५ के० डब्ल्यू० ए० तक पहुँच गई है।

(ग) वृन्दावन या मथुरा में संजूरशुदा बिजली की मांग से ज्यादा बिजली इस्तेमाल होने के यह माने नहीं हैं कि इन जगहों की और ज्यादा बिजली दी गई है। सब शहरों की मांगों का फ़ैसला उन शहरों को अपनी अलग-अलग आवश्यकताओं पर ही किया जाता है न कि किसी एक निस्वत पर।

श्री हकीम ब्रजलाल वर्मन—वृन्दावन और मथुरा के किलोवाट की संख्या जो दी गई है और जैसा कि जवाब से जाहिर है कि वृन्दावन बहुत छोटा कस्बा है, उसमें तो जितनी किलोवाट मुक़रर है, उससे दुगुनी खर्च हुई, लेकिन मथुरा में जहाँ कि अधिक खर्च होना चाहिये, उसकी सवाई बिजली भी खर्च नहीं हुई। तो क्या गवर्नमेंट इस तरफ तवज्जह देगी ?

श्री हाकिम मुहम्मद इब्राहीम—यह बात नहीं है कि वृन्दावन में ज्यादा बिजली दी जा रही हो। मथुरा के मुताल्लिक जो आप ने अर्ज किया, तो मथुरा से वृन्दावन जो तार गया है, उसमें खराबी हो गई है और इस साल के बजट में इसके लिये रुपया रखा गया था ताकि उस को तब्दील करा सकें। तो लाइन की खराबी की वजह से वहाँ के बिजली का वाल्टेज ज्यादा गिर जाता है और वहाँ के वाल्टेज भी बचाय ५८ के ११० तक पड़च गया। वह वाल्टेज अगर ठीक हो जायेगा तो यह किस्सा जाता रहेगा।

— सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारों के ऋण कम करने का विधेयक

सेक्रेटरी, लेजिस्लेटिव कौंसिल—श्रीमान् जी की आज्ञा से मैं सन् १९५२ का उत्तर प्रदेश जमींदारों के ऋण कम करने को विधेयक को मेज पर रखता हूँ। यह विधेयक उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा १६ अक्टूबर, सन् १९५२ को पारित हुआ और यहाँ २५ अक्टूबर सन् १९५२ ई० को आया।

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश विक्री कर (संशोधन) विधेयक

सेक्रेटरी, लेजिस्लेटिव कौंसिल—श्रीमान् जी की आज्ञा से मैं सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश विक्री कर (संशोधन) विधेयक को मेज पर रखता हूँ। यह विधेयक उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा १६ अक्टूबर सन् १९५२ ई० को पारित हुआ और यहाँ २५ अक्टूबर, सन् १९५२ ई० को आया। माननीय स्पीकर ने यह प्रमाणित किया है कि यह एक धन विधेयक है।

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश फायर सर्विस (संशोधन) विधेयक

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—

Sir, I beg to introduce the Uttar Pradesh Fire services (Amendment) Bill, 1952.

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कण्ट्रोल) (संशोधन) विधेयक

सेक्रेटरी, लेजिस्लेटिव कौंसिल—श्रीमान् जी की आज्ञा से मुझे यह घोषणा करनी है कि सन् १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कण्ट्रोल) (संशोधन) विधेयक पर राष्ट्रपति महोदय की स्वीकृति २६ सितम्बर, १९५२ ई० को प्राप्त हो गई और वह उत्तर प्रदेश का सन् १९५२ ई० का २१वाँ ऐक्ट बना।

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी ऐकोमोडेशन) रिक्वीजीशन (संशोधन) विधेयक

सेक्रेटरी लेजिस्लेटिव कौंसिल—श्रीमान् जी की आज्ञा से मुझे यह घोषणा करनी है कि सन् १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी ऐकोमोडेशन) रिक्वीजीशन (संशोधन) विधेयक पर राष्ट्रपति महोदय की स्वीकृति ३० सितम्बर, १९५२ ई० को प्राप्त हो गई और वह उत्तर प्रदेश का सन् १९५२ ई० का २२वां ऐक्ट बना।

सन् १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ सप्लाय्ज (कण्टीन्यूएस आफ़ पावर्स) (संशोधन) विधेयक

सेक्रेटरी लेजिस्लेटिव कौंसिल—श्रीमान् जी की आज्ञा से मुझे यह घोषणा करनी है कि सन् १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ़ सप्लाय्ज (कण्टीन्यूएस आफ़ पावर्स) (संशोधन) विधेयक पर राष्ट्रपति महोदय की स्वीकृति ३० सितम्बर, १९५२ ई० को प्राप्त हो गई और वह उत्तर प्रदेश का सन् १९५२ ई० का २३वां ऐक्ट बना।

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश (अस्थायी) कंट्रोल आफ़ रेंट ऐण्ड एविकेशन (संशोधन) विधेयक

सेक्रेटरी लेजिस्लेटिव कौंसिल—श्रीमान् जी की आज्ञा से मुझे यह घोषणा करनी है कि सन् १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश (अस्थायी) कंट्रोल आफ़ रेंट ऐण्ड एविकेशन (संशोधन) विधेयक पर राष्ट्रपति महोदय की स्वीकृति ३० सितम्बर, १९५२ ई० को प्राप्त हो गई और वह उत्तर प्रदेश का सन् १९५२ ई० का २४वां ऐक्ट बना।

सदन का कार्यक्रम

चेयरमैन—तीन विधेयकों पर इस सेशन में हम लोगों को विचार करना है। उसके संबंध में चेयरमैन की यही नीति रही है कि यदि सदन की स्वीकृति हो, तब सूचना संबंधी नियम स्थगित कर दिया जाता है। नहीं तो नियमानुसार दो दिन का समय चाहिये। पहले मिनिस्टर साहब इसके बारे में अपने विचार बतायें और फिर सदस्यों से मैं उनकी राय पूछूंगा।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—मेरी गुजारिश यह है कि इसमें यू० पी० जमींदारों के ऋण कम करने का जो बिल है उसमें कुछ ज्यादा तक्रारें हो सकती हैं, लेकिन यू० पी० सेल्स टैक्स अमेंडमेंट जो बिल है, उसको मेरे ख्याल से कल ही से लिया जा सकता है। या यू० पी० फायर सर्विस बिल को कल से लिया जा सकता है उसके लिये वक्त भी पूरा हो सकता है तो इन दोनों बिलों में से जो आप ठीक समझें, वह कल ले लिये जायें।

श्री कुंवर गुरु नारायण—माननीय अध्यक्ष जी, यह जो सेल्स टैक्स का बिल है, वह ऐसा है जिसमें हम चाहते हैं कि मौका दिया जाय और मेरी राय यह है कि २ दिन के बाद बहस शुरू की जाय। On a point of information मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ और मैंने एक लेटर भी लिखा था और रिक्वेस्ट की थी कि फाईव इयर प्लान..

चेयरमैन—यह दूसरी चीज है।

एक सुझाव यह है नियमानुसार संकल्पों (resolutions) के लिये नान आफिशियल डे (non. official day) हम लोग बृहस्पतिवार को रखते हैं । अगर सदन इनको कल ले ले यानी मंगल को अगर ले ले, तो बृहस्पतिवार का दिन हमको विधेयक के लिये मिल जायेगा । कल एक कुंवर साहब का रिजोलूशन है, और एक श्री सभापति उपाध्याय जी का भी है । अगर इनको कल ले लिया जाय तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को भी कोई दिक्कत न होगी और किसी और सदस्य को भी कोई दिक्कत न होगी ।

श्री प्रभू नारायण सिंह (स्थानीय संस्थाओं निर्वाचन क्षेत्र) —कल के बाद अगर नान आफिशियल डे (non official day) रख दिया जाय और उसके बाद सेशन का काम किया जाय तो हमको भी मौका मिल जायेगा । नान आफिशियल डे बुधवार को रख दिया जाय ।

चेयरमैन—जैसे बुधवार को लिया जा सकता है वैसे ही मंगलवार को लिया जा सकता है और मंगलवार को लेने से एक दिन की बचत हो सकती है ।

श्री प्रभू नारायण सिंह—बुधवार को काम शुरू करने से यह होगा कि हमको वक्त मिल जायेगा और हम बिल्स को भी प्रोपेयर कर लेंगे और अमेंडमेंट्स भी दे सकेंगे । अगर कल सेशन होगा तो दिन भर हाउस में बैठना पड़ेगा ।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—सेल्स टैक्स और फायर सर्विस बिल जो हैं उसको आप देखें तो मालूम होगा कि कोई खास बात नहीं है और उन में शायद ही कोई अमेंडमेंट दिया जा सके ।

श्री राजाराम शास्त्री (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र) —आपने जैसा कहा था ठीक है, कल का दिन इस्तेमाल करना है, मैं तो चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को इनकम्प्लीमेंट्स न हो और सदस्यों को भी दिक्कत न हो । मेरा अपना खयाल यह है कि सेल्स टैक्स और जमींदारों के ऋण का जो बिल है उन पर कल विचार न किया जाय । जैसे फायर बाला बिल है, वह मैंने देखा । वह ऐसा नहीं है कि भवन का उसमें समय ज्यादा लगेगा, उसको कल लिया जा सकता है । और उसके बाद प्रस्ताव लिखे जा सकते हैं ।

चेयरमैन—एक बात और यह है कि शनिवार को छुट्टी है । अगर हम लोग शुक्रवार को काम खत्म कर लेते हैं, तो घर जा सकते हैं, नहीं तो फिर सोमवार को भी बैठना होगा । मैं चाहता यह था आप सोच लें और ऐसा प्लान बना लिया जाय जिससे यह सेशन शुक्रवार को खत्म हो जाय । मेरे विचार में उस के अलावा और कोई काम तो है नहीं ।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—इस वक्त तो नहीं है ।

चेयरमैन—अगर आप ठीक समझें तो कल रेज्यूलूशंस ले लें और उसके बाद बिल ले लिये जायेंगे और इस तरह से शुक्रवार को काम खत्म हो जायेगा । मैं समझता हूँ कि इस पर किसी को एतराज नहीं हो सकता है ।

प्रोफेसर मुकुट बिहारी लाल (स्नातक निर्वाचन क्षेत्र) —कल रेज्यूलूशंस क्यों न लिये जायें ?

चेयरमैन—कल फायर सर्विस बिल और रेज्यूलूशंस ले लिये जाय तो पूरा काम हो जायेगा । फिर अगले ३ दिनों में ये बिल ले लिये जायेंगे ।

श्री परमात्मा नन्द सिंह (स्थानीय संस्थाएँ निर्वाचन क्षेत्र) — मैं यह निवेदन करना चाहता था कि पूर्णमासी शनिवार को है। अगर हम शुक्र के दिन काम करेंगे तो पूर्णमासी के दिन अपने-अपने स्थानों पर न पहुँच सकेंगे। मसलन बलिया हम पूर्णमासी के दिन न पहुँच सकेंगे। बलिया में कातिक का बहुत बड़ा मेला होता है। वहाँ गवर्नमेंट और कांग्रेस का भी कुछ काम करना रहता है। इसके अतिरिक्त स्नान भी करना रहता है। इसलिए मैं तो समझता हूँ कि अगर शुक्रवार को भी छुट्टी रहे तो अधिक उचित होगा।

चेयरमैन — इन सब बातों पर तो जब मीटिंग बुलाई जाती है तब मेम्बरों को विचार कर लेना चाहिये। शुक्र, शनि और रवि इन तीनों ही दिन हम काम न करें यह तो मैं ठीक नहीं समझता, वैसे तो मैं हाउस के हाथ में हूँ।

श्री कुंवर गुरु नारायण — मैं लीडर आफ़ दि हाउस से प्रार्थना करूँगा कि वह कल फ़ायर वाला बिल रख दें। परसों नानआफ़िशियल बिजनेस (non official business) रख दें। अब रहा यह कि सेंटरडे को छुट्टी रहेगी। तो अगर तब तक ख़त्म न होगा तो हम मंडे को भी बैठ जायेंगे।

चेयरमैन — क्या सब का मत यह है कि कल रेजोल्यूशन लिये जावें ? शिवराजवती जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या कल वह मूव कर सकेंगे ?

श्रीमती शिवराजवती नेहरू — (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र) — अगर आप इजाजत देंगे तो मैं मूव कर सकूँगी।

श्री कुंवर गुरु नारायण — मैं चाहता हूँ कि परसों मूव किया जाये।

चेयरमैन — उस रेजोल्यूशन में कोई नई चीज़ आपके पढ़ने या सीखने की तो है नहीं। मैं समझता हूँ कि कुंवर साहब को ज़रा भी दिक्कत अपने रेजोल्यूशन के करने में होगी। कल फ़ायर सर्विस बिल पर विचार किया जाये और जो सदस्य अपने रेजोल्यूशन मूव करना चाहें वह मूव कर लेंगे।

श्री कुंवर गुरु नारायण — कल फ़ायर सर्विस बिल न लिया जाये; खाली नान-आफ़िशियल रेजोल्यूशन रखे जायें जिससे हम लोगों को डिस्कशन करने का पूरा मौक़ा मिले।

चेयरमैन — बृहस्पतिवार के स्थान पर कल गैर सरकारी दिन रखा जायगा और अगले तीन दिन तक इन तीन विधेयकों पर विचार किया जायगा।

कल ११ बजे तक के लिये कौंसिल स्थगित की जाती है।

(कौंसिल की बैठक ११-३० बजे दूसरे दिन मंगलवार, २८ अक्टूबर, १९५२ को दिब के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गई।)

लखनऊ :
२७ अक्टूबर, १९५२।

श्याम लाल गोविल,
सेक्रेटरी, लेजिस्लेटिव कौंसिल,
उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौंसिल

उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौंसिल की बैठक, विधान भवन, लखनऊ में ११ बजे दिन के चैयरमैन (श्री चन्द्रभाल) के सभापतित्व में हुई।

२८ अक्टूबर, १९५२

उपस्थित सदस्य (६०)

अब्दुल शकूर नज़मी, श्री
अम्बिका प्रसाद वाजपेयी, श्री
इन्द्र सिंह नयाल, श्री
ईश्वरी प्रसाद, डाक्टर
उमानाथ बली, श्री
एम० जे० मुकर्जी, श्री
कन्हैयालाल गुप्त, श्री
कुंवर गुरु नारायण, श्री
कुंवर महावीर सिंह, श्री
कदारनाथ खेतान, श्री
कृष्णचन्द्र जोशी, श्री
खुशाल सिंह, श्री
जगन्नाथ झाचार्य, श्री
जमीलुर्रहमान कदवाई, श्री
ज्योति प्रसाद गुप्त, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेलराम, श्री
नरीत्तम दास टंडन, श्री
निजामुद्दीन, श्री
निर्मल चन्द चतुर्वेदी, श्री
प्रताप चन्द्र आजाद, श्री
प्रभू नारायण सिंह, श्री
प्रसिद्ध नारायण अनन्द, श्री
प्रेसचन्द्र शर्मा, श्री
पन्ना लाल गुप्त, श्री
परमात्मा नन्द सिंह, श्री
प्यारेलाल श्रीवास्तव, डाक्टर
बद्री प्रसाद कक्कड़, श्री
बशीर अहमद, श्री
बलभद्र प्रसाद वाजपेयी, श्री
बालक राम वैश्य, श्री
बाबू अब्दुल मजीद, श्री

बीर भान भाटिया, डाक्टर
बंशीधर शुक्ल, श्री
ब्रजलाल वर्मन, श्री (हकीम)
ब्रजेन्द्र स्वरूप, डाक्टर
महमूद अस्लम खां, श्री
मानपाल गुप्त, श्री
मुकुट बिहारी लाल, प्रोफेसर
राजा राम शास्त्री, श्री
राना शिवअम्बर सिंह, श्री
राम किशोर शर्मा, श्री
राम नन्दन सिंह, श्री
राम लखन, श्री
राम लगन सिंह, श्री
राय बजरंग बहादुर सिंह, श्री
लालता प्रसाद सोनकर, श्री
लाल सुरेश सिंह, श्री
विजय श्रानन्द आफ विजयानगरम,
महाराजकुमार डाक्टर
बिश्वनाथ, श्री
शांति देवी, श्रीमती
शांति देवी अग्रवाल, श्रीमती
शिवराजवती नेहरू, श्रीमती
शिव सुमन लाल जोहरी, श्री
श्याम सुन्दर लाल, श्री
सत्य प्रेमी उपनाम हरिप्रसाद, श्री
सभापति उपाध्याय, श्री
सरदार संतोष सिंह, श्री
सैयद मोहम्मद नसीर, श्री
हयातुल्ला अंसारी, श्री

निम्नलिखित मंत्री भी उपस्थित थे:—

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम (वित्त मंत्री)
श्री चरण सिंह (माल मंत्री)
श्री मोहन लाल गौतम (स्वशासन मंत्री)
श्री गिरधारी लाल (सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

प्रश्नोत्तर

१-११—श्री शिवसुमरन लाल जौहरी (स्थानीय संस्थाओं निर्वाचन क्षेत्र)—
अस मंत्री की इच्छानुसार २६ अक्टूबर, सन् १९५२ ई० के लिये स्थगित किये गये ।

उत्तर प्रदेश में आचार्य विनोबा भावे के भू-दान यज्ञ में दी गई भूमि

१२—श्री कुंवर गुरु नारायण (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—आचार्य विनोबा भावे के भू-दान यज्ञ के दौर में उत्तर प्रदेश ने कुल कितनी एकड़ भूमि दी ?

12. Sri Kunwar Guru Narain—(Legislative Assembly Constituency)
What is the total number of acres of land contributed by Uttar Pradesh to Acharya Vinoba Bhave in the course of his Bhudan Yagna tour ?

श्री चरण सिंह (कृषि मंत्री)—३० जून, १९५२ तक कुल १६८, ६४५. १५६५ एकड़ भूमि दान स्वरूप दी गई थी ।

Sri Charan Singh Minister for Agriculture—A total area of 198, 645. 1,959 acres was contributed up to June 30, 1952.

Sri Kunwar Guru Narain—Is all the land thus transferred situated in such a way that this can be calculated without extra efforts being taken by the administration ?

Sri Charan Singh—I just do not understand the question. What the Hon'ble Member means by calculation, I fail to follow.

श्री कुंवर गुरु नारायण—मैं यह जानना चाहता हूँ कि जो जमीन की तादाद बतलाई गयी है उस में बहुत ऊसर और बंजर है। इस में बहुत एक्सट्रा एफर्ट किया जायेगा तब वह कल्टिवेबिल हो सकेगा। एडमिनिस्ट्रेशन विदाउट एक्सट्रा एफर्ट (administration without extra effort.) के इसे कैसे कर सकता है ?

श्री चरण सिंह—सवाल में यह है कि कितनी कृषि योग्य है और कितना नहीं है। इसमें ४ कटेगरी हैं जिसे मालूम करने में बहुत समय लगेगा। इस जमीन के सिलसिले में यह मालूम करना कि एग्रोकल्चरेबिल है या नहीं बहुत मुश्किल है। इसमें बहुत वक्त लगेगा और देर भी लगेगी।

Sri Kunwar Guru Narain—If the beneficiary from this Bhudan Yagna is not in a position to cultivate the land transferred to him what arrangements Government propose to make to provide all facilities for such a person.

Chairman—The question is hypothetical and therefore cannot be allowed.

श्री कुंवर गुरु नारायण—मैं यह जानना चाहता हूँ कि जो ऊसर और बंजर जमीन है जिस को बिना एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सट्रा एफर्ट के कल्टीवेट नहीं कर पायेंगे तो उन लोगों को सुविधा देने के लिये सरकार ने क्या सोचा है ?

श्री चरण सिंह—ऐसे और भी लोग हमारे सूबे के अन्दर हैं जिनके पास सुविधा की कमी है या जिन के पास नयी जमीन है उनके पास भी सुविधा नहीं है। जैसे और लोगों को सुविधा दी जायेगी वैसे इन लोगों को भी दी जायगी। क्लिहाल सरकार का कोई सुविधा देने का विचार नहीं है।

१३—श्री कुंवर गुरु नारायण—(क) वर्तमान कानून की किन धाराओं के अन्तर्गत उपरोक्त जमीन का हस्तान्तरण हुआ ?

(ख) क्या यह बात सरकार के ध्यान में लाई गई है कि जमीन के इस प्रकार हस्तान्तरण करने में कठिनाइयाँ हैं ?

13. Sri Kunwar Guru Narain—(a) Under which provisions of the present law has the transfer been effected ?

(b) Has it been brought to the notice of the Government that legal difficulties are involved in the transfer of land in this manner ?

श्री चरण सिंह—(क) भूमि दान पत्रों के रूप में दी गई है परन्तु सरकारी कागजातों में अभी अमल दरामद नहीं किया गया है।

(ख) जी हाँ।

Sri Charan Singh—(a) The donations have been made in the form of *dan pattras*. The transfers have not been effected in the Government records.

(b) Government are fully aware of the legal difficulties.

Sri Kunwar Guru Narain—Are *dan pattras* permitted under the present law ?

Sri Charan Singh—Sirdars are not allowed to make any gift but the *bhumidars* are.

१४—श्री कुंवर गुरु नारायण—(क) क्या उपरोक्त जमीन का हस्तान्तरण वास्तविक रूप से हो गया है या अभी दान देने वालों के बायदे की शक्ल में है ?

(ख) प्रत्येक श्रेणी में कुल कितनी जमीन है ?

14. Sri Kunwar Guru Narain—(a) Has the transfer been actually effected or is still in the stage of promise of donors ?

(b) How much land is comprised in each category ?

श्री चरण सिंह—(क) इसका उत्तर ऊपर दिया जा चुका है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

Sri Charan Singh—(a) This has already been answered above.

(b) The question does not arise.

Sri Kunwar Guru Narain—The answer is that the question does not arise. Why does it not arise ?

Chairman—This is a matter of opinion.

१५—श्री कुंवर गुरु नारायण—इस प्रकार जो जमीन हस्तांतरित की गई है उसमें कितनी तर, खुश्क या कृषि योग्य है ?

15. Sri Kunwar Guru Narain—How much of the land thus transferred is wet, dry or arable ?

श्री चरण सिंह—यह सूचना सरकार के पास उपलब्ध नहीं है। इसके एकत्रित करने में बहुत समय, मेहनत तथा खर्च पड़ेगा।

Sri Charan Singh—The information is not available with Government. Its collection will take much time and will not be commensurate with the time, labour and expense involved.

१६—श्री कुंवर गुरु नारायण—इस जमीन को भूमि रहित मजदूरों में बांटने के लिये रखा गया है ?

16. Sri Kunwar Guru Narain—What is the basis on which the distribution of the land is to take place among landless labourers ?

श्री चरण सिंह—भूमि का वितरण आचार्य जी की स्वीकृत की हुई योजना के अनुसार होगा।

Sri Charan Singh—The distribution of land will be made according to a scheme approved by Acharya Ji.

Sri Kunwar Guru Narain—The answer is that the distribution of land will be made according to a scheme approved by Acharya Ji. I want to ask, will the Government have no hand in the scheme proposed by Acharya Ji and any scheme suggested by him will be accepted ?

Sri Charan Singh—I do not think there is any apprehension of a difference of opinion between Acharya Ji and Government on this subject.

Sri Kunwar Guru Narain—By what standard Government will judge that a particular applicant for the free gift will stick to the job of cultivation, will himself cultivate the land, and will not sublet it and become an absentee proprietor ?

Sri Charan Singh—This much is certain that nobody will be allowed to lease away the land whether he holds the holding in some other right or gets it from Acharya Ji.

श्री राजाराम शास्त्री (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—इस बारे में जमींदारों की राय ली जायेगी या नहीं ?

श्री चरण सिंह—जमींदार तो नहीं रहे।

श्री कुंवर गुरु नारायण—इस मामले पर क्या प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से भी कन्सलटेशन होगा ?

चेयरमैन—मैं इसकी इजाजत नहीं देता।

१७-२०—श्री प्रताप चन्द्र आज़ाद (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—[गृह मंत्री की इच्छानुसार अक्टूबर, १९५२ ई० [के लिये स्थगित किये गये।]

२१-२३—श्री राम नन्दन सिंह (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—[वर्तमान बैठक के पांचवें सोमवार के लिये प्रश्न संख्या १-३ के रूप में रखे गये।]

२४-३२—श्री दीप चन्द्र (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)—स्थगित।

३३-३४—श्री कुंवर गुरु नारायण—स्थगित।

उत्तर प्रदेश में मुस्तारों और रेवेन्यू एजेंटों की संख्या

आदि संख्या

२४

ता०

२३-९-५२

Original

No 24

Dated

23-9-52

३५—श्री ज्योति प्रसाद गुप्त (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि राज्य में इस समय वकालत करने वाले मुस्तारों और रेवेन्यू एजेंटों की संख्या क्या है ?

35. Sri Jyoti Prasad Gupta—(Local Bodies Constituency)—Will the Government kindly state the number of Mukhtars and Revenue Agents practising in the State at present ?

श्री चरण सिंह—इस राज्य में मुस्तारों और रेवेन्यू एजेंटों की कुल संख्या क्रमशः १,७१६ और १,२५४ है। १,७१६ मुस्तारों में से ३४८ मुस्तार रेवेन्यू एजेंट का भी काम करते हैं।

Sri Charan Singh—The total number of Mukhtars and Revenue Agents in the State is 1716 and 1254 respectively. Out of 1716 Mukhtars, 348 of them are also working as Revenue Agents.

३६—श्री ज्योति प्रसाद गुप्त—(क) क्या सरकार को मालूम है कि ग्राम पंचायतों के स्थापित होने और जमींदारी उन्मूलन और भूमि व्यवस्था ऐक्ट के लागू होने से अदालत माल का बहुत सा काम पंचायतों और दीवानी अदालतों को हस्तांतरित हो गया है, जहाँ कि मुस्तार और रेवेन्यू एजेंटों को वकालत करने से कानूनी मनाही है ?

आदि संख्या

२५

ता०

२३-९-५२

(ख) यदि हाँ, तो इस तबके के कानूनी वकालत करने वालों की सहायता के लिये सरकार क्या करना चाहती है ?

36. Sri Jyoti Prasad Gupta—(a) Is the Government aware that on account of the establishment of the village panchayats and enforcement of the Zamindari Abolition and Land Reforms Act, most of the Revenue work has been transferred to the Panchayats and the Civil Courts, where Mukhtars and Revenue Agents are legally barred from practising ?

Original

No 25

Dated

23-9-53

(b) If so, what step does the Government propose to take to afford relief to this class of legal practitioners ?

श्री चरण सिंह—(क) माल की अदालतों का कुछ काम निस्संदेह पंचायतों और दीवानी की अदालतों को दे दिया गया है जिनमें मुस्तार और रेवेन्यू एजेंट विधितः वकालत नहीं कर सकते किन्तु सरकार का यह मत है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५०, की अनुसूची २ और उसकी नियमावली के अध्याय १२ के अनुसार उनके

पास अब भी बहुत काफी प्रारंभिक (ओरिजिनल) और अपील संबंधी दोनों प्रकार का काम है।

(ख) जैसा कि ऊपर प्रश्न ३६ (क) के उत्तर में बताया गया है, सरकार प्रश्नकर्ता से बिल्कुल सहमत नहीं है। फिर भी इस मामले की ओर सरकार ध्यान दे रही है।

Sri Charan Singh.—(a) Some of the Revenue work has no doubt been transferred to the Panchayats and Civil Courts, where Mukhtars and Revenue Agents are legally barred from practising. But Government are of the view that for the present there is still quite sufficient case work both original and appellate for them in Revenue Courts as Chapter XII of the Rules and Schedule II of the U. P. Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950, will show.

(b) As stated in reply to question no. 36(a) above, Government does not agree with the questioner entirely. Still, the matter is engaging the attention of Government.

अदि संख्या

२६

ता०

१३-९-५२

३७—श्री ज्योति प्रसाद गुप्त—(क) क्या यह सच है कि आनरेबिल हाईकोर्ट, इलाहाबाद ने सन् १९५१ ई० से मुह्तारों और रेवेन्यू एजेंटों को जो तेहरी-गढ़वाल, रामपुर और बनारस रियासतों में बकायत कर रहे थे, प्लीडर ग्रेड २ घोषित करके, मातहत की बीवानी अदालतों में बकायत करने की आज्ञा दे रखी है।

(ख) यदि हां, तो क्या उन मुह्तारों और रेवेन्यू एजेंटों को भी यह सुविधा मिले जाने का इरादा है जो कि राज्य के दूसरे भागों में बकायत करते हैं?

Original

No. 26

Date

23-9-52

37. Sri Jyoti Prasad Gupta.—(a) Is it a fact that since 1951 the Hon'ble High Court, Allahabad has been pleased to allow Mukhtars and Revenue Agents practising in the old Tehri-Garhwal, Rampur and Banaras States to practise in the Subordinate Civil Courts there declaring them as Pleaders Grade II?

(b) If so, is it intended to extend this privilege to Mukhtars and Revenue Agents practising in other parts of the State also?

श्री चरण सिंह—(क) जो हां।

(ख) इस मामले का निर्णय हाई कोर्ट ही कर सकता है। सरकार का इससे कोई संबंध नहीं है।

अदि संख्या

२७

ता०

१३-९-५२

Sri Charan Singh.—(a) Yes.

(b) It is for the Hon'ble High Court to take decision on this question. Government are not concerned with it.

३८—श्री ज्योति प्रसाद गुप्त—(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश के मुह्तारों और रेवेन्यू एजेंटों से इस संबंध में कोई प्रार्थना-पत्र मिला है?

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है?

38. Sri Jyoti Prasad Gupta—(a) Has the Government received any representation from the U. P. Mukhtars and Revenue Agents in this connexion ?

Original
No. 27
Dated
23-9-52

(b) If so, what action has so far been taken thereon ?

श्री चरण सिंह—(क) जी हां ।

(ख) लीगल प्रैक्टिशनर्स ऐक्ट की धारा ६ के अनुसार हाईकोर्ट को ही यह अधिकार है कि वह मुह्तारों और रेवेन्यू एजेंटों को प्लीडर के पद पर नियुक्त करे। इस विषय में उनकी राय ली गई थी किन्तु वह सहमत नहीं हुये।

Sri Charan Singh—(a) Yes.

(b) Under section 6 of the Legal Practitioners Act, the High Court are the proper authority to raise the status of Mukhtars and Revenue Agents to that of pleaders. They were consulted in the matter, but were not agreeable to the proposal.

Sri Jyoti Prasad Gupta—Will the Hon'ble Minister kindly state if the High Court have given any reason for not agreeing to their suggestion ?

Sri Charan Singh—They consider that the Mukhtars are not possessed of sufficient legal knowledge to practise in the Civil courts.

Sri Jyoti Prasad Gupta—But in the case of Mukhtars who are practising in the States merged with U. P. they have already allowed that. ?

Sri Charan Singh—The reason is that the Maharaja of Banaras and Tehri-Garhwal and the Nawab of Rampur had allowed these Mukhtars to practise in Civil courts before the merger took place. So after the merger the High Court agreed to allow them to continue as before.

संकल्प कि उत्तर प्रदेश में अनाथालयों तथा विधवा आश्रमों का प्रबंध सरकार अपने हाथ में ल ले

श्रीमती शिवराजवती नेहरू (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—माननीय अध्यक्ष

महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव उपस्थित करती हूँ :

“यह परिषद् सरकार से अनुरोध करती है कि प्रदेश में अनाथालयों तथा विधवा आश्रमों का प्रबंध संस्थाओं अथवा व्यक्तिगत हाथों में न रख कर स्वयं अपने अधीन कर ले और कार्य को सुचारु रूप से संचालित करने के हेतु महिला तथा पुरुष सदस्यों को इनका निरीक्षण नियुक्त कर दे ।”

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ वर्षों से यह देख रही हूँ कि हमारे सारे प्रांत भर में जितने अनाथालय हैं या और भी जो ऐसी संस्थायें हैं, जैसे कि विधवा आश्रम हैं, इनमें जो कर्म हो रहे हैं वह बड़े ही घृणित हैं। आज जो जो बातें उनमें हो रही हैं उनको इस सदन के अन्दर रखना मेरे लिये बहुत ही दुश्वार है। अभी एक रक्षा मंडल के बारे में अखबारों में छपा है कि वहां कैसे-कैसे कर्म हुये और जो उसके संचालक थे वह आज जेलों में पड़े हुये हैं और उन्हीं कर्मों की बदौलत आज उनकी यह हालत हुई है। हमारे शहर में इस प्रकार की चार संस्थायें हैं, जैसे कि एक रक्षा-मंडल गोलागंज में है, एक हिन्दू कन्या आश्रम मोतीनगर में है और एक इसी तरह का आश्रम चौक में है एक और है। इस तरह चार आश्रम हमारे शहर के अन्दर हैं और इन आश्रमों की शाखायें चारों ओर फैली हुई हैं। जिस तरह से कोई व्यापारी होता है और वह अपना व्यापार चलाने के लिये जगह जगह में शाखायें खोलता है उसी प्रकार इन मंडलों की भी शाखायें कोई गोरखपुर

[श्रीमती शिवराजवती नेहरू]

में हैं, कोई उन्नाव में हैं, कोई गोंडा में और कोई बरेली में हैं। यह कितने दुख की बात है कि धर्म के नाम पर यह सब रक्षा मंडल खुले हुये हैं जिससे कि लोगों के ऊपर इसका अच्छा असर पड़े और बड़े बड़े धार्मिक पुरुषों के नाम पर खोले गये हैं जिससे कि लोगों के ऊपर यह असर हो कि लोग बड़ा परोपकार कर रहे हैं और दीन दुखियों के ऊपर दया करने के लिये आश्रम खुले हैं और जो देश को फायदा पहुंचाने वाले हैं और देश की जनता को सुविधा देने वाले हैं। परन्तु वास्तव में बात इसके विपरीत ही है। जो कुछ भी कार्य यहां होता है वह बहुत ही घृणित और निन्दनीय है। मैं इसके साथ ही साथ यह भी कहती हूं कि हमारे देश में ऐसी घंडलियों की आवश्यकता है जिससे हमारे देश और जो समाज की हीन दशा है वह दूर हो और जो कुछी स्त्रियां हैं, विधवा हैं, उनके लिये हमारे देश में इस बात की आवश्यकता है कि इस तरह के आश्रम खोल जायें। इस तरह के मंडल बनाये जायें कि जहां दीन दुखी स्त्रियां आयें और वहां रहकर अपना जीवन निर्वाह कर सकें। परन्तु आजकल वहां यह बात नहीं है। उन्होंने इस तरह के मंडल अपने व्यापार के अड्डे बना रखे हैं इसी लिये उन्होंने अलग अलग शाखायें खोली हैं कि शायद अगर कोई स्त्री गोरखपुर में मिलती है तो उसको गोरखपुर के आश्रम में नहीं रखा जाता है बल्कि उसको लखनऊ के आश्रम में भेज दिया जाता है और अगर लखनऊ में कोई स्त्री मिलती है तो उसे लखनऊ के आश्रम में न रख कर दूसरी जगह के आश्रम में रखा जाता है ताकि जो उनके बन्धु या भाई या पति उनकी ढूंढ में निकलते हैं वह उन स्त्रियों को उन स्थानीय आश्रमों में न पाकर वापस लौट जायें। इसके अलावा उनको तालों के अन्दर बन्द रखा जाता है और जिस तरह से हमारे सेंट्रल जेल में कैदियों को रखा जाता है उसी तरह से इनको भी तालों के अन्दर बन्द रखा जाता है। जो लोग उनको ढूंढने आते हैं अगर वे उस जगह पहुंच जाते हैं तो उनको वहां से दूसरी जगह भेज दिया जाता है। तो इस तरह से इन लोगों ने यह अपने व्यापार के अड्डे बनाये हैं और जो उनके संचालन करने वाले हैं वे बाज-बाज तो बहुत पैसे वाले और अमीर हो गये हैं। ऐसी दशा में इन आश्रमों की दशा उन लोगों की वजह से बहुत ही गिर गई है। इस तरह से स्त्रियों को रखा जाता है और फिर वहां रखा जाता है। कुटनियों वहां मंदिरों के पास जाकर या स्टेशनों पर जाकर उन स्त्रियों को लाती हैं और उनमें ऐसी भी बहुत सी स्त्रियां होती हैं जो कि अपने पति के बुरे आचरण से परेशान होकर अपना घर छोड़ बेती हैं और उनमें कई स्त्रियां ऐसी भी होती हैं जो कि अपने घर से लड़ झगड़ कर और बहुत तकलीफों से परेशान होकर घर से भाग जाती हैं, तो इन सब स्त्रियों को कुटनियों का शिकार होना पड़ता है। अच्छा महोदय, स्त्रियों में यह बात है कि जब तक उनको अपने घर में बहुत ज्यादा कष्ट न होवे आसानी से अपना घर नहीं छोड़ती हैं। इस तरह से कोई विधवा होती है जो कि अपने भाई या भावज से परेशान होकर अपना घर छोड़कर आ जाती है और इस तरह से कई स्त्रियां खुद अपने पति व अपने खानदान की इज्जत बचाने के लिये आश्रम में चली जाती हैं और वे यह सोचकर उन आश्रमों में जाती हैं कि वहां वे ईश्वर में मन लगाकर दो वक्त रोटी खाकर अपने जीवन का निर्वाह अच्छी तरह से कर सकें। लेकिन वहां होता क्या है कि वे महीने या पन्द्रह दिन तक वहां रहती हैं और उसके बाद उनको खरीद कर वहां से दूसरे लोग ले जाते हैं। वहां उनकी खरीदारी सूरत व शकल देख कर होती है और ऐसी स्त्री जिसकी सूरत शकल अच्छी हो उसकी ४००-५०० रु० और यहां तक कि एक हजार रुपये में शादी कर दी जाती है। इस तरह से उनको खरीद कर लोग अपने साथ ले जाते हैं, मगर वह वहां ज्यादा नहीं रह पाती हैं और अपने पति का जेवर, गहना और रुपये लेकर वह फिर आश्रम में लौट जाती है और फिर उसकी शादी दूसरी जगह कर दी जाती है। इस तरह से वहां स्त्रियों की दो दो, तीन तीन शादियां की जाती हैं। जो स्त्रियां बबशकल और बूढ़ी हो जाती हैं उनको कुटनियों का कार्य सौंपा जाता है। इस तरह से आज ये आश्रम पक्के व्यवसाय के अड्डे हो गये हैं और जो हमारा हिन्दू धर्म है, वह सब खत्म हो गया है।

इस कार्य में ऐसे हिन्दू भाई भी हैं जो कि आज कहते हैं कि हमारा हिन्दू धर्म खतरे में पड़ गया है, जो कहते हैं कि हमारी संस्कृति ही सबसे उत्तम है। तो आज क्या यही हिन्दू धर्म है, यही हिन्दू संस्कृति है। इन्हीं सब हालतों को देखकर मैं सरकार से इस बात की प्रार्थना करती हूँ कि वह इन आश्रमों का नियन्त्रण अपने हाथ में ले ले और इन आश्रमों से ऐसे लोगों को निकाल दे। वह इन आश्रमों में ऐसे लोगों का नियन्त्रण कर दे जो कि इन स्त्रियों को इस तरह से तालीम दें, इस तरह से व्यवहार-कुशल और उद्योग धंधों को सिखावें जो कि उनके लिये लाभप्रद सिद्ध हो और इस तरह से जो आज करोड़ों स्त्रियाँ परेशान हैं उनको ले जाकर वहाँ रखें और आज जिस तरह से रिस्पूजीज स्त्रियों को रखा जाता है, उसी तरह से उनको रखा जाय। इस तरह से वे सेल्फ सपोर्टिंग संस्थायें हो जायेंगे और वहाँ वे अपने जीवन का निर्वाह भी कर सकेंगी। यदि सरकार इसमें सहायता देगी और जो माननीय सदस्य हैं वे वहाँ जाकर इस चीज को देखेंगे और उन आश्रमों का नियन्त्रण अपने हाथ में लेंगे, तो इनकी उन्नति अवश्य होगी। इन्हीं सब कारणों को देखते हुये मैंने अपना यह प्रस्ताव अपने भाइयों के सामने रखा है कि जो आज हमारा देश कं दुखी और सताये हुये लोग हैं और जो ऐसी सताई हुई स्त्रियाँ हैं जो कि कुचल दी गई हैं, हमें उनकी आत्मा को ऊंचा उठाना है और इस तरह से अपने धर्म को कलंकित नहीं होने देना है।

यह अपनी हिन्दू संस्कृति के बचाने का सवाल है। इन सब बातों पर आप विचार करें। इन्हीं सब कारणों से मैंने यह प्रस्ताव इस सदन के सामने पेश किया है।

श्री एम० जे० मुकर्जी (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—Mr. Chairman, Sir, what we have just heard is a tale of sorrow and disgrace and whatever can be done must be done and must be done speedily.

चेयरमैन—You will please move your amendment first.

श्री एम० जे० मुकर्जी—The amendments that I suggest to this resolution are that 'in line 3 the word "management" be replaced by the word "control"

Insert the words "of ill-repute" after the word "homes" in line 4;

Delete the last sentence from "members..... visitors" and substitute the same by "official visitors from both the Houses be appointed".

I made a mistake in putting down "official". It should be "non-official".

श्रीमती शिवराजवती नेहरू—मेरा प्रस्ताव हिन्दी में है यदि हिन्दी में अमैडमेंट रखा जाय तो अच्छा होगा।

चेयरमैन—श्रीमती शिवराजवती नेहरू, आप हिन्दी के कार्यक्रम को देख लें, उसमें उसका तर्जुमा है।

श्री एम० जे० मुकर्जी—Sir, as I was saying, if even one-hundredth of the tale which has been told to us by the Mover is correct then whatever action can be taken by Government should be taken to stop it. It is clear from her description that these Ashrams are dens of debauchees and, as such they must be annihilated and absolutely squashed. The wording of the Resolution is unfortunately such that I cannot accept it because it includes all institutions of the type mentioned in the Resolution i. e. widow homes and orphanages. There are many widow-homes and orphanages established in this land of ours for the last 50 to 60 years and they are being managed very well indeed. They have prepared the women for all types of industrial work and they have prepared the orphans to take their legitimate share in the building up of the nation. I cannot understand why these institutions should be taken over by Government. Many of them are under religious practice and religious protection. The Constitution allows very freely, if you read Article 25 (1) and 26 (a) (b) and (d) they are permitted—not only permitted but encouraged—to open such institutions and do such work. I am sure the Mover does not want inclusion of such institutions that have been doing good work because the whole trend of her talk was that we should tackle only those institutions that are evil and those which are practising evil. There is also a directive in our Constitution that childhood and youth are to be protected against exploitation and against moral and material abandonment. This is required by our Constitution, Art. 39(f). It is all the more, therefore, necessary that we, sitting here in this House, should seriously consider this problem. So my amendment is that all those institutions that are of ill-repute should be taken over by Government. That is the amendment that I have put in. I have put in another small amendment—change the word “management” by the word “control”. I am prepared to change the word “control” also by the word “supervision” because it is not possible for Government to take over even these institutions with all the things that they have to tackle which they are seriously thinking of tackling for the construction of a welfare State. Economically from the point of view of finance or even from the point of view of personnel it is very difficult for them to take the whole management of even such ill-reputed institutions. Therefore, it is only by way of supervision that they can in any way be held responsible, and for that the Constitution requires that laws should be made that these people should be criminally treated. I would say that such persons as are involved in these things, a mill-stone may be hung round their neck and they may be put in to the Gomti or any other river where these institutions exist. It is really a disgrace. It is a cancer in our body politic. It has brought us down to dust in the eyes of other nations. I do not mean that other nations have not all these evils in them, but we are not concerned with them. We are only concerned with the women of our own country, and we feel that it is our responsibility to give them that protection. If the women are being treated in that way, certainly they need protection; but if we expect Government to do everything, Sir, I think we are asking for too much. There is a great deal of need for reformation in our own Samaj where we can lift the womanhood from the lowest pedestal to the highest level, where we may respect them and we may treat them as mothers of our nation. We are happy to see that we have brought them to the same level as men. The arrogant men in the past had always kept them as chattels in the homes and this is the result of all that. The demand of 20th century is that we must realise and realise very seriously that reform is needed to raise the status of womanhood from what it is now. If it is done, then I

am sure that many of the evils that are at present prevalent will disappear. My third amendment that I have put at the end of the Resolution, I take it back. I do not consider it very essential to be added to the Resolution.

चेयरमैन—श्री प्रेमचन्द्र शर्मा जी ने एक संशोधन की सूचना दी है, पहले वह संशोधन पेश कर दें उसके बाद दूसरे सदस्य बोलेंगे।

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा (स्थानीय संस्थाएँ निर्वाचन क्षेत्र)—श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं श्रीमती शिवराजवती जी के प्रस्ताव की पंक्ति दो में शब्द 'का प्रबन्ध' के स्थान में शब्द "समुदाय की देखरेख" रख दिया जाये, यह संशोधन करता हूँ। दूसरे पंक्ति दो में शब्द "कर" और शब्द "स्वयं" के बीच शब्द समुदाय "जहाँ उचित समझा जाय वहीं" रख दिया जाय।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इन संशोधनों के उपस्थित करने से मेरा मंशा यह है कि यह सही है जैसा कि प्रस्तावक महोदय ने कहा कि बहुत सी संस्थाएँ यहाँ ऐसी हैं जिनका प्रबन्ध ठीक नहीं है और जहाँ पर हित होने के बजाय स्त्री समुदाय और अनार्यों का अहित होने की ही बात रहती है। लेकिन साथ ही यह भी मानना पड़ेगा कि इस देश में ऐसी भी संस्थाएँ हैं और उनका प्रबन्ध ऐसे आदर्शों के हाथ में है जिनसे स्त्री जाति और अनार्यों की वास्तव में रक्षा होती है। उनका स्तर उठाया जाता है और उनको अच्छा नागरिक बनाया जाता है। इस संशोधन के रखने से मेरी मंशा यह थी कि समाज के सुधार का कोई मेजर इस सख्ती से न रखा जाय जिससे बजाय इसके कि जो लाभ सोचा गया है वह न होकर एक प्रतिक्रिया हो और वह मंशा पूरी न हो जो कि इस प्रस्ताव का है। इसी प्रकार से प्रस्ताव के द्वारा सरकार से यह मांग करना कि जितनी भी संस्थाएँ हैं उन सबका प्रबन्ध अपने हाथ में ले लें में समझता हूँ कि उचित न होगा। मुझे मालूम है कि अनेक संस्थाएँ ऐसी हैं जो आर्य समाज द्वारा अथवा दूसरी मिशनरीज के द्वारा चलाई जाती हैं। उन पर लाखों रुपया इन संस्थाओं का खर्च होता है। कुछ का प्रबन्ध ठीक भी है। यदि इस प्रस्ताव को मान लिया जाय तो उनका प्रबन्ध भी लाजिमी तौर से सरकार को अपने हाथ में लेना पड़ेगा। उनको जो किसी तरीके से चला रहे हैं और लाखों रुपया व्यय कर रहे हैं उनमें इस बात की प्रेरणा नहीं रह जायेगी कि दिलचस्पी से उन संस्थाओं में काम करें और रुपया खर्च करें। क्योंकि वे समझेंगे कि ये संस्थाएँ सरकार के हाथ में चली गई हैं और उन पर किसी किस्म का बोझ नहीं रह गया है। हमको मानना पड़ेगा कि इस देश में बहुत आरफनेज हैं जिनका उचित प्रबन्ध होता है और बहुत से ऐसे विधवा आश्रम हैं जिनका प्रबन्ध अच्छा होता है। उसमें काफी रुपया खर्च होता है। मेरा मतलब यह है कि मैं इस प्रस्ताव को फ्लेजबुल बनाना चाहता था। अतः पंक्ति २ में शब्द "का प्रबन्ध" के स्थान पर शब्द समुदाय "की देखरेख" रख दिये जायें तथा उसी पंक्ति के अन्त में शब्द "कर" और शब्द "स्वयं" के बीच में शब्द समुदाय "जहाँ उचित समझें वहीं" रख दिया जाय। जहाँ तक कि प्रस्तावक महोदय का मतलब है यदि वहाँ अत्याचार होता है तो ऐसी संस्थाओं की देखरेख सरकार कर सकती है। जहाँ सरकार उचित समझे वहाँ ऐसा कर सकती है। इस तरह से जो संस्थाएँ उचित प्रकार से अपनी संस्थाओं को चलाती हैं उसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार पर न पड़े। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन को हाउस के सामने रखता हूँ।

श्री मोहन लाल गौतम (स्वशासन मंत्री)—अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक इस प्रस्ताव का सम्बन्ध है, इसमें एकाध शब्द को छोड़ कर जिस भावना से प्रेरित होकर यह पेश किया

[श्री मोहन लाल गौतम]

गया है उससे कोई मतभेद नहीं रख सकता है। जहां तक इन संशोधनों का सम्बन्ध है, एक संशोधन तो श्री मुकुर्जी और श्री प्रेमचन्द्र शर्मा का एक ही है। मैनैजमेंट की जगह कंट्रोल के लिये उन्होंने कहा और सुपरवीजन हो तो और अच्छा है। श्री प्रेमचन्द्र जी का शब्द बहुत अच्छा है। उसको रखने में मुझे कोई एतराज नहीं है।

जहां पर इलरिप्यूट बढ़ने की बात कही गयी है। वैसे तो यह सही है कि ये होम्स प्राइवेट इन्स्टीट्यूट्स के हाथ में हैं। जिसकी बदनामी हो जाय उसका प्रबन्ध गवर्नमेंट अपने हाथ में ले ले तो इस तरह की जो चीज है एक माने में ठीक है। फिर इनके कंट्रोल और सुपरविजन के मामले में इस तरह से फौरन दो तरह का क्लासीफिकेशन कर देना कि कुछ को इलरिप्यूट डिक्लेयर कर दें और कुछ को ऐसे रखें इससे दिक्कत पैदा हो जायेगी। इसलिये इस अमेंडमेंट को मानने में दिक्कत पड़ रही है।

दूसरे संशोधन के मताल्लिङ्ग प्रेमचन्द्र जी ने कहा कि “जहां उचित समझें” स्वयं अपने आधीन कर लें। इसको मैं स्वीकार कर सकता हूँ। यह संशोधन दो और दो मिल कर चार होते हैं, लेकिन एक कामन है, तीन रह जाते हैं। तीन में मंजूर करता हूँ। उसमें अगर इलरिप्यूट न जोड़ा जाता तो अच्छा था। अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने पहले अर्ज किया यह ऐसा मजमून है जिस पर दो रायें नहीं हो सकतीं। जिस तरह की बातें इस प्रस्ताव के प्रस्तावक महोदय ने हमारे सामने रखीं, इससे भी कहीं ज्यादा करुण कहानी इन संस्थाओं और जीवों के बारे में कही जा सकती है। यह तो चिन्ह है हमारे सोसायटीज की उन बीमारियों के जो हमारे समाज में हैं। इस समाज की बीमारी के थोड़े मामले को चिन्ह के रूप में समाज हमारे सामने रखता है। इन चिन्हों को दूर कर देने से समाज को संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिये कि हमारी बीमारी के चिन्ह दूर हो गये। इसकी गहराई पर हमें विचार करना होगा। सोचना है कि ये स्त्रियां स्वीकार करने में तो कोई अड़चन ही नहीं है लेकिन जिस तरह से अब तक बगैर किसी सुपरवीजन के वे चल रहे हैं और जो खराबियां समाज में पैदा करते रहे हैं उसकी अब इजाजत सरकार नहीं देना चाहती। इसलिये गवर्नमेंट यह चाहती है कि सारे प्रदेश का एक बोर्ड बनाया जाय और उसकी कुछ रुपया दिया जाय ताकि वह सुपरविजन कर सके और जो उनकी वकिंग हो उसकी देखभाल कर सके और उस बोर्ड के शुरू होने के बाद, जब वह उनके सम्पर्क में आ जायेगा और देखेगा कि उनकी यह खराबियां हैं जिनका नतीजा यह निकलता है तो फिर उनपर विचार करना होगा। इस वक्त सारे विडो होम्स और अनाथालयों को लेना कहां तक सम्भव होगा यह सोचने की बात है। इसलिये फौरन इस बात का फंसला करना कि सब अनाथालयों और विडो होम्स गवर्नमेंट ले ले, यह दूसरा पहलू होगा। हम देखें कि जितने अनाथालय और विडो होम्स चल रहे हैं उनका कैसा इन्तजाम है। जिनमें शिकायतें हैं उन्हें हम देखें कि उनकी क्या संस्था है। तमाम को इस वक्त ले लेना मुमकिन नहीं है। लेकिन उनके सुपरविजन और देखरेख का इन्तजाम जल्दी हो यह फंसला हमने किया है। हम चाहते हैं कि जल्दी ही एक बोर्ड बन जाय और वह उसका इन्तजाम करे। इस सम्बन्ध में गवर्नमेंट बेखबर नहीं है। तो बहरहाल जो गवर्नमेंट की पालिसी है वह मैंने अर्ज कर दी है। और मेरा यह ख्याल है कि इसपर अब ज्यादा समय सदन को लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस मसले पर किसी को मतभेद नहीं हो सकता है।

श्रीमती शिवराजवती नेहरू—मैं सरकार से बिल्कुल सहमत हूँ सरकार ने जब आश्वासन दे दिया है तो मुझे और कुछ नहीं कहना है। मैं अपना प्रस्ताव वापस लेना चाहती हूँ।

चेयरमैन—क्या सदन की अनुमति है कि यह प्रस्ताव वापस लिया जाय।

(सदन की अनुमति से प्रस्ताव वापस लिया गया।)

संकल्प कि प्रदेश में माध्यमिक कक्षाओं में सैनिक शिक्षा अनिवार्य कर दी जाय

श्री कुंवर गुरु नारायण— माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित प्रस्ताव इस भवन में उपस्थित करता हूँ :

“In order to meet any threat of aggression, external or internal, and to assist the permanent armed forces in times of national emergency, this Council recommends to the Government to make military education a compulsory subject for the students in the intermediate classes.”

श्रीमन्, जिस प्रस्ताव को मैंने अभी इस भवन के सम्मुख रखा उसके सम्बन्ध में कोई बहुत ज्यादा लम्बी चौड़ी तकरीर मैं नहीं करना चाहता। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे देश के लिये यह बहुत आवश्यक है और ऐसे समय में जब कि हमने बहुत सी मुसीबतों के बाद अपनी आजादी हासिल की है कि हम उस आजादी को कायम रखने के लिये ऐसे उपाय सोचें कि हमारी आजादी चाहे वह इक्स्टर्नल एग्रेसन से अथवा अन्दरूनी तरीकों से भंग न होने पावे और उसकी रक्षा हो। यह मानी हुई बात है कि आज संसार में जब कि प्रत्येक मुल्क आटम बम्ब की खोज में लगा हुआ है और हर मुल्क अपने देश को बजबूत करने के लिये हर प्रकार से मिलिटरी तैयार कर रहा है तो ऐसी अवस्था में जरूरी है कि हमारा देश भी इस प्रवृत्ति पर शान्तिपूर्वक विचार करे। हमारा क्रीड नानवाइलेंस किसी समय में था, उस समय तो परिस्थितियाँ कुछ दूसरी थीं। महात्मा गांधी ने जब नानवाइलेंस का प्रयोग किया अंग्रेजों के मुकाबले में तो भुमकिन है कि अगर हिन्दोस्तान में अंग्रेज न होते और उनकी जगह जर्मन्स यह इटालियन्स होते तो उस वक़्त गांधी जी किसी और अस्त्र का आसरा लेते अथवा किस अस्त्र को अपने हाथ में लेते यह कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन उन्होंने सन्ध के अनुकूल जो हुकूमत भारतवर्ष में थी उसकी परिस्थिति को समझ करके यह उचित समझा कि अगर हमें भारतवर्ष को किसी प्रकार आजाद करना है और एक निहत्थे राष्ट्र को स्वतंत्रता दिला सकते हैं तो वह अहिंसात्मक तरीके से ही दिलाई जा सकती है। लेकिन आज की बदली हुई परिस्थिति में, बदले हुये वातावरण में हमको इस बात का विचार करना पड़ेगा कि हम अपने देश की स्वतंत्रता को आजकल जो और देशों में भयंकर घुड़ का वातावरण फैला हुआ है उसको देखते हुये किस प्रकार से रक्षा कर सकते हैं। मैं अपनी जगह पर यह समझता हूँ कि अगर हम अपने राष्ट्र को ऊंचा उठाना चाहते हैं तो हमें अपने यहां के लोगों को कंपलसरी मिलिट्री एजुकेशन देना जरूरी है। उनको लड़ाई की शिक्षा जितनी दे सकते हों, दें। लड़ाई की शिक्षा से एक बहुत बड़ा लाभ और हो सकता है वह यह कि आज हमारे प्रदेश में भ्रष्टाचार जो फैला हुआ है, हमारा मारेल जो गिर गया है तो अगर मिलिट्री शिक्षा दी जायेगी तो उसका वह गिरा हुआ मारेल नहीं रहेगा जो कि आज सामाजिक जीवन में फैला हुआ है। आज यूनाइटेड किंगडम में मिलिट्री शिक्षा कंपलसरी नहीं है लेकिन वहां की हालत दूसरे प्रकार की है। वहां की स्थिति ऐसी नहीं है जैसी कि हमारे देश की है। वहां लोगों में टीम वर्क की स्पिरिट है जो कि यहां पर क़तई नहीं है। वहां पर जब जर्मनी का बम्बार्डमेंट हो रहा था तो वहां पर लोगों ने अपने स्थानों से हटना उचित नहीं समझा वरन् अपने आप को मिटा देना उचित समझा। वह बराबर उसी जगह पर मौजूद रहे। उनकी परिस्थिति दूसरी थी और हमारी दूसरी है। इसी प्रकार से और भी मुल्क हैं जैसे जर्मनी को ले लीजिये, इटली को ले लीजिये जहां पर डिक्टेटरशिप थी। वहां पर मिलिट्री एजुकेशन कंपलसरी जरूरी नहीं थी लेकिन उनके तरीके दूसरे हैं। वहां पर इमर्जेंसी के समय तमाम लोग मिल सकते हैं और वह उससे अपना काम चला लेते

[श्री कंवर गुरु नारायण]

हैं। हर मुल्क की परिस्थिति दूसरी होती है और वह उसके हिसाब से उस पर विचार करते हैं। हमारे देश की स्थिति वैसी नहीं है जैसी कि पश्चिम के मुल्कों की है। यह सब लोगों को मालूम है कि सन् ४२ में जिस समय कि यहां से १,००० मील दूर पर लड़ाई हो रही थी और बम्बाईमें हो रहा था तो वहां पर ऐसा वातावरण फैल रहा था कि अगर जापानी यहां पर आ जायेंगे तो हम उनको सरेडर कर देंगे अथवा स्वागत करेंगे। तो हमारा जो डिसिप्लिन है, जो हमारी शिक्षा अभी तक रही है वह एक दूसरे ही ढंग की रही है। इस ढंग की नहीं रही है जो स्वतंत्र देशों की है जो काफी अपने को मजबूत कर चुके हैं। ऐसी हालत में मैं समझता हूं कि यह जरूरी है कि हम अपने नवयुवकों को कम्पलसरी मिलिटरी ट्रेनिंग दें।

अब मैं यह कह सकता हूं कि और जानता हूं कि इस सरकार ने शायद सन् ४८ में मिलिट्री ट्रेनिंग की योजना बनाई। इस वक्त १२४ कालेजेज और स्कूलों में यह मिलिट्री शिक्षा दी जा रही है। यह भी सत्य है कि १८ जिलों में मिलिट्री शिक्षा है। लेकिन जिस जोर से मिलिट्री शिक्षा का प्रचार पहले किया गया वह वेग अब नहीं रहा और वह बहुत कम हो गयी और फिर धीरे धीरे उसमें शिथिलता आती चली गयी। तो यह जरूरी है और मैं जरूरी समझता हूं कि इसको फिर से जोरदार तरीके से चलाया जाय। इस वक्त करीब करीब २० हजार लड़के इंटरमीजिएट में हमारे प्रान्त में परीक्षा में बैठते हैं। इन २० हजार में से यदि १० हजार भी फिजीकली फिट हैं, मिलिट्री ट्रेनिंग के योग्य हैं तो इन बच्चों को यह ट्रेनिंग दी जाय। ऐसे समय पर उनका मारेल ऊंचा उठ जायेगा और जब कभी नेशनल एमर्जेंसी हो तो काम आ सकते हैं। इसलिये यह जरूरी हो जाता है कि मैं सरकार से इस बात की प्रार्थना करूं कि वह इस पर विचार करे। यह प्रस्ताव जो मैंने रखा है उसके रखने में मेरा कोई दूसरा आउट लुक नहीं है। मैं केवल यह चाहता हूं कि हमारे राष्ट्र के नवयुवकों का दृष्टिकोण बदला जाय। हमारे राष्ट्र के नवयुवकों में वह जरूरी चीज पैदा की जाय जिससे वह देश को आगे बढ़ायें और जिससे हम सम्पन्न भी हो सकते हैं। तो इसलिये मैंने यह प्रस्ताव रखा है।

एक और सुझाव मैं सरकार को देना चाहता हूं वह मिलिट्री शिक्षा के सम्बन्ध में है। आपने मिलिट्री शिक्षा को स्कूलों में प्रचलित किया है। इसमें यूनीवर्सिटी की यू० टी० सी० या और एक्जलरी ट्रेनिंग फोर्स हैं। इस प्रकार की कुछ मिलिट्री संस्थाएँ हैं जिनमें लड़कों को जाने का मौका मिलता है। लेकिन जो कालेजेज हैं वहां टीचर इन्सट्रक्टर रखे गये हैं। वह इस प्रकार का वातावरण नहीं पैदा कर सकते हैं जो कि एक मिलिट्री मैन कर सकता है जो कि लड़ाई के फ्रन्ट में रहा हो। मैं चाहता हूं कि बजाय इसके कि आप एक सादे हवलदार, जो कालेजेज में ट्रेनिंग के लिये रखते हैं बहुत उचित होगा कि मिलिट्री आफिसर जिनको फ्रन्ट का भी तजुर्बा है उनको रखें तो वातावरण भी दूसरा हो जायेगा। इन टीचरों से जो शिक्षा दी जाती है उनसे जो वातावरण होता है वह दूसरा ही होता है। इसके अतिरिक्त लड़के लोग सिर्फ डमी राइफल ही इस्तेमाल करते हैं लेकिन जब मिलिट्री का आफिसर आयेगा तो वे वास्तविक राइफल को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां तक मिलिट्री ट्रेनिंग शिक्षा का सम्बन्ध है हम चाहते हैं कि हमारे राष्ट्र के नवयुवकों को अभी से तैयार किया जाय। फिर किसी समय में किसी प्रकार की इमर्जेंसी हो तो हम उस समय हर प्रकार से तैयार रहें और उस इमर्जेंसी का मुकाबिला करें। यदि इस चीज में शिथिलता रही और यह कि जब मौका आयेगा तभी विचार किया जायेगा तो ऐसी हालत में मैं समझता हूं कि फौरन कोई ऐसी चीज पैदा नहीं की जा सकती जिससे हमारे देश को कोई फायदा हो सकता है। मैं इसके अतिरिक्त इसके सम्बन्ध में कोई खास बात नहीं कहना चाहता हूं। मैं केवल सरकार से इस बात का अनुरोध करूंगा कि इस प्रस्ताव को जिस स्प्रिट से, जिस भावना से प्रेरित होकर मैंने

रखा है वह इस प्रस्ताव को स्वीकार करेगी और स्वीकार करने के बाद जो कुछ कार्रवाई होगी वह करेगी। अलावा इसके मैंने बजट में भी देखा कि जितना रुपया इस शिक्षा के लिये रखना चाहिये था वह नहीं रखा गया। तो इससे यह साबित होता है कि सरकार की जो स्कीम होती है उसके लिये अक्सर लोगों के हृदय में यह भावना पैदा होती है कि सरकार की कोई स्कीम आखीर तक तो जाती नहीं है वह बीच में ही खत्म हो जाती है। सरकार किसी स्कीम के बारे में सीरियस तो होती नहीं है इसी वजह से उसको सफलता भी नहीं मिलती। यह स्कीम सन् ४८ ई० में उठाई गई थी मगर सरकार ने उसकी ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया इसी कारण उसको उसमें काफी सफलता भी नहीं मिली। इसलिए मैं यह जरूरी समझता हूं कि राष्ट्र के कल्याण के लिए देश के प्रत्येक नवयुवक को सैनिक शिक्षा दी जाय। हमारे जन समुदाय को इसका काफी अच्छी तरह से ज्ञान होना चाहिये ताकि जरूरत पड़ने पर वह देश की सेवा कर सके। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव को उपस्थित करता हूं।

* श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम (वित्त मंत्री)—जनाबवाला, अभी कुंवर साहब ने यह कहा कि सरकार की जो स्कीम होती है वह पूरी तो होती नहीं है, मुमकिन है कि ऐसा हो, लेकिन जमींदारी अबालिशन में तो ऐसा हुआ नहीं है, वह तो पूरी हो गई है और अमल में भी आ गई है। इस वक्त जो मसला इस सदन के सामने पेश है उसकी निम्नत इतनी बात तो सही है कि अगर ऐसा हो जाय तो देश के लिये बहुत ही मुफ़ीद होगा। हमारे सूबे के बहुत से स्कूलों और कालेजों में मिलिट्री एजुकेशन जारी है। उसके बारे में यह ख्याल जरूर हो सकता है कि वह कम्पलसरी एजुकेशन तो जरूर है, लेकिन सिर्फ एक माने में नहीं है। यह सबजेक्ट इन्तहान के लिये जरूरी नहीं है। वह पढ़ाया तो जरूर जाता है। इसके साथ साथ मैं यह भी अर्ज कर देना चाहता हूं कि अगर उसको कम्पलसरी कर दिया जाय तो उसके लिए रुपये की जरूरत है और गवर्नमेंट के पास इतना रुपया नहीं है।

फिर इस काम को करने के लिये प्राइरिटी दी जाय और जो प्राइरिटी दी जाय वह किस दर्जे की हो तो इस तरह से बहुत सी जरूरतें हमारे सामने हैं जिनको कि हमको देखना चाहिये और यहां के रहने वालों के आराम की और आसाइज की बहुत सी जरूरतें हैं और उनकी तकलीफों को दूर करने की भी बहुत सी जरूरतें हैं। जो कि पूरी करनी है तो इसके लिये स्कीम में तो हमारे सामने है। शायद कुंवर साहब की नीयत में पूरी हो या न हो, मगर हमारे नज़दीक हैं और उनके ऊपर रुपया खर्च करने के लिये भी स्कीम रखी गई है अगर इस पूरी तस्वीर के अन्दर हम इस चीज को देखते हैं और फिर उस के लिये प्रायोरिटी दें तो जो रिजोल्यूशन का मकसद है उसके माने तो मेरे नज़दीक यही निकलेंगे कि हायस्ट प्रायोरिटी इस काम को हो और जो रुपया हो तो सब से पहले इस काम के लिये वह रुपया रखा जाय। यह तो ऐसी बात है कि जिसको बहुत ही सीरियसली कन्सीडर करने की जरूरत है। मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि इस रिजोल्यूशन के सिलसिले में जवाब में यह कह दिया जाय कि यह बिल्कुल मुमकिन है और इसको कर दिया जायेगा या यह कह दें कि नहीं किया जायेगा तो यह तो मैं समझता हूं कि ठीक नहीं होगा। मेरे ख्याल में बेहतर तो यह होता कि जो चीज इस वक्त जारी है उसके ऊपर हम कटेन्ड रहते और उसमें अगर किसी किस्म की कमी है तो उस कमी को पूरा करने की कोशिश इस माने में करते कि अब से भी अच्छी हालत में वह ट्रेनिंग हो। इस आइडिया के साथ इस रिजोल्यूशन को शुरू करने के बजाय हम इसी तरीके से कुछ दिन इसको करते रहें तो

* मंत्री ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री परमात्मानन्द सिंह]

एक जगह जब भगवान राम के सामने रावण मुद्ध के मैदान में एक बड़े विशाल रथ पर बैठ कर अस्त्र-शस्त्र से सुसज्जित होकर आया और रामचन्द्र जी के पैर में जूते भी न थे तो विभीषण घबड़ा गया :

रावण रथी विरथ रघुवीरा । देखि विभीषण भयज अधीरा ॥

अधिक प्रीति भा उर सन्देहा । बन्दि वचन कह सहित सनेहा ॥

नहि हय गज रथ नहि पद आना । कहि पिथि जितव रिपू बलवाना ॥

उसको सुनकर भगवान राम ने कहा कि इस प्रकार के रथ से जीत नहीं होती उन्होंने यह बतलाया कि जिससे जीत होती है वह रथ दूसरा होता है और उस रथ का रामचन्द्र जी ने वहाँ पर वर्णन किया है । सब सदस्य जानते हैं । मैं उसको अधिक कह कर समय नष्ट नहीं करना चाहता ।

औरज धीरज जेहि रथ चाका । सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका ॥

दम, विवेश, बल परहित घोरे । क्षमा, दया, समता रजु जोरे ॥ इत्यादि

तो भगवान राम ने उस समय बताया कि हमारे अन्दर सचाई होनी चाहिए, परोपकार की भावना होनी चाहिए, गरीबों की रक्षा की भावना होनी चाहिए । अगर ऐसे अस्त्र हमारे पास हैं तो हमारी जीत होती है और आज हम लोग इस आदर्श को लेकर दुनिया के सामने चल रहे हैं । जहाँ कहीं लड़ाई होती है वहाँ हम दुनिया की जो सबसे बड़ी संस्था यू० एन० ओ० हैं उसके जरिए से तय करने की कोशिश करते हैं कि लड़ाई के द्वारा । मैं नहीं कह सकता कि अब तक पूरी कामयाबी हुई है या नहीं, कुछ हिस्सों में तो कामयाबी हुआ है, और मैं उम्मीद करूँगा कि कुछ दिन बाद पूरी तरह से कामयाबी होगी और थोड़े दिन बाद दुनिया इस बात को समझगी कि यह तरीका ज्यादा अच्छा है बनिस्बत हथियार से सुसज्जित होकर लड़ने से । जब यह तरीका चल रहा है उस हालत में हम अपने सभी नौजवानों को फौजी शिक्षा देकर सभी को मिलिट्री माइन्ड बना दें मेरा यह निश्चित मत है कि संसार को इससे हानि पहुंचेगी, लाभ नहीं होगा । मैं यह भी उसी के साथ साथ महसूस करता हूँ जैसा कि माननीय मंत्री जी ने भी इशारा किया कि वर्तमान स्थिति में और कभी भी फौजीपन को एकदम मिटा नहीं सकते इसकी आवश्यकता भी एक हद तक है—परन्तु प्रधानता नहीं । प्राकृतिक रूप से लोगों के सम्मान और झुकाव अलग-अलग होते हैं—कुछ लोग जो प्राकृतिक रूप से फौजी मिजाज के होते हैं उनको यदि निकास का अवसर न मिले तो भी सरकार की कमजोरी है इसलिये मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट की तरफ से जो शिक्षा इस तरह की दी जा रही है वह बजाय अनिवार्य करने के वैकल्पिक कर दी जाये । यह आशानल सब्जेक्ट होता जिससे जिन लोगों की जन्म से प्रवृत्ति हो उनको एक रास्ता मिल जाये कि वह इस तरह की शिक्षा प्राप्त कर सकें । इसलिये मैं सरकार को सुझाव दूँगा कि बजाय इसके कि मिलिट्री ट्रेनिंग को कम्पलसरी रखें वह इसको आशानल करें और आशानल करके खास-खास बड़े बड़े इन्स्टीट्यूशन्स में इस बात की गुंजाइश कर दें कि जो जन्म से मिलिट्री माइन्ड हैं वह इस शिक्षा को प्राप्त कर सकें ।

मैं इस रिजोल्यूशन का, जो सब लड़कों को कम्पलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग देने के लिये पेश किया गया है, विरोध करता हूँ ।

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद (स्नातक निर्वाचन क्षेत्र)—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का भाषण सुनने के बाद मैं समझता हूँ कि इस विषय पर बहुत कुछ कहने की अब आवश्यकता नहीं है । आपने अपने भाषण में सैनिक शिक्षा के महत्व को स्वीकार किया और यह भी बतलाया कि सरकार ने इसके लिए प्रयत्न किया है

और जब आवश्यकता ऐसी समझी जायगी तब सरकार और भी विचार करने की चेष्टा करेगी। साथ ही आपने यह भी बतलाया कि यदि हम सैनिक शिक्षा अनिवार्य करते हैं तो इसमें खर्च बहुत पड़ेगा। आपने आंकड़े भी उपस्थित किये जिससे प्रतीत होता है कि १४ लाख और २२ लाख रुपया खर्च होगा जो शासक सरकार इस समय बरदाश्त करने के लिये तैयार नहीं है। प्रश्न यह है कि इस प्रकार की शिक्षा अनिवार्य होती चाहिये या नहीं। कुंवर गुरुनारायण साहब ने इसको स्पष्ट नहीं किया कि सैनिक शिक्षा से उनका क्या अभिप्राय है। क्या वह चाहते हैं कि मिलिट्री ट्रेनिंग लड़कों के लिये अनिवार्य हो जाय या वह चाहते हैं कि मिलिट्री साइंस के लिये एक अलग विषय हो जाये।

उन्होंने इसको साफ नहीं किया। क्या वे चाहते हैं कि सैनिक शिक्षा हर एक बालक को दी जाय या वे चाहते हैं कि मिलिट्री साइंस प्रत्येक विद्यार्थी के लिये अनिवार्य कर दिया जाय। यदि उनका अभिप्राय सैनिक शिक्षा से है तो सैनिक शिक्षा इंटरमीडियेट में अनिवार्य नहीं है। शारीरिक शिक्षा प्रत्येक विद्यार्थी के लिये अनिवार्य है।

श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम—इस प्रस्ताव के माने सबके लिये हो।

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद—शारीरिक शिक्षा हर एक स्कूल और कालेज में प्रत्येक बालक के लिये अनिवार्य है। प्रांतीय रक्षा दल सरकार ने बनाया था। उसके कुछ लोग कालेजों में गये और उन्होंने काम किये परन्तु विद्यार्थियों में कोई उत्साह नहीं दिखाई पड़ा। उसका अनुमान आप बजट को देखकर कर सकते हैं। हमारी यूनिवर्सिटी में मिलिट्री साइंस का डिपार्टमेंट बनाया गया और सरकार ने बड़ी कृपा करके उसमें तीन अध्यापक नियुक्त किये। एक रीडर है जिसकी तनख्वाह ५०० रुपया से ८०० रुपया तक है। दो लेक्चरर हैं। उस डिपार्टमेंट में ३०० विद्यार्थी हैं। सुना है कि गवर्नमेंट आफ इंडिया ने एक कमेटी नियुक्त की और उसके अफसरों ने यह सम्मति प्रकट की कि यह शिक्षा बिल्कुल बेकार है। यह प्रश्न बराबर हमारी कार्यकारिणी में आया। डा० हृदयनाथ कुंजरू ने फाइनल कमेटी में और इक्जीक्यूटिव कमेटी में कई बार कहा कि सैनिक डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटियों में बन्द कर देना चाहिये। इस प्रकार की शिक्षा से कोई विशेष लाभ नहीं है। ग्रांट्स कमेटी ने भी ऐसी ही सम्मति प्रकट की थी। सेना के अफसरों ने भी कहा है कि यह बिल्कुल बेकार है। इससे आर्मी को कोई फायदा नहीं हो सकता है। इस समय यूनिवर्सिटियों में यू० टी० सी० है। उसमें थोड़े लड़के जाते हैं, सैनिक शिक्षा जैसा कि मेरे मित्र श्री परमात्मनन्ध सिंह जी ने कहा है कि जिन बालकों की प्रवृत्ति सैनिक शिक्षा की ओर हो उनको देनी चाहिये। बहुत से बालक सैनिक शिक्षा के योग्य हैं। उनका समय नष्ट कराके बेकार खर्च करके जनता का रुपया नष्ट न कराना चाहिये। दूसरी बात जो कुंवर साहब ने कही कि हमारी आजादी की रक्षा के लिये इसकी बड़ी जरूरत है। मैं समझता हूँ कि आजादी के लिये कोई खतरा नहीं है। बाहरी आक्रमण हमारे देश पर नहीं हो सकता। अगर ऐसा आक्रमण होगा तो उसके लिये हमारी भारतीय सेना सदैव तैयार रहेगी। परन्तु इस समय कोई ऐसा भय प्रतीत नहीं होता है। आन्तरिक उपद्रवों से देश की रक्षा करने के लिये हमारी सरकार काफी मजबूत है। स्कूलों और कालिजों की शिक्षा उपयोगी है परन्तु उससे आपत्ति के समय कहां तक रक्षा हो सकेगी। यह विवादास्पद है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि कुंवर साहब के उद्देश्य की पूर्ति इस प्रस्ताव द्वारा न होगी।

एक बात कुंवर साहब ने कही और वह यह कि सेक्रेटरी एजुकेशन का प्रश्न अर्थात् माध्यमिक शिक्षा का प्रश्न इस समय सरकार के सामने विचार के लिये है। गवर्नमेंट आफ इंडिया ने अभी हाल ही में एक कमेटी नियुक्त की है जो विचार करेगी कि हमारी माध्यमिक शिक्षा में क्या सुधार होना चाहिये। किन्तु किन्तु विषयों को पढ़ाना चाहिये और किस-किस तरह से पढ़ाना चाहिये।

[डाक्टर ईश्वरी प्रसाद]

इस संबंध में हमारी सरकार ने भी एक कमेटी नियुक्त की है जिसके अध्यक्ष आचार्य नरेन्द्र देव जी हैं, और लोग भी हैं जो इस बात पर विचार कर रहे हैं कि किन किन विषयों को माध्यमिक शिक्षा में रखना चाहिये। इसलिये मैं समझता हूँ इस सदन के लिये यह असामयिक होगा कि इस पहलू पर विचार किया जाय, जब इस विषय पर बड़ी बड़ी कमेटियाँ विचार कर रही हैं। इसलिये मैं चाहता हूँ कि जब तक इन कमेटियों की रिपोर्ट हमारे सामने न आ जाय, तब तक हम इसके ऊपर विचार न करें। क्योंकि फिर हमें यह मालूम हो जायेगा कि इन कमेटियों में जो अनुभवी सदस्य हैं उनकी राय क्या है। श्री परमात्मा नन्द सिंह जी ने कहा कि हिन्सात्मक प्रवृत्ति ऐसी शिक्षा से बढ़ेगी। बालकों को व्यायाम की शिक्षा देना एक चीज है सैनिक शिक्षा देना एक दूसरी चीज है। बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जिनकी सैनिक शिक्षा में रुचि नहीं होती। कुंवर साहब का जन्म क्षत्री कुल में हुआ है। मेरा जन्म एक ब्राह्मण कुल में हुआ है। पहले ब्राह्मणों का पढ़ाने लिखाने का काम था। जो ब्राह्मण रुपया लेकर पढ़ाता था उसका जाति से बहिष्कार कर दिया जाता था, लेकिन अब तो हम लोग रुपया लेकर पढ़ाते हैं। इतना पतन हो गया है। क्षत्रियों का भी पतन हो गया है। इस पतन पर इस सदन में विचार करना मैं निरर्थक समझता हूँ। परन्तु यह निश्चय है कि सैनिक शिक्षा को अनिवार्य करने में बड़ी कठिनाई उपस्थित होगी। इससे लाभ नहीं होगा। कुंवर साहब अभी थोड़े दिन तक इन्तजार करें, देखें कि ये कमेटियाँ शिक्षा में क्या सुधार करती हैं। कुंवर साहब जानते हैं कि इस समय संसार में जो दृष्टिकोण है वह शांति का है। यू० एन० ओ० और अनेक संस्थाएँ ऐसी बनाई गई हैं जो युद्ध लिप्सा को समाप्त करने का काम कर रही हैं। युद्ध लिप्सा दूर करने के यह माने नहीं कि हमारा राष्ट्र सैनिक दृष्टि से बिल्कुल नष्ट हो जाय। इसका प्रबन्ध भारत सरकार पूर्ण रूप से कर रही है और आगे करेगी। इसलिये आज का प्रस्ताव थोड़ा सा असामयिक प्रतीत होता है। यदि उन कमेटियों के सुझाव में किसी प्रकार की त्रुटि होगी, तब हम फिर इस विषय पर विचार करेंगे।

श्री राजाराम शास्त्री—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्री गुरु नारायणजी ने जो प्रस्ताव इस सदन के सामने उपस्थित किया है उससे एक बहुत महत्वपूर्ण विषय की ओर इस सदन का ध्यान आकर्षित हो रहा है। इस प्रस्ताव के विषय में अभी तक जो भाषण दिये गये हैं मैं समझता हूँ सदन उन पर भी काफी गम्भीरतापूर्वक विचार करे। इस प्रस्ताव के सिलसिले में कहा गया कि बाहरी या अन्दरूनी किसी प्रकार का आक्रमण होता है तो उससे रक्षा करने का प्रबन्ध अभी से करना चाहिये। और उसके लिये यह सुझाव दिया गया है कि इन्टरमीडियेट कक्षाओं में सैनिक शिक्षा अनिवार्य कर दी जाय। इसमें कोई शक नहीं कि आज जिस स्थिति से हमारा देश गुजर रहा है, जैसी संसार की हालत है, वह बहुत ही विकट स्थिति है। दुनिया का प्रत्येक बड़ा राष्ट्र विश्वशांति के नाम पर युद्ध की तैयारियाँ कर रहा है। सभी बड़े राष्ट्रों को आज हम देख रहे हैं कि युद्ध की तैयारी में लगे हुये हैं। एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं और यही घोषणा की जा रही है कि हम दुनिया में शांति स्थापित करना चाहते हैं। लेकिन मेरा यह विश्वास है और जैसा मैंने पहले भी एक बार कहा था कि जब तक दुनिया में यह तरीका रहेगा कि बड़े बड़े राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों का शोषण करते रहेंगे, जब तक प्रत्येक राष्ट्र के अन्दर कुछ वर्ग दूसरे वर्गों का शोषण करते रहेंगे तब तक अशांति की संभावना बनी रहेगी। चाहे जितने ही शांति सम्मेलन क्यों न किये जायें लेकिन दुनिया में युद्धों का अन्त न हुआ है और न होगा जब तक कि मूलभूत कारणों पर विचार न किया जायगा कि आज दुनिया की जनता की प्रवृत्ति इस ओर क्यों हो रही है। हमारे राष्ट्र ने एलान कर दिया है कि अगर कहीं लड़ाई होती है, चाहे पड़ोसी राष्ट्रों में हो या दूर के राष्ट्रों में हो, तो हम उसमें शामिल न होंगे लेकिन मैं इस बात को साफ कह देना चाहता हूँ कि हमारी नीति यह सही है कि हम किसी युद्ध में शामिल न होंगे लेकिन उसका मतलब यह कभी न लगा लेना चाहिये कि दुनिया में जितने राष्ट्र हैं वह तो बराबर हथियारबन्द होते-उपय और हम इस भरोसे बैठे रहें कि हमें लड़ना नहीं है तो कोई हमसे भी न लड़ेगा, तो यह सरासर

एक धोखा है। आजकल के राष्ट्र ऐसे हैं कि वह चाहे कितने ही ऊंचे विचारों का प्रतिपादन क्यों न करें लेकिन जब उनके स्वार्थों की पूर्ति का सवाल होता है तो वह युद्ध करने से जब न आवेंगे। हमने पिछले महायुद्ध में और उसके बाद के युद्ध में जो देखा है उससे हमको कतई इस धोखे में न पड़ना चाहिये कि दुनिया में लड़ाई न आयेंगी और आयेंगी तो हम शामिल न होंगे और हम बच जायेंगे तो मैं इस बात को मानने के लिये तैयार नहीं हूँ। अभी डाक्टर साहब ने कहा कि दुनिया का शांतिमय वातावरण है। उनका शायद यह ख्याल है कि चूँकि बड़े बड़े राष्ट्र यह एलान कर रहे हैं कि लड़ाई न होनी चाहिये इसीलिये डाक्टर साहब पर भी उसका प्रभाव पड़ा कि दुनिया का शांतिमय वातावरण है लेकिन मैं पूछता हूँ कि क्या कोरिया, मलाया और ट्यूनीशिया का शांतिमय वातावरण है। हमारा यह विश्वास है कि आज दुनिया का वातावरण शांतिमय नहीं कहा जा सकता और छोटे छोटे राष्ट्रों की जान आजकल खतरे में पड़ी हुई है। मैं यह नहीं कहता कि हमारे राष्ट्र पर हमला होने वाला है लेकिन मैं यह विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि हमें यह न सोचना चाहिये कि ऐसा न होगा। इसी तरह से आंतरिक वातावरण का सवाल हमारे सामने आता है। हमारा विश्वास है कि मौजूदा समाज की जब तक हमारे देश में यही दशा रहेगी कि अधिकांश जनता गरीबी के दिन व्यतीत करती रहे और कुछ आदमी सुख का जीवन व्यतीत करते रहे तब तक हम चाहे कितने ही उपदेश क्यों न दें लेकिन हमारा अन्दरूनी वातावरण शांतिमय नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में हमें और आपको विचार करना है कि आखिर हम क्या करें। अभी डाक्टर साहब ने यह भी कहा था कि हमारे देश के अन्दर अभी कोई खतरा नहीं है। और अगर कोई होता भी है तो सरकार अपने आपको इतना मजबूत समझती है कि वह उसको दबा सकती है। मैं विनम्रता पूर्वक यह कहूँगा जैसा कि सदन में कई बार यह बात हुई कि आज हमको भलेही यह मालूम होता है कि देश में बिल्कुल शांतिमय वातावरण है लेकिन आप देखिये कि सूबे में कैसी कैसी डकैतियाँ पड़ रही हैं। डाकुओं के कितने बड़े बड़े दल हैं और उनमें कितने अधिक लोग शामिल हैं, कई कई जिलों में उनके गिरोह काम कर रहे हैं। देहातों में चोरियाँ और डकैतियाँ बढ़ती चली जा रही हैं कितने ही स्थान ऐसे हैं जो कि सुरक्षित नहीं हैं। वहाँ की जनता अपने आपको सुरक्षित नहीं समझती है। भले नागरिकों का जीवन आज गुंडों के हाथ में है। ऐसी स्थिति में अगर हम यह कहें कि हमारा देश अशांति की तरफ बढ़ रहा है तो वह बिल्कुल स्पष्ट है। अगर ऐसा वातावरण है तो उसका मुकाबिला कैसे किया जाये। जैसा कुंवर गुरुनारायण जी ने कहा कि उनका ख्याल है कि अगर अनिवार्य सैनिक शिक्षा दी जाये तो हम बाहरी और आंतरिक हमले का मुकाबिला कर सकते हैं। मेरा विश्वास है कि किसी भी राष्ट्र की सरकार चाहे वह कितनी ही हथियार क्यों न रखती हो और उसकी सैनिक स्थिति चाहे कितनी मजबूत क्यों न हो लेकिन किसी भी राष्ट्र की अगर हिफाजत होती है तो उसकी रक्षा इस बात पर मुनहसिर है कि वहाँ की सैनिक बल तो मजबूत हो ही लेकिन इस बात की भी आवश्यकता होती है कि वहाँ की जनता अपने वाले आक्रमण का मुकाबिला करने के लिये तैयार होती है। अगर जनता के अन्दर यह शक्ति नहीं है तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि कोई भी सरकार अपने देश की रक्षा करने में असमर्थ होती है। पिछला दूसरा महायुद्ध हमारे सामने हुआ। हमने देखा कि फ्रांसिस्ट सेनाएँ एक के बाद दूसरे मुल्क पर कब्जा करती चली गईं। फ्रांस, बेल्जियम, हालैंड इत्यादि राष्ट्रों की धनिक जनता ने हिटलर के आगे सर झुका दिये। लेकिन जब रूस पर आक्रमण होता है तो वहाँ की सरकार में और जनता में इतना निकट संबंध था कि उन्होंने हिटलर की सेनाओं को बाध्य कर दिया कि उनको पीछे हटना पड़ा। तो हमारा यह विश्वास है कि जहाँपर यह आशा है कि जनता को अनिवार्य सैनिक शिक्षा दी जाये वहाँ पर हमारा यह विश्वास है कि जनता में आन्तरिक और बाहरी आक्रमण के मुकाबिला करने की भावना जनता में पैदा की जाये। तब चाहे जिस प्रकार का आक्रमण हो हम उसका मुकाबिला कर सकते हैं। लेकिन मुझे अफसोस के साथ यह कहना पड़ता है कि अगर आज हमारे मुहल्ले में आक्रमण होता है और हम डरपोक होकर बैठ जाते हैं और हमारे ऊपर जुल्म होता है तो हम सहन कर लेते हैं तो अगर हमारे ऊपर

[श्री राजा राम शास्त्री]

देश में किसी प्रकार का हमला हो जाता है तो उसके सामने झुक जायेंगे। तो जब यह कहा जाता है कि सैनिक शिक्षा दी जाये तो एक माननीय सदस्य ने कहा कि अगर हमने सैनिक शिक्षा दी तो हिंसात्मक वातावरण पैदा हो जायेगा। नवयुवकों में वायलेंस की स्पिरिट पैदा हो जायेगी। अगर यह कहा जाये कि सैनिक शिक्षा दी जायेगी तो हिंसा की प्रवृत्ति पैदा होगी तो बस ही यह भी कहा जा सकता है कि अगर सैनिक शिक्षा न दी गई तो देश में बुझदिली पैदा होगी। मेरा ख्याल यह है कि सैनिक शिक्षा कोई बुरी चीज नहीं है। अगर सैनिक शिक्षा से दूसरे की लूटने की भावना पैदा होती है तो वह बुरी चीज है। लेकिन अगर हम सैनिक शिक्षा प्राप्त करके अपने देश की रक्षा के लिये तैयार होते हैं और देश का बच्चा बच्चा कुर्बान होने के लिये तैयार है कि हम आजाद रहें तो हम उसको बुरी चीज नहीं मानते।

हां, मैं यह जरूर मानता हूं कि आज यह चीज करीब करीब सत्य है कि सारा संसार शस्त्रीकरण कर रहा है। हमारा आजतक का यह अनुभव है कि सचमुच दुनिया जितना शस्त्रीकरण होती चली जा रही है जनता को उतना शिक्षित करना मुश्किल है। हमारा विश्वास हो गया है कि दुनिया की समस्याओं का समाधान हथियारों से नहीं हो सकता है। महात्मा गांधी ने जिस युग में जन्म लिया है जिस की ओर हमारा ध्यान आकषित करते हैं उन का मुकाबिला हम अहिंसात्मक जरिये से कर सकते हैं। यही ठीक नीति और आदर्श है। हमारी स्वतंत्रता का युद्ध इसी तरह से चलता रहा है। आज हमारी हुकूमत महात्मा जी के आदेशों को लेकर चलना चाहती है और हम उनकी आदेशों की पूजा करते हैं। लेकिन जित वातावरण की दुनिया में हम रहते हैं उसकी कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता है। जितने मतलब इस वक्त संसार के सामने हैं वे सब शांतिमय तरीके से किये जायें इस तरह का हमारा देश संदेश देता है लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा कि हम संदेश जरूर देते हैं लेकिन इसके माने यह नहीं है कि हम संसार के सामने कमजोर रहना चाहते हैं। हम तो साफ चाहते हैं कि हम किसी से लड़ाई नहीं चाहते इस बात पर जरा ठंडे दिल से विचार करें कि आज हम अपने यहां के नौजवानों को सैनिक शिक्षा देने का फैसला कर सकते हैं या नहीं। जब हमारे राष्ट्र में नौजवानों को इस तरह की शिक्षा दी जायेगी तो वे आक्रमण के समय देश की रक्षा कर सकते हैं। यह भी कहा गया है कि समय पड़ने पर प्रत्येक नौजवान को हथियार उठाना संभव हो सके। यदि नौजवानों की सैनिक शिक्षा नहीं दी जाती है और दुर्भाग्य से हमारे देश पर आक्रमण होता है तो हमारे देश के सैनिक हैं वह तो केवल फ्रंटलाइन में ही मुकाबिला कर सकते हैं अन्दर नहीं कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ हमारा एलान है कि यदि हमारे ऊपर कोई मुसीबत आती है तो उस वक्त उसका मुकाबिला करने के लिये हम तैयार रहेंगे यही हमारी नीति है। हम और आप इस समय जो नौजवान सैनिक शिक्षा प्राप्त होंगे यदि वे सहायता दें तो उनकी फ्रंट लाइन में भी यह भावना रहेगी कि हमारे पीछे और है जो कि मुकाबिला कर सकते हैं इसलिये मेरा ख्याल है कि जहाँ लोगों के दिलों में इस प्रकार की भावना को पैदा करने का सवाल है कि अगर हमारे राष्ट्र पर संकट पड़ेगा तो उस वक्त राष्ट्र की रक्षा करने का उत्तरदायित्व केवल हुकूमत पर ही नहीं रहेगा बल्कि जनता पर भी रहेगा। उस वक्त हथियार उठाने की आवश्यकता पड़ेगी और हम इसको उठाने में बाज नहीं आयेंगे। श्री गृहनारायण जी का जो अभिप्राय था वह मैं समझता कि अगर कोई होनहार बात हुई और हमारे देश पर आक्रमण हो गया, तब उस समय हमारी हुकूमत एलान करती है कि देश के ऊपर संकट है प्रत्येक नौजवान को मुकाबिला करना चाहिये तो जो लोग अभी तक क्वायद करना भी नहीं जानते हैं तो इस मौके पर बन्दूक एक ल ठी की तरह उनके साथ हाथ में रह जायेगी। अगर हमारे देश का प्रत्येक नवयुवक जानता है कि रिवाल्वर कैसे चलाया जाता है, बन्दूक कैसे चलाई जाती है तो यह बात हो सकती है कि देश में संकट आने पर वह मुकाबिला कर सकता है।

एक सवाल यहाँ पर उपस्थित किया गया लेकिन मैं यह नहीं समझता हूँ कि यह प्रस्ताव जो पेश किया गया है वह केवल मिलिट्री एजुकेशन देने के लिये ही उपस्थित किया गया है या उन

को हथियार भी चलाना सिखाया जायेगा। मेरे स्थाल में यह दोनों चीजें अलग अलग नहीं हो सकती हैं। अगर आप को हथियार चलाना नहीं आता है तो मिलिट्री शिक्षा बेकार है। इसलिये मैं यह जरूरी समझता हूँ कि कोरी मिलिट्री शिक्षा का ज्ञान होना तो बेकार है जब तक उसको हथियार चलाना नहीं आता है। मिलिट्री शिक्षा के साथ ही साथ थोड़ा सा हथियार चलाने का भी ज्ञान होना चाहिये। हम को राज्य के नवयुवकों को इस आदेश से ट्रेन्ड करना है कि राष्ट्र के संकट के समय वह देश के काम आ सकें और राष्ट्र की रक्षा कर सकें। अभी फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने एक विचित्र बात कही कि हम इस शिक्षा को तो शुरू कर देंगे लेकिन उसके लिये हम को रुपये की जरूरत है, तो उस के लिये हम जो टैक्स लगाने का प्रस्ताव लाते हैं मंजूर कर लीजिये। यहां पर फिर एक मतभेद आ जाता है। हम लोग चाहते हैं कि देश की उन्नति हो। देश के सुधार के लिये रुपये की जरूरत है, लेकिन उसके लिये यह जरूरी नहीं है कि वह रुपया टैक्स ही लगा कर आये। हमारे देश में ऐसी बहुत सी दौलत पड़ी हुई है जिसका सदुपयोग नहीं होता है बल्कि दुरुपयोग होता है। ऐसी दौलत सरकार को अपने हाथ में ले लेना चाहिये और राष्ट्र के निर्माण में लगा देना चाहिये। इस का बोझ निर्धन लोगों पर नहीं डालना चाहिये। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि कुंवर साहब ने जो प्रस्ताव पेश किया है कि देश में सैनिक शिक्षा दी जाय, अगर इसमें खर्च की आवश्यकता पड़ती है तो मैं आप को विश्वास दिलाता हूँ कि आप को देश की ऐसी तन्नाम दौलत जिस का उपयोग ठीक से नहीं होता है और व्यक्तिगत लोग उससे फायदा उठाते हैं, ऐसी दौलत को सरकार को अपने हाथ में लेना चाहिये। मैं चाहता हूँ कि जिस उद्देश्य से प्रस्ताव पेश किया गया है उसकी ओर ध्यान देना चाहिये।

श्री एम० जे० मुकर्जी—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो प्रस्ताव इस समय सदन के सामने पेश है कि देश की रक्षा के लिये सैनिक शिक्षा दी जाय लेकिन जिस वक्त लड़ाई शुरू होगी, उस वक्त हम इसका फैसला हाउस में न कर सकेंगे यह काम तो सेलूल गवर्नमेंट का है। वक्त जरूरत पर लड़ाई का इन्तजाम करने के लिये फास्टीट्रिशन के अन्दर शेड्यूल ७ और सेक्शन २४६ में साफ दिया हुआ है। लेकिन उसकी तैयारी में हम अपने नौजवानों को तैयार रखें, यह जरूरी है कि हम उसमें सोचें कि कहां तक हम अपने नौजवानों को अपने मुल्क की बेहतरी के लिये तैयार करेंगे। एक सवाल उसका यह है कि हमारे नौजवानों की तालीम का मसला हमारे सामने है और उसको इस तरह से रखा जाय कि जिसमें मुल्क की सब से ज्यादा बेहतरी हो। अगर हम सोचते हैं कि मुल्क की बेहतरी सिर्फ इसमें है कि हम उनको सैनिक शिक्षा दें और इस तरह से अपने नवजवानों को तैयार करें कि वह सिर्फ मुल्क की रक्षा कर सकें और दूसरा सवाल यह है कि हम अपने नौजवानों को ऐसी तालीम से तैयार करें कि न सिर्फ वह सैनिक शिक्षा को ही सीखें बल्कि हर विषय में अपने देश की रक्षा करने के लिये तैयार हों। मेरा मतलब यह है कि इस वक्त मैं सिर्फ दो शब्दों पर ही गौर करूंगा। पहला यह है कि सैनिक शिक्षा कम्पलसरी हो और दूसरे यह कि मिलिट्री एजुकेशन हो। अगर एजुकेशन को मिलिट्री नाम दिया जाय तो न वह लड़कों को ज्यादा तैयार करेंगे और न वह उस तरह से अपने देश की सेवा ही कर सकते हैं। अपने मुल्क की सेवा करने के लिये उनको लिबरल एजुकेशन दी जाय, ताकि वह मुल्क की ऐसी सेवा कर सकेंगे जिसकी वजह से मुल्क की बेहतरी हो। आपको भालूम होगा कि बिलायत में भी ईटन और हैरो के ऊपर यह इल्जाम लगाया गया, जहां पर मैं समझता हूँ कि एजुकेशन की बड़ी ही अच्छी हालत है कि बिलायत की एजुकेशन ऐसी है कि वह बच्चों को एक ही ढंग में तैयार करते हैं। जैसे कि वहां बच्चों को क्लासिकल की एजुकेशन दी जाती है और इस तरह की ट्रेनिंग दे करके उनको सिखाया जाता है कि अगर वह क्लासिकल की दुश्वारियों को हल कर लेंगे तो वह देश की हर दुश्वारी को हल कर सकेंगे। अगर हम यह समझते हैं कि मिलिट्री एजुकेशन ऐसी है कि अगर इस कार्य को बच्चों को सिखाया जायेगा तो वह केवल सैनिक शिक्षा से ही सारे कार्य कर सकते हैं तब तो हम उनको लें, वरना हमें अहमियत इस बात को देनी पड़ेगी कि हमारे मुल्क की बेहतरी के लिये किस प्रकार की तालीम लड़कों को दी जानी चाहिये।

[श्री एम० जे० मुकर्जी]

में समझता हूँ कि जो चीज़ जबरिया कहीं पर भी रखी जाती है या कम्पलसरी की जाय तो वह कभी भी उसमें कामयाब नहीं हो सकते हैं। हमारे देश के नेताओं ने भी यह कहा कि:

we went out our youth to have wider outlook and daper insight in to the problems of the country. Will the military training widhen the outlook of our youth. I take it from the educational point of view.

बच्चों को आज भी इस बात की जरूरत है कि उनको इस बात की तालीम दी जाय कि एक वक्त उसके सामने ऐसा आता है कि जिस वक्त उसको डिसीजन करना पड़ता है और जिन्दगी में भलाई और बुराई के डिसीजन की उसको जरूरत पड़ती है। अगर हम बच्चों को ऐसी तालीम नहीं देते हैं कि वक्त जरूरत पर फैसला किस किस का किया जाय तो बच्चों की तालीम कभी भी पूरी नहीं हो सकती है। इस तरह से मुल्क की बहुवूदी के लिये वह कभी भी तैयार नहीं हो सकते हैं। यहां पर यह भी जिक्र किया गया है मिलिट्री एजुकेशन से डिसिप्लिन ज्यादा आ जायगा मैं तो यह समझता हूँ कि डिसिप्लिन एक अन्दरूनी चीज़ है वह खुद बखुद पैदा होती है। अगर कोई हमारे ऊपर प्रेसर डाले और उससे हमको प्रेस करे तो उससे रिप्रेसन होने का अन्देश होता है और उसका नतीजा रिवेलियन होता है। चुनान्चे हमारे बच्चों में तालीम का जो असर होता है कि अगर उसको प्रेस किया जाता है तो छुटपन से ही रिप्रेसन करता चला जाता है और इस तरह से वह कभी भी हुक्म मानने के लिये तैयार नहीं होता। उसका एक खतरा है आप नहीं जानते कि "youth is volatile very inflammable and undependable, It will be very dangerous at times to give him arms" अगर कहीं उनके हाथ में बन्दूक दे दी जाय तो कहीं ऐसा न हो कि वक्त जरूरत पर वह हमारे ऊपर ही बन्दूक छोड़ दें।

हमारे मुल्क की अवस्था ऐसी हो रही है कि यहां के नौजवान ऐसे रास्ते पर चल रहे हैं कि उनका संभलना मुश्किल हो रहा है। फिर एक लपज और कहुंगा और इसके बाद मैं अपनी स्पीच को समाप्त करूंगा। यह है कि जो कुछ भी आप बच्चों की बहुवूदी के लिये सोचें और इस मुल्क की रक्षा का ख्याल करें तो इस बात की जरूरत है कि उनको तालीम चाहे थोड़ी ही दी जाय लेकिन वह अच्छी किसम की हो, तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है और मैं समझता हूँ कि सरकार जो तालीम दे रही है वह काफी है और उचित है। इसलिये इस वक्त इस रिजोल्यूशन की कोई खास जरूरत नहीं है और मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रस्तावक महोदय अपना रिजोल्यूशन वापस ले लें।

*श्री हयातुल्ला अंसारी (नामनिर्देशित)—माननीय डिप्टी चेयरमैन साहब, मैं आपको बधाई देता हूँ कि आज जिस वक्त यह प्रस्ताव पेश हुआ है और जो लोग इस पर बहस कर रहे हैं, वे ऐसे लोग नहीं हैं जिन्होंने कि मिलिट्री एजुकेशन कभी ली हो। अगर उन माननीय सदस्यों ने मिलिट्री एजुकेशन ली होती, तो शायद वे ऐसी बहस नहीं करते। ये चीजें जहाँ मौजूद होंगी वहाँ दूसरे ढंग से सब कायदे अख्तियार करने पड़ेंगे। क्योंकि वे अगर इस तरह की ट्रेनिंग पाते हैं तो उनको जैसी लड़ाई करनी पड़ती है, तो उनको वैसे फैसले भी करने पड़ते हैं। आज कहा जाता है कि लड़कों को मिलिट्री एजुकेशन देना है। अगर मिलिट्री एजुकेशन देने के लिये जैसे तरीके बतें जायें और जिन तरीकों को अख्तियार किया जाय तो उन सबका एक खास तरीका होना चाहिये। उनके दिमाग को, और खास करके उनकी किताबों को जिस तरह से स्टैण्डर्ड होना चाहिये अगर उस तरह नहीं होता है तो तब तक उनको मिलिट्री एजुकेशन नहीं दी जा सकती है। अगर मिलिट्री एजुकेशन देना होगा तो आपको उसके लिये टेक्स्ट बनाना पड़ेगा और दूसरे तरीके अपनाने पड़ेंगे और दूसरे तरह की किताबें उनके लिये होंगी, तभी मिलिट्री एजुकेशन दी जा सकेगी। तो इस तरीके से इसके लिये दो चीजें खास कर होनी चाहिये और तभी यह मुमकिन हो सकेगा कि हम उनके दिमाग में इस तरह

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

की चीज भर दें। हमको पहले वाले तरीके बदलने होंगे। अगर आपको मिलिट्री एजुकेशन देना है तो आपको नौजवानों के दिमाग को भी ठीक करना होगा जिससे कि वे उसके लिये तैयार हो जायें और आपको अपने दिमाग में भी इस बात को तय कर लेना होगा। लार्ड टेनिसन ने एक जगह कहा है "there is no reason why, But to do and die" तो फंसला करना अब उन नौजवानों का काम है। वे किसी काम के लिये भी एकदम फंसला कर सकते हैं। मिलिट्री एजुकेशन से हमारे बहुत से ऐसे नौजवान तैयार हो जायेंगे जो कि देखेंगे कि इस चीज की हमें जरूरत है और वे फौरन इसके फंसले पर पहुंच जायेंगे। अब इसके बाद एक चीज की हमें जरूरत है और वह यह कि इससे हर नौजवान को फिर इन्सान से हमदर्दी नहीं होनी चाहिये। इन्सान को हमदर्दी की जरूरत नहीं होगी क्योंकि वे फौजी लोग होंगे। आप इतनी फौज बनाकर क्या कीजियेगा। लड़ाई होगी तो फौजें काम में आयेंगी। अगर आज हमें इस तरह से बेकार २ लाख फौज की जरूरत नहीं है बल्कि हमें दो हजार ऐसे आदमी चाहिये जो कि काफी हो और जिनके पास हवाई जहाज और इस किस्म की दूसरी चीजें भी हों और वे हर वक्त तैयार हों। आप मिलिट्री एजुकेशन देकर ऐसी बात अपने नौजवानों में पैदा न कीजिये कि वे जिस तरह से चाहें उसका इस्तेमाल करें और सामला फिर कंट्रोल के बाहर हो जाय। इस तरीके से अगर फौज बनानी होगी, तो उनके अन्दर एक चीज, एक जजब पैदा करना होगा। एक नया अन्दाज और एक नयी निगाह पैदा करनी होगी। बल्कि मैं थोड़े अल्फाज में यह कहूंगा कि फौजी तालीम कहना ही गलत होगा। यह इन्सान की बदकिस्मती है कि अपने बचाव के लिये वह नाम लेता है मिलिट्री एजुकेशन का। मैं तो यह कहता हूँ कि दुनिया में अमन हो जाय तो फौज, बन्दूक और बम बगैर ही कोई जरूरत नहीं रहेगी और वह म्युजियम में ही रखने की चीज हो जायेगी। मैं यह नहीं कहता कि जो चल रहा है वह निकाल दी जाय, लेकिन उसकी सही जगह समझने की जरूरत है। बँरुनी और अन्दरुनी हालात देखने की है कि आया यह हालात क्यों है उसको अनालेसिस की जरूरत है और वह हालात कैसे दूर किये जा सकते हैं। मुझे एक किस्सा याद आता है मैं एक जगह गया था वहाँ पर एक पुल था तो वहाँ के एक आदमी ने मुझसे कहा कि आपको मालूम है कि यह पुल कैसे बना। मैंने कहा कि नहीं मालूम है। तो उसने बताया कि एक राजा था करीब १०० साल हो गये उसको डाकुओं का बड़ा डर था राजा ने वजीर को बुलाया और कहा कि एक किला ऐसा बनाओ कि डाकू हमला अगर करें तो हम लोग छिपकर अच्छी तरह से बैठ सकें। वजीर चला गया और ६ महीने के बाद वापस आया उसने कहा कि साहब किला तैयार हो गया आप देख लें। राजा साहब गये तो वजीर ने कहा कि साहब यह पुल आप की रक्षा करेगा और वह पुल वाकई वहाँ की जनता के लिये न्यामत साबित हुआ और उनकी ऐसी मजबूत फौज बन गई कि डाकुओं की हिम्मत ही नहीं रही कि वह हमला कर सकते। हकीकत में हमको सोसाइटी की तरफ देखना है और ऐसी सोसाइटी बनानी चाहिये कि अगर हमलावर हमला कर भी दे तो रूल न कर सके। मुझे इस बात का अफसोस है कि हमारे माननीय सदस्य ने महात्मा गांधी का नाम इतने भद्दे तरीके से लिया कि मैं कुछ कह नहीं सकता और मैं नहीं समझता कि उसको किस तरह से बयान किया जा सके। अगर जर्मन होता तो उसकी दूसरी थ्योरी होती यानी इसका मतलब यह है कि अंग्रेजों की मूर्खता थी कि वह छोड़कर चले गये। मैं तो कहूंगा कि उन्होंने नानवायलेंस की अहमियत को नहीं समझा। उन्होंने जो सबक दिया है वह भिट नहीं सकता है। यह हकीकत है कि वह एक ताकत है और आज का जमाना है कि लोगों का अकीदा एटम बम और दूसरी चीजों से उठ गया है, फौज से अकीदा उठ गया है। यह नई ताकत है। उस पर हमको भरोसा करना चाहिये और उसका इम्तिहान करना चाहिये उन्होंने समाज को बनाने का तरीका बताया है जिस पर कोई रूल नहीं कर सकता है। लोगों को मार सकते हैं और हुकूमत बना सकते हैं लेकिन रूल नहीं कर सकते हैं। मैं यकीन दिलाता हूँ कि बाहर दूसरे मुल्कों में हमारे मुल्क की बड़ी धाक है और बहुत रोब है। गांधी जी ने अपनी तहरीक चला कर के यह साबित कर दिया है कि अवाम की ताकत के सामने फौज कोई ताकत नहीं रखती है और मैं तो यह कहता हूँ जनता की ताकत ऐसी है कि उसको मजबूत बनाना चाहिये वही हमारी बेहतरीन फौज होगी।

[श्री ह्यातुल्ला अंसारी]

आज तालिबइल्मों की फौज को बनाने से यह अच्छा होगा कि हम रोटी का मसला हल करें। अगर हम रोटी और कपड़े का इन्तजाम कर दें तो हम देखेंगे कि कोई भी ताकत नहीं हो सकती है जो हम पर हमला कर सके। अगर हम मिलिट्री एजुकेशन में अकीदा रखते हैं तो हमको एटम बम बनाना चाहिये लेकिन एक चीज मैं और कहना चाहता हूँ वह यह है कि इस वक्त हमको कोई जरूरत नहीं है। आपस में टकराने का कोई अंदेशा नहीं है। इसलिये टक्कर लेने वाली जो बड़ी ताकतें हैं वह आपस में टकरायें। मुकाबिला इन्हीं दो ताकतों का है। इस मौके पर सबसे बेहतर पालिसी यही है कि किसी तरीके से उनकी फौज में दाखिल न हों। खतरे का अंदेशा जरूर है इसके लिये हमें तैयारी जरूर रखना चाहिये इसलिये मैं यह हार्जिज न कहूंगा कि हमारी जो फौजें हैं उनको तोड़ दिया जाये, ये रहें, लेकिन एक तनामुन्न रखना है। न तो हमें यह करना है कि सारा देश वर्दी पहन कर इन्सानियत छोड़ कर फौजी बन जायें। दूसरी तरफ फौज की जरूरत भी है। जब कभी लड़ाई में मुकाबिला करने की जरूरत दरपेश होगी तो यहां की जनता मुकाबिला करेगी। जब रूस पर जर्मनी ने हमला किया था तो वहां की जनता ने जर्मनी का मुकाबिला किया था। एक एक चट्टान की हिफाजत के लिये हजारों आदमी मर गये, मगर लेलिंग्राड पर जर्मनी का कब्जा नहीं होने दिया। इसलिये मैं कहता हूँ कि खुदा के लिये फौज पर बहुत ज्यादा भरोसा न करें। लड़ता इन्सान का दिल है हाथ नहीं लड़ा करता।

डिप्टी चेयरमैन—सदन की बैठक दो बजकर १० मिनट तक के लिये स्थगित की जाती है।

(सदन की बैठक १ बजकर १० मिनट पर स्थगित हो गई और २ बजकर १० मिनट पर डिप्टी चेयरमैन के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

श्री प्रताप चन्द्र आजाद—माननीय उपाध्यक्ष महोदय कुंवर साहब ने जो प्रस्ताव रखा है कि सैनिक शिक्षा इन्टरमीडियेट क्लासेज में कम्पलसरी हो जाय जहां तक उनके प्रस्ताव का संबंध है मैं भी उससे कुछ इत्तिफाक रखता हूँ, किन्तु जो प्रस्ताव के शब्द हैं उन्होंने जो प्रस्ताव की रूपरेखा बनाई है और उसके आरम्भ में जो शब्द रक्खा है उसमें कुंवर साहब ने लिखा है कि “बाहरी या भीतरी आक्रमण और भय का मुकाबिला करने के लिये राष्ट्रीय संकट के समय में सशस्त्र सेना की सहायता करने के लिये इन्टरमीडियेट कक्षा के विद्यार्थियों के लिए मिलिट्री ट्रेनिंग एक आवश्यक विषय बना दिया जाय”। ये वह शब्द हैं जिनसे मैं पूरी तौर से इत्तिफाक नहीं करता हूँ इसलिये मैं यह समझता हूँ कि इस समय न हमारे राष्ट्र को और न हमारी स्टेट को कोई बाहरी या भीतरी संकट का खतरा है और हम अगर स्कूलों और कालेजों में सैनिक शिक्षा का भी प्रबन्ध करें तो उसमें छात्रों की मनोवृत्ति यह कह कर बदलना चाहते हैं कि हम राष्ट्र को खतरे से बचना चाहते हैं इसलिये हम चाहते हैं कि आप सेना में भर्ती हो जायें और सैनिक शिक्षा प्राप्त करें, तो यह ठीक नहीं होगा। कुंवर साहब ने यह माना है और उन्होंने कहा है कि हम छात्रों की मनोवृत्ति इसलिये बदलना चाहते हैं कि उनका नैतिक स्तर ऊंचा हो, उनके अन्दर जो इनडिस्प्लिन है उसको दूर करने के लिये यह आवश्यक है कि मिलिट्री शिक्षा इन्टरमीडियेट क्लासेज में इन्ट्रोड्यूस करें। जहां तक उनके नैतिक स्तर ऊंचा करने का संबंध है मैं यह मान सकता हूँ कि सैनिक शिक्षा आवश्यक है लेकिन फिर भी मेरा अपना विचार है कि कम्पलसरी शब्द रखना मनासिब नहीं है। इसलिये कि हम और आप जानते हैं कि इन्टरमीडियेट क्लासेज में जो विद्यार्थी पढ़ते हैं, उसमें बहुत से विद्यार्थी शारीरिक तौर से इतने दुबले होते हैं कि वे बन्दूक और राइफल उठा नहीं सकते हैं। साथ ही साथ जो विद्यार्थी इन शिक्षालयों में पढ़ते हैं उनमें से आजकल बहुत से विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि जिनकी उम्र १०, १२ या १५ वर्ष की होती है। इस उम्र के अन्दर वे इन्टरमीडियेट पास कर लेते हैं। दस बारह वर्ष के उम्र में उन्हें मिलिट्री शिक्षा दी जाय, यह उचित नहीं है। इसलिये उन विद्यार्थियों को मिलिट्री शिक्षा दी

जाय जो शरीर से कमजोर है या जो बड़े-बड़े हथियार उठा नहीं सकते हैं मैं समझता हूँ कि इससे जो कुंवर साहब का अभिप्राय है, जो कुंवर साहब का ध्येय है और जो कुंवर साहब के प्रस्ताव की मनोवृत्ति है वह भी खत्म हो जाती है। माननीय राजाराम जी ने एक बात कही है और वह यह कि हम पीस लीविंग हैं, हम शांतिमय वातावरण चाहते हैं इसलिये हम किसी को कम्पेल नहीं कर सकते हैं। शांति और पीस के नाम से यह कहना कि हम अपने विद्यार्थियों को सैनिक शिक्षा न दें यह ठीक नहीं है। मैं भी राजाराम जी की बात से इत्तिफाक नहीं करता हूँ उन्होंने अक्सर यह कहा कि हम यह चाहते हैं कि हमारे देश के जो नौजवान हैं और विद्यार्थी हैं वह मजबूत बनें। हम यह चाहते हैं कि हमारे देश के विद्यार्थी मजबूत बनें और संकट के समय हमारे राष्ट्र के काम आयें। लेकिन मैं उपाध्यक्ष महोदय आपके जरिये पूछना चाहता हूँ कि जो बुजदिल आदमी हैं जिनको सैनिक शिक्षा से रुचि नहीं है जिन्होंने कभी हथियार भी नहीं उठाया है क्या वह यह काम कर सकते हैं। इम्तिहान दिला कर सैनिक शिक्षा का डिप्लोमा उनको ज़रूर दिला लेंगे, लेकिन जैसा कि आपका ख्याल है, इमर्जेंसी के समय, संकट के समय क्या वह संकट का मुकाबला कर सकते हैं? अगर नहीं कर सकते तो जो मरुसद आपका इस प्रस्ताव के रखने से है, वह मरुसद इससे नहीं पूरा होगा। फिर हमारा मतलब मिलिट्री शिक्षा से यह भी नहीं होना चाहिये कि दस्तूर के तौर पर जैसे आजकल दूसरी चीजें चल रही हैं आर्ट, क्राफ्ट वगैरह सिखाने के लिये तो सिखा दिया जाता है मगर जब वह स्कूल से बाहर निकलते हैं तो कुछ नहीं कर पाते सिवाय इसके कि उनके पास आर्ट और क्राफ्ट का डिप्लोमा है और प्रैक्टिकल कुछ नहीं कर सकते। आप यदि मिलिट्री शिक्षा को भी ऐसा ही चाहते हैं जैसे आर्ट और क्राफ्ट आदि की चीजें दस्तूर के मुताबिक पास करके डिप्लोमा हासिल कर लेते हैं और काम कुछ नहीं कर सकते तो यह बिल्कुल बेकार चीज है। हमें देखना यह चीज है कि हम ऐसे विद्यार्थियों और नवयुवकों को छांटें जो इससे दिलचस्पी रखते हों और जो इस बात की जिम्मेदारी ले सकें कि मिलिट्री शिक्षा पाने के बाद राष्ट्र की सेवा कर सकेंगे और वौम के काम आ सकेंगे तब तो मिलिट्री शिक्षा का जो हमारा उद्देश्य है वह पूरा हो सकता है, अन्यथा नहीं। इसलिये अब हमें इस बात की कोशिश नहीं करना चाहिये कि मिलिट्री शिक्षा हाई स्कूल या इन्टरमीजिएट या डिग्री से कालेजेज में कम्पलसरी कर दी जाय बल्कि हमारा उद्देश्य यह होना चाहिये कि मिलिट्री शिक्षा हाई स्कूल इन्टरमीजिएट्स और डिग्री कालेजेज में भी हो, मगर जो नवयुवक और विद्यार्थी उस मिलिट्री शिक्षा को लेने के काबिल हैं, जो शारीरिक तौर पर योग्य हैं, उनको ही यह शिक्षा दी जाय और उनके ऊपर ही ज्यादा खर्चा खर्च हो।

जैसा कि हाफिज़ जी ने कहा कि फिर इस पर धन भी खर्च होगा तो लाजिमी है कि टैक्सेशन हो। इसलिये राष्ट्र का खर्चा उन कामों में खर्च होना चाहिये जिसकी उपयोगिता हो। जिससे हमारा राष्ट्र समृद्धिशाली बन सके, जिससे हमारे नौजवान उन्नति कर सकें, वह खुद बलवान होकर दूसरों को बलवान बनावें। मैं समझता हूँ कि कुंवर साहब का मकसद यह था कि मिलिट्री शिक्षा केवल उन नौजवानों को दी जाय जो नौजवान संकट के समय में मिलिट्री कार्य करने के साथ-साथ देश के नैतिक स्तर को भी ऊंचा कर सकें। मैं समझता हूँ कि उनका मतलब यह कभी न होगा कि मिलिट्री शिक्षा हर एक को दी जाय चाहे वह लड़ने के योग्य हो अथवा न हो। इसलिये मैं यह उचित समझता हूँ कि मिलिट्री शिक्षा इन्टरमीजिएट में ही लागू न हो बल्कि डिग्री कालेजेज में और हाई स्कूल में भी लागू हो और उन्हीं नौजवानों को दी जाय जो इस शिक्षा के लेने के योग्य हों।

श्री इन्द्र सिंह नयाल (स्थानीय संस्थाएँ निर्वाचन क्षेत्र)—आजकल का जो युद्ध है वह केवल बन्दूक या तोपों या अन्य हथियारों का नहीं कहा जा सकता बल्कि आजकल का युद्ध टोटल वार होता है, जिसमें एक मुल्क की पूरी ताकत अपने स्थान पर काम करते हुये

[श्री इन्द्रसिंह नयाल]

दूसरे मुल्क की पूरी शक्ति के साथ युद्ध करती है। आजकल हथियारों से ही युद्ध नहीं जीता जाता है बल्कि मुल्क की पूरी ताकत अपनी जगह पर पूरी तरह से प्रयत्न करती है और वह सब काम करती है जिसस लड़ाई में पूरी जीत मिल सके। इसलिये मैं कहता हूँ कि यह टोटल वार का जमाना है। इसमें यह प्रस्ताव रखना कि हमारे देश के लिये खतरा है और इसके लिये अत्यावश्यक है कि हमारे स्कूलों में मिलिट्री शिक्षा अनिवार्य हो, यह मैं समझता हूँ कि ऐसा प्रस्ताव है कि अगर यह समस्या होती भी तो भी यह प्रस्ताव ज्यादा अच्छा न समझा जाता। जो पहली बात प्रस्तावक महोदय ने अपने ख्याल से दूर कर दिया वह यह कि युद्ध हथियारों से ही नहीं जीता जाता बल्कि इसके लिये नेशनल कैरेक्टर को भी ऊंचा उठाना पड़ता है। महायुद्ध को अंग्रेजों ने नेशनल कैरेक्टर के बल पर जीता था। वहाँ के नागरिक बड़ी निर्भीकता से अपना कार्य करते रहे यद्यपि वहाँ पर बराबर गोलाबारी जारी थी, लेकिन वह अपने काम में जुटे रहे। तो वहाँ के अर्सेनिक बहादुरों के कंधे पर भी वहाँ की जीत का श्रेय है। इसी तरह रूस में भी हुआ। जर्मनी रूस के अन्दर तक पहुँच गया लेकिन वहाँ के नागरिकों ने यह ख्याल करके कि हमारा अन्न दुश्मनों के हाथ न पड़ जाय अपने अन्न और मकानों में खुद ही आग लगा दिया। इस तरह की नीति अगर वह न बरतते तो उनका जीतना कठिन हो जाता। दूसरी बात यह है कि वहाँ के लोगों को इस बात का सबसे बड़ा श्रेय है कि वहाँ इतना बड़ा हमला होने पर भी वहाँ के लोगों का विश्वास स्टालिन और बोल्शेविक शासन पर बना रहा। ऐसा नहीं कि जैसे कि बहुत से लोग कहते हैं कि इस वक्त बहुत तकलीफ है और कहते हैं कि कांग्रेस बहुत खराब है उस रिप्रेंट के प्रतिकूल एक विश्वास की रिप्रेंट (spirit) से। हिटलर ने सारा जुआ ही इस बात पर खेला था कि अगर मैं वहाँ पर हमला करूँगा तो वहाँ के लोग स्टालिन के शासन के खिलाफ हो जायेंगे और मैं आसानी से रूस जीत लूँगा। मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आजकल की लड़ाई जो है उसमें जनता की पूरी-पूरी शक्ति काम करती है और इस बात पर निर्भर है कि हर एक नागरिक का आचरण ऊँचा हो। उसकी त्याग की भावना ऊँची हो? कार्य करने की लगन ऊँची होनी चाहिये। अगर कार्य करने की शक्ति बहुत है तो साथ ही साथ उसका ज्ञान भी ऊँचा होना चाहिये। विज्ञान का ज्ञान मैं यह निवेदन कर रहा हूँ कि अगर हमारे सामने लड़ाई की समस्या आ जाये तो यह जरूरी नहीं है कि हम मिलिट्री की एजुकेशन कंपलसरी कर दें, पहली चीज तो हमें यह देखना चाहिये कि हमारे देश में फैक्टरियाँ काफी कायम हो गई या नहीं। प्रोडक्शन बढ़ गया है या नहीं। हमारा प्रोडक्शन बढ़ जायेगा तो हम उस प्रोडक्शन और फैक्टरियों को युद्ध के कार्य में लगा सकेंगे। हमारा नैतिक स्तर ऊँचा होना चाहिये। देश और सरकार के प्रति विश्वास होना चाहिये। महात्मा जो ने सत्याग्रह आन्दोलन के द्वारा यह कोशिश की कि हमारे देश का चरित्र ऊँचा उठे, त्याग व देशभक्ति की भावना पैदा की। यही चीजें आज हमारे देश को ऊँचा उठाये हुये हैं। हमारे नेता पंडित जवाहर लाल नेहरू जी के नेतृत्व में हमारे राष्ट्र का स्थान ऊँचा उठा हुआ है। यही चीज हमें युद्ध में सफल बना सकती है। इसमें सन्देह नहीं है। दूसरी चीज जो मैं निवेदन करना चाहता हूँ वह यह है कि जहाँ तक मैंने इसका इतिहास देखा है मैंने किसी भी देश में कभी भी स्कूल और कॉलेजों में मिलिट्री एजुकेशन को कंपलसरी नहीं देखा। जर्मनी ने सन् १९१८ के युद्ध के पहले अडल्ट के लिये मिलिट्री एजुकेशन अनिवार्य किया था। जर्मनी चाहता था कि उसके तमाम बालिग नागरिक सिपाही के कार्य में ट्रेड हो जावें और तमाम मुल्कों में अपना राज्य जमा सके। इसलिये उसने अडल्ट्स के लिये मिलिट्री एजुकेशन कंपलसरी किया था। लेकिन अडल्ट्स याने सब बालिगों के लिये मिलिट्री एजुकेशन कंपलसरी करना एक बात है और स्कूल के बच्चों के लिये कंपलसरी करना दूसरी बात है। बच्चों के लिये इसको अनिवार्य करना ठीक नहीं है। इससे उनकी

मनोवृत्ति में फर्क पड़ सकता है और मुट्ठी भर बच्चों से युद्ध में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। अगर कोई युद्ध की समस्या हल करनी होती भी तो यह भारत सरकार का सवाल है। प्रदेश का सवाल नहीं है। सेंट्रल सरकार अगर सहसूस करती है कि किसी टेरिटोरियल आर्मी की जरूरत है तो वह उसके लिये इन्तजाम करेगी। फैक्टरियां अगर बढ़ानी हैं तो उसके लिये वह काम कर ही रही है। लेकिन हमारा याने प्रदेश का ध्येय तो शिक्षा देना है। हमारे मित्र गुरु नारायण जी ने जो प्रस्ताव रखा है उसका प्रियम्बुल ही गलत है। यह प्रस्ताव तो प्रियम्बुल ही से गलत हो जाता है। अगर हम यही मान लें कि हमारे ऊपर बहुत बड़ा संकट है इसलिये मिलिट्री ट्रेनिंग कंपलसरी कर दी जाये तब यह विषय प्रदेश के कार्य क्षेत्र से बाहर हो जाता है न तो कोई युद्ध का संकट है और न इस वक्त युद्ध संकट की तैयारी में स्कूलों में मिलिट्री एजुकेशन अनिवार्य होने की आवश्यकता है। इसलिये जो प्रस्ताव रखा गया है वह गलत रखा गया है यह सही है कि मिलिट्री एजुकेशन का आम शिक्षा में स्थान है और उस दृष्टिकोण से अपने बच्चों को मिलिट्री शिक्षा यथासंभव दें तो वह ठीक बात है। लेकिन उसको दूसरे उद्देश्य से सिखाया जाय। यह उचित नहीं है। इस प्रकार मिलिट्री एजुकेशन के दो पहलू हैं। इसमें से एक तो यह है कि यह डिसिप्लिन और ड्रिल से आदमी में नैतिक असर डालता है तथा शरीर को बलवान बनाने में भी असर डालता है। दूसरा साइन्स का ज्ञान इसमें है वह अप्लाइड साइन्स में आ जाता है। इससे यह होगा कि हमारे बच्चे ऐसे कार्य में यदि जायेंगे जहां अप्लाइड साइन्स की जरूरत हो तब वहां उसको आसानी से समझ सकते हैं। इन दो पहलुओं के अनुसार मिलिट्री एजुकेशन यथासंभव दी जाय। इस प्रकार विद्यार्थियों को फिजिकल एजुकेशन दें। तो इस हालत से यह आम शिक्षा के लिये सहायक है। दूसरी बात यह है जो साइन्स हमारे यहां पढ़ाते हैं उसमें व्यावहारिक ज्ञान कम होता है। अप्लाइड साइन्स में थ्योरी बताते हैं लेकिन प्रैक्टिकल कुछ नहीं होता है। इसी तरह से हथियारों के बारे में ले लीजिये। विद्यार्थियों को यह पता होता है कि टार्गेटिंग और ब्रेनगन इत्यादि होती है और उनकी थ्योरी भी जानते हैं लेकिन उनका प्रैक्टिकल नहीं होता है इसलिये ये विषय व्यावहारिक तरीके से सिखाया जाय। प्रस्तावक महोदय का जो प्रस्ताव है उसमें मुझे आपत्ति है और मैं उसका विरोध करता हूं।

मैंने सुना है कि फिजिकल शिक्षा फौजी ढंग से कुछ जिलों में लागू है लेकिन उसकी आवश्यकता इतनी नहीं है कि सब कामों को छोड़कर उसके ऊपर ही जोर दिया जाय। एक बात जो मैं अन्त में कहना चाहता हूं वह यह है कि महात्मा जी के सिद्धान्तों के यह बात विरुद्ध नहीं जाती है कि हम मिलिट्री साइड में सुरक्षित रहें यानी हम अपने देश की रक्षा करने के लिये हर वक्त तैयार रहें। व लोग जो महात्मा जी की शायामें बड़े हैं वह उनके सिद्धान्तों को जानते हैं वही हमारे देश की नीति को निर्धारित कर रहे हैं। हमारी नीति है कि हम किसी देश पर हमला नहीं करेंगे, हम किसी की चोख नहीं छीनेंगे। किन्तु यदि कोई हमारी आजादी छीनना चाहे या हमारे देश पर आक्रमण करे तो हममें इतना बल होना चाहिए कि हम उसका मुकाबिला कर सकें। यह नीति महात्मा जी की अहिंसात्मक नीति से टक्कर नहीं खाती है। अतएव मैं इन वक्तव्यों से सहमत नहीं हूं जो इस प्रस्ताव का विरोध केवल महात्मा जी के सिद्धान्तों के आधार पर कर रहे हैं। जो लोग महात्मा गांधी के सिद्धान्तों को मानते हैं यह इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि हमको अपने बल पर निर्भर रहना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं अपने भाषण को समाप्त करता हूं।

श्री सरदार संतोष सिंह (नाम निर्देशित)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव यहां पर कम्पलसरी मिलिट्री एजुकेशन के बारे में रखा गया है उसके बारे में मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि अगर हमारे यहां कम्पलसरी मिलिट्री एजुकेशन होगी तो उसको ठाकुर और जाटों के लड़के ही पसन्द करेंगे। जो बैरियर रस होती है

[श्री सरदार संतोष सिंह]

वही इस चीज को ज्यादा पसन्द करती है। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस प्रस्ताव में कम्पलसरी का नाम न रखा जाय। इसके साथ साथ मैं यह भी कह देना चाहता हूँ कि हमारे प्रदेश में कम्पलसरी और आर्गनल मिलिट्री एजुकेशन के लिए खया भी नहीं है। क्योंकि हमारा मुल्क इस वक्त कहेतसाली से गुजर रहा है। इस वक्त सरकार के पास खया नहीं है इसलिये यह सवाल बेमौका मालूम होता है। इस वक्त यह बात हमारे देश को ताकत के बाहर है। यह सवाल सेंट्रल गवर्नमेंट में होना चाहिए था और उसी को इस पर ध्यान देना चाहिये। इतना मैं कहूँगा कि हमारे यहाँ मिलिट्री एजुकेशन आर्गनल जरूर होना चाहिए। हिन्दुस्तान को किसी का डर नहीं होना चाहिए और वक्त जरूरत पर अपनी मदद कर सकें। मिलिट्री एजुकेशन का होना बहुत जरूरी है लेकिन यह सबजेक्ट आर्गनल होना चाहिए। हमारी प्रदेश की गवर्नमेंट को इसके बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट से बातचीत करनी चाहिए। और उसकी राय से इस काम को करना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं अपनी स्पीच को खत्म करता हूँ।

श्री विश्वनाथ (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं सब से पहले कुंवर साहब को धन्यवाद देता हूँ कि आज इतने महत्वपूर्ण विषय पर विचार करने का अवसर उन्होंने भवन को प्रदान किया है और इसके साथ ही इस प्रस्ताव को मैं अनावश्यक समझता हूँ और इसलिये इसका विरोध भी करता हूँ। यह सत्य है कि आज संसार की ऐसी मनोवृत्ति है, कि एक देश दूसरे देश को निगल जाने के लिये किसी न किसी तरह से, चाहे सही हो या गलत, तैयार है। हम यह भी जानते हैं कि भीतरी खतरा किसी समय सम्भव हो सकता है। इन दोनों चीजों से अपने देश की रक्षा होनी चाहिए। परन्तु इस रक्षा के क्या उचित साधन होंगे उस पर हमको विचार करना है। क्या वह साधन मिलिट्री शिक्षा होगी या और कोई नया रास्ता होगा ? जहाँ तक मैंने इसे सोचा है, तो मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि हिन्दुस्तान की रक्षा के लिये हो नहीं बल्कि समस्त संसार के कल्याण के लिये महात्मा गांधी का ही केवल एक मात्र मार्ग है जिस पर चलने से अपने देश की ही नहीं, बल्कि सारे संसार की रक्षा हो सकती है तथा हिंसा और कलह से बिलखती हुई इस वसुंधरा को सुखी कर सकते हैं। लोग कहेंगे कि जब कि दुनिया में आपस में होड़ लगी हुई है, कि एक देश दूसरे को किसी तरीके से निगल जाय, फिर तो ऐसी अवस्था में बिना सेना के कैसे अपनी रक्षा की जा सकती है। लेकिन आजकल तो लड़ाई सिर्फ तलवार और भाले-बर्छों से नहीं होती है, वह तो दूसरी तरह से होती है। हमारा भी यही कहना है कि आज की लड़ाई इतने में ही सीमित नहीं है। बल्कि हम तो यह कहेंगे कि आज दुनिया वाले सब अपने अपने देश में विशेष प्रकार की तैयारी कर रहे हैं, मेरे विचार से बँसी सूरत में हिन्दुस्तान ही अरक्षित नहीं है, बल्कि संसार का हर देश अरक्षित है। अमेरिका, रूस ब्रिटेन और फ्रांस सब बड़े शक्तिशाली देश हैं। जैसा कि कहा जाता है। लेकिन आज की स्थिति को देखते हुये कोई भी राष्ट्र बलवान या निर्बल नहीं कहा जा सकता। आप लोगों को भली भाँति मालूम होगा कि जिस वक्त यह गत युद्ध छिड़ा हुआ था, उस समय अमेरिका यह अनुमान कर रहा था कि अभी जापान में वह शक्ति है, अभी जापान में वह साधन मौजूद है जिनसे वह दो वर्ष और लड़ाई कर सकता है। परन्तु एक आटम बम्ब ने उसको खत्म कर दिया। मैं समझता हूँ कि आज जो भी बलवान देश हैं उनके मुकाबिले में और दूसरे देश जैसे स्विटजरलैण्ड, नार्वे और पोलैण्ड इत्यादि छोटे देश बलवान साबित हो सकते हैं बशर्ते उस देश के वैज्ञानिक भयानक से भयानक विनाशकारी यंत्र बना सकें। इसलिये इस बात को देखते हुये मैं समझता हूँ कि दुनिया की ही स्वाधीनता आज दिन अरक्षित है और हर देश की दशा सोचनीय है। जब कि हम समझते हैं कि दुनिया में ऐसे भयानक शस्त्रों के निर्माण करने में आपस में होड़ लगी हुई है। बँसी अवस्था में फिर हमारी रक्षा कैसे हो सकती है, यह अवश्य ही एक सोचने का विषय है। इसको देखते हुये मेरी समझ में यह आया है, कि गांधी जी का अहिंसा तथा सत्याग्रह का मार्ग ही एक रक्षा का अजेय मार्ग है जब कि ऐसे अस्त्रों का निर्माण हो रहा है और समस्त संसार में युद्ध की तैयारियाँ हो रही हैं। इस तरह

से अगर हम हिन्दुस्तान में तैयार नहीं हुये तो फिर कैसे हिन्दुस्तान की रक्षा होगी। मेरा कहना यह है कि अगर दूसरे देश तैयारी भी करें और हिन्दुस्तान में अपनी रक्षा के लिये एक भी पल्टन का सिपाही न हो, तो भी ऐसी हालत में दुनिया के हर एक देशों से हमारा देश सुरक्षित रह सकता है। अब प्रश्न उठता है कि वह किस तरीके से। तो मेरा कहना है कि कोई भी देश जब किसी देश पर हमला करता है तो उसके केवल चार ही कारण होते हैं। एक तो यह है कि अगर किसी देश को दूसरे देश द्वारा अपने ऊपर हमले का खतरा हो कि कहीं हमारे ऊपर कभी भी काबिज न हो जाय, तब वह उस देश पर सबसे पहले हमला करता है और दूसरा कारण आर्थिक स्वार्थ साधन, तीसरा कारण कोई बदले की भावना होती है और चौथा कारण किसी देश को अपना उपनिवेश बनाकर या अपने देश में शामिल करके अपना बल बढ़ाना। यही चार कारण हैं, जिससे एक राष्ट्र दूसरे पर हमला करता है। सबसे पहले मेरा कहना है कि जब संसार की स्वाधीनता आज सुरक्षित नहीं है और जब कि छोटे से छोटे मुल्क का भी विशेषज्ञ कोई ऐसे अस्त्र का निर्माण कर सकता है जिससे कि बड़े से बड़े मुल्क का भी विनाश किया जा सकता है। परन्तु जिस दिन किसी राष्ट्र के पास कोई ऐसा भयानक विनाशकारी अस्त्र-शस्त्र तैयार हो जायेगा, जिससे किसी देश का विनाश किया जा सके; तो सबसे पहले वह उस देश पर हमला करेगा, जिस देश के द्वारा अपने ऊपर हमले का विश्वास होगा। परन्तु जिस राष्ट्र से हमले की आशंका नहीं होगी, उस पर वह हमलावर होगा ही नहीं, या अगर दूसरे स्वार्थों के कारण भी हमला हो सकेगा, तो सब शत्रु देशों को जीत लेने के बाद। लेकिन भारतवर्ष (मेरे देश) की तो नीति है, यह सिद्धान्त है कि हम किसी देश पर हमला नहीं करेंगे; बल्कि दूसरों की स्वाधीनता की रक्षा में ही योग देंगे। दुनिया के किसी गुट में शामिल न होकर निपेक्ष रहेंगे।

आज दिन दुनिया भारत को इसी रूप में देखती है और समझती भी है। अतः भारत पर बाहरी हमले का खतरा नहीं है।

इसके अलावा आर्थिक शोषण के लिये यह हो सकता है कि वह हमारे देश पर आक्रमण करे, जिससे कि वह अपने को समृद्धिशाली बना सके। लेकिन गांधी जी ने रचनात्मक और स्वावलम्बी काम करने को कहा और उनका कहना था कि हर व्यक्ति स्वयं जहां तक संभव हो काम करके अपने जीवन का निर्वाह और भरणपोषण स्वयं करे और अपने इस्तेमाल की चीजों को स्वयं तैयार कर लें। यदि इस तरह से मुल्क के लोग तैयार हों, तो कोई देश फिर भारत पर किस लाभ के लिये या शोषण के लिये हमला करेगा इस तरह से भी सुरक्षित हो सकते हैं यदि गांधी जी के रास्ते पर चलें और कहने पर अमल करें। फिर भी कोई हमारे ऊपर निष्प्रयोजन हमला करता है और विजयी भी हो जाता है तो उसके लिये हमारे पास कोई लाभ की चीज प्राप्त ही नहीं होगी और सत्याग्रह भी हो तो हमारा है लेकिन अगर हम अपनी हर ज़रूरत की चीज स्वयं पैदा नहीं करेंगे, तो हमें आर्थिक स्वतंत्रता नहीं प्राप्त हो सकती है और देश पर हमले का भी खतरा रहता है। इसके बाद आवश्यक चीज है देश के लोगों में आपसी प्रेम, सन्तुष्टी और असाम्प्रदायिक भावना यह देश का सबसे बड़ा बल है और रक्षा का सुन्दर बलवान साधन है। दुख है कि देश के कुछ लोगों के अन्दर साम्प्रदायिक भावना है इसीलिये दूसरे देशों के लोग हम पर कब्जा करने का ख्याल कर सकते हैं। इसीलिये बल्लभ भाई पटेल के एक बार कहा था और वह भी उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, पहले अवसर पर कहा था कि देश का विभाजन किया गया है सिर्फ भविष्य के प्रखंड भारत के निर्माण के ही लिये। उनका मतलब था, हम में ऐसी असाम्प्रदायिकता की भावना पैदा हो जावे, ऐसी बन्धुत्व की भावना पैदा हो कि हम पहचान न सकें, कि कौन हिन्दू है, कौन मुसलमान या ईसाई है। हमें साम्प्रदायिकता की भावना को पैदा नहीं होने देना है नहीं तो हमारा नाश हो जायेगा और उससे हमारे देश की जनता कभी भी सुखी नहीं होगी। दूषित भावना को हमें मिटाना है और इस प्रकार के भावों को यहां नहीं पनपने देना है, और तभी

[श्री प्रभु नारायण सिंह]

कमी है उसकी और ध्यान दिलाते हुये कि अनुशासन की जो कमी है, सरकार अगर इसको स्वीकार कर ले तो अच्छा है। जहाँ तक संकट की बात है तत्काल तो कोई खतरा नहीं है, लेकिन मुल्क की राष्ट्रीयता के आधार पर संगठित रखना चाहिये ताकि जब कोई खतरा आये तो उसका हम मुकाबिला कर सकें। लेकिन उस खतरे का जिसे नाज़ी जर्मनी ने सोचा था और दूसरे मुल्क सोचते हैं या हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के बटवारे के समय हम लोगों की राय थी, हमें गौर करने की जरूरत नहीं है। यह अन्तर्राष्ट्रीय सवाल है। इसके ऊपर मैं अपनी राय का इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन इतना कहूंगा कि आज जो होना का सवाल है जैसा कि दूसरे मुल्क कर रहे हैं हिन्दुस्तान में उसकी जरूरत नहीं है। जैसा मैंने कहा यदि इन सामाजिक भावनाओं को लेकर नवयुवकों को प्रोत्साहित किया जाय तो हिन्दुस्तान के रचनात्मक कार्य में काफी सहायता मिलेगी और नये विचारों से प्रेरित नवयुवक हमें मिलेंगे।

* श्री बंशीधर शुक्ल (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र) —माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस मिलिट्री ट्रेनिंग पर करीब घंटे भर से विवाद चल रहा है। इसको मैंने ध्यानपूर्वक सुना। मैं यह ख्याल करता हूँ कि कुंवर साहब को अगर यह मालूम होता कि इन्टरनल और एक्सटरनल शब्द का प्रयोग करने से इतना विवाद बढ़ेगा तो शायद वह इन शब्दों का अपने प्रस्ताव में इस्तेमाल न करते। प्रस्ताव को देखते हुये जहाँ तक मैं समझता हूँ जरूरत इस बात की नहीं थी कि इन शब्दों का ही प्रयोग किया जाता। मैं समझता हूँ बुनियादी तौर से नवयुवकों को सैनिक शिक्षा किसी मुल्क में देना परमावश्यक है। हमारे मंत्री महोदय ने भी अपने भाषण में स्वीकार किया है लेकिन हमारे राष्ट्र के पास इतना साधन नहीं है कि हम समुचित रूप से इसका प्रबंध कर सकें। दूसरी बात यह चीज केन्द्र की है इसलिये केन्द्र स्वयं प्रबंध करे। लेकिन आपत्ति इस बात पर की गई कि इसमें शब्द कम्पलसरी का प्रयोग किया गया है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कम्पलसरी के माने यह है कि उन लोगों को छोड़कर जो शारीरिक दृष्टि से या अन्य किसी कारण से सैनिक कार्य नहीं कर सकते बाकी लोग कुछ हद तक सैनिक शिक्षा प्राप्त करेंगे। कहने का आशय यह है कि हर एक युवक को पूर्ण युवक बनने के लिये यह आवश्यक है कि कुछ न कुछ मिलिट्री ट्रेनिंग ख्वाह वह आत्म रक्षा के लिये हो या शारीरिक निर्माण के लिये हो, हासिल करनी चाहिये। इसमें दो रायें नहीं हो सकती। हम ऐसी जाति बनाना नहीं चाहते जो निर्बल हो। ऐसी जाति चाहते हैं जो राष्ट्र के निर्माण के काम आये महात्मा गांधी की दोहाई दी गई और कहा गया कि महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे इसलिये यह प्रस्ताव उसके प्रतिकूल है। मैं समझता हूँ उनका उद्धरण गलत ढंग से हमारे सामने पेश किया गया।

साथ ही साथ इस संबंध में मैं यह भी आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि स्टेट और सोसाइटी में जो अन्तर है वह यह है कि स्टेट में फोर्स का समावेश है परन्तु समाज में फोर्स का समावेश नहीं है वरन् परसुपेनन का समावेश है। जब प्रारम्भिक काल में हमारी रिपब्लिक में यह प्रश्न उठा था तो वाद विवाद में यह मान लिया गया था कि जब हमको राज्य का निर्माण करना है तो किसी न किसी रूप में सेना रखनी होगी। अब मैं उसी बात पर आता हूँ। हम यह चाहते हैं कि मिलिट्री ट्रेनिंग इस रूप में जरूर होनी चाहिये जिससे संगठित करने का भावना बढ़े और चरित्र निर्माण हो। प्रस्तावक का शायद यही आशय है। मेरे ख्याल में उनका यह आशय कभी नहीं था कि मिलिट्री ट्रेनिंग पा जाने से कोई लड़ाई का नक्शा उनके सामने होगा। इसका तो केवल इतना ही आशय है कि जिस तरह अब फोर्स का प्रयोग होता है उसी तरह सैनिक शिक्षा का भी प्रयोग किया जा सके। अभी कुछ दिन हुये पहले आप यह कहा करते थे कि हमारे यहां गुन्डाशाही बढ़ रही है, डकैती बढ़ रही है, मेरा कहना है कि सैनिक शिक्षा आपको किसी न किसी प्रकार अवश्य देनी चाहिये जिससे संगठित रूप से इस बढ़ती हुई गुन्डाशाही का मुकाबिला किया जा सके। मैं यह बात साफ कह देना चाहता हूँ कि अगर आप राष्ट्रीय ढंग पर मिलिट्री शिक्षा न देंगे तो हमारे नवयुवकों को किसी दूसरी तरफ आकर्षित कर दिया जायगा जैसा कि आजकल हो रहा है कि कुछ साम्प्रदायिक संस्थाएँ लड़कों को इकट्ठा करके उनको मिलिट्री की शिक्षा देती हैं यद्यपि उनके पास बन्दूक वगैरा नहीं होती है। इसीलिये

* सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

मैं कहता हूँ कि अगर आप युवकों को चैनेलाइज नहीं करते तो दूसरे लोग उनका गलत प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ यह भी कहा गया कि यह आटमिक वार का जमाना है टोटलेरियन वार का जमाना है लेकिन जब यह बात सत्य है तो फिर मिलिट्री ट्रेनिंग की और भी आवश्यकता हो जाती है। जब हम सुनते हैं कि दूसरी जगह औरतों को पुलिस में भर्ती किया जाता है तो फिर हमारे यहां युवकों को सैनिक शिक्षा क्यों न दी जानी चाहिये। तो हमारे नौजवानों के सामने यह रखना कि अगर वह मिलिट्री ट्रेनिंग पा जायेंगे तो वह क्रयामत ढा देंगे यह गलत बात है। मैं तो यह कहता हूँ कि मिलिट्री ट्रेनिंग सबके लिये कम्पलमरी होना चाहिये और हमको और आपको भी मिलिट्री ट्रेनिंग लेना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ कि मिलिट्री ट्रेनिंग यूथ्स के लिये आवश्यक है।

डाक्टर बीरभान भाटिया—(नाम निर्देशित)

Sir, I strongly support the Resolution which has been moved by my friend, Kunwar Guru Narain. I do not agree with the preamble and the objects with which he has moved this Resolution. From the medical point of view I feel that military education will be of immense value to the young men of our country. It will help to improve their physical health. It will give them the discipline which they very badly need and it will help them to develop their general knowledge and their power of concentration and judgment. None of the arguments which have been put forward to oppose this Resolution are of a convincing nature. For instance, it has been said that in the Intermediate classes there are young students of 11 or 12 years of age. Most of them have got very bad physical health and it will not be in their interest to have compulsory military education. On the other hand, I would have said that if there was any argument for introducing military education it was this argument that the physical health of the young men of this State is the poorest in India and the physical health of the young men of India is the poorest in the world, and as such we must introduce compulsory physical education by which the physical health of our young men would surely improve. Certainly, if there are any such young men who are suffering from such diseases in which physical education can be harmful such cases will be exempted on medical certificate; but to say that because majority of the young men have got poor physique and they should not be put to the hardship of military education is an argument which will not convince any educated assembly.

Secondly, it has been said that ours is a peace-loving country, we want peace, and if we give military education to our young men, it will be presumed that we are trying to be an aggressive nation. Personally I feel that India can only play its very important role of bringing peace in this world, by making itself very strong. If India is strong to-day, there will be no war between the two parties who are opposing to-day each other in this world. India with its nearly forty crores of people and with its tremendous resources can become a powerful nation; and once it is powerful it will prove a useful medium of giving peace to this world. Peace, as has been repeatedly asserted by our Prime Minister, is certainly the object and aim of every citizen of this country, but I feel we may play a very important role in winning that peace by making ourselves strong. By giving military education to our young men, we will find ourselves ready to meet any aggression that may come to this country. I feel that, even if this subject be not in the power of the State, even if the direction has to come from the centre, this State should move the centre that military education should be compulsory in the Intermediate classes through out India so that young men may be able to develop their physical health, may be able to develop discipline and may be ready to serve the country in time of need.

श्री कुंवर गुरु नारायण—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रस्ताव को मैंने इस सदन के सम्मुख रखा था मुझे दुःख है कि यह तो मैं समझा नहीं सका या हमारे बहुत से माननीय सदस्यों ने उसको सही समझा नहीं। माननीय हाफिज जी ने तो एक बात कही और वह यह थी कि उन्होंने यह नहीं कहा कि मिलिट्री ट्रेनिंग न होनी चाहिए या यह ठीक नहीं है, अच्छी नहीं और उचित नहीं है। वित्त मंत्री होने के नाते उनका केवल एक दृष्टिकोण रहता है वह यह कि खर्चा कहां से मोट करेंगे। खर्च का प्रश्न उनके सामने था। इसके अलावा और कोई आपत्ति माननीय लीडर आफ दि हाउस ने नहीं जाहिर की। लेकिन मुझे ताज़ुब जब हुआ जब इस भवन के बहुत से कांग्रेसी मੈम्बरों ने इस बात पर बहस शुरू कर दी और यह कहना शुरू कर दिया कि आज मिलिट्री शिक्षा बिलकुल गलत है कोई इन्टरनल या एक्सटरनल अग्रेशन का डर नहीं है और यह किज़ुल सो बात है। कोई कहता है कि इस शिक्षा से लोगों की हिंसात्मक वृत्ति हो जायेगी। जहां तक माननीय हाफिज जी की बात का ताल्लुक है वह तो मैं साफ समझ सकता हूं और उसका जवाब भी हो सकता है। लेकिन इसका जवाब ही क्या हो सकता है कि मिलिट्री शिक्षा ही लोगों को देना खराब है। एक हमारे भाई शायद श्री हयातउल्ला अन्सारी जो कि इस वक्त यहां नहीं हैं उन्होंने बहुत निन्दा की और घोर निन्दा की कि मिलिट्री एजुकेशन इतनी खराब है कि वह नहीं होनी चाहिये। तो अब मैं आपसे पूछूं कि क्या हमारे राष्ट्र का नैतिक पतन दिन पर दिन होता चला जाय और हम बंटे देखा करें ? हम जब यह कहते हैं कि मिलिट्री शिक्षा इन्टरमीडिएट क्लासेज में दें तो इसका असर राष्ट्र पर होगा। आगे चलकर जब यूनिवर्सिटी एजुकेशन का समय आयेगा तब हमारे नवयुवक कुछ एक दूसरे वातावरण में होंगे। मिलिट्री शिक्षा होने के नाते यह स्वाभाविक बात है। वह एक ऐसी चीज़ है जो किसी प्रकार के भ्रष्टाचार से बरी है। आज जितना समाज है और जिस तरीके वह नैतिक पतन में डूब रहा है वह किसी से छिपा नहीं है। लाख हाफिज जी यहां पर कहते रहे कि यहां चोरी और डकैती नहीं होती हैं, सब लोग रामराज्य में रहते हैं लेकिन यह मानने की बात नहीं है। मिलिट्री ही एक ऐसी जगह है जहां पर इन चीज़ों का वातावरण नहीं है। अगर हम इस बात की प्रार्थना करें कि हम अपने नवयुवकों को ऐसी मिलिट्री शिक्षा प्रारम्भिक स्टेज में दें ताकि उनके चरित्र का निर्माण हो तो कौन सा अपराध करते हैं। उसके साथ ही साथ हमारे देश में जब इसकी आवश्यकता है और इसके लिये हर प्रकार से हम तैयार हैं तो इसमें क्या आपत्ति की बात है। हमारे माननीय सदस्य श्री अन्सारी साहब ने न मालूम किस आशय से यह बात कह डाली उसे मैं समझता नहीं। जब हम मिलिट्री शिक्षा का प्रस्ताव लाते हैं तो वह भी आप नहीं मानते हैं और यदि हम कहते हैं कि धार्मिक शिक्षा दें तो कहते हैं कि साहब हमारी स्टेट सेक्युलर है इसमें रिलीजन की शिक्षा नहीं दी जा सकती। पूजा करने या नमाज पढ़ने की शिक्षा नहीं दी जा सकती। तो क्या किया जाय। जो भी चीज चरित्र के निर्माण के लिये है उसको आप मानने के लिये तैयार नहीं हैं। मिलिट्री शिक्षा के लिये आपको आपत्ति है। आगे चलकर मेरा एक और प्रस्ताव भारेल शिक्षा के बारे में है देखें सरकार उसको मंजूर करती है या नहीं।

आपको यह भी चीज़ नहीं मंजूर वह भी चीज़ नहीं मंजूर है तो फिर आप राष्ट्र को ऊंचा उठाने के लिये कौन सी चीज़ लाना चाहते हैं। जिस चीज़ से आप समझते हैं कि राष्ट्र का स्तर ऊंचा उठ सकेगा वही चीज़ हम लायें। लेकिन मैं आप को विश्वास दिलाता हूं कि नैतिक शिक्षा को भी आप निहायत खूबसूरती के साथ नामंजूर कर दीजियेगा। आप ही बतायें कि हम को अपने राष्ट्र को ऊंचा उठाने के लिये कौन सी शिक्षा देनी चाहिये। अगर आप यही चाहते हैं कि हमारे यहां के बच्चे चोरी करना, डकैती डालना और भ्रष्टाचार करना ही सीखें और किसी न किसी नेता जी की शरण में अपना काम करते रहें तो देश का भगवान ही मालिक है। मुझे इन बातों को सुनकर बहुत दुःख हुआ। जो चीज़ जरूरी है उन पर तर्क की क्या जरूरत है। यह शिक्षा देनी चाहिये या नहीं देनी चाहिये इसमें तर्क का क्या सवाल है देवरिया और गोरखपुर के और १८ पूर्वी जिलों में भुलसरी का सवाल पैदा हुआ तो हमारी

सरकार की समझ में उस वक्त तक वह नहीं आई जब तक कि भुखमरी बिलकुल उसके सामने नहीं आ गई। यह भी कहा गया कि इस वक्त इसकी क्या जरूरत है जब वक्त आयेगा उस वक्त इस को देखा जायेगा। यहीं हालत सरकार की फूड के मसले के बारे में रही है। जब स्थिति बहुत खराब हो गई तो सरकार उस पर वादविवाद करती है। किसी प्रकार का एग्जेशन हो या अभी न हो, सब से जरूरी मिलिट्री एजुकेशन है जो मनुष्य के मागतव चरित्र को ऊंचा उठाती है। हमारी जो नई जनरेशन है उसको हमें ऊंचा उठाना है। नवयुवकों को इस किस्म की शिक्षा की बहुत जरूरत है। हमारे जो नवयुवक हैं उनको मिलिट्री शिक्षा देने के लिये यह प्रस्ताव पेश किया गया है। मैं समझता हूँ कि यह बहुत जरूरी प्रस्ताव है, मगर यहां पर इसके बारे में कुछ ऐसी बातें कही गयीं जिनसे ऐसा मालूम हुआ कि मैंने इस प्रस्ताव को पेश करके बहुत बड़ा पाप किया है और इसकी सजा मुझे इस जन्म में नहीं दूसरे जन्म में भी दी जायेगी। जहां तक हाफिज जी का संबंध है उन्होंने फार्डिनैंस मिनिस्टर होने के नाते ठीक कहा कि हमको टैंक्स लगाने की जरूरत पड़ेगी मैं इस बात को कुछ हद तक मानता हूँ कि शायद सरकार को टैंक्स लगाने की भी जरूरत पड़ जाय। लेकिन मैं तो यह कहता हूँ कि गवर्नमेंट कोई भी हो, जब वह कोई चीज करना चाहती है तो उसके लिये रुपया उसके पास रहता है और जब वह किसी चीज को नहीं करना चाहती है तो पचासों रास्तों से उसमें अड़ंगे लगाये जाते हैं। अब मैं इसकी व्याख्या में नहीं जाना चाहता कि रुपया कहां से आये। पहले छः या सात मिनिस्टर होते थे और आज ११ या १२ हो गये हैं इसके अलावा डिप्टी मिनिस्टर्स हो गये हैं आपके पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज हुये, इनका खर्चा तो बढ़ता जा रहा है और बहुत सी फिजूल खर्ची को जो आप करते हैं तो उनके लिये रुपया आपके पास निकल आयेगा अगर चाहें तो आप इस एजुकेशन को भी चला सकते हैं। लेकिन वह जभी हो सकता है जब कि आपका भी दृष्टिकोण हो और आप भी इसी दृष्टि से सोचें कि नहीं हमारे राष्ट्र के लिये यह आवश्यक है और हमारे राष्ट्र का जभी कल्याण होगा जब हम अपने नवयुवकों को उचित शिक्षा देंगे और इस तरह से उनको आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। जब तक आपका दृष्टिकोण यह नहीं होता है तब तक खर्च का रुपया नहीं निकल सकता है और इस चीज का यही जवाब है कि कोई भी इसके ऊपर तर्क नहीं कर सकता है। मैं एक सुझाव रखता हूँ कि इस कार्य के लिये, चूंकि मिलिट्री सेन्टर के हाथ में है, तो आप सेन्टर से इस संबंध में धन की याचना कर सकते हैं। इस शिक्षा का परिणाम यह होगा कि जो शिक्षा हमारे यहां इस प्रकार की दी जायेगी उससे मिलिट्री के कार्य में मदद मिलेगी और ज्यादा आसानी के साथ वह लड़के मिलिट्री में शरीक हो सकते हैं। कम प्रयत्न के साथ और कम खर्च में हम अपने देश का फायदा कर सकते हैं। लेकिन यह चीज तो जभी हो सकती है जबकि आपका दृष्टिकोण उधर हो। अगर सरकार का भी दृष्टिकोण इस तरह का हो कि हमको यह कार्य करना है और हमें राष्ट्र को इस तरीके से ऊंचा उठाना है तभी यह हो सकता है। अगर यह हो कि यह हमारा दृष्टिकोण तो है पर किन्हीं वजूहात से नहीं कर पा रहे हैं तो फिर उसका कोई सवाल ही नहीं है। जहां तक मेरे इस प्रस्ताव का संबंध है, उसके विषय में एक साहब ने यह कहा कि जो फिजिकली कमजोर हैं उनके लिये यह कैसे संभव है कि कम्पलसरी मिलिट्री एजुकेशन की जाय और सभी लड़के कैसे मिलिट्री ट्रेनिंग में शरीक हो सकते हैं। मानी हुई बात है कि इसके लिये टेस्ट होता है और जो फिजिकली फिट होते हैं वही लिये जाते हैं। उसमें हर शक्स तो नहीं लिया जा सकता है। जो लड़के फिजिकली फिट नहीं होंगे उनको इसमें नहीं लिया जायेगा तो यह तो सोचने की बात है। अब रही यह बात कि इस समय एक्सटरनल एग्जेशन की हालत वाकई है और हम इन्टरनल एग्जेशन की हालत में वाकई हैं। एक्सटरनल एग्जेशन भी हो सकता है और इन्टरनल एग्जेशन तो हमारे देश में है और वह इतना है कि उसकी कोई व्यवस्था नहीं की जा सकती है। जैसा कि मैंने लालेसनेस के सिलसिले में पहले कहा था कि सिमटम तो आपके सामने है लेकिन आप दवा नहीं कर पाते हैं और जब रोग काफी बढ़ जाता है तब आखिरी खुली कि अब हमको कुछ करना चाहिये। जैसा कि अभी श्री प्रभुनारायण सिंह जी ने कहा कि ४, ५ पावर इस संसार में है और वह वार को कंट्रोल करते हैं

[श्री कुंवर गुरु नारायण]

और अगर ऐसा ही सिद्धांत हो और अपने मुल्क को एग्रेसन से हम न डिफेंड कर सके तो फिर कैसे हम अपनी आजादी को कायम रख सकते हैं। कितनी कुर्बानियों के बाद आप ही लोगों ने इस आजादी को प्राप्त किया है फिर उसको प्राप्त करने के बाद अगर आप ध्यान न दें कि इस आजादी को रखने के लिये कोई न कोई उपाय आप निकालें, तो इस आजादी को धक्का लग सकता है। मिलिट्री एजुकेशन के माने यह तो नहीं हैं कि लड़के फौजी हो गये और उन्होंने भी तमाम लड़ाई का काम शुरू कर दिया। मैं तो कहता हूँ कि मिलिट्री ट्रेनिंग के लिये स्कूल या कॉलेज फुल एक्विपड हों और उनको ट्रेनिंग दी जाय ताकि कहीं भी जरूरत हो, थोड़ी सी ट्रेनिंग के बाद ही उन लड़कों को ऐसा अनुभव हो जाय कि वह इस कार्य को संभाल सकें। ऐसी एजुकेशन को जारी करने में अगर मेरे भाई विरोध करते हैं तो उनकी खुशी है और यह उनका दृष्टिकोण है। लेकिन मैं उनसे यह कह दूँ कि उनका यह दृष्टिकोण जो है वह चाहे किन्हीं भी वजूहात से है, सही नहीं है।

अब रही और मुल्कों की बात, जैसा कि एक साहब ने अभी कहा कि पहले मैंने जो कुछ कहा था कि अगर गांधी जी जीवित होते और अगर भारतवर्ष पर इटली या जर्मनी का कब्जा होता, तो वे क्या करते? यह बिल्कुल साफ और खुली हुई बात है और ऐसा कहना कि गांधी जी होते तो उस वक्त क्या करते, यह मेरी समझ में नहीं आता क्योंकि गांधी जी कल क्या करने वाले हों यह तो सिर्फ गांधी जी ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जोकि स्वयं ही समझ सकते थे कि वह भविष्य में क्या करने वाले थे और वह जिस चीज को उचित समझते थे और करने को कहते थे उसको करके भी दिखलाते थे। आजकल हमारी जो लीडरशिप है उसको गांधी जी की लीडरशिप की गणना में रखना उचित नहीं है क्योंकि वे कहते तो बहुत कुछ हैं और बहुत सी स्क्रीमें बनाते हैं, मगर आगे जाकर कार्य रूप में उसका संचालन नहीं कर पाते हैं और उसका कारण यह है कि उनमें इतनी शक्ति नहीं है और उनका चरित्र उतना ऊंचा नहीं है कि वे उसको कार्य रूप में परिणत कर सकें। तो यहां पर गांधी जी के कहने और न कहने का कोई सवाल नहीं है। अगर आज इटली और जर्मनी की भारतवर्ष पर हुकूमत हो जाय तो मुमकिन है कि गांधी जी के न रहते हुये हम दूसरे ऐसे तरीके निकाल दें जिसमें कि लोगों को बड़ा भारी एतराज हो जाय, तो क्या हो सकता है। मैंने जो यह प्रस्ताव पेश किया है, मैं समझता हूँ कि यह बहुत ही इनोसेंट प्रस्ताव है और मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस समय इस चीज को अपोज करने का कोई सवाल ही नहीं है क्योंकि सरकार ने सन् १९४८ में इस चीज को मान लिया कि मिलिट्री ट्रेनिंग हमारे स्कूलों में होनी चाहिये और उसी के अनुसार १८ जिलों में मिलिट्री ट्रेनिंग का काम जारी भी हो गया है। यानी आज १२४ स्कूलों में मिलिट्री ट्रेनिंग दी जा रही है। तो मैं इतना ही कहता हूँ कि जो मिलिट्री ट्रेनिंग दी जा रही है हवलदार लोगों के जरिये से, तो उसको हम इस तरह से दें कि एक अच्छा वातावरण पैदा हो सके और उसको हमें सीरियसनेस के साथ ट्रेन अप करना चाहिये मैं चाहता हूँ कि हमारे नवयुवक किसी तरह से भी कमजोर न हों और किसी वक्त भी किसी चीज का मुकाबिला करने के लिये वे हमेशा तैयार रहें। इसमें मैंने इस वक्त कोई खास चीज की डिमान्ड नहीं की है बल्कि मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूँ कि पूरे प्रान्त के स्कूलों में यह शिक्षा हो जाय। मैं यह मानने के लिये तैयार नहीं हो सकता हूँ कि गवर्नमेंट यह कन्विन्स कराने की कोशिश करे कि इसके लिये वह आज खर्चा नहीं कर सकती है मैं कहता हूँ कि फिज़लखी छोड़कर और जिस तरीके से भी हो, इसके लिये बजट में रुपये निकालकर इसको शुरू कीजिये। इन्हीं चन्द शब्दों के साथ मैं यह निवेदन करता हूँ कि मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाय।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जनाब डिप्टी चैयरमैन साहब, मैं पहले यह समझा नहीं कि इस प्रस्ताव के पीछे आज इस हाउस में इतनी तकरीरें हुई हैं तो वह क्यों? मैं तो अपने नजदीक इसको एक सोचा साधा सा प्रस्ताव समझा था और इसलिये ऐसा समझता था कि वह जिस मकसद से पेश किया गया है इसे कि हिन्दुस्तान में कल हमला होने वाला है और हिन्दुस्तानियों के दिमाग में यह बात पैदा हो गई है कि किस तरह से उस वक्त अपने देश को बचाया जायेगा। इसी तरीके से आज इस प्रस्ताव में यह

बतलाया गया है और इसी को गौर करने की जरूरत है। तो मैं कतई इसको नहीं समझता हूँ। मैं तो यह समझता हूँ कि कुंवर साहब ने जो प्रस्ताव पेश किया है वह इस बिना पर नहीं किया है कि किसी किस्म का खतरा है या उसके लिये इस चीज की जरूरत है। उन्होंने यह समझा कि यह एक उम्दा चीज है और मुल्क के आदमियों को जानना चाहिये और उनमें इससे डिस्प्लिन भी पैदा हो सकता है। यह सही है कि उन्होंने गवर्नमेंट ने जो काम किया है उसकी दाद नहीं दी। हालांकि कुंवर साहब के दिमाग में क्या खयाल था, हम नहीं कह सकते उस जमाने में सरकार ने यह समझा कि इस किस्म की ट्रेनिंग होनी चाहिये और उसको कायम किया। पहले ११ जिलों में थोफिर १८ जिलों में की गई और वह एक प्रोग्रेसिव स्कीम है जो स्टेट के अन्दर बढ़ाई जा रही है और वह वक्त आने वाला है जब कि सारे प्रदेश में वह चालू की जायेगी। उस पर खयाल भी खर्च किया जा रहा है। मैंने एक नोट भी पढ़ कर सुनाया था। अभी प्रभुनारायण साहब ने कहा था और ठीक हो कहा था कि गवर्नमेंट ने इसकी ठीक समझा और ठीक समझ कर ही इस काम को शुरू किया। इसलिये इख्तलाफ राय का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। मेरे नजदीक एक वजह इसके न मानने की यह हो सकती है कि गवर्नमेंट जिस तरह से इसको डेवलप करना चाहती है वह इस प्रस्ताव से नहीं हो सकता है। यह प्रस्ताव इस चीज का फौरन हो कराना चाहता है; अगर इसको मान लिया जाय तो जैसा कि मैंने कहा कि इसके लिये रुपये की जरूरत पड़ेगी। उसका जवाब मैंने यह पाया कि मैं फाइनेंस मिनिस्टर हूँ मेरा प्वाइंट आफ व्यू यह हो सकता है कि मैं यह देखूँ कि इसकी मेरिट के साथ साथ फाइनेंस के एतबार से यह काबिले कबूल है या नहीं। मगर शायद उन्हें यह पता नहीं कि जब किसी मेम्बर का प्रस्ताव आता है तो वह कबल इसके कि उस पर यहां बहस हो वह सूबे को कैबिनेट के सामने पेश होगा और उस पर गौर करने के बाद उसका डिसेजिन होगा कि उसको मंजूर किया जाय या न किया जाय या जो भी फैसला किया जाय जैसा कि कुंवर साहब ने कहा कि स्टेट के जितने मिनिस्टर हैं वह सब इशो मर्ज में मुडितला है तब तो कुंवर साहब के लिये कोई भी बेचारा नहीं है सिवा इसके कि यह गवर्नमेंट चेंज हो वर्ना कोई वजह नहीं जो वजह मैंने पेश की है वह गलत हो। अगर मेरिट्स के हिसाब से मैं इसको देखूँ तो इसके लिये खर्च की भी जरूरत होगी।

एक बात मेरे एक दोस्त ने कही और वह एक दफा नहीं दो दफा नहीं बल्कि दसियों दफा इस हाउस में ज़रे बहस आ चुकी है लेकिन मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूँ। एक मेरे दोस्त ने कहा कि मैं तदबीर बता सकता हूँ लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि उसके करने के लिये जो जंजीर हमारे लिये रखी है और हम उसमें बंधे हैं उसी रास्ते को हमको अख्तियार करना पड़ता है। जो कान्स्टीट्यूशन बनाया गया है उसके अन्दर हमको काम करना पड़ता है। जब तक हम उसको चेंज न करें तब तक हम उस तदबीर से काम नहीं कर सकते हैं। कोई भी आदमी किसी भी खयाल का हो वह देखे कि गवर्नमेंट के लिये जो हद्द है उसके मुताल्लिक गवर्नमेंट क्या कर सकती है और उसको देखकर मशविरा दे तो वह मशविरा बहुत काबिले अमल भी हो सकता है, और गवर्नमेंट के लिए काबिले खयाल भी हो सकता है। आज मैं इस रिजोल्यूशन को गवर्नमेंट की तरफ से मंजूर कर लूँ और आज से दो महीने के बाद इस हाउस में फिर जवाब दे दे बूँ कि जो रिजोल्यूशन मंजूर किया था, उसके मुताबिक क्या इस वक्त तक किया गया है? क्या आप चाहते हैं कि इस वक्त में यह बताऊँ कि मैंने कुछ नहीं किया है, इसलिये कि मैं किसी तरीके से मजबूर था। तो क्या मैं इस हाउस को यह कहने का मौका दूँ कि जिस चीज को मैंने अच्छा कहा था जिसको मैंने मंजूर भी कर लिया था उसको नहीं किया। अगर मैं ऐसा करूँ तो मैं समझता हूँ कि मैंने धोखा दिया। यह बात ठीक नहीं हो सकती। हाँ, एक बात बढ़ती जा रही है कि मसला

[श्री हाकिम मुहम्मद इब्राहीम]

कुछ हो तालुक इस बात से हो कि न हो कि लीडरशिप कैसी है, मगर उस लीडरशिप पर कुछ तबरी, कुछ गवर्नमेंट के कामों पर तबरी, यह जरूर हो जाना है। उस बहस के अन्दर जो यहां हो। मुझसे यह कसूर नहीं हुआ। मैं किसी भी निस्वत किसी तरह की बात नहीं कही और न मैं कहना चाहता हूं। मैंने दरखास्त भी इस हाउस से यही की है कि बेहतर हो कि इस किस्म की बातें जो यहां होती हैं वह नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट अगर ऐसी है जैसा कि समझी जाती है और उसके सामने रखने का हल भी मालूम है तो फिर लाना ही फिजूल है। एक ऐसा काम करना जिसके करने का कुछ नतीजा नहीं, मैं यह नहीं समझता अपन उन दोस्तों के बावत जिनकी भावनाएं जिन के आइडियल्स सब कुछ मुझ से मुस्तलिफ हैं, मैं उसकी निस्वत यह नहीं समझता कि मैं उनको कुछ बात समझाऊं तो वह यह समझेंगे कि मैं कुछ और हूं और यह कुछ ख्याल रखता हूं, यह रिजोल्यूशन पेश किया तो नामंजूर हो गया, मारे लिटी के मुतालिक रिजोल्यूशन पेश किया तो वह भी नामंजूर हो गया। मैं नहीं समझता कि इस हद तक इन्फाक का मतलब है। जो साहब इसको कहते हैं मैं उनकी तबज्जह इस बात के बावत दिला सकता हूं। लेकिन मैं जो चीज नहीं कर सकता उसे मैं इसलिए मान लूं जिससे कि दूसरे आदमी यह यकीन कर लें कि मैंने मान लिया, ऐसा एंटीट्यूड अख्तियार करना मैं मुनाहिब नहीं समझता। मसलन मैंने एक सप्लीमेंट्री बजट पेश किया, उसको मेरे भाई कोई दोस्त इस नजर से देखें कि एक एक सतर जो इसमें शामिल हैं वह गलत हैं तो मेरे दिमाग में क्या इम्प्रेशन होगा, इस दुनिया में हजारों बातें करता हूं क्या कभी एक भी ठीक नहीं हो सकती। मैं ऐसा करना नहीं चाहता कि इस रिजोल्यूशन से और इस बहस से कोई मतलब नहीं था और बिल खसूस उस हालत में जब कि कुंवर साहब के दिमाग में मेरे कहे हुए का एनालिसिस मौजूद था। मैंने यह कहा कि इसमें खर्च का इतना सवाल है, इस फाइनेंशियल स्ट्रिजेंसी के जमाने में खर्च का इन्तजाम करना मुश्किल है। हां, मैंने प्रायोरिटी का जरूर लफ्ज इस्तेमाल किया था। मैंने कुंवर गुरु नारायण की राय सुनी। बाकी जनता की राय सुनी नहीं। फाइब इयर वह भी बने, सफाखाने भी कायम होते चले जायें, सड़क भी बनती चली, नहर भी बनती चली, ट्यूबवेल भी बनते चले। जिस तरीके से हमारे दोस्त चाहते हैं तो हमसे अगर इस जमाने में यह बात मुमकिन नहीं है। हम प्रायोरिटी इस बात की दें और कोई कह दे कि फाइब इयर प्लान जो है उसको हम इसके मुकाबिले में नहीं रख सकते हैं। इस प्रकार का सुझाव इस मुल्क का हो तो मैं भी इस पर सोचूं। मिसाल के तौर पर कुंवर गुरु नारायण के पड़ोस के सफाखाने में एक कम्पाउन्डर की कमी हो जाय तो उसकी भी शिकायत नहीं यहां हो जायेगी। मैं आम तौर पर कह रहा हूं। तालीम का मसला होगा तो तालीम ही तालीम का मसला होगा। यह मालूम होगा कि दुनिया में एक चीज तालीम है उस पर गवर्नमेंट को खर्च करना चाहिये। जब सड़क का मसला आयेगा तो उस पर वही सवाल होगा कि सड़क का मसला ठीक होना चाहिये। कोई ऐसा नहीं है कि वह गैर जरूरी है। यह नहीं कहेंगे कि सड़कों पर जो रुपये खर्च होता है वह गैर जरूरी है। अभी उन्होंने दो चार मिसालें बतलायीं कि १२ मिनिस्टर हो गये और १३ पालियामेंट्री सेक्रेटरी हो गये। मैं दावत देता हूं कुंवर गुरु नारायण साहब को कि वे बजट लेकर बैठ जायें और उसमें से जो अधिक है उसको काट दें? मैं उसको कटवाऊंगा तब जब वे बतला देंगे कि बाकी रुपये से वह काम पूरा हो जायेगा। मैं भी एक पब्लिक का नुमाइन्दा हूं। कहा जाता है कि पब्लिक की मेमोरी शार्ट है लेकिन उसके नुमाइन्दों की मेमोरी इतनी शार्ट नहीं हो सकती। पब्लिक ने क्या राय दी और उसने क्या राय नहीं दी और किस तरह से खर्चा घटाया गया है ये सब बातें आ चुकी हैं, अखबारों में छप चुकी हैं और यहां की किताब में भी मौजूद हैं। उस पर इसरार करना ठीक नहीं है।

उसी के बिना पर मैंने उनसे यह अर्ज कर दिया था कि वे अपने प्रस्ताव को वापस ले लें। मुझे वाणिज्य हो गयी थी कि इसका तबको करना शक्य है। एक बात जो मैं अर्ज कर सकता हूँ वह यह कि यह प्रस्ताव रहे या न रहे। मैं कुवर साहब को दावत देता हूँ कि वे स्कोम बना लें और उसका खर्चा जोड़ लें फिर हम उसको फैसला कर लेंगे कि उसमें प्रेक्टीकेबिलिटी कितनी है। जहाँ तक उसकी कमी का सवाल है, उनमें डिफेंड्स का सवाल है उसको मैंने पहले ही अर्ज किया कि उसमें जो कमी है उसको बतलाया जाय और आगे को उसकी बढ़ाया जाय। मैंने उन बातों को जो यहाँ पर कही गई हैं उनको दिलचस्पी के साथ सुना इसलिए कि मेरे मित्र मेम्बरान ने कहीं। हमारे मूवर साहब की ही तक्रारी ऐसी रही जिससे कम्प्यूजन पैदा हो जाता है। मैं तो इस क्वेर साफ कहता हूँ कि उसको हर एक जान जाये। अब यह कि आसमान साफ है फिर भी कोई कहे कि नहीं बादल नज़र आते हैं तो मैं मजबूर हूँ। लेकिन यह समझता हूँ कि कुंवर साहब ने प्रस्ताव इसलिए नहीं पेश किया कि खतरा है बल्कि इस गरज से पेश किया कि मुल्क में ऐसे आदमी तैयार होने चाहिये जो वक्त जरूरत पर काम आये। इस चीज को गवर्नमेंट ने आपसे पहले समझा था और उसको गुरु भी किया है। अब आप जो चीज चाहते हैं उसे अमल में किसी जगह बँड कर सोच लें फिर मैं उसको मानने को तैयार हो जाऊंगा।

डिप्टी चैयरमैन—The question is

In order to meet any threat of aggression, external or internal, and to assist the permanent armed forces in times of national emergency, this Council recommends to the Government to make military education a compulsory subject for the students in the intermediate classes.

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

(इस समय ४ बजे चैयरमैन ने सभापति का आसन ग्रहण किया।)

प्रस्ताव कि काशी के घाटों के सम्बन्ध में शीघ्र कार्य आरंभ किया जाय

श्री सभापति उपाध्याय—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से काशी के घाटों के विषय में यह प्रस्ताव उपस्थित करना चाहता हूँ :

“यह विधान परिषद् सरकार का ध्यान काशी के घाटों की शोचनीय दशा पर दिलाती है। परिषद् की राय में इनकी रक्षा अविलम्ब करना आवश्यक है। परिषद् सिफारिश करती है कि तत्सम्बन्धी कार्य शीघ्र आरम्भ कर दिया जाय।”

मे इस विषय पर कुछ प्रकाश डालना चाहता हूँ। काशी की प्राचीन स्थिति किसी से छिपी नहीं है। इसका महत्व भी किसी से छिपा नहीं है काशी के प्राचीन होने के अनेक प्रमाण मिलते हैं। ऋषि व्यास ने पुराण में वर्णन किया है जिससे मालूम होता है कि पुराणों से पहले की काशी स्थित है। उन्होंने कहा है कि काशी दिवोदास राजा की राजधानी थी। इसके अतिरिक्त यह भी पुराणों में मिलता है कि सब देवताओं का वहाँ आगमन हुआ है। कोई देवता ऐसा नहीं है जिसकी स्थिति काशी में न हो। इसलिये काशी के घाट प्राचीन हैं और वे देवताओं तथा ऋषियों के नाम पर प्रसिद्ध हैं। इसलिये उनकी रक्षा करना आवश्यक है। परन्तु बाद में जिन लोगों ने घाटों का निर्माण किया है उनके नाम से भी घाट प्रसिद्ध हुये। जब घाट नहीं बने थे तो इतिहास देखने में यह आता है कि जहाँ चौक है वहाँ पहले गंगा जी थीं। पर धीरे धीरे घाट बनते गये और अब गंगा जी घाटों के किनारे बहती हैं। अस्सी से लेकर वरुणा तक गंगा जी घनुषाकार में बहती हैं। काशी में यह विचित्र बात है कि गंगा जी वहाँ घाटों के पास से नहीं हटती हैं यद्यपि दूसरी जगह भी घाट बने हुये हैं लेकिन अक्सर गंगा जी उन घाटों को छोड़ कर दूर चली जाती हैं। आज काशी के घाटों की बहुत दुर्दशा हो रही है और वह बहुत ही जीर्ण-शीर्ण हो गये हैं। आपको मालूम होगा कि बूंदी का कोरा गिर गया है और उससे बहुत हानि हुई है। बहुत से मकान गिर गये हैं। अब यदि सुधार नहीं किया गया

[श्री सभापति उपाध्याय]

तो गंगा जी का प्रवाह शहर के अन्दर चला जायगा। इसी तरह से मेरा अनुमान है कि जो और घाट हैं जिनकी दशा खराब है और जो अभी गिरे हुए नहीं हैं लेकिन जिनके गिरने की सम्भावना है या जो टूट गये हैं उनकी इजीनियरों से जांच कराई जाय और उसके बाद उनको मरम्मत कराई जाय। प्रश्न यह हो सकता है कि जिन घाटों को लोगों ने बनाया है या जिनको जनता ने बनाया है उनको वह लोग क्यों न बनवाये या मरम्मत करावें। इसके विषय में मुझे यह कहना है कि जो लोग घाट बनवाने वाले हैं या जो जनता है आज उसकी दशा ऐसी नहीं है कि वह घाटों की मरम्मत करवा सके। उनमें आज धनभाव है। ऐसी अवस्थामें वह घाटों की रक्षा नहीं कर सकते। एक विशेषता और भी है कि जब अस्सी से बरुणा तक नौका पर आप सायं या प्रातः जायें तो बड़ा मनोरम दृश्य घाटों का दिखाई पड़ता है। कहीं पर जप, कहीं पर तप, कहीं पर सन्ध्या, कहीं पर हवन इत्यादि हुमा करते हैं। जो लोग देशाटन के लिये आते हैं वह भी इन दृश्यों का फोटो लेते हैं। यह हमारा एक दृश्य नगर है और इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य हो जाता है। सरकार यह कह सकती है कि उसके पास धन नहीं है और वह किस प्रकार से सहायता करे। मेरा इसके लिये यह कहना है कि सभी लोग काशी की यात्रा करते हैं उन पर किसी तरह का कर लगा दिया जाय और जो दूसरे लोग वहां रहते हैं उन पर भी इसका कुछ बोझ डाला जाय, कुछ म्यूनिसिपैलिटी दें तो यह काम आसानी से हो सकता है। इस तरह से जो आप ही वह काशी के घाटों की रक्षा करने में लगाई जाय। काशी की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। यहां पर कोई २०० घाट हैं। संस्कृत की एक पुस्तक है जिसमें सभी घाटों का वर्णन है। परन्तु वह पुस्तक मुझे मिली नहीं। इसमें कोई दो सौ घाटों का वर्णन है। मैं इससे अधिक प्रकाश नहीं डाल सकता इसकी जांच सरकार स्वयं कर ले और जिस तरह से भी हो सके वह काशी नगरी के घाटों की रक्षा करे।

श्री प्रभु नारायण सिंह— माननीय अध्यक्ष महोदय, काशी के घाटों के सम्बन्ध में तथा उनकी मरम्मत के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव इस सदन के सामने आया है उसके सम्बन्ध में कोई दो राय नहीं हो सकती हैं। मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये केवल इसलिये नहीं खड़ा हुमा हूँ कि चूंकि मैं काशी का हूँ। उसका एक दूसरा पहलू है जिसकी वजह से इस पर ध्यान जाना चाहिये। काशी एक प्राचीन नगरी है। सदियों से काशी संस्कृत का केन्द्र रहा है जिसके सम्बन्ध में माननीय उपाध्याय जी ने बातें बतलाई हैं। लेकिन इसके साथ साथ महात्मा बुद्ध के पदार्पण के बाद काशी का स्थान बहुत ऊंचा उठ गया और आज हमारे देश में काशी, सारनाथ, बुद्ध गया और लुम्बी ऐसे स्थान हो गये हैं जो अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के स्थान हो रहे हैं। ऐसी हालत में इन स्थानों के सम्बन्ध में हम जो राय दे रहे हैं उसका एक अन्तर्राष्ट्रीय महत्व है। आज हम इस बात को देखते हैं कि बहुत से अन्तर्राष्ट्रीय यात्री कई कई मुल्कों से इन स्थानों को देखने आते हैं और इस तरीके से यदि इन स्थानों की यदि समुचित व्यवस्था हो तो उसका नतीजा यह होगा कि आगे चल कर एक स्थायी भावना सहयोग का वातावरण दूसरे देशों के साथ पैदा कर सकेंगे। महात्मा बुद्ध ने जो विश्व को शान्ति का सन्देश दूसरे मुल्कों को दिया उससे काशी का सम्बन्ध है। इस नाते से हमारी अन्तर्राष्ट्रीय या वैदेशिक नीति है उससे हम काशी के महत्व को बढ़ाते हैं। इस पर उसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। बर्मा, जापान और चीन ऐसे बहुत से मुल्क हैं जो बौद्ध दर्शन से बहुत प्रभावित रहे हैं। ऐसी हालत में जब हम काशी को देखते हैं और उसकी प्राचीनता को देखते हैं और साथ ही साथ ऐसी परिस्थिति में इस बात का ख्याल रखते हैं कि उसको अन्तर्राष्ट्रीय ख्याल है तो काशी पर हमारा विशेष ध्यान जाता है। इसके साथ ही साथ यह भी बात है कि काशी में बहुत से यात्री विदेशों से आते हैं। यदि काशी का जीर्णोद्धार हो तो इसका नतीजा यह होगा कि विदेशों से मुद्रायें हमारे यहां आयेंगी। अब सवाल यह उठता है कि काशी के घाटों को कैसे ठीक किया जाय। जिन स्थानों का नाम अभी लिया गया है उनकी

मरम्मत के लिये सरकार इस बात को कह सकती है कि काफी पैसे की जरूरत होगी। जिस रूप में हम इन घाटों को देखना चाहते हैं उस रूप में बनाने में करोड़ों रुपये की जरूरत पड़ सकती है यह सही बात है। अध्यक्ष महोदय, इसकी जिम्मेदारी किसी प्रांतीय सरकार पर हम नहीं डाल सकते लेकिन कम से कम यह बात जरूरी होती है कि प्रांतीय सरकार को ध्यान इस पर विशेष तौर पर देना चाहिए और इसका कारण यह है कि काशी हमारे सूबे में स्थित है इस कारण प्रांतीय सरकार का ध्यान होना चाहिए। सवाल यह उठता है कि जो रुपये का सवाल है वह कैसे हल किया जाय। यदि इस मसले पर सरकार गौर करे और सोचे और जैसा कि सारनाथ के सम्बन्ध में है तो मेरी अपनी राय यह है कि विदेशी मुल्कों से इसके लिये मदद मिल सकती है। जैसा कि बर्मा सारनाथ को इमदाद देता है उसी प्रकार काशी के घाटों को मदद पहुंचाने की आवश्यकता है। मगर यह कार्य सरकारी आधार पर ही किया जाय। इसके साथ ही साथ इसमें ऐसे प्रतिनिधियों को शामिल किया जाय जो कि जनता के प्रतिनिधि हों और उसी आधार पर काशी का निर्माण अन्तर्राष्ट्रीय इमदाद को ध्यान में रखते हुये किया जाय। यदि आज इन घाटों की मरम्मत के लिये हिन्दुस्तान में रुपया उतर जाय तो मैं समझता हूं कि काफी तादाद में रुपया उतर सकता है। माननीय मंत्री यदि इस तरफ ध्यान दें तो मैं समझता हूं कि आज काशी के घाटों का जो सवाल है वह दूर हो जायेगा और वह फिर नहीं उठेगा बल्कि काफी रुपया जमा किया जा सकता है। यह तो फंड की बात रही कि वह रुपया कहाँ से आये। सरकार कहती है कि हमारे पास रुपया नहीं है तो कम से कम वह यह कर सकती है कि इस तरह का प्रचार किया जाय। इसमें सभी लोगों का सहयोग अवश्य होगा चाहे वह सरकारी है या गैर-सरकारी। इसके लिये केन्द्रीय सरकार पर भी दबाव होना चाहिए कि वह रुपया दे। प्रांतीय सरकार से जितनी सहायता हो सके उतना उसे अवश्य करना चाहिए। इसमें जो पहिला अभिप्राय है वह मरम्मत करने का है। वह शायद इस गम्भीरता से रखा गया है कि आज इन घाटों के खराब हो जाने से काशी की हालत बहुत खराब है। कई मुहल्लों पर इसका असर पड़ने की आशंका है। जहां तक इस बात का सवाल उठता है कि इतना काफी तादाद में रुपया चाहिए तो उसके साथ ही यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि इन घाटों के ठीक न होने से कितने मकानों पर प्रभाव पड़ेगा और आज जो मकानों की शक्ल में खड़े हैं वहां कुछ दिनों के बाद कुछ भी नहीं रहेगा। तो सबसे पहिला सवाल मरम्मत का है। यह ध्यान में रखना चाहिए यदि ऐसा नहीं किया गया तो कई मुहल्लों की हालत खराब हो जायेगी जिनमें काफी रुपया लगा हुआ है उनके धराशायी होने का डर है। उसका नतीजा यह होगा कि जहां हम सोचते हैं कि काफी रुपया इनकी मरम्मत पर लग जायेगा वहां करोड़ों रुपये की सम्पत्ति का नुकसान भी हो जायेगा। जैसा कि मैं पहले अर्ज कर चुका हूं कि यह बोझ प्रांतीय सरकार पर नहीं डालना चाहिए। काशी और सारनाथ बहुत महत्व रखते हैं इसलिए हिन्दुस्तान की जनता से चन्दे के रूप में या जिस शक्ल में हो सके रुपया लेना चाहिए और वह काशी के घाटों में लगाना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं सभापति जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री हकीम ब्रजलाल वर्मन—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव यहां पर रखा गया है उसका मैं हृदय से समर्थन करता हूं। काशी हमारे देश की पुनीत और ऐतिहासिक नगरी है, उसकी ओर सारे देश के लोगों का आकर्षण पाया जाता है। इसलिए मैं यह जरूरी समझता हूं कि इस कार्य को सरकार को अपने हाथ में लेना चाहिए। लेकिन इस सम्बन्ध में मेरा यह भी संशोधन है कि हमारे उत्तर प्रदेश में राम-कृष्ण और बुद्ध-ऐसे आत्माओं ने जन्म लिया और लीलायें कीं। ये ऐतिहासिक स्थान-वृन्दावन, मथुरा और अयोध्या हैं। यहां पर लाखों यात्री जाते हैं। इसलिए इन सब ही जगहों के घाटों का ध्यान रखना चाहिए। वृन्दावन में एक-एक घाट लाखों रुपये का है और वह बेकार पड़े हुए हैं। इसी तरह से मथुरा और अयोध्या भी पवित्र स्थान हैं जहां पर सारे

[श्री हकीम ब्रजलाल वर्मन]

हिन्दुस्तान के लोग आते हैं। इस प्रदेश की सरकार को सारे घाटों का ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि अभी श्री प्रभुनारायण सिंह जी ने कहा कि सरकार को घाटों की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए, मैं इस बात को मानता हूँ और यह प्रस्ताव जो सभापति जी ने पेश किया है उसका समर्थन करता हूँ।

श्री राजा राम शास्त्री—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव सभापति जी ने उपस्थित किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूँ। मैं इस प्रस्ताव को एक राष्ट्र के महत्व की दृष्टि से सामने रखना चाहता हूँ। जैसा कि अभी कहा गया कि काशी का महत्व एक धार्मिक दृष्टि से यहां पर रखा गया है। मैं समझता हूँ कि काशी का महत्व इस दृष्टि से भी है कि अगर हम इस पर एक प्राचीन संस्कृति और परम्परा की दृष्टि डालें तो यह कहा जा सकता है कि यह एक केन्द्र बिन्दु रहा है और इस निगाह से वास्तव में भारत की आत्मा काशी में है और यदि कहा जाय कि वास्तव में काशी में भारत की राष्ट्रीय आत्मा है तो अनुचित न होगा। इसी तरीके से प्रत्येक राष्ट्र के पास नाना प्रकार की पूंजी होती है और मेरा विश्वास है कि अगर भारत की नैतिक पूंजी के रूप में हम देखें तो काशी हमारे देश की नैतिक पूंजी है और उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। प्राचीन समय में ऐसी चीजों का महत्व समझते हुये सदैव सरकारों ने और धनपतियों ने मुक्त हस्त होकर दान की प्रणाली को स्वीकार करके उनकी रक्षा की है। सच्ची बात तो यह है कि चाहिये तो यह था कि हमारे देश के धनीमानी व्यक्ति को इस बात का गर्व सा होता है कि वह धर्म में विश्वास करता है और दान में विश्वास करता है और हमारा ख्याल है कि इससे बढ़ कर कोई भी काम नहीं हो सकता है कि जिसके लिये स्वयं काशी की दुर्दशा को हमारे सूबे के धनीमानी व्यक्ति दुरुस्त करते। अगर यह चीज हुई होती तो आज इस सदन की सरकार के सामने यह प्रार्थना न करनी पड़ती कि काशी की दशा की ओर ध्यान दिया जाय। सचमुच में तो यही कहूंगा कि हमारे देश का यह पतन है कि दुनिया की तमाम बातों के लिये हमारे पास पैसा हो सकता है, आप किसी भी शहर में चले जायें, जो हमारे देश के रईस हैं और जो सिनेमाओं पर रुपया खर्च कर सकते हैं वह १०, १० और १२, १२ सिनेमा खोल सकते हैं और नाना प्रकार की दूसरी चीजों पर बिना बात रुपया खर्च कर सकते हैं लेकिन जहां कोई ऐसा सवाल आ गया, वहां पर सचमुच इससे बढ़ कर क्या शोचनीय दशा हो सकती है कि ऐसे लोगों के होते हुये भी आज हमें सरकार के सामने खड़े होकर प्रार्थना करनी पड़ती है कि कैसे रुपया प्राप्त हो सकता है और कैसे काशी को हालत सुधर सकती है। मुझे भी अपने बचपन में काशी में ४ साल तक शिक्षा प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैं यह समझता हूँ कि कोई भी व्यक्ति चाहे देखने की दृष्टि से या चाहे और काम से अगर काशी में जाय और वहां गंगा जी के किनारे जाये तो निश्चय ही उसके भी दिल में कष्ट होगा। अगर एक धार्मिकता की दृष्टि से नहीं तो सौन्दर्य की दृष्टि से आप देखें काशी में गंगा के किनारे आप जायें, चाहे रात का समय हो चाहे प्रातःकाल का समय हो, किस प्रकार से एक इच्छा होती है कि हम गंगा में बिहार करें, उस पार गंगा क जायें और वहां से काशी नगरी की सुन्दरता देखें। शायद हमारे दिल में यह भावना न पैदा हो क्योंकि हम इस देश के ही निवासी हैं और हमेशा ही उसे देखते रहते हैं इसलिये हमारे दिल में उन चीजों का इतना महत्व न हो लेकिन मेरा विश्वास है कि दुनिया के कहीं के भी लोग अगर काशी जायें तो वह उसकी अवश्य ही सराहना करते होंगे और गंगा जी का सौन्दर्य उनके हृदय से मिटता न होगा। दूसरे मुल्कों के लोग जो इन चीजों के महत्व को जानते हैं कि राष्ट्रीय पूंजी की किस प्रकार रक्षा की जाती है और जो यह जानते हैं कि इस प्रकार की देश की जो गर्व की चीजें हैं उनको कैसे प्रतिष्ठित रखा जाता है वह अगर इस देश की पूंजी को इस तरह से नष्ट होते हुये देखेंगे तो उनके दिल में भी ठेस लगती होगी कि जो काशी इतना महत्वपूर्ण स्थान है, कैसे इस देश के लोग हैं जो इसकी ओर ध्यान नहीं देते हैं और क्यों नहीं ध्यान देते हैं। उनके दिलों ने इन्हीं बातों का ख्याल रहता है।

आज सचमुच मेरे दिल में ख्याल आता है कि सभापति जी ने इस प्रस्ताव को पेश करके बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कराया है। सरकार से हमारी प्रार्थना है कि आज तक तो यह दस्तूर इस भवन के अन्दर रहा है कि कितना ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव क्यों न हो, चाहे कितना ही अच्छा प्रस्ताव क्यों न आये, लेकिन कठिनाइयों की वजह से आर्थिक संकट की वजह से, या किन्हीं भी कारणों से सरकार ने इन प्रस्तावों को नहीं माना और अगर कोई प्रस्ताव आया तो वह वापस होता रहा और अगर वह यहां पर पेश भी किया गया तो असफल होता रहा। मेरा विश्वास है कि यह एक ऐसा प्रस्ताव है कि जिसमें सदन के अन्दर कोई दो मत नहीं होंगे चाहे सरकारी पक्ष हो या चाहे विरोधी पक्ष हो, सभी एकमत से यह समझते हैं कि वास्तव में काशी की गिरती हुई दशा को ठीक करना है और उसकी शोचनीय दशा को पुनः ठीक करना चाहिये। मुझे यह ख्याल होता है कि जो प्रस्ताव कांग्रेसी पक्ष की तरफ से या किसी भी पक्ष की तरफ से आता है तो आरम्भ में सरकार की राय पूछ ली जाती है कि उस विषय को वापस होना चाहिये। अगर यह मालूम हो जाय कि सरकारी पक्ष का क्या कहना है या जो प्रस्ताव सदन के अन्दर रखा गया है उस पर सरकार की राय जानने के बाद ही यहां भवन विचार करता है कि हमें क्या करना चाहिये और क्या नहीं करना चाहिए। यही मैं आशा करता था कि इस सज्जेक्ट पर पहले सरकार की बात सुन ली जाय कि इस सम्बन्ध में उसकी क्या राय है। अगर मान लिया जाय अध्यक्ष महोदय, सरकार शुरू में ही उसको स्वीकार कर लेती तो मैं समझता हूं कि सचमुच में ही एक बहुत बड़ी समस्या हल हो जाती और सदन का वक्त फिर बेकार न लिया जाता। इसीलिये मैं जरूर इस बात की दरखास्त कहंगा मंत्री महोदय जी से अगर वह अब भी इस सज्जेक्ट पर कुछ कहें तो इसमें ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है और सरकार हमको बतलाये कि इसके बारे में उसकी खुद की क्या राय है और अगर यह प्रस्ताव ऐसा है कि वह सरकार को स्वीकार हो, तब तो यह सब बहुत बेकार है और अगर किन्हीं कारणों से यह सरकार को स्वीकार न हो सके, तब इस पर सदन के और लोगों को गौर करना चाहिये जैसा कि इस सदन के अन्दर बहुत से सुझाव भी पेश किये गये हैं। मैं मानता हूं और वित्त मंत्री को विदबास दिलाता हूं कि जब कभी भी सदन के सामने ऐसी बातें आई हैं, तो उनका यह कहना कि उनके पास पैसा नहीं है, और किसी भी काम करने के लिये चाहे वह कितना ही अच्छा क्यों न हो आपके हाथ पर बंध जाते हैं, यद्यपि आपकी यह बिल्कुल इच्छा रहती है कि आप हर एक ऐसे काम को करें, मगर अपने आस-पास की परिस्थिति देखकर आप कहते हैं कि हमारे हाथ पांव बंधे हुये हैं और चाहते हुये भी आप ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो जितनी भी ऐसी बातें आई हैं, उस मौके पर काफी सुझाव दिये गये हैं और मैं इस बात को मानता हूं कि स्वेच्छापूर्वक हमारे सूत्र के धनियों से इस बात की अपील हो और उनसे रुपया लेकर इन घाटों की दशा को सुधारना चाहिये। मैं आशा करता हूं कि धनी-मानी व्यक्ति इसके लिये अवश्य आगे आयेंगे और वे लोग इसके लिये रुपया देंगे। और इसके लिये जिसके पास पैसा होगा वह स्वेच्छा से दे देगा। तो इसके लिये हुक्मत का यह कहना कि पैसे का प्रबन्ध कहां से हो सकता है यह उचित नहीं है मेरा ख्याल है जैसा कि बतलाया गया है अगर हुक्मत पैसे का प्रबन्ध करना चाहती है तो वहुऐसा प्रबन्ध कर सकती है। क्योंकि जैसे कहा गया है कि जहां चाह है वहां राह। अगर सरकार काम करना चाहे तो कर सकती है। इस कार्य के लिये मेरा विश्वास है कि कई लोग आगे आयेंगे और मैं आशा करता हूं कि जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव यहां पेश किया गया है वह स्वीकार होगा और यह सिर्फ स्वीकार ही नहीं होगा बल्कि इस पर अमल भी होगा और इस तरह से सचमुच काशी के गिरते हुये घाटों-को बनाया जायेगा और हम दुनिया के सामने यह दिखला देंगे कि हमारे राज्य की चीजें कितने महत्व की हैं और उसके लिये हमें कितना गर्व है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभापति जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उपाध्याय जी के प्रस्ताव का हृदय से समर्थन करत हूँ। मुझे खेद है कि यह प्रस्ताव उपाध्याय जी को इस सदन के सामने रखना पड़ा। मेरी सम्मति में तो बनारस म्युनिसिपैलिटी को इस बात की कोशिश करनी चाहिये थी कि वह घाटों की तरफ ध्यान देती उसे सरकार का ध्यान घाटों की शोचनीय अवस्था की ओर भी आकृष्ट करना चाहिये था परन्तु बनारस म्युनिसिपैलिटी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और उपाध्याय जी को यह प्रस्ताव इस सदन के सामने रखना पड़ा। इस कार्य से आपने हिन्दू जनता का बड़ा उपकार किया है। अध्यक्ष महोदय, काशी की प्राचीनता का वर्णन करना आप के सामने अनावश्यक है। आप काशी के निवासी हैं, आप के वंशज काशी में रहते आये हैं, आप के पिता जी ने काशी में विद्या पढ़कर विश्व में ख्याति प्राप्त की है। राजा हरिश्चन्द्र वहीं हुए, भगवान बुद्ध ने पहले सारनाथ में अपने धर्म का प्रचार किया। काशी अनादिकाल से धर्म और संस्कृति का केन्द्र रहा। उसके बारे में कहना इस भवन में अनावश्यक है। कौन हिन्दू ऐसा है जो काशी के गौरव को नहीं जानता, जो वहाँ शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता, कौन ऐसा हिन्दू है जिसके हृदय में काशी का नाम लेते ही अनेकों स्मृतियाँ जागृत नहीं हो जातीं। जैसा कि उपाध्याय जी ने कहा कि काशी में देवता विराजते हैं मैं समझता हूँ कि माननीय मंत्री जी पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उनके सम्मुख दृष्टकोण रखना पड़ेगा। काशी के घाटों की दशा शोचनीय है। वे काशी की उत्तम निधि हैं। जितने योरोप के यात्री आते हैं धर्म के ख्याल से नहीं प्राकृतिक सौन्दर्य की वह प्रशंसा करते हैं। अनेकों प्राचीन पुस्तकों में काशी का वर्णन है। दूसरे अभी बून्दी घाट की बात कही गई यदि उसका निर्माण न किया तो निकटवर्ती भवन गिर जायेंगे और बहुत नुकसान होगा। इन सब बातों पर सरकार को विचार करना चाहिये। अब सवाल यह पैदा होता है जैसा शास्त्री जी ने कहा कि रुपया कैसे आयेगा यह सही है कि जनता गरीब है और राजे—महाराजे और धनी मानी लोग अब नष्ट हो गये हैं उनमें सामर्थ्य नहीं है कि रुपया दे सकें परन्तु मेरा विश्वास है कि यदि धर्म के नाम पर सरकार जनता से अपील करेगी तो कोई मनुष्य ऐसा नहीं है जो इस कार्य में कुछ न कुछ न दे। मैं यह समझता हूँ कि जिस तरह से गवर्नमेंट आर्कोलाजिकल डिपार्टमेंट का जो ऐक्ट है उसके द्वारा प्राचीन इमारतों की रक्षा करती है उसी प्रकार घाटों की रक्षा का भी उपाय हो सकता है। इसमें कोई कठिनाई न होगी। सरकार जनता से यदि अपील करेगी और गवर्नमेंट आफ इंडिया से अपील करेगी की घाटों की रक्षा के लिये यह कार्य करना आवश्यक है, तो मैं समझता हूँ कि इसकी पूर्ति में कठिनाई न होगी। मैं इन शब्दों के साथ इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ और आशा करता हूँ कि गवर्नमेंट इस प्रस्ताव पर ध्यान देगी और इसे कार्यान्वित करेगी। बार-बार प्रस्ताव वापस लेना, अस्वीकार करना वैधानिक दृष्टि से कुछ अच्छा नहीं है। जैसे माननीय मंत्री जी ने दूसरे प्रस्ताव पर कहा कि अगर मैं इसको मान भी लूँ तो २ महीने के बाद आप ही लोग उसकी मुखालिफत करेंगे। मैं आपसे कहता हूँ कि आप देखेंगे कि हम लोग यह नहीं कहेंगे बल्कि हम लोग यह कहेंगे कि गवर्नमेंट पक्ष ने क्या किया है। गवर्नमेंट कठिनाइयों का वर्णन करेगी और उनके साथ हम लोग सहानुभूति रखेंगे और सहयोग करेंगे और कहेंगे कि इस तरह से इस उद्देश्य की पूर्ति होती है।

श्री गिरधारी लाल (सार्वजनिक निर्माण मंत्री)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जितनी बातें काशी का यहां के घाटों के विषय में कही गई उसमें मैं समझता हूँ किसी भी हालत में दो रायें नहीं हो सकतीं। लेकिन वास्तव में सच बात तो यह है कि बनारस के जो घाट हैं उनके लिये सरकार ने अब तक क्या क्या कार्य किया इस बात से थोड़ा भी हमारे माननीय सदस्य परिचित होते तो शायद इस प्रकार का प्रस्ताव लाने की जरूरत न समझते। वास्तव में बात तो यह है कि घाटों की अब तक किसी भी हालत में सूबे की सरकार के ऊपर बनाने की जिम्मेदारी नहीं थी। यह जितने भी घाट हैं, श्रद्धा, प्रेम और भक्तिवश बहुत से धनी मानी लोगों ने बनारस में बनाये थे और उन्हीं के द्वारा इनकी मरम्मत और देखभाल अब तक होती रही। लेकिन इसके बाद सन् १९४८ में सब से पहले यह प्रश्न य० पी० सरकार के सामने आया। उस वक्त एक बाढ़ आयी और जहां मामूली और घाटों को नुकसान पहुंचा होगा हनुमान घाट

जो था उसको बहुत काफी नुकसान पहुँचा। वास्तव में बात तो है कि वह घाट बिल्कुल टूट गया और सरकार ने उस घाट का २ लाख ८० हजार रुपये खर्च करके पुनर्निर्माण किया। वहाँ के करीब करीब सभी घाटों की हालत खराब है। इसके बाद यू० पी० सरकार ने अपने चीफ इंजीनियर के जरिये उन घाटों का सर्वे कराया और अन्दाजा लगाया गया कि इस सब कामों के लिये कितने धन की जरूरत पड़ेगी।

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद—क्या एस्टीमेट हुआ।

श्री गिरधारी लाल—चार करोड़ से ज्यादा रुपये इसके निर्माण में खर्च होने का इस्टीमेट है जो कि आप समझते होंगे कि सब की सरकार के बस की बात नहीं है। यू० पी० सरकार के सामने यह प्रश्न रहा है कि किस तरीके से वह इतनी बड़ी धनराशि को निकाले। इस बीच में दो और घाट एक मीर घाट और दूसरा मां आनन्दमयी घाट भी क्षतिग्रस्त हो गये और उनका भी प्रश्न सरकार के सामने आया। इसमें भी सरकार और बनारस के जितने भी प्रमुख नागरिक थे उनके बीच में यह तय हुआ कि जितना खर्च होगा उसमें आधा रुपये यू० पी० सरकार देगी और आधा जनता में से प्रबन्ध करके इन घाटों का पुनर्निर्माण किया जायगा और साथ ही एक लाख रुपये मां आनन्दमयी घाट के पुनर्निर्माण के लिये जनता ने दिया भी। इस तरह से दो लाख रुपये मां आनन्दमयी घाट पर खर्च किया गया। साथ ही इस वर्ष का बजट जो है उसमें चार लाख रुपये मां आनन्दमयी घाट और दूसरे घाटों की मरम्मत के लिये रखा गया है। इसी बीच ब्रह्मा घाट या बूझी का कोटा, जिसका जिक्र माननीय सदस्य ने किया है, का प्रश्न भी सरकार के सामने आया। मैंने जैसा कि पहले बतलाया कि चार करोड़ रुपये का जो मसला था वह इतना बड़ा सवाल है और सरकार के सामने यह परेशानी रही कि किस तरह से इतनी बड़ी धनराशि का इन्तजाम किया जाय। जैसा कि अभी माननीय सदस्य प्रभु नारायण सिंह जी ने और दूसरे साहबान ने सुझाव दिया है उससे यह साफ जाहिर है कि न सिर्फ यू० पी० की सरकार न सिर्फ हमारे प्रान्त के नागरिक बल्कि काशी और काशी के जो घाट हैं जिनसे बनारस की रक्षा हो रही है उनके प्रति हिन्दुस्तान के सम्पूर्ण नागरिकों की श्रद्धा और भक्ति है। इस बात को देखते हुये एक सरकारी कमेटी बनाकर जितने धन की जरूरत होगी उस सवाल को तय करने के लिये एक कमेटी बनाना तय किया गया है जो कि मैं समझता हूँ बहुत जल्द आपके सामने बात आ जायगी। जनता में से भी इसके लिये रुपये इकट्ठा किया जायगा और जितना यू० पी० गवर्नमेंट दे सकेगी, देगी तथा गवर्नमेंट आफ इंडिया भी मदद करेगी। इस प्रकार से मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसी स्थिति में यह प्रस्ताव लाने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। इसलिये मैं यह विरोध करूँगा कि माननीय सदस्य इस प्रस्ताव को वापस ले लें।

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद—क्या कमेटी सरकार ने बना दी है।

श्री गिरधारी लाल—कमेटी बनाने का निश्चय कर लिया गया है। मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी एलान हो जायगा।

श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम—जो जो सूरतें उनकी मरम्मत करने के लिये हो सकती हैं वे हो रही हैं अगर आप चाहते हैं तो उनको पढ़कर सुना दूँ। गवर्नमेंट आफ इंडिया से भी रुपये लेने को है।

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद—गवर्नमेंट आफ इंडिया का क्या रख है।

श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम—गवर्नमेंट आफ इंडिया से भी लिखा पढ़ी हुई है और पब्लिक से भी रुपये लेने की तजवीज हो सकती है और वह भी हो रहा है। इसके लिये इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट और म्यूनिसिपल बोर्ड दोनों काम कर रहे हैं। इसके लिये यह भी सोचा जा रहा है कि एक कमेटी बना दी जाय यह प्रस्ताव है वह बाद में आया है। यह कार्य तो पहले से हो रहा है।

श्री राजा राम शास्त्री—मंत्री महोदय ने जो कुछ कहा उससे मालूम होता है कि जो प्रस्ताव की भावना है उसकी बात को गवर्नमेंट स्वीकार कर रही है और जल्दी भी है।

श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम—जैसा प्रस्ताव है और जिस तरीके से आप चाहते हैं उस तरीके से हम कर रहे हैं। अगर हम इस प्रस्ताव को मान लेते हैं तो यह बात आइडेंटिफाई हो जायेगी कि इस काम को गवर्नमेंट कर रही है और इस काम की पूरी जिम्मेदारी गवर्नमेंट पर है। इस प्रस्ताव को मान लेने से जो नुस्तरा काम करने की स्थिति है वह खत्म हो जायेगी। इन्फ्रूवमेंट ट्रस्ट और म्युनिसिपल बोर्ड समझ लेंगे कि यू० पी० गवर्नमेंट ने इसका पूरा बोझ ले लिया है। इसके अलावा मेरे पास इस सिलसिले में एक नोट भी है, जो मेम्बरान साहबान उसे देखना चाहें वे देख सकते हैं।

श्री राजाराम शास्त्री—मैं चेयर से कहना चाहता हूँ कि आप उसको देख लीजिये और सरकार उस काम को आरम्भ कर दे।

चेयरमैन—यह चेयरमैन का काम नहीं है।

श्री सभापति उपाध्याय—अध्यक्ष महोदय, यदि सरकार इस संबंध में कार्य कर रही है तो मैं अपने प्रस्ताव को वापस लेता हूँ।

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद—मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि एक आध प्रस्ताव सरकार कर ले तो हम लोगों को इससे बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा।

श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम—हाउस ने जो चाहा वह काम जब पहले ही से हो रहा है तो फिर इस रीजोल्यूशन को पास करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी मैं सुन रहा हूँ कि हमारी जगान से जो भी बात निकलती है वह किसी तरह से काबिले कबूल नहीं होती। यह तो दूसरी चीज है।

श्री राजाराम शास्त्री—अगर यह बात है तो मैं यह कहूंगा कि आप ज़िद कर रहे हैं।

श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम—प्रजबूर हूँ। ज़िद की बात नहीं है।

चेयरमैन—क्या सदन की अनुमति है कि यह प्रस्ताव वापस लिया जाय ?

श्री राजाराम शास्त्री—आप भवन की राय लें। हम नहीं चाहते कि प्रस्ताव वापस हो।

चेयरमैन—प्रश्न यह है कि यह प्रस्ताव वापस लिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और विभाजन के पश्चात् स्वीकृत हुआ)

पक्ष में (२४)

१—श्री अब्दुल शकूर नजमी

२—श्री इन्द्र सिंह नयाल

३—श्री कन्हैयालाल गुप्त

४—श्री कुंवर महावीर सिंह

५—श्री केशर नाथ खेतान

६—श्री कृष्ण चन्द्र जोशी

७—श्री जगन्नाथ आचार्य

८—श्री जमीलुर्रहमान क़िदवई

९—श्री निजामुद्दीन

१०—श्री निर्मलचन्द्र चतुर्वेदी

११—श्री प्रेम चन्द्र शर्मा

१२—श्री पन्ना लाल गुप्त

१३—श्री बालक राम वैश्य

१४—श्री बाबू अब्दुल मजीद

१५—श्री बंशीधर शुक्ल

१६—श्री हकीम ब्रजलाल वर्मन

१७—श्री मानपाल गुप्त

१८—श्री राना शिव अम्बर सिंह

१९—श्री राम नन्दन सिंह

२०—श्री लालता प्रसाद सोनकर

२१—श्री विश्वनाथ

२२—श्री शिव सुमरन लाल जोहरी

२३—श्री सत्य प्रेमी उपनाम हरिप्रसाद

२४—श्री सरदार संतोष सिंह

विपक्ष में (४)

१—डाक्टर ईश्वरी प्रसाद

३—श्री प्रभु नारायण सिंह

२—श्री कुंवर गुरु नारायण

४—श्री राजाराम शास्त्री

चेयरमैन—प्रस्ताव के पक्ष में २४ मत हैं और विपक्ष में ४ मत हैं इसलिये सदन की इजाजत से प्रस्ताव वापस लिया गया।

सदन का कार्य-क्रम

चेयरमैन—कल के लिये कार्यक्रम इस प्रकार रहेगा। पहले डेट रिडक्शन बिल फिर सेल्स टैक्स बिल और उसके बाद फायर सर्विसेज बिल।

श्री कुंवर गुरु नारायण—श्रीमान् मैं यह जानना चाहता हूँ कि फाइव डियर प्लान के लिये मैंने लिखा था क्या मुझे लीडर आफ दौ हाउस यह बतायेंगे कि उस के विषय में क्या हुआ।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—मैं इस वक्त आज इतना ही कर सकता हूँ कि डिस्कशन का वक्त दिया जायगा और उसके लिये तारीख बाद में तय की जायगी।

चेयरमैन—सदन की बैठक कल ११ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।
(कौंसिल ४ बजकर ५१ मिनट पर दूसरे दिन, २६ अक्टूबर को ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गई)

लखनऊ,
२८ अक्टूबर, १९५२

श्यामलाल गोविल,
सेक्रेटरी, लेजिस्लेटिव कौंसिल,
उत्तर प्रदेश।

तहसील आंवल? यह ठीक है कि उपरोक्त फ़ार्मसी में दवायें

सं० ता०
१८-१०-५२

१—श्री प्रताप चन्द्र आज़ाद—या फ़ार्मसी आयुर्वेद की शिक्षा, विद्याथियों आयुर्वेदिक आतुरालय के लाखों रोगियों को यह मालूम है कि तहसील आंवल में आयुर्वेदिक दवायें विक्रय भी की जाती हैं जिनका लाभ की जनता को प्रति कष्ट उठाने पड़ने।

(ख) यदि हां, तो सरकार इसका यह सत्य है कि उपरोक्त फ़ार्मसी में बीस श्री गिरधारी लाल (साब)

(ख) सड़क निर्माण—कामों का रोकत फ़ार्मसी में २० से अधिक आदमी सड़कों की उन्नति पर ध्यान दिया जिसमें रस शास्त्री, वैद्य, लेखक, औषधि

श्री प्रताप चन्द्र आज़ाद—) क्या यह सत्य है कि उपरोक्त फ़ार्मसी के मुताबिक सड़कों कब तक बनना?

श्री गिरधारी लाल—जब करोगी कि वह उपरोक्त फ़ार्मसी तथा १९५६ ई० में पहिला करण खत्म होरखती है?

श्री प्रताप चन्द्र आज़ाद—
जो बरेली से बवायु को रोड जाती रही है।
बनाने की योजना है?

यह ठीक है कि उपरोक्त फ़ार्मसी में काम

श्री गिरधारी लाल—इसका नाम एल० एच० आयुर्वेदिक कालेज

२—श्री प्रताप चन्द्र आज़ाद
२८-१०-५२ से सिरौली और चम्पतपुर से सिरौलीयन श्री ललितहारी आयुर्वेदिक कालेज

(ख) यदि हां, तो सरकार उठा रही है? यह ठीक है कि उपरोक्त फ़ार्मसी में

श्री गिरधारी लाल—(त २५ रु० या उसके निकट है?)

(ख) यह सड़कों अब जिला बोर्ड जिम्मेदारी अब बोर्ड की है। यह ठीक है कि उपरोक्त फ़ार्मसी में

श्री प्रताप चन्द्र आज़ाद—सा बोर्ड के रूप में नहीं दिया जाता है? बोर्ड के अन्दर कब आई हैं। सूचना नहीं है।

श्री गिरधारी लाल—यह ठीक है कि उपरोक्त यूनिवर्सिटी कन्सोलिडेशन बोर्ड, बरेली (प्रदन संख्या १—११ जो कि २७ जून, १९५१ को थे परन्तु अम मंत्री की इच्छानुसार और बोर्ड की भी मांग थी?

एल० एच०

१—श्री शिव सुमरन साक्या यह ठीक है कि सरकार ने वेतन ठीक है कि पीलीभीत में एक एल० Judication) में भेजने से

डाक्टर सम्पूर्णानन्द (गुह) कालेज शिक्षा संस्था को प्रस्तावित होगा कि उपरोक्त फ़ार्मसी में काम नाम से संबोधित होता है। ना क्यों उचित नहीं समझा गया?

प्रश्नोत्तर

तहसील आंबला जिला बरेली के कच्चे मार्ग

सं० ता०
१८-१०-५२

१—श्री प्रताप चन्द्र आज़ाद (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—(क) क्या सरकार को यह मालूम है कि तहसील आंबला जिला बरेली में जाने के पक्के मार्ग न होने के कारण वहां की जनता को अति कष्ट उठाने पड़ते हैं और व्यापार करने में भी कठिनाई होती है ?

(ख) यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री गिरधारी लाल (सार्वजनिक निर्माण मंत्री)—(क) जी हां।

(ख) सड़क निर्माण—कार्य का द्वितीय चरण बनाया जा रहा है और उसमें इस इलाके की सड़कों की उन्नति पर ध्यान दिया जायगा।

श्री प्रताप चन्द्र आज़ाद—क्या माननीय मंत्री यह बतलायेंगे कि इस द्वितीय चरण के मुताबिक सड़कें कब तक बनना शुरू हो जायेंगी ?

श्री गिरधारी लाल—जब पहिला चरण खत्म हो जायेगा तभी होगा। सन् १९५६ ई० में पहिला चरण खत्म होने की मियाद है।

श्री प्रताप चन्द्र आज़ाद—क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि इस द्वितीय चरण में जो बरेली से बदायूं को रोड जाती है और उसमें जो राम गंगा नदी पड़ती है उस पर पुल बनाने की योजना है ?

श्री गिरधारी लाल—इसकी इत्तिला इस वक्त मेरे पास नहीं है।

२८-१०-५२

२—श्री प्रताप चन्द्र आज़ाद—(क) क्या यह सच है कि इस तहसील में मगोरा से सिरौली और चम्पतपुर से सिरौली जाने वाले दोनों मार्ग कच्चे और खराब दशा में हैं ?

(ख) यदि हां, तो सरकार उनको पक्का और अच्छी दशा में बनाने के लिये क्या क्रदम उठा रही है ?

श्री गिरधारी लाल—(क) जी हां।

(ख) यह सड़कें अब जिला बोर्ड के अधीन हैं इसलिये इनकी देख भाल तथा निर्माण की जिम्मेदारी अब बोर्ड की है।

श्री प्रताप चन्द्र आज़ाद—क्या माननीय मंत्री यह बतलायेंगे कि ये सड़कें जिला बोर्ड के अन्दर कब आई हैं।

श्री गिरधारी लाल—१ अगस्त, १९५२ में ली गई हैं।

(प्रश्न संख्या १—११ जो कि मंगलवार २८ अक्टूबर, सन् १९५२ ई० के लिये रखे गये थे परन्तु अम मंत्री की इच्छानुसार २९ अक्टूबर, सन् १९५२ ई० के लिये स्थगित किये गये थे।)

एल० एच० आयुर्वेदिक कालेज, पीलीभीत

१—श्री शिव सुमरन लाल जौहरी (स्थानीय संस्थाएं निर्वाचन क्षेत्र)—क्या यह ठीक है कि पीलीभीत में एक एल० एच० आयुर्वेदिक कालेज फ़ार्मैसी है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द (गृह तथा अम मंत्री)—पीलीभीत में ललितहारी आयुर्वेदिक कालेज शिक्षा संस्था के अंतर्गत औषधि निर्माण विभाग है, जो ललितहारी आयुर्वेदिक फ़ार्मैसी के नाम से संबोधित होता है।

२—श्री शिव सुमरन लाल जौहरी—क्या यह ठीक है कि उपरोक्त फ़ार्मैसी में दवायें बेचने के लिये बनायी जाती हैं और बेची जाती हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—उपरोक्त शिक्षा संस्था फ़ार्मैसी आयुर्वेद की शिक्षा, विद्यार्थियों को देने के उद्देश्य से संस्थापित है। इसका कार्य आयुर्वेदिक आयुर्विद्यालय के लाखों रोगियों को मुफ्त औषधि प्रदान करना है। शेष निर्मित औषधियाँ विक्रय भी की जाती हैं जिनका लाभ विद्यालय तथा आयुर्विद्यालय को प्राप्त होता है।

३—श्री शिव सुमरन लाल जौहरी—क्या यह सत्य है कि उपरोक्त फ़ार्मैसी में बीस से अधिक आदमी काम करते हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—यह सत्य है कि उपरोक्त फ़ार्मैसी में २० से अधिक आदमी काम करते हैं जिनकी कुल संख्या इस समय ३६ है जिसमें रस शास्त्री, वैद्य, लेखक, औषधि वितरक, पेषक सम्मिलित हैं।

४—श्री शिव सुमरन लाल जौहरी—(क) क्या यह सत्य है कि उपरोक्त फ़ार्मैसी फ़ैक्टरीज ऐक्ट के अनुसार अब तक रजिस्टर्ड नहीं है ?

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वह उपरोक्त फ़ार्मैसी तथा प्रबन्धक के खिलाफ़ क्या कार्यवाही करने का इरादा रखती है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—(क) जी हाँ।

(ख) इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

५—श्री शिव सुमरन लाल जौहरी—क्या यह ठीक है कि उपरोक्त फ़ार्मैसी में काम करने वाले मजदूरों की एक रजिस्टर्ड यूनियन है जिसका नाम एल० एच० आयुर्वेदिक कालेज फ़ार्मैसी वर्कर्स यूनियन है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हाँ। यह यूनियन श्री ललितहारी आयुर्वेदिक कालेज फ़ार्मैसी, वर्कर्स यूनियन के नाम से रजिस्टर्ड है।

६—श्री शिव सुमरन लाल जौहरी—क्या यह ठीक है कि उपरोक्त फ़ार्मैसी में काम करने वाले मजदूरों की न्यूनतम वेतन मंजूरी रहित २५ रु० या उसके निकट है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हाँ।

७—श्री शिव सुमरन लाल जौहरी—क्या यह ठीक है कि उपरोक्त फ़ार्मैसी में काम करने वाले मजदूरों को फ़ार्मैसी के लाभ में से कोई पैसा बोनस के रूप में नहीं दिया जाता है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—सरकार को इसकी सूचना नहीं है।

८—श्री शिव सुमरन लाल जौहरी—क्या यह ठीक है कि उपरोक्त यूनियन ने अपनी कुछ डिस्प्यूट्स (disputes) कन्सोलियेशन बोर्ड, बरेली (Conciliation Board, Bareilly) के पास २७ जून, १९५१ को भेजे थे और क्या अन्य बातों के अलावा उनमें वेतन वृद्धि और बोनस की भी मांग थी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हाँ।

९—श्री शिव सुमरन लाल जौहरी—(क) क्या यह ठीक है कि सरकार ने वेतन वृद्धि और बोनस के मामलों को ऐडजुडिकेशन (adjudication) में भेजने से इन्कार कर दिया ?

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त फ़ार्मैसी में काम करने वालों को न्याय प्राप्त करने की सुविधा दिया जाना क्यों उचित नहीं समझा गया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—(क) जी हाँ।

(ख) इस मामले को सरकार ने ऐडजुडिकेशन में भेजने योग्य नहीं समझा।

१०—श्री शिव सुमरन लाल जौहरी—(क) क्या यह ठीक है कि उपरोक्त झगड़े में कन्सोलिडेशन बोर्ड के चेयरमैन ने अपनी रिपोर्ट श्रम कमिशनर के पास भेजी थी?

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार उसकी एक नक़ल मेज पर रखने की कृपा करेगी?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—(क) जी हाँ।

(ख) जी नहीं। ऐसी रिपोर्ट गोपनीय रक्खी जाती है।

११—श्रीशिव सुमरन लाल जौहरी—क्या सरकार का इरादा है कि अब उपरोक्त फ़ार्मसी में काम करने वालों को न्याय प्राप्त करने की सुविधा दे और वेतन तथा बोनस के झगड़े को ऐडजुडिकेशन (Adjudication) में भेजे?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—सरकार इस मामले को ऐडजुडिकेशन के उपयुक्त नहीं समझती।

[प्रश्न संख्या १७—२० जो कि मंगलवार, २८ अक्टूबर, १९५२ ई० के लिये रक्खे गये थे परन्तु गृह मंत्री की इच्छानुसार २६ अक्टूबर, सन् १९५२ ई० के लिये स्थगित किये गये थे।]

१७—२०—श्री प्रताप चन्द्र आजाद (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—स्थगित।

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारों के ऋण

कम करने का विधेयक

श्री चरण सिंह (माल मंत्री)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि सन् १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारों के ऋण कम करने के विधेयक पर विचार किया जाय।

जिस वक्त से जमींदारी खत्म करने का सिलसिला चला तो १९४६ में विधान सभा ने एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी की इस बात की रिपोर्ट भी है कि जब जमींदारों से उनकी जायदाद ली जायगी तो उनको जो मुआविजा दिया जायगा वह बाजारों की क्रोमत के अनुपात या तनासुब के मुताबिक कर्जाजात को घटा कर दिया जायगा। इस तरह का आश्वासन और इत्मानान सरकार ने जमींदारों को दिया था। जब जमींदारी अबालिशन बिल २४ जनवरी, सन् १९५२ ई० को अधिनियम बना, तो बहुत से लोगों को मौका मिला और मुकदमेबाजी हुई। हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमे गये। ५ मई, सन् १९५२ ई० को यह अधिनियम बंध करार दिया गया और पहली जुलाई, सन् १९५२ ई० को यह ऐक्ट लागू हो गया। यह बिल असेम्बली से पास हो चुका है और अब परिषद में विचार करने के लिये प्रस्तुत किया गया है। इसमें ३-४ मोटे-मोटे उसूल हैं, एक तो यह कि जितने कर्जाजात हैं उनकी तहकीकात अदालत करे। लेकिन जो डिगरी वगैरा इजरा हो गई है, उनकी जिम्मेदार अदालत नहीं होगी कि वह उनको ग़ज़त में दे और लोगों के नाटिस में लाये। दूसरे यह कि जिस हद तक कर्जा लेंडेड प्रापर्टी के ऊपर उस जायदाद का है जिसको स्टेट ने एक्वायर कर लिया है या जो उत्तर प्रदेश के राज्य में निहित हो गये हैं तो जो भी कर्जा ऐसी जायदाद के हिस्से में आते हैं या जिस क्रदर हिस्सा उस जायदाद के हिस्से में पड़ता है, वह कर्जा घटाया जायगा और जो दूसरे क्रज उस जायदाद पर हैं, उससे किसी प्रकार का वास्ता नहीं है। क्योंकि उसूल इस विधेयक का यह है कि जिस क्रदर उसकी पेइंग कैपिसिटी कम हो गई है या किसी मक़रूज की या असामी को पेइंग कैपिसिटी कम हो गई है, उस क्रदर उसको राहत या सहूलियत मिलनी चाहिये। अगर यह मान लें कि एक आदमी को एक फैंकटरी है और एक गांव है और दोनों रहन थे तो उसका एक ही कर्जा घटाया जा सकता है। इसलिये जो शहरी जायदाद है उस पर कर्जा कम नहीं किया जायेगा। इसलिये फैंकटरी का कर्जा कम न कर के, जितना कर्जा ट्रान्सफर आफ़ प्रापर्टी ऐक्ट की दफ़ा २२ के मातहत उस गांव के हिस्से में आता है, उसका उतना कर्जा कम कर दिया जायेगा और जितना कर्जा फैंकटरी के जिम्मे पड़ता है, तो चूँकि वह उसका है तो उस असामी का मक़रूज शख्स की पेइंग कैपिसिटी बरकरार है लिहाजा जो मैं आता था वह नहीं घटाया जायेगा, यह इसका दूसरा उसूल है।

तीसरा उसूल यह है कि जिस कर्ज से ऐसा समझा जाता हो कि उसका पब्लिक इन्टरेस्ट पर असर पड़ता है, अगर वह घटा दिया गया तो वह कर्जा भी नहीं घटाया जायेगा। अगर देखा जाय तो लाजिकली उस कर्ज को स्ट्रिक्टली घटा दिया जाना चाहिये, लेकिन दुनिया में ऐसे उसूल, जिनको लाजिकली मान लिया गया हो, बहुत कम हैं। हर समय एक उसूल का दूसरे उसूल के साथ परस्पर सामन्जस्य करना पड़ता है, और उनको रिकान्साइल करना पड़ता है। तो ऐसी सूरत में पब्लिक इन्टरेस्ट की बात आती है जहां कि व्यक्तिगत इन्टरेस्ट को सरेन्डर करना पड़ता है। अगर वह सार्वजनिक हित में रोड़ा अटकाता है तो व्यक्तिगत का प्रश्न छोड़ देना पड़ता है। तो जो कर्ज ऐसे हैं कि जिनको घटाने से सार्वजनिक हित को धक्का पहुंचने का अन्देश हो, मसलन इस्टेट की तकाबी दगैरह, कोआपरेटिव बैंक या दूसरे रेलिजस प्वाइन्ट की चीजें हैं, तो उस हालत में वह कर्जा नहीं घटाया जायेगा। इसमें शेड्यूल बैंक का कर्जा न घटाने की बात है। इसके अलावा यह भी है कि जो आड़ी कर्जा जायदाद का इस्टेट पर पड़ता है, यानी जिसको जमींदारी विनाश और लेंड रिफार्म बिल में डिफाइन किया गया है, आम भाषा में यह है कि लेंड प्रॉपर्टी के ऊपर जो कर्जा पड़ता है तो उसका जो कम्पेनसेशन है, उस कम्पेनसेशन की इसमें जितनी इजाजत है, उतना कम्पेनसेशन या रिहैबिलीटेशन ग्रान्ट से उसूल हो जायगा। जो बाक्री बचे या जो बाक्री रुपया है वह फिर किसी जायदाद से वसूल नहीं हो सकेगा, यह भी इसमें रक्खा गया है। तो इसका नतीजा यह होगा कि इस से बहुत ज्यादा आराम जमींदारों और मीजूदा भूमिधरों को मिलेगा।

साथ ही साथ यह भी विचार किया गया है कि उनका सारा प्रतिकर या अनुदान कर्ज में न रहे। इससे वसूलयाबी भी हो सकती है ताकि रुपया उसके लिये बचा रहे। अब देखना यह है कि किस कदर रुपया घटाया जाय। कर्ज घटाने की बात, अध्यक्ष महोदय, मैंने आपकी इजाजत से माननीय सदस्यों के सामने रख दी लेकिन वह घटाया किस तरह से जाय, यह एक समस्या है। देखना यह है कि इसमें पैमाना क्या होगा। पैमाने के लिये हमने यह रखा है कि जायदाद की कीमत जितनी भानी जाती थी तो अब उसको किस तरह से आंका या जांचा जाय। इसके लिये हमने रखा है कि इन्कम्बर्ड स्टेट ऐक्ट जो है, उसके मुनाफे से निकाल दिया जायेगा। उसमें से गुणा करके उसकी कीमत निकाली जा सकती है। बर्ना किसी जायदाद की क्या कीमत है, यह नहीं पता चल सकता और इसके लिये हम कोई सीधा सा फारमूला नहीं रख सकेंगे। अब भी मुस्तकिल तरीके से कोई यह नहीं कह सकता है कि उसकी जायदाद की क्या कीमत थी और आप वैसे कह सकते हैं कि इतनी मान ली जाय। तो जायदाद की असली कीमत जानने के लिये इनकम्बर्ड स्टेट ऐक्ट में इससे जो अब तक की बात थी, उससे गुणा कर दिया जाय और इससे जितनी भी रकम आये वह उस जायदाद की कीमत मानी जायेगी और जो प्रतिकर मिल रहा है, प्रतिकर और उसे गुणा देने के बाद जो रकम आयेगी और प्रतिकर का जितना बाकी गुणा देने के बाद कीमत आई है, तो उससे जितनी कीमत हो उतनी कीमत कर्ज की कर दी जाय। मसलन बाकी आय मान लीजिये मेरठ के जिले में ३२ है और कम्पेनसेशन मिल रहा है और नेट इन्कम का ३२ गुना मेरठ का जो होता है जिस पर कि कर्जा होगा, तो उसका कर्जा ८/३२ कर दिया जायेगा और मान लीजिये दूसरी जगह १६ है तो वहां ८/१६ हो जायेगा। मान लीजिये गोरखपुर में मल्टीपुल ७० है तो सेलेक्ट कमेटी ने और उसके बाद प्रांतीय सभाने यह तय किया है कि मल्टीपुल चाहे जितना बड़ा हो, लेकिन वह ४० से ज्यादा नहीं माना जायेगा। लेकिन वहां ८/७० हो जायेगा। इस तरह से लोगों का प्रतिकर ज्यादा भी हो सकता है, इसलिये उसको ज्यादा से ज्यादा ४० कर दिया गया है लेकिन कहीं मसलन एक जगह १३ है, १६ है या १७ है, तो बाकी जगह २३, २४ और २७ भी हैं। इसलिये ४० से ज्यादा कहीं नहीं है और इससे कम जितना चाहें रख लें। तो वह इनकम्बर्ड स्टेट ऐक्ट से मल्टीपुल करके यह रकम दी जा रही है तो मेरे विचार से यह मोटी सी चीज है जो कि इस विधेयक का मतलब है और अगर इसके सिलसिले में कोई संशोधन बाद में होगा, तो मैं उनका जवाब फिर दूंगा। इस समय आपकी इजाजत से मैं इतना ही कहना चाहता हूँ।

श्री कुंवर गुरु नारायण (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय चरण सिंह जी को अक्सर यह शिकायत रही कि जमींदार जो हैं वह सरकार जो कुछ भी करती है उसको शक्ति का एक भी अल्फाज अदा नहीं करते हैं। लेकिन मैं एक बड़े असमंजस में हूँ वह यह है कि अगर इस विधेयक का विरोध करता हूँ तो डेटर्स की नाराजी हमारे ऊपर होती है और अगर सपोर्ट करता हूँ तो क्रेडिटर्स की नाराजी होती है। ऐसी हालत में मैं नहीं समझता कि किन शब्दों में मैं अपने विचार इस विधेयक के संबंध में रखूँ। फिर भी एक या दो बातें जो मुझको महसूस हुईं उसकी ओर मैं माननीय मंत्री जी और सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। श्रीमन्, मुझको आश्चर्य है कि यह विधेयक लाया ही क्यों गया। इसके लाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। सबसे पहले जो मैं कहना चाहूँगा वह यह कि इसके स्टेटमेंट आफ आबजेक्ट ऐन्ड रोजन्स में जो हमारी सरकार ने लिखा है उसका पहला हिस्सा मैं पढ़ कर सुनाता हूँ—

“The Zamindari Abolition Committee made certain recommendations as regards the scaling down of intermediaries' debts. They pointed out that our existing debt laws do not take into account the special problem of the reduced capacity of the land-lord to pay his debts due to abolition of zamindari. To the Committee it appears sound and equitable that after the abolition of Zamindari the land-lords' debts should be reduced in proportion to the reduction in the value of his land consequent upon the abolition.”

जो मैंने स्टेटमेंट आफ आबजेक्ट ऐन्ड रोजन्स को पढ़ा और उसके बाद जब मैंने विधेयक की शाराओं को पढ़ा तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि उसमें भी जमींदारी के साथ डिस्क्रि-मिनेशन किया गया है, वसूलन यह चीज ठीक नहीं थी। जो वैल्यूेशन प्रापर्टी की है इसे विधेयक में उसके घटाने और बढ़ाने की बात की गई है। जमींदारों के कर्ज को स्केल डाऊन करने की बात इस विधेयक में की गई है। इस बिल के अनुसार १० हजार या उससे कम के ही जमींदारों के ऋणों को स्केल डाऊन करने की ही व्यवस्था सी मालूम होती है और उससे ज्यादा मालगुजारी जो देते हैं उनके लिये कोई व्यवस्था नहीं है। तो इस चीज को जब मैं देखता हूँ तो मालूम होता है कि सरकार ने इसमें फर्क किया है। एक कैटेगरी बनाई गई है उन जमींदारी की जो १० हजार से कम देते हैं और दूसरे वे हैं जो ज्यादा देते हैं तो ऐसी हालत में जो अबोलिशन कमेटी की रिपोर्ट थी तो सरकार ने उसके उद्देश्य के खिलाफ यह डिफरेंसिएशन क्यों किया। जिस हिसाब से छोटे जमींदारों की प्रापर्टी की वैल्यू (value) घट सकती है तो उसी हिसाब से बड़े जमींदारों की भी घट सकती है। इसमें इस प्रकार का डिफरेंसिएशन हरगिज न होना चाहिये। यह उसूलन गलत चीज है। शायद सरकार की दृष्टि में यह चीज होगी कि जो बड़े जमींदार हैं और जैसा कि ज्यादातर ऐन्टानिस्टिक एंटीट्यूड गवर्नमेंट का उनके प्रति रहा है, इनके पास सरमाया ज्यादा है, इनको पैसे की जरूरत नहीं है, लेकिन यहां पर किसी के पास सरमाया ज्यादा है या सरमाया ज्यादा नहीं है, जब जमींदारी अबोलिशन कमेटी ने कोई उद्देश्य लिया और हमने उसको मान लिया तो फिर उसी उद्देश्य से सारा काम होना चाहिये। हमारे पास यह दृष्टिकोण न होना चाहिये कि हम इस कैटेगरी के जमींदारों को इसमें नहीं लाते; इस कैटेगरी के जमींदारों को इस में लाते हैं। हमारे सामने सब के कर्ज के लिये एक समान व्यवस्था का दृष्टिकोण होना चाहिये और उसूल भी यही कहता है।

श्री चरण सिंह—ऋज सभी लोगों के घटाये जा रहे हैं। यह भ्रम आपको कहां हो गया।

श्री कुंवर गुरु नारायण—अगर ऐसा है तो तो मुझे इस के संबंध में कुछ नहीं कहना है। सरकार का विचार तो ऐसा था। खैर दूसरी चीज मैंने जो इस विधेयक में देखी वह यह थी कि इस विधेयक में जो सरकार पास करने जा रही है उसके अनुसार यह होगा कि जो

रिहबिलिटेशन ग्रांट है और कम्पेनसेशन है, इन दोनों को सरकार ने जोड़ दिया है। कच्चा की अदायगी के लिये। मुझे आश्चर्य हुआ, इस समय जब कि सरकार कर्ज का भार कम करना चाहती है तो उसने यह निश्चय किया कि रिहबिलिटेशन ग्रांट और कम्पेनसेशन दोनों जोड़ दिये जायें। कर्ज के भार को आधा करने में और इस बिल के अनुसार जो ३/४ हिस्सा कम्पेनसेशन का या रिहबिलिटेशन ग्रांट का होगा वह किसी कर्ज की अदायगी में काट लिया जा सकता है और एक चौथाई जमींदार के पास रह जायेगा। मुझे केवल यह निवेदन करना है कि जिस समय रिहबिलिटेशन ग्रांट का सरकार ने प्राविजन किया था उस समय यही कहा गया था कि हम पुनर्वासन भत्ता दे रहे हैं। इसको कम्पेनसेशन न समझना चाहिये ऐसी हालत में इन छोटे-छोटे जमींदारों को जिनको पुनर्वासन भत्ता दिया जायेगा अगर वह भी कर्ज में ३/४ काट दिया गया तो आप समझ सकते हैं कि जो परपन्न है रिहबिलिटेशन ग्रांट देने का वह फारफोट हो जाता है। हर जमींदार का एट टाइम्स नेट आसेट्स का जो मुआविजा होता है उसी में ३/४ कर्ज की अदायगी में काटने की व्यवस्था सरकार करे। वह तो बहरहाल कुछ ठीक ही सही, लेकिन जो रिहबिलिटेशन ग्रांट सरकार ने इसमें शरीक करदी यह उसने ठीक नहीं किया। इसका नतीजा यह होगा कि जो कुछ भी थोड़ा बहुत उनको मिलता वह भी अब न मिलेगा। माननीय मंत्री इसके ऊपर यह कह सकते हैं कि अगर हम इतना भी न करते तो यह होता कि अगर डिग्री हो जाती तो सारे का सारा मुआविजा व पुनर्वासन भत्ते से वसूल हो सकता था और पूरी की पूरी ग्रांट जमींदारों को चली जाती। यह बात सही है लेकिन जब माननीय मंत्री जी ने यह निश्चय किया और इस सरकार ने निश्चय किया कि हमको एक प्रकार की रिलीफ जमींदारों को देनी है तो उस समय यह भी निश्चय कर सकते थे कि पुनर्वासन भत्ता जमींदारों का वचा रहे। आप उस समय रिडेक्शन करते तो रिहबिलिटेशन ग्रांट को असली कम्पेनसेशन की मद से निकाल सकते थे। कर्ज तमाम किस्म के सिक्कोर कर लिये गये हैं। मिसालन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, शैड्यूल बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटी इत्यादि तो उसके पास वचा क्या।

यह बहुत ही स्माल रिलीफ है जो नहीं के बराबर है और जिसको सरकार देना चाहती है। यह तो सिर्फ कहने के लिये है कि सरकार ने जमींदारों को यह रिलीफ दी। हमने जमींदारों को कम्पेनसेशन तो दिया ही है। हम जो कुछ जमींदारों के लिये कर सकते थे वह हमने किया। क्या कहें, प्रचार मात्र तो नहीं कह सकता। वास्तव में जो जमींदारों को रिलीफ मिलनी है वह उनको नहीं मिलती है। जितना उनका कर्जा है वह सिक्कोर कर दिया गया है तब उनके पास कोई ज्यादा नहीं रह जाता है जिससे कोई खास रिलीफ जमींदारों को इससे मिल सकती है। इसके अतिरिक्त इस विधेयक में कोई खास बात नहीं है। गवर्नमेंट ने जो कुछ किया है उससे जमींदारों को कोई खास फायदा नहीं होगा। ३/४ तो कुल मुआविजा का अटेच हो सकता है और १/४ रह सकता है, लेकिन यह आन पेपर ही १/४ की बचत रहेगी। जमींदार के पास कुछ नहीं बचेगा। इस बिल के लाने से कोई फायदा नहीं है। मैं तो नहीं समझ पाया कि क्या सरकार की नीति है। इस स्माल रिलीफ को देने की क्या आवश्यकता थी। जब इतनी बड़ी सम्पत्ति चली गयी तो इस मामली रिलीफ को कोई जरूरत नहीं थी। यह जो रिलीफ है वह बेकार हो जावेगी। सब कर्ज शैड्यूल बैंक में चला जायेगा और जमींदार के पास कुछ नहीं बचेगा। यह बिल सरकार वापस कर ले तो इसमें मुझे कोई रंज नहीं होगा। यह बिल सिर्फ प्रोपेगेंडा के लिये है। मुझे इसके संबंध में और कुछ नहीं कहना है।

श्री प्रताप चन्द्र आजाद—माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे आश्चर्य हुआ जब मैंने कुंवर साहब का व्याख्यान सुना, मैं तो यह समझ रहा था कि यह बिल शायद कुंवर साहब के एम्सपेक्टेशन से अधिक होगा। लेकिन कुंवर साहब के भाषण सुनने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुँचा कि सरकार जमींदारों को रिलीफ देने के लिये कितनी भी योजनाएँ बनायें, कुछ भी करे मगर वह सब बेकार होगी। जमींदार किसी प्रकार का कोई एहसान नहीं मानता

[श्री प्रताप चन्द्र आज़ाद]

कि उसको रिलीफ मिलती है। इस रिलीफ के बावजूद भी वह यह कहने को तैयार नहीं है कि सरकार ने हमको आराम पहुंचाने के लिये कोई सहायता दी है। जहां तक जमींदारों के कर्ज का संबंध है मैं यह समझता हूं कि छोटे जमींदारों को ऐसी रिलीफ देनी चाहिये। जो छोटे-छोटे जमींदार हैं और जिनको गणना काश्तकारों में है और जो ५०० रु० तक लगान देते हैं यह कर्ज का बिल उनके लिये आना चाहिये था। ५०० रु० से ज्यादा मालगुजारी देने वाले जमींदारों के लिये यह बिल नहीं आना चाहिये था। इसलिये कि जहां तक बड़े-बड़े जमींदारों का संबंध है, उन्होंने अपने दौरान जमींदारी में जितना भी जायज या नाजायज तरीके से पैदा किया उसके बाद में समझता हूं इस बात की अब जरूरत नहीं कि उनको रिह-विलिटेशन ग्रांट का फायदा मिले। फिर भी सरकार ने उनके साथ नभ्रता का व्यवहार किया कि उनको कम्पेनसेशन दिया। असल में होना तो यह चाहिये था कि जहां इन जमींदारों का कर्जा कम किया जा रहा है वहां मेरा अपना विचार है कि एक एग्रीकल्चरल रिफार्म कमेटी बनाई जाते और जो काश्तकारों ने जमींदारों से कर्ज लिया है उसमें भी कमी होती। काश्तकारों ने जमींदारों से जो कर्ज लिया है उसमें से ६० फीसदी गलत है और वह यों है कि किसी काश्तकार ने जमींदार की जमीन लूट मगर उसके पास नजराना देने के लिये रुपये नहीं थे जिसका उन्होंने कापज लिखा लिया। जमींदारी के खातों के बाद आज भी काश्तकार जमींदारों के कर्ज से लदे हैं। ६० फीसदी काश्तकारों के कर्ज फर्जी हैं और बनावटी हैं। काश्तकार ने कभी कर्जा लिया ही नहीं। जमींदार डेट रिडेक्शन बिल के साथ काश्तकारों के भी कर्ज के रिडेक्शन का एक बिल इस हाउस में आता, तो अच्छा होता। अगर जमींदारों के कर्ज के रिडेक्शन के संबंध में बिल आया है तो मैं सरकार के सामने एक अपना यह सुझाव रखना चाहता हूं कि पहली जुलाई, १९५२ की तारीख जो इसमें रखी गई है, वह पहली जुलाई, सन् ५२ न रखी जाय बल्कि जिस तारीख से जमींदारों का खात्मा हुआ है यानी जिस तारीख से जमींदारी अबालिशन ऐक्ट बना है वह तारीख रखी जाय। इसलिये कि जमींदारों को यह मालूम हो गया था कि जमींदारी अबालिशन के बाद सरकार कोई ऐसा मेजर एडॉप्ट करेगी जैसा कि कुंवर साहब ने बतलाया कि जमींदारी अबालिशन कमेटी जो बनी थी उसने यह तय किया था कि जमींदारों का कर्जा कम किया जायगा। जब यह चीज जमींदारों को मालूम थी तो यह लाजिमी बात है कि उसके बाद जमींदारों ने बनावटी कर्ज लिये होंगे। इसलिये मेरा अपना यह सुझाव है कि पहली जुलाई, १९५२ से न रक्खा जाय। बल्कि उस तारीख से होना चाहिये जिस तारीख से जमींदारी अबालिशन ऐक्ट बना। यह दो सुझाव मैं सरकार के सामने पेश करना चाहता हूं। जहां तक डेट रिडेक्शन बिल का संबंध है मैं यह समझता हूं कुंवर साहब ने जैसा कहा कि इसको यदि वापस ले लिया जाय तो उन्हें एतराज नहीं है, यदि उनका ऐसा ही विचार है तो मुझे सरकार को यह सुझाव देना है कि इस डेट रिडेक्शन बिल का जहां तक बड़े जमींदारों से संबंध है तो उसके अन्दर कुछ ऐसी योजनाएं बनाई जावें जिससे जो बड़े जमींदार हैं यानी ५०० से ज्यादा मालगुजारी देते हैं वह न आवें। बस यही मेरे सुझाव हैं।

*श्री प्रभु नारायण सिंह (स्थानीय संस्थाओं निर्वाचन क्षेत्र)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बिल इस सदन के सामने जमींदारों के ऋण को कम करने के लिये माननीय मंत्री जी ने रखा है, उसको देखने के बाद ऐसा प्रतीत हुआ कि जिस तरीके से जिन लोगों का जितना ऋण कम किया जाना चाहिये था उसमें कोई इस तरह की बात सोची नहीं गई कि बड़े जमींदारों में और छोटे जमींदारों में भेद रखा गया होता। अभी कुंवर साहब ने जो कुछ कहा उससे ऐसा मालूम होता है कि उनको यह भ्रम था कि बड़े जमींदारों और छोटे जमींदारों में कोई भेद बिल के अन्दर है और वह मुनासिब

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

नहीं है। मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि यदि बिल में यह भेद हुआ होता तो शायद इसकी अहमियत हमारी नजरों में बढ़ी हुई होती। हम ऐसा महसूस करते हैं कि सूदखोरी शोषण का बहुत ही निष्ठुर तरीका है और हम बराबर इसको मानते आये हैं। सभी प्रकार के धर्म सूदखोरी के खिलाफ हैं। खासकर जो सोशलिस्ट हैं उन्होंने व्यक्तिगत सूदखोरी को अन्त करने की बात रखी है। आज हमारे सामने इस बात के कोई आंकड़े नहीं हैं कि खेतिहर पर कितना कर्ज है या जो जमींदार ढाई सौ तक की मालगुजारी देते हैं उन पर कितना कर्ज है। कुछ दिन पहले सरकार की तरफ से आचार्य नरेन्द्र देव की अध्यक्षता में एक कमेटी बठी थी जिसमें खेतिहर मजदूरों के कज की जांच करने की बात थी लेकिन घनाभाव के कारण वह कमेटी फंक्शन नहीं कर पाई। बहरहाल, जो कुछ भी हो, लेकिन छोटे जमींदारों के संबंध में यह निर्णय करना बहुत जरूरी है कि जो रकम उन्हें रिहैबिलिटेशन ग्रांट के रूप में मिलने जा रही है उसके संबंध में सूदखोरों के लिये हमारी क्या नीति होगी या होनी चाहिये इस पर ध्यान देना चाहिये यह सवाल उठता है कि सोशलिस्ट लोग तो जमींदारों की मदद करने की बात इस समय कर रहे हैं और कहते हैं कि छोटे जमींदारों के पुनर्वास भत्ते के संबंध में जो बिल आया है उससे उनको इम्प्रेन्ट कर देना चाहिये। सवाल इस वक्त यह है कि सूदखोरों को चुने या छोटे जमींदारों को चुने जो १०-२० बीघे की खेती करते हैं और अपनी मेहनत से अपने मुक्त की दौलत को बढ़ाते हैं। यहां पर खेतिहर मजदूर और छोटे जमींदारों की तुलना नहीं की जा रही है बल्कि तुलना इस बात की की जा रही है कि सूदखोर और छोटे जमींदारों के अन्दर किस-किस की हम तरफ़दारी करें। और मैं साफ़ तौर से समझता हूँ कि जो छोटे जमींदार हैं उनकी तरफ़दारी सरकार और हर प्रगतिशील पार्टी को करना चाहिये। जहां तक सूदखोरों का सवाल है वह पैसा किस तरह से कमाते हैं, किस प्रकार से देहातों के छोटे जमींदारों और किसानों को लूटते हैं और उनको तबाह करते हैं, यह बात छिपी हुई नहीं है। सवाल यह है कि यह जो कर्ज का रुपया है, यह किसी पूंजीपति का नहीं है जो कि उद्योग-धंधों में लगाया जा सके सवाल इस बात का है कि आया यह जो रुपया किसानों से या छोटे जमींदारों से वसूल होगा वह देश की वृद्धि में काम आयेगा या उद्योग-धंधों में लगाया जायेगा। छोटे जमींदार के ऊपर जो कर्ज है वह गांवों में रहने वाले सूदखोर महाजनों का है जो कि न तो कोई उद्योग-धंधा करते हैं और न कोई उत्पादन ही करते हैं। मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि यदि आज इस बिल में छोटे जमींदारों के कर्ज की बिल्कुल ही माफ़ी न हुई होती तो कम से कम पुनर्वास भत्ता जो छोटे जमींदारों को मिलना है उसको माफ़ी तो देना ही चाहिये था। पुनर्वास भत्ता अनुदान इसलिये दिया जाता है जिससे वह अपनी जिन्दगी को चलाने के लिये किसी तरह से अपने को क्राबिल बना सकें नहीं तो रिहैबिलिटेशन ग्रांट की कोई जरूरत नहीं थी।

हमने पहिले ही कहा था कि छोटे जमींदारों और बड़े जमींदारों में भेद होना चाहिये। पहिले यह बात थी कि तमाम जमींदारों को चाहे वह छोटे हों, चाहे बड़े सब को बराबर ग्रांट मिलनी चाहिये। हमने कहा कि छोटे जमींदारों को ज्यादा से ज्यादा मिलना चाहिये। ऐसी सूरत में अगर यह मान लिया जाये कि उनको जो कम्पेनसेशन मिलता है उसको यदि पूरा न छोड़ दिया जायेगा तो कम से कम रिहैबिलिटेशन ग्रांट को तो इन सूदखोरों को न दिलाया जायेगा। इस बात को याद रक्खा जाना चाहिये कि गांवों के अन्दर रूरल बैंकिंग नहीं है। रूरल बैंकिंग न होने के कारण छोटे-छोटे सूदखोर जाते हैं वह किस प्रकार से सूद वसूल करते हैं, इसकी कल्पना नहीं हो सकती है। ऐसी हालत में मैं समझता हूँ कि इस बिल का काम जो है छोटे जमींदारों को रिहैबिलिटेशन ग्रांट को छोड़ देना है। प्रतिकर की रकम को भी कम करना चाहिये। उसको एक चौथाई रकम को पेमेंट करना चाहिये। मैं इस बात को फिर दोहराना चाहता हूँ कि यह रुपया जो छोटे जमींदारों के पास जाता वह वस्तुतः अपनी दुकानों को खोलने में या नमक, तेल की दुकानें खोलने में नहीं लगता बल्कि ये छोटे जमींदार जिनकी हैसियत किसानों जैसी है वह खेती को बढ़ाने में यह रुपया लगाते। जो छोटी रकम इनको मिलती वह खेती में लगाते।

[श्री प्रभु नारायण सिंह]

जहाँ तक कम्पेनसेशन वॉरर की बात है उसके संबंध में जिक्र करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ और जैसा कि प्रताप चन्द्र आज़ाद जी ने भी यह सवाल उठाया है कि बड़े जमींदारों ने नज़राने की शकल में या दूसरी शकलों में इतना रुपया कमाया है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। एक यह भी सवाल हमारे सामने उठता है कि आज जो जमींदारों के कर्जों का स्केल डाउन करने का सवाल है, उसकी रकम पर वह कम्पेनसेशन न दिया गया होता तो हमें निहायत खुशी होती और हम इसे प्रगतिशील समझ कर सपोर्ट करते। जो रुपया उन्होंने कमाया है उनको बिना पर उनको कम्पेनसेशन नहीं दिया जा रहा है। लेकिन आज सवाल यह है कि हम सूदखोरों और जमींदारों के बीच में फ़र्क करें। ऐसी सूरत में जो बिल हमारे सामने बड़े जमींदारों के ऋण को कम करने के सिलसिले में आया है उसमें यह सवाल भी आता है कि उन्होंने अन अरंड इस्कम को कायाम है। लेकिन इसकी दूसरी तरफ़ ऐसे भी लोग हैं जो कि छोटे जमींदार कहे जाते हैं। जहाँ तक इनका सवाल है हम समझते हैं कि सूदखोरों और छोटे जमींदारों के चुनाव में हम छोटे जमींदारों की तरफ़दारी करते हैं। हमने बराबर छोटे जमींदारों की तरफ़दारी की है और आज भी करते हैं। हम समझते हैं कि जितनी भी पूंजी इन छोटे जमींदारों के पास होगी वह उत्पादन पर लगायेंगे।

*श्री कुंवर महावीर सिंह (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—अध्यक्ष महोदय, न्याय की दृष्टि से इस बिल का बहुत बड़ा महत्व है। सच पूछिये जब जमींदारी अबालिशन ऐक्ट आया उस वक्त से ही हम इस कमी को महसूस करने लगे। जब जमींदारी के ज़ब्त होने के बाद बहुत थोड़ा रुपया जमींदारों को मिलना है तो यह लाज़िमी है कि उन जमींदारों के ऊपर जो कर्जा है उसको भी उ.ा.हद तक कम कर दिया जाय। यह बिल जिस सिद्धांत पर बनी है, जिस बुनियाद पर बना है, मेरा अपना हयाल है कि उस को सभी पक्ष के लोग बहुत जस्ट कहेंगे। सोशलिस्ट लोग भी इसको जस्ट कहेंगे, लेकिन उनको आज सोशलिस्ट कहे या जन-सोशलिस्ट कहे क्योंकि उन के सिद्धांत में भी बहुत चेजेंज हो गये हैं। लेकिन मैं उन सोशलिस्टों से कहता हूँ जिनकी पहले लाल टोपी थी और जो सिद्धान्तः सोशलिज्म को मानते थे। उन्होंने एक तरफ़ तो इस बात को स्वीकार किया कि बिना मुआविजे के जमींदारी ख़त्म कर दी जाय किन्तु दूसरे रूप में उन्होंने इस सिद्धांत को भी स्वीकार कर लिया है कि जब बिना पैसे दिये हुये जमींदारी ख़त्म होती है तो जिनको कुछ नहीं मिला उनके ऊपर कर्जा नहीं छोड़ा जाय। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि इस सिद्धान्त का प्रतिपादन होता है कि जिनको थोड़ा दिया गया है उनसे थोड़ा लिया जाय। मैं समझता हूँ कि इस बिल के जहाँ तक सिद्धांत का ताल्लुक है, जहाँ तक इसके न्याय का ताल्लुक है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती।

एक मिसाल ले लीजिये उससे यह साफ़ हो जायगा। मान लीजिये कि एक जमींदार १०० रुपये से कम मालगुजारी देता है। १०० रुपये उसका कर्जा है और वह बुलन्दशहर का रहने वाला है। इन्कम्बर्ड ऐक्ट से मलटीप्लायी करने से १६ रुपये होंगे और इस अमेंडमेंट से पहले उसको ८१ रुपये देने पड़ेंगे। अब जो सेलेक्ट कमेटी का फारमूला आया है उसके मुताबिक़ उसको ५० रुपये देने पड़ेंगे। कुंवर साहब ने यहां पर यह भी कहा कि इससे जमींदारों को कोई फ़ायदा नहीं होगा या जिनका कर्जा है उनको भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि यह शकल सी चीज़ है। शायद उन्होंने इस बिल को अच्छी तरह से नहीं पढ़ा है, इसलिये उन को इस बात का कंप्यूजन हो गया है। उनका यह भी कहना है कि १० हजार रुपये मालगुजारी देने वालों को इससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा यह भी उनका भ्रम है। कुछ जगहों पर इस बात का भी प्रचार किया गया है कि इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा खासतौर से सेटल पर्वनमेंट के कर्जों को, कोआपरेटिव के कर्जों को और कोर्ट आफ़ वाइंड द्वारा लिये गये कर्जों को इसमें किसी तरह का हेरफेर न करना हो जनता के लिये फ़ायदेमन्द होगा। यह सभी जानते हैं कि सरकार की इकोनामिक हालत ठीक नहीं है उसके लिये उसको टेक्स लगाने की जरूरत पड़ती है तो उस वक्त कुंवर साहब कहते हैं कि सरकार उन पर तो बोझ डाल रही है।

*सदस्य ने अपना माधण शुब नहीं किया।

अब पुनर्वासन अनुदान का सवाल है, इसमें अच्छा तो यह होता कि किसी तरह का कर्जा इसके द्वारा अदा नहीं होगा। यह जो पुनर्वासन दिया जा रहा है यह कम्पेनसेशन नहीं है बल्कि मदद के लिये दिया जा रहा है। श्रीमन् जी, अगर आप देखें तो यह पुनर्वासन सिर्फ छोटे जमींदारों को दिया जा रहा है और यह कह कर मदद दो जा रही है कि वह अपना रोजगार ठीक करें और अपने रहने का ठीक से इन्तजाम करें। मैं तो इस बात का हामी रहा हूँ कि जहाँ तक पुनर्वासन का सवाल है, मैं तो सरकार से यही प्रार्थना करूँगा कि वह इसको बिलकुल छोड़ दे। अगर किसी वजह से वह ऐसा नहीं कर सकती है तो कुछ अंश तक ही छोड़ दें। क्योंकि कुछ वाक्यात ऐसे हैं जिनके देखने से ऐसा आवश्यक हो जाता है, तो फिर मैं यह प्रार्थना करूँगा कि कम से कम कुछ हद तक उस पुनर्वासन को सुरक्षित किया जा सकता है। मेरे भाई श्री प्रभु नारायण जी ने ढाई सौ रुपये के जमींदारों को इससे मुक्त करने के लिये कहा है। लेकिन मेरी तो अपनी राय यह है कि जो १०० रुपये मालगुजारी देने वाले हैं उनको सुरक्षित कर दिया जाय, तो बेहतर होगा।

श्री राजा राम शास्त्री (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—क्या इसका अमंडमेंट है ?

श्री कुंवर महावीर सिंह—जो हाँ, वह तो आपकी टेबल पर है जरा उस ओर देखने की आप कृपा करें। मैं समझता हूँ कि सरकार इस पर विशेष ध्यान देगी। इसके अतिरिक्त मुझे दो एक बातें शैड्यूल पर भी कहनी हैं। जब मैंने उसे पढ़ा तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि यह शैड्यूल आदि ट्रेरी बनाया गया है। मैं मानता हूँ कि सरकार के सामने ऐसे कोई आंकड़े नहीं थे और सरकार के सामने कोई ऐसी चीज नहीं थी जिससे कोई खास साधन निकल सकता। ताहम इन्कम्बर्ड स्टेट के मल्टीपल के ऊपर जो बहुत की गयी है वह भी गलत है। इन्कम्बर्ड स्टेट का मल्टीपल जिस वक्त बनाया गया था, उस वक्त १९४४ का जमाना था जब कि काफी अशान्ति थी। एक तो उस में वाक्यात तथा परिस्थितियों और स्थानों का लिहाज नहीं रक्खा गया था और उस आबिट्रेरी बेसिस पर उनका आज मान लेना मेरी समझ से गलत होगा और उसमें न्याय नहीं होगा। कई जगहों पर से ४० से ऊपर मल्टीपल मान लिया गया और बहुत से ऐसे स्थान हैं जहाँ मल्टीपल ७० मान लिया गया है। जहाँ तक मल्टीपल का ताल्लुक है तो गोरखपुर में कई स्थानों में मल्टीपल ७० मान लिया गया है और अगर ७० मान लिया जाता है तो जिसको १०० रुपये देना होता है उस को केवल ११ रुपये ६ आने देने पड़ेंगे और जहाँ ४० है वहाँ २० रुपये देने पड़ेंगे। और जहाँ १६ है वहाँ उस को इस अनुपात से अधिक देना पड़ेगा। श्रीमान् जी, जिस जगह का मैं रहने वाला हूँ यानी बुन्देलखंड में अगर इस अनुपात को माना जायेगा तो एक जबरदस्त जुलम होगा क्योंकि जब एक आबिट्रेरी माना गया है कि हम ७० न रख कर ४० रखते हैं तो मालूम यह भी पड़ता है कि जहाँ आपने मैक्जिमम का लिहाज रक्खा था तो उधर जो मिनिमम है, उसका भी लिहाज आप को करना होगा। क्योंकि अगर आप १६ या १७ मानते हैं या उससे कम यानी १३ मानते हैं तो फिर उसे और भी अधिक देना पड़ेगा। तो मेरी आप से दरखास्त है कि यह चीज बिलकुल गलत हो जायेगी। इस सिलसिले में मैं सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट पढ़ कर आप को सामन इस बात को जाहिर करना चाहता हूँ कि यह अनुचित होगा :—

“At the same time the debt due from the zamindars in most of the Eastern districts would be reduced by a very very much greater proportion than debts due from the zamindars in the Western districts because the multiples under the Encumbered Estates Act in the Eastern districts were far higher than those in Western districts. In portions of Bijnor, Budaun and Saharanpur the Encumbered Estates multiple is so low that there would have been practically no reduction. Encumbered Estates Act multiples do not appear to have been fixed on a rational basis. We have, therefore, decided that the multiple of the rehabilitation grant should not be taken into account at all in making the calculation and that the multiple of the Encumbered Estates Act should in no case exceed the figure of 40.”

[श्री कुंवर महावीर सिंह]

एक तरफ जब आपने यह लिहाज रक्खा है ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स का और वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स का, तो मैं यह भी प्रार्थना करूँगा कि हमारे बुन्देलखंड की तरफ भी ध्यान दिया जायेगा। वहाँ अगर १६ मल्टीपल मान लिया जायेगा तो उसका नतीजा यह होगा कि बुन्देलखंड ऐसे स्थानों के रहने वालों को अधिक देना पड़ेगा। श्रीमान् जी, जहाँ तक बुन्देलखंड का ताल्लुक है, मैं अपनी तकलीफ़ सदन के सामने अर्ज कर देना चाहता हूँ कि एक तो वहाँ के रहने वाले या मालगुजारी देने वाले गरीब हैं, या दूसरे वहाँ की ज़मीन पथरीली है जिसमें कि मुश्किल से अनाज पैदा होता है और अगर वहाँ भी इसी मल्टीपल पर विश्वास किया गया तो फिर मैं तो यही कहूँगा कि वहाँ के रहने वालों के साथ इस तरह ज्यादाती की जायेगी। इसलिये मैं बड़े अदब के साथ सरकार से प्रार्थना करूँगा और आपके द्वारा गुजरािश करूँगा कि अगर १६ की जगह २० कर दिया जाय तो बड़ी ही रिलीफ़ वहाँ के रहने वाले लोगों को मिल जायेगी। मैं एक नोट पढ़ देना चाहता हूँ कि बुन्देलखंड इनकम्बर्ड स्टेट १९३० में बनी और उसमें इस बात को कहा गया है कि उस समय बुन्देलखंड की क्या हालत थी....

“The special enquiries that have been instituted show that the debts of the land-lords have again risen in that district to a large sum and that in the districts of Banda, Jalaun and Hamirpur the indebtedness is most serious.”

एक तरफ जब यह स्वीकार किया जाता है कि उन लोगों में इनडेब्टेडनेस बहुत ज्यादा है और उसके ऊपर इस आरबेट्रेरी चीज़ को मान कर, फिर सरकार उस चीज़ को न करे, तो वह उनके साथ ज्यादाती होगी और इन सब चीज़ों में सरकार इसी नतीजे पर पहुँचेगी जिसमें कि हम लोय पहुँचे हुये हैं और जहाँ उन्होंने मेक्सिमम ४० फिक्स किया है, वहाँ यह मिनिमम २० फिक्स कर दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

श्रीमती तारा अग्रवाल (नाम निर्देशित)—श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, आज माननीय मंत्री द्वारा सदन के समक्ष जो बिल पेश किया गया है, मैं उसका स्वागत करती हूँ। मैं समझती हूँ कि जिस तरीके से हमारी सरकार ने ज़मींदारी उन्मूलन करना आवश्यक समझा और इतना बड़ा कानून पास कर लिया और इसके बाद इस बात की आवश्यकता महसूस की कि उनको राहत देने के लिये किस तरह से कोई कानून बनाया जाय और उसने उसी की आवश्यकता महसूस करते हुये ही आज सदन के समक्ष इस तरह का कानून पेश किया है। किन्तु दो चार बातें मैं माननीय मंत्री द्वारा इससे सिलसिले में स्पष्ट करना चाहती हूँ और जिस तरह से यह बिल स्पष्ट होना चाहिये था, मैं समझती हूँ कि उतना यह स्पष्ट नहीं है। मान लीजिये एक ज़मींदार है जिसने किसी से १० हजार कर्जा लिया था और जब ज़मींदार ने कर्जा लिया था, इस कानून के बनने के पहले उसने ५ हजार अदा कर दिया है और उसे अब ५ हजार की रकम देनी है। तो इस कानून के अनुसार उसके लिये ५ हजार रुपया पड़ जायेगा या १० हजार रुपया पड़ जायेगा, यह बात स्पष्ट होनी चाहिये। दूसरी बात यह है कि अगर किसी भाई-भाई में बंटवारा हुआ है और एक भाई को ज़मींदारी मिलती है, मगर दूसरे भाई को इस तरह का आश्वासन मिलता है कि ज़मींदारी के मुनाफ़े से जो आमदनी होगी उससे उसकी रकम चुका दी जायेगी तो क्या इस कानून के द्वारा उसको भी कम कर दिया जायेगा यानी उस भाई की रकम में उस की जो लिखा पढ़ी की गई है, उसमें भी कमी कर दी जायेगी या नहीं और क्या उसका देना भी हम बन्द कर देंगे। तीसरी बात यह है कि कोई नाम मात्र का ज़मींदार है और वास्तव में वह व्यापारी है और व्यापार से ही उसकी आमदनी होती है और उसने अपनी सम्पत्ति रेहन रखी है ऋण के बतौर और उसके उस ऋण के लिये लिखा-पढ़ी कर दी है, तो वह जो रकम जो ऋण की मानी जाती है, वह उसे अपने बिजनेस में लगाता है, तो ज़मींदारी के इस कानून के अनुसार अगर उसको ऋण में किया गया है और उसको हम बन्द कर देते हैं, तो क्या उस ऋण में उसको भी लागू कर दिया जायेगा। मैं समझती हूँ कि यह कानून इस उद्देश से श्रुत है क्यों कि वास्तव में यह ज़मींदार नहीं है, वह तो पूँजीपति है और उस ऋण से अपनी आमदनी वह पहले

भी करता था और उसको उस बिजनेस की आमदनी में कोई नफ़ा या नुक़सान नहीं हुआ है और कोई हानि भी नहीं हुई है, तो ऐसी हालत में उस जमींदार को जो कि नाम मात्र का जमींदार है, और उसे बिजनेस के द्वारा ऋण दिया गया है, तो उस के उस बिजनेस में कमी नहीं होनी चाहिये। मैं आशा करती हूँ कि माननीय मंत्री सहोदय इन प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करेंगे।

श्री राजा राम शास्त्री—माननीय अध्यक्ष सहोदय, जो विधेयक इस सदन के सम्मुख पेश किया गया है वह बहुत ही सामयिक है। उसकी आवश्यकता को मैं महसूस करता हूँ। इस संबंध में जो अभी तक व्याख्यान हुए उनको मैंने बहुत गौर से सुना वास्तव में मैं यह चाहता हूँ कि इस पक्ष की तरफ से छोटे जमींदारों का समर्थन किया जा रहा है उसको भी आप भलीभाँति समझ लीजिये। इसमें कोई शक नहीं है कि आज इस भवन के सामने एक विचित्र बात आ रही है। समाजवादियों की तरफ से हमेशा सरकार पर यह लान्छन लगाया जाता रहा है कि वह जमींदारों का साथ देती है और आज कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि जमींदारों के लिये समाजवादियों के दिल में रहम है। जो प्रभु नारायण जी ने व्याख्यान दिया, उस में कहा गया कि छोटे जमींदार जो हैं उनके साथ इस संबंध में रियायत की जाय। और जोरदार शब्दों में छोटे जमींदारों का समर्थन किया, तब कांग्रेस पक्ष में यह ख्याल पैदा होना स्वाभाविक है तो जो लान्छन कांग्रेस पर लगाया जाता रहा है वही समाजवादियों पर भी लगाया जा सकता है तो एक बात यह आज सामने आयी और दूसरी बात सुन कर मुझे आश्चर्य हुआ वह यह कि जमींदारी विनाश कानून के विधान सभा में पेश होने के समय से लेकर आज तक बड़े-बड़े जमींदार हमेशा इस बात का प्रचार करते रहे कि जमींदारों की तादाद इस प्रदेश में २० लाख से अधिक है और छोटे जमींदारों को साथ ले कर उन्होंने मुआविजा पाने का प्रचार किया। आज जब यह विधेयक इस सदन के सामने आया तो मैं सोच रहा था कि आज श्रीगुरु नारायण जी अपने भाषण में क्या बात कहते हैं। मैंने आज तक उनको छोटे जमींदार या ताल्लुकेदार के रूप में समझा क्योंकि हमेशा से वह छोटे जमींदारों का पक्ष लेकर तक्रारें करते रहे हैं और मेरा विश्वास था कि आज भी जब मौक़ा आयेगा तो वह दिल खोल कर छोटे जमींदारों के पक्ष में अपना भाषण करेंगे। लेकिन उनका भाषण समझने की मैंने कोशिश की तो मुझे ऐसा मालूम हुआ कि वह इस झगड़े में पड़ गये जैसा कि उन्होंने खुद कहा कि धर्म संकट में पड़ गये। संकट यह था कि अगर इस बिल का बे स्वागत करते हैं तो भी मुसीबत और विरोध करते हैं तो भी मुसीबत, यह धर्म संकट उनके सामने था। मैंने उनका भाषण सुना और मुझ पर यह असर पड़ा। हो सकता है माननीय अध्यक्ष सहोदय, वह गलत हो कि वह एक बड़े ताल्लुकेदार के साथ-साथ एक महाजन भी हैं जिनका क़र्ज़ा दूसरों पर है इसलिये उनके सामने इस विधेयक के संबंध में धर्म संकट उठा। हमारे लोग जो हमेशा इस बात को कहते रहे कि जमींदारों को मुआविजा नहीं मिलना चाहिये और डंके की चोट पर कहते रहे, लेकिन जो कुछ छोटे जमींदारों के बारे में श्री प्रभु नारायण जी ने कहा उसका मैं समर्थन करता हूँ। मुझे इस बात के कहने में कोई शर्म या लज्जा नहीं मालूम होती है। मैं इस बात को साफ़ कर देना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि सफ़ाई हो जाय। मैंने प्रतिकर का विरोध किया और विश्वास रखा कि जिस तरह से जमींदारों ने जमींदारी हासिल की है और जिस तरह से उन्होंने किसानों को चूसा है और जिस तरह से उन्होंने स्वाधीनता संग्राम में गह्वारी का काम किया है उसको देखते हुये उनको एक पैसा भी नहीं मिलना चाहिये था। और जो हमारे प्रदेश की आर्थिक हालत थी उस को भी देखते हुये हमने इस चीज का विरोध किया था और इस वक्त भी मैं सही समझता हूँ।

जमींदारी का विनाश तो हम करना चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ हमारी आंख इस बात से भी बंद नहीं थी, हम जानते हैं कि हमारे सूबे के अन्दर बड़े-बड़े ताल्लुकेदार और जमींदार इतनी बड़ी तादाद में नहीं हैं जितने कि छोटे जमींदार हैं। छोटे जमींदार भले ही छोटे जमींदार कहलाते हों लेकिन उनका अधिकांश भाग ऐसा है जिन्हें वास्तव में किसान ही मानना पड़ेगा इसलिये जब हमने नैतिकता के आधार पर विरोध किया है कि उसमें प्रतिकर न दिया जाय,

[श्री राजा राम शास्त्री]

उस मौके पर हमने यह कहा था कि जो छोटे जमींदार हैं थोड़ा सा लगान देने वाले लोग हैं, उन को जमींदारों की श्रेणी से दूर किया जाये। पर हमको ख्याल था कि जमींदारी विनाश के बाद उनकी आर्थिक स्थिति क्या होगी, हम उनको तबाह करना नहीं चाहते थे चाहे वह भले ही भूत-काल में जमींदार कहलाते रहे हों। जमींदार के नाम को इन छोटे जमींदारों ने इतना बदनाम नहीं किया, जितना बड़े जमींदार और ताल्लुकदारों के जुल्म से किसानों में जमींदार का नाम बदनाम हुआ। इसीलिये हमने भेदभाव किया। जब प्रभु नारायण जी कह रहे थे कि इस विधेयक में छोटे जमींदारों और बड़े जमींदारों के बीच भेद नहीं किया गया तब कुंवर साहब ने कहा कि आप लोग भेदभाव में विश्वास करते हैं। बेशक, अध्यक्ष, महोदय, हम इस तरह के भेदभाव में जरूर विश्वास करते हैं। एक छोटा सा जमींदार जिसकी आर्थिक स्थिति कुछ नहीं है और कुंवर साहब ने बड़े बड़े ताल्लुकदार जिनके पास लाखों की सम्पत्ति है, इन दोनों को राष्ट्र के हित में समान स्तर पर में मानने के लिये तैयार नहीं हैं। अगर कल आप भूखों मरने लगें, आपकी वही हालत हो जाये जो गरीबों की है तो मानवता के नाते हम आपके साथ भी वही वर्तव करेंगे जो गरीबों के साथ इस समय करते हैं। लेकिन जहां तक सम्पत्ति और जायदाद का ताल्लुक है, वहां हुकूमत जब तक इस तरह का भेदभाव नहीं करेगी, आवश्यकता पड़ने पर धन-पतियों पर हाथ न लगायेगी तब तक हमारा दावा है कि इन्साफ नहीं हो सकता। इस विधेयक के अन्दर भी यह बात होनी चाहिए थी कि बड़े जमींदारों के लिये आप एक तरह की धारा रखते और जो छोटे जमींदार हैं उनको दूसरी दृष्टि से देखते। हमें इस बात की बड़ी खुशी है, अध्यक्ष महोदय, कि जो बात हम कह रहे हैं, चाहे उस दृष्टि में सरकारी पक्ष के लोग भले न देखें, लेकिन में जानता हूं कि उस पक्ष में कितने ही माननीय सदस्य ऐसे बैठे हैं, जो दिल में विश्वास करते हैं कि बड़े जमींदारों का रबैया दूसरा है और छोटे जमींदारों का दूसरा है। और मुझे खुशी हुई जब कि प्रताप चन्द्र आज़ाद ने यह शब्द कहे कि डाई सौ रुपये और पांच सौ रुपये लगान देने वाले जो लोग हैं उनको इससे अलग करना चाहिये था। उन्होंने बात जरूर कही, में नहीं जानता कि जब उसी प्रकार का हमारी तरफ से संशोधन आयेगा उस मौके पर वह कहाँ तक हमारे साथ जायेंगे। अच्छा हो कि इस सदन के अन्दर चाहे सरकारी पक्ष के सदस्य हों या विपक्ष के, यहां पर पार्टियों का कोई ख्याल नहीं किया जाये। हम यहां पर सदस्य हैं, जनता के नुमायन्दे की हैसियत से हैं। हम जो कुछ कहते हैं, चाहे वह उधर से कहा गया हो अगर वह उचित है तो उसे मानने के लिये तैयार रहना चाहिये। अगर हमारी तरफ से वही बात कही जाये जो उनके दिल की है तो हमारा उन्हें समर्थन करना चाहिये। मैं समझता हूं कि जो बात प्रताप चन्द्र जी ने कही उसी चीज को जब प्रभु नारायण जी संशोधन के रूप में उपस्थित करेंगे तो वह उसका समर्थन करेंगे। मान लीजिये किसी वजह से वे संशोधन पेश न करें तो मैं माननीय मंत्री जी से दरखास्त करूंगा कि यह बात समाजवादियों की तरफ से नहीं कही गई बल्कि उन्हीं की पार्टी के मेम्बर की तरफ से कही गयी। अगर उसको मान लें, तो ठीक है।

श्री चरण सिंह—उचित चीज को ग्रहण करने के लिये हर एक तैयार है।

श्री राजा राम शास्त्री—मुझे बड़ी खुशी होगी अगर हमारे माननीय मंत्री जी यह महसूस कर लें कि अगर कभी भी भूल भटके उनकी तरफ से सत्य बात भी कह दी जाय तो उस को मान लें। जैसा कि माननीय मंत्री जी को यह बात पूरी तरह से मालूम हो गयी है। यह सत्य बात है तो इसको भी स्वीकार करना चाहिये। इसलिये छोटे जमींदारों का सवाल उठाया गया है उस पर खयाल जरूर रखिये।

आपने प्रतिकर और पुनर्वास के भत्ते को एक ही तराजू पर रख दिया है। पुनर्वास और प्रतिकर दोनों एक चीज हैं, लेकिन यह दोनों एक चीज नहीं हैं। पुनर्वास तो यह समझ कर देते हैं कि उसकी फाइनेन्शियल हालत ठीक नहीं है। प्रतिकर तो अधिकार और रियायत वाली बात है। कम्पेन्सेशन की बात एक अधिकार की बात होती है। अगर कुछ चीज लेते हैं

तो उसकी क्रीमत देते हैं। पुनर्वास का भत्ता इस रूप में मानते हैं कि आपके ऊपर संकट है और आप तबाह हो गये हैं। आपको जीवित रहने के लिये सहायता देते हैं। ये दोनों चीजें एक नहीं हो सकती हैं। यह भत्ता दिया जाता है असहायों को। कितने ही छोटे-छोटे ऐसे जमींदार होंगे कि जमींदारी के अन्त होने के बाद उनके पास जीविका के लिये कोई साधन नहीं होगा। जिससे कि वे कोई दूसरा व्यापार कर के अपनी जीविका चला सकें। ऐसे व्यक्तियों को पुनर्वास भत्ता दिया जाना बहुत आवश्यक है। हमें दुःख है कि एक हाथ से न्यायपूर्ण समझ कर माननीय मन्त्रियों को दिये और दूसरे हाथ से उसको छीनना चाहते हैं। साथ ही साथ मुझे आश्चर्य होता है कि सत्य बात कही जाय तो उस चीज को साफ़ कर दिया जाता है। जैसा कि प्रभु नारायण जी ने कहा। यह कहा जाय कि हमारे सामने दो हैं। एक तरफ जमींदार हैं और दूसरी तरफ महाजन हैं। सरकार सबको एक निगाह से देखती है। किसी की बुराई नहीं चाहती है। दुनिया में हर एक की भलाई चाहते हैं तो इस नाम पर यह दोनों को कहते हैं। अगर हम जमींदारों को रियायत देंगे तो हम महाजनों के साथ में अन्याय करेंगे। साथ ही हुकूमत के विभाग में यह बात है कि वह जमींदारों की अपेक्षा महाजन को पूंजीपति समझती है और पूंजीपति वर्ग सामाजिक उन्नति को प्रगतिशील समझता है। इसलिये इन दोनों चीजों में अन्तर करना चाहिये। जब समाजवादी इस बात को समने रखते हैं कि आप जमींदारों का साथ दे रहे हैं और पूंजीपतियों का साथ दे रहे हैं तो इस मौके पर माननीय मंत्री जी हम लोगों को समझाने की चेष्टा करते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि यह दृष्टिकोण जो आपका है कि इंडस्ट्रियलिस्ट्स देश की पूंजी को बढ़ाते हैं इसके लिये वह एक कदम आगे जाते हैं। यह जमींदार जो हैं यह दूसरे की मेहनत पर जिन्दा रहते हैं। इस तरह की बात समाजवाद की फिलासफी में कही जाती है, और इसलिये दोनों में अन्तर है। बहरहाल छोटे-छोटे जमींदारों ने जो कर्जा लिया होगा, वह टाटा बिरला से तो जाकर नहीं लिया होगा। वह कर्जा तो गांव के ही रहने वाले छोटे-छोटे महाजनों से लिया होगा जिनका काम है एक देकर दस वसूल करना। जैसा कि प्रताप चन्द्र जी ने कहा बिल्कुल सही कहा। गांव के इन महाजनों के प्रति माननीय मंत्री जी अगर उदारता दिखला रहे हैं तो मुनासिब नहीं मालूम होता। मैं तो चाहूंगा कि इस चीज को न्याय के साथ देखिये। आज इस चीज को भले ही यहां पास कर लें, मगर देखेंगे कि जो छोटे-छोटे जमींदार हैं उनको पुनः जीवित करने के लिये कितनी कठिनाई का सामना करना होगा। श्री प्रतापचन्द्र जी ही ने नहीं कुंवर महावीर सिंह जी के तरफ से भी कहा गया कि १०० रु० तक मालगुजारी देने वालों को मुक्त कर दिया जाय। माननीय अध्यक्ष महोदय, हुकूमत की तरफ से जितने भी संशोधन आते हैं काफी सलाह और मशविरे होने के बाद आते हैं। कुंवर महावीर सिंह का जो १०० रु० का प्रस्ताव है वह बहुत सोच विचार के पश्चात् पेश हुआ होगा और शायद पास भी हो जाय इस भवन में, क्योंकि यह होता रहा है कि सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव पेश होते रहे हैं वह वापस हो जाते रहे। इसलिये अब जो संशोधन आते हैं वह सोच समझ कर लाये जाते हैं। इसलिये मेरा विश्वास है कि यह संशोधन जो महावीर सिंह जी का है १०० रु० का निःसंदेह स्वीकार किया जायेगा। अगर सरकार स्वीकार नहीं करेगी तो मेरी दरखवास्त आपके जरिये माननीय सदस्यों से होगी कि आपकी पार्टी के लोग जो एक न्याय पूर्वक बात कह रहे हैं उस न्याय पूर्वक बात को स्वीकार न करना इससे बढ़कर अन्याय पूर्ण और कौन बात होगी। हमारे सूबे के १६ लाख जमींदार जो छोटे-छोटे हैं वह आपकी तरफ देख रहे हैं कि हमारी कांग्रेस की सरकार है। यदि आप कुंवर महावीर सिंह जी के इस १०० रु० की बात को स्वीकार करते हैं तो हम बिला लिहाजा इसका समर्थन करेंगे। सोशलिस्ट हैं वह-वह कांग्रेस के हैं इसका लिहाज कोई नहीं है। न्याय पूर्वक बात हो चाहे वह किसी तरफ से कही जाय। मैं विश्वास करता हूँ कि जो बात कही गई है, माननीय मंत्री जी उसके ऊपर विचार करेंगे। जो विधेयक आप लायें उसमें इस चीज का संकोच आप क्यों करते हैं। जब इतना काम जमींदारी अबालीशन का आपने कर दिया तो अब अन्त में यह रहम दिली जो छोटे जमींदारों के लिये मांगी जा रही है क्यों नहीं स्वीकार कर लेते हैं। हम तो बिच्छू के डंक को

[श्री राजाराम शास्त्री]

काटना चाहते हैं उसको मारना नहीं चाहते। मैं जमींदारी का खात्मा चाहता हूँ, मगर छोटे-छोटे जमींदारों को मारना नहीं चाहता उनको बरबाद नहीं करना चाहता। मैं क्या हूँ अपने दिल में वह भी आप अच्छी तरह जानते हैं। इसलिये छोटे-छोटे जमींदारों की रक्षा के सवाल पर आप जरा ध्यान दीजिये। अगर इस बात को मान जायेंगे तो सारे सदन की तरफ से आपके इस विधेयक का पूर्ण रूप से समर्थन होगा।

श्री इन्द्र सिंह नयाल (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक को लाने का जो उद्देश्य है उसके साथ सब को पूर्ण सहानुभूति है और मैं भी पूर्णतया उसका समर्थन करता हूँ किन्तु दो एक बातों की तरफ माननीय मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूँ जो एम्स एण्ड आब्जेक्ट्स (aims and objects) के साथ मेल नहीं खाती हैं। पहली बात तो यह है कि सिक्योरिड डेट्स (secured debts) ज्यादातर जायदाद से वसूल किये जाते हैं अक्सर कर्जदार की दीगर जायदाद से वसूल करने का समय निकल चुकता है। ६ वर्ष का समय कर्जा की वसूली का होता है। जब आदमी कर्ज लेता है तो उसके पास काफी जायदाद होती है इसलिये कर्जा देने वाला पूरी मियाद तक रुकता है और जायदाद से वसूल करना चाहता है। आज जो डिक्रीज (decrees) अदालत से दी जाती हैं वह यही दी जाती हैं कि जायदाद से रुपया वसूल कर लिया जाय। इस तरह की डिक्रियाँ अदालत से होती हैं और इन्हीं डिक्रियों का वह मुश्तहक भी होता है। इस विधेयक की धारा ८ में यह हक दिया गया है कि वह कम्पेनसेशन के रुपयों और रिहैबिलिटेशन ग्रांट (Rehabilitation Grant) के रुपयों से ३/४ ले सकता है। लेकिन यह जो हक दिया जा रहा है कि रिहैबिलिटेशन ग्रांट से भी कर्जा गिरवी का वसूल हो सकता है इससे साहूकार को बहुत बड़ा हक दिया जा रहा है। यहां पर आपका आब्जेक्ट (object) हार जाता है और जो कर्जदार हैं उन पर और बोझ लादा जा रहा है जो मौजूदा कानून में उसको नहीं है मौजूदा डिक्री में उसको यह नहीं है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जो मकसद इस कानून का है वह विधेयक की दफा के पार्ट बी से जिसके द्वारा रिहैबिलिटेशन ग्रांट से साहूकार रुपया वसूल कर सकता है वह मारा जाता है। आप साहूकार का यहां फेवर कर रहे हैं। आपने जमींदारी अबोलिशन ऐक्ट (Zamindari Abolition Act) की धारा ६ से साहूकारों के हक को खतम कर दिया, लेकिन उसके साथ-साथ क्लज सात में यह रखा है कि जो जमींदार को देना है वह सरकार कम्पेनसेशन से दे सकती है या साहूकार मुआविजे से वसूल कर सकता है कम्पेनसेशन से साहूकार जिसके हम हक दफा ६ के द्वारा ले रहे हैं वह कम्पेनसेशन से वसूल कर लेगा। किन्तु रिहैबिलिटेशन ग्रांट (Rehabilitation grant) वसूल करने का कोई हक जमींदार उन्मूलन कानून द्वारा साहूकार को नहीं दिया गया। तो जमींदारी अबोलिशन ऐक्ट जो आपने हाल ही में पास किया उस वक्त आपकी मंशा यह थी कि जमींदारों के ऊपर जो कर्ज है वह कम्पेनसेशन में से वसूल कर लिया जा सकता है। लेकिन तब सरकार की मंशा यह नहीं थी कि रिहैबिलिटेशन ग्रांट में से भी साहूकार का कर्ज अदा करना पड़ेगा। उस वक्त तो ख्याल यह था कि रिहैबिलिटेशन ग्रांट जो दिया जा रहा है वह वास्तव में रिहैबिलिटेशन ग्रांट ही है। वह इसलिये दिया जा रहा है कि जो छोटे जमींदार हैं जिनकी आर्थिक अवस्था अच्छी नहीं है वह उनके पुनर्वास में सहायता के लिये दिया जा रहा है। किन्तु इस विधेयक की दफा ८ के पढ़ने से यह मालूम होता है कि सरकार कम्पेनसेशन और रिहैबिलिटेशन ग्रांट जो दे रही है वह दोनों एक ही चीज हैं और उसका नाम भर खाली अलग कर दिया गया है। तो मैं समझता हूँ कि इस प्रकार का गलत ख्याल जो इस विधेयक से पैदा होता है वह सरकार के लिये कोई अच्छी बात नहीं है। मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि वह इस पर विचार करें। जमींदारी अबोलिशन ऐक्ट में केवल कम्पेनसेशन साहूकार को दिया गया है उसको

विधेयक की दफा ८ के जरिये से बदल दिया गया है और रिहैबिलिटेशन ग्रांट को भी साहूकारों के हवाले कर दिया गया है, मैं चाहता हूँ कि मंत्री महोदय इस पर विचार करें और हो सके तो दफा ८ 'बी' को बिल्कुल ही हटा दें ताकि ऐसा करने से वह वाकई में रिहैबिलिटेशन ग्रांट हो जायेगा और सरकार की जो मंशा छोटे जमींदारों को रिहैबिलिटेशन ग्रांट देने की है वह पूरी हो जायेगी। दूसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहता हूँ वह विधेयक की दफा ९ की बाबत है उसमें लिखा हुआ है "Where a decree to which this Act applies relating to other than a secured debt is excuted by attachment and sale of the bonds granted to the judgement-debtor on account of compensation or rehabilitation grant for his estate, the court excuting this decree shall, notwithstanding anything in any law, enter satisfaction in accordance with the formula given in Schedule II." यह साधारण कर्जों के विषय में है उसके विषय में मुझे यह अर्ज करना है कि इस प्रकार की ग्रांटें अक्सर कर्जों की वसूली से सुरक्षित रखी जाती हैं और दफा ६० उसमें लागू कर दी जाती हैं ताकि ग्रांट उस व्यक्ति के प्रयोग में आ सके जिसको वह दी गई है। अच्छा होता यदि रिहैबिलिटेशन ग्रांट (Rehabilitation Grant) के विषय में भी ऐसा ही किया जाता। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ और मंने जो कुछ निवेदन किया है वह इसलिये किया है कि माननीय मंत्री महोदय विधेयक की दफा ८ विधेयक के आब्जेक्ट (objects) के अन्दर ला सकते हैं अन्यथा दफा ८ विधेयक के आब्जेक्ट को हानि पहुंचाती है।

*श्री बद्री प्रसाद कक्कड़ (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—माननीय चैयरमैन महोदय, मैं मुस्तसर अलफ़ाज में अपने ख्यालात इस बिल पर जाहिर करूंगा। यह तो वाक्या है कि यह बिल जो इस ऐवान में आया है, वह वक्त के तकाजे के साथ आया है और साथ ही खुशी का मसला है। हमारे राजा राम शास्त्री जी और प्रभु नारायण सिंह जी भी हम जबान हैं, हम ख्याल हैं और उन्होंने भी कहा कि दरअसल यह बिल बहुत जरूरी है। इस बात में भी दो राय नहीं हो सकती कि जमींदारी अबालिशन एक बहुत बड़ा मसला था और इस से इस सूबे के रहने वाले बहुत बड़ी तादाद में मुतासिर हुये हैं और उन को काफी नुकसान हुआ है। वह नुकसान ऐसा नहीं है कि मज्जा की टोकरी में डाल दिया जाय।

अगर यह कहा जाय कि यह बिल एक ऐसा बिल है जिस के लिये जमींदारों को मिल कर सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहिये।

"To be ungrateful is the unkindest act of humanity" नाशुक्राज्जार होना एक बहुत ही बड़ा जुर्म है, मैं खुद जमींदार हूँ और जमींदारों की तरफ से सरकार का शुक्रिया अदा करता हूँ।

हमारे दोस्त कुंवर साहब ने यह फरमाया कि उन को इस बात की परेशानी है कि इस पर ख्याल उधर से जाहिर किया जाय या उधर से जाहिर किया जाय। अगर मैं यह अर्ज करूँ तो ठीक है—

"To be guided by the eyes of others is rather misleading. It is always good to consult one's own conscience and self in such matters".

मेरे ख्याल में जमीर और जमीर की हकत से ख्यालात को पढ़े तो ज्यादा मुनासिब होगा। मैं उनके ख्यालात से और दूसरों के ख्यालात से बड़ा इतफाक करता हूँ कि रिहैबिलिटेशन ग्रांट अपनी जगह पर एक बहुत बड़ा महत्व रखती है। वह एक स्टेट का दान है जो किसी कौम को उठने के लिये, संभलने के लिये और सुधारने के लिये दिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ एक ख्याल मफजूल होता है कि क्या यह इन्साफ है कि जिस ने कर्जा दिया है

* सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री बट्टी प्रसाद कक्कड़]

उसको बिलकुल अलग कर दिया जाय। मेरे ख्याल में दिल को सकून नहीं मिलता है। इस ले में अपने दिल में परेशानी महसूस करता हूँ, लेकिन गवर्नमेंट के साथ इतफाक इस वजह से रखता हूँ कि इसमें रिहैबिलिटेशन ग्रांट को शामिल नहीं किया गया है। यह बात यही है कि रिहैबिलिटेशन ग्रांट एक खास अस्तर रखती है। अभी श्री राजा राम शास्त्री जी ने यह फरमाया कि हम जमींदारों के दुश्मन नहीं हैं, लेकिन छोटे जमींदारों के हमी हैं। जहाँ तक किसी जमींदार या जमींदार के बच्चे का ताल्लुक है मैं उनकी राय से इतफाक नहीं करता हूँ, यह तो वही मसल हुई कि सांप को तो मार डाला और सांप के बच्चे को दूध पिलाते हैं और उसकी परवरिश करते हैं। मैं समझता हूँ कि यह रास्ता ठीक नहीं है।

मेरे दोस्त ने अभी शिकायत की कि टेनेन्ट की हालत इस कदर नाजुक है, इस कदर खराब है और कर्ज से इस कदर दबे हुए हैं और फिर भी उनका कतई ख्याल नहीं किया गया है। मैं सदाकत के साथ आप से अर्ज करना चाहता हूँ कि मैं उनकी राय से, ख्वाह वह इस तरफ के बैठने वाले हों, ख्वाह वह उस तरफ के बैठने वाले हों, कतई इतिफाक नहीं करता हूँ। मैं अपने तजुबों से, यह देखता हूँ कि काश्तकारों ने अपना ही कर्जा क्या, अपने बाप का कर्जा और अपने दादाओं तक का कर्जा पे कर दिया है और अगर सोने और चांदी की खरीद को देखने जाना हूँ तो मैं भाई राजा राम साहब और प्रभु नारायण साहब से कहता हूँ कि वे मेरे साथ चले और तब वे इस नतीजे पर पहुँचेंगे कि लगान में इजाफा न होने की वजह से काश्तकार इस काबिल हो गये हैं कि वे सोना और चांदी खरीद सकते हैं। सोना और चांदी ऐसी चीज है कि जिसको आगे के जमाने में भी ठीक तरह से रक्खा जा सकता है। आज सबसे ज्यादा कपड़ा वही खरीदते हैं जो कि काश्तकार हैं आज जमींदारों का दरवाजा बन्द है, वह खरीदारी नहीं कर सकते हैं और अगर आज करते हैं तो मेरा दावा है कि ६ महीने के बाद यह दरवाजा भी बन्द हो जायेगा। मेरे दोस्त आजाद साहब ने बिलकुल आजादाना बात कही कि जमींदारों ने बिलकुल बोगस कर्जा लगा लिया है, मैं तो यह कहता हूँ कि ससपिशन ब्रीड्स ससपिडेशन जैसा कि श्रीमती शिवराजवती नेहरू ने कल स्त्रियों के बारे में कहा है उसके बारे में मुझे महात्मा गांधी जी का ख्याल आता है, इज इट ह्यूमनिटी में इस मसले पर अधिक नहीं कहूँगा किसी पर स्वीरिंग रिमार्क कर लेना बहुत आसान है, लेकिन ऐसी बात नहीं है और यह भी बात नहीं है कि ऐसी मिसालें आपको नहीं मिलेंगी। मैं तो कहता हूँ कि ऐसी मिसालें हैं, जहाँ अच्छे होते हैं वहाँ खराब भी होते हैं और मैंने तो यह सुना है, पढ़ा है कि अच्छों की संगत में बुरे भी निभ जाया करते हैं। इसके माने यह नहीं है कि मैं बोगस ट्रेजैक्शन का मददगार हूँ। मैं इस तरह सहायता करने के लिये तैयार हूँ तो ऐसी बात नहीं है। मेरे एक भाई ने कहा और वह खासतौर से बुन्देलखंड के बारे में एक बात कही और मेरा उससे कतई इतिफाक है। मैं तो कहता हूँ कि बुन्देलखंड ही क्या, किसी और सर्किल में अगर ऐसी बात है तो मल्टीपल इतना लो नहीं होना चाहिये।

कम से कम जैसा कि मेरे दोस्त ने कहा कि २० से कम मल्टीपल की बात बहुत नुकसानदेह है और मुल्क की बहबूदी के लिये नहीं है। इन चन्द शब्दों के साथ मैं गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ।

* श्री केदार नाथ खेतान (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र) —माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सदन में विधेयक पेश है, उसकी मैं तईद करता हूँ। जो कर्जा जमींदारों पर या उसकी माफ करने के लिये हमारी गवर्नमेंट यह बिल लाई। मेरा ख्याल है कि अगर आज यह कर्जा काश्तकारों पर होता, और गवर्नमेंट उसको माफ कर देती, तब भी काश्तकार कर्जा देने के लिये तैयार होते। मैं इस चीज को मानता हूँ कि जितने

* सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

ईमानदार हमारे गरीब लोग हैं। उतनी ईमानदारी हमारे बड़े आदमियों में नहीं है। मैं गवर्नमेंट से यह कहना चाहता था कि जो ६ पसैंट सूद लेते हैं या ५ पसैंट सूद लेते हैं, अगर उनका कर्जा माफ किया गया है, तो कर्जा उनका भी माफ होना चाहिये जो कि २५, २० या १५ पसैंट का सूद लेते हैं मुझे उसमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन इसमें बहुत से आदमी ऐसे हैं जिनको कि इससे बहुत नुकसान होगा। कुंवर साहब ने यह फरमाया कि यह जमींदारों के लिये है, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि यदि उनके लाखों रुपये बाकी होते, और उस वक्त वह उसको छोड़ते तो पता चलता। मैंने कुंवर साहब की केवल इसी स्पीच में देखा है कि उन्होंने ऐसा कहा, पहले उन्होंने अपनी स्पीच में कभी ऐसी बातें नहीं कही थीं। मैं समझता हूँ जैसा कि श्री राजा राम जी ने कहा कि कुंवर साहब जो अब तक स्पीच में कहा करते थे वह महज शो ही था। आप महज अब तक बड़े आदमियों और बड़े जमींदारों के लिये ही शायद ऐसी भावनायें दिखलाते थे। मुझे यह कहने में बड़ी खुशी है कि जो छोटे जमींदार हैं वे ही वाकई में काश्तकार हैं, और वे जमींदार बिल्कुल नहीं हैं। मैं इस बात को मानने के लिये तैयार हूँ कि जितने ऐसे छोटे जमींदार हैं, वे खुद खेत जोतते हैं और वे काश्तकार आसामी भी नहीं हैं। हमारी गवर्नमेंट ने जो बिल रखा है, उसको एक नजर से देखने से पता चलता है कि वाकई बात जो है वह यह है कि जो कम से कम १०० या २५० रुपये के मालगुजार थे, उनके साथ ही इस तरह की रियायत की गई है और ऐसे ही जमींदारों को फायदा हुआ है। अगर यह केवल बड़े २ जमींदारों के लिये ही नहीं रखा गया है, तो मैं इसकी जरूर ताईद करने के लिये तैयार हूँ और मैं यह चाहता हूँ कि सौ रुपये के काश्तकार के साथ यह रियायत होनी चाहिये। हमारे मिनिस्टर साहब ने उसको साफ नहीं किया। मसलन जैसा जमींदारों से लोग कर्जा ले जाया करते थे और वह उसके लिये शुगर केन सप्लाई करते थे और उसमें कुछ बाकी भी देना रह जाता था। ऐसे आदमी रुपया ले जाते हैं, तो वह कर्जा भी इसमें शामिल हो जायेगा। मसलन कोई जमींदार है और जमींदारी एबालिशन से पहले इस तरह का कर्जा लिया गया है, तो उसका क्या होगा। और बहुत से जमींदार ऐसे हैं जो कि पुरनोट लिखते हैं और रुपया ले जाते हैं।

उन्होंने कहीं भी अपनी जमीन मारगेज नहीं रखी तो उनके कर्ज की क्या हालत होगी। जब माननीय मंत्री जी स्पीच देंगे तो मैं आशा करता हूँ कि इसका भी वह उत्तर देंगे। मुझे और ज्यादा नहीं कहना है और मैं इसको सपोर्ट करता हूँ।

चेयरमैन—कौंसिल २ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

[कौंसिल १ बजे अवकाश के लिये स्थगित हो गई और २ बजे डिप्टी चेयरमैन (श्री निज़ामुद्दीन) के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।]

श्री मान पाल गुप्त (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन के सामने जमींदारों का ऋण कम करने का विधेयक उपस्थित है। इस पर अनेक माननीय सदस्यों ने बहस करते हुये अनेक भाँति के विचार प्रकट किये हैं। सब से पहले कुंवर साहब ने कृतज्ञता का इजहार किया, फिर असमंजस में पड़े। लेकिन जो कुछ उन्होंने कहा वह समय के परे की चीज थी और वे शब्द में नहीं कहना चाहता कि उन्होंने क्या कहा अर्थात् कृतज्ञता की बात या उसके विपरीत थी। सरकार एक विधेयक सामने लाई जिसमें कुछ उनके कल्याण की बात सोची, इस पर भी उन्होंने कहा कि कुछ नहीं किया। हमारे मित्र प्रभुनारायण जी ने कहा कि वे साहूकारी का अन्त करने की बात सोचते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से भी नम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि थोड़ा इतिहास को देखें। यहीं पर सन् १९२६ में जब जमींदारों का अधिकार था तो उन्होंने कानून बनाया था और उस का फल यह हुआ कि उसके बाद जब वे रुपया लेते थे तो उन्हें कहीं ज्यादा रुपया दस्तावेज और कागजों में लिखने पड़ते थे तब रुपया मिलता था। मैं समझता हूँ कि आदमियों का साधारणतः बिना साहूकारों

[श्री मान पाल गुप्त]

के काम तो चलता ही नहीं। एक आदमी कोई काम करना चाहता है, और उस काम को करने की उसमें योग्यता है परन्तु धन नहीं है, तब, जब तक धन की सहायता न हो तब तक वह काम नहीं कर सकता। कहीं कोआपरेटिव के जरिये धन की सहायता पड़ती है, कहीं साक्षात् करना पड़ता है। तो वास्तव में साहूकारों की जरूरत तो सारे देश को महसूस होती है। फिर साहूकारों के प्रति यह भावना क्यों? जहां तक ब्याज की बात कही गई हिन्दू शास्त्रों में तो चार आने से लगा कर सवा रुपया तक ब्याज रखा है और यह भी बतला दिया कि उस, अर्थात् कर्ज लिये रुपये से देने से अधिक तो कभी भी न लेना चाहिये।

वैदिक संस्कृति में तो धन के कर्ज से उच्छ्रण होना ही नहीं वरन् अन्य ऋणों से उच्छ्रण होना भी परम कर्तव्य माना गया है, जैसे देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण आदि।

हमारे यहां हिन्दू शास्त्रों में कर्ज के चुकाने की प्रथा थी, हिन्दू शास्त्रों में उसका चुकाना अपना परम कर्तव्य मानते थे। आज भी कहा जाता है कि मर्द का खसम कर्ज होता है। मैं आप से कहता हूँ कि ऋण की इस प्रकार से खतम कर देना अनुचित है यह थोड़ी सी उन संस्थाओं के आदमियों में और साहूकारों में एक दूसरे प्रकार की प्रतिक्रिया पैदा कर देना है। इसलिये माननीय मंत्री जी इसक ऊपर थोड़ा सा सोचें। सरकार ने यह ठीक किया था। जहां पर सरकार ने बचन दे दिया था उसको पूरा करेगी। जहां पर जमींदारों को नष्ट करके जमीनों को ले लिया है हालांकि उसका भी इतिहास है। इसलिये मैं कुछ न कहकर यह कहता हूँ कि किसी प्रकार से उन आदमियों को जिन्होंने रुपया लगाया है उनको बंचित नहीं करना चाहिये। इसके अतिरिक्त यह बात कही जाय कि उन्हें बिचौलिया का मुनाफा होता था, लेकिन साहूकारों में तो ऐसा नहीं होता था। साहूकारों में रुपया लगाते थे तो कुछ दफा ऐसा होता था कि उनका रुपया मारा जाता था। जो ऐसे व्यवसायी हैं उनको हमें हतोत्साह नहीं कर देना चाहिये। बैंक से रुपया कोई आदमी लेता है तो उनको कर्ज लेने में बड़ी आपत्ति होती है। वहां पर कानून की बड़ी दिक्कतें होती हैं। जैसे हमारे एक मित्र श्री राजा राम जी ने जो बात कही वह उन्होंने स्पष्ट शब्दों में शंका की। एक दिन श्री इंद्र सिंह जी ने इस प्रकार की बात कही थी तो भवन में आपत्ति हुई थी कि इस प्रकार की शंका न करें पर बराबर इस भवन में सरकार के प्रति शंकायें की जाती हैं। श्री महावीर सिंह जी के संशोधन के विषय में इस समय में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। हाँ, छोटे-छोटे काश्तकारों के साथ कोई रियायत की जाय तो वह उचित भी है। इस प्रकार से साहूकारों का कोई अधिक नुकसान नहीं होगा, जो बड़े-बड़े कर्ज जमींदारों पर है। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ।

श्री विद्वनाथ (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—उपाध्यक्ष महोदय, उपस्थित विधेयक बहुत ही सामयिक और आवश्यक विषय था। यह भिन्न बात है कि जिस रूप में आज वह पेश किया गया है उसी रूप में हो या उससे कुछ परिवर्तित रूप में हो। मैं जो कुछ अपना विचार व्यक्त करने जा रहा हूँ संभव है, कि यह हमारा भ्रम हो, या समझने की कमी हो। परन्तु जैसा समझ में आया मैं निवेदन कर देना चाहता हूँ।

किसी विधेयक पर विचार करते समय हमें यह सोचना पड़ता है कि वास्तव में उसका क्या फल होगा और उसी के लिये विधेयक प्रस्तुत भी किया जाता है। वस्तु स्थिति वास्तव में है क्या, उसको भी हमें समझना ही पड़ता है। जमींदार शब्द या महाजन शब्द, हमें इन शब्दों के पीछे पड़ना मुनासिब और उचित नहीं मालूम होता। देखना तो चाहिये कि वह महाजन किस श्रेणी का है। क्या वह खदक से भी गरीब है या कमजोर है या उससे खुशहाल है। इसका विचार न कर और महाजन के पीछे पड़े, यह सुन्दर बात नहीं होती। वैसे ही जमींदार शब्द के पीछे पड़ जायें, कोई उचित बात नहीं है। मुझे भली भाँति मालूम है।

बहुत से स्थान हैं, जैसे मेरा ही एक गांव है वह किसानों का एक गांव है, उसमें लगभग २ हजार जमींदार परिवार हैं जिनके पास जमीन थोड़ी-थोड़ी है और वह सब जोतते हैं। जमींदारी का खात्मा हो जाने के बाद वहां के लोगों का कोई नुकसान नहीं हुआ। सिर्फ उनका नाम तब्दील हो गया। जो जमींदार कहे जाते थे वह अब भूमिधर कहे जाते हैं। उनकी स्थिति में कोई अंतर नहीं हुआ। यह भी मुझे मालूम है कि जिन्हें कर्जा दिया गया था, उनमें बहुतों को तक्रलीफ नहीं है। बहुत से कर्जा देने वाले महाजन ऐसे भी होते हैं, जो अपना पेट काट कर छोटी-छोटी नौकरियां करके, अपना रुपया वचाते हैं और इस तरह से वचा कर कर्जा इसलिये देते हैं, कि यह हमारे लिये आगे चल कर सहारा रहेगा। इसलिये ऐसा करते हैं। मुझे याद पड़ रहा है सन् १९३८, ३९ में एक किसान कर्ज राहत ऐक्ट, किसानों और गरीब आदमियों के हित के लिये बना। परन्तु हमारे यहां तो अधिकांश गरीब आदमियों का ही रुपया था और वह बहुत कुछ मारा गया और नुकसान हुआ। हां, कुछ ऐसे भी जमींदार हैं जिनके पास सौ एकड़ सीर की जमीन है और १०, १२ बीघे ऐसी जमीन रही जिस पर काश्तकार रहे। तो मेरा कहना है कि सिर्फ नाम बदला है उनको कोई हानि नहीं हुई है। अतः मैं डिटेल्स में न जाकर, मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि वह इस बात पर कि इस बिल का उन पर क्या असर पड़ेगा, प्रकाश डालें, ताकि मेरा भ्रम निवारण हो जाय और अगर मेरा ख्याल सही है तो इस पर विचार करें।

श्री वेणी प्रसाद टंडन (स्नातक निर्वाचन क्षेत्र)—उपाध्यक्ष महोदय, जो विधेयक, माननीय मंत्री जी ने आज हमारे सामने रखा है, इसके सिलसिले में आपने बतलाया कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी कि जिस समय जमींदारी उन्मूलन का भार गवर्नमेंट ने अपने ऊपर लिया था उस वक्त जमींदारों को यह आश्वासन दिया गया था कि उनके कर्ज भी उसकी एवज में कम कर दिये जायेंगे। मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि हमारे सूत्रों में मौजूदा कर्ज के सिलसिले में कितने ही कानून हैं जिनका फायदा हर कर्जदार उठा रहा है या उठा सकता है। इन्कम्बर्ड स्टेट ऐक्ट का फायदा जमींदारों ने उठाया, फिर डेट रिडक्शन ऐक्ट का भी फायदा उठाया। जब इस तरह के कानून हमारे प्रदेश में लागू रहे हैं तो फिर डेट रिडक्शन बिल की क्या आवश्यकता थी। इस संबंध में जो तरीका या फारमूला डेट रिडक्शन का माननीय मंत्री महोदय ने रखा है उसमें भी इन्कम्बर्ड स्टेट ऐक्ट के उसूलों को लागू किया है। मेरी समझ में नहीं आता कि इन्कम्बर्ड स्टेट ऐक्ट से जब हर कर्जदार को फायदा पहुंच चुका है तो फिर फरदर रिडक्शन (कभी कर्जा) क्यों दिया जाय। जमींदारी उन्मूलन के बाद जमीन की कीमत कम हो गई है, तो क्या यह उचित नहीं है कि इन्कम्बर्ड स्टेट ऐक्ट में ही अमेंडमेंट आता और उसकी कीमत घटा दी जाती।

एक सुझाव तो मेरा यह है और दूसरी बात मुझे फारमूला के सिलसिले में कहना है। इस फारमूले से साहूकारों के बीच मतभेद होगा, क्योंकि माननीय मंत्री महोदय ने बतलाया कि इसके जरिये से ४ आने से आठ आने की रकम निश्चित की जा सकती है।

इस कानून का नतीजा यह होगा कि किसी साहूकार का आठ आना नुकसान होगा किसी का १२ आना नुकसान होगा। सरकार को जब जमींदारों को मदद देनी थी तो यह क्यों किया गया कि किसी को ८ आना दिया जा रहा है और किसी को ६ आना दिया जा रहा है। यह भेदभाव जो पैदा किया जा रहा है इससे आशंका पैदा होने की संभावना है। हमारे साहूकारों के लिये माननीय राजा राम जी ने और प्रभु नारायण जी ने यह कहा कि साहूकार लोग उत्पादन नहीं करते। यह बात तो है। लेकिन वह यह बतलाये कि उत्पादन करने वाले जो लोग हैं उनको साहूकार लोग मदद करते हैं या नहीं करते? अगर किसी से कर्ज लेकर कोई उत्पादन करता है तो जो व्यक्ति उसको उत्पादन के लिये रुपया देता है वह अगर

[श्री वेणी प्रसाद दंडन]

उसमें से ५ परसेंट ले लेता है तो क्या वह कोई बहुत ज्यादा है ? हमारे संविधान में कोई ऐसी बात नहीं है कि ब्याज खाना पाप है। अगर ब्याज खाना पाप होता तो संविधान में लिखा होता कि यह पाप है और कोई किसी से कर्ज न ले और कोई ब्याज न खाये। जब जमींदारों पर सख्त मुसीबत पड़ती थी और उसका बगैर रुपये के काम नहीं चलता था तब वह साहूकार के पास जाता था और उससे बड़ी-बड़ी रकमें कर्ज में लेता था। पहिले तो जमींदार साहूकारों से रुपया लेकर अपना काम निकालता था और अब साहूकार को यहां पर गाली दी जाती है। यह कौन सी अच्छी बात है।

इस विधेयक के सिलसिले में एक बात की ओर और ध्यान देने की जरूरत है। बहुत से अनसिक्योर्ड डेट्स जो जमींदारों ने मार्गेंज के अलावा लिया है उसका कानून में कोई साफ रास्ता नहीं बतलाया गया है। जिन्होंने प्रोनोट्स में रुपया दिया है उनकी रकम कैसे वसूल होगी ? एक सेक्शन में कहा गया है कि अगर बांड्स को अनसिक्योर्ड करारकर दिया जावे तो उनकी बाकी रकम वसूल समझी जायेंगी। अनसिक्योर्ड डेट्स जिसने दिया उसने जमींदारों की पोजीशन देखकर कि यह बड़ा जमींदार है रुपया कर्ज दे दिया। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इसके लिये भी पूरी योजना होनी चाहिये कि उनका रुपया कहीं न मारा जाये। उनको मौका दिया जाये कि अगर कम्पेनसेशन से उनका रुपया वसूल होता है तो वसूल किया जाये नहीं तो उनको दूसरे तरीके से दिलाया जाये। जिसके पास और कोई जायदाद नहीं उसका तो कोई सवाल ही नहीं, लेकिन जिनके पास है उनसे रुपया क्यों न वसूल किया जाये ? उनमें यह लिखा है कि बांड ही दिया जायेगा। इसके सिलसिले में मुझे यह निवेदन करना है कि साहूकारों ने तो नक़द रुपया दिया है और आज जमींदारी उन्मूलन के कारण आप उनको बांड्स दे रहे हैं। उनको अगर आप बांड्स देंगे तो उनका क्या फायदा होगा ? जो रुपया आप कर्ज का निर्धारित करें उसे आप उनको नक़द दे दें तो अच्छा है। इससे यह होगा कि वह रुपया उत्पादन के काम में आयेगा। कर्जा देने वाले का ध्याज ही नहीं पायब हुआ बल्कि उसकी असली रकम भी मारे जाने का अन्देशा है।

क्या इसका न्याय करेंगे। मेरी समझ में इसमें आप को ध्यान देना चाहिए और उसके लिये विचार भी करना चाहिए कि साहूकारों को बजाय बांड्स के उस रकम को नक़द में दे दिया जाय। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का स्वागत करता हूं।

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद (स्नातक निर्वाचन क्षेत्र)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का जो सदन में इस समय उपस्थित है स्वागत करता हूं परन्तु स्वागत करने के साथ साथ उसकी आलोचना किये बिना नहीं रह सकता। मैं समझता हूं कि सदन का सदस्य होने के नाते दो चार शब्द उसके बारे में आपके सामने कहूं। इसमें संदेह नहीं कि इस विधेयक को लाकर सरकार ने अपनी विचारशीलता और सहानुभूति का परिचय दिया है। सरकार ने जमींदारी को खत्म किया। सरकार ने अनुभव किया कि उनकी सम्पत्ति के चले जाने से जमींदारों को कष्ट हुआ इसलिये उस कष्ट को कम करने के लिये उनको प्रतिकर दिया। इसके अलावा एक छोटा जमींदार है जिसको इससे अधिक कष्ट हुआ और जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई उसको रिहबिलिटेशन ग्रांट दिया। अब कर्ज के सम्बन्ध में सरकार ने अनुभव किया कि जमींदारी की कीमत कम हो जाने से यह आवश्यक है कि कर्जा भी कम कर देना चाहिए। मैं समझता हूं कि इस उद्देश्य से जिन जमींदारों पर कर्जा है जिनकी जायदाद की कीमत बहुत कम हो गई है उनको किसी प्रकार की सहायता पहुंचती है। मैंने इस विधेयक के उद्देश्य और कारणों को पढ़ा। उनमें से क्लॉज ६ को पढ़ कर मुझे विशेष प्रसन्नता हुई। वक्फ, ट्रस्ट और धार्मिक उद्देश्य की जो चीजें हैं उनका किसी पर कर्जा है तो सरकार ने उसकी कम करने का इरादा नहीं किया है। इसमें सरकार ने न्याय का अनुशीलन किया है। और ऐसा करके जनता का बहुत बड़ा उपकार किया है। मंत्री जी ने अपने

भाषण में इस बिल का वर्णन किया है और उन्होंने स्पष्ट रूप से बतलाया कि उनका उद्देश्य क्या है। एक बात जो ध्यान देने योग्य है वह यह है कि इस बिल की भाषा ऐसी बनाई गई है जो आसानी से समझ में नहीं आती है। मैं यह कहे बिना नहीं रह सकता कि जितने नियम, अधिनियम और कानून जमींदारी के सम्बन्ध में बने हैं उनकी भाषा, क्लिष्ट बनाई गई है। हमने पुराने कानून को जो लैंड टेन्थोर से सम्बन्धित थे, पढ़ा। वे आसानी से समझ में आ जाते हैं। परन्तु इसका आवेक और रीजन समझ में नहीं आता। दूसरे शब्दों में यह कहना चाहता हूँ कि यह ऐसा लग रहा है जैसा कि मैथमेटिकल रिसर्च का पेपर हो। माननीय मंत्री जी इसको विशेषज्ञ हैं वे समझते हैं कि सदन का प्रत्येक सदस्य इसका विशेषज्ञ है। मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि जब वे उत्तर देने के लिये खड़े हों तो एक वास्तविक केस को लेकर बतलायें कि किस प्रकार से कर्जा कम होगा और कितने जमींदारों को इससे मदद मिलेगी। मैं समझता हूँ कि ५० फ्रीसदी सदस्य इस सदन में ऐसे हैं जो इसकी व्याख्या नहीं कर सके। इसलिये हम चाहते हैं कि एक उदाहरण देकर समझायें कि कितना कम होगा और कितनी सहायता मिलेगी। कानून को सरल तथा स्पष्ट होना चाहिये।

आप को याद होगा और उपाध्यक्ष महोदय, आप ने इतिहास में पढ़ा होगा कि फ्रान्स में राज क्रान्ति हुई और जमींदारियाँ छिन गईं। जब क्रान्ति असफल हुई और देश की शासन व्यवस्था बिगड़ गई तब नेपोलियन ने राज्य की शक्ति अपने हाथ में ली। उसने कानून बनाने के लिये एक कमीशन नियुक्त किया। उसने कमीशन के सदस्यों से कहा कि देखो—

“Men have bowels, the law hath not.”

इसका अर्थ यह है कि आदमी की आतों से तो मल निकल जाता है परन्तु कानून की आतों से मल नहीं निकलता है। इसलिये कानून स्पष्ट होना चाहिये। नेपोलियन कानून तो नहीं जानता था परन्तु बार बार कानून के ज्ञाताओं से कहता था :—

“I want to legislate not for the abstract man but for the ceperisian of actual flesh and blood.”

इसका अर्थ है कि मैं किसी काल्पनिक व्यक्ति के लिये कानून बनाना नहीं चाहता। वरन् वास्तविक पेरिस निवासियों के लिये। इसलिये शब्दों पर बहस करना सिर्फ कानून का उद्देश्य नहीं है। कानून ऐसा बनाना चाहिए जिससे जनता का कल्याण हो, देश का फायदा हो, मैं समझता हूँ कि इसी दृष्टिकोण से कानून बनाया जाता है। जमींदारी उन्मूलन का भी यही उद्देश्य है कि गरीब जनता को सुख मिले और जमींदारों को भी किसी प्रकार का कष्ट न हो। छोटे जमींदारों के लिये रिहैबिलिटेशन ग्रांट की व्यवस्था की गई है। मंत्री जी ने जो कुछ कहा उससे कुंवर साहब को संतोष नहीं हुआ। यह ठीक भी है कि जिसका एक लाख रुपये का मुनाफा जाता रहे उसकी परेशानी बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन फिर भी मैं कुंवर साहब के धैर्य और सहनशीलता को प्रशंसा करता हूँ। इस सदन में कुंवर साहब ने दो बातें कहीं, एक तो मंत्री जी के कहने के अनुसार उन्होंने स्वीकार कर ली परन्तु दूसरी को नहीं माना। मुझे दुःख है कि इस समय कुंवर साहब सदन में उपस्थित नहीं हैं।

एक सदस्य—लीजिये कुंवर साहब आ गये।

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद—इसमें कोई शक नहीं कि कुंवर साहब सदा सत्य को ढूँढ़ते रहते हैं। दूसरी बात उन्होंने यह कही कि इस बिल से कोई विशेष लाभ नहीं होगा। हमारे मित्र श्री राजा राम शास्त्री और श्री प्रभु नारायण सिंह जी और अन्य सदस्यों ने इस सदन में जमींदारों के अत्याचार का वर्णन किया और साहूकारों के विषय में भी बहुत कुछ कहा। मैं तो

[डाक्टर ईश्वरी प्रसाद]

समझता हूँ कि जमींदारों के अत्याचारों का विस्तृत वर्णन करना एक असंगत सी बात है। जब जमींदार ही खत्म हो गये तो उनके अत्याचार भी समाप्त हो गये। अगर आप इतिहास को देखें तो बहुत से लोगों ने अत्याचार किये हैं। कहावत है :—

“The greatest champion of liberty ends by being a tyrant.”

जो स्वतंत्रता का समर्थक होता है वही सब से बड़ा जालिम बन जाता है। जमींदारों के अत्याचारों का वर्णन करने से अब कोई लाभ नहीं। इस तरह महाजनों के दुष्कर्मों का वर्णन करना भी निरर्थक है। बहुत समय व्यतीत हुए थियोडोर मोरीसन नामक अलीगढ़ कालिज के अध्यक्ष ने अपनी पुस्तक इंडस्ट्रियल आगनाइजेशन (Industrial organisation) में लिखा था कि बनिया मदद तो देता है परन्तु उसकी मदद बिनाशकारी होती है। यह बात सत्य नहीं थी। महाजन हमारे राज्य में कई प्रकार के हैं। बनिया इन सब में नरम होता है। मारवाड़ी साहूकार होता है। मारवाड़ी साहूकार को हमारे जिले में अठवरिया कहते हैं। वह एक के आठ लेता है, दूसरे साहूकार होते हैं भूमिहार। कहते हैं कि भूमिहार के पल्ले जो पड़ जायेगा, तो फिर उससे बचना कठिन होता है। उसका ऋण एक पुस्त में क्या सात पुस्त में भी नहीं चुक सकता है। पूर्वी जिलों में खत्रियों के यहां भी लेन-देन होता है और वह भी सूद लेने में किसी से कम नहीं है। दूसरे प्रकार के लोग भी लेन-देन करते हैं। कोई साढ़े १२ रुपये सैकड़ा सूद लेता है कोई २५ रुपये सैकड़ा लेता है। और कोई ५० और ७५ रुपये सैकड़े तक भी सूद लेता है और कहीं कहीं पर तो इससे भी अधिक व्याज लिया जाता है। जरूरत के समय व्याज देना ही पड़ता है। हमारे मित्र वेणी प्रसाद टंडन जी ने, जो कि साहूकारों के समर्थक है बताया कि साहूकार अच्छे होते हैं। परन्तु वास्तव में ऐसा कम देखा जाता है। बाइबिल में कहा गया है कि

“Interest is the breed of barren metal”.

कुरान शरीफ ने भी व्याज की निन्दा की है। उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि मुसलमानों के लिये सूद लेना हराम समझा गया है। परन्तु आज कल समय ऐसा आ गया है कि सूद लिये बिगैर काम नहीं चलता। यह बातें तो उस समय कही गई थीं जब कि समाज साधारण था, सीमित था। आज की तरह बड़े बड़े स्केल पर व्यापारिक लोग नहीं थे और उस समय इतने रुपये की जरूरत नहीं पड़ती थी लेकिन आज के समाज में हमें रुपये की जरूरत पड़ती है और उसके लिये हमको साहूकारों के पास जाना पड़ता है। इसमें साहूकारों का भी कार्य बड़ा सराहनीय है। वह भी बड़ा त्याग करते हैं। अपना पेट काट कर इतना रुपया जमा करते हैं और आपकी जरूरतों को पूरा करते हैं। साहूकारों का भी समाज में स्थान है। उनके प्रति हमें घृणा, द्वेष या ईर्ष्या का भाव नहीं रखना चाहिये। मैं समझता हूँ कि सरकार ने कर्जा देने वालों की सुविधा के लिये उपाय निकाल कर एक बहुत न्याय का काम किया है और उनके लिये जो कुछ भी किया गया है उसके लिये मैं उसका धन्यवाद करता हूँ। सूद के मामले में आप देखेंगे कि साहूकार ही नहीं, इम्पीरियल बैंक में आप जाइये तो वहां क्या होता है। अपने डिपोजिट में से रुपया लेने जाइये तो ६ परसेंट सूद मांगते हैं। इसको आप क्या करेंगे। अपने ही जमा किये हुये रुपयों में से अगर रुपया लें जाते हैं तो सूद मांगते हैं। इससे ज्यादा और क्या जुलूम हो सकता है। परन्तु सूद का लेना भी जरूरी है और कर्जा लेना भी जरूरी है। कर्जा के बिना कोई समाज चल नहीं सकता है। मैं तो समझता हूँ कि साहूकारों की सुविधा के लिये यह बिल पेश किया गया है। मगर इसमें भी चुट्टि है। जितने भी अब तक सदन के अन्दर भाषण किये गये हैं उनमें यही सिफारिश की गई है, और हमारे समाजवादी मित्रों ने और अन्य मित्रों ने भी यही कहा है कि छोटे जमींदारों का इसमें विशेष ध्यान रखना चाहिये। सरकारी पक्ष से

श्री प्रताप चन्द्र आजाद जी ने भी कहा कि छोटे जमींदारों को अधिक सहायता मिलनी चाहिये। मैं समझता हूँ कि कोई भी सदस्य इस सदन में ऐसा न होगा जो कि इस बात से सहमत न हो कि छोटे जमींदारों को सहायता मिलनी चाहिये।

मंत्री जी ने जो प्रतिकर को पुनर्वास अनुदान से मिलाया है कर्ज के वास्ते तो वह ठीक न होगा। जैसा कि श्री राजाराम जी ने बतलाया कि इन दोनों में सरकार को भेद करना होगा। प्रतिकर तो एक प्रकार से जमीन की क्रोमत है जो कि सरकार ने नियत की है। आपने जो बाजार में कीमत थी, वह कीमत भी उनको नहीं दी है, आप नहीं दे सकते थे और आपने समझा कि जनता के हित के लिये इतना हाँ देना इस समय उपयुक्त है या आपने निश्चय किया कि जिस भूमि को आपने लिया है यही उसकी उचित कीमत होगी, कम हो या ज्यादा हो तो इससे तो कोई वास्ता नहीं है।

आपने जो रिहैबिलिटेशन ग्रांट दिया है वह क्यों दिया? जब इसके लिये हाई कोर्ट फैसला हुआ तब आपने यह दिया। जब चारों तरफ से आवाज आई कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिये, तब आपने ऐसा किया। छोटे जमींदारों में लाखों आदमी ऐसे जो कि इतने परेशान थे और उनको सुविधा पहुँचाना राष्ट्र का कर्तव्य है। हमारे देश में २० लाख जमींदार हैं और उनमें से १६ लाख ८६ हजार ऐसे हैं जो कि ५० तक जानाजारी देते हैं। आप देखेंगे कि जो छोटे जमींदार हैं उनकी ही संख्या बहुत बड़ी है और उन्हीं की सुविधा के लिये आपने रिहैबिलिटेशन ग्रांट की व्यवस्था की है। इससे आपका उद्देश्य यह था कि उन जमींदारों को फिर कोई भी कारोबार करने में सुविधा होगी। और उनके लड़के जो अब तक अखाड़े में कुश्ती लड़ा करते थे। और गाय भैंस का दूध घी खाते थे वे किसी भी काम में लग जायेंगे।

श्री चरण सिंह—कोई उनकी भैंसें थोड़े ही छीनी गई हैं।

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद—भैंसें नीलाम हो जायेंगी। मैं यह कह रहा था कि छोटे जमींदारों को सुविधा पहुँचाने के लिये ही गवर्नमेंट ने रिहैबिलिटेशन ग्रांट देने की व्यवस्था की है और इसके लिये मैं समझता हूँ कि प्रत्येक मनुष्य सरकार का आभारी है कि सरकार ने इस पर विचार किया और उन बुरी स्थिति वाले जमींदारों के लिये इस तरह का काम किया। अब उससे कर्ज वसूल होने की जो बात है, वह मैं समझता हूँ ठीक नहीं है। दोनों तरफ से यह कहा गया है कि सरकार इस बात पर विचार करेगी। जो इस समय तजवीज है उस पर अमल करने से जो रिलीफ आप देना चाहते हैं वह नहीं के बराबर हो जायेगा और यदि आप प्रतिकर और पुनर्वास अनुदान दोनों मिला देंगे। कुंवर साहब तो बड़े आदमी हैं, उन पर किसी का कर्जा नहीं है परन्तु बड़े जमींदारों का ३/४ कर्ज में चला जायेगा। केवल १/४ उनके पास रहेगा। तो यह क्या मदद हुई। आप दोनों कीमत मिलाइये और आप एक ऐसी रकम निश्चित कीजिये जो कि इतने वाला भी ठीक समझे। जैसा कि कहा गया कि सौ रुपया २५० रुपये या ५०० रुपये हों। आजाद साहब ने २५० रुपये कहा और मैं समझता हूँ कि २५० रुपये ही ठीक है। इतना भूमिकर देने वालों के साथ साथ यह रियायत कर दी जाय। इस सदन में लोगों ने कई विचारधाराओं का वर्णन किया। और साहूकारों के बारे में भी कहा। परन्तु मैं आप से यह कहना चाहता हूँ कि समय अब प्रगतिशील है। निजी सम्पत्ति पर बराबर आक्रमण हो रहा है। निजी सम्पत्ति पर ही नहीं बल्कि आपके परिवार पर भी राष्ट्र का अधिकार हो जायेगा और आपसे कहा जायेगा कि इतने बच्चे से ज्यादा आप पैदान करें। वे भी फिर आपके नहीं हो सकेंगे। आपका रुपया भी फ्रीज कर दिया जायेगा। अब समय ऐसा आ रहा है और मंत्री जी को भी कुछ वर्षों के बाद यह मालूम हो जायेगा।

श्री चरण सिंह—वह समय नहीं आने वाला है?

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद—आप यूनीवर्सिटी में आइयेगा तब आपको पता लगेगा, आप तो यहां बैठे हुए हैं, इसलिये ऐसा कह सकते हैं। वहां आपको पता चलेगा कि क्या विचार-धारा इस समय काम कर रही है। इसके लिये हम सब को तैयार हो जाना चाहिये। पुरानी बातों को दोहराने में समय नष्ट न करना चाहिये। सरकार ने छोटे जमींदारों पर दया की है। मैं आशा करता हूँ कि जो नियम अथवा अधिनियम बनाये जायेंगे उनमें उनके हितों का ध्यान रखा जायगा। अब एक बात कह कर मैं समाप्त करूँगा और वह बात विशेष कर मैं मंत्री महोदय से कहूँगा कि उन्होंने जो सहानुभूति का परिचय दिया है उसके लिये हम उनका धन्यवाद करते हैं। अब जमींदार लोग भी इतना अवश्य समझें कि वे भी राष्ट्र के ही एक अंग हैं। वे भी इस देश के नागरिक हैं हमें भी उनके साथ सहानुभूति दिखानी चाहिये। इससे समाज का हित होगा। कुंवर साहब को जो आश्चर्य हो रहा है वह मैं समझता हूँ बहुत जल्द दूर हो जायेगा अब सरकार ऐसी नीति का अवलम्बन नहीं करेगी जिससे उनको किसी प्रकार का कष्ट हो।

श्री प्रेम चन्द्र शर्मा (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, फ्रंट रोलिंग पर काफ़ी बहस हो चुकी है, मैं इस पर क्लोजर मूव करना चाहता हूँ।

डिप्टी चैयरमैन—प्रश्न यह है कि प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री चरणसिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो बहस इस विधेयक के विचार करते समय हुई वह काफ़ी लम्बी चौड़ी हुई और दिलचस्प भी हुई आखिरी लम्हों में मैं मुह्तसरन जो नुक्तें उठाये गये हैं या आलोचना की गई है उनका जवाब देने की कोशिश करूँगा। माननीय गृह नारायण जी जिस वक्त खड़े हुये तो उनका यह कहना था कि मुझ को आम तौर पर यह शिक्षायत रहती है कि जमींदार साहबान ने किसी भी गवर्नमेंट की कोशिश के लिये जो उसने जमींदारों के लिये हकूक दिये या हकूक छोड़ दिये उनके लिये धन्यवाद नहीं दिया। मैं सोच रहा था कि आज हमको मुबारकबाद मिलने वाला है लेकिन वह अलफाज उनकी जवान पर आये ही थे तभी उनके अन्दर जो साहकारा था वह उन पर हावी हो गया और वह अलफाज बीच में हो रह गये। पहली शिक्षायत यह है। उनको यह भ्रम हुआ कि १० हजार वालों का कर्जा कम करने का इतने कोई प्रावोजन नहीं है। ऐसा तो शुरू ही से नहीं जब से यह बिल असेम्बली में पेश हुआ था और जब यहां आया तो कोई भी तफ़रीक जमींदारों के बीच नहीं की गई है और और जमींदारों का कर्जा खत्म करने की कोशिश की गई। खैर, वह छोटी सी शिक्षायत थी लेकिन सबसे बड़ी मेरी शिक्षायत यह है कि वह इस विधेयक को पढ़ कर नहीं प्राये हैं जैना कि वह जैन्ड सप्लोमेंट्री बिल पर वह नाराज हो गये थे और उन्होंने कुछ कहा नहीं था और किसी कारणों से उस समय वह जवाब नहीं दे पाये थे आज वह बात नहीं है। २ या ३ मतों पर बहस हुई। एक तो यह रिट्रिब्यूशन प्रॉट से कर्जा वसूल नहीं होना चाहिये और वह जमींदारों के लिये महफूज छोड़ देना चाहिये। इस विषय पर खासतौर से माननीय इशॉन्ट जी ने इस बात पर बहुत बल दिया कि कम्पेन्सेशन और रिट्रिब्यूशन दो चीजें हैं। अब इन तीनों शरी अन्वार्शन लैन्ड रिफॉर्म ऐक्ट बना चुके हैं और हमने उसमें पुनर्वासन अनुदान और प्रतिहर में विवेक किया है और फिर एकदम से इस बात को भूल जायें और दोनों चीजों को मिटा दें तो इस से जनता में गलतफ़हमी पैदा हो सकती है कि गवर्नमेंट अपनी बातों पर या अपने उसूलों पर कायम नहीं रहती।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रिट्रिब्यूशन प्रॉट और कम्पेन्सेशन में एक टेक्निकल अन्तर है और वह हम को जानूँगे मजबूरियों की वजह से करना पड़ा। छोटे लोगों को जो ज्यादा कम्पेन्सेशन दिया जा रहा है, उस का नाम पुनर्वासन अनुदान है और बाकी पक्की आय का अठगुना तक उस का नाम हमने कम्पेन्सेशन रखा है। अगर सब को एक रकम देने का निश्चय होता तो

यह उलझन न पेश होती। हालांकि आमतौर से राय यह थी कि छोटे मध्यवर्तियों को ज्यादा प्रतिकर मिले या उनका गुनक ज्यादा हो बनिस्वत बड़े जमींदारों के। अगर इस बात को मान कर हम कम्पेनसेशन का मुश्किल मल्टीपुल रखते तो उस में कानूनी अड़चन थी। मैं मिसाल के तौर पर बताता हूँ कि मन्तलन मशाराज बनरामपुर का किसी गांव के एक खेबट में आधा हिस्सा है और उसी गांव से रहने वाले किसी छोटे जमींदार का उसी खेबट में १/१५ हिस्सा है जब मशाराज बनरामपुर को हम कम्पेनसेशन देते उनकी आय का अठगुना और दूसरे जमींदार को हम वही जमीन देते, हस्व हैसियत उनको हम देते २५ गुना तो हमारे संविधान का अनुच्छेद १३ या १४ है, उसके बिना बिना विचारीत पड़ता। इन इक्विटी विफोर दि आई आफ ला (Inequality before the eye of law) हो जाती जिसको हम किसी प्रकार डिफेंड नहीं कर सकते थे। बिहार की गवर्नमेंट ने अपने जमींदारी एबालीशन ऐक्ट में इसी प्रकार किया था कि उसका नाम कम्पेनसेशन रखा और गुना छोटे बड़े के हिसाब से कम व बेश रखा। लिहाजा यदना हाईकोर्ट ने बिहार जमींदारी एबालीशन ऐक्ट को इसी बिना पर अवंध करार दिया। जब कि आपके हाईकोर्ट के सामने पेश किया गया तो हमारी तरफ से जवाब यह था कि कम्पेनसेशन को रकम हम पक्की आय का दसगुना सबको दे रहे हैं इसके ऊपर १० से लेकर २० गुना तक जो हम दे रहे हैं वह कम्पेनसेशन नहीं है, उसके वह कानूनन मुस्तहक नहीं हैं, उनके साथ हम रियायत कर रहे हैं। हम उनको रिहैबिलिटेशन दे पान दें। वह कानून में इन्टाइडल्ड नहीं हैं। अगर इन्टाइडल्ड हैं तो केवल अपनी आय के अठगुने को हूँ। उसको हाईकोर्ट ने माना और हमारे बिल को बंध करार दिया। संविधान के अनुसार अगर न होता और सुप्रीम कोर्ट में फिर बहस होती, उस वक्त इसका नतीजा क्या होता यह मैं नहीं कह सकता। इतनी बातें जो हमारे सामने आ गईं उनकी मैं साफ कहना चाहता हूँ। लेकिन इस डेक्लरेशन डिक्लरेशन को जरूर मान लें कि रिहैबिलिटेशन और कम्पेनसेशन बिल्कुल अलहाश है। क्या वह उत असानी मल इज का जायशद नहीं है। अगर गवर्नमेंट की तरफ से इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के लिये सहायता मिल रही है तो उसके खिलाफ कर्जल्वाह डिप्री क्यों नहीं प्रोसीड करता है। जिस तरह से दफा ७ के अन्दर कुछ चीजें मुस्तारना कही गई हैं कि उनको कूरनी नहीं हो सकती है। किसानों को छोड़कर वे कूरन कर सकते हैं। उसके पुनर्वासन के लिये वह कितना ज़रूरी क्यों न हो इस बात को हम भूल जाते हैं। लिहाजा जो दलीलें पुनर्वासन के खिलाफ हैं वे ये हैं कि उसको बिल्कुल महकूज कर दिया जाय और कर्जल्वाह उससे न ले सके। तो यह थोड़ी सी भ्रन पर आश्रित है असेट के खिलाफ प्रत्येक को प्रोसीड करने का अस्थित्यार होता चाहिये। माननीय इन्ड्र सिंह ने जमींदारी एबालीशन ऐक्ट का हवाला दिया। जमींदारी एबालीशन ऐक्ट में लिखा है रेंट सेस लेने का जो ख्याल है उसमें कर्ज का जिक्र नहीं है, "अदर ड्रज" लब्ज है। उसमें डेड नहीं आता है उस टाइम का सेस रेंट जो है वह प्रतिकर से वसूल होता है कर्ज का जिक्र नहीं है। यह कहना कि रेंट की डिग्री जिक्र है वह पुनर्वासन से न ले सके तो यह भी इससे नतीजा नहीं निकल सकता है। जमींदारी एबालीशन ऐक्ट की धारा ७ में क्या लिखा है। उससे कोई एनाला जी निकाजी नहीं जासकरी है। रही बात १०० रुपया से कम मालगुजारी की, तो जो संशोधन पेश किया गया है उसमें पुनर्वासन अनुदान ही नहीं बल्कि प्रतिकर है। मुझे इस बात को देखकर खुशी हुई कि सदन के चारों तरफ से इस बात की आवाज उठ गई गयी है। अगर सारी बातें सदन के सामने आ जायें तो सदन हमारे साथ होगा। छंदे आशमियों के साथ हमदर्दी करना यह हर मनुष्य का धर्म है और यह होना चाहिये। तो उस अवस्था में हम सब लोगों की एक राय है। बहुत से लोगों की राय है कि उनका प्रतिकर महकूज रहे लेकिन क्यों इस पर विचार किया जाय। इसका मतलब यह है कि १०० रुपया की मालगुजारी पर जो कर्जा है उसको वसूल न किया जाय। क्यों वसूल किया जाय। इसका मतलब यह होगा कि जितने भी कर्जल्वाह होंगे और साहूकार होंगे उनका रुपया जस्त होगा जबकि हर जमींदार को हम कुछ न कुछ दे रहे हैं। जैसा एक मित्र

[श्री चरणसिंह]

कह रहे थे और इसके खिलाफ बहुत बलीलें आयी हैं कि जमींदारों और साहूकारों को एक लेबिल पर रखा नहीं गया है।

इसमें शक नहीं कि जमींदारों के खिलाफ ज्यादा बातें हैं। लेकिन मैं उन लोगों में से हूँ जो जमींदारों और साहूकारों को एकसां समझते हैं। ज्यादा अन्तर उनमें नहीं है। लेकिन दोनों की तौल करनी पड़े तो जमींदारों का पलड़ा भारी होगा। तो जब हम ऐसे जमींदारों की जमींदारी खतम नहीं कर सकते, जिन्होंने १८५७ में मुरादाबाद में फलां काम करने के उपलक्ष में ज़मीन पाई थी, उस गवर्नमेंट की सेवा करने के बदले में पायी थी, उनको जब हम मुआवजा दे रहे हैं तो फिर साहूकारों ने क्या कसूर किया है जो उनका रुपया एक कलम ज़ब्त कर दिया जाय। छोटे छोटे जमींदारों के साथ हमदर्दी हो मुझे तसलीम है। मगर उन लोगों ने क्या कसूर किया है। अगर आप ऐसा करते कि बड़े बड़े जमींदारों या छोटे ही जमींदारों को कहते कि मालगुजारी बिल्कुल ज़ब्त हो तो कुछ बात समझ में आती। लेकिन वह तो समझ में बात नहीं आती है। जब छोटे जमींदारों को मुआविजा दे रहे हैं तो जिन लोगों ने कर्जा दिया है वह भी तो कुछ न कुछ पाने के मुस्तहक होते हैं। फिर आप कहते हैं कि कैसे कर्जख्वाह और साहूकार एकसां होंगे। अगर कुंवर साहब माफ करेंगे तो मैं कहूंगा कि आप कर्जख्वाहों और साहूकारों की फेहरिस्त लेकर देखिये। आप देखेंगे कि हर एक गांव में उन लोगों का एक दूसरे पर कर्जा है। किसी भी गांव में जाकर देखिये। एक किसान ने दूसरे किसान को कर्जा दिया है। जो कर्जा लेने और कर्जा देने का पेशा नहीं करते। बल्कि किसी साल ईश्वर की फसल लग गई तो कुछ रुपया निकल आया और वह रुपया अपने पड़ोसी को ज़रूरत पड़ी तो दे दिया बिना कुछ लिखाये या कभी कभी दस्तावेज लिखा कर रुपया दे देते हैं। वह सब खेती करते हैं। हाथ फेल गया तो छोटा मोटा कर्जा दे दिया। बहुत से किसान रेहन लिखाते हैं। अपने पड़ोसी को रुपया देकर उसका बीघा दो बीघा खेत लिखा लिया। आप चाहते हैं कि उसका रुपया खतम हो जाय तो यह कोई जंचने वाली बात नहीं है। फिर कर्जों के लेने की बात है। यह मैं मानता हूँ कि हमारे किसानों की हालत खास कर पूर्वी जिलों के और इस साल तो पश्चिमी जिलों में भी बर्निस्वत पिछले सालों के कुछ बढतर है। फिर भी आज कर्जा बहुत कम है। रजिस्ट्री और रेहननामों के आंकड़ों को अगर आप जाकर देखें, नीलाम और कुरकी के आंकड़ों को देखें तो साबित होगा कि कर्जों बहुत कम लिये गये हैं। कम से कम जो छोटे लोग गांव के हैं। उनके ऊपर कर्जा बहुत ही कम है क्योंकि सन् ३६ में जो कांग्रेस मिनिस्ट्री थी उसने एक डेट रिडम्पशन ऐक्ट बनाया था, उससे फिर उसके बाद ही इन्फ्लेशन आया, यानी किसानों की जो पैदावार थी उससे उनको पैसा ज्यादा मिला। रियल वैल्यू भले ही बढी हो या न बढी हो, मगर पैसा उनके पास काफी बढ गया। लगान या आबपाशी का जो देते थे वह तो उतना ही रहा। मगर सेविंग दूनी हो गई और कर्जा बहुत बेबाक हो गया। कर्जा हुआ तो इस साल या पिछले साल थोड़ा बहुत लोगों पर हुआ होगा और इसका सबूत यह है कि आप दीवानी में चले जाइये वहां जाकर वकीलों से पुछिये तो वह कहेंगे कि वहां नालिशों का या दस्तावेजों का वह नम्बर नहीं है जो और सालों में हुआ करता है तो कर्जा कम की एक बात है। दूसरी बात यह है कि कर्जा लेने और देने वाले अमूमन वही हैं जो काश्त करते हैं और जिनका पेशा काश्तकारी ही है न कि मनीलेंडिंग बिजनेस। तीसरी बात यह है, इसको मैं पहले भी कह चुका हूँ कि आखिर सौ की ही क्यों लिमिट रखी जाय क्यों न ढाई सौ की रखी जाय। आखिर मनीलेन्डर्स ने क्या कसूर किया है। जब आप हर जमींदार को मुआविजा दे रहे हैं, देने या न देने के मसले में दो राय है और हर मसले पर दो राय हुआ करती है, लेकिन हमने तय किया है कि मुआविजा दिया जाय तो जब उनको मुआविजा दिया जा रहा है तो यह युक्ति संगत नहीं है कि साहूकारों का कर्जा न दिया जाय और जमींदारों को मुआविजा दिया जाय।

शैंड्यूल बैंक्स की बात कही गई। कहा गया कि उनका कर्जा नहीं घटाया गया। कुंवर साहब की शिकायत थी कि क्यों नहीं उनका कर्जा घटाया गया और इसके न होने

की वजह से जमींदारों को कुछ सुभीता नहीं हो रहा है। आमतौर पर शेड्यूल बैंक्स बहुत कम कर्ज के बिल की बात तीन चार साल से चल रही है। इस बीच मुझे एक या दो बैंक्स की बात याद है जिन्होंने इस बात की कोशिश की कि वह इस कानून की जद से सहफुज कर दिये जायं यानी उनका कर्जा दिलाया जाय और उसे न घटाया जाय। इससे मालूम होता है कि आमतौर पर बड़े बैंक्स जमींदारों को कर्जा नहीं देते हैं और यही दो एक बैंक्स हैं जिन्होंने कर्जा दिया, लिहाजा कुंदर साहब को इस पर कोई चिन्ता न करनी चाहिये। शेड्यूल बैंक्स की जो बात है वह यह है कि वह मनी लेंडिंग का काम नहीं करते बल्कि यह सव्सी-डेयरी हैं और अगर किन्हीं एक दो बैंक्स ने कर्ज दिया है तो अगर वह घटाया गया तो डिपॉजिटर्स को नुकसान होगा। इस तरह से बैंक्स को नुकसान होने से डिपॉजिटर्स को जरूर नुकसान होगा। इसीलिये हमने शेड्यूल बैंक्स को इस बिल के आपरेशन से मुबर्रा रखा है।

बहुत देर तक मैं सुनता रहा लेकिन साहूकारों के बारे में किसी ने कुछ नहीं कहा। टंडन साहब ने जरूर कुछ कहा है। जहां तक कॉर्पोरेट गवर्नमेंट का संबंध है वह सब की है। हम आख मीच कर या एक आख बन्द करके काम नहीं कर सकते और यह मुनासिब भी नहीं है। जो बात उचित है वही करना चाहिये। जहां तक हो सके काम भी हो जाय और खून भी न निकले, यह हमारी कोशिश है। मेरी समझ में नहीं आता कि फिर शिकायत किस बात की की जाती है। सिद्धांत यह है कि जिसकी वजह से यह बिल आया कि जमींदारों की स्टेट ली गई उनकी पेइंग कैपेसिटी (Paying capacity) कम हुई। हमारे बिल का उद्देश्य यह है कि जिस क्रदर जिस हद तक उनकी पेइंग कैपेसिटी कम हुई है उसी हद तक कर्ज भी कम कर दिया गया है। अब आप यह चाहते हैं कि जमींदारों की पेइंग कैपेसिटी तो थोड़ी सी कम हुई लेकिन उसका कर्ज बिलकुल ही माफ कर दिया जाये। तो जिस क्रदर आप की पेइंग कैपेसिटी कम हुई है उसी क्रदर आपको रिलीफ भी मिलना चाहिये। यह कर्ज हमने किसी उद्देश्य की बिना पर कम किया है। इसमें जमींदार और मनी लेंडर किसी की शिकायत नहीं होनी चाहिये। जमींदारी खत्म की गई वह टाइम की मांग थी। हमने जमींदारों से कहा कि आप थोड़ी सी सैक्रिफाइस कीजिये। और उसी हद तक हम मनीलेंडर्स से भी कहते हैं कि वह भी थोड़ी सी कुरबानी करें। लेकिन यह नहीं हो सकता कि हम जमींदारों को तो कंपेन्सेशन दें और मनीलेंडर्स से कहें कि तुम कर्ज बिलकुल ही छोड़ दो। उनका सब का सब जवत कर लें। यह जो इनकम्बर्ड स्टेट ऐक्ट का मल्टिपल मुल्टिलिफ जगहों पर मुल्टिलिफ है उसका मतलब यह है मिसाल के लिये आप बदायूं जिले को ले लीजिये। बदायूं में २० गुना इनकम्बर्ड स्टेट पर है तो वहां पर एक तिहाई हुआ और इलाहाबाद में ४० गुना है तो वहां पर पांचवां हिस्सा होगा। लिहाजा दोनों जगह बिला वजह डिसक्रिमिनेशन हो जायेगा। जो जायदाद बदायूं की है उसकी हैसियत के लिहाज से वहां पर कर्जा दिया गया है मान लीजिये कि इलाहाबाद में ४० गुना दिया गया तो उसके माने यह है कि वहां पर उसकी हैसियत से ज्यादा दिया गया है अगर दोनों जगह एक रकवा लीजिये तो मान लीजिये कि २० बीघा बदायूं में और २० बीघा इलाहाबाद में जायदाद है, तो बदायूं में २० बीघे पर ६० रुपया कर्ज दिया गया और इलाहाबाद में १०० रुपया दिया गया है तो वहां पर एक तिहाई होगा और दूसरी जगह पांचवां हिस्सा होगा। इसलिये डिसक्रिमिनेशन नहीं होता है।

सिम्पल डेट्स का जिक्र किया गया। सादे कर्जों के मुतालिक उसमें एक खंड दिया हुआ है। खंड ६, उसमें यह है कि आपका कर्जा दस्तावेज की बिना पर है या हैसियत की बिना पर है। अगर उसकी डिग्री हो गई है तो आपका कर्ज वसूल हो जायेगा, मैं मिसाल देकर समझाने की कोशिश करता हूं। डाक्टर ईश्वरी प्रसाद इत्तिफाक से इस वक्त यहां पर नहीं है वह कहते थे कि दो चार कंफरोट मिसाल दी जायं तो ज्यादा समझ में आ जाय। मान लीजिये कि ढाई हजार कर्जा है और वह भी सिम्पल मनी डिक्री का है। अब एक जमींदार को जिस पर यह कर्जा है उस को अनुदान और प्रतिकर दोनों मिलाकर ४ सौ मिलते हैं। उस पर ढाई हजार रुपये को डिग्री हो गयी। तो वह आदमी जिस का कर्जा है वह किसी भी जायदाद पर चाहे भूमिधर की हो या कोई कारखाना हो, वह वसूल कर सकता है। लेकिन अगर अनुदान और

[श्री चरण सिंह]

प्रतिकर से वसूल करना चाहे तो ४ सौ रुपये के प्रतिकर और अनुदान पर तीन चौथाई की शर्त रहेगी। लेकिन जितने जितने का वह आदमी रहने वाला है वहाँ का मल्टीपल अगर ३२ है तो उस को १६ तो बेझाको मिल जायेगा। अगर वह किसी ऐसे जगह का रहने वाला आदमी है जहाँ का मल्टीपल ४० है तो कर्जा एक बड़ा पांच होना चाहिये और उस का प्रतिकर तथा अनुदान ४ सौ पर ले ले इस का पांच गुना कर दो हजार हो जाता है तो इसमें अभी पांच सौ बाकी रहेगा। यह सिर्फ उस रूप में है जब अनुदान और प्रतिकर के खिलाफ कोई प्रोसीडिंग करना चाहे क्योंकि उसको हैसियत तो घट गई है। जब जमींदारी की कीमत घट गयी है तो वह कैसे उस पर ढाई हजार वसूल कर सकता है। श्रीमती तारादेवी अग्रवाल ने प्रश्न किया था और जितने को मैंने अपनी इन्तर्दाई तक्रारी में भी साफ कर दिया था लेकिन उस को मैं फिर दोहराना चाहता हूँ। बात सीधी है कि इस बिल की मंशा यह है कि किसी स्टेट पर या जिसे हम आशयान भी कहते हैं उसके लिये भूमि व्यवस्था अधिनियम में यह कहा है कि जिस कदर जमीन की कीमत घटी है उस कदर कर्जों में भी कमी कर दी जायेगी। जितने रुपये उस की जायदाद के हिस्से में आते हैं उस हिस्से में से इतनी कमी की जायेगी, मसलन एक कारखाना है और उसकी कीमत ५० हजार रुपये है। जिस का यह कारखाना है उस का एक गांव में खेवट भी है और उस की कीमत १५ हजार रुपये मल्टीपल हैसियत से आ जाती है तो ये दोनों मिलाकर ६५ हजार हो जाते हैं। इस ६५ हजार में मानलीजिये २६ हजार कर्जा है। डेट जो है वह सेक्योर है तो इस २६ हजार कर्जों का मतलब है कि २० हजार रुपया फेक्ट्री पर हुआ और ६ हजार रुपया खेवट पर हुआ जिसकी कीमत १५ हजार रुपये है। अब मान लीजिये इस १५ हजार के खेवट पर अनुदान और प्रतिकर दोनों मिल गये और वह ४० हजार रुपया है। तो इस ४० हजार में जो जमींदार पर कर्जा आया वह केवल ६ हजार ही आया।

अब मैं एक बात अपने माननीय मित्रों से कहना चाहता हूँ। यह बात गौर करने की है। अगर कम्पेन्सेशन और रिहैबिलिटेशन ग्रांट, जितना कर्जा आया है उस से ज्यादा है तो जब यह बिल ऐक्ट बन जायेगा उस के मातहत यह ६ हजार रुपया उस ४० हजार रुपये से वसूल नहीं हो सकता। वह ६ हजार में से घट गया। मान लीजिये वहाँ १ बड़ा पांच है तो वह ८ हजार हो गया। ऐसी सूरत में कर्जा जरूर घटेगा। अभी श्री महावीर सिंह जी की एक तरमीन आये आने वाली है जिस के अनुसार १ बड़ा ५ कर्जा हर जगह हो जायेगा। यदि अनुदान और प्रतिकर उससे ज्यादा भी है तब भी वह कर्जा उससे पूरा वसूल नहीं होगा। वह फिर १ बड़ा ३ घटाया जायेगा और १ बड़ा ५ किया जायेगा। तो श्रीमती तारा देवी अग्रवाल ने जो प्रश्न उठाया था, उसका जवाब यह है कि जो २६ हजार का कर्जा था वह २६ हजार घटाया नहीं जा रहा है बल्कि वह ६ हजार बढ़ा क्योंकि २० हजार तो फेक्टरी पर पड़ा और ६ हजार खेवट पर पड़ा। ६ हजार रुपये जो लैन्ड के जिम्मे आये थे उसमें से घटा है। अब मान लीजिये किसी खेवट पर अनुदान और प्रतिकर ८० रुपया आया और उस पर अदालत में ६ हजार रुपया कर्जा करार दिया गया तो वह उसका १/५ हो कर केवल १२ सौ ही रह जायेगा। वह वसूल भी हो सकता है। लेकिन उस को प्रतिकर और अनुदान केवल ८० रुपये ही मिले हैं तो वह ६० रुपये ही ले सकता है। तो इतनी चीज हो गई है।

यह मैं समझता हूँ कि मेरी कुछ गलत कहने की आदत हो गई है लेकिन वह आदत किसी आधार पर है। गवर्नमेंट और उसकी पार्टी जो काम करती है वह बहुत समझदारी के साथ काम करती है। इतना मैं जरूर कहूँगा कि यहाँ की सरकार ने जमींदारों के साथ जिस उदारता का बरताव किया वह शायद और कहीं पर नहीं हुआ। हम जो उसूल बनाते हैं वह देश के फायदे के लिये ही बनाते हैं। हम भी देश का फायदा चाहते हैं। वास्तव में जो अन्रैडेड प्रायरटी है उसको घटा नहीं रहे हैं। मैंने हर माननीय सदस्य के सवाल के जवाब को देने की कोशिश की। हो सकता है कि कुछ रह गया हो तो मैं उसको

आइन्दा तकरीर में जवाब देने की कोशिश करूंगा। डा० ईश्वरी प्रसाद इस समय इस सदन में मौजूद नहीं हैं वरना मैं उनकी बात का भी जवाब दे देता। उन्होंने जो बात कही वह बिल्कुल निर्मूल है। यहां पर कोई कालेज और स्कूल नहीं है जहां पर गैर-जिम्मेदार लड़कों की बातें हों। यहां पर जो काम होता है वह जिम्मेदारी के साथ होता है। हम महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर बराबर चलते हैं। १५ साल के बजाय ६ साल बैंक नम्बर हो जाय, मैं तो समझता हूं कि ऐसा नहीं हो सकता है। इसके लिये कई मिसालें अंग्रेजी में दी गईं। यहां पर च्यांगकाई शोक का भी जिक्र किया गया। उन्होंने जो क्रदम उठाया था वह दूसरा था। हमारे यहां लेजिस्लेचर है, कांस्टीट्यूशन है, जैसा कि डिमांडेसी में होना चाहिये। यहां पर इतिहास से कोई संबंध नहीं है कि किसने क्या किया है। हमारी सरकार तरक्कीयावत है और ठीक रास्ते पर चलती है। मैं आशा करता हूं कि जो प्रस्ताव मैंने विचार करने के लिए पेश किया है उस को यह सदन स्वीकार करेगा।

डिप्टी चैयरमैन—प्रश्न यह है कि सन् १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारों के ऋण कम करने के विधेयक पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड २

२--विषय या प्रतीक में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस अधिनियम परिभाषाएँ :
में :—

- (क) "देय धनराशि (amount due)" का तात्पर्य उस धनराशि से है जो, यदि यह अधिनियम पारित न होता तो, देय होती;
- ऐक्ट १०,
१८६७। (ख) "केन्द्रीय सरकार" का वही अर्थ है जो जेनरल क्लॉजेज ऐक्ट, १८६७, की धारा ३ में "सेंट्रल गवर्नमेंट" को दिया गया है;
- (ग) "कोर्ट आफ वार्ड्स" का तात्पर्य यू० पी० कोर्ट आफ वार्ड्स ऐक्ट, १९१२, के अधीन संघटित कोर्ट आफ वार्ड्स से है।
- (घ) "डिक्री" का वही अर्थ है, जो उसे कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८, में दिया गया है;
- ऐक्ट ५,
१९०८। (ङ) "डिक्री जिसके विषय में यह अधिनियम प्रवृत्त होगा" का तात्पर्य ऐसी डिक्री से है जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से पूर्व अथवा पश्चात् ऐसे वाद में दी गई हो जिसके विषय में यह अधिनियम प्रवृत्त होता हो (a suit to which this act applies);
- (च) "ऋण (debt)" का तात्पर्य किसी भी ऐसे ऋण (advance) से है जो नक़द या वस्तु के रूप में दिया गया हो और उसके अन्तर्गत कोई भी ऐसा संव्यवहार (transaction) है जो वास्तव में (in Substance) ऋण के रूप में हो किन्तु इसके अन्तर्गत ऊपर कहा गया कोई ऐसा ऋण (advance) जिसका १ जुलाई, १९५२ को या उसके बाद अस्तित्व हुआ हो, अथवा जो निम्नलिखित को देय हो, ऋण नहीं है—

(१) केन्द्रीय सरकार अथवा किसी राज्य की सरकार;

(२) स्थानिक अधिकारी (local authority);

उत्तर प्रदेश
अधिनियम
१, १९५१ ।

- (३) शेड्यूल्ड बैंक;
- (४) सहकारी संस्था (co-operative society), तथा
- (५) वक्फ, न्यास (trust) या निबन्ध (endowment) जो केवल दानोत्तर अथवा धर्मोत्तर हों।
- (६) व्यक्ति, यदि ऋण उसकी ओर से कोर्ट आफ वाड्स द्वारा किसी संरक्षित व्यक्ति को दिया गया हो।

(छ) “दानोत्तर”, “आस्थान”, “प्रतिकर”, “पुनर्वासन अनुदान” तथा “धर्मोत्तर” का वही अर्थ है जो उन्हें क्रमशः १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारों विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम में दिया गया है और प्रतिकर के अन्तर्गत उक्त अधिनियम की धारा २६ के अधीन देय अन्तरिम प्रतिकर भी है।

(ज) “स्थानिक अधिकारिकी” के अन्तर्गत कान्टेनमेंट बोर्ड भी है;

(झ) “बन्धक” का आपने अनुरूप पदों सहित वही अर्थ होगा जो ट्रान्सफर आफ प्रापर्टी ऐक्ट, १८८२, में “mortgage” को दिया गया है और उसके अन्तर्गत ऐसा भार भी है जिसकी परिभाषा ‘charge’ के रूप में उक्त ऐक्ट की धारा १०० में की गई है;

(ञ) “बन्धककर्ता (mortgagor)”--

(१) के अन्तर्गत, यदि बन्धक किसी संयुक्त हिन्दू परिवार के प्रबन्धक अथवा कर्ता के रूप में अथवा प्रतिनिधि के रूप में निष्पादित किया गया (executed) हो, तो सभी सहभागी (co-parceners) अथवा वे व्यक्ति जिनका इस प्रकार प्रतिनिधित्व किया गया है, भी हैं; और

(२) का तात्पर्य, यदि बन्धककर्ता के अधिकार, आगम तथा स्वत्व फ़रीक़न (parties) के कृत्य अथवा विधि के व्यापार (operation of law) से, दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के पक्ष में संश्रामित हो गये हों तो ऐसे व्यक्ति अथवा व्यक्तियों से है;

(ट) किसी आस्थान में मातहतदार (under-proprietor) “अवना मालिक (sub-proprietor), ठेकेदार अवध का पट्टेदार दवामी या इस्तमरारी (permanent lessee in Avadh) या दवामी काश्तकार (permanent tenure holder) के स्वत्व के बन्धक के सम्बन्ध में “स्वामी (proprietor)” का तात्पर्य धारा ३ और ४ और अनुसूची १ में, उक्त आस्थान के, यथास्थिति, मातहतदार, अवना मालिक, ठेकेदार, पट्टेदार दवामी या इस्तमरारी या दवामी काश्तकार से है;

(ठ) “शेड्यूल्ड बैंक” का वही अर्थ है जो रिजर्व बैंक आफ इंडिया ऐक्ट, १९३४, में उसे दिया गया है;

- (ड) “सुरक्षित ऋण (secured debt)” का तात्पर्य किसी आस्थान अथवा किसी आस्थान तथा दूसरी अचल सम्पत्ति के बन्धक द्वारा सुरक्षित ऋण से है;
- (ढ) “राज्य सरकार” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है;
- (ण) “वाद जिसके विषय में यह अधिनियम प्रवृत्त होता है” का तात्पर्य किसी ऋण से सम्बद्ध वाद अथवा व्यवहार (suit or proceeding) से है चाहे उक्त ऋण सुरक्षित हो अथवा अन्यथा; और
- (त) “संरक्षित व्यक्ति” का अर्थ वही होगा जो शब्द “वार्ड (award)” का यू० पी० कोर्ट आफ वार्ड्स ऐक्ट, १९१२, की धारा ३ की उपधारा (३) में किया गया है।

श्री प्रभु नारायण सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन उपस्थित करना चाहता हूँ। खं० ३२ के उपखंड (ड) के बाद निम्नलिखित नया उपखंड (डड) बढ़ा दिया जाय :—

(डड) “पुनर्वासन अनुदान” का तात्पर्य किसी ऐसे पुनर्वासन अनुदान से है जो १९५० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम के अनुसार २५० रुपये से अधिक सालाना मालगुजारी देने वाले जमींदारों को दिया गया हो।”

हम यह चाहते हैं कि खंड दो निकाल दिया जाय। इसके निकाल देने से मतलब साफ हो जायगा। मैं आशा करता हूँ कि मंत्री जी इस संशोधन को स्वीकार करेंगे।

श्री चरणसिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैं अभी अर्ज कर चुका हूँ कि मैं तक्रारीबन सारी बातें ही इस सिलसिले में कह चुका हूँ, लेकिन एक बात कहने से रह गई है। अच्छा हुआ कि इस संशोधन के जवाब में उसको कहने का मौका मुझे मिल गया और वह यह है कि जो छोटे मध्यवर्ती हैं उनके पास सीर और खुदकाश ज्यादा है और बड़े मध्यवर्ती के पास सीर और खुदकाश अपेक्षितया पूरी है और छोटे के पास अपेक्षितया ज्यादा है और जितना ही सीर और खुदकाश ज्यादा है उतना ही प्रतिकर और अनुदान उनको कम मिलेगा। तो जितना प्रतिकर मिला, उससे उनका कर्जा बेबाक हो जायेगा। जैसे कि कोई ६० बीघे का मालिक है और ५६ बीघे का मुआविजा मिला तो फिर आपको क्या मिला, आपको तो कोई मुआविजा नहीं मिला और ऐसे लोगों की तादाद ज्यादा है, इसलिये वह रकम ज्यादा हो जाती है और जो अनुदान है वह भी केवल अनुमान की ही बात है, कुल कितन आंकड़े बैठेंगे यह कहना भी मुश्किल है, लेकिन आदमी जितना छोटा है उतना ही उसको प्रतिकर कम मिलेगा, लिहाजा उसका कर्जा उतना ही माफ़ है। इसलिये कोई अन्देशा नहीं है। फिर मैं अर्ज करता हूँ कि वह चीज खंड ८ (२) में दी हुई है और किसी चीज से बसल हो ही नहीं सकेगी। मान लिया जाय कि ६० बीघा है और वह सारी जमीन सिक्योरिड है और मान लिया जाय कि किसी ऐसे बेवकूफ साहूकार ने ६ हजार का कर्जा दिया या ६ हजार की डिक्ली हुई और वह १२ सौ की रह गई या मान लिया जाय कि ३० हजार की डिक्ली हुई और वह ६ हजार रह गई तो उससे हम क्या लगायें। जो ६ हजार का भूमिधर हुआ सिर्फ पुनर्वास अनुदान या प्रतिकर ही ले सकता है। पहले तो यह था कि वह ६० बीघा का नीलाम कर सकता था, लेकिन अब वह उसका नीलाम नहीं कर सकता है। सिर्फ उसको अनुदान या प्रतिकर ही मिलता है, उससे ही वह काट सकता है। क्योंकि ट्रांसफर आफ प्रापर्टी ऐक्ट की जो दफा ७३ है, उसके मुताबिक उसको राइट्स हैं कि वह कर्जा ले सकता है

[श्री चरण सिंह]

और जो मुआविजा मिले या उसका जो पुनर्वास अनुदान या प्रतिकर मिले तो उससे ही उस कर्जे की अदायगी हो सकती है। अब मान लिया जाय कि उसको एक रुपया मिला, १० मिला या १०० मिला या जितना भी मिला, वह उसे ले सकता है। जमीन जो पहले नीलाम हो जाती थी, तो आज जमीन का नीलाम नहीं हो सकता है क्योंकि वह भूमिधर हो गया है और उसका मुआविजा ही वह ले सकता है। मगर इसमें रिहैबिलिटेशन का प्रैक्टिकली कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इसके डिटेल् की तीन-चार चीजें हैं। एक आदमी का अधिकार होता है हस्तान्तरण करने का, जमीन का इस्तेमाल करने का, या इस्तेमाल न करने का या बुरी तरह से इस्तेमाल करने का। यह चार प्रोपराइटरीशप की किस्में हैं, यानी सदुपयोग, दुरुपयोग, अनुपयोग और हस्तान्तरण। दुरुपयोग इस रूप में हो सकता है कि जमीन को लीज पर उठाना और सदुपयोग के रूप में यह आता है कि सेल्फ कल्टीवेशन जो करता है वह सदुपयोग होता है। सदुपयोग एग्रीकल्चर के लिये ही नहीं बल्कि नान एग्रीकल्चरल परपज के लिये भी कर सकता है। इसका अधिकार उसको पहले से ही रहा है।

जमींदार नहीं हो सकता है तो जमींदार और भूमिधर में यह फर्क है। बहुत से लोग कहते हैं कि साहब जमींदार और भूमिधर में कोई फर्क नहीं है, वही लैंड लाईजेंस है, लेकिन वह अब लैंडलार्ड नहीं है बल्कि लैंड ओनर है और पहले जब कि जमींदारी खत्म नहीं हुई थी तो उनकी जमीन नीलाम हो जाती थी, आज जमींदारी खत्म हो गई है। जमीन उसके ही पास रहेगी और वह भूमिधर कहलाने लगे और पुनर्वास अनुदान जो ३/४ मिला तो वही वह ले सकता है और जमीन को नहीं ले सकता है। तो इस नुक्ते निगाह से अगर देखा जाय तो कोई नुकसान नहीं हो रहा है, उल्टे लाभ ही हो रहा है और इतना फायदा हो रहा है जितना हम सोचते हैं कि हमारे और आपके जहन में नहीं है। इसलिये इसके बाद यह बिल्कुल अनावश्यक है।

श्री प्रभु नारायण सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो राय जाहिर की, उससे यह मालूम होता है कि छोटे जमींदारों का इससे फायदा होगा, तो जहां तक फायदे का सवाल है, तो यह तो हम पहले से ही इस बात को समझ कर इस बिल का समर्थन कर रहे हैं और चूंकि इससे छोटे जमींदारों का भी फायदा होने वाला है....

श्री चरणसिंह—मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आपको और आपके मित्रों को यह बात मालूम है कि वह जमीन नीलाम हो जायेगी। मगर मैं आपको एक नई बात बतलाना चाहता हूं और वह यह है कि उसकी जमीन नीलाम नहीं होती है। जब इस तरह से हो जायेगा तो उसको क्या नुकसान होगा।

श्री प्रभु नारायण सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, बात यह है कि किसी खास हद तक लोगों को पूरी जमीन हम देना चाहते हैं। चूंकि हमारे मंत्री महोदय की वैसी राय है तो उस राय का क्या किया जाय। अपनी राय रखने का हक सबको है और मैं समझता हूं कि मंत्री जी ने अपनी राय दी है और उन्होंने जो बात कही है यदि उसका जवाब दिया जाय तो उसके लिये एक बड़ी तक्रारीर देनी पड़ती है। मैं इस समय मंत्री जी से इतना ही कहना चाहता हूं और मंत्री जी से ही क्या, बल्कि सदन के सामने यह बात निवेदन करना चाहता हूं कि अगर यह संशोधन मान लिया जाय तो इससे छोटे जमींदारों को बहुत बड़ा फायदा हो जाये। तो यह बात सिर्फ छोटे जमींदारों की भलाई के लिये ही होगी और इस बात का ख्याल रखते हुए मैं समझता हूं कि यह संशोधन बिल्कुल वाजिब है और मंत्री जी को इसको मान लेना चाहिये।

श्री चरणसिंह—मुझे अफसोस है और मुझे इस बात का भी अफसोस है कि मेरे न मानन से वे नाराज न हो जायें।

डिप्टी चेयरमैन—प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (ड) के बाद निम्नलिखित नया उपखंड (डड) बड़ा दिया जाय :—

(डड) “पुनर्वासित अनुदान” का तात्पर्य किसी ऐसे पुनर्वासित अनुदान से है जो १९५० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम के अनुसार २५० रुपये से अधिक सालाना मालगुजारी देने वाले जमींदारों को दिया गया हो।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री जमीलुर्रहमान किदवई (स्थानीय संस्थाएँ निर्वाचन क्षेत्र)—

Sir, I beg to move that in sub-clause (f) lines 3 and 4 of clause 2 the words “an advance” be substituted for the words “and advanced.”

श्री चरणसिंह—मुझे स्वीकार है।

डिप्टी चेयरमैन—The question is that in sub-clause (f) lines 3 and 4 of clause 2 the words “an advance” be substituted for the words “and advanced”.

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री कुंवर महावीर सिंह—उपाध्यक्ष जी, आपकी इजाजत से मैं श्री ज्योति प्रसाद जी के प्रस्ताव को पेश करना चाहता हूँ।

Sir, I beg to move that in sub-clause (f) (v) of clause 2 the word “purposes” be replaced by “purpose”.

श्री चरणसिंह—मुझे स्वीकार है।

डिप्टी चेयरमैन—The question is that in sub-clause (f) (v) of clause 2 for the word “purposes” the word “purpose” be substituted.

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

डिप्टी चेयरमैन—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड २ इस बिल का भाग बना रहे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ३

३—(१) किसी विधि अथवा अनुबन्ध (agreement) डिक्की देते अथवा लेख्य (document) में किसी बात के होते हुए भी सुरक्षित ऋण समय ऋण से सम्बद्ध किसी ऐसे वाद में जिसके विषय में यह अधिनियम प्रवृत्त होता है, का कम न्यायालय, देय धनराशि के अवधारित होने पर, किन्तु डिक्की देने से पूर्व यहाँ करना। पर आगे लिखे के अनुसार कार्यवाही करेगा।

(२) यदि बन्धक की गई संपत्ति (mortgaged property) उत्तर प्रदेश में केवल आस्थान ही हो और उक्त आस्थान १९५० ई० उत्तर प्रदेश जमींदारी अधिनियम १, विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम के अधीन हस्तगत कर लिया गया हो १९५१। तो न्यायालय,

(क) यदि एक ही बन्धककर्ता हो, जो ३० जून, १९५२ ई० को उक्त आस्थान के स्वामी के रूप में अधिकारी था, अनुसूची १ में दिये हुये सूत्र (formula) के अनुसार देय धनराशि को कम कर देगा;

(ख) यदि दो या अधिक बन्धककर्ता हों, और उनमें से सभी या एक से अधिक ३० जून, १९५२ ई० को उक्त आस्थान के स्वामी के रूप में अधिकारी थे तो

(१) यदि बन्धक पत्र (mortgage deed) में ऋण के लिए उनका अपना-अपना उत्तरदायित्व निर्दिष्ट किया गया है, उनके अपने दायित्व के अनुपात में (in the ratio of their liability) देय धनराशि को उक्त प्रकार के अधिकारी बन्धककर्ताओं में विभाजित कर देगा, अन्यथा उक्त आस्थान में उनके अपने-अपने अंशों के अनुपात में; और

(२) देय धनराशि के उक्त प्रकार विभाजित होने के बाद प्रत्येक बन्धक कर्ता के लिये विभाजित धनराशि को अनुसूची १ में दिये हुये सूत्र के अनुसार कम कर देगा।

(३) जब बन्धक की गई सम्पत्ति अंशतः उक्त प्रकार का आस्थान हो और अंशतः उक्त प्रकार के आस्थान से भिन्न दूसरी सम्पत्ति हो, तो न्यायालय दोनों सम्पत्तियों पर देय धनराशि को ट्रांसफर आफ प्रापर्टी ऐक्ट, १८८२ की धारा ८२ में उल्लिखित सिद्धान्तों के अनुसार अलग-अलग विभाजित करेगा, मानों वे सम्पत्तियां दो ऐसे विभिन्न व्यक्तियों की थीं जिनका पृथक् तथा भिन्न स्वत्वाधिकार रहा हो और—

(क) देय धनराशि के उक्त प्रकार से विभाजित होने के पश्चात् निम्नलिखित कार्यवाही करेगा—

(१) यदि केवल एक ही बन्धककर्ता था जो ३० जून, १९५२ को उक्त आस्थान के स्वामी के रूप में अधिकारी था तो उपधारा (२) के खंड (क) में लिखी रीति के अनुसार आस्थान द्वारा देय धनराशि को कम कर देगा मानों वह उक्त आस्थान पर भारित (charged) ऋण हो, तथा

(२) यदि दो या अधिक बन्धककर्ता हों और उनमें से सभी या एक से अधिक बन्धक किये हुये आस्थान के ३० जून, १९५२, को स्वामी के रूप में अधिकारी रहे हों तो यदि बन्धक पत्र में उनका अपना-अपना उत्तर-दायित्व निर्दिष्ट हो तो उनके दायित्व के अनुपात में आस्थान द्वारा देय धनराशि को बन्धककर्ताओं में विभाजित कर देगा अन्यथा उक्त आस्थान में उनके अंशों के अनुपात में; और

(ख) जब देय धनराशि इस प्रकार विभाजित हो जाय तो न्यायालय अनुसूची १ में दिये हुये सूत्र के अनुसार प्रत्येक बन्धक कर्ता द्वारा देय धनराशि को कम कर देगा।

श्री कुंवर महावीर सिंह—मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उपखंड (१) में शब्द “किन्तु” निकाल दिया जाय और आगे लिखे शब्दों के पहिले शब्द “यहां पर” और पीछे शब्द “के” निकाल दिये जायें।

श्री चरण सिंह—मैं चाहता हूं कि शब्द “किन्तु” रहे और अल्फाज “यहां पर” और “के” निकाल दिये जायें।

डिप्टी चैयरमैन—प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (१) में से शब्द “यहां पर” और “के” निकाल दिये जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री कुंवर महावीर सिंह—मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के उपखंड २ (ख) १ में शब्द “उक्त प्रकार के अधिकारी” के स्थान पर शब्द “उन अधिकृत” रख दिये जायें।

श्री चरणसिंह—मुझे स्वीकार है।

डिप्टी चैयरमैन—प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड २ (ख) १ में शब्द “उक्त प्रकार के अधिकारी” के स्थान पर शब्द “उन अधिकृत” रख दिये जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री कुंवर महावीर सिंह—मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के उपखंड २ (ख) में शब्द “बाद” के स्थान में शब्द “पश्चात्” रखा जाये।

श्री चरणसिंह—मुझे स्वीकार है।

डिप्टी चैयरमैन—प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड २ (ख) में शब्द “बाद” के स्थान में शब्द “पश्चात्” रखा जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री प्रभु नारायण सिंह—मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के उपखंड (३) के बाद निम्नलिखित नया उपखंड (४) बढ़ा दिया जाये।

(४) यदि बंधक दी गई संपत्ति में बंधककर्ता (mortgagee) व उसके कुटुम्ब का स्थायी निवास (permanent residence) भी सम्मिलित हो तो न्यायालय उक्त निवासस्थान को किसी भी अन्य विधि के रहते हुये भी ऋण के देय धनराशि व डिक्की के अभिप्राय से मुक्त कर देगा।

इस संशोधन के लाने का मतलब यह है कि जमींदार का परमानेंट रेजिडेंस जो उसका निवासस्थान है वह कम से कम डिक्की से मुक्त होना चाहिये। इस सिलसिले में केवल यह बात कहना है कि सरकार तो बड़ी न्यायप्रिय है और खासतौर से जमींदारों के साथ बड़ी हमदर्दी रखती है इसलिए मैं आशा करता हूं कि कम से कम जो जमींदारों के परमानेंट निवासस्थान हैं वह तो उनके लिये छोड़ देगी। यह बात सही है कि देहात में एग्रीकल्चरल रिजोर्न एक्ट के मुताबिक जो खेत के मकान होंगे वह जरूर छूट जायेंगे लेकिन यह हो सकता है कि कोई आदमी वहां पर न रह कर किसी ऐसी जगह पर रहता हो, जहां खेत न हों।

श्री चरणसिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, संशोधन तो जो कुछ है वह तो है ही, लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरे मित्र वकालत और पैरवी भी करते जाते हैं और साथ ही साथ उलाहना भी देते हैं। जमींदारों के साथ मुझे हमदर्दी है इसमें शक नहीं, आज कुंवर गुरु नारायण जी इसको मानें या न मानें। खैर, इसमें शलतफहमी हुई। इस संशोधन की कोई जरूरत नहीं है। दफा सात जान्ता दीवानी के मातहत उसका रहायसी मकान और मकानात जो कि किसान के कब्जे में बहसियत काशत हों वह पहले से भी कुर्क नहीं हो सकते। सन् १९४६ ई० में जब गवर्नमेंट आई उस समय में दीवानी की वकालत करता था। मैंने देखा कि साहूकार किसान के मकान को आड़ करा लिया करता था, मारगेज करा लिया करता था, क्योंकि सेक्शन ६० में सादे कर्ज की डिक्की की इजराही में ही

[श्री चरण सिंह]

वह मुस्तसना हो सकता था। और सेक्शन साठ में यह लिखा है कि अटैचमेंट से बरी होगा। लेकिन आज मारगेज की डिगरी होती है उसमें अटैचमेंट नहीं होता। उसमें एकदम सेल होता है। लिहाजा साहूकारों ने यह तरकीब की कि उन्होंने किसानों के मकानों को मारगेज करा लिया। सेक्शन ८ का मंशा जो फायदा देने का था उससे वह लोग महरूम हो गए। इसलिये हमने सन् १९४७ में यह तहरीक की कि अगर मकान उसका मारगेज भी हो जाये तब भी उसका सेल नहीं हो सकता। लिहाजा हमने यह अटैचमेंट कर दिया कि रहायश के मकानों के अलावा भी जिन मकानों को उसको बहसियत किसान के जरूरत पड़ती है मसलन जहां वह चारा रखता है या अपने जानवरों को बांधता है वह भी मुस्तसना पहले सेथे और अब आड़े कब्जे में मुस्तसना होंगे। और यही नहीं, अगर शहर के अन्दर भी वह किसान रहता है तो वहां भी मुस्तसना रहे। फिर कौन सा मकान रहे। आप चाहते हैं कि जो खेती नहीं करते हैं वे मुस्तसना रहें। मैं समझता हूँ कि यह इसकी मंशा है। फिर सवाल यह है कि वह खेती नहीं करता है तो उसको मुस्तसना नहीं होना चाहिये।

श्री प्रभु नारायण सिंह—स्थायी इससे निकल जाता है।

श्री चरणसिंह—यह भी नहीं है कि सौ फीसदी खेती करते हों बल्कि यह है कि वह अधिकतर खेती करता हो।

श्री प्रभु नारायण सिंह—जो सजेशन माननीय मंत्री जी ने दिया है, उससे मैं अपना संशोधन वापस लेता हूँ।

डिप्टी चैयरमैन—क्या सदन की अनुमति है कि यह संशोधन वापस लिया जाय।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

डिप्टी चैयरमैन—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ३ बिल का भाग बना रहे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ४ व ५

डिक्री देने के पश्चात् ऋण न्यून करने का अधिकार। ४—(१) कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ या किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुये भी कोई भी न्यायालय, जिसने सुरक्षित ऋण से सम्बद्ध डिक्री जिसके विषय में यह अधिनियम प्रवृत्त होगा, दी हो, डिक्रीदार (decree-holder) अथवा वाद-ऋणी (judgement-debtor) द्वारा प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर आगे बताई हुई रीति के अनुसार कार्यवाही करेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम १, under the decree), केवल आस्थान ही हो और उस आस्थान १९५१ को १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम के उपबन्धों के अधीन हस्तगत कर लिया गया हो तो, न्यायालय—

(क) यदि केवल एक ही ऐसा वाद-ऋणी हो जिसे आस्थान के स्वामी होने का अधिकार प्राप्त हो, १ जुलाई, १९५२ को देय धनराशि का हिसाब लगायेगा और तब उसे अनुसूची १ में दिये हुए सूत्र के अनुसार कम कर देगा;

(ख) यदि दो या दो से अधिक वाद-ऋणी हों जिनमें सभी या एक से अधिक ३० जून, १९५२ को बन्धक किये गये आस्थान के स्वामी होने का अधिकार रखते थे;

- (i) १ जुलाई, १९५२ को देय धनराशि का हिसाब लगायेगा;
 - (ii) उक्त प्रकार अधिकार रखने वाले वाद-ऋणियों के बीच धनराशि को, यदि डिक्री में उनका अपना-अपना दायित्व निर्दिष्ट हो, उनके दायित्व के अनुपात से अन्यथा उक्त आस्थान में क्रमशः उनके अंशों के अनुपात से विभाजित करेगा, तथा,
 - (iii) जब देय धनराशि उक्त प्रकार से विभाजित हो जाय तो अनुसूची १ में दिये हुये सूत्र के अनुसार प्रत्येक वाद-ऋणी के लिये धनराशि को कम कर देगा।
- (३) यदि डिक्री द्वारा भारित सम्पत्ति अंशतः आस्थान हो और अंशतः आस्थान से भिन्न अन्य सम्पत्ति हो तो न्यायालय,
- (क) १ जुलाई, १९५२, को देय धनराशि अवधारित करेगा और उसको ट्रांसफर आफ़ प्राप्तों ऐक्ट, १८८२, की धारा ८२ में उल्लिखित सिद्धान्तों के अनुसार अलग-अलग दोनों सम्पत्तियों पर विभाजित करेगा मानों कि डिक्री ऋण हो और वह दो सम्पत्तियाँ ऐसे दो व्यक्तियों की हों जिनका पृथक् तथा भिन्न स्वत्वाधिकार हो, तथा
 - (ख) आस्थान के सम्बन्ध में देय धनराशि का हिसाब लगाये जाने के पश्चात् न्यायालय निम्नलिखित कार्यवाही करेगा—
- (i) यदि एक ही वाद-ऋणी हो जो उक्त आस्थान का ३० जून, १९५२, को स्वामी के रूप में अधिकारी था तो अनुसूची १ में दिये हुये सूत्र के अनुसार उसे कम कर देगा,
 - (ii) यदि दो या अधिक वाद-ऋणी हों और उनमें से सब को या एक से अधिक उक्त आस्थान के ३० जून, १९५२, को स्वामी के रूप में अधिकारी रहे हों तो उनके बीच देय धनराशि को, यदि डिक्री में उनका अपना-अपना दायित्व निर्दिष्ट हो तो, उनके दायित्व के अनुपात में उस प्रकार विभाजित करेगा अन्यथा उनके अपने अपने अंशों के अनुसार, तथा
 - (iii) जब देय धनराशि इस प्रकार विभाजित हो जाय तो अनुसूची १ में दिये हुए सूत्र के अनुसार प्रत्येक बन्धककर्ता द्वारा देय धनराशि को कम कर देगा।

५—धारा ३ तथा ४ के प्रयोजनों के निमित्त प्रत्येक बन्धककर्ता अथवा बन्धककर्ता अथवा वाद-ऋणी जिसका इन धाराओं के अनुसार आस्थान पर अधिकार रहा हो, वाद ऋणी पृथक्-पृथक् इकाई (unit) समझा जायगा; को अलग-किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पत्ति की दशा अलग इकाई में कोई भी पिता पुंजातीय वंशानुक्रम में पुंसति (male lineal descen- समझा जायगा। dants in the male line of descent) सहित, जहां तक संयुक्त सम्पत्ति का सम्बन्ध है, यदि पिता १ जुलाई, १९५२ को जीवित था, एक इकाई समझा जायगा।

स्पष्टीकरण—८ अगस्त, १९४६ को या इसके बाद कोई बटवारा होने पर भी, परिवार संयुक्त समझा जायगा।

डिप्टी चेयरमैन—प्रश्न यह है कि खण्ड ४ व ५ बिल के भाग बने रहें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ६

कम किये गये
धनराशि के
लिए डिक्ली।

६—(१) देय धनराशि के धारा ३ के अधीन कम हो जाने पर, न्यायालय निम्नलिखित की डिक्ली देगा—

- (क) उक्त धारा की उपधारा (२) के खंड (क) के अधीन मामलों (cases) में इस प्रकार कम की गयी धनराशि के लिए,
- (ख) उक्त उपधारा के खंड (ख) के अधीन मामलों में ऐसी धनराशि के लिये, जो उसके अधीन प्रत्येक बन्धककर्ता के लिए कम की गयी धनराशियों के जोड़ (aggregate) के बराबर हो,
- (ग) उक्त धारा की उपधारा (३) के खंड (क) के उपखंड (१) के अधीन मामलों में ऐसी धनराशि के लिए जो, आस्थान से भिन्न अन्य सम्पत्ति पर देय धनराशि तथा उक्त उपखंड के अधीन कम की गयी धनराशि के जोड़ के बराबर हो, तथा
- (घ) उक्त उपधारा के खंड (क) के उपखंड (२) के अधीन मामलों में ऐसी धनराशि के लिए जो आस्थान से भिन्न अन्य सम्पत्ति पर देय धनराशि तथा उक्त उपखंड के अधीन प्रत्येक बन्धककर्ता के लिए कम की गयी समस्त (aggregate) धनराशि के जोड़ के बराबर हो,

(२) उपधारा (१) के खंड (ग) और (घ) के अनुसार तैयार की गयी डिक्ली में, बन्धक किये गये आस्थानों के सम्बन्ध में प्रत्येक बन्धककर्ता के विषय में कम की गयी धनराशि भी अलग-अलग दिखायी जायगी।

श्री कुंवर महावीर सिंह—Sir, I beg to move that in sub-clause (2) of clause 6“(b)” be substituted for “(c)” occurring between the words “clauses” and “and (d)”.

श्री चरणसिंह—जो छपाई की गलती है, उसको मैं स्वीकार करता हूँ।

डिप्टी चेयरमैन—The question is that in subclause (2) of clause 6 “(b)” be substituted for “(c)” occurring between the words “clauses” and “and (d).”

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

डिप्टी चेयरमैन—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ६ इस बिल का भाग बना रहे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ७

डिक्ली की
अदायगी।

७—जब धारा ४ के उपबन्धों के अधीन और उसके अनुसार देय धनराशि कम कर दी जाय तो इस प्रकार कम की गयी डिक्ली के सम्बन्ध में यह समझा जायगा कि सभी प्रयोजनों और अवसरों के लिए उसके कम किये हुए अंश का यथावत् भुगतान हो चुका है।

डिप्टी चेयरमैन—प्रश्न यह है कि खंड ७ इस बिल का भाग बना रहे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ८

८—(१) किसी अनुबन्ध लेख्य अथवा समय विशेष पर प्रचलित प्रतिकर की विधि में (agreement document or law for the time being in force) धनराशि तथा कोई बात होते हुए भी किन्तु उपधारा (२) के उपबन्धों के अधीन सुरक्षित पुनर्वासन अनु-
 ऋण के सम्बन्ध में किसी ऐसे वाद में दी गयी डिक्की जिसके विषय में यह दान से ऋण
 अधिनियम प्रवृत्त होता हो।
 वसूल किया
 जाना।

(क) जहां तक बन्धक किये गये आस्थान के प्रतिकर का सम्बन्ध है, उक्त प्रतिकर की धनराशि की तीन-चौथाई तक ही निष्पादित (execute) हो सकेगी, तथा

(ख) उक्त डिक्की या समय विशेष पर प्रचलित किसी विधि के अधीन डिक्कीदार को प्राप्त प्रत्येक अन्य साधन के अतिरिक्त और उन पर विपरीत प्रभाव डाले बिना, बन्धक किये हुए आस्थान के सम्बन्ध में देय पुनर्वासन अनुदान के विरुद्ध भी अनुदान के तीन चौथाई भाग तक निष्पादित की जा सकेगी।

(२) किसी विधि में किसी बात के रहते हुए भी बन्धक किये हुए आस्थानों के सम्बन्ध में धारा ३ या ४ के अधीन यथास्थिति बन्धककर्ता या वाद-ऋणी के विषय में कम की गयी धनराशि ऐसे आस्थानों के सम्बन्ध में ऐसे बन्धककर्ता या वाद ऋणी को देय प्रतिकर और पुनर्वासन अनुदान में से ही विधिपूर्वक वसूल की जा सकेगी अन्यथा नहीं।

श्री प्रभु नारायण सिंह—मैं प्रस्ताव करता हूँ कि खंड ८ के उपखंड (१) के भाग (क) के बाद निम्नलिखित प्रतिबन्ध बढ़ा दिया जाय :—

“किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि २५० रुपये या इससे नीचे मालगुजारी देने वाले भूतपूर्व जमींदारों के प्रतिकर का १/४ ही इस सम्बन्ध में निष्पादित हो सकेगा।”

यह संशोधन जो मैंने रखा है, इसका मतलब यह है कि जो ढाई सौ रुपये तक मालगुजारी देते हैं उनके प्रतिकर की रकम जो होगी उसका १/४ कर्ज के रूप में लिया जा सकेगा। माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण के सिलसिले में यह कहा कि ऐसी हालत बहुत ही कम होगी जिसमें छोटे जमींदारों के कोई विशेष नुकसान की बात हो इससे तो उन्हें बहुत ही लाभ होगा। जहां तक लाभ की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन केवल इतना चाहता हूँ कि उनको पूरा-पूरा लाभ अपने संशोधन के जरिये दिलाऊँ। हमारी अपनी राय है। जिस समय जमींदारी अबालीशन कमेटी की बैठक चल रही थी, उस वक्त जो हमने राय जाहिर की उसका मतलब हर समय कहा था कि छोटे-छोटे जमींदारों को अधिक से अधिक रकम पुनर्वासन के रूप में मिले जिससे वह अपनी जिन्दगी को ठीक तरह से चला सकें। मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि छोटे जमींदारों की जो प्रतिकर की रकम है वह भी एक तरह से उनके लिये पुनर्वासन की रकम समझी जानी चाहिये। अपनी व्यवस्था करने के लिये जो रकम पुनर्वासन के नाम से मिलेगी वह इतनी काफ़ी नहीं होगी जितनी वह समझी जाती है। इसी के साथ-साथ सवाल यह उठता है कि आखिर न्याय का प्रश्न उठाया जाता है न्याय की जहां तक बात है वह अपनी जगह पर है। न्याय एक ऐसी वस्तु है जिससे कह देने के बाद फिर कोई बात कहने को नहीं रह जाती है।

[श्री प्रभु नारायण सिंह]

लेकिन हम तो इस वक्त यह न्याय समझते हैं कि मुल्क की बहुवृद्धी को ध्यान में रखते हुये जो भी कार्य किया जाय, उसी को हम न्याय समझते हैं और हम इस बात को समझते हैं कि उत्पादन के कार्यों में जो यह छोटे जमींदार आज काश्तकार के रूप में लगे हुये हैं और जो मेहनत करके आज देश का धन बढ़ा रहे हैं, उनको जितनी भी सहाय्य दी जा सके, दी जाय। हमारे पास आंकड़े नहीं हैं कि हम बता सकें कि छोटे जमींदारों पर कितना कर्ज है लेकिन इसके साथ-साथ हम इस बात को महसूस करते हैं कि देहातों में उन्होंने ही कर्जा दिया है, जो खेतिहर हैं। इस बात को मंत्री जी ने कहा है लेकिन सब जगह ऐसा नहीं है। यह चीज कुछ स्थानों पर हो सकती है लेकिन मैंने इस बात को भी देखा है कि खेती का काम करते हुये भी वह बड़ा मनी-लेंडिंग का काम करते हैं और १४ रुपया देकर २० रुपया तक कमाते हैं। ऐसी हालत में हम इस बात को महसूस करते हैं कि यदि रुपया आज उनके पास अधिक है, साहूकारों की बात छोड़ भी दीजिये, यदि दूसरों की बात है जिनसे मुल्क की खेती में उन्नति हो सकती है तो उनको इस तरह की राहत मिलनी चाहिये जिससे मुल्क की दौलत बढ़ सके।

हमारी सरकार का नुस्तेनजर जो भी हो, लेकिन अभी मंत्री जी ने कहा कि उन्हें हर वर्ग के साथ न्याय करना है, उन्होंने यह भी कहा कि हमारी सरकार ने जितनी अक्लमंदी बरती, उतनी किसी ने नहीं बरती। हर सूबे का उन्होंने मुकाबिला किया तो जब अक्लमंदों अक्लमंदों में मुकाबिला है तो फिर किसको ज्यादा अक्लमन्द कहा जाय और किसको कम कहा जाय, लेकिन हम इस बात को समझते हैं कि उन्होंने जो कुछ किया उससे हमारे सूबे की बहुवृद्धी नहीं हुई है, हमारे सूबे की उन्नति नहीं हुई है। इस बात का इजहार हमने सैकड़ों मौकों पर और हर तरह से किया है, लेकिन यह दूसरी बात है कि उसकी सुनवाई हो या न हो, लेकिन हम फिर भी यह कहना चाहते हैं कि उत्पादन के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिये यह जरूरी है कि छोटे जमींदारों को आज राहत मिले। उसके सिलसिले में जो मैंने मांग रखी है कि २५० रुपये या इससे कम मालगुजारी देने वाले भूतपूर्व जमींदारों के पुनर्वासित अनुदान की रकम से कोई विधि-पूर्वक वसूली न की जाय। इसको माना जाय। अगर यह भी हमारी सरकार नहीं मानती है, तो फिर कोई रास्ता नहीं है। हम चाहते हैं कि अगर हमारे बताये रास्ते पर आप चलते तो मुल्क को अच्छी तरह उठा पाते। इसलिये आज मुल्क की बहुवृद्धी के लिये यह जरूरी है कि जो उत्पादन करने वाले हैं उन्हें अधिक से अधिक सहायता पहुंचाई जाय जिससे मुल्क का अनाज और दौलत बढ़ सके।

श्री कुंवर गुरु नारायण—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन कि अभी हमारे मित्र प्रभु नारायण सिंह जी ने रखा है जिसके द्वारा उन्होंने मांग की है कि एक बड़ा चार ही केवल काटा जाय कम्पेनसेशन से, कर्ज की अदायगी में, न कि ३/४, और ३/४ जमींदार के लिये बच जाय तो उसका मैं समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूँ।

श्रीमान, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब यह संशोधन हमारे समाजवादी भाइयों की तरफ से आया। मुझको तो यह विश्वास भी हो गया कि वाकई आप लोग समाजवादी हैं। और उस पर पूरे तौर से विश्वास रखते हैं। मार्क्स का सिद्धांत था कि जो देश की बेल्ट है चाहे वह इंडस्ट्रियल हो या ऐग्रीकल्चरल हो वह कुछ लोगों के पास न एक्त्रित होने पावे और अगर वह कुछ लोगों के पास एक्त्रित हो जातो है तो वह वर्किंग क्लास के लिये मिनस (menace) साबित होती है इसके साथ ही साथ जब उन लोगों से वह दौलत ले ली जाये तो वह लोग भी कामन पोपुल में गिने जाने चाहिये और फिर उन लोगों को भी वही सहाय्यते मिलने लगती हैं जो कि कामन पोपुल को मिलनी चाहिये। ऐसी हालत में जो आपने यह संशोधन रक्खा है तो वह आपने अपने सिद्धांतों के नुताबिक ही रक्खा है। अब जब कि जमींदारों से जमींदारी ले ली गई उनकी बेल्ट

उनके पास से चली गई तो फिर अब हमको उनके साथ वही व्यवहार करना चाहिये जो कि कामन पोपुल यानो प्रोलोटेरियट (Proletariat) के साथ होता है। ऐसी हालत में आपने इस संशोधन को सोशलइज्म के बसूलों के मुताबिक ही रक्खा है। इससे हम समझते हैं कि आपने यह समझकर कि जमींदारों की हालत क्या है और वह अब कामन पोपुल में आ गये हैं और अब उनको हालत वह नहीं है जो पहिले थी इसीलिये आपने इसको रक्खा है। आपका यह जो विचार है मैं उसको सराहना करता हूँ और मुझे बहुत खुशी हुई कि इन भावनाओं से प्रेरित होकर आपने इसको रक्खा है। अब जहाँ तक हमारी कांग्रेस बुकूमत की बात है तो वह भी कहते हैं कि वह भी सोशलइज्म में विश्वास करते हैं। ऐसी हालत में वह मार्क्स की आइडिप्रालोजी को भी मानते हैं तो कोई बजह नहीं है कि आप इस संशोधन को स्वीकार न करें। अगर आप इसको नहीं स्वीकार करते हैं, जिस भावना से प्रेरित होकर जिसे हमारे समाजवादी भाइयों ने इस संशोधन को रक्खा है, तब तो फिर मैं यह कहूँगा कि न तो आप सोशलइज्म में विश्वास करते हैं न कम्युनिज्म में विश्वास करते हैं। बल्कि आप विंदिक्टिवइज्म (vindictivism) में विश्वास करते हैं। ऐसी हालत में यह जो संशोधन है वह बहुत ही उचित है उसमें कोई आपत्ति कम से कम इस विचारधारा के मानने वाले को हो ही नहीं सकती। आशा है कि सरकार इसको मंजूर करेगी। इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूँ।

श्री चरण सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी तक कभी-कभी मुझको यह ख्याल हो जाता था श्री राजा राम शास्त्री और श्री प्रभु नारायण जी को देख कर कि शायद ये लोग सोशलइज्म में कुछ विश्वास रखते हैं। लेकिन कुंवर गुप्त नारायण जी की बात सुनकर मुझे कुछ शक पैदा होने लगा है कि आपका मेरा ख्याल कहां तक सही था। खैर, यह दूसरी बात है कि उनको सर्टिफिकेट दिया जा रहा था और कहां तक उनको मंजूर था या नहीं था। यह जो संशोधन पेश किया गया, इस के बारे में मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूँ और अब कोई नयी बात नहीं है केवल इस पहलू को और ध्यान दिखाना चाहता हूँ वह यह है कि २० रुपये कर्जा है तो ४ रुपये ही उसका १/५ होगा और फिर इस ४ में से एक रुपया बसूल नहीं हो सकता क्योंकि २५ फीसदी इसमें से छोड़ना है तो २० रुपये में केवल ३ रुपये ही बसूल हो सकते हैं। अब आप कहते हैं कि १/४ कर्जा बसूल किया जाय। यह कहां तक न्याय संगत बात है इसको स्वयं संशोधन पेश करने वाले को न्याय बुद्धि पर मैं छोड़ देता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि जो पहले कर्ज को वसूलना चाहते थे तो उसमें जायदाद नीलाम होती थी, लेकिन अब जायदाद नीलाम नहीं होगी। केवल जो नूराविजे की बात है, उसके ३/४ के बसूल करने की बात कही गई है। जिस बिना पर मैंने पहले विरोध किया था उसी बिना पर मैं इसका विरोध करता हूँ।

डिप्टी चैयरमैन—प्रश्न यह है कि खंड ८ के उपखंड (१) के भाग (क) के बाद निम्नलिखित प्रतिबन्ध बढ़ा दिया जाय—

“किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि २५० रुपये या इससे नीचे मालगुजारी देने वाले भूतपूर्व जमींदारों के प्रतिकर का १/४ ही इस संबंध में निष्पादित हो सकेगा।”

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री प्रभु नारायण सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन उपस्थित करना चाहता हूँ। खंड ८ के उपखंड (१) (ख) के बाद निम्नलिखित प्रतिबन्ध बढ़ा दिया जाय :—

“किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि २५० रुपये या इससे कम मालगुजारी देने वाले भूतपूर्व जमींदारों का पुनर्गठन अगुशन इस कार्य के लिये निष्पादित नहीं हो सकेगा।”

इस संबंध में मैं इस सदन में काफी बातें कह चुका हूँ।

श्री चरणसिंह—ट्वाइंट आर आर्डर सर, जो मंशा श्री प्रभु नारायण जी की पहले संशोधन से थी वही इस संशोधन से है यानी २५० रुपये से कम मालगुजारी देने वालों की जो रिहबिलिटेशन ग्रांट दी जाय, वह रिहबिलिटेशन ग्रांट न समझी जाये, उसी को उन्होंने यहाँ पर दूसरे शब्दों में रखा है।

श्री प्रभु नारायण सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो संशोधन पेश किया है वह बिलकुल ही दूसरी चीज है। पहले संशोधन में सिर्फ डेफिनीशन की बात कही गई और इसमें क्लोज में संशोधन को लिये कहा गया है। एक में तो डेफिनीशन और दूसरे में संशोधन की बात कहना बिलकुल अलग सी बात है। मैंने अपनी पहली स्पीच में बहुत कम कहा। अगर मैंने पहले कुछ कहा होता तो शायद मंत्री जी का हृदय परिवर्तित हो सकता था।

श्री चरण सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जो तक पहले था वही है-वही इसमें भी है। उसको यहाँ पर दूसरे शब्दों में बदल कर रखा गया है।

डिप्टी चैयरमैन—इसी तरह का संशोधन पहले अस्वीकार हो चुका है इसलिये मैं अब इसकी अनुमति नहीं देता हूँ।

श्री प्रभु नारायण सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि खंड ८ के उपखंड (२) के बाद निम्नलिखित प्रतिबन्ध बढ़ा दिया जाय:—

“किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि २५० रुपये या इससे कम मालगुजारी देने वाले भूतपूर्व जमींदारों के पुनर्वासन अनुदान की रकम से कोई विधिपूर्वक वसूली नहीं की जा सकेगी।”

श्री चरण सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, पहले संशोधन में यह था कि निष्पादित नहीं की जा सकेगी और अब यह है कि वसूली नहीं की जा सकेगी दोनों का एक ही मतलब है और इसमें और उसमें कोई भेद नहीं है।

श्री प्रभु नारायण सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो हमारे ऊपर बाइंडिंग हो गई है लेकिन मैं यह समझता हूँ कि यहाँ पर जो संशोधन रखा गया है वह अपनी जगह पर बिल्कुल वाजिब है। अब चूँकि संशोधन पर कहीं पर डिस्कशन नहीं हो सकता तो ऐसी बात नहीं है। संशोधन ऐसी सूरत में रूल आउट करना मेरे स्थान में मुनासिब नहीं है। अभी तक तो जहाँ संशोधन का सत्राल है तो जो विधेयक की क्लोज २ है उसके विद्वलण करने की बात है और उसको डेफिनीशन इसमें दी गई है। दूसरे इस संशोधन में यह है कि २५० रुपये से अधिक मालगुजारी देने वाले जो मालगुजार हैं उनको इस डेट बिल से बिलकुल अलग कर दिया जाय। और पुनर्वास अनुदान को डेफिनीशन के बाद ही यह संशोधन दिया गया है। अगर संशोधन में कोई बात ऐसी हो कि जो डेफिनीशन में रह गई हो तो क्या इसके माने यह हैं कि इसके लिये संशोधन आना ही नहीं चाहिये था। आप चीज को समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं। मैं समझता हूँ कि जो खंड २ है वह डेफिनीशन को क्लोज है और दूसरी जगह वह अमेंडमेंट की शक्त में आया है।

श्री चरण सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो मेरे दोस्त ने दलील दी कि परिभाषा में यह रक्खा रहे और यह संशोधन की परिभाषा में भी रक्खा रहे कि २५० रुपये से अधिक मालगुजारी देने वाले जमींदारों का रिहबिलिटेशन ग्रांट नहीं माना जायेगा तो इसका जिक्र तो क्लोज ८ में आता है। इसकी मंशा तो यह हुई कि २५० रुपये से कम की हालत में रिहबिलिटेशन ग्रांट न हो तो फिर इसमें कोई फर्क नहीं है। तीसरी बात यह है कि जो दलील आपने यहाँ दी है वही वहाँ भी दी है। सबसे पहली बात तो यह है कि आर्गुमेंट्स कैसे ऐडवांस किये जा सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, अगर आप गौर फरमायें तो जो संशोधन आपने अभी ओवर रूल किया है उसमें भी यही बात है कि “किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि २५० रुपये या इससे नीचे

मालगुजारी देने वाले भूतपूर्व जमींदारों के प्रतिकर का १/४ ही इस संबंध में निरपवादित हो सकेगा।" और यहां यह कहते हैं कि "किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि २२० रुपये या इससे कम मालगुजारी देने वाले भूतपूर्व जमींदारों के पुनर्वासन अनुदान की रकम से कोई विधिपूर्वक वसूली नहीं की जा सकेगी।"

एक में यह चाहते हैं कि एकजीक्यूट नहीं किया जायेगा और दूसरे में यह चाहते हैं कि रिप्लाइज नहीं किया जायेगा। तो इनमें क्या फर्क है, इससे बेकार सदन का समय नष्ट होता है।

डिप्टी चेयरमैन—यह संशोधन आउट ऑफ़ आर्डर है। क्या श्री प्रभु नारायण जी इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं ?

श्री प्रभु नारायण सिंह—मैं इसका एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं। यदि मंत्री जी ऐसा समझते हैं कि इस सदन का समय बहुत कीमती है और उनके ऊपर ही इसकी जिम्मेदारी है और हम लोग यहां बेंकर बैठे हुये हैं, तो यह कहां तक उचित है। उनको किसी चीज को सोच-समझकर कहना चाहिये।

श्री चरण सिंह—मैं आपकी इजाजत से यह कहना चाहता हूं कि जो दलील एक बार कही जा चुकी है, उसको दुबारा रिपीट करने से सदन का समय खराब होता है इसमें नाराज होने की क्या बात है।

डिप्टी चेयरमैन—आपके तीनों संशोधन बिल्कुल मिलते हुये से हैं और वह सिर्फ दूसरे लफ्जों में रख दिये गये हैं लिहाजा मैं इसकी सम्मति नहीं देता हूं।

प्रश्न यह है कि खंड ८ इस बिल का भाग बना रहे।

(प्रश्न यह उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ६ व १०

६—सुरक्षित ऋण को छोड़कर अन्य ऋण से सम्बद्ध कोई डिक्ली बन्धों के विरुद्ध असुरक्षित जिसके विषय में यह अधिनियम प्रवृत्त हो, वाद ऋणी को उसके ऋण के संबंध में डिक्लियर आस्थान के विषय में प्रतिकर अथवा पुनर्वासन अनुदान के रूप में का प्पादन। दिये गये बन्धों (.bonds) की कुरकी या नीलाम द्वारा निष्पादित की जाय तो डिक्ली को निष्पादन करने वाला न्यायालय, किसी विधि में किसी बात के होते हुये भी, अनुसूची २ में बताये हुये सूत्र के अनुसार अदायगी प्रमाणित कर देगा।

१०—आवश्यक परिवर्तनों के साथ इस अधिनियम के भरण पोषण की वृत्ति उपबन्ध, ऐसे गुजारा या भरणपोषण की वृत्ति (Maintenance Allowance) की बकाया की वसूली की डिक्ली या वाद में, जिनमें कोई भी आस्थान अकेले या अन्य सम्पत्ति सहित बन्धक किया गया हो, अथवा किसी विधि, डिक्ली, अनुबन्ध (agreement) अथवा लेख के अन्तर्गत अन्य किसी प्रकार से भारित हो, उसी प्रकार लागू होंगे मानों गुजारा या भरणपोषण की वृत्ति ऋण हो और धारा ३, ४ और ५ के प्रयोजनों के लिये इस प्रकार बन्धक की हुई या भारित सब अचल सम्पत्ति बन्धक की हुई सम्पत्ति समझी जायगी।

सप्लीकरण—यह “भरणोपयोग की वृत्ति” (Maintenance Allowance) के अन्तर्गत अवध स्टैंडर्स ऐक्ट, १८६६ की धारा २४ अथवा यू० पी० इस्टैंडर्स ऐक्ट, १९२० की धारा १३ के अन्तर्गत “annuity” (वार्षिक वृत्ति) भी है।

डिप्टी चेयरमैन—प्रश्न यह है कि खंड ६ और १० इस बिल के भाग बने रहें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृति हुआ।)

खंड ११

नियम बनाने के अधिकार ११—इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजनों के निमित्त पूर्व प्रकाशन के बाद राज्य सरकार नियम बना सकती है।

श्री प्रभु नारायण सिंह—मैं प्रस्ताव करता हूँ कि खंड ११ के अन्त में शब्द “और उसे लागू करने के पूर्व सदन के सम्मुख रखा जायेगा और स्वीकृति ली जायेगी” बढ़ा दिये जायें। इसमें जो खंड ११ है, उसमें यह है कि “इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजनों के निमित्त पूर्व प्रकाशन के बाद राज्य सरकार नियम बना सकती है” तो उसके बाद मेरे ये शब्द बढ़ा दिये जायें। मेरा जो संशोधन है उसका तात्पर्य है कि उसको लागू करने के पूर्व सदन के सामने स्वीकृति के लिये रखा जायेगा। यह संशोधन मैंने इसी लिये रखा है कि इसके संबंध में जो नियम बनेंगे तो उसमें सिर्फ सरकार अपने को ही उसके लिये महबूद रखती है और जो विरोधी पार्टियों की तरफ से या दूसरे लोगों की तरफ से बात होती है, उनको सरकार नहीं देखती है, इसलिये इस संशोधन का जो मुख्य तात्पर्य है वह यही है कि नियमों को लागू करने के पूर्व उसको स्वीकृति के लिये सदन के सम्मुख रखा जायेगा। जो नियम बनाये जायें वे सदन के सामने आने चाहिये और फिर सदन से वे पास किये जायेंगे। मैं समझता हूँ कि यह संशोधन बिल्कुल वाजिब है और यह मान लिया जायेगा।

श्री चरण सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि इस संशोधन का मुझे विरोध करना होगा। इसका कारण यह है कि इसमें शायद एक, दो नियम ही बनेंगे और वे नियम भी ऐसे नहीं होंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण हों। जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की तरह इन्हें नहीं ई बल्कि इसमें इस तरह से व्यवस्था की गई है कि वे विधान मंडल के सामने रख जायें। लिहाजा वे विधान सभा से भी स्वीकार किये जायेंगे और विधान परिषद् के सामने भी यह बात आयेगी। तो जहाँ ऐसी बातें हैं कि दूरगामी का ज्यादा असर हो, उसके लिये कोई पुनराज नहीं है। लेकिन यह नियम जो होगा बहुत सीधा सादा है और यदि वह हाउस के सामने आयेगा तो समय ही नष्ट होगा और उससे कोई फायदा न होगा। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूँ।

श्री प्रभु नारायण सिंह—जो मैंने संशोधन रखा है, उसमें मैं यह चाहता हूँ कि हाउस का यह रेजिशन बन जाय कि जो नियम बनें वह हाउस के सामने आयें। यहाँ पर कोई कंट्रीबर्सी का सवाल उठता नहीं है ऐसी हालत में तो यह २ मिनट में ही दोनों हाउस से पास हो जायेगा इसलिये मैं चाहता हूँ कि इसे हाउस के सामने आना चाहिये।

श्री चरण सिंह—मुझे अफसोस है कि मैं कनक्विन्ड नहीं हूँ।

डिप्टी चेयरमैन—प्रश्न यह है कि खंड ११ के अन्त में शब्द “और उसे लागू करने के पूर्व सदन के सम्मुख रखा जायेगा और स्वीकृति ली जायेगी” बढ़ा दिये जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृति हुआ।)

डिप्टी चेयरमैन—प्रश्न यह है कि खंड ११ इस बिल का भाग बना रहे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुसूची १

१—धारा ३ और ४ में अभिविष्ट (referred to) ऋण की कमी के लिये सूत्र (formula)

$$X = \frac{DX8}{ME}$$

२—उक्त सूत्र में

(१) “X” का अभिप्राय धारा ३ और ४ में अभिविष्ट कम की गयी धनराशि से है।

(२) “D” का अभिप्राय

(क) यदि बन्धकर्ता (mortgagor) या वाद ऋणी (Judgement-Debtor) बन्धक किये हुए आस्थान के स्वामी के नाते एकाई के रूप में (in one unit) अधिकारी रहा हो, तो यथास्थिति निम्नलिखित में अभिविष्ट धनराशि से है:—

(१) धारा ३ की उपधारा (२) के खंड (क), अथवा

(२) उक्त धारा की उपधारा (३) के खंड (क) का उपखंड (१), अथवा

(३) धारा ४ की उपधारा (२) का खंड (क), अथवा

(४) उक्त धारा की उपधारा (३) के खंड (ख) का उपखंड (१), तथा

(ख) यदि उक्त बन्धकर्ता या वाद-ऋणी एक से अधिक हों तो यथास्थिति, निम्नलिखित में अभिविष्ट प्रत्येक बन्धकर्ता या वाद-ऋणी को विभाजित धनराशि से है,

(१) धारा ३ की उपधारा (२) के खंड (ख) का उपखंड (१), अथवा

(२) उक्त धारा की उपधारा (३) के खंड (क) का उपखंड (२), अथवा

(३) धारा ४ की उपधारा (२) और (३) के खंड (ख) के उपखंड (ii)।

(३) “ME” का अभिप्राय यू० पी० इन्कम्बर्ड स्टेट्स ऐक्ट, १९३४ के अधीन आस्थान के मूल्य अवधारण के लिये गुणक (multiple) से है और जब कोई बन्धकर्ता या वाद ऋणी ऐसे दो या उससे अधिक आस्थानों का स्वामी के रूप में अधिकारी हो जिनके लिये उक्त अधिनियम के अधीन भिन्न गुणकों की व्यवस्था की गयी हो, तो ऐसे आस्थानों के संबंध में गुणकों का औसत जिसकी गणना नियत रीति से की जायगी;

किन्तु सदैव यह प्रतिबन्ध है कि जहां उक्त अधिनियम के अधीन ME ४० से अधिक हो तो वह ४० के बराबर समझा जायगा।

श्री कृंवर महावीर सिंह—Sir, I beg to move that in Schedule I, in the proviso the following words be added *after* the words “to be equal to 40.”

“and where it is less than 20 it shall be deemed to be equal to 20”.

श्रीमान् जी, जिस समय बहस हो रही थी उस समय में मैंने काफी दलीलें इत पर दी थीं और मैं आशा करता हूँ कि उनको समझकर यह संशोधन मंजूर किया जायगा। जहां ४० मंजूर रखा गया है तो उस जगह २० रखने में कोई नुकसान न होगा। बल्कि उन प्रदेशों को फायदा होगा जो बाकी गरीबी के दरवाजे पर अपना भाग्य खटखटा रहे हैं। मैं इन शब्दों के साथ इस संशोधन को रखता हूँ।

श्री चरणसिंह—मुझको यह संशोधन मंजूर है और कारण यह है कि हमारे प्रदेश में बहुत से जिले ऐसे हैं जहाँ मल्टीपल बहुत कम रखा गया है, किसी जगह १३ है जैसे बदायूँ जिले में एक दातागंज तहसील है वहाँ १३ है, सहारनपुर और बिजनौर में करीब १४ है और बुन्देलखंड में १६ है तो ऐसा करने से २।३ या १/२ होगा।

इसलिये जहाँ हमने अपर लिमिट रक्खी कि ४० से ज्यादा न होगा वहाँ जरूरी है कि नीचे भी हम एक सीमा बांध दें इसलिये यह संशोधन है कि २० से कम न हो। ४० और २० के बीच में जिले की स्थिति के मुताबिक २४, २५, २७, २८ कुछ भी हो सकता है। यह संशोधन हमें स्वीकार है।

डिप्टी चेयरमैन—

The question is that in Schedule I, in the proviso the following words be added *after* the words “to be equal to 40.”

“and where it is less than 20 it shall be deemed to be equal to 20.”

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

डिप्टी चेयरमैन—प्रश्न यह है कि संशोधित अनुसूची १ इस बिल का भाग बनी रहे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुसूची २

(बेखिमे धारा ६)

बेचे गये बन्ध (bond) में अंकित मूल्य के प्रत्येक रुपये के लिये, ऐसी धनराशि जो उसकी $\frac{ME}{8}$ होगी।

उक्त सूत्र में ME का तात्पर्य वही होगा जो उसका अनुसूची १ के पद २ की मद (३) में है।

डिप्टी चेयरमैन—प्रश्न यह है कि अनुसूची २ इस बिल का भाग बनी रहे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

प्रस्तावना तथा खंड १

उत्तर प्रदेश अधिनियम
१, १९५१।

१९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम के उपबन्धों के अधीन जिन जमींदारों के आस्थान हस्तगत किये गये हैं उनके ऋणों को कम करने के लिये

विधेयक

उत्तर प्रदेश अधिनियम
१, १९५१।

यह आवश्यक है कि उन जमींदारों के ऋणों को कम करने (scaling down) को व्यवस्था की जाय जिनके आस्थान १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम के अधीन हस्तगत किये जा चुके हैं; अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार
तथा प्रारम्भ।

१—(१) इस अधिनियम का नाम उत्तर प्रदेश जमींदारों के ऋण कम करने का अधिनियम, १९५२, होगा।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

डिप्टी चेयरमैन—प्रश्न यह है कि प्रस्तावना खंड १ इस बिल का भाग बने रहे।

और

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री चरणसिंह—मैं प्रस्ताव करता हूँ कि सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारों का ऋण कम करने का विधेयक जैसा कि इस परिषद् से संशोधित हुआ है, पारित किया जाये।
(इस समय ४ बजकर २७ मिनट पर, चेयरमैन ने सभापति का आसन ग्रहण किया।)

श्री प्रभु नारायण सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन में यह बिल हमारे सामने थर्ड रीडिंग में आया है और जिन संशोधनों को मान लेने पर यह बिल पूर्ण हो सकता था, खासतौर से २५० रु० मालगुजारी देने वाले छोटे जमींदारों के पुनर्वासन अनुदान को यदि कर्ज से बाहर कर दिया जाता तो इस बिल की शकल काफी अच्छी हो जाती। इसमें कोई शक नहीं है लेकिन बिल की जो मौजूदा सूरत है उसमें भी जमींदारों को काफी राहत मिलेगी। हाँ, यह जरूर है कि जितनी राहत मिलनी चाहिये उतनी न मिलेगी। यह कहना तो कुछ ठीक नहीं मालूम होता है कि रिहैबिलिटेशन ग्रांट और कम्पेन्सेशन में एक टेकनिकल अंतर है। जब से जमींदारी अबालीशन का सवाल उठा तब से हमने इस बात को रखने की बराबर कोशिश की कि रिहैबिलिटेशन ग्रांट और कम्पेन्सेशन देने का एक आधार होना चाहिये और इसीलिये हमने यह मांग की थी कि छोटे जमींदारों को अधिक से अधिक रिहैबिलिटेशन ग्रांट मिलनी चाहिये। ऐसी शकल में जब यह बिल सामने आया तो हमने इस बात को सहस्र किया कि जितने रिहैबिलिटेशन ग्रांट छोटे जमींदारों को मिलना चाहिये उतनी रिहैबिलिटेशन ग्रांट तो तभी हो सकती थी जब उनके कम्पेन्सेशन की रकम उस से छोड़ दी जाती और इस हालत में जब मैं इसे देखता हूँ तो यह सहस्र करता हूँ कि आज यह जरूरी था कि जमींदारों को जो पुनर्वासन दिया जाने वाला है उस को डेट से सहस्र कर दिया जाना चाहिये था। न्याय और अन्याय की बात तो हुआ ही करती है। अन्याय की रोकथाम तो होना ही चाहिये। आज समाज में छोटे जमींदार को एक हैसियत होने जा रही है और वह हैसियत एक खेतिहर की होने जा रही है। ऐसी हालत में उसे जितनी भी सहूलियत दी जाये वह मुक्त और समाज की बहबूदी और कल्याण के लिये ही होगा। यह कहना कि आपने कम्पेन्सेशन के मामले में बराबर जमींदारों की मुवालिफत की आज कैसे जमींदारों के साथी हो गये। हमने छोटे जमींदारों के बारे में कहा था। आज भी हम इस बात को कहते हैं कि जहाँ हम पहले थे आज भी वहीं हैं। हमारे कार्यक्रम में कोई फर्क नहीं और इसी सूरत में वह इस बिल की शकल में है। कम्पेन्सेशन और रिहैबिलिटेशन ग्रांट जिन जमींदारों को मिलने वाली है उनमें से अगर २५० रुपया मालगुजारी देने वाले जमींदार यदि डेट से अलग हो जाते हैं तो इस बिल की शकल बहुत अच्छी हो जाती। बहरहाल, बिल की शकल जो कुछ भी है इस हालत में, मैं उसका स्वागत करता हूँ।

श्री चरणसिंह—अध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस है कि माननीय प्रभु नारायण सिंह ने बिल का समर्थन करते हुये साथ ही साथ कुछ ऐसी बातें कहीं जो वास्तविकता से बहुत दूर हैं। आप बराबर इस बात पर जोर देते हैं कि २५० रुपया तक मालगुजारी देने वालों को इससे राहत मिलनी चाहिये। मैंने इसका जवाब दिया था और उनको भी दो दफा बोलने का मौका मिला। १९४० ई० के बाद एग्रीकल्चर क्राइसिस में ऐसा हुआ कि कर्ज में कमी हो गयी। नालिखें आज कम हैं, कुरकी कम हैं, नीलाम कम हैं। लिहाजा कर्ज की कमी हुई। दूसरी बात जो कर्जा देने वाले आदमी हैं वे प्योर लैंड ओनर्स नहीं हैं। मामूली किसान को कर्जा देता है। कहीं पर कम हैं और कहीं पर ज्यादा हैं। किसान किसान को देता है। गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़, बलिया और गाजीपुर में एक एक बीघे की रेहन पूर्वी जिलों में है। रेहन क्या है। जो बड़े आदमी होते हैं वे ही रेहन नहीं लेते हैं। जो खेतिहर का रेहन लेगा वह खेतिहर होगा। लिहाजा आप चाहते हैं कि जो २५० रुपये से कम मालगुजारी देता है उसका कर्जा कम्पेन्सेशन और रिहैबिलिटेशन ग्रांट से काटा जाय तो यह ठीक नहीं है। जब कर्जदार की जमीन को सरकार ने ले लिया तो उनको भी कर्जा रिफंड करना चाहिये।

[श्री चरण सिंह]

कर्जा हमने १/५ कम कर दिया। फिर आप कहते हैं कि २० फीसदी कम करने के बाद ५ फीसदी और छोड़ दिया जाय। यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। क्या वजह है कि १०० में से १५ रुपया भी नहीं लिया जा सकता। जब ५०० में से हमने १०० कम कर दिये जिसमें से ७५ ही वसूल हो पायेगा फिर कहना कि ढाई सौ से कम वालों को बिलकुल ही छोड़ दिया जाय, समझ में नहीं आता है। एक रुपया मालगुजारी देने वाला जमींदार अगर जमीन लगान पर देता है तो वह शोषक है वैसे ही जैसे २,००० रु० मालगुजारी देने वाला शोषक है। अध्यक्ष महोदय, बराबर दलील इस पर दी जाती है मेरी समझ में नहीं आता कि क्यों छोड़ दिया जाय। यह तो सिवाय इसके कि प्रोपैगन्डा का प्लेटफार्म तैयार किया जाता है और कोई बात इस खिरह की नहीं हो सकती है। अगर मान लीजिये जमींदारी खत्म न हुई होती तो १०० बीघा जो सीर उसकी थी वह तो कायम रह जाती इसलिये कि उसकी वह साकितुल हो जाती। महाजन केवल खेवट पा जाता। आज क्या होगा। आज यह होगा कि १०० बीघा जो खुदकाश्त है वह उसके पास रह जाती है। घर का घर आ जाता है। हमने यह किया कि मुआविजा और आमदनी से जो वसूल हो जाय उसका ३/४ तक तो दिया जाय। यानी १२५ में से १०० बीघा की खुदकाश्त है सिर्फ २५ बीघा का इन्टरमिडियरी वह होता है। खंड ८ में साफ दिया है। इस हद तक डिग्री इजराय महदूद रहेगी। मैं अब अधिक कुछ और नहीं कहना चाहता। इन शब्दों के साथ मैं अपना प्रस्ताव पेश करता हूँ।

चेयरमैन—प्रश्न यह है कि सन् १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारों के ऋण कम करने के विधेयक को, जैसा कि, संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक

श्री मोहन लाल गौतम—मैं श्रीमान् की आज्ञा से सन् १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

चेयरमैन—अब कौंसिल कल ११ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(कौंसिल ४ बज कर ४० मिनट पर दूसरे दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गई।)

लखनऊ;

२६ अक्टूबर, १९५२।

श्याम लाल गोविल,
सेक्रेटरी, लेजिस्लेटिव कौंसिल,
उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौंसिल

गुरुवार, ३० अक्टूबर, १९५२

उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौंसिल की बैठक, कौंसिल हाल, विधान भवन, लखनऊ में दिन के ११ बजे चेयरमैन (श्री चन्द्रभाल) के सभापतित्व में हुई।

उपस्थित सदस्य (६०)

अब्दुल शकूर नजमी, श्री
अम्बिका प्रसाद वाजपेयी, श्री
इन्द्र सिंह नयाल, श्री
ईश्वरी प्रसाद, डाक्टर
उमानाथ बली, श्री
एम० जे० मुकर्जी, श्री
कन्हैया लाल गुप्त, श्री
कुंवर गुरु नारायण, श्री
कुंवर महावीर सिंह, श्री
कदार नाथ खेतान, श्री
कृष्ण चन्द्र जोशी, श्री
खुशाल सिंह, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
जगन्नाथ आचार्य, श्री
जमीलुर्रहमान कदवई, श्री
ज्योति प्रसाद गुप्त, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेलू राम, श्री
निजामुद्दीन, श्री
पन्नालाल गुप्त, श्री
परमात्मा नन्द सिंह, श्री
प्यारे लाल श्रीवास्तव, डाक्टर
प्रताप चन्द्र आज़ाद, श्री
प्रभु नारायण सिंह, श्री
प्रसिद्ध नारायण अनन्द, श्री
प्रेम चन्द्र शर्मा, श्री
बद्री प्रसाद कक्कड़, श्री
बशीर अहमद, श्री
बलभद्र प्रसाद वाजपेयी, श्री
बालक राम वैश्य, श्री

बाबू अब्दुल मजीद, श्री
महमूद अल्लखान, श्री
महादेवी वर्मा, श्रीमती
मानपाल गुप्त, श्री
राजा राम शास्त्री, श्री
राना शिवशम्बर सिंह, श्री
राम किशोर शर्मा, श्री
राम नन्दन सिंह, श्री
राय वजरंग पहाड़ुर सिंह, श्री
लल्लू राम द्विवेदी, श्री
लालता प्रसाद सोनकर, श्री
लाल सुरेश सिंह, श्री
वंशीधर शुक्ल, श्री
विश्वनाथ, श्री
वीरभान भाटिया, डाक्टर
बेणी प्रसाद टंडन, श्री
ब्रज लाल वर्मा, श्री (हकीम)
ब्रजेन्द्र स्वरूप, डाक्टर
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति देवी अग्रवाल, श्रीमती
शान्ति स्वरूप अग्रवाल, श्री
शिवराज दाती नेहरू, श्रीमती
शिव सुमरन लाल जीहरी, श्री
श्याम सुन्दर लाल, श्री
सत्य प्रेमी उपनाम हरिप्रसाद, श्री
सभापति उपाध्याय, श्री
सरदार संतोष सिंह, श्री
सैयद मुहम्मद नसीर, श्री
हृदय नारायण सिंह, श्री
हयातुल्ला अन्सारी, श्री

निम्नलिखित मंत्री भी उपस्थित थे:—

श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम (वित्त मंत्री)
श्री हर गोविन्द सिंह (शिक्षा मंत्री)

श्री सैयद अली जहीर, (न्याय मंत्री)
श्री मोहन लाल गौतम (स्वशासन मंत्री)

प्रश्नोत्तर

१-३—श्री प्रताप चन्द्र आजाद (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—स्थगित ।

४-५—श्री राम नन्दन सिंह (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—[वर्तमान बैठक के पांचवें सोमवार के लिये प्रश्न संख्या १०-११ के रूप में रखे गये ।]

विलीन काशी राज्य क्षेत्र की ग्राम पंचायतों के रुपयों की वापसी

६—श्री राम नन्दन सिंह—(क) क्या स्वायत्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विलीन काशी राज्य क्षेत्र की ग्राम पंचायतों का ४७०११ रुपया आठ आना, जो सरकार के पास जमा है, उन ग्राम सभाओं को दे दिया गया ?

(ख) यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहन लाल गौतम (स्वशासन मंत्री)—(क) जी नहीं ।

(ख) इसमें कुछ वैधानिक कठिनाई उपस्थित हो गई है जिस पर द्वायतन विचार कर रहा है ।

श्री राम नन्दन सिंह—ग्राम पंचायतों को रुपया देने में कौन सी वैधानिक कठिनाई हो गयी है ?

श्री मोहन लाल गौतम—यह रुपया उन ग्राम पंचायतों का है जो बनारस राज्य की थीं और वह रुपया सरकारी खजाने में जमा था । जब वह स्टेट भर्ज हुई तो वह रुपया भी सरकारी हिसाब में जमा हो गया । पंचायत राज को ट्रांसफर करने में वैधानिक कठिनाई है जिस पर कार्यवाही हो रही है ।

श्री राम नन्दन सिंह—कब तक आशा की जाती है कि वह रुपया दिया जायेगा ?

श्री मोहन लाल गौतम—मैं प्रयत्न करूंगा कि जल्द से जल्द इसका फ़ैसला किया जाय ।

श्री कन्हैया लाल गुप्त (अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र)—क्या माननीय मंत्री ने जो कहा है उससे यह परिणाम निकाला जा सकता है कि सरकार अभी कोई टाइम लिमिट फिक्स करने की स्थिति में नहीं है ?

श्री मोहन लाल गौतम—जैसा मैंने इसमें कहा कि हम टाइम टेबिल उस समय बना सकेंगे जब लेजिस्लेचर से यह बिल पास हो जायेगा । इससे पहले यह हमारे फ़ाबू से बाहर की चीज है । वह तो लेजिस्लेचर के हाथ में है । जब तक लेजिस्लेचर कानून पास न कर दे तब तक ऐसा टाइम टेबिल बनाना मुश्किल है ।

श्री कुंवर गुरु नारायण (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि लेजिस्लेचर से पास होने के बाद कितना समय लगेगा यानी कितने दिनों में यह हो जायेगा ?

श्री मोहन लाल गौतम—इन इलेक्शन के लिये हमने एक अलग मुहकमा खोल दिया है जो सब तैयारी कर रहा है । वह भी कार्य शुरू हो रहा है और यह बिल भी पास हो जायेगा तब हम यह देखेंगे कि वह मुहकमा किस हद तक काम कर चुका है, तभी तय किया जायेगा ।

श्री कन्हैया लाल गुप्त—क्या माननीय मंत्री कृपा करके बतलायेंगे कि यह बात कहाँ तक ठीक है कि उन्होंने फ़रवरी में इलेक्शन करने की बात जनता में कही है ?

श्री मोहन लाल गौतम—वह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें जो बातें हुई उसका लोगों ने यह मतलब निकाला है। अब्बवार में जिस तरह की चीज छपी है वह बात बिल्कुल इस तरह से नहीं है। हो सकता है कि फरवरी में ही इलेक्शन हो जाय लेकिन जो बात मैंने कही थी वह यह थी कि चूंकि मार्च में बजट सेशन होगा, इसलिये मार्च में इलेक्शन कराना कठिन है तो यदि इलेक्शन फरवरी में न हुये तो अप्रैल या मई में होंगे।

म्युनिसिपल और टाउन एरिया कमेटीयों के चुनाव

७—श्री कन्हैया लाल गुप्त—सरकार राज्य में म्युनिसिपल और टाउन एरिया कमेटीयों के चुनाव को कब तक कराने का विचार रखती है ?

SRI KANHAIYA LAL GUPTA:—When do the U. P. Government intend to hold elections to Municipal and Town Area Committees in the State ?

श्री मोहन लाल गौतम—सरकार इन चुनावों को यथासंभव शीघ्र कराना चाहती है और जैसा ही म्युनिसिपल बोर्डों तथा टाउन एरियाओं से संबंधित संशोधन बिल विधान सभा और विधान परिषद् द्वारा पास कर दिये जायेंगे, इनके निर्वाचन का कार्यक्रम दिया जा सकेगा।

SRI MOHAN LAL GAUTAM:—Government want to hold the elections as soon as possible, and we will be able to give the time-table of elections of the Municipal Boards and the Town Areas as soon as the amending bills relating to them have been passed by the Legislature.

श्री कन्हैया लाल गुप्त—क्या माननीय मंत्री जो यह बतलाने की कृपा करेंगे कि मौजूदा बोर्ड जो अब आखिरी एक्स्टेंशन के मातहत काम कर रहा है, वह एक्स्टेंशन कब खत्म होगा ?

श्री मोहन लाल गौतम—जैसा कि समाचार पत्रों में निकला है कि वह ३० अप्रैल सन् १९५३ ई० को खत्म हो जायेगा।

श्री कन्हैया लाल गुप्त—क्या मंत्री जो यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो इलेक्शन करने की बात कही जा रही है उसमें सारे म्युनिसिपल बोर्ड हैं, या कुछ बोर्ड श्रवण भी हैं ?

श्री मोहन लाल गौतम—इस समय लगभग १० बोर्ड सुपरसीड हैं, उनमें से ५, ६ के इलेक्शन नहीं होंगे, बाकी ११९ के करने का इरादा है।

श्री कन्हैया लाल गुप्त—क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन म्युनिसिपल बोर्ड के इलेक्शन करने का इरादा नहीं है उसका कोई विशेष कारण है ?

चेयरमैन—इसकी मैं इजाजत नहीं देता हूँ।

प्रदेश के पंचायत राज्य निरीक्षकों की संख्या-वृद्धि

८—श्री परमात्मा नन्द सिंह (स्थानीय संस्थाएँ निर्वाचन क्षेत्र)—(क) क्या सरकार प्रदेश के पंचायत राज्य निरीक्षकों की संख्या बताने की कृपा करेगी ?

आदि संख्या

५१

ता० ६-१०-५२

(ख) इनमें कितने स्नातक अर्थात् ग्रैजुएट हैं ?

श्री मोहन लाल गौतम—(क) स्थलापन्न पंचायत निरीक्षकों को सम्मिलित करते हुये ४३० पदों पर पंचायत निरीक्षक कार्य कर रहे हैं।

(ख) २२५।

९—श्री परमात्मा नन्द सिंह—(क) क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सुयोग्य और श्रद्धा काम करने वाले पंचायत राज इन्स्पेक्टरों को आगे सरकारी के क्या क्या रास्ते और अवसर हैं ?

(ख) इन ग्राम पंचायत निरीक्षकों के शिक्षण के अन्त में दीक्षान्त भाषण देते हुये क्या प्रदेश के मुख्य मंत्री जी ने ऐसी आशा दिलायी थी कि अच्छा काम करने वालों को तहसीलदारी और डिप्टी कलेक्टरों तक में चुना जा सकेगा ?

श्री मोहन लाल गौतम—(क) सुयोग्य और अच्छा काम करने वाले पंचायत निरीक्षकों को सहायक जिला पंचायत अफसरों के रिक्त पदों पर पदोन्नतिगत वर्ष दी जा चुकी है।

(ख) इस विषय में माननीय मुख्य मंत्री को दीक्षान्त भाषण* के संबंधित भाग का उद्धरण संलग्न है।

श्री परमात्मा नन्द सिंह—क्या सरकार कुछ सहायक पंचायत अफसरों की जगह और बढ़ाने का इरादा कर रही है ?

श्री मोहन लाल गौतम—जैसा कि माननीय सदस्य को मालूम है कि हर जिले में एक सहायक पंचायत अफसर होता है, क्योंकि जिले नहीं बढ़ रहे हैं, इसलिये अफसरों के बढ़ने का कोई प्रश्न नहीं उठता है।

१०—श्री परमात्मा नन्द सिंह—(क) क्या सरकार ने कोई ऐसी आज्ञा दे रखी है कि ग्राम पंचायत निरीक्षक यदि किसी दूसरे पद के लिये अर्जी दे तो उनकी अर्जी तब तक आगे न बढ़ायी जाय जब तक कि वे इन्स्पेक्टरों से इस्तीफा न दे दें ?

(ख) यह आज्ञा कब जारी हुई और किसने किया ?

(ग) क्या सरकार ने इस आज्ञा को रद्द कर दिया है या कुछ बदल दिया है ?

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस आज्ञा को रद्द करना या बदलना चाहती है ?

श्री मोहन लाल गौतम—

(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रदेश के मुख्य तीर्थ स्थानों को आदर्श बनाने की योजना

११—श्री (हकीम) ब्रज लाल वर्मन (स्थानीय संस्थाएँ निर्वाचन क्षेत्र)—क्या सरकार काशी, प्रयाग, अयोध्या, मथुरा, बृन्दावन, हरिद्वार जैसे तीर्थ स्थानों को आदर्श बनाने की कोई योजना बना रही है ?

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस संबंध में कोई योजना बनाने का इरादा रखती है ?

श्री मोहन लाल गौतम—(क) सरकार ने नगरों और ग्रामों को सुधारने के लिये एक नगर और ग्राम नियोजन विभाग की स्थापना की है। इस विभाग ने काशी तथा प्रयाग को आदर्श बनाने के लिये योजनाएँ (Master plans) बनाकर उनको कार्यरूप में परिणत करने के लिये स्थानीय इम्प्रूवमेंट ट्रस्टों को दे दिया है। हरिद्वार की इसी प्रकार की योजना अभी बनायी जा रही है। अयोध्या, मथुरा तथा बृन्दावन के लिये अभी कोई योजना नहीं बनी है परन्तु मथुरा में दो आवासिक उपनियमों के निर्माण का मानचित्र बन चुका है ?

(ख) प्रश्न के पहले भाग के उत्तर में ही इस भाग का उत्तर भी निहित है। ये योजनाएँ भिन्न-भिन्न नगरों के लिये क्रमशः बनेंगी।

श्री हकीम ब्रज लाल वर्मन—क्या मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस योजना की कब तक बनने की आशा है ?

श्री मोहन लाल गौतम—यह कहना बहुत मुश्किल है। काम बराबर हो रहा है।

*भाषण के लिये देखिये नत्थी "क" आगे पृष्ठ १३८ पर

श्री हकीम ब्रज लाल वर्मन—क्या पंचवर्षीय योजना के अन्दर उसके बन जाने की आशा है ?

श्री मोहन लाल गौतम—इसका उत्तर में पहले दे चुका हूँ।

आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट को संशोधित करने के विषय में जानकारी की प्रार्थना

श्री कुंदर गुरु नारायण—Sir, I have read in the press that there is a move to amend the Agra University Act. An Ordinance is going to be issued by the Governor. So I wanted to know about it. Generally Ordinances are issued when the House is not in session.

चेयरमैन—You cannot ask anything of any kind at any time. This matter is not on the agenda. I do not think we can take up anything which is not on the agenda.

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन) विधेयक

*श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम (वित्त मंत्री)—जनाबवाला, मैं आपकी इजाजत से प्रस्ताव करता हूँ कि सन् १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन) विधेयक पर विचार किया जाय।

जिस रोज़ कि पहली बैठक शुरू हुई थी तो मैंने उस वक़्त यह अर्ज कर दिया था कि यह बिल ऐसा है कि जिसमें बहुत थोड़ा वक़्त लगेगा और वह इसलिये कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो कि कंट्रोवर्सियल हो और जिससे कि इसमें ज्यादा देर लगने की तवक्को हो। अब यह बिल हाउस के सामने पेश है। इसके अलावा जो दूसरे बिल हैं जिनमें कि कुछ अमेंडमेंट आये हैं, तो मेम्बरों के लिये इस बात का मौक़ा होगा कि वह चाहें तो आज ही इसको ख़त्म कर देंगे। यह बात मैं इसलिये अर्ज कर रहा हूँ कि ताकि हर मेम्बर को इसमें आसानी हो। इसके अलावा मेम्बरान को मौक़ा होगा कि वे अपने संशोधन आसानी से पेश कर सकते हैं। यह प्रस्ताव जो कि मैंने पेश किया है, उससे कई अमेंडमेंट्स हैं और जो उसमें पहली तरमीम है उसका तो इस हाउस के अन्दर तज़क़िरा आ चुका है जब कि यह बिल पहले पेश हो रहा था तो कुंवर साहब ने एक अमेंडमेंट दिया था, उसमें इसके मुतालिक़ उन्होंने यह कहा था कि जो बिक्री कर लगाये जाते हैं, वह मौकूफ़ हो जायें। तो मैंने उस वक़्त यह अर्ज किया था कि इस बिल के ज़रिये से सेल्स टैक्स में यह तरमीम आ रही है, चूनाच्चे यह वही चीज़ है। मैं हर एक तरमीम को और इस मूल ऐक्ट की दफ़ाओं को साथ-साथ पढ़कर समझा दूंगा कि यह तरमीम क्या है और कैसे इसकी ज़रूरत महसूस हुई है और किस जगह पर यह तरमीम आई है और उसमें क्या चीज़ें थीं और इस तरमीम के बाद क्या पोजीशन हो जायेगी। जैसे कि मैंने पहले ही अर्ज कर दिया है कि इस मूल ऐक्ट का जो सेक्शन २ है जिसमें किलपज की डेफ़िनिशन दी गई है उसमें ही 'डी' क्लाज के अन्दर गुड्स की डेफ़िनिशन दी हुई है और वह इस तरह से है :

'Goods' means all kinds of moveable property other than actionable claims, stocks, shares or securities, and includes electrical energy and every material, article and commodity, whether or not to be used in construction, fitting out, improvement or repair of immovable property ;"

तो इसमें जो असली एनर्जी है उसको निकाला जा रहा है। कम से कम इस संशोधन के मुतालिक़ मुझे तो यह तवक्को है कि इसमें कोई बहस की बात नहीं है और मेरे ख़्याल

*मंत्री ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

से इसके मुताल्लिक कोई मुखालिफत भी नहीं है। अब जो उसका दूसरा अमेंडमेंट है उसको पढ़ने से असली पोजीशन मालूम हो जाती है। मूल ऐक्ट का जो सेक्शन तीन है वह इससे ताल्लुक रखती है और इसके मातहत जो इसकी लाइबिलिटीज आती हैं वह किस तरह से इससे ताल्लुक रखती हैं, वह इसमें दिया हुआ है। अब जो इसमें प्रोविजो है उस प्रोविजो के नम्बर ४ में यह सब दिया हुआ है और फिर बिजली के ऊपर जो टैक्स उसके जरिये से लगता था तो इसमें उसको भी साफ कर दिया गया है। वहां से उसको निकाला जायेगा क्योंकि इससे पहले जो था वह इसके अन्दर रखा हुआ है और यह भी उसके अन्दर निकल जायेगा इसके बाद तीसरे सेक्शन में जो बात है, उसमें इस अमेंडमेंट के जरिये से एक नया प्रोविजो जोड़ दिया गया है। वह प्रोविजो इसमें लिखा हुआ है :

“Provided further that if the amount prescribed under clause (ii) of the preceding proviso is reduced during an assessment year, the tax payable as aforesaid by a dealer shall be computed as follows:”

यानी इसके बाद अगर में इसको पढ़ा तो मालूम हो जायेगा कि इस ऐक्ट में यह मुकर्रर किया गया है कि कितना बिक्री कर पर टैक्स लगा और उसकी लिमिट मुकर्रर की गई है। उसको अगर घटाया गया है, तो उसके घटाने के बाद, उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा, वह पहले बतला दिया गया है कि वह उस हिस्से का है जो कि इसके घटाने के बाद आयेगा, उसमें उसी तरीके से हिसाब होगा, इसमें है :

“Provided further that if the amount prescribed under clause (ii) of the preceding proviso is reduced during an assessment year, the tax payable as aforesaid by a dealer shall be computed as follows: that is to say,

- (a) on the turnover relateable to the period previous to the reduction, as though the amount had not been reduced, and
- (b) on the remainder as though the reduced amount had been in force on all material dates.”

इससे पहले की जो बात है, उसके लिये इस हिसाब से लगाया गया है और उसमें तरमीम नहीं हुई है। इसके बाद जो है उसमें इस हिसाब से लगाया गया है कि उसमें तरमीम हो गई है। अब इसे समझने से पहले आप यह देखें कि जो इस ऐक्ट की मूल दफा है उसके अन्दर क्या है ?

“Subject to the provisions of this Act, every dealer shall pay on turnover in each assessment year a tax at the rate of 3 pies a rupee”

इसके पढ़ने के बाद यह समझ में आ जायेगा। यह दफा कहती है कि जो टैक्स लागू होगा इस कानून से, तो उसमें एक शख्स दूसरे के हाथ बँचे और वह दूसरा तीसरे के हाथ बँचे और इस तरह से वह चलता रहे और उसके ऊपर टैक्स लगा दिया जायेगा और इसके आगे जो है वह कहती है कि :

Provided that—

- (i) “the state Government may, by notification in the official Gazette, reduce the rate of tax on the turnover of any dealer or class of dealers on or on the turnover in respect of any goods or class of goods”

अब मैं इसमें दूसरी जगह पढ़ता हूँ जो कि सुनने के लायक है:—

- (ii) “a dealer whose turnover in the previous year is less than Rs. 12,000 or such larger amount as may be prescribed shall not be liable to pay the tax under this Act for the assessment year:”

इसके मातहत यह लिमिट मुकर्रर है कि जिसकी बिक्री साल भर में १२ हजार के ऊपर है यह टैक्स लगेगा और उससे नीचे के ऊपर नहीं लगेगा। तो हमारे सामने जो यह बात है, इसके

लिये अमंडमेंट नहीं है। तो यह १२ हजार की बात है और इस लिमिट के ऊपर ही वह टैक्स लगेगा। यह जगह मुस्तकिल है और कानून में लिखा है कि १२ हजार से कम बिक्री पर टैक्स नहीं लगेगा और जब तक यह कानून है और तरमीम नहीं होती है उस वक्त तक घट नहीं सकता है, लेकिन उसके आगे जो अलफाज है, 'सच लार्ज एमाउन्ट' उसमें २ चीजें रखी गई हैं, एक तो १२ हजार कम से कम या १५ हजार के बीच में, जो कानून मुकर्रर कर दे। गवर्नमेंट ने १२ हजार और १५ हजार के बीच मुकर्रर किया है। अब जो बसूल होता है वह १५ हजार और उसके ऊपर बसूल होता है। १२ और १५ हजार के बीच की जो रकम है उसके बढ़ाने और घटाने का सवाल है, लेकिन १२ हजार से नीचे जाने का कोई सवाल उठता नहीं है। यह मैं इसलिये कह रहा हूँ कि इस मजमून पर एक अमंडमेंट आगे है और मैं समझता हूँ कि वह शलतफहमी पर है। जो आज कानून है उसमें १२ हजार से नीचे हम जान नहीं सकते हैं। यह हक बेवशक है कि १२ और १५ हजार के बीच में गवर्नमेंट कोई रकम कर दे। जो गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन के जरिये मुकर्रर किया है अगर उसको विद्वड़ा कर लिया जाय तो १२ हजार की रकम रह जायेगी और आइन्दा जमाने के लिये और जो गुजर चुका है, उसमें एक आदमी का हिसाब कैसे लगाया जायगा और टैक्स कैसे लिया जायेगा, इसके लिये एक प्रोबिजन जो दिया गया है। नई पोजीशन कायम नहीं की जा रही है, बल्कि पोजीशन कानून की जैसी थी वैसी ही रहेगी, सिर्फ उसके साथ जो कमी थी उसको ही पूरा किया गया है, लिहाजा उस प्रोबिजो को मैंने पढ़ कर सुनाया है। इस अमंडमेंट के जरिये यह अस्तियार लिया गया है।

अब उसका एक सेक्शन ३ (ए) मूल ऐक्ट का है, वह है सिंगिल प्वाइन्ट, जो हर बिक्री पर लिया जायेगा और मल्टीपल प्वाइन्ट का मतलब यह है, मसलन ४ फिगर्स हैं, तो एक या २ या आखरी तो उसमें किसी के ऊपर भी लगाया जा सकता है। मैं अर्ज करता हूँ कि प्रिंसिपल जो इस ऐक्ट का है वह यह है कि जो टैक्स लगे वह मल्टीपल प्वाइन्ट से लगे और सिंगिल प्वाइन्ट कैसे हो सकता है, यह ३ (ए) में दिया हुआ है।

"Single point taxation (1) Notwithstanding anything contained in section 3, the state Government may, by notification in the official Gazette, declare that the proceeds of sale of any goods or class of goods shall not be included in the turnover of any dealer except at such single point in the series of sales by successive dealers as may be prescribed."

In section 3 the State Government may by notification in the official Gazette declare that the proceedings.....

इससे गवर्नमेंट को यह अस्तियार होगा कि जितने टर्नओवर हैं उनमें किसी एक को मुकर्रर कर दे और वह टैक्स देने को प्रेस्क्राइब कर सकती है।

अब इससे जो मैं पढ़ रहा हूँ, यह कापी सन् १९५० ई० से भी शायद पहले की थी। सन् १९५० ई० में इसमें एक तरमीम हो गई थी। इस वक्त जो हम तरमीम कर रहे हैं, वह तो इस तरह से सेम्बरान पढ़ेंगे, प्रेस्क्राइब लफ्ज के बजाय, "दि स्टेट गवर्नमेंट में स्पेसिफाई" यह अलफाज इसमें लिखे जावेंगे। तो बात यह है कि प्रेस्क्राइब करना रूल्स के जरिये से ऐक्ट में होता है। हमेशा यह लफ्ज आता है और उसमें डेफिनिशन में यह लिख दिया जाता है। वह रूल्स गजट में छप जाते हैं, उनके मुताल्लिक कोई एतराज करना चाहे, तो एतराज कर सकता है। इन एतराजात को कंसीडर करके गवर्नमेंट रूल्स बनाती है। यह मामला क्या है, यह मामला यह है कि हम गवर्नमेंट की तरफ से एक आसानी पैदा करते हैं, पब्लिक के लिए, वह यह है कि मल्टीपल प्वाइन्ट्स जो टैक्स थे उनको हम सिंगिल प्वाइन्ट करें यानी ५ बिक्रियों में से उन पर किसी एक बिक्री पर टैक्स मुकर्रर कर दिया जाये। इसमें हम यह कर दें कि प्रेस्क्राइब इन दि नोटिफिकेशन। तो यह पब्लिक के लिए भी अच्छी बात है और जो थोड़ी सी बेर इस काम को करने में लग जाती है उससे भी बचा जा सकता है। यह एक सीधा रास्ता पब्लिक के फेवर का अच्छा काम करने का है। यह तरमीम इसी मकसद से की गई है। एक और तरमीम जो इसमें है, वह यह है :

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

"In clause (a) of sub-section (1) of section 4 of the Principal Act the words "electrical energy" for industrial purposes shall be *omitted*"

यह सेक्शन में दिया हुआ है कि लपज, जहाँ जहाँ आया है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी के मुताल्लिक है, वह सब इसके अन्दर से निकाल दिए जायें। इसके बाद बलाज ६ है। इसमें है—

"In sub section (2) of section 23 of the Principal Act."

जो मूल ऐक्ट है, उसकी जो दफ़ा २३ है, उसका अमेंडमेंट और अमेंडमेंट का मसदा यह है कि एक तो हुआ सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट, और एक गवर्नमेंट आफ इंडिया का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, इन दोनों के बीच में अक्सर इनफारमेशन एक्स्चेंज करने की जरूरत पड़ती है। गवर्नमेंट आफ इंडिया के इनकम टैक्स ऐक्ट में यह तरमीम हो गई है कि स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट आफ इंडिया के आफिसर्स आपस में इनफारमेशन एक्स्चेंज कर सकते हैं। इसी तरह की हम भी तरमीम कर रहे हैं जिससे हमारी स्टेट के आफिसर्स गवर्नमेंट आफ इंडिया और दूसरी स्टेट से इनफारमेशन एक्स्चेंज कर सकेंगे।

अभी तक सेक्शन २५ का जो प्रिन्सिपल ऐक्ट है वह बिजली के मुताल्लिक है। एज फार एज आई रिमेम्बर उसकी इबारत पढ़ने की जरूरत नहीं है। वह बिजली के मुताल्लिक है उसको भी निकाल दिया गया है। इसके जरिये से इस वक़्त कोई ऐसी बात नहीं हो रही है कि उसको ज्यादा बहस में लिया जाय। मेरा मतलब यह नहीं है कि मेम्बरान साहब इस पर बहस न करें। जरा राइट प्वाइंट आफ व्यू पर निगाह रखकर बहस करें कि कहां तक वह माकूल है? मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने अर्ज किया है वह मेम्बरों की समझ में आ गया होगा। मैं देखूंगा, अगर कुछ बाकी रह गया होगा, तो बाद में अर्ज कर दूंगा।

श्री कुंवर गुरु नारायण—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सेल्स टैक्स अमेंडमेंट विधेयक अभी माननीय वित्त मंत्री ने इस भवन के सम्मुख रखा उसके सम्बन्ध में अपना विचार रखना चाहता हूँ। मैं उम्मीद कुछ और करता था और मुझे आशा कुछ और ही थी। मैंने अखबारों में पढ़ा था अभी दिल्ली में फाइनंस मिनिस्टर्स की कोई कानफ्रेंस बुलाई गई थी और उस कानफ्रेंस के जरिये से इस बात की कोशिश गवर्नमेंट आफ इंडिया कर रही थी कि यूनिफारमिटी सेल्स टैक्स में हर प्रान्त में होनी चाहिये और इस सम्बन्ध में फाइनंस मिनिस्टर्स की कानफ्रेंस के बाद भी श्री राजगोपालाचारी, जो मद्रास के फाइनंस मिनिस्टर भी हैं उनका एक स्टेटमेंट निकला था जिसके जरिये से उन्होंने इतना ही कहा था कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं और बहुत कुछ यूनिफारमिटी की उम्मीद है। जहाँ तक सेल्स टैक्स का मसला है, यह जो सेल्स टैक्स है, यह जाहिर है कि सेल्स टैक्स सन् ३८ में लगाया गया था। सन् ३८ में इस प्रकार का सेल्स टैक्स लगाने का जो अभिप्राय था, उसमें एक बात यह भी थी कि प्राहीबिशन स्कीम लगाने को कहा गया था। यह मुनासिब समझा गया था कि इस सेल्स टैक्स के जरिये से गवर्नमेंट की जो कुछ रेवेन्यू घट गई है प्राहीबिशन से उसमें उनको कुछ थोड़ी सी रिलीफ मिल जायगी। लेकिन उस वक़्त जब यह सेल्स टैक्स लगाने का विचार हुआ तो यह एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि सेल्स टैक्स कोई मेजर आइटम होगा सोर्स आफ रेवेन्यू का। क्योंकि उस वक़्त यह भी सोच लिया गया था कि सेल्स टैक्स लक़्ज़री के ही ऊपर लगाया जायेगा, जिन्दगी के इसेन्शियल चीज़ों के ऊपर सेल्स टैक्स नहीं लगाया जायेगा। बहरहाल, उसके बाद वार (war) हुई, वार में रेवेन्यू की आवश्यकता थी और उसका परिणाम यह हुआ कि सेल्स टैक्स इसेन्शियल और नान इसेन्शियल हर एक क्मोडिटी के ऊपर लगाया जाना शुरू हो गया। लेकिन हमारा प्रान्त जो है उसने और प्रान्तों की बनिस्बत नान इसेन्शियल चीज़ों पर भी सेल्स टैक्स कमी के साथ

लगाया। मद्रास और द्रावनकोर में तो तमाम इसेन्शियल कमोडिटीज पर भी सेल्स टैक्स लगाया गया। इन्टर स्टेट्स ट्रेड जो इस टैक्स द्वारा बैन थी कि इन्टर स्टेट्स ट्रेड के संबंध में सेल्स टैक्स न होना चाहिये, उसमें भी तमाम प्रदेश ने इन्टर स्टेट्स ट्रेड पर सेल्स टैक्स चार्ज करना शुरू किया। एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पर भी सेल्स टैक्स लगाना शुरू हो गया। ऐसी हालत में मैं कहना चाहता हूँ कि सेल्स टैक्स के लगाने की जो मन्शा थी वह मन्शा ही बिल्कुल फ़ारफ़ीट हो गई। मैं इस बिल का विरोध तो नहीं करता हूँ, लेकिन मैं माननीय फ़ाइनेन्स मिनिस्टर साहब से प्रार्थना करूंगा कि चूंकि इस संबंध में विचार हो रहा है, मुमकिन है कि कुछ और तब्दीलियां हों सेन्टर से और उसके अनुसार फिर आपको भी तब्दीलियां करनी पड़ें तो आप थोड़े दिन के लिये ठहर जायें तो ज्यादा अच्छा होगा। जहां तक इस सेल्स टैक्स का संबंध है, मैं बतलाना चाहता हूँ कि कांस्टीट्यूशन के २८६ आर्टिकल के मातहत वहां इसका वायलेशन हो रहा है, उसको मैं श्रीमान् की आज्ञा से पढ़कर सुना देना चाहता हूँ :-

“(1) No law of a State shall impose or authorise the imposition of a tax on the sale or purchase of goods where sale or purchase takes place.

(a) outside the State, or

(b) in the course of import of goods into or export of the goods out of the territory of India.”

आउट ऑफ़ इट्स टेरिटरी, सेल्स टैक्स लगाना किसी भी प्रदेश को इस कांस्टीट्यूशन के मातहत अधिकार नहीं है। लेकिन किस सूरत में अधिकार ऊपर बतलाई हुई दफ़्ता से है, वह भी मैं आपकी आज्ञा से पढ़ बता हूँ:-

“EXPLANATION:—For the purposes of sub-clause (a) a sale or purchase shall be deemed to have taken place in a State in which the goods have actually been delivered as a direct result of such sale or purchase for the purpose of consumption in that State notwithstanding the fact that the general law relating to the sale of goods, the property in the goods, has by reason of such sale or purchase passed in another State.”

इसके माने यह भी हुये कि प्रान्त के लोगों के कन्जम्पशन के लिये सेल्स टैक्स वस्तुओं पर नहीं लिया जाय पर अगर अभिप्राय तिजारत का है तो लिया जायेगा। मैं एक कांफ़ीट इक्वाम्पुल लेकर इसको बतलाना चाहता हूँ। मसलन् अलीगढ़ के लाक अगर यह गवर्नमेंट विन्ध्य प्रदेश की गवर्नमेंट को बेचती है तो अगर वह कन्जम्पशन के लिये बिकता है तब तो कोई अधिकार नहीं है कि गवर्नमेंट किसी दूसरे स्टेट के ऊपर सेल्स टैक्स लगा सके लेकिन अगर दूसरी स्टेट इस परपज के लिये यहां से आर्टिकिल्स लेती है कि वह यहां से लेकर किसी दूसरी स्टेट को बेच दे तो उस हालत में एक प्रदेश की गवर्नमेंट को अधिकार होगा कि वह सेल्स टैक्स दूसरे प्रदेश से वसूल कर सकती है। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो सेल्स टैक्स लिया जाता है वह इस वक़्त उन चीजों पर ही नहीं लिया जाता है जो चीजें कन्जम्पशन के लिये ली जाती हैं बल्कि उन चीजों पर भी लिया जाता है जिन पर कानूनन न लेना चाहिये। इसके अलावा मैं यह बतलाना चाहता हूँ कि हमारे प्रदेश की गवर्नमेंट ने जो प्राविजन अपने सेल्स टैक्स में सन् १९४८ ई० में रखा है उसमें उन्होंने निहायत होशियारी के साथ इसको बचाने की कोशिश की है और वह सेक्शन २ इस तरह से है—

“Notwithstanding anything in the Indian Sales of Goods Act, 1930, or any other law for the time being in force, the sale of any goods,

(ii) which are purchased or manufactured in the United Provinces by the producer or manufacturer thereof, shall wherever the delivery or contract of sale is made be deemed for the purpose of this Act to have taken place in the United Provinces.”

[श्री कुंवर गुरु नारायण]

इसके माने यह है कि अगर किसी चीज की बिक्री का कन्ट्रैक्ट हो गया तो गवर्नमेंट को राइट होगा कि वह सेल्स टैक्स लगा सकती है यह बात गोल कर दी गयी कि जो चीज बिकेगी वह प्रदेश के कन्जप्शन के लिये भी नहीं अथवा इन्डियन कमोडिटी तो नहीं है। यह चीज इस ऐक्ट में दी हुई है लेकिन अगर कान्स्टीट्यूशन की धारा २८६ को हम देखें तो मालूम होगा कि वह प्रदेशीय ऐक्ट की धारा २८६ को बिल्कुल विपरीत है। हम देखते हैं कि यह जो गवर्नमेंट आफ इंडिया का एक्सप्लेनेशन है:—

It is not clear whether it is for consumption or for sale to any other State.

श्री इन्द्र सिंह नयाल (स्थानीय संस्थाओं निर्वाचन क्षेत्र) —On a point of order, जो माननीय सदस्य अपनी स्पीच दे रहे हैं वह इर्रेलेवेन्ट हैं। जो अमैंडमेंट हाउस के सामने है उससे यह प्रश्न नहीं उठता।

चेयरमैन—ट्वाइन्ट आफ आर्डर उठते समय आप स्पीच नहीं दे सकते।

श्री इन्द्र सिंह नयाल—मुझे यह कहना है कि माननीय सदस्य इर्रेलेवेन्ट स्पीच कर रहे हैं।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—

As far as discussion of the amendments-to the bill are concerned, the discussion has to be confined only to the amendment, and the whole law should not be discussed. Out of deference to the wishes of my friend I did not want to say anything but now that a point of order has been raised, it seems to me that what Mr. Guru Narain is saying is not at all relevant to the amending Bill.

इस वक्त तो जितनी भी बहस मैंने सुनी वह इर्रेलेवेन्ट है। जितनी भी तक्ररीर अब तक की गयी है उससे मालूम होता है कि वह अमैंडमेंट पर नहीं है।

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद—(स्नातक निर्वाचन क्षेत्र)—The policy of the sales tax is under discussion.

चेयरमैन—यह बात तो स्पष्ट है कि जो बिल इस वक्त पेश है उसी के संबंध में कुछ बातें कही जा सकती हैं। कुंवर साहब इसका ध्यान जरूर रखें।

श्री कुंवर गुरु नारायण—श्रीमान्, मैं तो यह समझता हूँ कि मैंने बिल के बाहर तो कोई बात नहीं कही। मैं तो यह कह रहा हूँ कि जो कान्स्टीट्यूशन है और जो हमारा सेल्स टैक्स विधेयक है वह बिल्कुल ही एक दूसरे से फ़र्क करते हैं।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—इसमें अगर कोई अनकान्स्टीट्यूशनल बात है तो आप उसको बतलाइये। अमैंडमेंट की बाबत बतलाइये।

श्री कुंवर गुरु नारायण—श्रीमान्, मैं उसी की बाबत कह रहा हूँ.

चेयरमैन—यह जो मूल सेल्स टैक्स ऐक्ट है उसकी वैधानिकता पर आप बहस न करें।

इस वक्त जो संशोधन विधेयक प्रस्तुत है अगर उसको आप अवैधानिक समझें तो उस पर कहें। सरकार की सेल्स टैक्स की जो नीति है उस पर निर्णय देने का अधिकार तो सुप्रीम कोर्ट को है। इस वक्त जो विधेयक सदन में पेश है उसके बारे में आप कहें।

श्री कुंवर गुरु नारायण—श्रीमान्, मुझे अफ़सोस है कि मैं कोई ऐसी बात नहीं कह रहा था जो कि सेल्स टैक्स से संबंध न रखती हो, इस बिल से संबंध न रखती हो। मैं दो चीजों

की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता था कि यह जो सेल्स टैक्स है वह लागू है आज इंटर स्टेट ट्रेड ऐक्ट पर और उन चीजों पर भी जो कि इसमें शामिल हैं फार दि लाइफ़। यह दोनों चीजें कांस्टीट्यूशन में वर्जित कर दी गयी हैं। इसमें शामिल चीजें फार दि लाइफ़ और इंटर स्टेट ट्रेड के ऊपर यह सेल्स लागू कानूनन नहीं हो सकता है। इससे हम भारत के संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं.....

चेयरमैन—You should confine yourself to the actual amendments embodied in the Bill.

श्री कुंवर गुरु नारायण—इसके बाद जहां तक इंटर स्टेट ट्रेड ऐक्ट और इसमें शामिल वस्तुओं पर न लागू होने का सवाल है, वही तो हो चुका। लेकिन इस विधेयक के संबंध में मैंने एक संशोधन रखा है और वह संशोधन इस आशय का है। डिफरेंट स्टेट्स जो हैं उन्होंने अपने-अपने टर्नओवर फिक्स किया है फार दि परपज आर इन्वेंशन मसलन आसाम में ५ हजार रखा गया है तो हमारे उत्तर प्रदेश में १० हजार रखा गया है। सेक्शन ३ यू० पी० सेल्स टैक्स ऐक्ट का जो अब है उसमें यह कहा गया है कि जो पिछले साल का यानी मिसाल के तौर पर १९५०-५१ का अगर किसी का टर्नओवर १२ हजार रहा हो तो उस पर सेल्स टैक्स असेस किया जाय अगर वह १९५२-५३ में कम हो। इस सेक्शन में मैंने एक संशोधन रखा है जब वह आयेगा। तब उस पर बहस करूंगा। लेकिन मैं यह समझता हूँ कि इस सेल्स टैक्स ऐक्ट की धाराओं हमारे कांस्टीट्यूशन की धाराओं का बायलेशन करती हैं।

चेयरमैन—जो संविधान की अवहेलना की बात आप कहते हैं तो क्या वह मूल ऐक्ट से भी हो रही है।

श्री कुंवर गुरु नारायण—इस से भी हो रहा है।

चेयरमैन—आप का कहना है कि जो मूल ऐक्ट है उस के द्वारा आप की राय से संविधान की अवहेलना हो रही है तो इस वक़्त उस पर बहस नहीं की जा सकती है। इसके लिये सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिये।

श्री कुंवर गुरु नारायण—जो कुछ मुझे कहना था वह मैंने कह दिया, अब श्रीमान् की आज्ञा नहीं है तो कुछ नहीं कहूँगा और बैठता हूँ।

***श्री प्रभु नारायण सिंह** (स्थानीय संस्थाएँ निर्वाचन क्षेत्र)—अध्यक्ष महोदय, जो बिल इस सदन के सामने है, वह खास तौर से सेल्स टैक्स को अमेंड करने के लिये है। मैं कुछ ऐसा महसूस करता हूँ कि जब कोई बिल सदन के सामने हो तो उसके ऐसे माने होते हैं कि उस बिल पर भी बातचीत की जा सकती है। लेकिन चूंकि अध्यक्ष महोदय, आप की ऐसी रुचि है इसलिये मैं इस अमेंडिंग बिल के संबंध में ही कहूँगा। फाइनेंस मिनिस्टर महोदय ने जिस समय इस बिल को सदन के सामने रखा उन्होंने उस संशोधन पर भी और किया जो संशोधन इस बिल के सिलसिले में यहां पर हमारी तरफ से दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, इन संशोधनों की ध्यान में रखते हुये माननीय फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने जो तक्रारीर की, इस सिलसिले में उन्होंने इस बात को साफ़ करने की कोशिश की कि शायद ये अमेंडमेंट कुछ गलतफहमी से आ गये हैं या न समझने की वजह से आ गये हैं। मैं ऐसा समझता हूँ कि शायद यह उन की गलतफहमी रही हो। जो अमेंडमेंट इस बिल के जरिये हमारे माननीय मंत्री जी करना चाहते हैं और खासतौर से सेक्शन ३ में जो कि ओरिजिनल ऐक्ट का है तो उस सेक्शन ३ (२) में एक प्रोविजो जोड़ने की बात है। इसके संबंध में कहना चाहता हूँ कि सेक्शन ३ का खंड २ जो है वह इस तरह है।....

"A dealer whose turnover in the previous year is less than Rs. 12,000- or such larger amount as may be prescribed shall not be liable to pay the tax under this Act for the assessment year."

* सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री प्रभु नारायण सिंह]

इसके साथ ही साथ यह प्रोविजो जोड़ने की बात है—

“Provided further that the amount prescribed under clause (ii) of the previous proviso is reduced during an assessment year the tax payable as aforesaid by a dealer shall be computed as follows:—

that is to say,

- (a) on the turnover relateable to the period previous to the reduction, as though the amount had not been reduced, and
- (b) on the remainder as though the reduced amount had been in force on all material dates.”

इसके बाद जो दफ़ा ३ में प्रोविजो दिया हुआ है उस में साफ़ तौर से इस बात को कहा गया है कि १२ हजार रुपये या १२ हजार से कम रकम इस सेल्स टैक्स में नहीं रखी तो इस ऐक्ट के मुताबिक़ सरकार को इस बात का हक़ होगा कि वह दफ़ा २४ के मुताबिक़ इस ऐक्ट में नियम बना सकती है। दफ़ा २४ में दिये गये नियमों के बनाते वक़्त सरकार रुल ७ के मुताबिक़ इस बात को तय करे की १२ हजार रुपये की जगह वह १५ हजार रुपये पर सेल्स टैक्स लगाये। मेरे कहने का मतलब है कि जो सरकार प्रेसक्राइब कर दे वह १२ हजार के नीचे नहीं होगा। जैसा कि श्री मंत्री जी ने कहा तो ऐसी सूरत में कोई अमेंडमेंट लाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी सूरत में, मैं समझता हूँ कि जो प्रोविजो लाया गया है उसके रखने की कोई ज़रूरत नहीं थी। दफ़ा २४ में आप को हक़ है कि जो नियम आप बनायें वह १५ हजार रुपये की रकम पर हो। अगर वह रकम १२,१३ या १४ हजार रुपये हुई तो उसकी वसूली किस प्रकार होगी। मैं समझता हूँ कि सरकार के सब लोग अक्लमन्द हैं और उनके जो सलाहकार हैं वह भी अक्लमन्द हैं, इसलिये उन के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। मैं समझता हूँ कि जो प्रोविजो जोड़ने की कोशिश की गयी है उससे जो ख़तरा महसूस होता है, वह ख़तरा साफ़ है। ऐसी सूरत में जब यह नियम में दिया हुआ है कि सरकार को इस बात पर नियम बनाने का हक़ है, तो मैं समझता हूँ कि जो खंड २ रखा गया है उस की कोई ज़रूरत नहीं है। इस खंड को रखने से जो दिक्कत महसूस होती है उसको हमारे मिनिस्टर अच्छी तरह से समझ गये होंगे। हमारे मिनिस्टर काफ़ी अक्लमन्द हैं और उनके सलाहकार भी अक्लमन्द हैं, तो ऐसी हालत में सरकार को यह राउंड अवाउट तरीक़ा नहीं अख़्तियार करना चाहिये। मैं समझता हूँ कि जो मंत्री जी ने कहा वह सही है और मैं उस को सही भी मानता हूँ। इस नियम के मुताबिक़ १५ हजार पर जितना सेल्स टैक्स होगा वह १४ हजार पर हो जायेगा, तो यह जो एक हजार रुपये का डिफरेंस होगा, इसका हिसाब-किताब कौन करेगा? सरकार तो काफ़ी समझदार है उसको कोई ठीक रास्ता अख़्तियार करना चाहिये। इसलिये खंड २ जो कि प्रोविजो के रूप में यहाँ आया है, उस की कोई ज़रूरत नहीं है।

दूसरी बात जो कि माननीय मंत्री जी ने अपनी तक्रार के दौरान में कही है, वह दफ़ा ३ (ए) के संबंध में कही है, और उसमें सिंगल प्वाइंट टैक्सेशन की बात है। उसमें कहा गया है कि.....

“Notwithstanding anything contained in Section 3, the State Government may, by notification in the official gazette, declare that the proceeds of sale of any goods or class of goods shall not be included in the turnover of any dealer except at such single point in the series of sales by successive dealers as may be prescribed.”

तो इस संबंध में जो नियम दिये गये हैं उन नियमों के सिलसिले में एक दिक्कत की बात यह भी कि उसमें सिंगल प्वाइंट पर टैक्सेशन की बात है, तो जहाँ तक सिंगल प्वाइंट टैक्सेशन की बात है और जो कि टैक्स पे करने वाले हैं, उसके सिलसिले में यह कहा गया कि चूँकि वह इसके

वित्तज्ञान नहीं है और सभी इस बात के पक्ष में हैं इसलिये मंत्री महोदय ने यह बल्लोली दी है कि उसके सिलसिले में कोई कन्ट्रोवर्सियल बात नहीं है और इसको मान लेना चाहिये। मैं तो ऐसा समझता हूँ कि यदि माननीय मंत्री जी इसको थोड़े में और एक्सप्लेन कर दें तो हमारा जो शुबहा है वह कुछ दूर हो जाय। मैं समझता हूँ कि जहाँ तक सिंगल प्वाइंट टैक्सेशन का सवाल है वह आवश्यक नहीं होगा और इसके साथ-साथ इस टैक्सेशन की जो बैलूएशन है, जैसे कि एक रुपये पर ३ पैसे लेने का सवाल है, तो उसको ६ पैसे भी वह कर सकती है, यह बात मैं इन्फ़ॉर्मेशन के तौर पर जानना चाहूँगा। यदि ऐसी बात है तब तो मैं समझता हूँ कि दफ्ता २४ के मातहत जो हक मिले हुये हैं लेजिस्लेचर को, कि वह टैक्सेशन कर सके, या जहाँ सरकार इस तरह से करना चाहती है, तो इसका विरोध कर सके, या इसके पक्ष में अपनी राय दे सके, सब बेकार है, लेकिन इस संबंध में मुझे शुबहा है, इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूँगा कि दफ्ता ३ (ए) के सम्बन्ध में जिसको कि यहाँ दफ्ता ४ के जरिये से अमॉडिफ़ाई बिल में चेंज करने जा रहे हैं, वह क्यों ऐसा किया जा रहा है, अगर वह इसलिये है कि कुछ चीजों पर मल्टीपिल प्वाइंट के हिसाब से आप लेने जा रहे हैं, तब तो हमारा कोई एतराज नहीं है, लेकिन यदि इसमें यह सवाल है कि मल्टीपिल प्वाइंट को लिगल प्वाइंट करने जा रहे हैं, तो यह चीज भी डाउट में रहेगी कि ३ पैसे की जगह पर ६ पैसे भी हो सकते हैं। मैं समझता हूँ कि दुबारा बोलते समय माननीय मंत्री जी इस संबंध में अपनी राय जाहिर करेंगे। इसके साथ-साथ इलेक्ट्रिसिटी के सिलसिले में जो सेल्स टैक्स जोड़ने की बात कही गई है, मैं उसका स्वागत करता हूँ।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जनाबवाला, मैंने जो बात सुनी है उसको मैंने अपनी समझ के मुताबिक पहले ही यहाँ अर्ज कर दिया था। एक तो सेक्शन तीन का जो अमॉडिफ़ाई उसमें एक क्लॉज बढ़ाई गयी है जो कि नई है और जिसका मकसद यह है कि पिछले जमाने साल के पहले हिस्से में किस तरह से टैक्स लगाया गया और इसके बाद में किस तरह से लागू किया गया है, तो इस बात का जिक्र किया गया है। इसके बारे में मैं अधिक तफ़्सील में नहीं जाऊँगा। मैं यह देख रहा हूँ कि इसको भी मेरे दोस्त ने यह समझा कि गालिबन यह ग्रैंड ज़ररी है, तो इसकी वाबत में यह अर्ज कर दूँ कि कानून में १२ हजार की लिमिट रक्क़ी हुई है यानी जिस किसी की विक्की १२ हजार रुपया सालाना है उसके ऊपर टैक्स लगाया जाय, लेकिन गवर्नमेंट को कानून ने यह अख्तियार दिया है कि यह जो लिमिट मुक़र्रर की गई है या इससे कोई ऊँची लिमिट मुक़र्रर करके वह उसे बन्द कर सकती है। मान लिया जाय कि गवर्नमेंट ने १२ हजार की जगह १५ हजार की लिमिट मुक़र्रर कर दी, लेकिन लीगल पोज़ीशन यह है कि अगर यहाँ आय हुये या अगर लेजिस्लेचर को कन्सल्ट किये हुये अगर गवर्नमेंट चाहे कि वह १५ हजार को १२ हजार कर दे, तो यह कानून के जरिये से कर देगी, उसमें गवर्नमेंट को कोई रुकावट नहीं है। अब १५ हजार को १२ हजार तो वह कर दे, लेकिन इसके बाद वह १२ हजार से ११ हजार नहीं कर सकती है। १५ और १२ के बमियान जो फ़रमाया गया है, तो उसको घटाने और बढ़ाने का सवाल है। तो जितना घटाना चाहते हैं उसके लिये तो अख्तियार है। अगर यह अमॉडिफ़ाई न हो तब भी ऐसी बात की जा सकती है। हम इसके लिये एक नोटिफ़िकेशन कर दें कि १५ हजार के बजाय १२ हजार कर दिया जाय। इसके लिये किसी तरमीम की जरूरत नहीं है। इसमें सवाल यह है कि बजाय घटाने के उन लोगों के ऊपर जिनके ऊपर यह टैक्स पड़ेगा, तो इसके लिये यह जरूरत होगी, तो यही क़ायदा होगा उसके लिये नोटिफ़िकेशन जारी किया जायगा। और जितना हिस्सा पहले गुज़र चुका है, उसका उसी तरीके से होगा। तो इसमें नियम बनाने का कोई सवाल ही नहीं है और गवर्नमेंट को यह अख्तियार वैसे ही है। इसके लिये किसी तरह के ला बनाने की जरूरत नहीं है। इसके लिये यह बात है कि अगर गवर्नमेंट ऐसा करती है तो उसके लिये कैलकुलेशन कैसे हो। तो इस सबके लिये कहना कि यह रडिंडेन्ट है, ठीक नहीं है। गवर्नमेंट को जरूरत होगी तो वह ऐसा कर सकती है।

श्री प्रभु नारायण सिंह—वह तो नियम बना कर हो सकते हैं।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—वह इस तरह से नहीं हो सकते हैं। जो ऐक्ट की बातें पहले से हैं, उनमें नियम नहीं बनाये जा सकते हैं, यदि वे पहले से नहीं। तो उनको हम किसी भी रूल से नहीं बना सकते हैं और उसके अन्दर ऐसा कोई क्रायदा नहीं हो सकता है। यह तो सिर्फ़ अमेन्डमेंट की बात है। उसकी और बातों में मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल, मैं यह समझता हूँ कि वह रिजोल्यूशन हो नहीं सकता है। गालिबन एक बात जो कुबेर साहब ने इसमें अपने अमेन्डमेंट की कही है, तो उसके मुताल्लिक मैंने पहले से ही अर्ज कर दिया है। अगर थोड़ी देर के लिये मान भी लिया जाय कि उनका अमेन्डमेंट मंजूर हो गया, तो उसमें यह है कि जो प्रोविजो इस सेक्शन ३ में लिखा है, वह न रहे। यह उनका अमेन्डमेंट है। अगर उसको निकाल दिया जाय तो क्या पोजीशन रह जाती है। उसके लिये जो कैलकुलेशन करना होगा, उसका क्या तरीका होगा। तो इसके लिये भी गवर्नमेंट जिस तरीके से चाहे कर सकती है। मैं तो समझा नहीं कि किसकी बाबत वैसा कहा गया। शायद यह दो बातें कही गईं और अगर कुछ कहा गया तो वह मुझे याद नहीं है और अगर कुछ बातें हों तो वे मुझ से पूछी जा सकती हैं।

चेयरमैन—इस प्रकार का संशोधन पेश होगा, तब आप ऐसा कहियेगा।

श्री प्रभु नारायण सिंह—यदि उसका क्लेरिफिकेशन हो जाय तो शायद हम लोग अपने अमेन्डमेंट्स मूव न करें। ३ (ए) के संबंध में दफा ४ जो है, उसके बारे में है, वह क्या है?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—उसमें मैंने पूरे तौर से पहले ही बयान कर दिया है। सेक्शन ३ जो है उसमें यह लिखा हुआ है कि हर बिक्री पर टैक्स लगाया जाय। ३ (ए) से यह बात क्रायम की गई है। अगर अब जो यह चाहें कि किसी बिक्री पर टैक्स न लगे, तो हम क्या ३ (ए) के जरिये से उसे कम करेंगे और अगर करें तो करने से पहले उसके ऊपर लफ्ज 'प्रिसक्राइब' लिखा हुआ है। प्रिसक्राइब के माने क्या हैं? उसके माने यह होते हैं कि 'prescribed by rules made under this Act' तो जो ऐक्ट है उसके प्रिसक्राइब होने के लिये रूल मैकिंग पावर जो गवर्नमेंट की है, उससे हमें वह करना है। मैंने यह कहा कि अगर हम किसी टैक्स को घटाना चाहें, तो उस वक्त इस चीज की ज़रूरत है। तो रूल उसके लिये अलग बनायें और उसमें दो, तीन महीने का वक्त लगायें, तो उसकी क्या ज़रूरत है। यह बिल्कुल गैर ज़रूरी बात है, इसलिये मैं अल्फाज 'प्रिसक्राइब' निकाल कर, 'स्पैसीफाई' लाना चाहता हूँ। उसका मतलब यह है कि 'बाई नोटिफिकेशन' गवर्नमेंट यह तय करेगी कि यह टैक्स मल्टीपल हो या सिंगल हो, या किसी सेल पर उसको मुकर्रर करे। मसलन एक आदमी है वह किसी के हाथ बेच रहा है और जो खरीदता है वह होलसेलर है। इस तरह से वह आदमी दूसरे आदमी के हाथ बेचता है वह उसे तीसरे के हाथ बेचता है तो किस जगह पर टैक्स उस बिक्री पर लिया जाय? इसके लिये स्पैसीफाई करना होगा।

श्री प्रभु नारायण सिंह—कितना लगेगा? That is the real point.

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—मेरे दोस्त फरमाते हैं कि वह रियल प्वाइंट है। फर्ज कीजिये बिक्री कर जो लगा हुआ है, हर एक प्वाइंट पर ३ पाई है और मैं कल एक प्वाइंट पर ६ पाई कर दूँ तो उससे किसी का कोई नुकसान न होगा, और उसे ज्यादा न देना पड़ेगा।

श्री प्रभु नारायण सिंह—अगर आप ६ पाई कर दें तो?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—अनरीजनेबिलनेस, जो गैर सरकारी आदमी हैं, के साथ है, हर एक आदमी ऐसा नामाकूल काम नहीं करेगा।

चेयरमैन—इस प्रकार के प्रश्नोत्तर इस समय सदन में परस्पर एक दूसरे से नहीं किये जा सकते।

प्रश्न यह है कि सन् १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २

२—संयुक्त प्रान्तीय बिक्री-कर ऐक्ट, सन् १९४८ ई० (जिसे आगे चलकर “मूल अधिनियम” कहा गया है) की धारा २ के खंड (घ) में शब्द “विद्युत् शक्ति और” निकाल दिये जायेंगे।

१९४८ ई० के संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट संख्या १५ की धारा २ का संशोधन।

चेयरमैन—प्रश्न यह है कि खंड २ इस बिल का भाग बना रहे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ३

३—मूल अधिनियम की धारा ३ में:

- (१) वर्तमान प्रतिबन्धात्मक खंड का उपखंड (४) निकाल दिया जायगा,
- (२) वर्तमान प्रतिबन्धात्मक खंड के पश्चात् निम्नलिखित द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खंड के रूप में जोड़ दिया जायगा:

“प्रतिबन्ध यह भी है कि यदि पूर्वगामी प्रतिबन्धात्मक खंड के उपखंड (२) में निर्धारित धनराशि किसी कर निर्धारण वर्ष में कम कर दी जाय तो किसी व्यापारी द्वारा देय कर, जैसा कि ऊपर बताया गया है, की गणना निम्नलिखित रीति से की जायगी, अर्थात्:

(क) जिस अवधि के संबंध में कमी की गई हो उससे पहले की अवधि से संबंधित विक्रय धन पर, इस प्रकार मानो उक्त धनराशि कम नहीं की गई थी, और

(ख) शेष अवधि से सम्बन्धित विक्रय धन पर, इस प्रकार मानो कम की हुई धनराशि (reduced amount) सभी महत्वपूर्ण दिनांकों (material dates) पर ऐसी ही थी।”

१९४८ ई० के संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट संख्या १५ की धारा ३ का संशोधन।

श्री प्रभु नारायण सिंह—मैं खंड ३ में अपना संशोधन पेश करना नहीं चाहता।

श्री कुंवर गुरु नारायण—मैं भी अपना संशोधन इस खंड में पेश नहीं करना चाहता।

चेयरमैन—प्रश्न यह है कि खंड ३ इस बिल का भाग बना रहे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ४

४—मूल अधिनियम की धारा ३-क की उपधारा (१) में शब्द “जो निर्धारित की जाय” के स्थान पर शब्द “जिसे राज्य सरकार निर्दिष्ट करे” रख दिये जायेंगे और उसके संबंध में यह समझा जायगा कि वे सदा से ही उस स्थान पर रखे गये थे।

१९४८ ई० के संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट संख्या १५ की धारा ३-क का संशोधन।

श्री प्रभु नारायण सिंह—मैं यह संशोधन भूव करना चाहता हूँ:

पंक्ति ३ व ४ के शब्द “और उनके संबंध में यह समझा जायगा कि वे सदा से ही उस

[श्री प्रभु नारायण सिंह]

स्थान पर रखे गये थे”, के स्थान पर शब्द “तथा ऐसे निर्देशन के हेतु, मूल अधिनियम की धारा २४ उपधारा (३), (४), व (५) में प्रयुक्त विधि का पालन करना आवश्यक होगा,” रख दिये जायें।

दफ़ा तीन (ए) का प्रश्न है उसका ही संशोधन किया जा रहा है। दफ़ा ३ तो बहुत साफ़ है। इसके संबंध में अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि जहाँ पर मल्टीपुल टेबलें लगने लगे हुये हैं, एक चीज़ पर, कई स्थान पर टेबल देना पड़ता है। उस के द्वारा एक ही जगह पर टेबल लगाने का अधिकार हम सरकार को देते हैं। देखने में यह चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि हमारी सरकार बहुत नेक सरकार है कि चार जगहों पर जो टेबल लगता है, उस को एक ही जगह पर लगाना चाहती है। लेकिन इस एक्सप्लेनेशन से हमारे दिल में जो शंका थी वह साफ़ हो गई। इसके द्वारा सरकार को यह भी हक़ रहेगा कि कितना टेबलेशन किसी चीज़ पर वह लगाये। यह एक वाइडल प्वाइंट है। इस के सिलसिले में जो दफ़ा २४ के मुताबिक़ नियम बनाने की बात है, उसमें जो श्रीरोजिनल ऐक्ट है, उसमें यह साफ़ किया गया है:

“(3) The power to make rules conferred by this section shall be subject to the condition of the rules being made after previous publication for a period of not less than four weeks.

(4) All rules made under this section shall be published in the Gazette and upon such publication shall have effect immediately as if enacted in this Act.

(5) All rules made under this Act shall be laid for not less than seven days before the Legislature as soon as possible after they are made and shall be subject to such modifications as the legislature may make during the session in which they were so laid.”

मैं यह चाहता था कि जो नॉटिफ़िकेशन हैं उनमें लेजिस्लेचर को दफ़ा २४ के मुताबिक़ यानी इसके दफ़ा ३, ४ व ५ में जो हक़ इस लेजिस्लेचर को मिले हुये हैं, इसके अन्दर सुझाव देने के, या अमंडमेंट करने के हक़ लेजिस्लेचर को रहना चाहिये। वह खासतौर से इस वजह से कि देखने में अच्छा लगता है कि कई जगहों पर टेबल लगते हैं, उनको हम एक ही जगह पर कर देंगे। लेकिन जब हम देखते हैं कि दफ़ा ३ में यह है कि ३ पाई से ज्यादा टेबलेशन नहीं हो सकता और इस सेक्शन की दफ़ा ३ (ए) में कहा गया है कि दफ़ा ३ का कोई भी बंधन दफ़ा ३ (ए) पर न रहेगा। इस हालत में यह हो सकता है कि ३ पाई की जगह ६ पाई, १२ पाई या १६ पाई लगा दिया जाये, क्योंकि सरकार को डेवलपमेंट स्कीम्स के लिये रुपये की बहुत जरूरत है। पुराने ऐक्ट के मुताबिक़ इस बात का बंधन रहेगा कि जो रूल्स वह बताये उनका पब्लिकेशन करें उसके बाद सजेशन आयें, और सजेशन के बाद वह टेबुल पर ले किये जायें और यदि लेजिस्लेचर संशोधन करना चाहे तो कर सके और अपनी राय जाहिर कर सके। इसके पास हो जाने पर लेजिस्लेचर को यह हक़ न रहेगा कि वह इस पर विचार कर सके। यह गवर्नमेंट की स्वेच्छा पर है कि वह कितना टेबल लगाये। अभी कम से कम लेजिस्लेचर इस पर विचार तो कर लेता है और बाहर की जनता की राय इससे प्रकट हो जाती है। वह हक़ जिनको दिया गया है माननीय मंत्री जी ने इतनी ख़ुबसूरती से समझाया कि हम लोगों का दिमाग़ परिवर्तित हो गया था। मैं समझता हूँ कि इसके मुताबिक़ जो अमंडमेंट दफ़ा ४ में किया जायेगा, वह भी वाइडल है। इसके उद्देश्य और कारणों में कहा गया है कि इसमें कुछ अन्य साधारण संशोधन करने की आवश्यकता थी। इसको हम बहुत वाइडल समझते हैं। हम इसलिये समझते हैं कि आप कितना लगाना चाहते हैं और कितना लगाने जा रहे हैं, लेजिस्लेचर इस पर विचार करे। इसको भी हम वाइडल समझते हैं। यदि आप की हमदर्दी है, यदि आप तीन महीने नहीं चाहते हैं, तो हमें इन्तहा खुशी होगी। आप चाहते हैं कि दो, तीन महीने का समय न दिया जाय जिससे उसका सिगिल प्वाइंट हो जाय, लेकिन लेजिस्लेचर को हक़ है कि वह उस पर डिसकशन कर सके। इस

हक को आप छीनना चाहते हैं। केवल मानवता के नाम पर आप इतना करना चाहते हैं। जो यह बिल आया है 'वह राउन्ड एबाउट बे' से आया है। उसको देखने से मालूम हुआ कि यह वाइटल संशोधन है। इसलिये हमने समझा कि यह संशोधन बहुत जायज है और सदन इस को मान लेगा।

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद—जो कुछ हमारे मित्र श्री प्रभु नारायण ने कहा है उसमें मुझे एक तथ्य मालूम होता है। माननीय मंत्री महोदय ने बहुत साफ़ तौर से समझाया कि गवर्नमेंट को कोई ऐसी मंशा नहीं है कि किसी तरह से पब्लिक को तकलीफ़ हो। यह गवर्नमेंट इस क्रायदे के जरिये इस टैक्स को वसूल करेगी मगर एक बात मुझे मुश्किल मालूम पड़ रही है कि ऐसा न हो कि शायद गवर्नमेंट ने इस पर विचार किया होगा। जब इस क्लार्ज को बनाया है तो गवर्नमेंट की इससे निरंकुश शक्ति नहीं घट जायेगी। मंत्री महोदय ने फरमाया कि प्रेस्काइब का मतलब यह है कि अग्वार्डेड अथॉरिटी। आपने फरमाया कि इसमें देर लगती है और इसमें असुविधा होती है। गवर्नमेंट नोटिफिकेशन कर देगी और जल्दी की जायेगी कि काम में किसी प्रकार की डिलाई न हो। यह टैक्स बढ़ाने की नियत से गवर्नमेंट नहीं कर रही है। अगर गवर्नमेंट ३ पाई का बारह पाई कर देगी तो क्या होगा। स्पेसीफाई का शब्द रखने से गवर्नमेंट आर-बिट्टरी के रास्ते पर तो नहीं बढ़ जायेगी। यह जानने की बात है। अगर गवर्नमेंट कोई नियम बनावेगी तो वह विधान सभा के सामने आयेगा। स्पेसीफाई करने का गवर्नमेंट को अधिकार होगा। इस शक को दूर करने के लिये मंत्री महोदय थोड़ा फिर इस पर प्रकाश डालें कि क्या गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है। इस क्लार्ज के द्वारा तीन पाई की सोलह पाई कर हो जायेगा। स्पेसीफाई करने से वह साफ़ हो सकता है। अगर आप जैसा कहते हैं वैसा है तो इसको स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं हो सकती।

***श्री राजा राम शास्त्री (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)**—माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री प्रभु नारायण जी ने जो संशोधन पेश किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूँ। मैं इस बात को शुरू में ही स्पष्ट कर देता हूँ कि इस कानून के संबंध में ऐसे मौके पर बहस करते हुये जो दलील माननीय मंत्री जी ने दी वास्तव में इसमें जितनी जानकारी होनी चाहिये और जितना अध्ययन होना चाहिये था उतना हमारा अध्ययन नहीं हुआ। लेकिन जो शंकायें इस विधेयक के विषय में और कई बातों से उत्पन्न हुईं और जिन शंकाओं को श्री प्रभु नारायण जी ने पेश किया, उनको मैं जहाँ तक उनमें त्रुटियाँ हैं साफ़ कर देना चाहता हूँ। मुझे प्रतीत होता है कि इधर कुछ समय से गवर्नमेंट को चूँकि रुपये की जरूरत है, उसके लिये कुछ बिलस भी सदन में आये और नये-नये टैक्स लगाये गये या पुरानों को बढ़ाया गया उससे हमारे दिल में ऐसा ख्याल हुआ, हो सकता है वह ख्याल गलत हो, चूँकि इस वक्त गवर्नमेंट को टैक्स की मीनिया हो रही है, इसलिये वह सेल्स टैक्स में जो सुधार कर रहे हैं वह कहीं उस वकालत प्वाइन्ट आफ व्यू से तो नहीं समझाते हैं कि अन्दर ही अन्दर वह टैक्स लगा लें और उसे बढ़ा लें। जब यह ख्याल होता है तब इस विधेयक को हम दूसरी ही नज़र से देखने लगते हैं। मल्टीप्लाइन्ट के बजाय सिंगल प्वाइन्ट करने का यह अधिकार, अगर गवर्नमेंट चाहती है कि उसको दे दिया जाय तो क्या इस अधिकार के देने से अभी तक जो जनता पर बोझ था और जगह-जगह पर जो इस टैक्स के खिलाफ़ आवाज़ उठती थी, उस बोझ में कुछ कमी पड़ती है। अगर कमी पड़ती है तो बड़ी खुशी है और हर एक सदस्य इसका स्वागत करेगा। लेकिन जैसा मैंने कहा अगर इस तरह की सुन्दर-सुन्दर बातों के अन्दर कुछ छिपी बातें हैं यानी जनता का वह बोझ कुछ कम नहीं होता तो सदन के सेम्बर भले ही संतुष्ट हो जाय और सरकार बघाई की पात्र हो जाय और गवर्नमेंट के खजाने में रुपये पहुँच जाय, मगर जो जनता के चिंता की चीज है वह तो वैसी ही बनी रही। यह मैं क्यों कहता हूँ। मैंने पहली अक्टूबर के समाचार-पत्रों में पढ़ा था कि सरकार ने नये

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री राजा राम शास्त्री]

टैक्स और बढ़ा दिये हैं और पुराने में भी इजाफा कर दिया है, कुछ नई चीजों पर भी टैक्स लग रहे हैं। ऐसे मौके पर हम लोगों को शंका हुई कि कहीं दूसरी दफा हुकूमत जो पहले दियासलाई, बीड़ी, सिगरेट आदि चीजों पर जो कि जनता के रोज के इस्तेमाल की चीजें हैं, टैक्स लगाये और फिर उसे बढ़ा दे तो आज कहीं यह सुन्दर-सुन्दर बातें कह कर के फिर वह टैक्स को न बढ़ा दें और दियासलाई का टैक्स भी साथ ही साथ पास न हो जाय।

दूसरी दफा लेजिस्लेचर ने पास कर दिया कि एक रुपये पर एक पैसा सेल्स टैक्स आप लगा सकते हैं, लेकिन ख्याल होता है, जैसा कि आप का ख्याल है कि दूसरे सूबों में काफी टैक्स है, महज इसी सूबे में कम से कम टैक्स है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि चूंकि दूसरे सूबे में सेल्स टैक्स ज्यादा है और हुकूमत की तबियत आई है कि यहां भी ज्यादा हो, यहां भी मद्रास की तरह ही सेल्स टैक्स हो, और उस बात को आप सीधे न कह कर इस तरह से कर रहे हैं। यह मेरे दिल में शंका है। जो शंकायें हैं वह मैं आपके सामने रखे देता हूं। इस ऐक्ट की दफा ३ से यह था कि ३ पाई लिया जायगा लेकिन अब जो दूसरी दफा आ रही है उसमें यह लिखा है कि हम उस टैक्स को बढ़ा भी सकते हैं। तो यह बहुत वाइटल प्वाइंट आ गया है। लेजिस्लेचर ने जो हुकूमत के हाथ बांध दिये थे कि इससे ज्यादा टैक्स न लिया जाय तो इस तरह करने से उसके हाथ खुले जा रहे हैं और हम बढ़ाई देते जा रहे हैं। माननीय मंत्री जी ने मसला ही इस तरह से पेश किया कि वह इस बात का अधिकार चाहते हैं कि जहां उनको पहले एक पाई टैक्स लगाने का अधिकार था वहां २ पाई और ३ पाई का अधिकार मिल जाय। मैं माननीय मंत्री जी की इसके लिये प्रशंसा हमेशा ही किया करता हूं। सदन में मैंने कई बार उनकी प्रशंसा इसके लिये की है कि वह इस तरह से एक चीज को रखते हैं कि हमारा गला भी कटता जाता है और हम बढ़ाई भी देते चले जाते हैं। तो मुझे इस बात की शंका है।

जब आगे दफा ८ आयेंगी तो उसमें लिखा है कि हुकूमत ने जो कारनामे पिछले समय में किया है वह इसको रू से सब सही हैं। इस सब का मतलब क्या निकलता है। जब मेरी निगाह पहली अक्टूबर पर जाती है जिसमें दियासलाई वगैरह पर टैक्स बढ़ा दिया और २५ दिन तक न सके, कि लेजिस्लेचर के सामने यह चीज आजाती तो इससे तो यही मालूम होता है कि दफा ८ की रू से आप हर समय अपना ऐक्शन लिगलाइज करना चाहते हैं। २६, २७ अक्टूबर से यह सेशन होने वाला था तो मेरी समझ में नहीं आता कि पहली अक्टूबर से ही क्यों टैक्स बढ़ा दिया गया। पहले तो आपने काम शुरू कर दिया पहली अक्टूबर से और अब उसको आप लिगलाइज करना चाहते हैं हमसे। पहली अक्टूबर को अगर हुकूमत रुक गई होती और कहती कि फलों फलों काम हम करना चाहते हैं तो भवन को भीका होता और वह अपनी राय देता कि किस पर लगाना चाहिये टैक्स और किस पर नहीं, अब तो मजबूरी है। पहली अक्टूबर से तो आपने लागू कर दिया इसलिये कि आप समझते हैं कि जो कुछ आप कहेंगे या करेंगे वह पास तो हो ही जायेगा। हुकूमत समझती है कि चाहे जहां जितनी अन्धेरगर्दी कर ले, वह सब पास हो ही जायेगी। इसलिये मैं माननीय मंत्री से कहूंगा कि पास तो वही होगा जो आप चाहेंगे। ऐसी दशा में जो कम से कम असली मंशा है वह तो बतला दिया जाये ताकि हम भी समझें कि आपका मतलब क्या है? इसीलिये मेरे जो दो तीन प्रश्न हैं वह बिल्कुल स्पष्ट हैं। पहला तो यह है कि क्या सचमुच इस दफा में जो सारा संशोधन लाया गया है वह यह है यानी उसकी मंशा यह है कि जो टैक्स पहिले से लगा है उसकी रकम को कुछ बढ़ा दिया जाये। दूसरी चीज यह है कि सचमुच यह जो ऐक्ट है जिसमें आपके हाथ बंधे हुये हैं कि यह जो एक पैसा लगा हुआ है उसको आप बढ़ा नहीं सकते हैं, तो आप इस संशोधन के द्वारा ऐसी ताकत तो नहीं ले रहे हैं कि ओरिजिनल ऐक्ट को तोड़ कर आप अपनी ताकत

को बढ़ा रहे हों और इसके द्वारा आपको टैक्स बढ़ाने का अख्तियार मिल रहा हो ? तीसरी चीज यह है कि पहिली अक्टूबर से जो कुछ भी आपने किया है उस सबको आप लीगलाइज करना चाहते हैं क्या ? आपको मंशा यह तो नहीं है, कि नये ढंग से कानूनी गोरख-धंधों में डाल कर, आप टैक्स तो नहीं बढ़ाना चाहते हैं। सिगिल टैक्स के नाम पर कहीं आप टैक्स तो नहीं बढ़ाना चाहते हैं ? और अगर आपका इन्नेसेन्ट में इरादा है तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई बात कहने की नहीं है और इसी लिये पहिले हमने कुछ कहा भी नहीं है। मैं आशा करता हूँ कि माननीय मंत्री जी इस पर रोशनी डालें और इन बातों को स्पष्ट कर दें।

श्री इन्द्र सिंह नयाल—अध्यक्ष महोदय, इसमें जो संशोधन दफा ४ विधेयक में रक्खा है, उसका मैं विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूँ। कारण कि जो मूल ऐक्ट दफा ४ में है उसके ऐसे माने नहीं लगाये जा सकते हैं जैसे कि राजा राम जी और प्रभु नारायण जी लगाते हैं। यह इस प्रकार है :

“Sec. 3-A. Notwithstanding anything contained in Section 3, the Provincial Government may, by notification in the official Gazette, declare that the proceeds of sale of any goods or class of goods shall not be included in the turnover of any dealer except at such single point in the series of sales by successive dealers as may be prescribed.”

टैक्स एक ही स्थान में लगेगा यह नोटिफिकेशन के द्वारा सरकार उपरोक्त धारा के अनुसार पहिले से ही कर सकती थी, केवल किस स्थान में यह टैक्स लगेगा वह इस तरमीम के द्वारा नियमों के बजाय नोटिफिकेशन द्वारा अब हो सकेगा। यह अधिकार सरकार के मूल ऐक्ट में दिये हुये हैं कि एक ही स्थान में टैक्स लगाने पर वह तीन पाई से टैक्स बढ़ा कर चार पाई कर देवे। अतएव श्री राजा राम जी का व्यक्तव्य इस विधेयक में निर्मूल है। टैक्स बढ़ाने या घटाने से इस तरमीम में कोई अन्तर नहीं आता है।

श्री हाकिम मुहम्मद इब्राहीम—जनाबवाला, मुझ से गुलती हुई कि मैं इस बात को पहले नहीं बतला सका। अगर मैं उसको कह देता तो शायद मेरे दोस्त राजा राम जी को तक्रलीफ न करनी पड़ती। शिकायत जो उन्होंने की तो यहां हिन्दुस्तान में हुस्न और इश्क के हिस्से में बहुत बदगुमानी होती रही है। शायरों ने इसका बहुत सज्जिकारा किया है। वह बदगुमानी जो मेरे दोस्त ने यहां जाहिर करवायी उनके लिये शायद कोई छप्तर इस वक्त नहीं था कि उसकी बिना पर वह बदगुमानी की जाय। एक जवाब उसका साफ यह है कि इस रू से कोई अख्तियार गवर्नमेंट नहीं बढ़ा रही है। सिगिल प्वाइंट टैक्स लगाने का जो उसूल है वह ऐक्ट में खुद मुक़र्रर कर दिया गया है। यह अख्तियार तो दिया गया है कि इतना लगा सकते हैं। जरा आप इस दफा को पढ़ें तो मालूम हो जायेगा। जिस दफा में हम ने अमेंडमेंट किया है उसको पढ़ा जाय तो यह साफ़ हो जायेगा। मैंने उसको पहले नहीं कहा क्योंकि यह बात मेरे ख्याल में नहीं थी। जो टैक्स लगता है चाहे सिगल प्वाइंट पर हो या मस्टीपिल हो वह तो लेजिस्लेचर मुक़र्रर करता है और उस में चीज को स्पेसिफाई करता है। यह तो लिखा हुआ है, मैं कोई और पावर नहीं ले रहा हूँ। नोटिफिकेशन के लिये पहले भी कह रखा है और अब भी कह रहे हैं। इससे लिमिट आगे नहीं जा सकती। इस के बारे में पहले भी कह चुका हूँ, आप मेरी स्पीच को देख सकते हैं, वह छपी होगी। किसी चोर दरवाजे से डाका नहीं डाल रहा हूँ। जितना गवर्नमेंट को लेजिस्लेचर ने अख्तियार दे रखा है, उसको गवर्नमेंट इस्तेमाल करती है। जहाँ नये अख्तियार लेने की जरूरत है वहाँ उस अख्तियार की बात कही जाती है। मैं कोई नया अख्तियार नहीं मांग रहा हूँ। वह बदगुमानी नहीं होनी चाहिये जो मेरे दोस्त कर रहे हैं। डाक्टर साहब प्रश्न कर रहे थे, मैं शायद इस बात को भूल गया, लेकिन मक़सद उसका भी यही था। डाक्टर साहब की नज़र में वह हो या नहीं। वह लिमिट तो है ही, उसके वियोन्ड गवर्नमेंट नहीं जा सकती। यों तो कह दिया

[श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम]

जाता है कि सरकार मेजरिटी में है, वह जोर से पास कर सकती है, तो यह हर बात में लागू होता जायेगा। जो रीजनेबिल बात होती है उसके लिये लेजिस्लेचर एक लिमिट लगाता है, उसके ऊपर मैं जा नहीं सकता। मेरे नजदीक इस्मीनान होना चाहिये कि मैं जो कर रहा हूँ वह कानून के मुताबिक कर रहा हूँ।

श्री कन्हैया लाल गुप्त—इसको जो रिट्रासपेक्टिव इफ़ेक्ट दे रहे हैं, उसकी ज़रूरत क्यों हुई?

श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम—नोटिफिकेशन की वजह से हुई है। वह किस्सा मैंने आपको सुना दिया है।

चेयरमैन—प्रश्न यह है कि पंक्ति ३ व ४ के शब्द “और उनके संबंध में यह समझा जायगा कि वे सदा से ही उस स्थान पर रखे गये थे” के स्थान पर शब्द “तथा ऐसे निर्देशन के हेतु मूल अधिनियम की धारा २४ की उपधारा (३), (४) व (५) में प्रयुक्त विधि का पालन करना आवश्यक होगा” रख दिये जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

चेयरमैन—प्रश्न यह है कि खंड ४ बिल का भाग बना रहे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ५—द

५—मूल अधिनियम की धारा ४ की उपधारा (१) के खंड (क) में शब्द “औद्योगिक प्रयोजनों के लिये बिजली” निकाल दिये जायेंगे।

१९४८ ई०
के संयुक्त
प्रांतीय ऐक्ट
संख्या १५ की
धारा ४ का
संशोधन।

६—मूल अधिनियम की धारा २३ की उपधारा (२) में—

(१) खंड (५) में पूर्ण विराम (Full-stop) के स्थान पर अर्ध विराम (Comma) रख दिया जायगा और उसके पश्चात् शब्द “या” जोड़ दिया जायगा :

(२) खंड (५) के बाद एक नये खंड के रूप में निम्नलिखित जोड़ दिया जायगा:—

“(६) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा कोई कर लगाय जाने या उसके द्वारा लगाये गये किसी कर की उगाही के लिये उसके किसी अधिकारी को उनका प्रकट किया जाना आवश्यक हो।”

१९४८ ई०
के संयुक्त
प्रांतीय ऐक्ट
संख्या १५ की
धारा २५ का
निकाला
जाना।

७—मूल अधिनियम की धारा २५ निकाल दी जायगी।

८—इस अधिनियम के प्रचलित होने के पूर्व मूल अधिनियम के उपबंधों के अनुसार और उनके अधीन किया गया प्रत्येक प्रख्यापन (declaration) या कर-निर्धारण (assessment) लगाया गया कर, की गई कार्यवाही या व्यवहार अथवा प्रयुक्त क्षेत्राधिकार (jurisdiction) के संबंध में यह समझा जायगा कि वह विधिवत् और वैध (good and valid in law) है, मानो वारा ४ द्वारा संशोधित मूल अधिनियम सब महत्वपूर्ण दिनांकों (material dates) पर प्रचलित था।

चेयरमैन—प्रश्न यह कि खंड ५, ६, ७ और ८ इस बिल का भाग बने रहें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

प्रस्तावना और खंड १

समय समय पर संशोधित संयुक्त प्रांतीय बिक्री-कर ऐक्ट, सन् १९४८ ई० में आगे चलकर दिये हुये प्रयोजनों के लिये और संशोधन करना आवश्यक है ;

अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

१—(१) इस अधिनियम का नाम “उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) अधिनियम, १९५२” होगा।

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

(२) यह उस दिनांक से प्रचलित होगा जिसे राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा निश्चित करे।

चेयरमैन—प्रश्न यह है कि प्रिम्बल और खंड १ इस बिल का भाग बने रहें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम—जनाबवाला, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सन् १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक को पारित किया जाय।

चेयरमैन—प्रश्न यह है कि सन् १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक को पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश फायर सर्विस (संशोधन) विधेयक

श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम—जनाबवाला, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सन् १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश फायर सर्विस (संशोधन) विधेयक पर विचार किया जाय।

इस बिल की कापी सब मेम्बरों को मिल गई होगी, उनको मालूम है कि यह ऐक्ट सन् १९४४ ई० में जारी किया गया था। उस वक्त इलाहाबाद और कानपुर में कुछ ओहदे का जिक्र नहीं किया गया था इसी वजह से इस बिल को इस वक्त लाने को जरूरत पड़ी है। इसके प्लान २ में जो दिया हुआ है इससे दो बातें होंगी, एक तो यह कि ओहदों को लीगल समझा जायेगा और दूसरे उनको इन्स्पेक्शन की पावर दी जायेगी। इसमें कोई खास बात नहीं है, इसलिये मैं समझता हूं कि इसमें किसी को कोई एतराज नहीं होगा और सदन इस प्रस्ताव को स्वीकार करेगा।

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बिल जो इस समय इस सदन के सामने पेश है, मैं समझता हूं कि इस पर किसी भी सदस्य को कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन एक बात मैं सरकार से जनाना चाहता हूं। इसके उद्देश्य और कारणों में दिया हुआ है :

[डाक्टर ईश्वरी प्रसाद]

"It is now proposed to amend the Act in order to give these officers, now to be designated as Chief Fire Officers, definite legal status and powers, both administrative and executive, in order that they may be authorised to act under the Act and the rules made thereunder."

कुछ आफिसर्स ऐसे हैं जिनके लीगल स्टेटस और पावर्स को निश्चित करता है इस ऐक्ट के द्वारा, तो क्या यह आफिसर्स नियुक्त हो गये हैं।

श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम—जी हां, अप्वाइन्ट हो गये हैं और वह गवर्नमेंट के जमाने से चले आ रहे हैं और यह पहले से ही लखनऊ, इलाहाबाद और कानपुर में हैं।

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद—अगर यह आफिसर्स अप्वाइन्ट हो गये हैं, तो क्या गवर्नमेंट को मालूम है कि वह किस सन् में अप्वाइन्ट हुये हैं?

श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम—यह तो मैं नहीं बता सकता हूं कि किस सन् में इनका अप्वाइन्टमेंट हुआ था।

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद—क्या यह पब्लिक सर्विस कमिशन द्वारा अप्वाइन्ट हुये थे, या गवर्नमेंट ने इनको डाइरेक्ट अप्वाइन्ट किया है?

श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम—मुझे इसका भी कुछ पता नहीं है।

I have no information whether this service is subject to the approval of the Public Service Commission and as far as the appointment of these officers is concerned, I cannot say definitely without referring to the State records, when they were appointed. But they are working already and is simply because that legal status has to be conferred on them through the enactment of this amendment.

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद—जो कुछ माननीय मंत्री जी ने कहा है उसको सुनकर हमारे लिये कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि हम इस बिल को पास करें। क्योंकि वह आफिसर जिनका कि इसमें उल्लेख है, पहले से ही काम कर रहे हैं और पहले से ही सरकार की सर्विस में हैं।

*श्री कन्हैया लाल गुप्त—माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है केवल अभी जो सवाल डाक्टर साहब ने किये हैं और जिसकी बाबत माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि वह निश्चित सूचना देने में असमर्थ हैं, मैं समझता हूं कि सदन की जानकारी के लिये यह बहुत ही जरूरी है, इसलिये माननीय मंत्री जी इस विषय में सूचना हासिल कर लें कि आया जो तीन आफिसर्स लखनऊ, कानपुर और इलाहाबाद में हैं वह पब्लिक सर्विस कमिशन के मार्फत अप्वाइन्ट हुये हैं या गवर्नमेंट ने उनको डाइरेक्टली अप्वाइन्ट कर लिया है, और क्या-क्या उनकी क्वालीफिकेशन्स हैं। जब तक यह बातें निश्चित रूप से सदन को नहीं मालूम हो जाती हैं तब तक यह सदन इस बिल के ऊपर अपनी ओपीनियन दे सके, यह भूविज्ञान की बात होगी। मैं समझता हूं कि माननीय गृह मंत्री द्वारा यह बिल पेश किये जाने का था शायद वह हाजिर नहीं हैं इसलिये यह सूचना मंत्री महोदय को, जो इस बिल को पेश कर रहे हैं, पूरी तरह से मालूम नहीं है। इसलिये मैं आपके द्वारा यह दरखास्त करूंगा कि अच्छा हो कि हाउस एडजार्न हो जाने के बाद, माननीय गृह मंत्री उपस्थित हों और तब ही इसके बाद इस बिल को लिया जाय। इस सूचना के प्राप्त किये जाने के बिना ही इस बिल पर बहस करना मैं समझता हूं कि गलत होगा।

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

श्री सरदार संतोष सिंह (नाम निर्देशित) — क्या मेम्बर साहब यह बता सकते हैं कि जो फायर आफिसर्स हैं, उनके लिये किसी प्रकार की क्वालिफिकेशन्स की ज़रूरत है और अगर है, तो उनकी कितनी क्वालिफिकेशन्स होनी चाहिये ?

चेयरमैन — कोई सदस्य किसी दूसरे सदस्य से प्रश्न नहीं पूछ सकता। सदस्यों को हक है कि वह अपनी राय किसी बिल के ऊपर चेयर को दे सकते हैं लेकिन प्रश्न दूसरे सदस्य से नहीं पूछ सकते।

श्री सरदार संतोष सिंह — मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके ही द्वारा पूछ रहा हूँ मेम्बर साहब से कि क्या उनको यह मालूम है कि ऐसे आफिसर्स के लिये कितनी क्वालिफिकेशन्स की ज़रूरत है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम — कन्हैया लाल साहब ने यह बात कही है कि पहले उनको वह इत्तिला मालूम हो जाय और फिर बिल के ऊपर विचार किया जाय, तो मैं यह कहता हूँ कि अगर मेम्बर साहब इसके ख्वाहिस्तगार हैं, तो मैं उन्हें वैसे ही बता सकता हूँ। अगर हाउस की राय हो कि जब तक उन्हें यह मालूम न हो जाय कि वह पब्लिक सर्विस कमिशन से अप्वाइन्ट हुये हैं या नहीं हुये हैं और वह क्वालिफाइड हैं या नहीं, तब तक विचार नहीं होगा, तो मैं उन्हें सरसरी तौर से बता देना चाहता हूँ कि अगर यह अप्वाइन्मेंट अभी हुआ होता, तब तो पब्लिक सर्विस कमिशन का सवाल पैदा हो सकता था, लेकिन जबकि वे पहले से ही काम कर रहे हैं तो उस हालत में यह प्रश्न ही पैदा नहीं होता है और फिर भी अगर हाउस की यह राय हो कि इस इत्तिला की वजह से इस ला को रोका जाय और अगर इसको इस वक्त रोकना ज़रूरी मालूम होता है, तो मैं यही कह सकता हूँ कि हाउस फिर बैठे और फिर जो कुछ भी सजेशन्स होंगे या जो कुछ भी वह पूछना चाहते हों, वह सब उनकी मालूम हो जायेगा।

श्री कन्हैया लाल गुप्त — On a point of information, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। मुझे कोई भी एतराज इस बिल के सिलसिले में नहीं है लेकिन जब कोई सूचना मंत्री महोदय से पूछी गई है और यह ठीक तरह से नहीं बता सके, तो मैंने यही ज़रूरी समझा कि आपके द्वारा सरकार से अर्ज करूँ कि जो कुछ सवाल डाक्टर साहब ने उठाये हैं, उनका जवाब इस सदन को निश्चित रूप से मिल सके। जब यह जवाब मिल जायगा तो उसके बाद इसके संबंध में जो कुछ हमें कहना होगा, वह हम कहने की कोशिश करेंगे।

चेयरमैन — यह तरीका बहुत गलत हो रहा है कि बीच २ में एक सवाल पूछा जाय और फिर उसका जवाब दिया जाय और फिर इस तरह से दूसरा सवाल पूछा जाय और उसका जवाब दिया जाय। यह हमारे सदन का तरीका नहीं है। जो मसला पेश है हर सदस्य को यह अधिकार है कि उस पर वह अपनी राय दे और इस तरह से जब सब सदस्य अपनी राय दे देते हैं तब उन सबका जवाब मंत्री द्वारा दिया जाता है। जो कुछ सवाल यहां पेश है उस पर सदस्यों को अपनी राय देनी चाहिये और मंत्री महोदय तब उसका जवाब देंगे। यह भी नहीं हो सकता है कि जब तक उनका जवाब नहीं दिया जा सकता है, तब तक उस बिल पर यहां विचार न किया जाय और इस तरह से विधेयक पर बहस को रोका नहीं जा सकता। इस प्रस्ताव के बारे में जो कुछ कहना हो वह कहा जाय।

श्री कन्हैया लाल गुप्त — मुझे मेम्बरों के राइट्स ऐन्ड प्रिविलिजेज के बारे में कहना है। गवर्नमेंट कुछ इनफ़ार्मेशन नहीं रखती है, तो मेम्बरों को यह कहने का हक है कि उनके पास यह इनफ़ार्मेशन नहीं है जब कि उन्हें इसकी ज़रूरत है।

चेयरमैन — इस वक्त राइट्स ऐन्ड प्रिविलिजेज (rights and privileges) का सवाल नहीं है। मंत्री महोदय सेक्रेटेरियट के हर डिपार्टमेंट की बातें हर वक्त अपने विभाग में तो नहीं रख सकते हैं। हमारे नियमों के अनुसार किसी विधेयक के विषय में किसी

[चेयरमैन]

सूचना के न मिलने तक उस पर विचार स्थगित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार विचार स्थगित करने के लिये तो सदन में प्रस्ताव करने की जरूरत है। इस प्रकार का प्रस्ताव हर वक्त करने का अधिकार सदस्यों को है।

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद—आपने जो फरमाया वह बिल्कुल वृष्ट है, लेकिन यह गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि मिनिस्टर इनचार्ज जो भी बिल यहां पेश करता है, उसको पूरी इन्फार्मेशन रहनी चाहिये। इस वक्त तो वह मिनिस्टर हैं नहीं लेकिन फिर भी उनको इससे संबंधित सब कागजात यहां भेज देना चाहिये था।

The Minister Incharge of the subject should provide this information. We are asked to define the legal status and the duties and functions of the fire service officers. We have the right to know what their qualifications are ? Why they were appointed and how they were appointed ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—मैं आपकी इजाजत से एक बात यह अर्ज करूं कि जब मेम्बरों को कई रोज से मालूम था कि यह बिल आने वाला है, तो इस तरह की इन्फार्मेशन कई दिन पहले भी मांगी जा सकती थी।

श्री कन्हैया लाल गुप्त—किस तरह से मांगी जाती ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—लिख करके, इस तरह से एक बहुत गलत डेडिशन कायम हो जाता है कि एक सवाल पूछा जाय और फिर उसका जवाब दिया जाय और जब तक सवाल का जवाब नहीं मिलता है, तब तक दूसरी बात हो न हो सके।

चेयरमैन—I cannot allow making of questions and answers across the floor.

श्री परमात्मानन्द सिंह—क्या मैं दो लफ्ज कह सकता हूं ?

चेयरमैन—आप बिल के बारे में बोलिये।

श्री प्रेम चन्द शर्मा (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)—माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार ने जो यह फायर सर्विस (अमेन्डमेंट) बिल रखा है, उसमें सिर्फ यह है कि जो आलरेडी आफिसर्स काम कर रहे हैं उनका स्टेट्स लीगलाइज किया जाय और उनको अधिकार दिये जाय कि वह मकानों में जा सकें और इन्ट्री लोगल हो तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिसके लिये यह जरूरी हो कि वह पब्लिक सर्विस कमिशन से पास है या नहीं मैं सप्रसन्नता हूँ कि यह सबजेक्ट बिल का नहीं है। इसलिये मैं इसका समर्थन करता हूँ।

चेयरमैन—प्रश्न यह है कि सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश फायर सर्विस (संशोधन) विधेयक पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जनाबवाला, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि सन् १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश फायर सर्विस (संशोधन) विधेयक को पारित किया जाय।

चेयरमैन—प्रश्न यह है कि सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश फायर सर्विस (संशोधन) विधेयक को पारित * किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कोर्ट के लिये दो सदस्यों के चुनाव का प्रस्ताव

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—Sir, I beg to move that the Legislative Council do elect in such manner and on such date as the Chairman may direct, two members to serve on the Court of the Allahabad University.

*बिल के लिये देखिये नयी 'ख' पृष्ठ १३६-१४० पर।

चेयरमैन—The question is that the Legislative Council do elect in such manner and on such date as the Chairman may direct, two members to serve on the Court of the Allahabad University.

(The question was put and agreed to)

चेयरमैन—क्या माननीय मंत्री जी बता सकेंगे कि सदन की अगली बैठक कब होगी ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—हम लोग तीसरी तारीख से बैठेंगे ।

चेयरमैन—माननीय सदस्य नामीनेशन ४ तारीख को १२ बजे तक सेक्रेटरी को दें ।

सदन का कार्यक्रम

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जो यूनिवर्सिटीज (अमेंडमेंट) बिल इंट्रोड्यूस हो चुका है, वह ३ तारीख को लिया जायेगा ।

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद—श्रीमान् जी, कल छुट्टी और उसके बाद १ और २ तारीख को छुट्टी है तो ३ दिन रहना पड़ेगा, मैं समझता हूँ कि ६, ७ या ८ तारीख से लिया जाय, तो क्या हर्ज होगा ।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—५ तारीख से यहाँ काम शुरू होने वाला है और हम लोग उसमें लगे होंगे, इसलिये हम बैठ नहीं सकेंगे और इसलिये हमने ३ तारीख रखी है ।

चेयरमैन—इस समय एक ही बिल है । तीसरी चौथी को शायद समाप्त हो जायगा ।

श्री कुंवर गुरु नारायण—मैंने यह दरिदासता करना चाहा था कि प्रेस में यह न्यूज है कि अगर यूनिवर्सिटी का एक ऐक्ट है गवर्नमेंट उसको अमेंड करना चाहती है उसके लिये गवर्नर साहब आर्डिनेंस ईशू करने जा रहे हैं । चूँकि कौंसिल आजकल इन-सेशन है, तो मैं समझता हूँ बजाय इसके आर्डिनेंस ईशू किया जाय इस विषय में कौंसिल को कन्सल्ट किया जाय । मैं जानना चाहता हूँ कि इसमें गवर्नमेंट को क्या आपत्ति हो सकती है ।

श्री राजा राम शास्त्री—मैंने कुछ शार्ट नोटिस क्वेश्चन इसी विषय पर गवर्नमेंट के पास भेजे थे । गवर्नमेंट की तरफ से जो जवाब आया है, मैं पढ़े देता हूँ । वह इस प्रकार है :

The Education Minister regrets that he is unable to answer short notice questions as the above matter is being confidentially considered by Government at this stage."

चेयरमैन—अब यह है कि समाचार-पत्रों में जो कुछ छपता है उसके बारे में सदन में इस तरह से प्रश्न नहीं किये जाते जैसा कि राजा राम जी ने कहा कि उन्होंने अल्पसूचक प्रश्न इसके बारे में दिये थे । अल्पसूचक प्रश्नों के लिये नियमों के अन्तर्गत सरकार को अधिकार है कि अगर जवाब दे सके तो दे और न देना चाहे तो न दे । इन प्रश्नों का उत्तर न दिये जाने पर अगर आप चाहें तो एडजर्नमेंट मोशन मूव करें या और कोई तरीका अख्तियार करें ।

श्री कुंवर गुरु नारायण—श्रीमान् अब पोजीशन बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि यह कांफिडेंशियल नेचर का है ।

चेयरमैन—इस पर इस समय बहस नहीं की जा सकती ।

कौंसिल तारीख ३ को ११ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है ।

(कौंसिल की बैठक दिन के १ बजेकर ५ मिनट पर ३ नवम्बर, १९५३, को दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गई ।)

लखनऊ,

३० अक्टूबर, १९५२ ।

श्यामलाल गोविल,
सेक्रेटरी, लेजिस्लेटिव कौंसिल,
उत्तर प्रदेश ।

नत्थी 'क'

माननीय मुख्य मंत्री महोदय के द्वारा पंचायत राज निरीक्षकों के शिक्षण शिविर में दिये गये दीक्षान्त भाषण का उद्धरण:—

“मैं आशा करता हूँ कि आप में से हर एक सेवाभाव से प्रेरित हो कर अपने कर्तव्यों को पूरा करेंगे और सरकार से तब आप आशा कर सकते हैं कि आप अगर अच्छी तरह से सेवाभाव से और निस्वार्थ भाव से काम करेंगे तो आप में से जो अच्छा काम करने वाले हैं उनकी उन्नति और तरह से स्वयं ही होगी। वह तहसीलदार भी शायद हो सकेंगे और डिप्टी कलेक्टर भी हो सकेंगे। ऊंची ऊंची पदवियों को पा सकेंगे, यदि वे अपने कार्य से इस बात को सिद्ध कर देंगे कि वे सेवाभाव से प्रेरित हो कर अपनी परवाह न कर के जनता के हित में अपने को खपाने की शक्ति रखते हैं। अपनी उन्नति का मार्ग भी यही होता कि यदि आदमी अपने स्वार्थ की परवाह न करे तो स्वयं उसका स्वार्थ सिद्ध हो जाता है।”

नत्थी 'ख'

उत्तर प्रदेश फायर सर्विस (संशोधन) विधेयक, १९५२

कुछ प्रयोजनों के निमित्त, जो यहां पर आगे चल कर प्रतीत होंगे,
यू० पी० फायर सर्विस ऐक्ट, १९४४, में संशोधन करने के निमित्त

यू० पी०
ऐक्ट ३,
१९४४।

विधेयक

कुछ प्रयोजनों के निमित्त, जो यहां पर आगे चल कर प्रतीत होंगे, यू० पी०
फायर सर्विस ऐक्ट, १९४४ में संशोधन करना आवश्यक है, अतएव निम्नलिखित
अधिनियम बनाया जाता है।

यू० पी०
ऐक्ट ३
१९४४।

१—(१) इस अधिनियम का नाम उत्तर प्रदेश फायर सर्विस (संशोधन)
अधिनियम, १९५२ होगा।

संक्षिप्त
नाम तथा
प्रारम्भ।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

२—यू० पी० फायर सर्विस ऐक्ट, १९४४ (जिसे यहां पर आगे चल
कर मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा ४ में शब्द:

यू० पी०
ऐक्ट ३,
१९४४ की
धारा ४ का
संशोधन।

“(1) Fire Station Officers, (2) Fire Station Second Officers,
(3) Leading Firemen, and (4) Drivers and Firemen”

के स्थान पर निम्नलिखित रखे जायें:

- “(1) Chief Fire Officers,
- (2) Fire Station Officers,
- (3) Fire Station Second Officers,
- (4) Leading Firemen and Drivers, and
- (5) Firemen”.

३—मूल अधिनियम की वर्तमान धारा ५ के स्थान पर निम्नलिखित
रख दिया जायः—

यू० पी०
ऐक्ट ३
१९४४ की
धारा ५ का
संशोधन।

“Superin- 5. (1) The superintendence and control of the U. P. Fire Service
tendence, Powers shall vest in the Inspector General of Police, and subject
and Functions, to the general control of the Inspector General of Police, and
the District Superintendent of Police within the area of his
jurisdiction.

- (2) The State Government may appoint such officers as it may
think fit to assist the Inspector General of Police and the
Superintendent of Police in the discharge of their duties.
- (3) Subject to the provisions of sub-sections(1) and (2), the
Chief Fire Officer, Fire Station Officers and Fire Station
Second Officers shall exercise such administrative powers and
perform such administrative functions as may be prescribed”.

४—मूल अधिनियम की धारा १९ के बाद निम्नलिखित नई धारा १९-ए के
रूप में रख दी जायः

यू० पी० ऐक्ट
३, १९४४ में
नई धारा १९-
ए का रक्खा
जाना।

Power to 19-A. (1) The Chief Fire Officer or any officer authorized by the
Search Premises Superintendent of Police in this behalf may enter and inspect
any land, premises or building for the purpose of determining

whether the precautions against fire required to be taken on such land, premises and buildings under any law for the time being in force have been so taken.

- (2) If any person voluntarily obstructs, offers any resistance to, or impedes or otherwise interferes with any Officer acting in the course of his duty under sub-section (1), he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three months or with fine up to Rs. 500 or with both."

उद्देश्य और कारण

राज्य में इस समय तीन रीजनल फायर आफिसर्स हैं जो क्रमशः लखनऊ, कानपुर तथा इलाहाबाद में नियुक्त हैं। किन्तु फायर सर्विस ऐक्ट में उक्त स्थानों की कोई व्यवस्था नहीं है। अब यह प्रस्ताव है कि उक्त ऐक्ट को इस प्रकार संशोधित कर दिया जाय जिससे कि उक्त अधिकारियों को जो अब चीफ फायर आफिसर्स कहलायेंगे वैध प्रस्थिति (लीगल स्टेटस) तथा प्रशासकीय एवं कार्यकारी अधिकार प्राप्त हों और वे उक्त अधिनियम तथा उसके अधीन बने नियमों के अधीन कार्य करने के लिये अधिकृत हों। प्रस्तावित विधेयक में उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये इमारत तथा भूमि के निरीक्षण के निमित्त भी व्यवस्था की गयी है।

सम्पूर्णानन्द

गृह मंत्री।

उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौंसिल

सोमवार, ३ नवम्बर, १९५२

उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौंसिल की बैठक, कौंसिल हाल, विधान भवन, लखनऊ, में दिन के ११ बजे चेयरमैन (श्री चन्द्रभाल) के सभापतित्व में हुई।

उपस्थित सदस्य (५४)

अब्दुल शकूर नजमी, श्री
अम्बिका प्रताप वाजपेयी, श्री
उमानाथ बली, श्री
एस० जे० मुकर्जी, श्री
कन्हैया लाल गुप्त, श्री
कुंवर गुरु नारायण, श्री
केशरनाथ खेतान, श्री
कृष्ण चन्द्र जोशी, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
जगन्नाथ आचार्य, श्री
जनीशुरहमान क़िदवाई, श्री
ज्योति प्रसाद गुप्त, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेल राम, श्री
नरीतमदास टंडन, श्री
निजामुद्दीन, श्री
निर्मल चन्द्र चतुर्वेदी, श्री
पद्मा लाल गुप्त, श्री
पूण चन्द्र विद्यालंकार, श्री
प्रतापचन्द्र आजाद, श्री
प्रभुनारायणसिंह, श्री
प्रसिद्ध नारायण अनन्द, श्री
प्रेमचन्द्र शर्मा, श्री
बद्री प्रसाद कक्कड़, श्री
बशीर अहमद, श्री
बलभद्र प्रसाद वाजपेयी, श्री
बालक राम वैद्य, श्री

बाबू अब्दुल मजीद, श्री
महमूद अस्लम खां, श्री
महादेवी वर्मा, श्रीमती
भानपाल गुप्त, श्री
राजा राम शास्त्री, श्री
राना शिवशम्भर सिंह, श्री
राम किशोर शर्मा, श्री
राम लगन सिंह, श्री
रवनुद्दीन खां, श्री
लालता प्रसाद सोनकर, श्री
लाल सुरेश सिंह, श्री
वंशाधर शुक्ल, श्री
बिहनाथ, श्री
ब्रजलाल वर्मन, श्री (हकीम)
ब्रजेंद्र स्वरूप, डाक्टर
शांति देवी, श्रीमती
शांति देवी अग्रवाल, श्रीमती
शांति स्वरूप अग्रवाल, श्री
शिषराजवती नेहरू, श्रीमती
श्याम सुन्दर लाल, श्री
सत्य प्रेमी उपनाम हरिप्रसाद, श्री
सभापति उपाध्याय, श्री
सरदार संतोष सिंह, श्री
संयद मुहम्मद नसीर, श्री
हृदय नारायण सिंह, श्री
हयातुल्ला अन्सारी, श्री
हरगोविन्द मिश्र, श्री

निम्नलिखित मंत्री भी उपस्थित थे:—

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम (वित्त मंत्री)

श्री हरगोविन्द सिंह (शिक्षा मंत्री)

श्री मोहन लाल गौतम (स्वशासन मंत्री)

प्रश्नोत्तर

१-३—श्री राम नन्दन सिंह (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र) —स्थगित

केन कैनाल डिवीजन, बांदा में हिस्साब-किताब में देरी

४—श्री कुंवर महावीर सिंह (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र) (अनुपस्थित)—

(क) क्या यह ठीक है कि केन कैनाल डिवीजन, बांदा में उस पेशगी रुपये का जो कि वहां के चपरासियों आदि को सन् १९५० और १९५१ ई० में रेल और लारी के किराये के लिये दिया गया था हिस्साब-किताब नहीं हुआ बावजूद इसके कि टी० ए० बिल बहुत पहिले कैश (Cash) कर लिये गये थे?

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार कृपा करके यह बतायेगी कि यह जनसाधारण का रुपया इतने समय तक कहां रक्खा रहा और सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की?

4—Sri Kunwar Mahavir Singh (Legislative Assembly Constituency) (absent): (a) Is it a fact that in Ken Canal Division, Banda some advances made to the menial staff on account of railway and lorry fares in the year 1950 and 1951 were not adjusted inspite of the fact that their T. A. Bills were cashed long before?

(b) If so, will the Government state where this public money remained for such a long time and what action did the Government take in this connexion?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम (वित्त मंत्री)—(क) उस पेशगी रुपये का हिस्साब-किताब जो कि चपरासियों आदि को सन् १९५० और १९५१ में रेल तथा लारी के किराये के लिये दिये गये थे सम्पूर्णतः ठीक हो गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Sri Hafiz Muhammad Ibrahim (Minister for Finance): (a) Advances made to menial staff on account of railway and lorry fares in 1950 and 1951 were duly adjusted.

(b) Does not arise.

श्री प्रताप चन्द्र आज्ञाद (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो इसमें लिखा गया है कि सम्पूर्णतः ठीक हो गया है वह कब ठीक हुआ है?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—वह तो अपने ड्यू टाइम (due time) में ठीक हो गया है।

५—श्री कुंवर महावीर सिंह (अनुपस्थित)—(क) क्या यह ठीक है कि केन कैनाल डिवीजन में इरिगेशन मैनुअल आफ आर्डर्स के पैरा ९२ (४) के विरुद्ध खसरों की नकल करने के लिये २,००० रुपया दिया गया है?

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार यह बतायेगी कि गवर्नमेंट रुल्स की पाबन्दी न करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है?

5—Sri Kunwar Mahavir Singh (Absent): (a) Is it a fact that in Ken Canal Division a payment of about Rs.2,000 on account of copying *Khasras* has been made in contravention of paragraph 92 (4) of the Irrigation Manual of Orders?

(b) If so, will the Government state what action has been taken for the non-compliance of the Government rules?

श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम—(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Sri Hafiz Muhammad Ibrahim: (a) No.

(b) Does not arise.

६—श्री कुंवर महावीर सिंह (अनुपस्थित)—क्या यह ठीक है कि प्रश्न संख्या ५ में लिखित खसरे इरिगेशन मैन्युअल के अनुसार पूरे नहीं हुए थे जब कि रकबा पूरी दर के हिसाब से दिया गया है ?

6—Sri Kunwar Mahavir Singh (*absent*): Is it a fact that the *Khasras* referred to in question no. 5 were not complete as provided in the Irrigation Manual while the payment has been made at the full rate?

श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम—जी नहीं।

Sri Hafiz Muhammad Ibrahim: No.

७—श्री कुंवर महावीर सिंह (अनुपस्थित)—क्या यह ठीक है कि केन कैनल डिवीजन, बांदा में ग्राम मोरवाल के खसरा बन्दाबस्त की दो कापियां बनायीं गयीं और इसके फलस्वरूप इस संबंध में दो कापियों के लिये दो बार रकबा दिया गया ?

7—Sri Kunwar Mahavir Singh (*absent*): Is it a fact that in Ken Canal Division, Banda, *Khasra Bandobast* of village Morwal was copied in duplicate and consequently double payment for both the copies was made on this account?

श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम—जी हाँ। इस ग्राम के खसरे की एक नकल बन जाने पर भूल से पुनः बन गई थी और उसके दाम जो लगभग ७ रुपये थे दे दिये गये थे। दूसरी कापी सुरक्षित कर ली गई है और भविष्य में काम आवेगी।

Sri Hafiz Muhammad Ibrahim: Yes, The *Khasra* of this village after having been copied once was again copied due to an oversight and payment which cost about Rs.7 was made.

श्री प्रताप चन्द्र आजाद—इसमें जो लिखा हुआ है कि ७ रुपये गलती से खर्च करने पड़े तो मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूँ कि यह किस की गलती से हुआ है ?

श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम—वह तो एक नकल के बजाय दो कर दी गई और उसमें ७ रुपये खर्च हो गये। यह गलती से हो गया था लेकिन १ के बजाय २ नकल तो बन गई।

८—श्री कुंवर महावीर सिंह (अनुपस्थित)—यदि प्रश्न संख्या ७ का उत्तर हाँ में है, तो सरकार उस अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही करना चाहती है जो इस प्रकार अधिक रकबा देने का ज़िम्मेदार था ?

8—Sri Kunwar Mahavir Singh (*absent*): If the answer to question no. 7 is in the affirmative, what action do the Government propose to take against the authority responsible for this over payment?

श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम—क्योंकि प्रतिलिपि भूल से बनी थी तथा थोड़े से रुपयों का मामला है किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है। विशेषतः ऐसी स्थिति में जब कि यह प्रतिलिपि भविष्य में काम में लाई जा सकती है।

Sri Hafiz Muhammad Ibrahim : As the omission was inadvertant and as the cost involved was small, no action against any authority is called for, especially as the duplicate copy will be of use to the Department.

६—श्री कुंवर महावीर सिंह(अनुपस्थित)—क्या यह ठीक है कि प्रश्न संख्या ५ में उल्लिखित खसरो में से कुछ को नकल केन कैनाल डिवीजन, बांदा के कुछ मुंशियों ने किया था जब कि उसका ठेका सत्यनारायण लाल को दिया गया था ?

9—Sri Kunwar Mahavir Singh (absent): Is it a fact that some of the Khasras referred to in question no. 5 were copied by some of the *munshis* of Ken Canal Division, Banda while the so called contract was given to one Satyanarayan Lal?

श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम—जी नहीं, ठेका सत्यनारायण को दिया गया था और उन्होंने अपने ही आदमियों से यह कार्य कराया था।

Sri Hafiz Muhammad Ibrahim: No. The contract was given to Satya Narayan who executed the work by his own men.

महाराजा बनारस का अपने राज्य का सर्वोच्च सत्ताधारी होना

१०—श्री रामनन्दन सिंह(अनुपस्थित)—क्या मुख्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि महाराजा बनारस विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के पूर्व और १५ अगस्त, १९४७ ई० के बाद अपने राज्य के सर्वोच्च सत्ताधारी थे ?

श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम—जी नहीं।

११—श्री रामनन्दन सिंह(अनुपस्थित)—क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेशीय सरकार को उनके उक्त काल के किसी भी आदेश पत्र की वैधता पर विचार करने का अधिकार नहीं था और न आज है ?

श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम—जी नहीं।

१२—श्री हकीम ब्रजलाल वर्मन(स्थानीय संस्थाप्य निर्वाचन क्षेत्र)—स्थगित सूचना विभाग की नियुक्तियां

१३—श्री कुंवर गुरु नारायण (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—क्या सरकार सूचना विभाग की नियुक्तियों को राजनैतिक नियुक्तियों मानने का इरादा रखती है ?

13—Sri Kunwar Guru Narain (Legislative Assembly Constituency)
Do the Government propose to treat the appointments in the Information Department as of a political nature?

श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम—जी नहीं। परन्तु ज़िला सूचना अधिकारी और अतिरिक्त ज़िला सूचना अधिकारियों के पदों पर जो लोग नियुक्त किये जाते हैं उनकी योग्यता

का निर्णय करने समय उनके सार्वजनिक कार्य के अनुभव पर भी ध्यान दिया जाता है जिसमें राजनैतिक अनुभव भी शामिल हो सकता है।

Sri Hafiz Muhammad Ibrahim: No, Sir, but in deciding on the suitability of candidates for appointment to the posts of District Information Officers and Additional District Information Officers, their experience of public work, which may also include experience of political work, is also taken into consideration.

Sri Kunwar Guru Narain: Will the Government please let us know if such appointments are outside the scope of the Public Service Commission?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जी नहीं, यह बात नहीं है। जितना कानून के मुताबिक पब्लिक सर्विस कमिशन के जरिये होता चाहिये वह तो हो ही रहा है।

Sri Kunwar Guru Narain: I want to know if these appointments i.e. of District Information Officers and Additional District Information Officers in the Information Department are within the scope of the Public Service Commission.

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जी हां, वह तो है ही। सिवाय उनके, जिनको कंटेक्ट पर रखा गया, जैसा कि हर डिपार्टमेंट में है।

आगरा विश्वविद्यालय के उप-कुलपति का चुनाव एक आर्डिनेंस द्वारा स्थगित किये जाने के सम्बन्ध में कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री राजाराम शास्त्री (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो एक काम रोकने का प्रस्ताव आपकी सेवा में भेजा है, अगर आप उसको मान लेने की कृपा करें तो बहुत अच्छा होगा।

चेयरमैन—श्री राजाराम शास्त्री जी ने जो काम रोकने का प्रस्ताव भेजा है वह यह है—

“एक अत्यन्त आवश्यक और सार्वजनिक महत्व के विषय पर विचार करने के लिये मैं निम्नलिखित प्रस्ताव आपकी सेवा में भेज रहा हूँ। विश्वास है कि आप मुझे इस प्रस्ताव को विधान परिषद् में पेश करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करेंगे।”

यू० पी० सरकार ने आगरा विश्वविद्यालय के उपकुलपति के चुनाव को एक आर्डिनेंस निकाल कर स्थगित करके आगरा विश्वविद्यालय के वैधानिक अधिकारों तथा विधान परिषद् के सेशन के दिनों में ऐसा आर्डिनेंस जारी करके परिषद् के अधिकारों को अवहेलना की है, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि इस अत्यन्त आवश्यक और सार्वजनिक महत्व के विषय पर विचार करने के लिये आज सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाय ताकि सम्मानित सदस्य उस पर विचार कर सकें और सरकार के समक्ष अपने सुझाव पेश कर सकें।

चेयरमैन—इसके मुताल्लिक सब से पहली बात यह है कि प्रस्ताव १० बजकर ४५ मिनट पर आया और हमारे नियमों के अनुसार यह आधा घंटा पहले आना चाहिये। इस प्रस्ताव को आधा घंटा पहले मुझे और लीडर आफ दी हाउस को मिलना चाहिये। सरकार इसके बारे में क्या राय रखती है?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—इसके बारे में मैं तो यह अर्ज करूंगा कि इस प्रस्ताव को कल ही लिया जाय तो बेहतर होगा।

चेयरमैन—अब यह प्रस्ताव कल लिया जायेगा और उसकी एंडमिसिबिलिटी के सम्बन्ध में कल ही बातचीत हो जायेगी।

श्री राजाराम शास्त्री—इसकी ऐडमिनिस्ट्रिलिटी के सम्बन्ध में सिर्फ १५ मिनट का ही सवाल है या और भी कोई प्रश्न इसके सम्बन्ध में पैदा हो सकता है।

चेयरमैन—१५ मिनट का प्रश्न कल नहीं उठेगा। अन्य दूसरी बातें हैं उनके बारे में विचार करने का मेरा तात्पर्य है।

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश म्यूनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक

श्री मोहन लाल गौतम (स्वशासन मंत्री)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि सन् १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश म्यूनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक पर विचार किया जाय।

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने पहले भी इस सदन के सामने निवेदन किया था कि यह संशोधन या अमेंडिंग बिल एक खास मतलब को सामने रखते हुए लाया गया है यों तो अगर समय होता तो जो म्यूनिसिपैलिटीज ऐक्ट सन् १९१६ है, उसमें जड़मूल से संशोधन करने की आवश्यकता है, क्योंकि वह काफी पुराना हो चुका है और उसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि जो अभी संशोधित होनी चाहिये। लेकिन इस समय जो जरूरी सवाल हमारे सामने है वह यह है कि अगर सारे म्यूनिसिपैलिटीज ऐक्ट को पूरी तरह से संशोधित किया जाय तो उसमें काफी देर लग जायेगी और हम उन म्यूनिसिपैलिटीज का चुनाव जल्दी नहीं कर पायेंगे जिनके चुनाव हुये करीब सात साल के लगभग हो गये हैं। इसके अतिरिक्त जैसे कि मांग है कि इनके चुनाव जल्दी हों तो उस मांग को पूरा करने के लिये या उनका चुनाव जल्दी कराने के लिये ही इस विधेयक का खास हिस्सा संशोधन करने के लिये, इस सदन के सामने लाया गया है। चूंकि म्यूनिसिपैलिटीज का चुनाव कराना बहुत जरूरी हो गया है और वह इसलिये कि उन संस्थाओं और उन नागरिकों के साथ ज्यादाती करना होगा अगर इन बोर्डों का जीवन काल हर ६ महीने के लिये हम बढ़ाते चले जायेंगे और इस तरह से धीरे धीरे समय बढ़ाने में दिक्कतें भी होती हैं और वह बोर्ड जो कि यह समझता है कि हमारा जीवन सिर्फ ६ महीने के लिये है, कोई नया काम नहीं कर सकता है और न किसी प्रकार की सख्ती हो कर सकता है और इस तरह से उसके ऐडमिनिस्ट्रेशन में ढिलाई आ जाया करती है। म्यूनिसिपैलिटीज ऐक्ट जो कि सन् १९४५ में बनाया गया था उसके अनुसार समय समय पर उनका चुनाव-काल बढ़ता गया और इस तरह से उनके ऐडमिनिस्ट्रेशन में धीरे-धीरे सुस्ती आ जाना भी स्वाभाविक है। आज अगर हम इस बात का इन्तजार करते हैं कि पूरा म्यूनिसिपैलिटीज ऐक्ट अमेंड हो जाय तो उसमें अधिक समय लगेगा। इसलिये यह विचार किया गया है कि चुनाव जल्दी कराने के लिये जितने भी आवश्यक अमेंडमेंट हैं उनको तुरन्त कर लिया जाय। इसलिये जो इस बिल का मुख्य उद्देश्य है वह चुनावों को जल्दी कराने के लिये और वह तमाम संशोधन करने का है जो कि इस नई परिस्थिति में या नई व्यवस्था में आवश्यक हो गये हैं। इसके साथ ही साथ जो कि बहुत ही आवश्यक विषय समझे गये और जिनकी वजह से म्यूनिसिपैलिटीज के ऐडमिनिस्ट्रेशन में मुहकमे को जो जो दिक्कतें मालूम होती रही हैं उनसे सम्बद्ध थोड़े से संशोधन हैं। इसलिए मैं इसको एक आंशिक और पार्शियल (partial) अमेंडमेंट कह सकता हूँ जो कि म्यूनिसिपैलिटीज ऐक्ट में है और जो बड़े भारी अमेंडमेंट आगे किसी रोज सदन के समक्ष आयेंगे उस वक्त वे तमाम मसले लिये जा सकेंगे। आज इस सदन के सदस्यों के सामने इतनी ही बात है, इसलिये मेरी पहले से प्रार्थना है कि उसमें जितने विषय रखे गये हैं वे किसी विशेष हद तक सीमित या महदूद रखे गये हैं और जो भी चीजें संशोधन के रूप में सदस्य पेश करना चाहें वे कुछ दिनों

तक इन्तजार करें ताकि जो दूसरा इस सिलसिले में अर्मेडिग बिल आयेगा, उस वक्त हम उसको ले लेंगे। यह जो म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट सन् १९१६ का है और उसमें १९४८ में कुछ संशोधन हुये थे, तो उसमें कुछ खास बातें थीं जैसे कि इलेक्टोरल रोल, एडल्ट फ्रॉन्टाइज, और प्रेसीडेंट का डायरेक्ट इलेक्शन इत्यादि और उसमें नामिनेशन की जगह कोआप्शन था। यहाँ वे चीजें अभी अमल में नहीं आईं, क्योंकि अभी यहाँ चुनाव नहीं हुये। यहाँ पहले चुनाव १९४८ में हुये थे, तो अब वे सब बातें इस बार अमल में लाई जायेंगी और इसलिये यह अर्मेडिग बिल यहाँ से पास हो जाना चाहिये। अब इस बिल की जो मुख्य-मुख्य बातें हैं में उनको इस सदन के सदस्यों के सामने रखूँगा ताकि जो इसमें अमेंडमेंट हुये हैं, मुझे आशा है कि वह सब लोगों को मंजूर होंगे। इसलिये मैं बहुत ज्यादा समय भी नहीं लूँगा और इस बिल की जो मुख्य-मुख्य बातें हैं उन्हीं का आगे के सामने चिक कर दूँगा। चुनाव को सम्बन्ध में वह भी विचार होंगा कि हमारा जो असेम्बली का एलेक्टोरल रोल है, उसी को हम एडल्ट कर लें और जो क्वालिफिकेशन्स म्युनिसिपल बोर्ड की उस वक्त थीं, वे सब हटा दी जायें। यह चीज आज नहीं हो सकती है कि किसी भी एडल्ट को जो असेम्बली या पार्लियामेंट का बोटर हो जाला है, और इस तरह से चुनाव लड़ कर वह भारतवर्ष का भी प्राइम मिनिस्टर हो सकता है, तो उसके लिये यह कहा जाय कि वह म्युनिसिपैलिटी का बोटर नहीं हो सकता, तो यह चीज आज नहीं मानी जा सकती है और यह उचित भी नहीं है। इसलिये दोनों के लिये हमें एडल्ट फ्रॉन्टाइज को मंजूर करना पड़ेगा और इसके लिये कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जहाँ तक रिजर्वेशन का सम्बन्ध है, तो उसमें शेड्यूल कास्ट के लिये रिजर्वेशन है। कुछ रॉज हुये मैंने अखबार में एक खबर पढ़ी थी कि नम्राज हाई कोर्ट के सामने कुछ लोगों ने यह सवाल पेश किया कि स्त्रियों के लिये रिजर्वेशन किसी ऐक्ट में रखा गया है, तो वह ऐक्ट चलता है क्योंकि वह सेक्स की इन्वेलिटी को वायलेट करता है। इसलिये इस दिशि का जहाँ तक सम्बन्ध है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है और केवल शेड्यूल कास्ट के लिये इसमें रिजर्वेशन है और किसी के लिये नहीं है। इसमें बहुत से सवाल पैदा हो सकते हैं। फिर हमारे सामने बहुत सी चीजें आ जाती हैं। कहा जाता है कि लेबर का रिप्रिजेंटेशन हो। इस तरह से जब किसी भी हिस्से की किसी चीज को आप मान लें तो उसमें शक करने के बाद बहुत सी दिक्कतें बाद में पेश हो सकती हैं, इसलिये एडल्ट फ्रॉन्टाइज का सवाल रखना बहुत जरूरी है। इसमें इस तरह से अलग रिप्रिजेंटेशन हो और उनके लिये अलग अलग हिस्से हों, रिजर्वेशन हो, यह बात ठीक नहीं है। इसलिये शेड्यूल कास्ट के अलावा इसमें और कोई रिजर्वेशन नहीं रखा गया है। जिस तरह से यह चुनाव होंगे वह जैसे असेम्बली के चुनाव हुये हैं उसी आधार की नज़र की गई है। इसलिये इसमें कोई दिक्कत और कन्ट्रोवर्सी का सवाल न होगा। इसके अन्दर एक सवाल यह भी है कि यह एलेक्शन डायरेक्ट चीफ इलेक्शन आफ़ीसर के मातहत होंगे जिससे किसी पोलिटिकल पार्टी को शिकायत का मौक़ा न हो कि किसी के साथ पक्षपात हुआ है। जो बात और जो मशीनरी असेम्बली के इलेक्शन में थी वसी ही इसमें इलेक्शन आफ़ीसर से लेकर और दूसरे लोगों की होगी। एक चीज़ इलेक्शन आफ़ीसर के मातहत चुनाव होगा जिसको सरकार नियुक्त करेगी। बोर्डों की संख्या के सम्बन्ध में जो १९४८ के अमेंडमेंट में की गई थी वह २० से लेकर ८० तक थी अब इस अमेंडमेंट में १५ से ५० कर दिया गया है। जो छोटी छोटी म्युनिसिपैलिटीज हैं और जिनकी आबादी १५ हजार भी नहीं है उसमें १५ की संख्या ही काफी है लेकिन इससे कम करना मुनासिब नहीं समझा गया। यह भी देखने में आता है कि म्युनिसिपैलिटीज में ५० सेम्बर बैठकर किसी मामले पर वादविवाद करें तो इसमें ५० की संख्या काफी है और इससे ज्यादा सेम्बर अगर कर दिये जायें तो उससे कोई ज्यादा फायदा न होगा ऐसा मेरा ख्याल है। मैं समझता हूँ कि म्युनिसिपैलिटीज में ५० की

[श्री मोहन लाल गौतम]

संख्या काफ़ी होनी चाहिये। म्यूनिसिपैलिटीज के लम्बे चौड़े क्षेत्र नहीं हैं। इसलिये वहाँ की समस्या को समझने के लिये कोई दिक्कत न होगी जो मेम्बर रह चुके हैं उनको मालूम होगा कि एक वार्ड का जो मेम्बर है वह अपने शहर की हालत को अच्छी तरह से समझता है इस तरह से ५० आदमी काफ़ी होंगे। सन् १९४८ के ऐक्ट में नार्मिनेशन बदल दिया गया था और कोअपेशन रखा गया था लेकिन इसमें दोनों को उड़ा दिया गया है। अब जो भी मेम्बर बोर्ड के होंगे वह चुने हुये होंगे कोई खास परिस्थिति हो जाय तो दूसरी बात है। यह इलेक्शन के सम्बन्ध में मोटी मोटी बातें हैं। इसलिये मैं इसमें सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता हूँ।

एक बात और जो जरूरी इस मुद्दामें के अन्दर आई उसके बारे में मुद्दामें की राय यह है और मुद्दामें को चलाने के लिये वह जरूरी बातें इसमें की गई हैं। म्यूनिसिपैलिटी की कम्पोस्ट बनाने का अधिकार दिया गया है। यह सवाल ऐसा है कि गवर्नमेंट आफ इंडिया अपना फूड प्रब्लम या प्रोमोर फूड के मसले को हल करने के लिये कोशिश कर रही है और मेरा ख्याल है कि वह इस काम में कुछ मदद भी देगी और मैं समझता हूँ कि यदि म्यूनिसिपैलिटीज इस काम को करेंगी तो कम्पोस्ट बढ़ेगा और प्रोमोर फूड में भी आता ही होगा अब एक सवाल और है जिसको सदन के मेम्बरान नये रूप में देखते होंगे हालांकि वह इस तरह से नहीं है। एक इसमें प्रावीजन है मेम्बरों को सस्पेंड करने का। अलग करने का प्रावीजन तो पहले ऐक्ट में है। आज भी गवर्नमेंट को यह अधिकार है कि वह मेम्बरों को अलग कर दे अगर कोई ग़लती वह करे। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया, जैसा कि सब को अनुभव है कि जो भी पब्लिक सर्विस में प्रोजेक्शन आक़्पाई करता है, जिसको ला (law) ने कुछ प्रोटेक्ट कर दिया है वह अगर ग़लती करे तो उनके खिलाफ तब तक ठीक इन्क्वायरी नहीं हो सकती जब तक कि उनको सस्पेंड न किया जाये। मुझ को इसका कुछ ज़ाती अनुभव है जो कि काफ़ी तल्ल है। मैं मेम्बर जब था उस ज़माने में एक मामूली मुलाज़िम के खिलाफ़ शिकायत करने के लिए मेरे खिलाफ़ म्यूनिसिपल बोर्ड ने ज़ाली कागज़ात तैयार किए और उनको पेश किया। सन् ३६ में जित छोटें छोटें मुलाज़िमान के खिलाफ़ मेने रिडवत की शिकायत की थी और जो डिस्मिस हो गये उनका मुक़द्दमा मेरे ऊपर अब तक चल रहा है। जिन मेम्बरों ने मज़बूती के साथ, सही के साथ काम किया है, उन आदमियों में से यहां भी चन्द मेरे दोस्त मुझे नज़र आ रहे हैं। उनको अनुभव है कि क्या क्या दिक्कतें सामने आती हैं। उनको यह भी मालूम है कि कोई ग़लत काम करने में मैं कभी हिस्सेदार नहीं था, इस वजह से मुसीबतें मुझ पर भी आईं और उस केस में मुझको सज़ा हो चुकी है लेकिन अपील से मैं उससे बरी हो गया। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि अगर हम किसी मेम्बर के खिलाफ़ इन्क्वायरी करना चाहें, तो उसको सस्पेंड करके ही हम इन्क्वायरी अच्छी तरह से कर सकते हैं। इसके साथ ही चेयरमैन, और प्रेसीडेंट जो कहलायेंगे उनका भी सवाल है। प्रेसीडेंट को हम आज अलग तो कर सकते हैं लेकिन उसमें यह लिखा हुआ है कि परसिस्टेंट क्लेयोर होना चाहिए। हमारे सामने एक ऐसा केस आया जिसमें रुपया ख़बन हो चुका है। उसमें हमारे लीगल एक्सपर्ट की यह ओपीनियन है कि यह पहला मौक़ा है, वॉरिंग भी कभी नहीं दी गई इसलिए उसको अलग नहीं कर सकते। अब मेरे सामने दिक्कत यह आई कि अगर हम पब्लिक मीटिंग में जाते हैं और लोग मुझ से यह कहते हैं कि तुम हमारे रुपये के कस्टोडियन हो, तुमको हमारा रुपया अच्छी तरह से रखना चाहिये। इसके बाद अगर यह कहें कि यह चेयरमैन है इसने रुपया ख़बन किया है और रुपया ख़बन करने के बाद भी यह चेयरमैन मौजूद है तो फिर आप हमारे रुपये के कैसे कस्टोडियन हैं जो कि इसको सज़ा भी नहीं दे सकते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर कोई ग़्रास मिसयूज़ आफ़ पावर्स हो तो हम पहली बार ही चेयरमैन को रिमूव कर

सके जिससे कि अगर हम से कोई कहे कि जिसने गवन किया था वह आज भी चेयरमैन कैसे बना हुआ है तो हम उस चेयरमैन को पहली बार ही अलग कर सकें। दूसरी बात यह है कि यदि जरूरत हो तो हम सस्पेंड भी कर सकें। हमने मेम्बरों के बारे में कहा कि उसको सस्पेंड करके ज्यादा अच्छी तरह से इन्क्वायरी कर सकते हैं। इसके साथ साथ यह हो कि चेयरमैन जो प्रेसीडेंट कहलायेगा वह मैट्रिक पास हो या उसके बराबर की परीक्षा पास हो। ऐसा इसमें रखा गया है। टाइम्स आफ इंडिया ने लिखा कि जब पार्लियामेंट के मेम्बर और पड़े लिखे जूस कर सकते हैं तो चेयरमैन क्यों नहीं कर सकता है। अगर कोई पार्लियामेंट का मेम्बर, असेम्बली का मेम्बर और कौंसिल का मेम्बर हो और वह यह नहीं समझता है कि जो संशोधन आया है उसके क्या माने हैं और वह नहीं जानता कि म्यूनिसिपैलिटी का ऐक्ट क्या है तो वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। पार्लियामेंट के मेम्बर, असेम्बली के मेम्बर तथा कौंसिल के मेम्बर और एक्जिक्यूटिव हेड में अन्तर होता है। चांस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर यह नहीं जानता कि कानून क्या है तो कैसे काम चला सकता है। मेम्बर है, तो कुछ हिस्सा लेगा और कुछ नहीं लेगा इस तरह से पार्लियामेंट और असेम्बली का काम चल जायेगा लेकिन अगर प्रेसीडेंट नहीं जानता है कि गवर्नमेंट ने जो सरक्यूलर भेजा है उसके क्या माने हैं तो वह म्यूनिसिपैलिटी के ऐडमिनिस्ट्रेशन को नहीं चला सकता है। सेक्रेटरी अपने मतलब के लिये जो चाहे वह करवा सकता है। यह विष्कत हमारे सामने है। आप अगर कोई रास्ता निकालेंगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जब तक गवर्नमेंट की हिदायत को नहीं समझेगा तब तक कैसे काम चलेगा। अगर आप उसमें कोई दूसरा रास्ता निकालें तो मुझे इसके मानने में कोई एतराज नहीं है। पहले इलेक्शन होता था और म्यूनिसिपैलिटी के मेम्बरों का वह वोट लेते थे। उसमें बहुत से लोग काम करते थे लेकिन अब तो ऐडमिनिस्ट्रेशन से चुना जायेगा इसलिये पब्लिक ओपिनियन इस बात के हक में होगी कि वे पड़े लिखे पेश करें। एकाउन्ट आफिसर रखा जाय। बहुत सी म्यूनिसिपैलिटी से शिकायत आती है। उसके सुधारने का रास्ता इतना धीमा है कि वह सुधरता नहीं है। जो सुधारते हैं उससे न तो संतोष हमको है और न आपको है। जब जनता समझती है कि हिसाब में गड़बड़ी है और गड़बड़ी होती है तो इसके माने हैं कि उसका इन्तजाम ठीक तरह से नहीं होता है। इसलिये जो हिसाब है उसको ठीक तरह से रखा जाय उसके लिये एकाउन्ट आफिसर की नियुक्ति के बारे में एक संशोधन है। सुपरिन्टेंडेंट आफ ऐजुकेशन भी अपने मातहत को रख सके और बरखास्त कर सके। एक सवाल जो हमारे सामने आज बहुत बड़ा हो रहा है वह यह है कि आक्ट्रार्ड के बारे में हम क्या करें। आक्ट्रार्ड के बारे में बहुत गड़बड़ बताई जाती है। ऐसी शिकायतें मेरे कानों तक बहुत पहुंचती हैं। मान लिया ४० लाख की आमदनी हुई और उसमें ३० लाख रिफंड हो जाता है। अब इस ३० लाख में गड़बड़ी भी बहुत होती है। म्यूनिसिपैलिटी की यह शिकायत है कि यह जो खर्चा हमने लिया और रिफंड किया तो इसमें चूक करने वालों की तनख्वाहें हम बेते हैं, कागज स्याही का खर्च करते हैं और जहाँ रिफंड हुआ वहाँ भी नोट हुआ तो यह ३० लाख का जो रिफंड हुआ इसमें म्यूनिसिपैलिटीज का जो खर्च हुआ और गवन और बेईमानी भी होती है, वह अलग। इस तरह से यह समस्या आक्ट्रार्ड की हमारे सामने है और इसका मतलब हल करने के लिये क्या चीज है। यह बात सोची गई है कि आक्ट्रार्ड रिफंड न हो, इस तरह का कोई तरीका निकाला जाय। इस तरह से यह एक बड़ी स्कीम का हिस्सा है जिसको पूरा करने की कोशिश हम कर सकते हैं।

दूसरी चीज यह है कि सिनेमा हाउसेज, प्लेसेज आफ वरशिप के पास न बन सकें। उससे बहुत सी दिक्कत पैदा होती है। प्लेसेज आफ वरशिप भी बहुत जल्दी बन जाते

[श्री मोहन लाल गौतम]

हैं। आपने सुना होगा कि रात रात में मन्दिर और मसजिदें तैयार कर दी गईं। मान लिया कि कोई आदमी सिनेमा बनाने वाला है और उसका कोई दुश्मन है बस रात-रात में वहां मन्दिर या मसजिद बन जाती है तो इस परेशानी को दूर करने का इरादा है लेकिन इसके माने यह नहीं है कि हम हर प्लेस आफ वरशिप के पास सिनेमा बनाना चाहते हैं। लेकिन इस तरह की जब दिक्कतें उठती हैं तो जब तक हमारे पास कोई कानूनी अधिकार नहीं तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर इस तरह का अधिकार हमारे पास रहेगा तो बेकार परेशान करने की किसी को गुंजायश नहीं होगी।

एक बात और है, आपको यह अन्दाजा तो होगा ही कि एक टाउन प्लानिंग का मुहकमा गवर्नमेंट के सामने है। हम यह चाहते हैं कि जो कोई टाउन बसे वह एक खास ढंग से बसे। इसके लिए एक मास्टर प्लान बनाया गया है और इसके मुताबिक टाउन बसाये जाने की योजना है, लेकिन इसके यह माने नहीं हैं कि जो टाउन बसे हुये हैं उन्हें खोद कर हम नया बनायेंगे लेकिन हम चाहते हैं कि अगर इस प्लान के मुताबिक ही काम हो ताकि इसकी एक अच्छी शक्ल निकल आवे और चीजें ठीक होती जायें। इसके लिये कोई कानूनी अधिकार नहीं है अब तक।

इसके लिये भी एक एडहाक कमेटी बना दी जाये। इसके लिये हमको कुछ कानूनी अधिकार हों ऐसा इस पर इशारा किया गया है। म्युनिसिपल इम्प्लाइज के बारे में भी एक कूल बनाने के लिये है। इससे यह होगा कि म्युनिसिपल ऐडमिनिस्ट्रेशन ठीक हो सकता है। एक बात में और कहना चाहता हूँ कि इस वक्त म्युनिसिपैलिटीज के जो टर्म्स हैं वह चार साल के रखे गये हैं। चार साल के बाद अगर गवर्नमेंट चाहे तो वह ज्यादा से ज्यादा दो साल और बढ़ा सकती है। अभी तक ऐसा नहीं था। अभी तक तो यह था कि अगर सरकार चाहे तो वह १० साल तक बढ़ाती चली जा सकती है। इस अर्मेडिंग बिल में यह रक्खा गया है कि चार साल के बाद म्युनिसिपैलिटीज का टर्म खत्म हो जायेगा और ज्यादा से ज्यादा अगर गवर्नमेंट चाहे तो वह दो साल और बढ़ा सकती है। ६ साल के बाद तो म्युनिसिपैलिटीज को इलेक्शन करना ही पड़ेगा। यह मुख्य मुख्य बातें हैं जो इस अर्मेडिंग बिल में हैं इसमें एकाध बातें हैं जो इस अर्मेडिंग बिल में कंट्रोवर्सी की हो सकती हैं और मेरा ख्याल है कि सदन अधिकांश बातों पर सहमत होगा। इन शब्दों के साथ मैं इस अर्मेडिंग बिल को विचार के लिये इस सदन के सामने पेश करता हूँ।

चेयरमैन—श्री राजाराम शास्त्री ने एक संशोधन की सूचना दी है कि उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक को एक सेलेक्ट कमेटी के विचारार्थ भेज दिया जाये।

श्री राजा राम शास्त्री—मैं प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक को एक सेलेक्ट कमेटी के विचारार्थ भेज दिया जाये।

मैं इस प्रस्ताव को इस लिये पेश करना चाहता हूँ कि यह विषय काफी महत्व रखता है और इसपर काफी अच्छी तरह से विचार होना चाहिये। माननीय मंत्री जी ने अभी जो भाषण किया उसमें जो बातें उन्होंने पेश कीं उनमें बतलाया कि यह विधेयक क्यों लाया गया है। जहां तक चुनाव करने की बात है उसमें कोई ज्यादा विवाद की आवश्यकता नहीं है। असेम्बली का चुनाव जिस तरीके से हुआ है उसके संबंध में सब लोग जानते हैं। साथ ही साथ माननीय मंत्री जी ने कुछ बातें ऐसी पेश कीं कि मेरा ख्याल है कि उनमें से कुछ बातें ऐसी हैं जिनके बारे में कुछ विवाद हो सकता है और विरोध भी हो सकता है। मेरा ऐसा ख्याल है कि इस विषय के साथ अगर हमें पूरा इन्साफ करना है तो हमको पूरा मौका इसके संबंध में विचार करने का मिलना चाहिये। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूँ कि अध्यक्ष महोदय, आप इस बात को देखते हैं कि जिस दिन यह संशोधन रक्खा गया था उसके बाद तीन रोज की छुट्टी हो गई थी। वह इसलिये हो गई थी कि हम लोग इस पर विचार कर सकें। दो रोज तक आफ्रिसेज बन्द

रहे और कितने ही माननीय सदस्य अपने अपने घरों को भी चले गये। इस वक्त ११ बजे से बहस शुरू हो गई। मैं यह महसूस करता हूँ कि अगर मंत्री जी को हमें पूरी सहूलियत देना है कि हम भी इसमें संशोधन ला सकें तो इसको सेलेक्ट कमेटी के सामने पेश होना चाहिये। संशोधनों को देखने से मालूम होता है कि जितने भी संशोधन आये हैं वह सब गवर्नमेंट की तरफ से आये हैं। सिवाय सरकारी पक्ष की तरफ से और किसी ने तो शायद अपने संशोधन अभी तक दिये नहीं हैं। एक तो यह मुश्किलता हमारे सामने रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं चाहता हूँ कि इस प्रस्ताव को लाकर हम पर यह इल्जाम लगा दिया जाय कि पहले तो हम लोग शोर मचाते रहे और पब्लिक में सरकार की आलोचना करते रहे कि सरकार चुनाव नहीं कराना चाहती है और जब सरकार चुनाव करने के लिये बात करती है तो हम डिप्लॉयंग टैक्टिक्स करते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरी मंशा कतई ऐसी नहीं है कि चुनाव रोक दिये जाय। लेकिन मैं इतना जरूर चाहता हूँ कि जो चुनाव किया जा रहा है और नये-नये अधिकार दिये जा रहे हैं या लिय जा रहे हैं ये सब चीजें ऐसी हैं जिस पर विचार होना चाहिये। इसलिये मैं चाहता हूँ कि आप एक विशिष्ट समिति मुकर्रर कर दीजिये और उस का समय एक हफ्ता या इससे भी कम समय रखा जाय तो मुझे एतराज नहीं है। लेकिन मैं सहस्र करता हूँ और शायद हर मेम्बर इसको महसूस करता होगा। चूंकि आज बहस शुरू हो जायेगी तो बहस हम करेंगे ही और देखने पर मालूम पड़ेगा कि इन्साफ हो रहा है या नहीं यह सब बातें तो होंगी ही, लेकिन हमको मौका अवश्य मिलना चाहिये, क्योंकि सही ढंग से हमें मौका नहीं मिल पाया। इसकी मांग हम सरकार के सामने करते हैं। इसमें आपका ज्यादा टाइम नहीं लगेगा यदि सेलेक्ट कमेटी के सुपुर्व कर दिया जाय। यदि आप सात दिन की मियाद ज्यादा समझते हैं तो वह ५ या ६ दिन हो सकता है। लेकिन विशिष्ट समिति में जब जायेगा तो वहां लोगों को मौका मिलेगा।

दूसरी ओर मैं सरकार को विश्वास दिलाता हूँ कि विशिष्ट समिति के अन्दर पूरी बहस हो जायेगी जिससे संशोधन जो यहां पर आये हैं वे वहीं हो जायेंगे और विरोधी तथा सरकारी पक्ष इस तरह से मित्रजुल कर इसे जल्दी पास कर देंगे। माननीय मंत्री जी ने कहा कि यह एक मालूम बिल है, कोई लम्बी बहस या विरोध का सवाल नहीं है। अगर विशिष्ट समिति में आप ६ दिन खर्च करें तो मैं आप को विश्वास दिलाता हूँ कि इस सदन में पाइलेट करने में कम समय लगेगा और आप को आसानी होगी। आपकी मंशा से यह पता लगता है कि आज बहस हो जाय और कल संशोधन पेश कर दिये जाय लेकिन यदि सरकार अपोजीशन को साथ लेकर चलती है और जिस नीयत से मैंने प्रस्ताव पेश किया है उस नीयत से काम किया जाय तो इससे मिनिस्टर को स्वयं सहूलियत होगी। इसमें किसी को विरोध नहीं होगा इस गरज से मैंने यह प्रस्ताव पेश किया है। मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री जी अवश्य इसे स्वीकार करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपने प्रस्ताव को सदन के सामने पेश करता हूँ।

चेयरमैन—आप की क्या राय है।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जो बहस हो रही है, होने दीजिये।

श्री राजा राम शास्त्री—मैंने जो अभी बहस की थी, वह अपने प्रस्ताव पर की थी कि इसको सेलेक्ट कमेटी के सुपुर्व कर दिया जाय। लेकिन ऐसा माना जाता है कि यहां तो बहस पहली रीडिंग पर हो रही है। क्या दोनों चीजें साथ ही साथ चल रही हैं।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जनाबवाला, बदकिस्मती से दोनों चीजें साथ ही साथ चलती हैं। जो मोशन पेश हुआ है कि इसको सेलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाय और बिल पर साथ ही साथ बहस होती है। यह कोई नई बात नहीं है यह तो मैंने पहले ही कह दिया था।

चेयरमैन—माननीय मंत्री जी ने जो कुछ कहा वह ठीक कहा है। दोनों पर साक्ष्य ही बहस होगी।

श्री राजा राम शास्त्री—अभी मैंने दोनों पर बहस नहीं की है।

चेयरमैन—इस संबंध में हमारा नियम इस प्रकार है :—

If the member incharge moves that the Bill be taken into consideration, any member may move an amendment that the Bill be referred to a select committee or a joint select committee etc.

तो इस इस समय सदन के सम्मुख मूल प्रस्ताव यह है कि इस विधेयक पर बहस की जाय और उस में यह संशोधन प्रस्तुत किया गया कि इस विधेयक को सेलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाय। यह दोनों साथ ही साथ बहस में लिये जायेंगे। अगर आप को मूल प्रस्ताव पर भी कुछ और कहना है तो कह सकते हैं।

श्री राजाराम शास्त्री—माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की खुशा है कि आज कई सालों के बाद माननीय मंत्री जी को एकाएक यह बात महसूस हुई कि म्युनिसिपैलिटीज का चुनाव हो जाना चाहिए। सूबे की जनता बहुत दिनों से इसकी मांग कर रही है। सरकार बहुत दिनों से बराबर जनता को इस बात का विश्वास दिलाती रही है कि चुनाव बहुत जल्द हो जायेगा लेकिन फिर भी चुनाव बराबर टलता ही रहा। मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने इस संशोधक विधेयक को पेश करके एक तरीके से म्युनिसिपल चुनाव की ओर जनता का ध्यान आकर्षित किया है। मैं माननीय मंत्री जी को एक बार फिर बधाई देता हूँ कि उन्होंने समय की आवश्यकता को समझ कर यह विधेयक पेश किया है। इस विधेयक का एक तो यह उद्देश्य है कि चुनाव किस तरीके से हो। दूसरे यह कि किस मौके से लाभ उठाया जाय। क्योंकि वह तो पार्लियामेंट का एक कानून बना और उसके मुताबिक बालिग मताधिकार के आधार पर सारे देश में चुनाव कराया गया और पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन का जो ऐक्ट है, उसकी चुनाव के संबंध में जो धारारें हैं, मेरे ख्याल से अक्षरशः करीब करीब वही धारारें इस विधेयक के अन्दर उठाकर पेश कर दी गई हैं। इसके अतिरिक्त मुझे इस संबंध में और अधिक नहीं कहना है, हाँ रिप्रेजेंटेशन के सिद्धांत की जितनी बातें हुई, जैसे कि आपने कहा कि महिलाओं को कोई रिप्रेजेंटेशन सीट नहीं दी गई है, ठीक बात है। इसी प्रकार आपने कहा है कि म्युनिसिपैलिटीज में इस तरह के रिप्रेजेंटेशन का कोई सवाल नहीं रहा है, अब शेड्यूल कास्ट का रिप्रेजेंटेशन रखा गया है लेकिन लेबर के संबंध में खास तौर से माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि पहले किसी वक्त में मजदूरों की सीटें मांगी जा रही थीं। यह कहा जा रहा था कि मजदूरों को सीटें मिलनी चाहिये। लेकिन यह कहा गया है कि जहां तक बालिग मताधिकार का हक है उसकी वजह से मजदूरों को अलग से सीट देने का सवाल उचित नहीं है। मेरा तो ख्याल यह है कि रिप्रेजेंटेशन का जो सिद्धांत है वह यह है कि ओपेन कम्पिटिशन में अगर कोई वर्ग अपने को कमजोर पाता है जो राजनैतिक दृष्टि से आगे न बढ़ा हो, उसके पास ऐसे साधन न हों कि जिनकी वजह से वह दूसरों का मुकाबिला कर सके, तो उसकी रक्षा के लिये और उसकी प्रगति में सहायता देने के लिये यह रिप्रेजेंटेशन का तरीका अस्तित्वार किया जाता है। यह तो ठीक है और मैं भी मानता हूँ कि जब बालिगमताधिकार का तरीका हो गया है और हर नर नारी को वोट देने का अधिकार दिया गया है तो उस मौके पर धर्म के नाम पर सब रिप्रेजेंटेशन को खत्म किया गया है और इसलिये हर एक वर्ग का रिप्रेजेंटेशन मांगना गलत बात है, चुनाव में लोग भिन्न नहीं रह सकते हैं जिस तरह से जातीयता के नाम पर शेड्यूल कास्ट है और जो ऐसा वर्ग है कि उसकी रक्षा करने के लिये इस तरीके से किया गया, तब सचमुच में महसूस करता हूँ कि जहां तक विचार धारा का ताल्लुक है, राजनैतिक लड़ाइयों का ताल्लुक है, और राजनैतिक चेतना का जहां तक ताल्लुक है, मैं मानता हूँ कि लेबर वर्ग काफी आगे बढ़ा हुआ है, लेकिन जिस तरीके से आजकल के चुनाव हुये और उन चुनावों में घनघोर लड़ाई हुई, तो उस चुनाव में बहुत से साधन ऐसे होते हैं जैसे कि पैसा, और आजकल सबसे बड़ा साधन पैसा है। जिसके पास पैसा नहीं है वह कुछ नहीं कर सकता है। आज हजारों रुपया खर्च होता है, बड़े बड़े आदमी मुकाबिले में खड़े होते हैं तो उनके मुकाबिले में अगर हम यह कहें कि मजदूरों को ट्रेड यूनियन चुनाव की लड़ाई

लड़े, या दूसरी पार्टीज का या और जो दूसरे चुनाव के साधन हैं, उनका मुकाबला कर सकें तो यह कठिन सी बात है मेरा अपना ख्याल यही है। अभी जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि अब व्यक्तित्व का जमाना नहीं रहा है और मजदूर ट्रेड यूनियन को लड़ना चाहिये तो इसके लिये मैं यह कहूंगा कि उसकी भी मुश्किलें हैं। मैं तो कहूंगा कि मजदूर आज सचमुच राजनैतिक दृष्टि से इतने पिछड़े हुये हैं कि जिसका कोई भी अन्त नहीं है। उसकी राजनैतिक पार्टी इस रूप में नहीं है जैसे कि इंग्लैंड में है, जो कि मजदूरों की रक्षा करने के लिए मजदूरों से ही बनी हुई है, तो ऐसी पार्टी को जरूर सामने आ जाना चाहिये। जब इस प्रेसीडेंट पर हम विचार करने लगते हैं तब मुझे पूरी आशा हो जाती है कि सचमुच में इस आम चुनाव में मजदूर व गरीब वर्ग की रक्षा वह कर सकेगा, परन्तु इसमें भी मुझे कुछ संदेह है, इसलिये कि यदि इस समस्या को माननीय मंत्री जी विचार करें, तो मेरा ख्याल है कि मजदूरों की परिस्थिति से उनको यह अच्छी तरह से मालूम हो जायेगा। साथ ही साथ मैं एक बात और यह भी बतलाना चाहता हूँ कि देश के अन्दर आज ट्रेड यूनियन बहुत पीछे हैं और अगर उनको भी कुछ अधिकार हों और वे भी अपने नुमाइन्दे चुनाव में नहीं ला सकेंगे, तो उनकी रक्षा करना और उनके नुमाइन्दे म्युनिसिपैलिटीज में रखे जायें तो ज्यादा अच्छा होगा। मेरा अपना ख्याल है कि यदि ऐसा हो जाये तो हमारे लिये यह अधिक हितकर है।

साथ ही साथ मैं इस बात का भी विचार रखता हूँ कि इस बिल के अन्दर और सब चीजें जैसी हैं, वे तो उचित हैं ही, लेकिन जैसा कि मेम्बरों को और प्रेसीडेंट को सस्पेंड करने और उनको अलग कर देने का जो अधिकार दिया है, यह देखना है कि वह सचमुच में कहां तक उचित है। कोई भी प्रेसीडेंट जो कि आम चुनाव से चुनकर किसी म्युनिसिपैलिटी का प्रेसीडेंट बनता है, और जनता का उस पर पूरा विश्वास है, और जिस तरीके से आम चुनाव में वोट लेने के बाद, इस तरह से जो हुकूमत बनती है, और उसका यह दावा है कि चूंकि जनता ने हमें वोट दिया है और उसके बल पर और उसके विश्वास पर ही हमने हुकूमत बनाई है, और दूसरी तरफ हुकूमत यह कहती है जिस चीज को वह हितकर समझती है, उसी को करती है, तो इस तरह से वो मुश्किलें पैदा हो सकती हैं, और वे जो चुने हुये हैं, यह कह सकते हैं कि हुकूमत ने गलत काम किया। इस तरह जो मुश्किल पैदा होती है और माननीय मंत्री जी के भाषण को सुनकर जैसा ज्ञात हुआ कि किसी भी म्युनिसिपैलिटी के प्रेसीडेंट को जो कि आम चुनाव से वोट पाकर और जिस पर कि जनता ने विश्वास प्रकट किया, और अगर अपनी दृष्टि से कोई काम करता है और यह समझता है कि उसने सही काम किया, मगर इसके विपरीत हुकूमत समझती है कि उसने गलत काम किया और उसने अपने उस काम से नुकसान पहुंचाया, तो उस समय सरकार उस अधिकार को अपने हाथ में लेगी और उसको सस्पेंड करके निकाल भी देगी। यह बात यदि डेमोक्रेसी में संभव है, तो यह अधिकार किसी भी बालिग मताधिकार पर बनी हुई, जो बाडी है, और यदि म्युनिसिपैलिटी के अन्दर इस तरह से कोई गलत काम करने की वजह से उसको सस्पेंड किया गया या हटाया गया, तो यह चीज तो मुझे पसन्द आई, मगर ऐसी भी चीज डेमोक्रेसी में होती है कि अगर हम यह महसूस करते हैं कि हुकूमत कोई गलत काम करती है और हुकूमत जनता के खिलाफ कोई काम करती है तो उस वक्त भी कोई ऐसा आर्डिनेंस जारी किया जाय और हुकूमत को सस्पेंड किया जाय और तभी इस कानून से जो म्युनिसिपैलिटी के मेम्बरों या प्रेसीडेंट का सस्पेंशन होगा, वह ठीक जंच सकता है। लेकिन जब आपको सस्पेंड करने का सवाल पैदा होता है, तब माननीय अध्यक्ष जी, यह सवाल दूसरों के लिये पैदा हो जाता है, मगर अपने लिये आप कहते हैं कि हमें यहां जनता ने चुनकर भेजा है। मैं कहता हूँ कि अगर म्युनिसिपैलिटी के किसी प्रेसीडेंट ने गलत काम किया है, तो वह भी यहां जनता के विश्वास से और उनके द्वारा चुनकर आया है, तो यदि जनता समझती है कि वह अयोग्य है, उसको निकालकर बाहर किया जाय तो उस समय यह बात हुकूमत अपने हाथ में ले लेती है, तो यही बात हुकूमत के लिये भी होनी चाहिये। इस तरह से नागरिकों के बहुमत से सब चीज होना चाहिये।

अब सवाल इसमें यह हो सकता है कि इसके लिये फंसला कौन करे कि उसने सही काम किया या गलत काम किया है। म्युनिसिपैलिटी डिपार्टमेंट के लिये तो फंसला हुकूमत ने किया

[श्री राजा राम शास्त्री]

है कि उसने गलत काम किया है, मगर जो जनता की मंजारिट्री के द्वारा चुनकर प्रेसीडेंट हुआ है, और उसके खिलाफ किसी भी तरह से मिनिस्टर साहब को यह विश्वास हो गया हो कि इस प्रेसीडेंट या चेयरमैन ने गलत काम किया है, तो उस वक़्त क्या हो सकता है। अगर उस चेयरमैन ने कोई गलत काम किया आपने उसको सस्पेंड कर दिया और निकाल दिया तो उस समय आप की बात चलेगी या म्युनिसिपैलिटीज के जो मेम्बर्स हैं अगर वह कहते हैं कि चेयरमैन ने कोई गलत काम नहीं किया है तो उस वक़्त आप की बात चलेगी या उन मेम्बर्स की। इसी तरह से यह भी कहा गया कि म्युनिसिपैलिटीज के चेयरमैन को मंटीकुलेट होना जरूरी है। अगर मेम्बर अयोग्य है और उसको पता नहीं कि हाउस में आज क्या हो रहा है तो मेरे ह्याल में वह किसी का कोई नुकसान नहीं करता है सिवा इसके कि वह जिस क्षेत्र से चुन कर आया उसका वह सही तौर से प्रतिनिधित्व न करे। मेरे पास भारत का संविधान नहीं है, पता नहीं उसमें किसी राष्ट्रपति के लिये या मिनिस्टर के लिये कोई योग्यता के लिये कोई शर्त रखी गई है या नहीं। मान लीजिये कि म्युनिसिपैलिटी का एक चेयरमैन है वह कोई गलती करता है तो वह जनता को नुकसान पहुंचाता है इसलिये उसको मंटीकुलेट होना चाहिये। मैं पूछता हूँ कि सरकार ने किसी डिपार्टमेंट के मंत्री को जिसके हाथ में लाखों रुपया दे दिया जाता है, उसके लिये कोई शर्त रखी है या नहीं कि उसका मंटीकुलेट होना जरूरी है या नहीं। मेरा ह्याल यह है माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस हाउस का एक साधारण सदस्य हूँ, मुझे पता नहीं है, अगर कोई गलती हो जाय तो मैं कोई हाउस का नुकसान नहीं करूंगा लेकिन मान लीजिये कोई गलती माननीय मंत्री जी कर बैठते हैं तो वह सबे का कितना नुकसान कर सकते हैं, करोड़ों रुपया उनके हाथ में है तो मालूम नहीं कि उनके लिये कोई शर्त है या नहीं कि वह मंटीकुलेट हो या न हो। अगर मौका आया और यह बिल पास हुआ तो किसी मौके पर मेरी ख्वाहिश यह है कि एक प्रस्ताव इस सदन के अन्दर लाया जाय, जिसमें यह हो कि माननीय मंत्री को बनाने के लिये यह देखना जरूरी हो कि मंटीकुलेट है या नहीं यदि मंटीकुलेट नहीं है तो कम से कम बरनाकुलर मिडिल पास होना तो जरूरी है। अगर कोई शर्त नहीं है और वह कोई गलती करता है तो वह देश का कितना नुकसान करता है। मैं इसके पक्ष में हूँ कि शर्त होनी चाहिये इसलिये जो प्रेसीडेंट के लिये शर्त रखी गई है वह जरूरी है।

अब दूसरी बात यह है कि अगर गलती करता है तो उसको हटाने की बात है। अगर कोई सदस्य गलती करता है तो उसको हटाया जा सकता है, तो हटाने का अधिकार किसको होना चाहिये। मैं समझता हूँ कि इलेक्टोरेट को यह अधिकार होना चाहिये। अगर जनता यह समझती है कि इसने गलती की है और काम ठीक नहीं कर रहा है, जो उसने चुन कर भेजा है उसको यह अधिकार होना चाहिये कि वह उसको निकाल सके, इसके लिये सरकार को या किसी और को अधिकार न होना चाहिये। सदन के अन्दर मान लीजिये कोई अयोग्य मेम्बर है और अगर सरकार के हाथ में या मिनिस्टर के हाथ में यह अधिकार दे दिया जाय कि वह किसी को निकाल सकता है मुझे पता नहीं कि सरकार को ऐसा अधिकार है या नहीं कि यदि कोई सदस्य कोई गलती करता है तो मिनिस्टर उसको निकाल सकता है या नहीं, तो जब तक कि वह अपना इस्तीफा न दे। अगर माननीय मंत्री जी को यह अधिकार नहीं है कि वह किसी भी मेम्बर को जो अयोग्य हो जो असेम्बली, कौंसिल या पार्लियामेंट में हो, निकाल सके, अगर यह हो जाय तो मुझे डर है कि मेरा ही सबसे पहला नम्बर आयेगा कि कोई राजनैतिक गलती मंने की तो मुझे निकाल दिया जायगा। इस अधिकार को देने में मुझे यह खतरा मालूम होता है। हो सकता है, और मुझे विश्वास है कि अगर माननीय गौतम जी या हाफिज जी के हाथ में यह अधिकार हो और वह मुझे न निकाले लेकिन फिर भी अधिकार देने में डर लगता है। इसलिये मेरा अपना विचार यह है कि जिस क्षेत्र से वह निर्वाचित होकर आया वहां की जनता को यह अधिकार होना चाहिये कि वह उसे निकाल सके और जिसको चाहें उसको वह वापस बुला लें।

आज सदन के अन्दर पावर्स तो हम सरकार को दे दें लेकिन पार्लियामेंटरी हुक्म में जो पाटी इन पावर होती है उसके मेम्बर्स का सुबह से शाम तक यही पेशा रहता है कि क्या काम

किया जाय, जिससे हमारी पार्टी ही पावर में रहे। यह पावर देते वक्त अध्यक्ष महोदय, मुझे डर लग रहा है। आज इतनी पार्टी बन्दी हो रही है कि जीवन नरक के समान हो गया है। मैं उदाहरण के लिए एक बात कहना चाहता हूँ, और वह बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिससे यह चीज स्पष्ट हो जाये कि आज पार्टीबन्दी किस सीमा तक पहुँच गई है। परसों हमारे कानपुर में एक बाक़या हुआ। हमारी पार्टी के एक खास वक्ता के घर में दूसरे पक्ष, अर्थात् कांग्रेस के कुछ लोगों ने रिवाल्वर रखवा दिया और पुलिस से उसके खिलाफ़ केस चलाने की बात सोची। उसके बाद जब मैंने दरोगा जी और सुपरिटेण्डेंट पुलिस से कहा कि चलाइए शुकदमा, तो उससे केस बाद मामला दबाया जा रहा है, और मुकदमा नहीं चल रहा है। कहा यह जा रहा है कि फलां आदमी ने इसको रख दिया, केस झूठा है। मैं यह इसलिए कह रहा हूँ कि माननीय मंत्री जी आज आप तो बहुत ऊपर उठ गए हैं इसलिये नीचे क्या हो रहा है इसका आपको पता नहीं। हम लोग जो मोहल्लों में रह रहे हैं, हम देखते हैं और महसूस करते हैं कि अगर ऐसे लोग जो यह काम कर रहे हैं कल वही अगर म्युनिसिपैलिटीज या असेम्बलियों में पहुँच जायें और हर तरह से अपने विरोधियों को दवाने की कोशिश करें, मैं यह बात कोई मंत्री जी के लिए नहीं कह रहा हूँ, मेरा मतलब यह है कि आज तो मंत्री जी जैसे आदमी इन कुत्तियों पर बैठे हुये हैं लेकिन कल अगर मेरे जैसे आदमी जो पार्टीबाज हैं वह मंत्री बन जायें और गौतम जी म्युनिसिपल बोर्ड के मेम्बर बन जायें उस वक्त मैं यह कहूँ कि गौतम जी ने यह गलत काम किया है और मुझ राजाराम शास्त्री मंत्री को पूरा अधिकार है कि गौतम जी ने गलत काम किया है इसलिए इनको निकाल दूँ। आप बताइए कि क्या यह मुनासिब होगा। हम पावर्स तो आपको देना चाहते हैं लेकिन यह चाहते हैं कि पावर्स आप इस तरह से लें कि आज जिस तरह से डेमोक्रेसी की वकिंग हमारे देश में हो रही है उसमें इस तरह से पावर्स लीजिए जिससे जो पावर को इस्तेमाल करने वाले लोग हैं उनके भी हाथ बंधे रहें। क्योंकि आज की डेमोक्रेसी में हम देख रहे हैं कि सारा संसार त्रस्त हो रहा है। सत्ता जैसे-जैसे केन्द्रित हो रही है वैसे-वैसे उसका दुरुपयोग हो रहा है। आजादी के नाम पर गुलामी लाई जा रही है। मैं चाहता हूँ कि आज जो सत्ता आप लखनऊ और दिल्ली में केन्द्रित कर रहे हैं उसको म्युनिसिपैलिटीज के अन्दर केन्द्रित कीजिए। अगर कोई उसमें गलत काम करता है तो मैं चाहता हूँ कि आप इलेक्टोरेट को अधिकार दीजिए, म्युनिसिपल बोर्ड को अधिकार दीजिए, उनसे कहिए कि तुम्हारा चेयरमैन या कोई सदस्य गलत काम करता है उसको निकालो। यह ठीक है और मैं इसका स्वागत करता हूँ। जिस तरह से समय निर्धारित कर दिया गया अधिक से अधिक दो साल और बढ़ाया गया। इस चीज की आवश्यकता थी। एक अनन्त काल तक समय बढ़ाते चला जाना ठीक नहीं था। मेरा विश्वास है कि ६ साल के बाद जनता की मौक़ा मिलेगा कि वह आवश्यक चीजों को कर सके। माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम इम्प्लॉयज (employees) के लिये कन्डक्ट रूल बना रहे हैं। जहाँ उनके कन्डक्ट का रूल बनाना जरूरी है उसके साथ यह भी कर सकें और घोषणा कर सकें तो हमारे सारे सूबे में राहत आयेंगी। जो सबसे अधिक असंतोष आज हमारे सरकारी विभाग में है वह लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है। चाहे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हो, चाहे म्युनिसिपैलिटी हो। इनके अध्यापकों को तीन-तीन और चार-चार महीने तक तनख्वाह नहीं मिलती है। साल भर में हर साल ऐसा होता है कि जब तक अध्यापक अनशन नहीं करता है, हड़ताल नहीं करता है तब तक उनको तनख्वाह नहीं मिलती है। आज लखनऊ में क्या हो रहा है, कानपुर में कितनी लड़ाई है। वहाँ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अध्यापकों को तनख्वाह तीन चार महीने से रुकी हुई है। जब आप चाहें, नियम बनायें तो हुकूमत पहले अपना कन्डक्ट दुरुस्त करे। ठीक समय पर उन लोगों को तनख्वाह मिलनी चाहिये। जब तक समय पर वेतन नहीं मिलता तब तक म्युनिसिपल बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अध्यापकों को लड़ाई खत्म नहीं होगी।

[श्री राजा राम शास्त्री]

जितना रुपया इकट्ठा होता है वह लखनऊ में चला आता है। आप कहते हैं कि म्युनिसिपल बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड अपना काम चलायें। जितनी आमदनी देहात में होती है उसका १/४ भाग डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को दीजिये। जब आप उनके हाथ में रुपया छोड़ देंगे तो शासन अच्छी तरह से हो सकता है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से कुछ कहा जाता है तो वह कहता है कि गवर्नमेंट को हमने लेटर लिखा है। गवर्नमेंट कहती है कि हमें इससे क्या वास्ता है। हमारे कर्मचारी अनुशासित हों और ठीक तरह से काम करें तो आपको डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के पास फंड छोड़ना होगा तो मैं चाहता हूँ कि माननीय स्वशासन मंत्री की अच्छी व्यवस्था स्वशासन की तभी होगी, जब कि आप उनके पास कुछ फंड छोड़ेंगे। म्युनिसिपैलिटी के प्रबन्धकों को तनखाह तब तक न बांटी जाय, जब तक कि तनखाह वहाँ के अध्यापकों को नहीं मिल जाती है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और म्युनिसिपल बोर्ड के जो सर्वेसर्वा हैं उनको ऐसा सोचना चाहिये कि जब तक हमारे डिस्ट्रिक्ट बोर्डों की व्यवस्था अच्छी नहीं हो जायगी तब तक हम अपनी तनखाह नहीं लेंगे। मैं चाहता हूँ कि इन बातों की तरफ ध्यान दिया जायेगा और सदन के अन्दर विचार किया जायेगा। मैं माननीय अध्यक्ष जी, आपके द्वारा मंत्री जी का ध्यान इस तरफ आकर्षित कराना चाहता हूँ कि यह मसला इतना सीधा नहीं है जितना कि वह सोचते हैं। मैं देखता हूँ कि इस भवन में बड़ी-बड़ी बातें मिनिस्टर लेकर आते हैं और हर एक यही कहता आता है कि बहुत सीधा सादा मसला है, बड़ा इन्फोसेंट मसला है, इसको पास कर दीजिए, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन जब उस पर विचार होने लगता है तो उसमें बहुत बड़ी-बड़ी बातें निकलती आती हैं। इसीलिये मैं अपील करूँगा कि मेरी बात मानी जाय और २, या ४ दिन की मोहलत इस पर विचार करने के लिये दी जाय, क्योंकि अगर ऐसा किया जाता है तो कोई चुनाव नहीं टले जाते हैं और हर मेम्बर को विचार करने का मौका भी मिल जाता है। इसलिये मैं आशा करता हूँ कि जो प्रस्ताव मैंने सदन के सामने रखा है उसको सदन स्वीकार करेगा, फिर यह भी बात है कि अगर यह मसला सेलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाता है तो इसका मतलब यह भी नहीं है कि यह रिजेक्ट किया जा रहा है। मुझे आशा है कि मेरा प्रस्ताव भवन पास करेगा।

श्री प्रताप चन्द्र आज़ाद—माननीय अध्यक्ष महोदय, इससे पहले कि मैं इस विधेयक के सम्बन्ध में कुछ अर्ज करूँ मैं उस प्रस्ताव के सम्बन्ध में जो कि इस विधेयक को नेक्स्ट कमेटी में दिये जाने के लिये पेश हुआ है, कुछ कहना चाहता हूँ। मैं श्री राजा राम शास्त्री की इस बात से इन्फाक करता हूँ कि यह बिल बहुत अहम है और उस पर विचार करने के लिये थोड़े समय का मौका होना चाहिये किन्तु दूसरी ओर जब हम यह देखते हैं कि म्युनिसिपैलिटीज का चुनाव बहुत असें से मुलतबी होता चला आया है और मैं समझता हूँ कि इससे बहुत दिन पहले ही म्युनिसिपैलिटीज का चुनाव हो जाना चाहिये था तो यह बिल अगर सेलेक्ट कमेटी को भेजा जाता है तो इसमें कोई सन्देह नहीं है कि चुनाव करने में काफी देर होने की संभावना है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के मिनिस्टर साहब ने अखबारों में ऐलान किया था कि उनकी यह योजना है कि फरवरी के अन्त तक म्युनिसिपल बोर्ड्स के चुनाव हो जायें तो उसके लिये मैं यह समझता हूँ कि अगर यह बिल सेलेक्ट कमेटी को जाता है और उसके बाद फिर दोनों हाउसेज में पास होने के लिये आता है तो फिर चुनाव शायद सन् ५३ में भी न हो सकेंगे। इसलिये मैं माननीय राजाराम जी से, जिन्होंने यह प्रस्ताव रखा है, यह निवेदन करूँगा कि वह इस प्रस्ताव को वापस ले लें।

जो बिल माननीय स्वशासन मंत्री जी ने पेश किया है उसके लिये मैं समझता हूँ कि वह बहुत महत्व पूर्ण है और यदि और के साथ इस अमेन्डमेंट को पढ़ा जाय तो इसमें कोई शक नहीं है कि इस विधेयक की बहुत सी बातें और बहुत से संशोधन ऐसे

हैं कि यह कहा जा सकता है कि इस अमंडमेंट के मानने के बाद, इस बिल को स्वीकार करने के बाद, म्यूनिसिपैलिटीज में काफी उन्नति होगी। सब से पहली चीज जो इस बिल में रखी गई है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है और वह यह है कि इम्पाशियल इलेक्शन और उसके सम्बन्ध में डाइरेक्टर आफ इलेक्शन को नियुक्ति की जो योजना इस बिल में रखी गई है, में समझता हूँ कि वह बहुत बड़ा अहम कदम है और उस योजना के लिये मेरा अपना विचार है कि वह गड़बड़ी, वह बुराईयाँ और वह खराबियाँ जो अक्सर इलेक्शन के सम्बन्ध में हो जाती थीं नहीं होंगी। वह इसलिये होती थीं कि म्यूनिसिपल बोर्ड के आदमी इलेक्टोरल रोल बनाते थे। जब वह तैयार हो जाती थीं तब कोई इलेक्शन आफिसर मुकर्रर होता था उसके पास न तो इतना समय होता था और न उसके पास कोई बिल्कुल समझी बूझी योजना ही होती थी। नतीजा यह होता था कि म्यूनिसिपल बोर्ड के आदमियों के द्वारा बनाये हुये इलेक्टोरल रोल के मुताबिक काम होता था और उसी के मुताबिक चुनाव कराया जाता था। इन रोलों में अधिकतर शहर के बाहर के आदमियों के नाम भी भर लिये जाते थे। जो मेम्बर उस वार्ड से खड़ा होता था वह हजारों आदमियों को जिनके नाम वार्ड में गलत भरे होते थे उनके द्वारा वोट डलवाया करते थे। इस तरीके से वह आदमी उस वार्ड से मेम्बर बन जाता था। इस बात को दूर करने के लिये एक आफिसर मुकर्रर कर दिया जायेगा।

दूसरी चीज जो इस बिल के अन्दर है वह यह है कि एक आदमी एक ही जगह से वोट दे सकता है। अभी तक म्यूनिसिपल बोर्ड में कोई ऐसा नियम नहीं था। एक आदमी जहाँ उसकी दूकान होती थी, वह वहाँ से भी मेम्बर हो सकता था और जहाँ उसका घर होता था, वहाँ से भी मेम्बर हो सकता था और इसी तरीके से वह ५-५, ६-६ जगहों से मेम्बर हो सकता था। वह वोट तो एक ही जगह से दे सकता था लेकिन मेम्बर वह कई-कई जगह से हो सकता था। वह व्यक्ति ८ या १० जगहों से वोट ले सकता था। जब तक कोई व्यक्ति उसके खिलाफ इस बात की दख्खास्त नहीं देता था कि इस व्यक्ति ने इतनी जगहों से वोट लिया है तब तक कोई उस पर आब्जेक्शन नहीं होता था। इसलिये यह भी बड़ी अहम चीज है कि एक आदमी एक ही जगह से नाम दर्ज कराये। जहाँ तक शिक्षा का सम्बन्ध है हमारे भाई ने कहा है कि मेट्रोकुलेशन रक्खा जाये। यह बात ठीक नहीं है। इसके सम्बन्ध में उन्होंने सलाह दी है कि जब नज़रियों के लिए शिक्षा की योग्यता नियत नहीं की गई है तब प्रेसीडेंट के लिये भी वह नियत नहीं होना चाहिये। जब मंत्रियों के लिये यह नहीं है कि वह इंट्रेस पास हों, तब प्रेसीडेंट के लिये भी नहीं होना चाहिये कि वह इंट्रेस पास ही हो। मुझे भारतवर्ष की किसी भी स्टेट की बात मालूम नहीं है जहाँ पर कि कोई ऐसा मिनिस्टर हो जो कि इंट्रेस पास न हो। हाँ, यह बात जरूर है कि विधान के अन्दर यह लिखा हुआ नहीं है कि मिनिस्टर का इंट्रेस पास होना जरूरी है। लेकिन किसी भी स्टेट के अन्दर कोई भी मिनिस्टर ऐसा नहीं है जो कि इंट्रेस पास न हो। हमको किसी बात के हेरफेर में न जाना चाहिये एक सच्चाई यह है कि अगर म्यूनिसिपल बोर्ड का चेयरमैन इंट्रेस पास नहीं है तो वह काम नहीं कर सकता है। अगर वह मेट्रोकुलेट नहीं है तो वह इक्जीक्यूटिव आफिसर के हाथ में खेलता है और सेक्रेटरी के हाथों में खेलता है। मैंने तो एक मसला भी सुना है कि किसी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के सेक्रेटरी ने वहाँ के चेयरमैन साहब के दस्तखत एक अंग्रेजी के लेटर में करवा दिये जिसमें लिखा कुछ था और बतलाया कुछ और ही। जब यहाँ यह चीज चलती है तो मैं यह समझता हूँ कि होना तो यह चाहिये था कि जो सिटी म्यूनिसिपल बोर्ड है जैसे लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, बनारस, आगरा, बरेली इत्यादि इनके लिये मेरा अपना ख्याल यह था कि इन सिटी म्यूनिसिपल बोर्ड का प्रेसीडेंट कम से कम प्रेजुएट होना चाहिए। क्योंकि इन शहरों में ऐसे बहुत से योग्य व्यक्ति मिल जायेंगे।

[श्री प्रताप चन्द्र ग्राजाव]

जहां की आबादी ३ लाख से ज्यादा है वहां का प्रेसीडेंट जो होगा वह मेरी अपनी राय से प्रेजुएंट होना चाहिए। इन सिटीज के अलावा जो दूसरे म्युनिसिपल बोर्ड हैं वहां पर कम से कम मैट्रिक लपज होना चाहिये। इसी ढंग से जो मेम्बर हैं उनके लिये यह होना चाहिए कि जो हिन्दी लिखना और पढ़ना जानते हों। मैं समझता हूँ कि यह निहायत आवश्यक चीज है। हर वक्त यह इलील पेश की जाती है कि असेम्बली और कौंसिल का मेम्बर तो अंगूठा लगाने वाला भी हो सकता है तो क्यों म्युनिसिपल बोर्ड के लिये ही ऐसा किया जा रहा है। यह बात इसलिये ठीक नहीं है क्योंकि असेम्बली और कौंसिल का जहां तक सम्बन्ध है वह तो वाइडर सेंस में हो सकता है कि वह अपनी कान्सटीट्यूएन्सी को ठीक ढंग से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं लेकिन म्युनिसिपल बोर्ड ऐसा स्थान है जहां पर लोगों के लोकल इन्टरेस्ट होते हैं और एक छोटा सा दायरा उसका होता है। उस दायरे से जो लोग चुन कर जाते हैं वह लोगों के छोटे छोटे इन्टरेस्ट की रक्षा कर सकते हैं ऐसी उनसे उम्मीद भी रखी जाती है कि वे लोग वहां जाकर हमारे इन्टरेस्ट की रक्षा करेंगे। जहां तक असेम्बली और कौंसिल का ताल्लुक है इसके लिये यदि हमारे विधान में रख दिया जाय कि अंगूठा लगाने वाला नहीं हो सकता तो मुझे उसकी भी मुश्कालिफत नहीं होगी। लेकिन यह कहना कि वहां पर भी यह बात नहीं है, इसलिये यहां भी नहीं होनी चाहिये, इसका मैं विरोध करता हूँ। इसके अलावा १, २ बातें विधेयक के अन्दर और हैं जो निहायत आवश्यक हैं। एक तो यह है कि जो असेम्बली के इलेक्टोरल रोल हैं वही म्युनिसिपल बोर्ड के लिये भी बनेंगे। असेम्बली के इलेक्टोरल रोल ऐसे होते हैं जो कि इम्पॉजिबल अथॉरिटी के जरिये बनाये जाते हैं। मैं समझता हूँ कि काफी ध्यान के बाद ये बनाये जाते हैं और लोगों को भी आब्जेक्शन करने का काफी मौका दिया जाता है। जो लोग इसमें होंगे उसके अलावा और भी हो सकते हैं। इससे साबित होता है कि बहुत कम तादाद में ऐसे लोग रह जायेंगे जिनके नाम म्युनिसिपल बोर्ड के इलेक्टोरल रोल में दर्ज न होंगे। अब तक ऐसा होता था कि जिस वार्ड का मेम्बर होता था यदि वह जान ले कि इस एरिया के आदमी मेरे खिलाफ हैं और मुझको वोट न देंगे तो वह उनका नाम उड़ा देता था और उस इलेक्टोरल रोल के अन्दर एक ग्रुप का ग्रुप नहीं होता था। लेकिन अब यह सम्भव नहीं है। यह तो वह दो तीन बातें थीं जो इसके अन्दर अच्छाई की हैं और जिनसे म्युनिसिपल बोर्ड्स के इलेक्शन होने के बाद म्युनिसिपल बोर्ड की काफी तरक्की हो सकती है। एक बात इसमें रिजर्वेशन आफ सीट्स फार शैड्यूल्ड कास्ट है। रिजर्वेशन के बारे में एक बात अर्ज करनी है और वह यह है कि रिजर्वेशन आफ सीट्स सन् ४८ में जो बिल बनाया उसमें भी रखा गया था लेकिन जो सेपरेट इलेक्टोरेट था वह खत्म कर दिया गया।

यह जो नया विधेयक है इस में जो रिजर्वेशन आफ सीट को खत्म किया गया है यह निहायत जरूरी है। मैं समझता हूँ कि इसको किसी भी हालत में रखना ठीक नहीं है। सन् १९४६ ई० में जो म्युनिसिपल ऐक्ट बना था उस में रिजर्वेशन आफ सीट की शुरुआत हुई थी। उसी वक्त इस का श्री गणेश हुआ था। मैं समझता हूँ कि अब इस तरह से सीट का रिजर्वेशन ठीक नहीं है। अब इसकी जरूरत नहीं है। चूंकि हमारे भारतवर्ष के संविधान के अनुसार यह परम्परा कायम की गई है। लिहाजा भारतवर्ष के स्वतंत्र होने के बाद इसको खत्म कर देना चाहिये। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप के द्वारा माननीय मंत्री जी के सामने इस सम्बन्ध में एक दो सुझाव और रखना चाहता हूँ। मेरी राय में इस बिल में सबसे बड़ी कमी यह है कि सन् १९१६ ई० में इस बिल के अन्दर कुछ योजना बड़े शहरों के लिए बनाई गई थी, उसके बाद सन् १९४८ ई० में भी कुछ योजना बनाई थी, लेकिन अब इसके अन्दर कोई विशेष योजना नहीं है। मैं समझता हूँ कि एक अच्छे ढंग से यह संशोधन यहां पर आना चाहिए था। माननीय मंत्री जी के अखबारों के वक्तव्य से मालूम होता है कि लखनऊ और कानपुर में एक कारपोरेशन की योजना बनायी जाय। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि इसके अलावा भी जो बड़े शहर हैं, जैसे बनारस, आगरा, इलाहाबाद और बरेली हैं,

उनमें भी यह योजना लागू होनी चाहिये। जिन शहरों की आबादी २ लाख और ४ लाख से अधिक हो, जें समझता हूं कि वहां पर यह कारपोरेशन की योजना कायम होनी चाहिए। इस के अलावा मैं यह भी अर्ज कर देना चाहता हूं कि इस विधेयक में सेविन सीटीज के बारे में कोई योजना नहीं रखी गई है।

दूसरी बात जो मैं अर्ज करना चाहता हूं वह यह है कि १५ और ५० की जो तादाद रखी गई है वह ठीक नहीं है। मेरा अपना सुझाव है कि जैसा कि सन् ४८ के ऐक्ट में था कि ज्यादा से ज्यादा ६० होनी चाहिए। मैं तो समझता हूं कि यह भी कम है। मेरा अपना विचार है कि कम से कम २० से लेकर ६० तक होनी चाहिए। यानी बड़े शहरों के अन्दर ६० और जो छोटे-छोटे शहर हैं उनके अन्दर २० की संख्या होनी चाहिए। अब मुझे डिप्लोमैटिकेशन के सम्बन्ध में कुछ अर्ज करना है। डिप्लोमैटिकेशन के सम्बन्ध में जितनी भी क्लॉज हैं, मैं उन सब से मुत्तफिक हूं लेकिन एक क्लॉज ऐसी है कि जिससे मुत्तफिक नहीं हूं इसमें एक क्लॉज ऐसी है कि जिसके अन्दर लिखा हुआ है कि वह आदमी वोट नहीं दे सकेगा या खड़ा नहीं हो सकेगा जो कि पुलिस कस्टडी में हो या जेल के अन्दर अन्दर ट्रायल हो, यह चीज मैं समझता हूं कि कुछ मुनासिब नहीं है। म्युनिसिपल बोर्ड के चुनाव के समय में या अन्य किसी चुनाव के समय में पार्टीज में आपस में मनमुटाव हो जाया करता है और पुलिस को प्रोकाशन के तौर पर उस आदमी को गिरफ्तार करना पड़ता है या कोई आदमी एक्सीडेंटली जेल चला जाता है किसी जुर्म के सिलसिले में, लेकिन उस आदमी का कथुर नहीं है और वह वैसे ही गिरफ्तार हुआ है और जब उसका ट्रायल हुआ तो वह बिल्कुल बेकसूर साबित हुआ और वह रिहा हो जाता है तो इस अमेडमेंट के जरिये उस आदमी को डिबार किया जाता है कि वह वोट न दे सके या चुनाव में खड़ा न हो सके। मैं तो समझता हूं कि इस के अन्दर इस चीज को रख दिया जाय कि जिस आदमी को किसी मामले में जेल हो गई हो तब तो वह वोट नहीं दे सकता, ठीक है। लेकिन कोई आदमी पुलिस कस्टडी में हो या जेल में अन्दर ट्रायल हो, वह वोट न दे सकेगा या खड़ा नहीं हो सकेगा, मैं समझता हूं कि यह मुनासिब नहीं होगा। मेरा माननीय मंत्री जी से यह सुझाव है कि इसपर पुनः विचार करें तो ज्यादा अच्छा हो।

नो कान्फीडेंस वोट का इस बिल के अन्दर संशोधन के द्वारा हेरफेर नहीं किया गया है। पहले जब कि प्रधान को मेम्बर ही चुना करते थे या जो भी प्रधान चुना जाता था वह मेम्बरों में से ही आपस में से चुन लिया करते थे उस समय तो यह प्रथा ठीक थी लेकिन अब जब कि प्रधान, बालिंग मताधिकार के आधार पर चुन कर आ जाय तब इतनी जल्दी और इतनी आसानी के साथ उसके खिलाफ नो कान्फीडेंस का प्रस्ताव आ जाय या पास हो जाय और वह निकाल दिया जाय, मैं समझता हूं कि यह ज्यादा मुनासिब नहीं है। एक मेम्बर असेम्बली का या कौंसिल का अपने क्षेत्र से चुन कर आता है वह अडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पर चुन कर आता है तो मैं यह समझता हूं कि उसके खिलाफ इस सदन के अन्दर या असेम्बली के अन्दर कोई ऐसा कानून नहीं है कि उसके खिलाफ नो कान्फीडेंस का मोशन पास कर दिया जायेगा और जब चेयरमैन भी बालिंग मताधिकार के आधार पर चुन कर आयेगा तो जो कोई भी उसको वोट देता है उसका पूरा कान्फीडेंस उसके ऊपर है और इसीलिये वे उसको चुनते हैं। लेकिन मेम्बर अगर किसी अन्य कारणों से चेयरमैन से नाराज हो जाय तो उसके खिलाफ नान कान्फीडेंस का मोशन से आते हैं और उसको निकाल दिया जाता है। मैं समझता हूं कि यह ठीक मालूम नहीं होता है। जहां तक मेम्बरों के सस्पेंश का सवाल है उसके बारे में थोड़ा सा कहूंगा और वह यह कि जैसा कि श्री राजाराम जी ने कहा कि उनको हटाने की प्रथा नहीं होनी चाहिये। इस बात से मैं मुत्तफिक नहीं हूं और वह इसलिये नहीं कि वह चाहे कितना ही बुरा करे, कितना ही इम्बेजेलमेंट हो वह वहां से न निकाला जाय उनके कहने का मतलब यह है कि उसको सर्टिफिकेट मिल जाता है कि ५ साल का जो टाइम है उसके अन्दर कोई उसको निकालने वाला न हो चाहे उनके दिल में

[श्री प्रताप चन्द्र आजाद]

कितनी ही बुराई हो, तो मैं इससे इतिफाक नहीं करता हूँ कि वह न हटायें जायें। अभी जैसा कि राजा रामजी ने कहा है कि अगर मेंबर नहीं हट सकते हैं तो उनकी हटाने की कोई गुन्जाइश नहीं होनी चाहिये।

मैं कहता हूँ कि हमारे सामने एक मेंबर होता है और उस मेंबर के मुतालिक यह मालूम हो जाता है कि उसके खिलाफ बड़े ग्रेव चार्ज हैं, तो उसके लिये जो हटाने का प्रावीजन है, वह मैं समझता हूँ कि ठीक है, लेकिन सब लोगों को यह मालूम हो जाता है कि फलों मेंबर या चैयरमैन ने यह इम्बेजलमेंट किया है, और इस तरह से खराबी की है, तो मैं समझता हूँ कि उसको उस वक्त तो हटा दिया जायेगा, लेकिन उसको हटाने से पहले ही सस्पेंड कर देना मैं समझता हूँ कि यह मनासिब नहीं है, इसलिये कि जनता ने उसको अपना प्रतिनिधि चुना है और जनता के प्रतिनिधि को भी आप उसी तरह से सस्पेंड कर देंगे जैसा कि गवर्नमेंट और आफिसरों को करती है, तो मैं समझता हूँ कि यह चीज उचित नहीं है। एक और चीज इसमें यह है कि लोगों को यदि यह मालूम हो जाये कि यह आदमी या प्रधान सस्पेंड है, तो मेंबरों या दूसरे लोगों में उसका बहुत खराब रेपुटेशन हो जायेगा और एलेक्शन की निगाह में उसकी रेपुटेशन खत्म हो जायेगी। इस तरह से जब वह दुबारा रिइन्स्टेट होता है, और वह फिर प्रेसीडेंट हो जाय, तो उसमें सिर्फ सवाल उसकी पहले वाली रेपुटेशन की ही है। इस तरह से सस्पेंड हो जाने से उसकी रेपुटेशन बिल्कुल खत्म हो जायेगी। इसलिये मैं समझता हूँ कि सस्पेंशन वाला क्लोज न तो मेंबरों के लिये होना चाहिये और न प्रेसीडेंट के लिये होना चाहिये। जहां तक एक्सटेंशन की चीज है, इस विषयक के अन्दर यह बात है कि म्युनिसिपैलिटी का टर्म ४ साल का होगा और इसके साथ ही साथ इसके क्लोज में यह भी है कि दो साल तक उसमें एक्सटेंशन हो सकता है। मैं समझता हूँ कि ये दो साल भी जोड़कर इस तरह से पूरे ६ साल हो जाते हैं और मेरे विचार से एक्सटेंशन एक ही साल का होना चाहिये। कुल मिलाकर ५ साल काफी हैं और एक साल से ज्यादा किसी भी तरीके से नहीं होना चाहिये। डिस्कवालिफिकेशन के संबंध में जो बात है तो उसमें एक जगह लिखा हुआ है कि करों का एरियर किसी पर है, तो वह आदमी न तो खड़ा हो सकता है और न वोट दे सकता है। मैं समझता हूँ कि आज बीसों प्रकार के टैक्स हैं, तो उनमें अक्सर ऐसा होता है कि आदमी अपील करता है और इस तरह से ६ महीने, साल भर या डेढ़ साल, उसमें लग जाता है, और इससे अगर यह कर दिया जाय कि फलों आदमी ने टैक्स नहीं दिया इसलिये वह एलेक्शन में खड़ा भी नहीं हो सकता है और वोट भी नहीं दे सकता है, यह मैं समझता हूँ कि ठीक नहीं है। यह होना चाहिये कि अगर किसी आदमी का टैक्स एरियर में म्युनिसिपैलिटी का हो, तो उसके लिये यह होना चाहिये कि खड़ा नहीं हो सकता है और यह चीज मेरे ख्याल से मनासिब भी है। एक चीज मैं आक्ट्राय के संबंध में अर्ज करना चाहता हूँ। उसमें जानवरों के संबंध में यह बात है कि अगर वह कहीं बाहर से म्युनिसिपैलिटी एरिया के अन्दर कंजम्पशन या सेल के वास्ते लाये जाते हैं, तो उनकी आक्ट्राय देना पड़ता है। मैं समझता हूँ कि यह क्लोज ज्यादा ठीक नहीं है। जानवरों में बहुत से छोटे जानवर ऐसे होते हैं जैसे कि भेड़ और बकरी और अगर देहात से कोई आदमी एक बकरी लाता है और उसमें एक आना या ६ पैसे रुपये के हिसाब से आक्ट्राय लगता है, तो मैं समझता हूँ कि यह चीज ज्यादा मनासिब नहीं है।

इस तरह जो जानवर देहात से शहर में आये उनसे आक्ट्राय नहीं लेनी चाहिये। मैं एक बात कह कर समाप्त करना चाहता हूँ। इसके अन्दर एक नया क्लोज बढ़ाया गया है वह यह कि म्युनिसिपैलिटीज की जो प्रोसीडिंग्स हैं उसके लिये यह रखा गया है कि उनको किसी हिन्दी के पेपर में छपवाना आवश्यक होगा। इस संबंध में अध्यक्ष महोदय, मैं आप की इजाजत से यह अर्ज करना चाहता हूँ कि जहां तक छपवाने का संबंध है मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन मैं यह समझता हूँ कि बहुत सी जगह उसका दुरुपयोग होता है कुछ अखबार ऐसे होते हैं जो किसी मेंबर के होते हैं और उसका काम यह होता है, कि वह प्रेसीडेंट और मेंबरों की बड़ाई ही

छापता रहता है और उसकी तारीफ़ छापता रहता है और वह अगर कोई गड़बड़ी करता है तो कभी आप उस पेपर में न पायेंगे। इस तरह से वह हज़ार या डेढ़ हज़ार रुपये की आमदनी कर लेता है। मेरा अपना विचार यह है कि उसके अन्दर यह शब्द रख दिये जायें कि प्रोसीडिंग्स उन अखबारों में छपनी चाहिये जो डी० एम० की ऐम्बेड लिस्ट में हों। जो पेपर अच्छी रट्टिंग के हैं और कोर्ट की नोटिस के लिये वह डी० एम० की ऐम्बेड लिस्ट में हैं उन्हीं में प्रोसीडिंग्स छपना चाहिये इसलिये मेरा विचार यह है कि जो-जो अखबार छोटे हैं और जिनका सरकुलेशन कम है उनमें प्रोसीडिंग्स नहीं छपना चाहिये। यह मेरा सुझाव था जो मैंने माननीय मंत्री जी की खिदमत में पेश किया। एक बात में और कहना चाहता हूँ वह यह कि इलेक्शन के संबंध में माननीय राजा राम जी ने यह बात कही कि आज कल जो इलेक्शन होते हैं अगर देखा जाय तो गरीबों और मजदूरों के लिये नहीं हैं और न वह धनी लोगों के मुकाबिले में फाइट आउट कर सकते हैं यह गरीबों के बूते के नहीं हैं। मैं उनकी इस बात से इतिहास नहीं करता हूँ आपने देखा कि पिछली दफा जब इलेक्शन हुये तो बड़े-बड़े राजा महाराजा नवाब व धनी और करोड़पति लोग छोटे-छोटे वालन्टियर्स के मुकाबिले में हार गये तो यह कहना मुनासिब नहीं है। इलेक्शन में वही आदमी जीतता है जिसके साथ पब्लिक ओपीनियन हो। मैं इन शब्दों के साथ इसका समर्थन करता हूँ।

*श्री निजामुद्दीन (स्थानीय संस्थाएँ निर्वाचन क्षेत्र)—माननीय चैयरमैन साहब, जो संशोधन मेरे दोस्त श्री राजा राम जी ने पेश किया है इस वक्त सदन के सामने मैं उसका विरोध करने के लिये और जो प्रस्ताव हमारे माननीय मंत्री जी ने यहां रखा है उसकी ताईद करने के लिये खड़ा हुआ हूँ और मेरा ख्याल है कि छुट्टी होने की वजह से उन्होंने इस अमेंडमेंट को पड़ा नहीं है अगर वह पड़े होते तो मेरा ख्याल है कि जो अमेंडमेंट उन्होंने यहां पेश किया है हरगिज पेश न करते। जो अमेंडमेंट इस वक्त मंत्री साहब ने माँके के लिहाज से रखा है वह इतना इन्नोसेंट है (innocent) कि उसमें कोई गुंजाइश ऐसी नहीं है जिसमें कोई संशोधन हो सके। शास्त्री साहब ने जो स्पीच यहां पर दी उससे खुद पता लगता है कि उन्होंने सिर्फ़ एक या दो बातों पर एतराज किया। एक तो म्युनिसिपैलिटी के चैयरमैन के रिमूवल के बारे में और दूसरे लेबर के बारे में कि लेबर का भी कोई रिप्रेजेंटेशन होना चाहिये। जहां तक म्युनिसिपैलिटी के प्रेसीडेंट के रिमूवल का ताल्लुक है मेरा ख्याल है कि इस की निस्वत जो कुछ उन्होंने कहा, माननीय मंत्री जी बगैरह की पावर पर आक्षेप था। मैं समझता हूँ कि अगर वह ग़ौर करेंगे तो शायद वह इस बात पर सहमत होंगे कि अगर कोई कंट्रोल किसी पर न हो, हर शख्स जैसा चाहे वैसा करता चला जायें, आपका रुपया भी ग़बन करता रहे और ५ वर्ष तक चैयरमैन भी बना रहे और आप उसे रिमूव भी न कर सकें तो यह निहायत बुरी चीज़ होगी। अगर किसी हेड आफ़ दि डिपार्टमेंट्स के कर्मचारी ऐसा काम करते हैं तो उन को निकाल दिया जाता है। अगर उन को निकाला न जाय तो कोई काम ही नहीं हो सकता। राजा राम जी ने सोचा कि कुछ न कुछ एतराज होना चाहिए, बस इसी ख्याल से कुछ एतराज कर दिया। वैसे शास्त्री जी ही बतायें कि उन्होंने कौन सी बात काबिले एतराज कही जिस की वजह से वह समझते हैं कि इसे सेलेक्ट कमेटी में भेजना जरूरी है। लेबर रिप्रेजेंटेशन के बारे में उन्होंने जो कुछ फरमाया, अब आप ही बतायें कि हज़ारों लेबर आर्गनाइज़ेशन्स हैं, किस को किस को रिप्रेजेंटेशन दिया जाय। निहायत इन्साफ़ के साथ बगैर किसी पक्षपात के निहायत अक्लमन्दी से गवर्नमेंट ने इस चीज़ को रखा है। स्पेशल इन्टरेस्ट जो थे, जैसे प्रोफेसर्स, डाक्टर्स वगैरह, उनको भी उन्होंने उड़ा दिया, महज इस ख्याल से कि अन्तरेस्ट न हो। इस से पता चलता है कि गवर्नमेंट कितनी इम्पार्शियल है। रह गया डिड्यूल कास्ट का मामला सो मैं समझता हूँ कि हर शख्स इस से सहमत होगा कि जो कोम बैकवर्ड है उसको उठाना चाहिये। इससे तो कोई शख्स एतराज नहीं कर सकता। मैं अर्ज करूंगा कि शास्त्री जी ने जो यह तरमीम दी है कि सेलेक्ट कमेटी में इसे भेज दिया जाये

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री निजामुद्दीन]

वहाँ से यह जल्द से जल्द पास किया जाये, जो साहबान म्युनिसिपैलिटीज में रहे हैं वह जान सकते हैं कि कितनी भी जल्दी की जाय, ५६ महीने तो लग ही जाते हैं। आप एक तरफ तो कहते हैं कि बहुत जल्दी इलेक्शन्स हो जाने चाहिये। दूसरी तरफ कहते हैं सेलेक्ट कमेटी में जाय। मैं इस बात को मानने के लिये तैयार हो जाता जैसा कि मंत्री साहब ने कहा कि हम फुल अमेंडमेंट लायेंगे, इसको ओवरहाल करने के लिये, अगर शास्त्री जी भी कुल बिल को ओवरहाल करने के लिये सेनेट कमेटी में भेजने के लिये कहते तो यह बात मानी जा सकती थी।

एडल्ट फ्रेन्चाइज करके तो वह हो जाता। माइनारिटीज के लिये भी रिजर्वेशन का प्रबन्ध किया गया है। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने इस सदन के सामने कहा। अगर आप उस शास्त्र को सतरेड नहीं करेंगे जिसने इम्बेजिलमेंट किया है और उसको आप रिमूव करना चाहें तो यह ठीक नहीं है। जिस डिपार्टमेंट में वह रहता है वहाँ पर जितने काम करने वाले होते हैं वे भी उसकी हेल्प करते हैं। वे बहुत से कागजात निकाल लेते हैं और दूसरे कागजात रख देते हैं। यदि आप उनको सस्पेंड नहीं करते तो जितने कागजात इम्बेजिलमेंट के होते हैं वहाँ पर वह फिर नहीं मिल सकते हैं। उस कागज को हटा दिया जाता है। जहाँ तक रिमूव का ताल्लुक है यह निहायत जरूरी चीज है। कोई आदमी आप के सामने चोरी करता है और उसको सजा नहीं दी जाती है तो जनता को नुकसान होगा। अगर आपको सजा नहीं दी जायेगी तो जनता का काम कैसे होगा। कंट्रोल के बगैर बुनिया में ठीक तरह से काम नहीं हो सकता है। आमतौर से म्युनिसिपैलिटी में ऐसा होता है कि अगर कहीं पर इम्बेजिलमेंट होता है तो इम्बेजिलमेंट करने वाले को सजा नहीं मिलती है। अभी माननीय मंत्री जी ने कहा है कि अभी वक्त नहीं है लेकिन जब वक्त मिलेगा तो म्युनिसिपल बोर्ड को ओवरहाल करने के लिये एक अमेंडमेंट लाया जायेगा उसके ऊपर आप सोच विचार कर सकते हैं और गवर्नमेंट को राय दे सकते हैं। मैं तो इस सदन से यही कहूँगा कि आप इस तजवीज को जो शास्त्री जी ने पेश किया है, रजेक्ट कर दें।

इस तजवीज से मेरे ह्याल से कोई खास मत्तसब हल नहीं होता है इसलिये मेरी राय में इसको रिजेक्ट हो जाना चाहिये।

चेयरमैन—अब कौंसिल २ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(कौंसिल १ बजे अवकाश के लिये स्थगित हुई और २ बजे डिप्टी चेयरमैन (श्री निजामुद्दीन) के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

श्री कुंवर गुरु नारायण—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस विषयक को अभी हमारे माननीय स्वशासन मंत्री ने इस भवन के सामने रक्खा है उसके संबंध में मैं अपने विचार रखना चाहता हूँ। अभी हमारे मित्र राजाराम शास्त्री जी ने उसके ऊपर यह संशोधन रक्खा कि यह बिल एक सेनेट कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाये। उसका भी मैं समर्थन करना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि जब पहिले म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट में संशोधन हुआ सन् ४८ में तो उसके बाद फिर उस समय संशोधन आया, तो बहुत सी चीजें ऐसी जरूर हैं जिनमें विचार होना आवश्यक है आफिशियल एडवाइज जहाँ तक थी, वह तो माननीय मंत्री जी को सेक्रेटेरियट से मिली हो, लेकिन इतिफाक ऐसा है कि अभी समय भी है, गालिबन आखिरी नवम्बर या शुरू दिसम्बर में जब असेम्बली का सेशन हो उसके पहिले इस भवन का सेलेक्ट कमेटी इस बिज पर विचार कर सकती है। अभी कोई ऐसी बात नहीं है कि यह सेलेक्ट कमेटी के सुपुर्द न किया जाये और मैं समझता हूँ कि जो राजाराम जी ने प्रस्ताव रक्खा है वह मुनासिब है और उसको मानने में कोई दुश्वारी नहीं होनी चाहिये।

जहाँ तक इस बिल का संबंध है श्रीमान्, मुझे यह कहने में संकोच नहीं है कि इस बिल के द्वारा बहुत सी अच्छी अच्छी बातें म्युनिसिपैलिटी के एडमिनिस्ट्रेशन में रक्खी गई हैं।

सबसे पहले इसमें जो स्ट्रेंथ थी बोर्ड की १५ से लेकर ८० तक हो सकती थी, उसमें ५० तक रक्खी गई है। मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा मेम्बर होने से पार्टिसिपेशन होता है और जहाँ तक पब्लिक रिज्रैजेशन का सवाल वह नो कम मेम्बर में भी हो जाता है। पचास मेम्बर होंगे तब भी पब्लिक रिज्रैजेशन आजायेगा, दूसरी बात जो है, वह है अप्वाइन्टमेंट आफ एकाउन्ट्स आफिसर्स का। एकाउन्ट्स आफिसर्स का अप्वाइन्टमेंट बहुत जरूरी है। म्युनिसिपल बोर्ड में काफी रुपये का गबन हुआ करता है और इस तरीके की बहुत सी बातें आई भी हैं। लेकिन अगर एकाउन्ट्स आफिसर्स हो जाते हैं तो इससे यह जरूर होगा कि जो बात रुपये पैसे के गबन की या इस तरह के व्यर्थ खर्च की चीज होगी वह दूर हो जाएंगी। लेकिन इसमें जो माननीयमंत्री जी ने रखा है वह शायद इस प्रकार रखा है कि ये एकाउन्ट्स आफिसर्स होंगे लेकिन लाजिमी नहीं होगा कि उनको अप्वाइन्ट किया जाय। यह भी हो सकता है कि इनका अप्वाइन्टमेंट न हो। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये एकाउन्ट्स आफिसर्स परमानेंट बेसिस पर इन म्युनिसिपल बोर्ड्स में अप्वाइन्ट किये जायें। इसके अतिरिक्त इसमें जो बोर्ड के एक्सटेंशन की बात रखी गई है वह भी ठीक है। अभी तक इनका एक्सटेंशन दया १० वर्ष तक होता चला जाता है जिसका परिणाम यह होता है कि इस प्रकार से जनता में असन्तोष होता है और ऐडमिनिस्ट्रेशन ढीला पड़ जाता है। यह ठीक नहीं था। अब इसमें रखा गया है कि एक्सटेंशन २ वर्ष से ज्यादा नहीं हो सकता। इसके माने होते हैं कि ६ वर्ष में अवश्य किसी भी बोर्ड का चुनाव हो जायेगा। इसके अतिरिक्त इस विधेयक में ऐडहाक कमेटी को अप्वाइन्ट करने की योजना की गई है। उसका भी मैं स्वागत करता हूँ और समझता हूँ कि म्युनिसिपल बोर्ड का मास्टर प्लान बनाने के लिये इसकी आवश्यकता है आज शहरों में यह होता है कि एक्सटेंशन की कोई स्कीम नहीं होती है, आज शहरों के लिये प्लान की आवश्यकता है? किसी भी शहर को लीजिये कन्जेशन होता चला जा रहा है। लोग सोचते हैं कि इतने से छोटे दायरे में किस तरह से एक मकान बनाया जाय। इसका नतीजा यह होता है कि उसका असर लोगों की हेल्थ पर पड़ता है जो शुद्ध वायु मिलनी चाहिये, वह नहीं मिलती है। ऐसी हालत में जब हम शहरों का, चाहे छोटे हों या बड़े उनका एक्सटेंशन करते हैं तो यह जरूरी है कि ऐडहाक कमेटी के जरिये सुझाव दिये जायें तो काफी रिफार्म हो सकता है। जहाँ तक इन चीजों का ताल्लुक है मैं तो समझता हूँ इस बिल का स्वागत करना चाहिए लेकिन एक बात में जरूर इस समय कहना चाहता हूँ। यह है कि जो बोर्डों में आपके एक्जीक्यूटिव आफिसर्स हुआ करते हैं उनको म्युनिसिपल बोर्ड के मातहत न रखा जाय। यह एक सुझाव मैं माननीय मंत्री जी के सामने रखता हूँ। म्युनिसिपल ऐडमिनिस्ट्रेटर को आप अप्वाइन्ट करें और इनके अप्वाइन्टमेंट तथा डिसमिसल की जिम्मेदारी सरकार पर हो। अगर एक्जीक्यूटिव आफिसर या म्युनिसिपल ऐडमिनिस्ट्रेटर का अप्वाइन्टमेंट इन बोर्ड के जरिये हुआ और बोर्ड के प्रति वे जिम्मेदार हुये तो वे आजादी और ईमानदारी के साथ काम नहीं कर पाते हैं जितना कि उन्हें करना चाहिए और इससे कम में भी नुकसान होता है। चाहे कोई भी सरकार हो और किसी भी पार्टी को हो वह पार्टी क्लिकशन को रोक नहीं सकती और वह होकर रहेगा। लेकिन अगर एक्जीक्यूटिव हेड प्रथक है और उसका अप्वाइन्टमेंट किसी बोर्ड के जिम्मे नहीं है तो वह ऐडमिनिस्ट्रेशन को ज्यादा अच्छा चला सकता है बमुक़ाबिले ऐसे एक्जीक्यूटिव आफिसर्स के, जो कि अपने अप्वाइन्टमेंट और डिसमिसल के लिये इन बोर्ड्स पर डिपेन्ड करते हैं। माना कि वह सरकार से अपील कर सकते हैं लेकिन फिर भी इतनी उनका हृदय में सही काम करने की हिम्मत नहीं पड़ सकती जब तक वे इन बोर्डों से प्रथक और स्वतंत्र नहीं। माननीय मंत्री जी ने उसमें एक चीज और रखी है वह यह कि प्रेसीडेंट का रिमूअल हो सकता है। माननीय मंत्री जी ने बताया

[श्री कुंवर गुरु नारायण]

कि यदि किसी प्रेसीडेंट के खिलाफ चार्जेंज हों तो उसके रिमूवल का सवाल होगा। अब जो इस बिल में धारा रखी गई, उस धारा के अनुसार तो कोई चारा ही नहीं है। आप वाणिग नहीं दे सकते हैं। वह प्रेसीडेंट अपनी जगह से फौरन हटाया जा सकता है। मैं समझता हूँ कि एक्स्ट्रेड प्रेसीडेंट के लिए यह मुनासिब और उचित चीज नहीं है कि आप उसको इस प्रकार से हटा दें और उसको मौका भी न दें। जहां तक वाणिग में मौका देने का सम्बन्ध है यह सरकार के हाथ की चीज है। हम उसको महीना, दो महीना या १५ दिन का मौका दे सकते हैं। लेकिन उसको बिल्कुल मौका न दें और एक दम डिसमिस कर दें यह चीज उचित नहीं है। इसके अलावा मैं अपनी जगह पर समझता हूँ और ईमानदारी के साथ समझता हूँ, मुमकिन है कि हमारे बहुत से साथी इससे इतफाक न करते हों कि इसमें कोई न कोई प्राविजन वाणिग का चाहिए।

इसके अतिरिक्त एक और बात जो मैं कहना चाहता हूँ वह यह है कि आज जो म्युनिसिपैलिटीज में खराबियां पैदा हो गई हैं वह इसी कारण से हो गई हैं कि पालिटिक्स की चीजें म्युनिसिपल बोर्ड में चलने लगी हैं। सिविकसेन्स और सर्विस का भाव तो बिल्कुल जाता रहा है। मैं तो यहां तक कहता हूँ कि अगर उसमें कोई पोलिटिकल पार्टी का मेम्बर है तो आप उसको इन जगहों के चुनाव से अलग कर दें। इससे म्युनिसिपल बोर्ड का सुधार हो जायगा और जो इसमें खराबियां हैं वह दूर हो जायेंगी। जब लोगों में पार्टी बन्दी का भाव पैदा हो जाता है तो इसका नतीजा यह होता है कि जो सर्विस का दृष्टिकोण होता है वह जाता रहता है। मैंने अपना संशोधन रखा है कि कोई भी पोलिटिकल पार्टी का आदमी म्युनिसिपल बोर्ड में नहीं आना चाहिये। इसके साथ ही साथ मैं यह भी चाहता हूँ कि इसमें यह भी रखा जाय कि लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट का मेम्बर या असेम्बली का मेम्बर इसका प्रेसीडेंट नहीं हो सकता है। लेजिस्लेचर के मेम्बर म्युनिसिपल बोर्ड में जाते हैं और नतीजा यह होता है कि वहां पर भी पालिटिक्स पैदा करते हैं। इसके अलावा उनको अवकाश भी कम मिलता है। जितना अवकाश उनको मिलना चाहिये उतना नहीं मिलता है। एक बात यह भी रखी गई है कि इस विधेयक में कि कम से कम हाई स्कूल तक प्रेसीडेंट के चुनाव के लिये हर व्यक्ति को पास होना चाहिये। मुझे ताज्जुब हुआ जब इस प्रकार कहा गया कि इस विधेयक में माननीय मंत्री की संज्ञा यह है कि हम ऐसे आदमियों को चाहते हैं जो कम से कम कुछ समझ सकें और वह किसी का शिकार न बन सकें। लेकिन उसके उदाहरण में जो दलील माननीय मंत्री ने दी है उसमें मुझे और भी आश्चर्य हुआ। उन्होंने यह कहा कि जहां तक लेजिस्लेचर का सम्बन्ध है वहां पर अगर बेपढ़े हो जायें तो वहां भी काम चल सकता है। पर इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि यहां पर पढ़े लिखे होंगे। अभी जैसा कि मेरे भाई राजाराम जी ने कहा कि प्रेसीडेंट आफ इंडिया जो है उसके लिये आज कोई कैंद नहीं है। मैं तो यह कहता हूँ कि यह डेमोक्रेसी की ब्यूटी है कि आप जनता के कामनसेंस पर चुनाव छोड़ दें, जो डेमोक्रेटिक मेथड्स में चुनाव होता है, उसकी खूबसूरती यही है कि जनता को चुनने का हक है और जनता के कामनसेंस की परीक्षा है कि वह किसे इस जगह पर भेजना चाहती है। अब रही यह बात कि वह मैट्रिक्यूलेट हो या न हो तो अगर मैट्रिक्यूलेट हुआ और अक्वल नम्बर का बेईमान हुआ तो उसमें कोई फायदा नहीं है। मैं तो उस बेपढ़े को बेहद अच्छा समझता हूँ जो कि ईमानदारी से काम करता है और अपने कर्तव्य को अच्छी तरह से समझता है। बजाय इसके कि वह पढ़ा लिखा हो और अक्वल नम्बर का बेईमान हो।

श्री मोहन लाल गौतम—इससे किसको मतभेद है ?

श्री कुंवर गुरु नारायण—यही मैं कह रहा हूँ। उसमें जो आपने रक्खा कि मैट्रिक्यूलेट होना चाहिये तो उसके माने तो यह है कि आपने जो समाज का राइट था उसको उससे वंचित कर दिया। एक तरफ तो आपने जनता को अधिकार दिया और दूसरी तरफ आपने जनता से वह अधिकार छीन लिया तो यह कोई उचित बात नहीं है। थोड़ी देर के लिये मान लिया जाय और मैं भी मानता हूँ कि हमारे देश में इतने लोग शिक्षित नहीं हैं जितने कि होने चाहिये तो मैं यह कहता हूँ कि इस कमी का उत्तर-दायित्व सरकार के ऊपर है। हमारी स्थिति ऐसी नहीं है कि इतने लोगों को जल्दी से जल्दी शिक्षित कर सकें तो इसके लिये अगर हम लोगों को आज जल्दी से जल्दी शिक्षा नहीं दे पाते हैं और लोग ऐसे हैं कि जो बिना पढ़े ही सार्वजनिक कामों में अपना कार्य संचालन अच्छी तरह से कर सकते हैं तो कोई वजह नहीं है कि उसको इस चीज से डिप्राइव किया जाय। इसलिये मैं इस धारा का विरोध करता हूँ। इसके अलावा अगर किसी की यह राय हो सकती है कि वह मैट्रिक्यूलेट होने चाहिये तो किसी की राय यह भी हो सकती है कि वह मिडिल ही हो तो यह ऐसी चीज है जो विवाद की है और प्रजातन्त्र के उसूल में नहीं आती है। आप ऐडल्ट फ्रॉचवाइज करते हैं तो उसमें हर शख्स को आपको अधिकार देना चाहिये और जनता अवश्य ही इस बात को महसूस करती है कि वह ऐसे लोगों को ही चुनेगी जो उस काम के काबिल होंगे चाहे वह शिक्षित हों या नहीं। फिर इसके लिये कोई क्वालिफिकेशन शिक्षा का मुक़रर करना कुछ उचित नहीं है।

अब यह जरूरी है कि सबसे बड़ी चीज जो हम लोगों को कन्सीडर करनी होगी वह यह कि हम हर तरफ से इम्प्रूवमेंट तो चाहते हैं कि म्युनिसिपल बोर्ड में हर तरफ से इम्प्रूवमेंट हो लेकिन जब तक इनके फाइनेंस ज़रूरत नहीं होंगे तब तक कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता है। मैं जानता हूँ कि म्युनिसिपल बोर्ड्स और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को आज क्या हालत है डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का तो चेयरमैन रहने का इतिफ़ाक मुझे भी १०, १२ साल तक रहा है और मैं कह सकता हूँ कि कोई भी डेवलपमेंट स्कीम का कार्य किसी भी बोर्ड में नहीं हो सकता है चाहे वह म्युनिसिपल बोर्ड हो और चाहे वह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हो जबतक कि उसके फाइनेंस की मजबूती नहीं होती है। बहरहाल सरकार टेक्स से ज़रिये से अपने पास रुपया लेती है तो यह बात आपको ज़रूर करना होगा और निष्पक्षता के साथ आपको सोचना होगा कि आप क्या तरीका इस सम्बन्ध में अख्तियार करना चाहते हैं। मसलन गवर्नमेंट का एक रेवेन्यू है जेंसे कि ट्रांसपोर्ट है। नेशनलाइजेशन आफ ट्रांसपोर्ट सरकार ने कर दिया तो इसकी रेवेन्यू म्युनिसिपैलिटीज को जो मिलती वह न मिलेगी, इसी प्रकार के और अनेकों ज़रिये थे वह स्वयं सरकार ने अपना लिये हैं। तो जब तक सही तरीके से और गम्भीरता के साथ इन प्रश्नों पर विचार नहीं किया जाता तब तक लाखों रीफार्म आप करें, वह बिल्कुल अधूरा रह जायेगा, अगर म्युनिसिपल बोर्ड के अन्दर पैसा नहीं है। मुझे आज बड़ा आश्चर्य हुआ जब मैंने श्री राजाराम जी की स्पीच सुनी कि लेबर को रिजर्वेशन दिया जाय और उनका भी रिजर्वेशन हो। मैं आज तक यह समझता था कि जो सिद्धान्त उनके दल के हैं और जिन पार्टीज का वह संचालन करते हैं, तो उससे वे रिजर्वेशन द्वारा पैदा किये गये भेद को बिल्कुल ही हटा देंगे लेकिन जब उन्होंने कहा कि लेबर का रिजर्वेशन हो, तो मुझे आश्चर्य हुआ जब कि आज मैं समझता हूँ कि लेबर का रिजर्वेशन जरूरी नहीं है। हम आज जब सब रिजर्वेशन को हटा रहे हैं और सिर्फ शेड्यूल्ड कास्ट्स के रिजर्वेशन को रख रहे हैं, वह भी इसलिये कि हमारे कान्स्टिट्यूशन में यह है कि १५ साल तक उनको इस तरह फेसिलिटी मिलेगी तो उनके लिये हमें ऐसा करना चाहिये। लेकिन लेबर के रिजर्वेशन का कोई सवाल नहीं है क्योंकि इस समय लेबर के पास जितने ज्यादा वोट हैं, उतने और किसी के पास नहीं हैं।

[श्री कुंवर गुरु नारायण]

तो अब उसूलो तौर पर जैसा कि कहा गया कि उनके लिये रिजर्वेशन हो, तो इसमें मुझे आश्चर्य हुआ और यह बात राजारामजी के मुख से निकली कि लेबर के लिये रिजर्वेशन हो और वह भी उसूलो तौर पर, तो मुझे और भी आश्चर्य हुआ। अब तो कोआप्शन प्रथा हटा दी गई है। इसकी कोई जरूरत नहीं है कि किसी के लिये भी इसमें रिजर्वेशन रखा जाय।

इसके अलावा इस विधेयक के द्वारा म्युनिसिपैलिटीज के एम्पलाइज के सम्बन्ध में रूल बनाये जायेंगे जिससे कि उनके स्टैंडर्ड और सेलेरी यानी पे (pay) में जो आज कमी है और फर्क है, वह खत्म हो जायगा और इस तरह से उसको ठीक किया जायेगा, तो इस चीज का तो हम सभी को स्वागत करना चाहिये। मैं इस विधेयक की जनरल बातों का तो हृदय से स्वागत करता हूँ लेकिन जो कुछ बातें और सुझाव मैंने यहां पर रखे हैं, मैं आशा करता हूँ कि माननीय मंत्री जी उन पर गौर करेंगे और यदि इसके लिये सेलेक्ट कमेटी में गौर होता तो और भी अच्छी बात थी। सेलेक्ट कमेटी में विचार करने के बाद इस पर और भी संशोधन हो जाते। इस तरह से दिसम्बर में जब आप सेशन करते और असेम्बली मीट करती तो फिर और भी इम्प्रूवमेंट के साथ इसको लिया जा सकता था। फिर भी मैं आशा करता हूँ कि जो चीजें मैंने रखी हैं उन पर अवश्य विचार किया जायगा। एक चीज दुबारा जो मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ और वह यह है कि हर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जो एम्प्लॉय किया जाय तो उनका एम्प्लॉयमेंट और डिसमिसल सरकार के हाथ में हो और यह म्युनिसिपल बोर्ड को नहीं देना चाहिये। अगर आप ऐसा करेंगे तभी म्युनिसिपल डिपार्टमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन सुधरेगा, नहीं तो उसमें हमेशा पार्टी फ्रिक्शन रहेगा।

दूसरी बात जो मैं और कहना चाहता हूँ वह यह है कि इन बोर्डों से राजनैतिक पार्टियों को अलग रहना चाहिये। राजनैतिक पार्टियों से बहुत सी खराबियां पैदा हो जाती हैं। अगर इस चीज की पाबन्दी रहेगी तो म्युनिसिपल बोर्ड में जो सिविक सेंस की भावना है, वह आयेगी और तभी उनका सुधार हो सकेगा। यद्यपि विलायत में ऐसी चीज नहीं है, वहां राजनैतिक पार्टियां इलेक्शन लड़ती हैं इन बोर्डों में भी। पर वहां का जो स्टैंडर्ड है और वहां का जो डिसिप्लिन है, वह दूसरा है। हमारे देश में यह चीज अभी उतनी डेवलप नहीं हुई है जितनी कि वहां के लोगों में डेवलप है। वहां का जो तरीका, जो स्टैंडर्ड है वह हमारे देश के लोगों का नहीं है और यह भी है कि हम कम से कम १० या १५ साल तक उस स्टैंडर्ड को ऊंचा भी नहीं उठा सकते हैं, इसलिये मैं यह कहता हूँ कि पोलिटिकल पार्टीज पर बैन (ban) कर दिया जाय और असेम्बली और पार्लियामेंट के मेम्बर को म्युनिसिपल बाडीज से अलग रक्खा जाय और उनको कोई हक, इन म्युनिसिपल बोर्डों में घुसने का न रहे, वरना कोई फायदा तो होगा नहीं और नुकसान अधिक हो सकता है। इन शब्दों के साथ मैं अपने विचार इस विधेयक पर रखता हूँ।

* श्री प्रभुनारायण सिंह (स्थानीय संस्थाएँ निर्वाचन क्षेत्र) — माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो म्युनिसिपल असेम्बलेंट बिल इस समय सदन के सामने है और उसके सम्बन्ध में जो संशोधन माननीय राजाराम जी ने पेश किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूँ कि इस बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाय। पहली बात इस बिल के सिलसिले में यह कही गई है कि जो इस बिल को पेश करते समय माननीय मंत्री जी ने कही है और यह माना है कि यह बिल खासतौर से इसलिये लाया गया है कि इलेक्शन हुये बहुत

* सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

दिन हो चुके हैं और उसको जल्द कराया जाय। इस सिलसिले में उन्होंने यह भी कहा कि लोकल बाडीज के सम्बन्ध में ओरियन्टेशन का भी सवाल है। इसे मैं सहसूस करता हूँ। आज जो बिल इस सदन में लाया जाता है उसको जल्दबाजी के नाम पर किसी तरीके से कहा जाता है कि इसको जल्दी पास करना चाहिये और इसके लिये यह वजह है। उस समय विव्क्त सदन की यह हो जाती है कि सदन क्या करे। इलेक्शन का जहाँ तक सवाल है तो सन् १९४५ में म्युनिसिपैलिटीज के इलेक्शन हुये और आज सात साल गुजर गये, सही बात है। कोई इस बात को कह कर जिम्मेदारी नहीं ले सकता है कि हमारी वजह से यह इलेक्शन टाला जाय। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से और सरकार से यह जानना चाहूंगा कि जब १९३७ में कांग्रेस की सरकार बनी उसने सन् १९३८ में एक कमेटी बिठाई जिसके सामने यह पहलू था कि लोकल बाडीज के सिलसिले में क्या किया जाय, स्वायत्त शासन का स्कोप कितना बढ़ाया जाय उसके फाइनैलेज और सविसेज के बारे में क्या किया जाय इसके लिये एक कमेटी बिठाई गई थी जिसके अन्दर इस सदन के माननीय अध्यक्ष महोदय और विधान सभा के माननीय स्पीकर साहब और अन्य माननीय सदस्य भी थे। उसकी रिपोर्ट शायद होकर हमारे सामने मौजूद है। वह पूरी रिपोर्ट कि लोकल बाडीज के सम्बन्ध में क्या होना चाहिये और उसका स्कोप क्या होना चाहिये, फाइनैलेज और सविसेज के बारे में क्या दृष्टिकोण हो, वह रिपोर्ट हमारे सामने है। मैं समझता हूँ कि सन् १९३८ में सरकार ने कमेटी बिठाई थी और सन् १९४६ में दूसरी सरकार आई और वह भी वही कांग्रेस की सरकार आई जो सन् ३७ में थी। सन् ४८ में एक बिल आता है इलेक्शन कराने के लिये छोटे-मोटे अमेंडमेंट के साथ। मैं क्या जान सकता हूँ कि जब रिपोर्ट कमेटी के सामने थी उसके बाद सन् ४६ से लेकर ५२ तक सरकार क्यों बैठी रही और आज कहा जाता है कि इलेक्शन जल्दी होना चाहिये। मैं तो घबराता हूँ अगर मैं कहूँ कि इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाय तो फौरन कहा जा सकता है कि विरोधी पक्ष वालों ने कहा है कि सेलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाय और इसी लिये इलेक्शन पोस्टपोन कर दिये गये हैं। हमारे सामने यह चीज आती है कि जब ४६ से ५२ तक आपकी हुकूमत रही और कमेटी की रिपोर्ट भी रही और सन् ४८ में एक अमेंडमेंट होता है तो उसके बाद पूरा बिल हमारे सामने क्यों नहीं आया?

दूसरी बात यह कहना है कि सन् १९४८ में बिल के अन्दर अमेंडमेंट किया गया था, उस वक्त इलेक्शन नहीं कराये गये थे तो क्या उपाध्यक्ष महोदय, यह समझा जाये कि जो पार्टी पावर में है उसे यह खतरा था कि अगर लोकल बाडीज का चुनाव करा दिया जाता है और उसमें हमारी हार होती है तो जनरल इलेक्शन पर भी असर पड़ेगा, और आज इसलिये इलेक्शन कराने की बात होती है कि चूँकि एलेक्शन में हमारी जीत हो गई है। फरवरी और मार्च में जो चुनाव हों, मैं नहीं चाहता कि उसकी तारीख किसी तरह से बढ़े। हमें खुशी है, उपाध्यक्ष महोदय, कि हमारे नये मंत्री जी, जिन्होंने इस कार्य को सम्हाला है, उन्होंने इस बात की घोषणा की है कि अधिक से अधिक मार्च सेशन के बाद अप्रैल-मई में लोकल बाडीज के चुनाव हो जावेंगे। मैं समझता हूँ कि राजाराम जी ने जो संशोधन रखा है कि इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाये बहुत ही उचित है। अभी असेम्बली के होने में २०-२५ दिन का मौका है। २०-२५ रोज इस बिल को बनाये जाने में लग सकते हैं एक कमेटी पहले ही इस मसले पर अपनी राय जाहिर कर चुकी है। हमारे नये देश के अन्दर जो असेम्बली चुन कर आई है उससे एक ऐसा बिल जाना चाहिए जो स्वायत्त शासन में एक तब्दीली पैदा कर सके।

आज जो कानून बना हुआ है वह सन् १९१६, २०, २२ का है जब कि ब्रिटिश हुकूमत हमारे यहां बैठी थी। उपाध्यक्ष महोदय, आज हमें यह सहसूस होने लगा है कि यदि इलेक्शन

[श्री प्रभु नारायण सिंह]

में सरकार हार जाती है तो नया बिल, जिसके लिये वादा किया जा रहा है, सरकार उसे लायेगी या नहीं, इस विषय में संदेह पैदा होने लगा है। इस कमेटी की रिपोर्ट अगर लागू हो जाये तो आज हमारी लोकल बाडीज का नक्शा ही बदल सकता है। सन् १९३८ की बनी हुई कमेटी की रिपोर्ट पर आज तक कार्यवाही क्यों नहीं की गई और आज इस मौके पर यह कहना कि चूंकि हम को इलेक्शनस जल्द कराने हैं, इसलिये इसको पास कर दिया जाये फिर इसके बाद पूरा बिल लायेंगे, यह बात मेरी समझ में नहीं आती। अभी असेम्बली के बैठने में २०-२५ दिन का मौका है इस अर्थ में आप दूसरा बिल तैयार कर सकते हैं इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजकर इस पर विचार-विनिमय हो सकता है। सेलेक्ट कमेटी में भेजने से इसकी विककतें दूर की जा सकती हैं और एक ऐसा नया बिल सामने लाया जा सकता है जिससे नई दिशा में हम कदम उठा सकें। आज जिस हालत में हमारी लोकल बाडीज हैं वह बहुत अच्छी हालत नहीं कही जा सकती। आज इसलिये लोकल बाडीज की हालत अच्छी नहीं है कि इनीशिएटिव लोकल बाडीज के हाथ में नहीं है। हम यह मानते हैं कि जो पुराना ऐक्ट है उससे किसी भी हालत में यह अच्छी तरह से नहीं चलाई जा सकती। इस कमेटी की रिपोर्ट में यह बात साफ तौर से लिखी हुई है जिसे में पढ़ देना चाहता हूँ:—

The functions at present prescribed for district and municipal boards are in our opinion inadequate. To make a full success of local self-Government we have, therefore, suggested a considerable extension in the scope of activities of these local bodies, including the making of provisions for the administration of Civil and Criminal Justice within municipal limits and at the district and tahsil headquarters and the maintenance of a police force. It may be that our proposals may sound alarming to those who have been used to thinking that the scope of local self-Government is confined only to such matters as education, public health, roads, watersupply, sanitation and lighting.

कहने का मतलब यह है कि आज यह कमेटी भी महसूस करती है कि जिस तरह के फंक्शन लोकल बाडीज के हैं उनसे इनीशिएटिव नहीं पैदा हो सकता। हम ऐसी डिसेन्ट्रलाइज्ड लोकल बाडीज का स्वप्न देखते हैं जिसमें कि सत्ता केवल लखनऊ और दिल्ली में ही केन्द्रित न होकर उसकी यूनिट्स डिस्ट्रिक्ट बोर्ड या म्युनिसिपैलिटीज में होंगी।

में इस बात को समझता हूँ और यदि आप चाहते हैं कि लोकल मामले और स्थानीय मामले म्युनिसिपैलिटी द्वारा हों तो म्युनिसिपैलिटी को पूरा हक मिलना चाहिये। म्युनिसिपल बोर्ड के काम को चलाने के सिलसिले में जितने फाइनेंस की जरूरत हो तो उस फाइनेंस का पूरा प्रबन्ध होना चाहिये। हम देखते हैं कि उस कमेटी ने रिपोर्ट दी कि सेल्स टैक्स का प्रबन्ध म्युनिसिपैलिटी के हाथ में जाना चाहिये। लेकिन आज सेल्स टैक्स के प्रभुत्व को प्राविशियल सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है। आज प्राविशियल गवर्नमेंट और म्युनिसिपल बोर्ड जो हैं उनका ताल्लुक बतलाया जाता है। इसमें प्राविशियल गवर्नमेंट और म्युनिसिपल बोर्ड का कोऑर्डिनेशन रह जाता है। इस तरह से प्राविशियल गवर्नमेंट लोकल बाडीज को ले सकती है इसके सिलसिले में एक कमेटी ने एक बात सुझाई कि लोकल सेल्फ बोर्ड बनना चाहिये। उसमें कोई परमानेंट चेयरमैन न हो, उसमें लोकल बाडीज यूनियन से चुने हुये सात या आठ प्रतिनिधि आयें और एक एक्सपर्ट हों। इस तरह से वे तमाम लोग उसको सुपरवाइज करें। इस लोकल बाडीज का एक नया बिल हो।

जहां तक सेंट्रलाइजेशन की बात है, वहां तक ठीक है। जहां पर पावर डिसेन्ट्रलाइज्ड करने की बात है वहां पर ठीक नहीं है। एक विद्वान ने लिखा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की टेंडेंसी है वह सेंट्रलाइजेशन के ऊपर है। वह ज्यादा से ज्यादा प्राविशियल मामलों में हस्तक्षेप

करना चाहती है। इस हालत में जो बिल सदन के सामने पेश है और उसमें जो बातें लखनऊ के सिलसिले में हैं उसमें दो रायें नहीं हो सकती हैं। लेकिन एक ऐसा मसला है जिस पर दो रायें हो सकती हैं। इसी के साथ साथ इस बिल के प्रभुत्व को बढ़ाने के लिये, कि लोकल बाडीज अच्छी तरह से काम करें, यह आवश्यक है कि यह सवाल सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाय। अभी २५-३० दिन का मौका है इसके बाद लेजिस्लेटिव असेम्बली की बैठक होने जा रही है। इस पर गौर किया जाय तो ज्यादा अच्छा हो सकता है। इन शब्दों के साथ जो बिल सदन के सामने है मैं उसके मेरिट और डीमेरिट के संबंध में न जाकर, मैं उपाध्यक्ष महोदय, आप के जरिये माननीय मेम्बरों से और माननीय मंत्री जी के जरिये सरकार से इस्तुआ करना चाहता हूँ कि यदि लोकल बाडीज के संबंध में ऐसी पार्टीकुलर बात का कोई कारण नहीं है और जबकि इसके पास कुछ मसाले मौजूद हैं तो आप सेलेक्ट कमेटी की मीटिंग बुलाकर एक नया बिल लायें, जिससे एक नयी जिन्दगी की लहर तमाम शहरों में लाई जा सके।

*श्री सभापति उपाध्याय (नाम निर्देशित)—जो माननीय मंत्री जी ने बिल उपस्थित किया मैं उसका समर्थन करता हूँ। इसके विषय में माननीय सदस्य श्री कुंवर गुरु नारायण ने जो सुझाव रखा है मैं उसका भी समर्थन करता हूँ। मैं भी देखता हूँ कि म्युनिसिपल बोर्ड में पार्टीबन्दी रहती है जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा कि प्रेसीडेंट को मैट्रीकुलेट होना चाहिये, तो यह भी ठीक है। राज्य में क्या हो रहा है उसका निरीक्षण मेम्बर नहीं करते हैं, इसलिये सदस्यों का कर्तव्य होना चाहिये कि वे अपने सारे क्षेत्र की पूरी तरह से जानकारी रखें। यह काम हो सकता है सदस्यों के चुनाव से। जब तक उनके ऊपर कोई निरीक्षण नहीं होगा कि हमारे म्युनिसिपल बोर्ड में क्या काम होता है जब तक उसकी नहीं देखभाल हो सकती है। उसका निरीक्षण सरकार की तरफ से होना चाहिये।

श्री (हकीम) ब्रजलाल वर्मन—माननीय उपाध्यक्ष जी, बहुत काफी से ज्यादा अर्से गुजरने के बाद म्युनिसिपैलिटियों के चुनाव के संबंध में जो प्रस्ताव माननीय मंत्री जी किया है मैं उसका खैरमुकद्दम करता हूँ। इसमें और ताखीर करने से बहुत बेचैनी फैल जाती है लेकिन जैसा कि हमारे कुछ मित्रों की तरफ से यह सुझाव रखा गया है कि इसको सेलेक्ट कमेटी में भेज दिया जावे तो मेरा इस संबंध में एक सुझाव है अगर यह मंजूर कर लिया जाये तो दोनों रास्ते ठीक हो जायेंगे। यानी यह कि इलेक्शन का ताल्लुक जिन धाराओं से है वह तो इसी सेशन में पास कर ली जायें। प्लानिंग एकाउन्ट के संबंध में धाराएं पास करने के बाद और जो चीजें हैं उनको जब माननीय मंत्री विस्तृत बिल लायेंगे उस समय के लिये मुल्तवी कर दिया जाये। क्योंकि हाई स्कूल पास करने की जो बात रखी गई है वह कइ नुक्ते नज़र से सही नहीं हैं। आज़ाद साहब ने यह जो संशोधन रखा है कि वह प्रेजुएंट होना चाहिये तो मैं समझता हूँ कि यह बात भी ठीक नहीं है। बहुत से प्रेजुएंट बिलकुल ही अनिभिन्न होते हैं। उनसे तो कई हमारे देहातों भाई ही अधिक बतला सकते हैं। बहुत से प्रेजुएंटों से, जब वह नौकरी करने के लिये जाते हैं और उनसे सवाल में यह पूछा जाता है कि वह कौंसिल की बाबत कुछ जानते हैं तो वह कुछ भी नहीं बतला पाते हैं। ऐसी हालत में मेरा यह विचार है यह जो प्रेजुएंट की डिफ़ी होने की बात कही जाती है वह ठीक नहीं है। मेरी दरखास्त है कि इसपर गवर्नमेंट फिर से विचार करे और इस क्लार्ज की बिलकुल हटा दे। दूसरी बात यह है कि मिनिस्टर को प्रेसीडेंट को सर्पेंड करने का जो अख्तिয়ার दिया जा रहा है वह मेरे ख्याल में बहस की चीज है। दूसरे मुकों में काउंटिज और मेयर्स को बहुत कुछ अख्तिार होते हैं। उनको पुलिस पर अख्तिार होता है। वह मुकदमें भी करते हैं। ऐसी हालत में यह अख्तिार मिनिस्ट्रों को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिये। इस अख्तिार को अपने हाथ में लेने से सरकार को गुरेज करना चाहिये यह काफी है कि वह उनको बरखास्त कर सकते हैं। यह सही है कि जब तक वह व्यक्ति या चेयरमैन अपनी जगह पर बना रहता है तब तक इन्क्वायरी करने में दिक्कत होती है लेकिन जहां तक दिक्कत

* सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री (हकीम) ब्रजलाल वर्मन]

द्वार होती है वहीं पर दूसरी और दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। जो नौ बातें बिल में हैं उनमें से एकाउन्ट, कम्प्लैट और प्लानिंग बनाने की बातें तो मान ली जायें और बाकी भाग को मूलतः कर दिया जाये। खासकर म्युनिसिपैलिटीज का अहम मसला है यदि आपने ५२ में अर्नेडमेंट कर दिया और ६ महीने के बाद आपने यह महसूस किया उसमें कुछ गलतियाँ रह गई हैं फिर आपको कोई गलती मालूम हुई तो बारबार उस को तरमीम करें इससे अच्छा है कि दो तीन महीने के अन्दर अच्छी तरह से सब बातों को गौरखोज करने के बाद तरमीम भौजूदा ऐक्ट में लायी जाय ताकि सर्वसम्मति से उसको पास किया जाय। एक बात का ख्याल जाहिर किया गया है कि लोकल बाडीज में पोलिटिकल पार्टीज को हिस्सा नहीं लेने देना चाहिये कि कानून में यह चीज लाजिमी नहीं है लेकिन जिन साहब ने यह राय जाहिर की में उस पर बहुत असें से गौर कर रहा हूँ और उस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि अब वक्त आ गया है कि लोकल बाडीज में पोलिटिकल पार्टीज को दखल नहीं देना चाहिये? मैं इन शब्दों के साथ उपाध्यक्ष जी, आप के जरिये गवर्नमेंट से अर्ज करूँगा कि मेरी तजवीज पर वह गौर करे। इस वक्त सिर्फ उन्हीं क्लबजों को पास किया जाय जिनका ताल्लुक इलेक्शन से है और बाकी को अभी स्थगित किया जाय तो मेरा यकीन है कि जिन साहब ने सेलेक्ट कमेटी बनाने का प्रस्ताव रखा है वह भी उस को वापस ले लेंगे। इन शब्दों के साथ मैंने अपनी राय जाहिर कर दी है। आशा है सरकार इस पर ध्यान देगी।

श्री श्यामसुन्दर लाल (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र) —माननीय उपाध्यक्ष जी, मुझे इस विधेयक में शेड्यूल्ड कास्ट के रिप्रेजेंटेशन के प्राविजन के बारे में अर्ज करना है। इस समय जो म्युनिसिपल ऐक्ट फोर्स में है उसके मुताबिक म्युनिसिपैलिटीयों में नामिनेशन के जरिये एक शेड्यूल्ड कास्ट का प्रतिनिधि होता है। प्राविजन इस कारण किया गया था कि चुनाव में शेड्यूल्ड कास्ट का प्रतिनिधि नहीं चुना जा सकता था। जो विधेयक इस समय हाउस के सामने है उसमें उनके लिये प्राविजन रिजर्वेशन आफ सीट्स आन पापुलेशन बेसिस पर किया गया है। शेड्यूल्ड कास्ट समाज का सबसे कमजोर अंग है। एजुकेशनली, सोशली और इकोनामिकली इनकी हालत बहुत ही बबतर है। इनके रिप्रेजेंटेशन का मसला कान्स्टिट्यूट असेम्बली में कंसिडर किये जाने पर विधान में उनके लिये रिजर्वेशन आफ सीट्स पापुलेशन बेसिस पर किया गया है और वही प्राविजन इस विधेयक में लाया गया है। हमारे कुछ माननीय मित्रों ने कहा है कि अब इनको स्पेशल ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं है। इस पर मुझे कहना है कि श्योरी और प्रैक्टिकल में बहुत फर्क होता है। जो सुविधायें सरकार ने उन्हें शिक्षा और सर्विस इत्यादि के संबंध में दी हैं उनकी हालत बेहतर हो रही है। परन्तु एकाएक रहोबदल नहीं हो सकता है इसमें कुछ समय लगेगा। बस्तियों में ये लोग अधिकतर ऐसी जगहों में रहते हैं जहाँ कि वाटर सप्लाई, सेनीटेशन और लाइटिंग की बहुत ही खराब हालत होती है। इस प्रकार रिप्रेजेंटेशन से म्युनिसिपल बोर्ड में इनकी इफेक्टिव वाइस (effective voice) होगी और इसके जरिये इनमें सेल्फ रिलायेंस की भावना होगी और ये अपनी हालत की बेहतरी के लिये स्वयं एफर्ट करेंगे। इसलिये इस विधान के अनुसार जो प्राविजन इनके रिप्रेजेंटेशन के लिये इस विधेयक में किया गया वह बहुत ही आवश्यक और न्यायानुकूल है और उसके लिये सरकार धन्यवाद की पात्र है। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का स्वागत करता हूँ।

* श्री बट्टी प्रसाद कक्कड़ (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र) —जनाब डिप्टी चेयरमैन साहब, इस बात से सब लोग मुत्तफिक हैं कि यह बिल जो इस ऐवान में है वह अपनी जगह पर काफी अहमियत रखता है। वरअसल म्युनिसिपल बोर्ड का इलेक्शन बहुत ही जरूरी था और यह काफी पिछड़ गया था, इस वजह से लोगों में काफी बदगुमानी और बदख्याल पैदा हो गये थे। असल में म्युनिसिपैलिटी ने कोई भी आजादी की श्रलक नहीं देखी थी, मूलक के आजाद होने के बाद उसका भी चुनाव आजादाना होगा। इस बिल को पढ़ने के बाद जो नक्शा दिमाग में आता है, वह

* सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

में एक लपज में अबा कर देना चाहता हूँ। गवर्नमेंट के पास बहुत से काम हैं। एक जान और दस बलायें। मैं पेज, ३, ११ और १३ की तरफ आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ।

पेज ३ में है कि

Amendment no. 23 (1) (a) reads as follows:—"That there has been a failure on the part of the President in performing his duties, give him a warning or remove him from office as the State Government think fit, or"

पेज ११ में है कि—

Amendment of Sec. 73:

73 (2) (b) "In the case of an order of dismissal or removal passed by the Education Committee to the State Government."

इन जगहों पर और इन नदों पर गवर्नमेंट को अपने अहल को अमल में लाना पड़ेगा। डीसेन्ट्रलाइजेशन के ऊपर ध्यान देते हुये तो मेरे ह्याल में गवर्नमेंट को भी लाजमी है कि वह अपना बोझ कम करे। अगर एजुकेशन कमिटी ने कोई फैसला किसी टीचर के डिसमिसल वगैरह का किया तो क्या वजह है कि उस फैसले की अपील किसी इन्स्पेक्टर आफ स्कूल या डाइरेक्टर और डिप्टी डाइरेक्टर के पास न जाये। यह मैंने एक मिसाल के तौर पर कहा है। अभी एक मौका था जब कि मेरे दोस्तों ने यह कहा कि ६० की तादाद ज्यादा से ज्यादा और २० की तादाद कम से कम म्युनिसिपैलिटीज में केमेम्बरो की होनी चाहिये। दरअसल कोई हार्ड ऐंड फास्ट क्लस नहीं ह्याल किया जा सकता है या लाइन आफ डिमार्केशन नहीं खींची जा सकती है। मुझे एतमाद होता है कि ८० की तादाद बहुत ज्यादा थी ५० की तादाद काफी माकूल है। मैं इस चीज को इस तरह समझता हूँ कि Too many cooks spoil the broth। ५० आदमियों का फैसला किसी शहरी माबले में होना कोई कम अहमियत नहीं रखता है लिहाजा ५० की तादाद निहायत काफी है। हमें जहां वोट के कास्ट करने का मौका आता है उसके बारे में मैं दफा १३ (ई) (३) और दफा (१३) (एफ) (२) की तरफ ध्यान दिलाऊंगा मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि दुनिया में इनकन्सीसटेंसी है। मैं जनाब के ऊपर दफा १३ ई (३) पढ़ता हूँ वह इस प्रकार है—

"No person shall vote at a general election in more than one ward and if a person votes in more than one such ward, his vote in all such wards shall be void".

अगर कोई एक से ज्यादा वोट डालता है तो उसके कुल वोट खत्म कर दिये जायेंगे और जहां प्लूरल नम्बर की वोटिंग है उसके सिलसिले में दफा १३ (एफ) (२) इस तरह है—

"If an elector gives more than one vote to any one candidate in contravention of the provisions of sub-section (1), then at the time of counting of votes, not more than one of the votes given by him to such candidate shall be taken into account and all other votes given by him to such candidate shall be rejected as void".

कहने का मतलब यह है कि एक भी वोट इस मौके पर शामिल नहीं होने चाहिये जबकि एक ह्याल को शाये ह्याल करते हुये हमने यह कह दिया कि जब एक से ज्यादा कोई वोट देता है तो उसकी वोट नहीं मानी जायेंगी तो इस तरह से वह सूरत यहां पर भी आयद होती है और यहां पर भी उसको वोट नहीं माननी चाहिये।

गवर्नमेंट की जानिब से और मेम्बरों की जानिब से यह भी कहा गया था कि कोअप्शन और नामिनेशन की जहां तक बात है इन दोनों को इस बिल में निजाद मिला। जहां तक कोअप्शन का ताल्लुक है, मुझे इससे इत्तिफाक है कि कोअप्शन नहीं है, लेकिन नामिनेशन के बजाय उसमें रिनामिनेशन है। इसके लिये मैं सेक्शन ३१ (ए) सब-क्लाज (ए) की

[श्री बद्री प्रसाद कक्कड़]

तरफ आपकी तबज्जो दिलाऊंगा। जब नामिनेशन से निज़ाद हुई तो रिनामिनेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। वह रिनामिनेशन एकजिस्ट करता है आपटर नामिनेशन। ससपेंशन आफ मेम्बर्स ऐन्ड प्रेसीडेंट के बारे में तजकिरा था और उसमें कुछ साहबान का यह ख्याल था कि जो ड्यूरेशन ससपेंशन का है, वह गैर मुनासिब है। मैं भी बहुत हद तक इससे इत्तिफाक करता हूँ। जब तक केस न बन जाय तब तक मेम्बर या प्रेसीडेंट को मुअ्तिल नहीं होना चाहिये। मैं एक बात यह कहूंगा कि चार्जज जब फ़्रेम किये जाते हैं और उसके बाद उसका ससपेंशन करते हैं तो अगर मिसऐप्रोप्रिएशन हो, तो मेरे ख्याल में उसका ससपेंशन ही क्या, रिमूवल ही कर दिया जाय तो ज्यादा बेहतर हो। लेकिन अगर मिसऐप्रोप्रियेएशन न हो तो ऐसी सूरत में किसी मेम्बर या प्रेसीडेंट के खिलाफ जो उसका निकालने की बात हो, तो इस पर मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को ज़रूर ख्याल करना चाहिये, इसके पहले कि वह उसको ससपेंड कर दे।

चुनाव के सिलसिले में प्रेसीडेंट की क्वालिफिकेशन्स का तजकिरा था। इस बिल में यह है कि उसकी क्वालिफिकेशन्स हाई स्कूल होनी चाहिये। हाई स्कूल इसमें क्या अहमियत रखता है, यह मेरी समझ में नहीं आया। इसमें हाई स्कूल पास की जो क्वालिफिकेशन रखी है, वह काबलियत, उसमें क्या माने रखती है। आजकल हाई स्कूल पास को वैसे क्या काबलियत होती है। मैं समझता हूँ कि हमें देखना यह चाहिये कि म्युनिसिपल बोर्ड के प्रेसीडेंट को क्या देखना है। उसको देखना है कि सेंनेटरी कन्डीशन कैसी है, एजुकेशन कैसी है, स्ट्रीट की लाइट्स का क्या हाल है, इन्हीं सब बातों को उसे देखना है। ऐसी सूरत में उसकी क्या काबलियत होनी चाहिये, मैं समझता हूँ कि उसका कैरेक्टर और उसका चरित्र अच्छा होना चाहिये। उसका कैरेक्टर ही मेन चीज़ है। मैं आपके सामने एक जिन्दा, बल्कि जिन्दा ही नहीं, एक स्वर्गीय नज़ारा खींचना चाहता हूँ। मेरे ज़िले में जिस वक्त कांग्रेस का सच्चा जोर हुआ था, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चुनाव था, श्री मदन लाल स्वर्गीय जो पटवारी थे, दर्जा ४ ही मुश्किल से पास थे, जैसा इन्तज़ाम और बन्दोबस्त उन्होंने किया, मैं आप से हकीकत से बयान करता हूँ कि आज तक किसी ने नहीं किया और आगे के लिये मैं कह नहीं सकता। आज मैं आप से दरियाफ्त करूँ चर्चिल ने क्या पास किया, (What is the education of Mr. Churchill) लेकिन आज चर्चिल की काबलियत और फज़ालत का सिक्का हिन्दुस्तान में ही नहीं बल्कि दुनियाँ में है। मैं स्टालिन की काबलियत के बारे में कहना चाहता हूँ आर्थोडाक्स मिशनरी आफ स्कूल ही पास थे इसके अलावा डिग्री वाली कोई काबलियत उनके पास नहीं है और किस तरह से आज भी वह हुकूमत कर रहा है वह रोशन जमाना है। बड़े बड़े आपके पोयेट हुये उन्होंने किस स्कूल में डिग्री प्राप्त की मैं महाराज तुलसीदास जी की मिसाल देता हूँ उन्होंने किस हाई स्कूल और किस विद्वदविद्यालय से डिग्री प्राप्त की, लेकिन आज तक उनकी काबलियत का सिक्का जमा हुआ है और उसके पैरलल कोई मिसाल नहीं है। कहने का मतलब यह है कि यह क्वालिफिकेशन मेरे ख्याल में सच्ची अहमियत नहीं रखती है। गवर्नमेंट इस पर गौर करे। यहां पर यह बिल म्युनिसिपैलिटीज को एक ताक़त दे रहा है कि आक़्दाय वसूल करे। जहां तक कन्जम्पशन का सवाल है मुझे इख़्तलाफ नहीं, लेकिन जहां सेल का सवाल है यह गौर तलब होगा कि जो ताजिर सेल के लिये जाते हैं तो कुल चीज़ सेल नहीं होती है इसलिये उनको खपया वापस किया जाता है, रिफ़न्ड किया जाता है, इसलिये जो सूरत पहले थी वह रखनी पड़ेगी और रहनी होगी और अगर नहीं रखी जाती तो ताजिर कौम के साथ एक बड़ी ज़्यादती होती है जिससे ताजिर को बहुत बड़ा धक्का पहुंचेगा। सबसे बड़ी चीज़ म्युनिसिपैलिटीज के अन्दर गवर्नमेंट को ख्याल करने की ज़रूरत यह है कि वह देखे कि खुल्लमखुल्ला किस ढ़ंवर आक़्दाय गम्ब की जा रही है। और उस आक़्दाय से म्युनिसिपैलिटीज बिल्कुल फायदा नहीं उठा रही है। रात के वक्त शाम को सात बजे से स्मर्गलिंग

की भरमार रहती है। इस क्रूरदर ज्यादा स्मर्गलिंग होती है कि अल्लामा अल्लामा। इस स्मर्गलिंग को बन्द करने के लिये गवर्नमेंट को वैरियर्स कायम करना चाहिये। अगर वैरियर्स नहीं कायम होते तो स्मर्गलिंग और करप्शन का दरवाजा बहुत जोरों से खुला रहेगा और इसके ऊपर आपके आक्राम्य को चाहे वह जिस क्रूरदर ताकतवार हो कोई कंट्रोल न रहेगा।

हमारे बुजुर्ग दोस्त श्री राजा राम जी ने रिजर्वेशन पर स्टेदलाल दिया। अगर उनका ख्याल नहीं है तो मेरा इस तरफ ध्यान भी नहीं है और अगर उनका ख्याल है तो मैं उनसे पूछूँगा कि आप उल्टी गंगा किस तरह से बहाने के लिये तैयार हैं। आपतो रिजर्वेशन के इतने मुखालिफ थे, मैं भी रिजर्वेशन का मुखालिफ हूँ लेकिन अब यह आवाज कैसी। जिस वक्त एक रिजर्वेशन की सूरत पैदा होगी उस वक्त तमाम रिजर्वेशन की सूरतें पैदा हो जायेंगी और वह डेमोक्रेसी को ठीकर लगायेंगी। लिहाजा डेमोक्रेसी की बात तो ठीक नहीं। इन शब्दों के साथ मैं दोबारा इस बिल का स्वागत करता हूँ।

डाक्टर ब्रजेंद्र स्वरूप (स्नातक निर्वाचन क्षेत्र)—जनाब डिप्टी चैयरमैन साहब, मैंने इस बिल को अच्छी तरह से पढ़ा है और इसका मुकाबला सन् १९१६ और ४९ के बिल से किया है। मेरे ख्याल में इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि जहाँ तक इस तहरीक का सवाल है हम सबको इसका स्वागत करना चाहिये। मैं इसका स्वागत इस वजह से करता हूँ और तमाम पहलू को देख कर मेरी राय यह है कि This Bill tends to give more democracy, while at the same time it extends Government Control over certain important affairs of the Municipality इन बातों के लिहाज से जब मैं देखता हूँ तो बिल को तीन तत्वों में डिवाइड करता हूँ। पहला तो यह कि गुड फीचर्स इस बिल के क्या क्या हैं। दूसरे डिफेक्ट्स क्या क्या हैं और तीसरे ओमीशन्स क्या क्या हैं। जहाँ तक ओमीशन्स का ताल्लुक है, मैं पहिले यह कहना मुनासिब समझता हूँ कि इसके मुताल्लिक सजेन्स रखूँगा और जैसा कि मंत्री महोदय ने कहा है कि वह उन सजेन्स का लिहाज रखेंगे जब कि दूसरा बिल लायेंगे।

श्री राजा राम शास्त्री ने एक अमंडमेंट के तौर पर तजवीज रखी है। उस तजवीज का विरोध मैं इस वजह से करता हूँ कि उससे इलेक्शन में विकृत होगी। जैसा कुंवर गुरु नारायण जी ने कहा कि अभी काफी मौका है सेलेक्ट कमेटी के लिये, वह अपनी रिपोर्ट पेश कर सकती है। मगर मैं इस बात के खिलाफ हूँ। हमको जो ऐडमोरेन्स मंत्री महोदय ने दिया है वह यह है कि वह जल्दी एक बिल लायेंगे और उस वक्त मौका होगा इस चीज को पेश करने का, जिस पर कि विचार विनिमय किया जायेगा। यह मैं मानने के लिये तैयार नहीं हूँ कि सेलेक्ट कमेटी अपनी माकूल रिपोर्ट छः या सात दिन में दे सकती है। आजकल यह माना गया है कि म्युनिसिपैलिटी आफेयर एक खास चीज है। जहाँ तक गुड फीचर्स का ताल्लुक है, वह इस बिल में है जब यह बिल सन् १९४८ में आया था तो उस वक्त भी मैंने मुखालिफ़ की थी, इस बिना पर कि इलिमिनेशन आफ कोआप्शन की जो पार्टें बन गयी हैं उसके इसमें सेम्बर होंगे। मैं यह मुनासिब नहीं समझता था। मेरे ख्याल में इस गवर्नमेंट ने कुछ मुनासिब तरकीबें पेश की हैं। जहाँ तक रिजर्वेशन का ताल्लुक है, मैं उसकी तारीफ़ करता हूँ। मेरा तजुर्बा है कि जहाँ पर म्युनिसिपल बोर्ड होता है वहाँ पर अच्छा काम नहीं होता है नतीजा यह होता है कि जो आसानियाँ म्युनिसिपल बोर्ड को हैं वे नज़रन्दाब कर दी जाती हैं। जहाँ पर प्रापर मेन्टेनेन्स आफ ऐकाउन्ट्स का सवाल है हम लोगों को उसका स्वागत करना चाहिये। प्रापर ऐकाउन्ट्स न होने की वजह से गड़बड़ी भव जाती है। जो असुविधायें हो रही हैं बेकिसी से छिपी नहीं हैं। मुझको यह तजुर्बा है कि म्युनिसिपल बोर्ड का ऐकाउन्टेन्ट चैयरमैन के ऊपर हावी हो जाता है। अगर चैयरमैन ऐसा है जो ईमानदारी से दूर रहना चाहता है तो ऐकाउन्टेन्ट की बन आती है और वह सैकड़ों रुपया बना लेता है।

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[डाक्टर ब्रजेन्द्र स्वरूप]

इस स्थल से मैं समझता हूँ कि यह बात जो इस तरमीम में है उसके साथ मैं यह कहना चाहता हूँ कि एग्जाइन्टमेंट आफ एकाउन्ट आफिसर्स का होना चाहिये। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा। अगर गवर्नमेंट इसको भी पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिये से कराये तो बहुत अच्छा होगा पब्लिक सर्विस कमीशन पाठों पालिटिक्स से बिलकुल ही अलग है। वहाँ इसका सवाल नहीं है। अगर यह पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिये से कराया जाये तो ज्यादा मुनासिब होगा।

एक बात मैं एक्सटेन्शन की बाबत कहना चाहता हूँ। कानपुर बोर्ड का ही एक्सटेन्शन ४ या ५ वर्ष से हो रहा है। तीन चार चेंबरमें तब्दील हो चुके हैं मगर बोर्ड का एक्सटेन्शन होता चला जा रहा है। इसका नतीजा बोर्ड पर बहुत बुरा पड़ता है। अगर कानपुर की कारपोरेशन बनाना है तब तो दूसरी बात है वना उसका इलेक्शन बहुत जल्द होना चाहिये। अगर कारपोरेशन करना है तब तो उसके लिये कानून जल्दी लाना चाहिये। पाँचवीं बात जो है वह मैं एंडहाक कमेटी की निस्वत कहना चाहता हूँ। जब मैं चेंबरमें था तब हालांकि पावर्स बहुत कम थीं लेकिन इस एंडहाक कमेटी के जरिये से एक्सपर्ट्स की राय लेने में आसानी होती थी। यह भी बहुत अच्छी चीज है।

दूसरी बात यह है कि मैं यह देखता हूँ कि म्युनिसिपैलिटीज को यह अख्तियार दिया जाता है कि वह प्लानिंग को कंसिडर करें और उनको डाइरेक्ट करें। यह बहुत जरूरी है। इससे बहुत कुछ दिक्कतें दूर हो जायेंगी। अब मैं कहना चाहता हूँ कि जो आबजेक्शनेबुल फीचर्स हैं वह दो तरह की हैं। पहिली तो यह है, कि जिसकी तरफ मैं खास तवज्जह दिलाना चाहता हूँ कि बोट देने का हक्क उस शख्स को नहीं होगा जो इंप्रिजनमेंट में होगा या पुलिस कस्टडी में होगा। पुलिस कस्टडी की बात बहुत वाइड है। दूसरी बात, अगर अगर वाइज इंप्रिजनमेंट का जो शब्द है यह भी बहुत वाइड है। इसको लेकर गवर्नमेंट को खतरा न उठाना चाहिये। दूसरी चीज की निस्वत मैं यह कहना चाहता हूँ कि एक डिफेक्ट यह है कि अभी तक यह था कि अंग्रेजी पेपर्स में पब्लिकेशन आफ रेजोल्यूशन होना चाहिये अब उसके लिये यह हो रहा है कि वह किसी हिन्दी पेपर में भी हो सकता है। बहुत से लोग यह कर सकते हैं कि अपने रिश्तेदार के जरिये से कोई पेपर निकाल कर उसमें पब्लिकेशन करा सकते हैं। उसके लिये यह होना चाहिये कि पब्लिकेशन उन्हीं पेपर्स में होना चाहिये जो कि गवर्नमेंट से रिजिस्टर्ड हों। एक बात जो मंत्रीकुलेशन की लियाकत की बाबत कही गई है उसकी बाबत मुझे यह कहना है कि मेरे तजुबों में बहुत से लोग ऐसे आये हैं जो कि पुराने वक्त के छठे बजे तक पढ़े हुये हैं मगर वह लियाकत में मंत्रीकुलेशन और प्रेजुएंट को मात करते हैं। अंग्रेजी की बाबत तो मंत्रीकुलेशन का तो कहना ही क्या, प्रेजुएंट भी उनका मुक़ाबिला नहीं कर पाते हैं। उसकी जगह पर यह होना चाहिये कि आनेस्ट और कैपेबुल आदमी होना चाहिये। कैपेबुल में उसकी कैपेबिलिटी हर तरह से देखी जा सकती है और जहाँ तक उसकी आनेस्टी का सवाल है वह तो अनक्वेशनेबुल होना चाहिये, नहीं तो वह तरक्की नहीं कर सकते। अब मैं और चन्द बातों की तरफ तवज्जह दिलाना चाहता हूँ। जहाँ तक रेजोल्यूशन का ताल्लुक है उसके लिये रूल में है कि उसी मीटिंग में पास हो जाना चाहिये और यदि पास न हो सका तो नेक्स्ट मीटिंग में पास हो जाना चाहिये। मगर यह देखा गया है कि इसकी तामील नहीं होती है। उसका नतीजा यह होता है कि ५, ६ मीटिंग होने पर वह रेजोल्यूशन पास होता है और वह भी सब्सीच्यूट कर दिया जाता है और फिर पास करते हैं। इस हालत पर सरकार का तवज्जह दिलाना चाहता हूँ। दूसरा यह है कि बोर्ड्स का ससपेंशन आप ने अनलिमिटेड पीरियड के लिये रखा है। मेरा स्थल है कि सुपरसेशन दो साल से ज्यादा नहीं होना चाहिये वैसे एक वर्ष भी ज्यादा है। जब कोई बोर्ड सुपरसीड होता है तो उसकी इन्क्वायरी होनी चाहिये। इसके माने यह नहीं कि आप इनफिनिट पीरियड के लिये ससपेंड रखें।

तीसरी बात में ऐंवाइन्टमेंट के बारे में कहना चाहता हूं। मैंने पहले भी इस विषय पर जोर दिया था कि बोर्डों की तमाम खराबियां इस वजह से हैं कि वहां ऐंवाइन्टमेंट चेयरमैन के हाथ में होता है। वहां के कानून में है कि वे २५० रुपये तक का ऐंवाइन्टमेंट कर सकते हैं और बाद में कर्म कमेटी से करवा लेते हैं। मेरा ख्याल है कि वहां भी ऐंवाइन्टमेंट पब्लिक सर्विस कमीशन से होना चाहिये। यदि १००,०० से ज्यादा के लिये ऐंवाइन्टमेंट पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिये से हो तो बहुत अच्छा होगा। नहीं तो बहुत से ऐसे आदमी आ जाते हैं कि म्युनिसिपल बोर्ड के अफेयर्स को बदनाम करते हैं। जहां तक टेम्पोरेरी ऐंवाइन्टमेंट का सवाल है, मैंने देखा है कि चेयरमैन जिसको चाहता है उसको टेम्पोरेरी कर देकर ऐंवाइन्टमेंट कर लेता है क्योंकि टेम्पोरेरी ऐंवाइन्टमेंट करने की पावर उसको होती है। कानून में यह है कि जब टेम्पोरेरी ऐंवाइन्टमेंट हो जाता है तो उसके बाद ही जो बोर्ड की मीटिंग हो उसमें इस को रख देना चाहिये। जब ऐंवाइन्टमेंट हो चुका तो मेरा अपना तजुर्बा है कि ऐंवाइन्टमेंट होने के बाद बोर्ड की ताकत नहीं है कि उसकी खिलाफत कर सके। इन सब बातों के साथ ही मैं फिर मंत्री महोदय को सुधारक-बाद देना चाहता हूं कि वह इस किस्म का बिल लाये हैं जिससे बहुत कमियां दूर हो जायेंगी। हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही ऐसा बिल आयेगा कि जिस समय लोगों को अपनी राय देने का मौका आयेगा। जहां तक सेलेक्ट कमेटी का ताल्लुक है उसका मौका इस बिल ज्यादा मुनासिब नहीं है।

श्री नरोत्तम दास टंडन (स्थानीय संस्थाओं निर्वाचन क्षेत्र)—श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, यह जो यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) बिल सन् १९५२ ई०, सुबह से डिस्कस हो रहा है, उसके संबंध में मेरे जो विचार हैं उन को मैं आप के सम्मुख रखता हूं। इस बिल में कुछ तो बहुत सी अच्छी बातें हैं, परन्तु इसके साथ ही साथ इसमें कुछ खराबियां भी हैं। इसमें सब से बड़ी खराबी यह है कि सरकार मेम्बर और प्रेसिडेंट को हटा सकती है इससे उनकी गरदन हमेशा दबी रहेगी। वह कोई भी काम ऐसा न कर सके कि जिससे जनता को फायदा पहुंच सके, क्योंकि उनको हमेशा इस बात का डर रहेगा कि कहीं सरकार नाबुश न हो जाय या उनके साथी दुश्मन जिनका असर सरकार में ज्यादा है वह उनकी किसी बात से नाजायज फायदा न उठा लें। मैं समझता हूं कि सरकार को खुद ऐसी कोई पावर नहीं लेनी चाहिये जिससे उसकी बदनामी होने की आशंका हो। एक मेम्बर जिसको जनता ने चुन कर भेजा है, जनता को ही उसके हटाने का पूरा अख्तियार होना चाहिये, परन्तु बिल में ऐसा नहीं है। दूसरी बात में यह कहना चाहता हूं कि मैं इलाहाबाद बोर्ड का ८ साल से मेम्बर हूं। इस से पहले जितने भी चेयरमैन हुये, उनमें से कोई भी ऐसे नहीं थे जो लेजिस्लेचर का मेम्बर रहा हो। मैं यह समझता हूं कि उनको अपना काफ़ी समय म्युनिसिपल बोर्ड में देना पड़ता था या इससे पहले इलाहाबाद में बाबू कामता प्रसाद चेयरमैन थे वह १२ बजे म्युनिसिपल बोर्ड में आ जाते थे और शाम के ६ बजे तक काम करते रहते थे। आज कल जो चेयरमैन हैं उन के खिलाफ वोट आफ नो कांफिडेंस पास होने जा रहा है। बहुमत की राय है कि वह मंजूर भी कर लिया जाय। यह जरूर होना चाहिये कि लेजिस्लेचर का मेम्बर लोकल वाडीज का मेम्बर नहीं होना चाहिये।

दूसरी बात में म्युनिसिपैलिटीज के ऐडमिनिस्ट्रेशन के बारे में यह कहना चाहता हूं कि एग्जीक्यूटिव आफिसर का ऐंवाइन्टमेंट सरकार के जरिये से होना चाहिये क्योंकि इससे उनको किसी का भी डर नहीं रहता और वह आजादी के साथ काम कर सकता है। अगर वह लोग बोर्ड ही के जरिये से मुहरंर किये जायेंगे तो नाजायज फायदा भी उठाया जा सकता है और इस में बोर्ड की बदनामी होने का डर है। लिहाजा मैं इस बात का समर्थक हूं कि इन कर्मचारियों को सरकार को मुहरंर करना चाहिये। इस तरह से उन कर्मचारियों का स्टेटस भी ऊंचा हो जायगा और उन से अनुचित रूप से कोई फायदा भी नहीं उठा सकेगा।

[श्री नरोत्तम दास टंडन]

दूसरी बात जो इस ऐक्ट में है वह बहुत ही सुन्दर है कि सरकार दो साल से अधिक एक्सपेंशन नहीं कर सकती है। इस तरह से जनता को भी मालूम हो जायेगा कि जिनको वह चुन कर भेज रही है वह सिर्फ ६ वर्ष के लिये ही अधिक से अधिक हैं इसके आगे मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि प्रेसीडेंट की ऐजेंटेशनल क्वालिफिकेशन इसमें क्यों रखी गई है। मैं इसका विरोध करता हूँ। मैं समझता हूँ कि प्रेसीडेंट वह आदमी होगा, जो जवान हो। अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में कहा है कि अब पब्लिक इतनी सचेत हो गई है कि वह ऐसे वेंसों को वोट देने के लिये तैयार नहीं है वह अब समझने लगी है कि वोट देने का जो अधिकार हमको दिया गया है उससे हम क्या कर सकते हैं। जब पब्लिक में इतनी समझ आ गई है तब प्रेसीडेंट के क्वालिफिकेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। जो भी काबिल होगा पब्लिक उसी को वोट देगी। मुमकिन है कि कोई ऐसा वर्कर हो जिसके पास कोई ऐजेंटेशनल क्वालिफिकेशन न हो परन्तु वह बहुत ही योग्य हो तो ऐसी सूरत में पब्लिक उसको भी चुन सकती है। आप जानते हैं और दुनिया जानती है कि डाक्टर सर चिन्तामणि ऐसे व्यक्ति थे कि जो हाई स्कूल भी नहीं थे परन्तु बहुत ही विद्वान् थे। इसलिये मैं इस हाई स्कूल की क्वालिफिकेशन का होना आवश्यक नहीं समझता।

दूसरी बात यह है कि जैसा इसमें कहा गया है कि डिटेन्शन जिसका हो गया या जिसका इम्प्रिजनमेंट हो गया उसको वोट देने का अधिकार नहीं है तो यह उचित बात नहीं है। जब इलेक्शन लड़े जायेंगे और अगर किसी को किसी के खिलाफ कोई व्यक्तिगत शिकायत हो और वह पुलिस में जाकर रिपोर्ट लिखा दे और अगर उसका किसी दरोगा से इन्फ्रूँस हो और अपने इन्फ्रूँस से वह उसका डिटेन्शन करा सकता है तो ऐसी हालत में डिटेन्शन या इम्प्रिजनमेंट के ऊपर वोट देने का अधिकार ले लेना उचित नहीं मालूम होता है।

तीसरी बात यह है कि जो रेजोल्यूशन होंगे वह हिन्दी के अखबारों में ही छपेंगे तो उसके लिये मेरी भी यही राय है कि इस तरह से और भी नये नये अखबार निकलने शुरू हो जायेंगे और उनको रोकने के लिये यह जरूरी है कि जो कलेक्टर के यहां ऐम्बुड लिस्ट हो, बड़ा अच्छा हो, अगर उन्हीं में यह रेजोल्यूशन छापे जायें और जो नये अखबार निकलें उनमें वह न दिये जायें। इस ऐक्ट के पढ़ने से यह पता चलता है कि नामिनेशन अब खत्म कर दिये गये हैं और प्रेसीडेंट का भी अब डाइरेक्ट इलेक्शन होगा तो यह भी एक बहुत ही अच्छी चीज है। पहले तो ऐसा होता था कि मेम्बर अपने ही आदमियों में से प्रेसीडेंट चुन लेते थे और जिसकी चाहत थी निकाल भी देते थे पर अब जनता द्वारा प्रेसीडेंट का चुनाव होगा और इसी तरह जनता की ही प्रेसीडेंट के हटाने का अस्तित्वार होना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं अपनी स्पीच समाप्त करता हूँ।

श्रीमती शिवराजवती नेहरू (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह विषयक जितना महत्वपूर्ण है वह सब जानते हैं। यह मैं मानती हूँ कि इसको पास करके देश का अधिक से अधिक कल्याण हो होगा। परन्तु केवल दो बातें में अपनी सरकार से कहना चाहती हूँ। एक तो यह है कि स्त्रियों का जो रिजर्वेशन आफ सीट था उसको उन्होंने खत्म कर दिया है। इसके अलावा यह कहा जाता है कि हम किसी की भी सीट का रिजर्वेशन नहीं चाहते हैं। वैसे तो शुरू में भी स्त्रियों का रिजर्वेशन नहीं होता था, यह न तो कोई अलग समाज है और न कोई अलग संस्था है, स्त्रियां तो सभी समाज की हैं और उनको रिजर्वेशन मिलना ही चाहिये था। इससे यह होता कि योड़ो बहुत स्त्रियां भी म्युनिसिपैलिटी में पढ़ चुकी हैं। परन्तु आज हमारे मिनिस्टर साहब कहते हैं कि हम स्त्री पुरुष समान हैं और स्त्रियों को समान ही समझ कर हम उनको रिजर्वेशन नहीं देना चाहते हैं। लेकिन अभी तो हमारे देश में स्त्री पुरुष को समान नहीं

समझा जाता है। जब असेम्बली और कौंसिल की बात आई तब भी यही कहा गया, जब कि कौंसिल और असेम्बली में हम लोगों का रिजर्वेशन आफ सीट्स था, रिजर्वेशन आफ सीट्स जरूरी नहीं है और सरकार खुद ही न्याय करके स्त्रियों को स्थान दे देगी। हमारी मांग थी कि हर जिला से एक स्त्री आये इस प्रकार ५२ जिलों से ५२ स्त्रियों की मांग थी परन्तु ५२ जिलों में कुल १५ या १६ असेम्बली और कौंसिल में स्त्रियाँ हैं। इस तरह से कुल ५२ जगहों में से १५ या १६ जगह स्त्रियों को मिली हैं। क्या इससे इस बात की आशा की जा सकती है कि म्युनिसिपैलिटीज में जबकि आज रिजर्वेशन नहीं है, तो कोई भी पुरुष इस तरह से नहीं करेगा कि वह स्त्रियों को जगह दे दे। पहले के पुरुषों में स्त्रियों के प्रति उदारता भी थी मगर आजकल उदारता बिल्कुल नहीं है क्योंकि आज पुरुष समझते हैं कि स्त्रियों ने भी वही स्थान ग्रहण किया है और उनकी निगाह में आज स्त्रियाँ पुरुषों के ही बराबर आगे बढ़ती चली जा रही हैं तो उनका कहना है कि वे स्त्रियों का उतना साथ नहीं दे सकते हैं जितना कि पहले देते थे। अगर आज रिजर्वेशन आफ सीट्स हमारे लिये न हो तब तो बड़ी मुश्किल हो जायेगी और इसके विपरीत अगर स्त्रियों के लिये रिजर्वेशन आफ सीट्स होता तो स्त्रियों को स्त्रियों से ही लड़ना पड़ता और इस तरह से भी जिसकी हार होती, उसमें स्त्री ही आती, मगर यह बात नहीं है। अगर आज कोई स्त्री खड़ी होती है, तो उसको पुरुष के खिलाफ लड़ना पड़ता है, तो यह भी उसके लिये बड़ा मुश्किल है। इसलिये अध्यक्ष महोदय, इस बात पर मैं विशेष रूप से मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहती हूँ कि वे इस मामले में स्त्रियों का विशेष ख्याल करेंगे। जहाँ तक म्युनिसिपैलिटी के मेम्बरों की ईमानदारी की बात है और उनके चरित्र की बात है, तो मैं कहूँगी कि ज्यादा पढ़ी लिखी न होने पर भी एक स्त्री में जितनी ईमानदारी हो सकती है और अगर उसका चरित्र जितना अच्छा हो सकता है, उतनी ईमानदारी और उतना अच्छा चरित्र किसी पुरुष का नहीं हो सकता है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुये अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार का इस बात की तरफ ध्यान दिलाना चाहती हूँ कि वे इस बात पर गौर करें। एक बात जो मैं कहना चाहती हूँ वह यह है कि आजकल सिनेमा इस कदर बनते चले जा रहे हैं कि उनका कुछ पूछना ही नहीं। ऐसा मालूम होता है कि जितना लोगों के पास पैसा है और उनकी जितनी आमदनी है, वह सब वे सिनेमा बनाने में खर्च कर रहे हैं। यह मैंने माना जैसा कि मंत्री महोदय ने कहा कि इस तरह से नहीं होना चाहिये, मगर आजकल लोग सिनेमा भी मंदिरों के पास बनाने लग गये हैं और सिनेमा वाले इतने होशियार होते हैं कि वे यह कहने लगते हैं कि यहाँ पर मंदिर नहीं है। इस तरह से मंदिरों के पास सिनेमा बनने लगे हैं और आजकल जगह २ पर यह हालत पैदा होगई है और इस तरह से सिनेमा बनते हैं, तो वहाँ पर चारों ओर चाट वाले, पान, बीड़ी और सिगरेट वाले नंगफली वाले और दुनियाँ भर के लोग बैठे रहते हैं और इस तरह से जो लोग वहाँ एकोन्त में ईश्वर की पूजा करने के लिये मंदिर में जाते हैं उनको इन सब चीजों से बहुत असुविधा होती है। इन्हीं दो बातों की तरफ मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहती हूँ। इन चन्द बातों में इस प्रस्ताव का ध्यान दिलाना चाहती हूँ और इन चन्द बातों के साथ मैं इस प्रस्ताव का स्वागत करती हूँ।

* श्री कन्हैया लाल गुप्त (अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र) —माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत विधेयक जो कि सदन के सामने है मैं सबसे पहले यह आवश्यक समझता हूँ कि श्रीयुत राजा राम शास्त्री ने जो प्रस्ताव सदन के सम्मुख उपस्थित किया है कि इस बिल के पास करने के पहले इसको एक विशिष्ट समिति के सिफुई कर दिया जाय, तो उसका मैं समर्थन करता हूँ। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल जो यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है, वह एक बहुत ही स्वागत करने योग्य वस्तु है।

*सबस्य ने अपना भाषण शुरु नहीं किया।

[श्री कन्हैया लाल गुप्त]

आज सारा प्रांत कई वर्षों से उसकी बाट देख रहा था और हमारे माननीय मंत्री जी उसके लिये बधाई के पात्र हैं कि आखिर एक दिन आया कि उन्होंने इसको प्रस्तुत करने की कृपा की। परन्तु जब यह बिल इतना महत्वपूर्ण है, वहां यह भी कहे बिना नहीं रहा जाता कि जितनी चीजों की आशा इससे की जाती थी वह इसमें नहीं पाई जाती है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदन के सदस्यों की भोजीभांति विदित है कि म्युनिसिपैलिटीज और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड आदि संस्थाएं ऐसी हैं जो नागरिक अधिकारों की मूल हैं। यही पहली संस्थाएँ हैं जहाँ हम अपने नागरिकों के प्रति और समाज के प्रति कर्तव्यों को अदा करने का सबक सीखते हैं। जो विधेयक इन संस्थाओं को चला रहा था वह पुराना हो गया था और लम्बे अरसे से यह महसूस किया जा रहा था कि इसमें परिवर्तन होना चाहिये। सन् ३७ में कांग्रेस सरकार के आने के बाद सरकार ने एक कमेटी नियुक्त की जिसने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की। दुर्भाग्य से यह सरकार उस समय खत्म हो गई और सन् ४६ में वापस हुई। उस रिपोर्ट के आधार पर एक विधेयक सन् ४८ में आंशिक रूप से प्रस्तुत किया गया कि इस विधेयक के प्राविजन लागू किये जायेंगे और नये बोर्ड बनेंगे। कुछ की बात यह रही कि कमेटी, कांग्रेस सरकार ने ही बिठाई और उसकी रिपोर्ट होने पर भी पूरी तरह से विधेयक को नहीं बनाया और इतने सालों तक म्युनिसिपैलिटीज के इलेक्शन को टाला, और स्थगित रखा। जब माननीय राज्यपाल महोदय ने अपना भाषण इस सदन में दिया है तब यह बात कही गई थी कि म्युनिसिपैलिटीज के इलेक्शन बिल्कुल टाले नहीं जायेंगे और जल्द ही एक विधेयक इस सिलसिले में प्रस्तुत किया जायेगा, तो इतने दिन बाद एक विधेयक आता है और वह भी जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा है लंगडो और लूजी दशा में, यह अफसोस की बात है। सन् ४८ में विधेयक बनाया था और तब से इलेक्शन टलते आ रहे हैं और एक मई से सरकार वादा करती आ रही है कि इलेक्शन जल्द होंगे। इतना होते हुये भी जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है वह भी अचूरा है। यह तो मैं नहीं समझता कि सरकार अपने को किस प्रकार प्रशंसा की पात्र समझती है और अपने में संतुष्ट हो पाती है, लेकिन जितना मैंने देखा है मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार के पास इतना सेक्रेटिरियेट है और इतना अरसा हो जाने के बाद भी वह एक कम्प्लोट बिल हाउस के सामने क्यों नहीं रख पाती। आज ज़रूरत पर मंत्री महोदय को यह कहना पड़ा कि बिल बहुत ही अचूरा है और बहुत जल्द हम दूसरा बिल लायेंगे जो कि सम्पूर्ण होगा। मैं नहीं जानता कि वह दूसरा बिल कितने असें के बाद इस सदन में प्रस्तुत कर सकेंगे।

अब मैं श्री राजा राम शास्त्रीजी के प्रस्ताव के संबंध में कुछ निवेदन कहूंगा। श्री राजा राम जी ने प्रस्ताव किया है कि यह बिल सेलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाये। मेरे माननीय भाई श्री आज़ाद साहब ने और माननीय श्री निज़ामुद्दीन साहब ने अपनी तकरीरें करते हुये कहा कि यह बहुत प्रेर ज़रूरी प्रस्ताव है। यह बिल बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसके अन्दर ऐसी चीजें नहीं हैं जिनकी आलोचना की जा सके। माननीय आज़ाद साहब ने कहा कि अगर आप इसको सेलेक्ट कमेटी के सुपुर्व करते हैं, तो इलेक्शन बहुत जल्द न हो सकेंगे हालांकि राजा राम जी ने यह आश्वासन दिलाया है कि सेलेक्ट कमेटी बहुत थोड़े असें के अन्दर, अधिक से अधिक एक हफ्ते के अन्दर अपनी रिपोर्ट दे देगी। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि इलेक्शन सन् ५४ तक के लिये टल जायेंगे। मेरी समझ में नहीं आता कि यह दलील कहाँ तक ठीक है। आप इतने दिन से इस बिल को न लाये, जनता इतने दिन से इस बिल की मांग कर रही थी मगर आप नहीं लाये तब तक तो कोई बुराई की बात नहीं हुई और अगर आज यह सदन यह मांग करता है कि इस बिल को सेलेक्ट कमेटी के सुपुर्व कर दिया जाये जिससे इस भवन के सदस्य इस पर अच्छी तरह से विचार कर सकें और जो बहुत सी चीजें इस में रह गई हैं उनको इनकारपोरेट किया जा सके और गलतियाँ ठीक की जा सकें तो कहा जाता है कि सन् ५३ तक फिर इलेक्शन न हो सकेंगे।

में नहीं समझता कि यह मनोवृत्ति कहां से आती है। लेकिन निष्पक्ष रूप से कोई भी व्यक्ति अगर इन सारी बातों पर गौर करे तो में समझता हूं कि किसी को भी यह स्पष्ट हो जायेगा कि यह मनोवृत्ति निष्पक्ष मनोवृत्ति नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत में यह कहना चाहता हूं कि जहां तक यह दलील दी जाती है कि यह इन्फ्लेक्टेड बिल है, और इसमें कोई भी ऐसा प्राविजन नहीं है जिससे जनता को नुकसान पहुंच सके तो में यह अर्ज करूंगा कि आजाद साहब ने खुद ही इस बिल के ज्यादातर प्राविजन पर एतराज किया है। यह बात दूसरी है कि अगर कांग्रेस पार्टी के सदस्य इस बिल की आलोचना करें, इस पर एतराज करें तो उसे एतराज न समझा जाये और अगर अपोजीशन के सदस्य किसी चीज पर भी एतराज करें तो उसे गैर ज़रूरी एतराज समझा जाये। उन्होंने खुद कई ऐसी चीजें बतलाईं कि वह चाहते हैं कि इन पर ज्यादा गौर किया जाये। श्री राजा राम जी ने बार-बार इस बात को कहा है कि अगर हम इसे सेलेक्ट कमेटी को देते हैं तो इसके अन्दर जो बहुत सी गलतियाँ हैं वह दूर हो जावेंगी और आसानी से बिल पास हो सकेगा। में समझता हूं कि यह बहुत जो सज्जन हैं और सहानुभूति के साथ इस पर विचार किया जाना चाहिये। अभी डा० वृजेन्द्र स्वरूप साहब ने अपनी तक्रारी में कई बातें ऐसी बताईं जो इस बिल के अन्दर रखी जानी चाहिये थीं, और जो नहीं रखी गई। जो ओमीशंस उन्होंने बतलाये उन पर अभी विचार किया जाना चाहिये। अगर हम यह क्या करें कि इन ओमीशंस पर विचार करने की ज़रूरत इसलिये नहीं है कि सरकार नया बिल लाने वाली है तो यह भी माकूल बात नहीं है।

सरकार के सेक्रेटेरियेट में जो अभी तक काम करते रहे हैं उनसे हरगिज इस बात की उम्मीद नहीं की जा सकती है कि वह दूसरा बिल बहुत जल्दी ला सकती है। उस अमेंडमेंट की बिना पर इस बिल को सेलेक्ट कमेटी में रिफर किये जाने से रोकना, जनता के साथ अनुचित व्यवहार होगा। जिन सज्जनों ने पिछली लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की रिपोर्ट को पढ़ने की कोशिश की है उनको मालूम है कि उस कमेटी ने बहुत जोर दिया है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जो रूकशन इस वक्त है वह बहुत हद तक सीमित है उसको बढ़ाना चाहिये। हमारे मुल्क की तरक्की के लिये एक बुनियादी चीज है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को बढ़ाये और उनके ऊपर बहुत सी चीजें छोड़ दें। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जैसे काटेज इंडस्ट्री और एजुकेशन। ये चीजें हमारी रोजमर्रा की ज़िन्दगी से ताल्लुक रखती हैं। चूंकि उन्होंने सिपारिश की है अगर ये चीजें बोर्ड के अन्दर दे दी जाती हैं तो हमारा जीवन सुखी हो सकता है। खास तौर से इस सूरत में ज़रूरी है कि यह बिल सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाय। वहां इन बातों के ऊपर विचार किया जाय। यह बात बहुत आवश्यक है और यह बहुत बहस तलब नहीं है। सेलेक्ट कमेटी जो सिपारिश करे वह इस बिल के अन्दर इनकारपोरेट की जा सकती है। यह बिल जो हाउस के अन्दर है इससे मुफीद बिल आ सकता है। अभी परसों की बात है मैं एक कांग्रेस पार्टी के सदस्य के साथ बैठा हुआ था और बातें कर रहा था। उनमें से एक सज्जन ने कहा कि बहुत सीधे स्वभाव से कि समझ में नहीं आता कि हम इस गुलामी को कहां तक मार पाये। ज्यादा से ज्यादा अहम बिल जो कि हमारी रोजमर्रा की ज़िन्दगी से ताल्लुक रखता है वह हाउस के अन्दर आ जाता है और पार्टी के अन्दर नहीं आता है। पार्टी का जो कुछ भी उसूल हो वह इस सदन के लिये और कम से कम हमारे लिये कोई ऐसी बहस और मुबाहिसे की चीज नहीं है। मेरा हक नहीं है कि मैं उसको छोड़ूं और उस पर अपना विचार प्रकट करूं।

श्री मोहन लाल गौतम—माननीय मेम्बर जो कुछ कह रहे हैं वह प्राइवेट बात है और इर्रेलेवेन्ट है।

श्री कन्हैया लाल गुप्त—मैं जो कुछ कह रहा हूं वह सेलेक्ट कमेटी को रेफर करने से ताल्लुक रखता है। मैंने जो कुछ कहा है वह एक ऐसी चीज है जो इस सदन के सदस्यों से ताल्लुक रखती है। मैं नहीं जानता कि वह इर्रेलेवेन्ट है। यदि ऐसा है और

[श्री कन्हैया लाल गुप्त]

आप उसे इर्रैलेवेंट करार दें तो मैं उसको यहीं खत्म करता हूँ। यहां पर स्थिति ऐसी है कि मेम्बरों को खुद इस हालत पर विचार करने का मौका नहीं मिलता है। सेलेक्ट कमेटी में यह बिल रैफर कर दिया जाय तो जरूर मौका मिल सकेगा। मैं इस बिल के प्राविजन के ऊपर कुछ बातें अर्ज करना चाहता हूँ।

पहली बात सेक्शन नाइन के अन्दर कही गयी है कि किसी भी बोर्ड के अन्दर मेम्बरों की तादाद १५ से कम और ५० से ज्यादा न हो। यह अच्छी चीज है। श्रीमती शिवराजवती ने कहा है कि उसके अन्दर स्त्रियों को अलग से प्राविजन होना चाहिये। स्त्रियों के लिये प्राविजन करना खास नुकत्येनजर से जरूरी है। माननीय मंत्री जी ने कहा है कि स्त्रियों की मांग का मामला मद्रास गवर्नमेंट से आ गया है। मद्रास हाई कोर्ट के सामने ऐसी चीज आ गयी है इसलिये शायद उन्होंने सोचा है कि ऐसा कोई प्राविजन न किया जाय जिससे कोई दिक्कत हो जाय। शायद इसलिये उन्होंने प्राविजन नहीं किया। अगर ऐसी बात है तब तो लाचारी है और कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन अगर कोई लाचारी नहीं है तो मैं उनसे दरखास्त करूंगा कि इस बात पर विचार करने का कि अभी तक जो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड क्लास की म्युनिसिपैलिटीज हैं उनमें वीमेन मेम्बर के रखने का जहां तक ताल्लुक है उसको इसी प्रकार चलने दिया जाय या नहीं, क्योंकि अभी तक हमारी स्त्री समाज की ऐसी स्थिति नहीं है कि वह स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ कर आ सकें। म्युनिसिपैलिटीज ही एक ऐसा रास्ता है जिसमें वह आदर्शियों के साथ बैठ कर काम कर सकती हैं और आगे बढ़ने के लिये कोशिश कर सकती हैं। अगर उनको नहीं रखा जाता है और यह चीज खत्म कर दी जाती है तो, उनके लिये बोर्ड में आना बहुत मुश्किल हो जायेगा। बोर्ड में बहुत से ऐसे फंक्शन होते हैं जिनमें मिडवाइच्च वगैरा काम करती हैं और उनके लिये औरतें जितनी अच्छी तरह से सलाह दे सकती हैं, सर्व उतनी अच्छी तरह से नहीं दे सकते हैं। इसलिये मैं दरखास्त करूंगा कि उनके रखने के लिये प्राविजन किया जाय। यह बहुत इम्पार्टेंट है।

दूसरी बात यह है कि यह तादाद तो फिक्स की गई, इसके लिमिट्स तो बतलाये गये हैं लेकिन यह नहीं बतलाया गया कि किस म्युनिसिपल बोर्ड में कितने मेम्बर हैं तथा सरकार किस प्रकार से इस बात को तय करेगी। इसमें हो सकता है कि बहुत ही आरबीट्रेरी ढंग से तादाद मुकर्रर की जाय और वह प्रोपोरशन में न हो। इसलिये यह अच्छा होता कि अगर इस सेक्शन के अन्दर यह भी बतलाया गया होता कि किस तरह से डिफरेंट क्लासेज में या डिफरेंट साइजेज में रेगुलेट किया जायगा।

इसके बाद दूसरी चीज यह है कि बोर्ड की लाइफ का ऐक्सटेन्शन, सातवें क्लाज के अन्दर दो साल का रखा गया है। मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि इसको एक साल की होना चाहिये क्योंकि मैं यह नहीं देखता हूँ कि दो साल रखने की क्या जरूरत महसूस हो रही है। हमें मालूम है कि अमेरिका के प्रेसीडेंट का एक टर्म मुकर्रर है और उसी के अन्दर हमेशा इलेक्शन हो जाया करता है। अभी जब लड़ाई चल रही थी तो वहां पर एडल्ट सफरेज की बेसिस पर इलेक्शन हुआ था। मेरे ह्याल में ऐसी कोई सुरत नहीं मालूम होती है कि २ साल का ऐक्सटेन्शन रखा जाय, अगर जरूरत हो तो उसे एक वर्ष के लिये रखा जा सकता है। मेरी समझ में यह बात नहीं आती है कि क्यों २ साल का रखा जा रहा है।

इसके बाद मैं माननीय मंत्री का ध्यान ६ पृष्ठ पर १३ (डी) में सब-क्लाज (ए) की तरफ आकर्षित करूंगा।

श्री मोहन लाल गौतम—यह जेनरल डिस्कशन है। क्लाजवाइज तो कल होगा।

श्री कन्हैया लाल गुप्त—अभी हम अमेंडमेंट ला नहीं पाये हैं। अध्यक्ष महोदय, अभी हम अमेंडमेंट्स नहीं दे पाये ।

श्री मोहनलाल गौतम—जब यह क्लोज आयेगा तब उस पर डिस्कशन हो जायेगा । अभी आप जेनरल डिस्कशन कर लीजिये ।

श्री कन्हैया लाल गुप्त—लेकिन मुझे तो जहां तक याद है कि मिनिस्टर साहब ने कहा था कि क्लोज बाई क्लोज डिस्कशन होना चाहिये ।

श्री मोहन लाल गौतम—मैंने प्वाइंट बाई प्वाइंट कहा है ।

श्री कन्हैया लाल गुप्त—इसमें जो डिसमिस्ड गवर्नमेंट सर्वेंट को डिसक्वालिफाई किया गया है वह रीजनेबल नहीं है । वह बेचारा गवर्नमेंट सर्विस से तो गया ही, साथ ही सिटिजनशिप के राइट्स भी खो बैठता है । इसके अन्दर यह कहा गया है कि २७ और ४१ के अन्दर जो डिसक्वालिफाई होंगे, तो और जगह तो कोई मियाद रखी भी गई है कि कोई व्यक्ति ४ या ५ साल के लिये डिसक्वालिफाई होगा, लेकिन वह बेचारा गवर्नमेंट सर्वेंट हमेशा के लिये डिसक्वालिफाई हो जाता है । हो सकता है कि कोई व्यक्ति ब्रिटिश टाइम में डिसमिस्ड हो गया हो तो वह अब भी जब कि हमारी अपनी गवर्नमेंट है तब भी वह डिसक्वालिफाई ही रहेगा ।

दूसरी चीज यह है कि आनरेरी मैजिस्ट्रेट को भी डिसक्वालिफाई किया गया है । मैं नहीं समझ सका कि उनको क्यों डिसक्वालिफाई किया गया है । उनके लिये यह हो सकता था कि वह अपनी म्युनिसिपैलिटी की हद तक मुकदमें नहीं कर सकते । दूसरी एक बात है जिसकी बाबत काफी कहा गया है कि मेम्बरों का हिन्दी पढ़ना लिखना जरूरी समझा गया है । यह है तो अच्छी बात लेकिन जब तक लिट्रेसी प्रोग्रेस अच्छी नहीं है तब तक उसके हिसाब से अभी तीन या चार साल इसको नहीं लाना चाहिये था । जब लिट्रेसी ड्राइव अच्छा हो जाता तब इसको लाते तो ठीक था । एक बात यह है कि जो आजकल हमारे नौजवान पढ़कर निकलते हैं उनसे हमारे बुजुर्ग जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो कि म्युनिसिपैलिटीज के मेम्बरों रह चुके हैं उनकी सूझ बूझ, उन नये ग्रेजुएट नवजवानों से कहीं अच्छी है । पार्लियामेंट या असेम्बली के अन्दर अगर यह कहा जा सकता है कि वह ज्यादा खतरनाक नहीं हो सकते हैं क्योंकि ज्यादा से ज्यादा यह हो सकता है कि वह अपनी कांस्टीट्यूएन्सीज को अच्छी तरह से न रिप्रेजेंट कर पायें और यह ज्यादा खतरनाक बात नहीं होगी । इसी तरह से यह भी हो सकता है कि म्युनिसिपैलिटीज का वह मेम्बर ज्यादा खतरनाक नहीं साबित हो सकता जो कि पढ़ा लिखा न हो क्योंकि ज्यादा से ज्यादा यह हो सकता है कि वह अपने वार्ड को जहाँ से वह चुन कर आया है ठीक तरह से रिप्रेजेंट न कर सके । जब तक हमारी लिट्रेसी परसेंटेज बहुत कम है कम से कम तब तक के लिये यह मुल्तवी हो जाना चाहिये ।

इसके बाद मैं दूसरी चीज डिसक्वालिफिकेशन के सिलसिले में कहना चाहता हूँ कि १३ (ई) के (५) में यह है कि अगर कोई पुलिस की कस्टडी में है तो वह मेम्बर नहीं हो सकता है । यह बहुत से लोगों के लिये नुकसानदेह बात है । मैं इस बात को जानता हूँ कि आजकल जो इलेक्शन होते हैं उसमें एक पार्टी दूसरी पार्टी के खिलाफ बहुत ही गलत प्रोपेगन्डा करती है । अभी अभी माननीय राजाराम जी ने जो बातें कही हैं, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता हूँ । हमें यह बात मालूम होती है कि हमारे यहां बहुत से ऐसे आदमी हैं जिनकी आत्मा के विरुद्ध अगर काम होता है तो वह किसी हद तक कुछ भी करने के लिये तैयार हो जाते हैं । परन्तु बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो गलत बातों के खिलाफ सत्याग्रह या आंदोलन करते हैं तो उनको जेल में भेज दिया जा सकता है । ऐसे लोगों को कम से कम मौका दिया जाय कि वे इस इलेक्शन में भाग ले सकें । अगर यह क्लोज यहां पर रहेगी तो उनके खिलाफ पड़ेगा और फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक पार्टी के लोग दूसरी पार्टी के लोगों के प्रति किसी तरह से आफिशियल्स के साथ मिल कर उनको कस्टडी में ला सकते हैं । अगर इस

[श्री कन्हैया लाल गुप्त]

सेन्टेंस (sentence) को हटा दिया जाय तो में समझता हूं कि ज्यादा अच्छा होगा। इस के बाद जहां पर क्लोज १३ (१) में प्राविजन किया गया है कि अगर किसी मेम्बर की वेंकेंसी होती है तो उसका एक साल के अन्दर ठम डिटरमिन होगा। और वह पूरी नहीं की जा सकती। पहले एक साल के बजाय ६ महीने का पीरियड था, में नहीं जानता कि यह एक साल का क्यों किया गया है जब कि दो साल तक आप बोर्ड की लाइफ को एक्सटेन्ड करने जा रहे हैं। जब वह जानते हैं कि एक साल या ६ महीने के अन्दर इलेक्शन होने वाले हैं तो फिर क्या होगा। जब वह देखते हैं कि किसी दूसरी पार्टी का मेम्बर इस वक्त वहां पर जोर में है तो इलेक्शन को टाल देते हैं। नतीजा यह होता है कि कितने ही साल तक के लिये सीट खाली पड़ी रहती है। मुझे अपने शहर के अन्दर की बात मालूम है। तीन चार साल तक सीटें इस तरह से खाली रही हैं। इससे बड़ा भारी नुकसान होता है। जनता चाहती है कि हमारा अच्छा आदमी बोर्ड में जाये, लेकिन वे नहीं चाहते हैं कि यह आदमी जाये इसलिये इलेक्शन नहीं करवाते हैं और इस तरह से सीट खाली पड़ी रहती है। इसलिये मेरी राय है कि इसमें ६ महीने का वक्त रखा जाय तो ठीक होगा। इसके बाद उपाध्यक्ष महोदय, में ज्यादा नहीं कहूंगा। चेयरमैन की क्वालीफिकेशन के बारे में भी कहा गया है। में समझता हूं कि माननीय मंत्री जी ने इसके बारे में जो कुछ कहा है उसमें कुछ तथ्य न हो, यह बात नहीं है। जिन लोगों ने कहा कि यह गैर जरूरी है, में उनसे इत्तिफाक नहीं करता हूं। इसलिये कि चेयरमैन का काम ऐडमिनिस्ट्रेटिव है। यदि वह निरक्षर होता है तो बहुत खराबी हो सकती है लेकिन जो क्वालीफिकेशन हाई स्कूल की रखी है वह ठीक नहीं है। इसके साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि इसके एक्वेविलेन्ट की क्वालिफिकेशन भी हो सकती है। में तो यह समझता हूं कि इसके बजाय यह कर दिया जाय कि अगर किसी खास देश में सरकार समझती है कि इसको क्वालीफिकेशन पूरी नहीं है तो उसको परमिट कर सकती है। इतनी ताकत सरकार अपने हाथ में रख ले तो ज्यादा अच्छा होता। लेकिन में समझता हूं कि गवर्नमेंट अपने हाथ में हाईस्कूल या एक्वेविलेन्ट चीज को रखना चाहती है। लेकिन इससे यह होगा कि जो लोग न तो हाईस्कूल पास हैं या न उनके पास इसके एक्वेविलेन्ट का ही सर्टिफिकेट है वे इससे महरूम हो जायेंगे। इसलिये में समझता हूं कि यह क्लोज अमंड किया जाना चाहिये ताकि सरकार ऐसे लोगों को भी परमिट कर सके जो कि इसके लायक हों। अब इसके बाद चेयरमैन के सस्पेंशन का सवाल आता है, इसके लिये इसमें एक क्लोज है। माननीय मंत्री जी ने इसके लिये एक उदाहरण भी दिया है कि एक शास्स इम्बेजिलमेंट करता है और वह उस वक्त तक नहीं पकड़ा जाता है जब तक कि वह दो या तीन दफा तक इम्बेजिलमेंट न कर ले। इस तरह की भी खराबियां हो सकती हैं। में समझता हूं कि इस तरह की बातें ठीक नहीं हैं उन को दूर ही करना चाहिये। जहां तक पावर का सवाल है उसके बारे में यह भी कहा जाता है कि उसका मिसयूज भी हो सकता है। एक तो बात यह है कि आज कल पार्टीबन्दी का भी बहुत जोर है। निर्दोष चेयरमैन को भी सजा मिल सकती है। आज कल एम० एल० ए० और एम० एल० सी० का युग है, वह लोग सरकार के पास आसानी से पहुंच सकते हैं। वह लोग मिनिस्टर साहब के आसानी से कान भर सकते हैं। ऐसी सूरत में निर्दोष आदमी को भी सजा मिल सकती है। अगर यह कहा जाय कि सस्पेंशन कोई सजा नहीं तो में इस बात को भी नहीं मानता हूं। जहां तक मुझे याद है क्लासीफिकेशन आफ कंट्रोल ऐंड अपील रूल्स में दिया हुआ है कि सस्पेंशन भी एक सजा है। सस्पेंशन से उस आदमी की इज्जत भी नहीं रहती है, जनता में काफी बदनामी हो जाती है और लोग उसको एक खराब निगाह से देखने लगते हैं। इसलिये ऐसी हालत में कोई दूसरा तरीका निकालना चाहिये। इसमें अगर कोई ऐसा प्राविजन हो सकता है कि सस्पेंशन न किया जाय तो उन लोगों के साथ न्याय होगा। इसके बाद मैं यह भी कहूंगा कि इस बिल को सेलेक्ट कमेटी में ले जाने की जरूरत है। सरकार को ऐसा

सूरीका अख्तियार करना चाहिये जिससे जनता का फायदा हो और उसको किसी तरह की कठिनाई न पड़े। मैं आशा करता हूँ कि सरकार हर बात को देखभाल कर, करेगी ताकि किसी तरह की कोई परेशानी न हो। सरकार जो पावर बोर्ड को दे उसका भी प्रयोग ठीक तरह से हो।

एक बात माननीय निजामुद्दीन साहब ने कही थी कि सस्पेंशन अगर नहीं होगा तो नतीजा यह होगा कि चेयरमैन पर कन्ट्रोल नहीं रहेगा और फिर वह किसी की भी परवाह नहीं करेगा। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बोर्ड में जो इम्प्लाइमेंट की शिकायतें हुईं उनमें से ६० परसेन्ट कोसेज छूट गये। यह बात जो उन्होंने कही है वह खूब ही इस सस्पेंशन के खिलाफ है। इसका मतलब यह है कि सी में से ६० चेयरमैन को अगर सस्पेंड कर दिया गया होता जो कि निरपराध होते और उनकी हालत यह होती कि उनको खामएवाह ही डंड दिया जाता तो उनकी जो बलील है वह स्वयं ही सस्पेंड न करने के पक्ष में है। इसके बाद प्रोसीडिंग्स को अखबारों में छापने की बात हुई। यह मैं कहता हूँ कि बहुत ही सुन्दर विचार है लेकिन यह भी कहा गया कि नये अखबार न निकाले जाय और ऐसी कोई प्रोसीडिंग्स उनके ऊपर नहीं छपी जायेंगी। बोर्ड की प्रोसीडिंग्स छपने से जनता को काफी फायदा होगा और उसको भी बोर्ड के विचार मालूम होने रहेंगे और दूसरी तरफ सेंवरों को भी डर रहेगा कि वह कोई गलत बात न कर बैठें। इसमें यह लिखा हुआ है कि लोकल पेपर में प्रोसीडिंग्स निकाली जाय या जो भी उचित समझा जाय उसमें निकाली जाय। मैं नहीं समझता कि गवर्नमेंट को किसी प्रकार का प्रतिबन्ध लगाना चाहिये। एक बात यहां पर और अर्थ कर्हंगा और वह यह है कि अब तक ऐसे नियम थे और जो सन् १९१६ का ऐक्ट है उसके मातहत एक्जीक्यूटिव आफिसर्स को छोड़ कर बाकी जो दूसरे प्रकार के आफिसर्स हैं जिनका कि सेक्शन २७ में जिक्र किया गया है उनको बोर्ड ऐसे रेजोल्यूशन से पतिश कर सकता था लेकिन अब २८ (२) के अन्दर और ६६ (२) जो ठीक किया गया है, उसके अन्दर गवर्नमेंट ने सारी ताकत अपने पास ले ली है। सेक्शन २७ के अन्दर जिन आफिसर्स का जिक्र किया गया है उनकी बाबत बोर्ड जो कुछ भी रेजोल्यूशन करे उसके खिलाफ अपील अब सरकार चुन सकेगी और बोर्ड का जो भी डिसेशन है उनको आल्टर कर सकेगी। मैं समझता हूँ कि यह एक ऐसी चीज है जो कि बोर्ड की वर्किंग को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने वाली है, उसका नतीजा यह होगा कि जितने भी आफिसर्स हैं अगर बोर्ड उनको किसी प्रकार भी सजा देती है तो वह सबजेक्ट टू रिवीजन आफ गवर्नमेंट है जिसका बहुत बुरा नतीजा होता है। अगर कोई आफिसर यह समझता है कि उसकी अपारिटी बोर्ड नहीं है तो वह बहुत बुरा बोर्ड के कन्ट्रोल में ठीक तरह से नहीं रहेगा। बाकी एक्जीक्यूटिव आफिसर्स के लिये जो प्राविजन था वह ठीक था लेकिन उसकी भी ज्यादा अच्छी शकल इनक्वायरी कमेटी के अन्दर बतलाई गई है और वह यह थी कि कुछ कैडर आफ सर्विस की ट्रांसफरेंसिलिटी होनी चाहिये यानी वह एक बोर्ड से दूसरे बोर्ड में ट्रांसफर किये जा सकें। मैं समझत हूँ कि वह एक ऐसा प्राविजन था जो कि बहुत जरूरी था। अगर यह किया गया होता तो ज्यादा अच्छा रहता। अब मैं कुछ म्युनिसिपल इम्प्लाइज एसोसियेशन का अध्यक्ष होने के नाते और कुछ दिनों से इस बात का तजुर्बा रखते हुये यह कहना चाहता हूँ कि म्युनिसिपल इम्प्लाइज की क्या क्या मुसीबतें हैं। ऊंचे से ऊंचा म्युनिसिपल इम्प्लाइ किस प्रकार से अपनी नौकरी की बाबत डर में रहता है और किस प्रकार, पार्टीबाजी के अन्दर पड़ कर वह अपना काम नहीं कर पाता है तो इसका इलाज ट्रांसफरेंसिलिटी आफ सर्विस है। उनको यह मौका देना कि वह गवर्नमेंट के पास अपील कर सकते हैं तो इसका नतीजा यह होगा कि वह बोर्ड के कन्ट्रोल में नहीं रह सकता है।

इसके बाद एक, दो, बातें कह कर मैं अपना वक्तव्य खत्म करूंगा। एक बात यह है कि एनीमल्स पर जो कि बाहर से शहर या बस्ती में आते हैं, उन पर आक्रांय लगेगा। मैं सरकार से दरखास्त करूंगा कि वह इस बात पर विचार करे कि इससे, जो जानवर किसी हाट

[श्री कन्हैया लाल गुप्त]

या मेल में आते हैं, उन लोगों के लिये कितना नुकसान हो सकता है। मेरा ह्याल यह है कि इसमें जो यह प्रावीजन रखा गया है, तो इस तरह से उन लोगों के लिये जो कि जानवर लाते हैं, बड़ी मुश्किलें पैदा हो जायेंगी क्योंकि वे लोग अपने जानवर बहुत दूर-दूर से लाते हैं और अगर वहां वे उनको न बेच सकें, तो ऐसी हालत में भी उनको आकट्टाय देना पड़ेगा और जबकि उसे देने में वे काफी एतराज करेंगे और इस तरह से बहुत मुश्किलें पैदा हो जायेंगी। इस निवेदन के बाद में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, और सब बातों के लिये सरकार को बधाई दूंगा। उसने ऐंडहाक कमेटी के विधान का अधिकार लिया है, तो वह बहुत अच्छी बात है और उनसे निश्चित सिफारिशें होंगी। लेकिन मेरा अपना ह्याल यह है कि यह बिल अगर सेलेक्ट कमेटी में जाता तो वह इस पर अपनी ऐसी सिफारिशें करती जो कि इस बिल के उपयोग को और भी बढ़ा देते और इसकी वजह से मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा प्रबन्ध बहुत आसानी से किया जा सकता था।

श्री प्रेम चन्द्र शर्मा (स्थानीय संस्थाएं निर्वाचन क्षेत्र)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जो विधेयक सदन के सामने रखा गया है, सब लोगों ने उसका स्वागत किया है, लेकिन कुछ लोगों का ऐसा विश्वास था और कुछ लोग ऐसी आशा रखते थे कि स्थानीय स्वशासन विभाग में इसके द्वारा कुछ रेडीकल चेंजेज होंगे और कुछ लोग यह भी आशा लगाये थे कि ट्रैफिक आदि की जो भी चीजें हैं, उनमें भी कुछ इम्प्रूवमेंट होंगे और कुछ सुझाव रखे जायेंगे। कुछ का ह्याल यह भी था कि इससे ऐडमिनिस्ट्रेशन में काफी सुधार होंगे। माननीय मंत्री महोदय ने इसके बारे में यह बतलाया है कि इसके लिये जो कुछ भी आवश्यक और बड़ी तरमीमें होंगी, उसके लिये फिर यहां एक बिल लाया जायेगा और वह माननीय सदस्यों के सामने आयेगा। तब सदन को यह अधिकार होगा कि वह उस पर अपने संशोधन रखे। इसमें जो बात सेलेक्ट कमेटी की बाबत कही गयी कि इसको वहां भेजा जाना चाहिये, तो मैं कहता हूं कि माननीय सदस्यों को इसके लिये काफी समय मिला है कि वे इस पर यदि चाहते तो अपने संशोधन रख सकते थे और उनका यह कहना कि अधिक समय भी नहीं मिला, ग़लत है। वे जो कुछ भी तरमीम अपने ह्याल से उचित और आवश्यक समझते थे उसको इतने समय में ला सकते थे और उनकी दलील इस मामले में आज सही नहीं उतरती है क्योंकि उनको ३ दिन का समय मिला और इस विधेयक पर यदि वे चाहते तो संशोधन ला सकते थे। माननीय सदस्य यह नहीं कह सकते हैं कि उनको संशोधन देने का समय नहीं मिला इसलिये इस बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाय और उन्होंने समय के अभाव के कारण यहां संशोधन पेश नहीं किये। मैं कहता हूं कि यह तो आज फर्स्ट रीडिंग चल रही है और यदि वे चाहते तो आज भी अपने संशोधन १० बजे तक दे सकते थे। जैसा कि आज फर्स्ट रीडिंग हो रही है तो वे कल को भी अपने संशोधन ला सकते हैं और इस तरह से सेलेक्ट कमेटी में जो बात होती वे यहां अपने संशोधन द्वारा उसको पेश कर सकते हैं और माननीय मंत्री जी अवश्य ही उन पर विचार करेंगे। इस बिल को इस वक्त सेलेक्ट कमेटी में रखने की जो बात है वह उपयुक्त नहीं है। दूसरी बात जो सदन में वादविवाद का विषय बनी, वह यह है कि इस में जो प्रावीजन किया गया है कि प्रेसिडेंट के लिये मिनिमम क्वालिफिकेशन कर दी जाय, तो मैं समझता हूं कि जहां तक इस का सम्बन्ध है, इसमें सिवाय एक माननीय मेम्बर के और सभी ने चाहे वह ट्रेजरी बेन्चेज की तरफ से हों या अपोजीशन की तरफ से हों, इस बात का विरोध किया है कि कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन उसके लिये प्रिसक्राइब किया जाय।

(इस समय ४ बजकर २५ मिनट पर चेयरमैन ने सभापति का आसन ग्रहण किया।)

श्री प्रेम चन्द्र शर्मा—जैसा कि अपना उसूल रहा है और योग्यता का एक पैमाना है, उसमें यह ध्यान दिया गया है कि एक व्यक्ति की समाज के प्रति कितनी सेवा है और जनता के लिये कितनी सेवा की है

न कि उसकी ऐकेडेमिक क्वालीफिकेशन क्या है। यह एक खास पैमाना था और आज भी बहुत से ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं जो काबिल हैं और उनकी ऐकेडेमिक क्वालीफिकेशन ज्यादा नहीं है बहुत से लोगों ने उदाहरण पेश किये हैं उनकी बराबरी कोई नहीं कर पाया है। मुझे स्मरण है कि संविधान बनते समय एक सदस्य ने कहा था कि माननीय सदस्य लेजिस्लेचर के लिये कोई क्वालीफिकेशन नियत कर दी जाय उस पर माननीय प्रधान मन्त्री जी ने कहा था कि हम इस तरह की कोई क्वालीफिकेशन प्रिस्क्राइब न कर सकेंगे, हमारा ध्येय यह है कि हम देखें कि किसने कितनी ज्यादा सेवा जनता और समाज की है। इस पर एक माननीय सदस्य ने मञ्चा के तौर पर यह रखा था "Do you mean to say that this Parliament should be a body of idiots." इस पर माननीय प्रधान मन्त्री ने कहा "If the electorates so desire it should be a body of idiots and its leader should be the greatest idiot" यह उनकी भावना का प्रतीक है। क्वालीफिकेशन का मतलब यह है कि किसकी कितनी सेवा है। क्वालीफिकेशन का मैं भी विरोध करता हूँ उस पर एक दलील दी गई कि जो अंग्रेजी पढ़े लिखे नहीं होते हैं वह ग़ज़तफ़हमी में दस्तख़त कर बेते हैं। मैं समझता हूँ कि हमारी राज्यभाषा हिन्दी हो चुकी है इसलिये अंग्रेज़ी का प्रश्न नहीं उठता है।

एक चीज़ इसमें है वह अक्काय के सम्बन्ध में कहा गया है कि ऐसा होता था कि रिफण्ड-एबिल अक्काय थी तो उसमें काफी रुपया जमा होता था, मान लीजिये ३५ लाख जमा हुआ और रिफण्ड हुआ ३० लाख तो इस तरह से यह होता था कि कागज़ात की कार्यवाही होती थी और एकाउन्ट बगैरह और आडिट बगैरह का खर्च देना होता था और कोई खास फायदा नहीं होता था। इनमें एक प्रावोजन यह भी रखा गया है कि प्लेतेज आफ वॉशप के नज़दीक सिनेमा हाउसेज नहीं बनाये जायेंगे। इसमें एक दलील दी गई कि एक प्लेस है वॉशप की लेकिन सिनेमा वाले कहते हैं कि नहीं है और सिनेमा बन जाता है तो इस तरह से कोई रोक नहीं सकता है। मैं समझता हूँ कि अगर कोई ऐसा क़ैस आ जाय तो ग़ौर कर लिया जाय और इस तरह से अमेन्डमेन्ट करना उचित नहीं है। माननीय सदस्य श्री गुरुनारायण जी ने सस्पेंशन और रिमूवल के सम्बन्ध में कहा है कि उनको वॉरिंग और एक्सप्लेनेशन के सम्बन्ध में मौका दिया जाय मैं समझता हूँ कि जो पहले का अमेन्डमेन्ट है उसमें यह साफ है कि एक्सप्लेनेशन लिया जायेगा और उनके साथ अन्याय नहीं किया जायेगा। श्री राजा राम जी ने मज़दूरों के रिजर्वेशन के बारे में कहा, मैं समझता हूँ कि विधान में यह नहीं है इसलिये वह नहीं हो सकता है, एक बात और कही गई है, वह यह है कि स्त्रियों के रिजर्वेशन के बारे में यह भी नहीं हो सकता है। चेयरमैन या प्रेसीडेंट के चुनाव के बारे में कहा गया है कि पोलिटिकल पार्टीज़ का कोई हाथ नहीं होना चाहिये। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। इन्डिपेन्डेंट कैंडिडेट्स के बारे में प्रधान मन्त्री जी ने कहा है कि उनका कोई ध्येय नहीं है, उनकी कौम एक निकम्मा कौम है। आज का ज़माना पोलिटिकल पार्टीज़ का है। एक बात एक्ज़ोक्लूटिव आफ़िसर्स के लिये है कि उनकी सर्विस प्राविन्शियल हों। यह दरअसल सोचने वाली चीज़ है और कई एक सुझाव दिये भी गये हैं और माना भी गया है। लेकिन इस मौजूदा अमेन्डमेन्ट में ऐसा नहीं आया है। मैं इस बात की आशा करता हूँ कि इस तरीक़े का कोई विधेयक सरकार की तरफ से अवश्य आयेगा और उनकी सर्विस प्राविन्शियलाइज़ की जायेगी। इन शब्दों के साथ जो विधेयक हाउस के सामने रखा गया है, उसका समर्थन करता हूँ और सेलेक्ट कमेटी की बाबत जो प्रस्ताव रखा गया है उसका विरोध करता हूँ।

श्री विश्वनाथ (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चंद शब्दों के साथ इस विधेयक का समर्थन करता हूँ। भाई राजा राम जी ने कुछ बातें कही हैं जिन में दो एक बातों की चर्चा मैं करूँगा। उन्होंने बताया है कि सन् ४६, ४७ की सरकार ने और सन् ३७, ३८ की सरकार ने म्युनिसिपैलिटीज़ के अन्दर सुधार करने के लिये एक रिपोर्ट तैयार की थी। उन रिपोर्टों के बावजूद भी उनमें उल्लिखित बातों का ख्याल नहीं किया गया और जल्दी में यह विधेयक ला दिया गया। उसके विषय में मुझे यह निवेदन करना है कि सेलेक्ट कमेटी समय को बेख़तरे हुये रिपोर्ट तैयार करती है। लेकिन समय इतनी तेज़ी से आगे बढ़ता जा

[श्री विद्वानाय]

रहा है कि कभी कभी ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि पीछे दो हुई रिपोर्टों का बहुत ज्यादा ख्याल न किया जाये। मुझे दो तीन बातें इस विषय में याद हैं कि सन् ३७, ३८ को कांग्रेस सरकार ने टेनेन्सी ऐक्ट बनाया था उसमें ढाई सौ तक के मालगुजारी में सीर सुरक्षित रखी गई थी लेकिन आज जमींदारी उन्मूलन और भूमि व्यवस्था बिल में क्या हुआ है यह आप सभी को भली भांति मालूम है। फिर सन् ४८ में जो सेलेक्ट कमेटी बनी थी उसने बड़ी लम्बी रिपोर्ट लिखी। परन्तु आज आप देखें जो ऐक्ट बना है उसमें और उस रिपोर्ट में कितना बड़ा अन्तर है। अतः दिन प्रति दिन समय बदलता है, तथा जनता का रुख बदलता है और शासन का अनुभव जैसे-जैसे बढ़ता जाता है उसी तरह से वह रिपोर्ट पीछे पड़ती जाती है। भाई राजा राम जी ने मजदूरों की बात कही कि मजदूरों का प्रतिनिधित्व सुरक्षित होना चाहिये। उसके विषय में मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि पहली कठिनाई तो वह है जैसा कि पूर्व वक्ता महोदय ने बतलाया है भारतीय विधान की बात लेकिन अगर उस को थोड़ी देर के लिये गैर ज़रूरी भी मान लिया जाये तो भी हर म्युनिसिपैलिटी में वर्गीकरण करना कि कौन-कौन मजदूर हैं, बड़ी मुश्किल बात है। इस में भी विवाद है कि शारीरिक तथा बौद्धिक मजदूरों में कौन-कौन लोग आ सकते हैं। इस दृष्टिकोण से जन-संख्या के समय गणना नहीं हुई थी जिससे उनकी संख्या के अनुपात से सीट सुरक्षित की जा सके। आज देश में अनेक जाति तथा सम्प्रदाय सम्बन्धी झगड़े, हर दिशा में देश को कमजोर और भ्रष्ट बना रहे हैं, इसी प्रकार समस्वार्थ के लोगों का अलग वर्गीकरण करना, उसी प्रकार घातक सिद्ध होगा जिस तरह आज के दिन देश की विभिन्न जातियां तथा उप-जातियां जो कभी इसी आधार पर मंगठित थीं; घातक और विनाशक सिद्ध हो रही हैं तथा देश में यह अत्यन्त जटिल और भयानक परिस्थिति उत्पन्न कर दी है। वर्ग संघर्ष में यद्यपि आज दिन कुछ लोग विश्वास करते हैं परन्तु यह वास्तव में विनाशात्मक है। इस लिये अगर आप चाहें कि उनके लिये प्रतिनिधित्व हम रिजर्व कर दें तो यह उचित नहीं मालूम देता। एक तो वर्षों से हम देखते रहे हैं, विधान सभा में देखा और यहां भी विचार होता रहा है कि शीघ्र से शीघ्र चुनाव हों और दूसरी तरफ सेलेक्ट कमेटी बैठकर उस में विलम्ब कर दिया जाये, शायद यह दो तरह की बातें समझ में नहीं आती कि किस मकसद से कही जाती हैं। जब कि स्वायत्त शासन मन्त्री ने साफ साफ बतलाया है कि बहुत बड़ा परिवर्तन इसमें किया जायेगा और इसके लिये विचार विनिमय हो रहा है। शीघ्र ही उसके लिये भी विधेयक उपस्थित किया जायेगा, और आज जल्द से जल्द चुनाव कराने के लिये ही यह विधेयक उपस्थित किया गया है।

अतः सेलेक्ट कमेटी की बात कहना असंगत मालूम देता है। भाई राजा राम तथा और कुछ सदस्यों ने जो मुलतवी के विषय में कहा है वह उचित होते हुये भी आज की स्थिति में असामयिक है। मैं तो उस विचार धारा का आदमी हूँ कि आज देश का जैसा नैतिक स्तर है उसको देखते हुये हमारे देश में अधिनायकवाद कुछ दिन के लिये ज़रूरी था और देश में बहुत से आदमी ऐसे हैं जो इस विचार धारा के हैं। वे समझते हैं कि यदि आज देश में अधिनायकवाद होता तो जो सुधार हुआ है उससे आगे हुआ होता, हम काफी आगे बढ़े होते। जब किसी देश का नैतिक स्तर ऊंचा नहीं होता है तो उस समय की जो जनता होती है वह ऐसा सोचती है जैसा कि मैंने बतलाया है। मैं मानता हूँ कि शासन का विकेन्द्रीकरण होना चाहिये। आप देखते हैं कि हो भी रहा है। पंचायत राज और म्युनिसिपल बोर्ड कायम हैं। शासन का विकेन्द्रीयकरण तेजी से किया जा रहा है। परन्तु साथ ही साथ इनमें जो खराबियां हैं उसको हमारे सोशलिस्ट भाई जोर जोर से कहते हैं। वह कहते हैं कि काफी छानबीन के साथ विकेन्द्रीयकरण हो और यह भी कहा गया कि ऊपर से देखें तो, जिनकी गलती और खराबी दिखाई दे उनको मुअत्तल कर दिया जाय। जांच के समय मुअत्तल किये बिना समुचित जांच का होना कहीं कहीं कठिन होता है, अतः यह अधिकार लेना ठीक है। एक भाई ने बतलाया है कि एक्जीक्यूटिव आफिसर को नियुक्त सरकार से हो। कहीं कहीं पर मैं देखता हूँ कि सेक्रेटरी भी पार्टीबाजी के दल दल में पड़कर अच्छी तरह से काम नहीं करते हैं। कहीं कहीं मैं देखता

हूँ कि जो सेक्रेटरी मुत्फन्नी नहीं होता है वहाँ के लोगों को अपने चंगुल में फंसाकर नहीं रख सकता या गलत काम को न करके सिर्फ अपने कर्तव्य पालन का ही ख्याल रखता है, वह सदस्यों की पाटी बाजों का शिकार बना दिया जाता है और इस तरह से उसकी जिन्दगी बर्बाद कर दी जाती है, कहीं कहीं में देखता हूँ कि वे बहुत ही मुत्फन्नी हैं, चलते पुरजे हैं, वहाँ के अधिक से अधिक सदस्यों को अपने जाल में फंसाये रखते हैं और अपने मतलब के लिये गृहित कार्य भी करते हैं। जब ऐसी स्थिति है तो सरकार को इनको अपने हाथ में लेना चाहिये और इनकी नियुक्ति के तरीके में रद्दोबदल करना चाहिये। साथ ही इन्हें बर्खास्त करने का अधिकार भी सरकार को अपने हाथ में कुछ दिन के लिये लेना चाहिये।

एक बात मुझे और कहनी है। मेरे चन्द भाइयों ने जैसा कि बतलाया है कि हवालातियों को शाय देने से बंचित करना अनुचित है। इसके लिये मेरा भी यही ख्याल है।

इसके अलावा एक बात मैं बड़े जोरदार शब्दों में निवेदन करना चाहता हूँ। मैट्रिक की शिक्षा की क़ैद प्रेसीडेन्ट के लिये रखी गई है। यह पढ़ कर मुझे आश्चर्य हुआ। आज जब कि हमारे देश का एक भिन्न तथा योग्य समुदाय इस बात का समर्थन करता है कि हमारे देश की आधुनिक परीक्षा प्रणाली को ही समाप्त कर दिया जाय, तब यहाँ पर इस बात के लिये क़ैद कर देना कि मैट्रिक का प्रमाण-पत्र प्रेसीडेन्ट के लिये जरूरी है यह कम आश्चर्य में डालने वाली बात नहीं है। मैं पूछता हूँ कि क्या जो शिक्षा और परीक्षा अब है वह सत्यता, संगठन इत्यादि गुणों को देती है। मैं कह सकता हूँ कि हरगिज़ नहीं देती है। विद्या क, ख, ग, घ और ए, बी, सी, डी के ज्ञान से सम्बन्धित नहीं है बल्कि विद्या एक भिन्न वस्तु है और लिखना पढ़ना एक भिन्न वस्तु है। विद्योपार्जन करने के अनेक साधनों में यह भी एक साधन मात्र है। यह शिक्षा जो आजकल दी जा रही है यह वास्तव में विद्या नहीं है और इस चीज़ को लेकर आज देश में एक तूफान मचा हुआ है। आज लोग इस बात पर विचार कर रहे हैं कि शिक्षा में आमूल परिवर्तन किया जाय, ताकि इसमें जो खराबी है वह न रहे और वास्तव में विद्या प्राप्त हो। जब तक ऐसा प्रश्न है, ऐसी बात है और शिक्षा की योग्यता इस बात पर निर्भर नहीं करती है तब तक मैट्रिक की क़ैद लगाना शायद ठीक नहीं है। इसलिये जरूरी है कि इसमें संशोधन हों। मैं इन्हीं शब्दों के साथ इस बिल का समर्थन करता हूँ।

चेयरमैन—क्या माननीय मन्त्री जी इसका जवाब देना अभी पसन्द करेंगे या कल देंगे।

श्री मोहन लाल गौतम—अगर आज बहस समाप्त हो चुकी है तो मैं कल उत्तर दूंगा।

चेयरमैन—अब कौंसिल कल ११ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(कौंसिल ४ बजकर ४८ मिनट पर ४ नवम्बर को ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गई।)

श्याम लाल गोविल,

सेक्रेटरी,

सेजिस्ट्रेटिव कौंसिल,

लखनऊ :

३ नवम्बर, १९५२

उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौंसिल

मंगलवार, ४ नवम्बर, १९५२

—:—:—

[उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौंसिल की बैठक, कौंसिल हाल, विधान भवन, लखनऊ, में
दिन के ११ बजे चेयरमैन (श्री चन्द्रभाल) के सभापतित्व में हुई।]

उपस्थित सदस्य (५६)

अब्दुल शकूर नजमी, श्री
अम्बिका प्रसाद वाजपेयी, श्री
ईश्वरी प्रसाद, डाक्टर
उमानाथ बली, श्री
एम० जे० मुकर्जी, श्री
कन्हैयालाल गुप्त, श्री
कुंवर गुरु नारायण, श्री
कृष्ण चन्द्र जोशी, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
जगन्नाथ आचार्य, श्री
जमोलूरंहमान क़िदवाई, श्री
ज्योति प्रसाद गुप्त, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेलु राम, श्री
नरोत्तमदास टण्डन, श्री
निज़ामुद्दीन, श्री
निर्मल चन्द्र चतुर्वेदी, श्री
पद्मलाल गुप्त, श्री
पूर्ण चन्द्र विद्यालंकार, श्री
प्यारेलाल श्रीवास्तव, डाक्टर
प्रताप चन्द्र आजाद, श्री
प्रभु नारायण सिंह, श्री
प्रसिद्ध नारायण अनंद, श्री
प्रेमचन्द्र शर्मा, श्री
बद्री प्रसाद कक्कड़, श्री
बशीर अहमद, श्री
बलभद्र प्रसाद वाजपेयी, श्री
बालक राम वैश्य, श्री

बाबू अब्दुल मजीद, श्री
महमूद अस्लम खां, श्री
महादेवी वर्मा, श्रीमती
मानपाल गुप्त, श्री
राजाराम शास्त्री, श्री
राना शिवप्रभु सिंह, श्री
रामकिशोर रस्तोगी, श्री
रामकिशोर शर्मा, श्री
राम लाल सिंह, श्री
रघुनाथ खां, श्री
लालू राम द्विवेदी, श्री
लालता प्रसाद सोनकर, श्री
लाल सुरेश सिंह, श्री
विश्वनाथ, श्री
वीर भान भाटिया, डाक्टर
ब्रजलाल वर्मन, श्री (हकीम)
ब्रजेन्द्र स्वरूप, डाक्टर
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति देवी अग्रवाल, श्रीमती
शान्ति स्वरूप अग्रवाल, श्री
शिवराजवती नेहरू, श्रीमती
श्याम सुन्दर लाल, श्री
सत्यप्रेमो उपनाम हरिप्रसाद, श्री
सभापति उपाध्याय, श्री
सरदार सन्तोष सिंह, श्री
सैयद मुहम्मद नसीर, श्री
हृदय नारायण सिंह, श्री
हयातुल्ला अन्सारी, श्री

निम्नलिखित मंत्री भी उपस्थित थे:—

श्री हाकिम मुहम्मद इब्राहीम (वित्त मंत्री)
श्री हर गोविन्द सिंह (शिक्षा मंत्री)
श्री गिरधारी लाल (निर्माण मंत्री)
श्री मोहनलाल गौतम (स्वशासन मंत्री)

प्रश्नोत्तर

बरेली-हलद्वानी रोड पर गवर्नमेंट रोडवेज की वसें

- सं० तारीख १—श्री इन्द्र सिंह नयाल (स्थानीय संस्थाएं, निर्वाचन क्षेत्र) (अनुपस्थित)—वह कौन से उपाय हैं जिनके जरिये सरकार बरेली-हलद्वानी रोड पर गवर्नमेंट रोडवेज के कन्डक्टरों द्वारा टिकट बेचे जाने की रोकती है?
- 1 7-10-52 1. Sri Indra Singh Nayal:—(local authorities constituency) (Absent) What are the measures by which the Government checks the sale of tickets by Government roadways conductors on the Bareilly-Haldwani Road?
- २ ७-१०-५२ २—श्री इन्द्र सिंह नयाल (अनुपस्थित)—क्या सरकार ने कोई ऐसा आह्वान नियुक्त किया है जो सड़क पर इधर-उधर घूम और अचानक जांच करके यह मालूम करे कि आया कन्डक्टरों ने जो किराये का रुपया मुसाफिरों से वसूल किया है वह सब ठीक तरह से रसीद की किताब में चढ़ गया है या नहीं?
- 2 7-10-52 2. Sri Indra Singh Nayal (Absent)—Has the Government appointed any officer to move about on the road to make surprise checks to see whether the fare realised by the conductors from the passengers has been duly and fully credited in the receipt book or not?
- ३ ७-१०-५२ ३—श्री इन्द्र सिंह नयाल (अनुपस्थित)—क्या सरकार को ज्ञात है कि कन्डक्टर और ड्राइवर उन मुसाफिरों को जो बरेली और हलद्वानी के दरमियान रास्ते में रोडवेज की बसों पर चढ़ते हैं, टिकट न देकर या कम फासले का टिकट देकर, बहुत बड़ी रकम पैदा करते हैं?
- 3 7-10-52 3. Sri Indra Singh Nayal (Absent)—Is the Government aware that the conductors and drivers earn a large amount of money by not issuing tickets or by issuing tickets for a lesser distance to the passengers who pick up the roadways buses at casual points in between Bareilly and Haldwani?
- ४ ७-१०-५२ ४—श्री इन्द्र सिंह नयाल (अनुपस्थित)—यदि प्रश्न ३ का उत्तर हाँ में है, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में जांच करने का इरादा रखती है?
- 4 7-10-52 4. Sri Indra Singh Nayal (Absent):—If the answer to question no. 3 is in the affirmative do the Government intend to make enquiries in this connexion.
- ५ ७-१०-५२ ५—श्री इन्द्र सिंह नयाल (अनुपस्थित)—उपरोक्त नाजायज बातों या इसी प्रकार की नाजायज बातों के होने की संभावना को रोकने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है?
- 5 7-10-52 5. Sri Indra Singh Nayal (Absent):—What steps does the Government propose to take to check the aforesaid mal-practice or to check any likelihood of a mal-practice of the aforesaid nature?
- ६ ७-१०-५२ ६—श्री इन्द्र सिंह नयाल (अनुपस्थित)—बरेली-हलद्वानी और हलद्वानी-अल्मोड़ा सड़कों पर सन् १९४६, १९५०, व १९५१ ई० में क्रमशः कितने (क) व्यक्ति, (ख) जानवर, मोटरबुधटनाओं से (१) मर गये और (२) जखमी हुये?
- 6 7-10-52 6. Sri Indra Singh Nayal (Absent):—How many (a) human beings and (b) cattle were (i) killed and (ii) injured by motor accidents on the Bareilly-Haldwani and Haldwani-Almora cart roads in 1949, 1950 and 1951 respectively?

- ७—श्री इन्द्र सिंह नयाल (अनुपस्थित)—उपरोक्त मोटर दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में सन् १९४९-१९५०, व १९५१ ई० में क्रमशः कितने ड्राइवरों का चालान किया गया? ७-१०-
 ७ ७-१०-
 7. Sri Indra Singh Nayal (Absent):—How many drivers were challaned for the aforesaid motor accidents in 1949, 1950 and 1951 respectively? Original no. d
 7 7-10
- ८—श्री इन्द्र सिंह नयाल (अनुपस्थित)—(क) उपरोक्त दुर्घटनाओं में फंसे हुए एस कितने ड्राइवर हैं जिनका चालान नहीं हुआ? ८ ७-१०-
 (ख) उनके चालान न करने के क्या कारण थे?
8. Sri Indra Singh Nayal (Absent):—(a) How many of the drivers involved the aforesaid accidents were not challaned? 8 7-10
 (b) What were the reasons for not challaning them?
- ९—श्री इन्द्र सिंह नयाल (अनुपस्थित)—चालान किये गये ड्राइवरों में से कितनों को सजा मिली और कितने छूट गये? ९ ७-१०-
 ९ ७-१०-
9. Sri Indra Singh Nayal (Absent):—How many of the drivers challaned were convicted and how many acquitted? 9 7-10
- १०—श्री इन्द्र सिंह नयाल (अनुपस्थित)—हलद्वानी-काठगोदाम रोड पर एक गवर्नमेंट रोडवेज बस से हाल ही में कितने व्यक्ति मर गये? १० ७-१०-
 १० ७-१०-
10. Sri Indra Singh Nayal (Absent):—How many persons were killed by a Government Roadways bus on the Haldwani-Kathgodam Road recently? 10 7-10
- ११—श्री इन्द्र सिंह नयाल (अनुपस्थित)—उस दुर्घटना के कारण क्या थे? ११ ७-१०-
 ११ ७-१०-
11. Sri Indra Singh Nayal (Absent):—What were the reasons for the accident? 11 7-10
- १२—श्री इन्द्र सिंह नयाल (अनुपस्थित)—क्या प्रश्न ६ में उल्लिखित दुर्घटनाओं इसलिये हुईं कि ड्राइवर मोटरों को चलाते समय शराब पिये हुए थे? १२ ७-१०-
 १२ ७-१०-
12. Sri Indra Singh Nayal (Absent):—Were many of the accidents referred to in question no. 6 due to the drivers being drunk at the time of driving? 12 7-10
- १३—श्री इन्द्र सिंह नयाल (अनुपस्थित)—मोटर दुर्घटनाओं के इस बढ़ते हुए भय को रोकने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करता चाहती है? १३ ७-१०-
 १३ ७-१०-
13. Sri Indra Singh Nayal (Absent):—What steps does the Government propose to take to check the growing menace of motor accidents? 13 7-10
- १४—श्री इन्द्र सिंह नयाल (अनुपस्थित)—क्या सामान के भार का कोई ऐसा परिमाण नियत है जिसे एक मोटर ट्रक को बरेली-हलद्वानी रोड पर ले जाने की इजाजत है? १४ ७-१०-
 १४ ७-१०-
14. Sri Indra Singh Nayal (Absent):—(a) Is there a limit to the weight of goods that a motor truck is allowed to take on the Bareilly-Haldwani Road? 14 7-10
 (b) If so, what is the maximum weight fixed?
- १५—श्री इन्द्र सिंह नयाल (अनुपस्थित)—क्या यह ठीक है कि बरेली-हलद्वानी रोड पर जो मोटर ट्रक चलती हैं उन पर आम तौर से हद से ज्यादा बोझ लदा होता है? १५ ७-१०-
 १५ ७-१०-
15. Sri Indra Singh Nayal (Absent):—Is it a fact that the motor trucks driving on the Bareilly-Haldwani Road are usually overloaded? 15 7-10
- १६—श्री इन्द्र सिंह नयाल (अनुपस्थित)—सन् १९५१ ई० में बरेली-हलद्वानी रोड पर ट्रकों द्वारा हद से ज्यादा बोझ लादने के कितने मामले पुलिस द्वारा पकड़े गये? १६ ७-१०-
 १६ ७-१०-
16. Sri Indra Singh Nayal (Absent):—How many cases of over-loading were checked by the police on the Bareilly-Haldwani Road during the year 1951? 16 7-10

१७—श्री इन्द्र सिंह नयाल (अनुपस्थित)—सन् १९५१ ई० में बरेली-हलद्वानी रोड पर हव से ज्यादा बोझ लादने के कितने मामले चालान किये गये?

17. Sri Indra Singh Nayal (*Absent*)—How many cases of over-loading on the Bareilly-Haldwani Road were challaned during the year 1951?

१-१७—श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम (वित्त मंत्री)—आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है। प्राप्त होने पर उत्तर दिया जायगा ?

Sri Hafiz Mohammad Ibrahim (Minister for Finance)—Necessary information is being collected and the questions will be answered when the same is available.

१५ अगस्त को प्रदर्शन

१८—श्री पन्ना लाल गुप्त (स्थानीय संस्थाएं निर्वाचन क्षेत्र)—(क) क्या सरकार कृपा करके यह बतलायेगी कि जहानाबाद, जिला फ़तेहपुर में १५ अगस्त को वहां के मुसलमानों ने काले झंडे का जुलूस निकाला और पब्लिक मीटिंग की ?

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

श्री हर गोविन्द सिंह (शिक्षा मंत्री)—(क) जी हां।

(ख) प्रदर्शन के नेताओं के विरुद्ध क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा १०७/११७ के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है। मामला अदालत में चल रहा है।

फ़तेहपुर ज़िले में चोरियों और डकैतियों की संख्या

१९—श्री पन्ना लाल गुप्त—क्या सरकार कृपा करके यह बतलायेगी कि फ़तेहपुर ज़िले में इस साल कितनी डकैतियां व चोरियां हुईं और कितने का पुलिस ने पता लगाकर चालान किया और इनमें से कितनों को सजा हुई ?

श्री हर गोविन्द सिंह—मांगी हुई सूचना इस प्रकार है :

डकैती—सन् १९५२ में अभी तक १० डकैतियां हुई हैं जिनमें से ३ का पता लगा कर चालान किया जा चुका है और अभी तक इनके मुकदमे अदालत में चल रहे हैं।

चोरी—अभी तक सन् १९५२ में कुल ५६६ चोरी की वारदातें हुईं जिनमें से ७० का पता लगा कर चालान किया जा चुका है, और १२ आदमी अभी तक सजायावद्ध हैं।

नैनीताल में बन्दूक के लाइसेंसदारों से जबर्दस्ती चन्दा वसूल किया जाना

२०—श्री इन्द्र सिंह नयाल (अनुपस्थित)—क्या यह ठीक है कि सन् १९३९-४५ ई० के युद्ध में जिला नैनीताल में बन्दूक के लाइसेंसदारों से जबर्दस्ती या और किसी तरह से लड़ाई का चन्दा वसूल किया गया था ?

20. Sri Indra Singh Nayal (*Absent*)—Is it a fact that during the war of 1939-45 subscription for the war was raised forcibly or otherwise from the holder of gun licences in the Naini Tal District ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द (गृह मंत्री)—इस प्रकार की कुछ शिकायतें सरकार के पास आई थीं पर यह नहीं कहा जा सकता था कि वह कहां तक ठीक थीं, क्योंकि जिला के सम्बन्धित पत्रावलियां नष्ट हो चुकी थीं।

Dr. Sampurnanand (Home Ministre)—A few complaints of this nature were no doubt received by Government but it could not be said definitely as to what extent these allegations were true as district records in this connexion had since been weeded out.

२१—श्री इन्द्र सिंह नयाल (अनुपस्थित)—क्या यह ठीक है कि जिन लोगों ने चन्दा देने से इन्कार किया, उनके लाइसेंस जब्त कर लिये गये और उनकी बन्दूकें बेच दी गईं ?

21. Sri Indra Singh Nayal—(Absent): Is it a fact that the licences of those who refused to pay the subscription were forfeited and their guns sold ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—कृपया प्रश्न संख्या २० का उत्तर इस सम्बन्ध में देखिये ।

Dr. Sampurnanand—Reply to question no. 20 may please be seen in this connection.

२२—श्री इन्द्र सिंह नयाल (अनुपस्थित)—यदि हाँ, तो क्या सरकार उन लाइसेंसों की संख्या बताने की कृपा करेगी जो नैनीताल जिले में इस प्रकार मंसूख किये गये । उनके नाम क्या ह जिनके लाइसेंस मंसूख किये गये और किस वर्ष वह मंसूख किये गये ?

22. Sri Indra Singh Nayal—(Absent)—If so, will the Government please give the number of licences thus cancelled in the Naini Tal District and also the names of the persons whose licences were cancelled and the year when the same was cancelled ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—प्रश्न नहीं उठता ?

Dr. Sampurnanand—Question does not arise.

२३—श्री इन्द्र सिंह नयाल (अनुपस्थित)—क्या यह ठीक है कि प्रश्न नं० २२ में उल्लिखित लोगों ने उपरोक्त चन्दे को इण्डियन नेशनल कांग्रेस के सिद्धान्तों और नीतियों के अनुसार देने से इन्कार किया था ?

23. Sri Indra Singh Nayal (Absent)—Is it a fact the persons referred to in question no. 22 refused to pay the aforesaid subscriptions in accordance with the principle and policies of the Indian National Congress ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—प्रश्न नहीं उठता ।

Dr. Sampurnanand—Question does not arise.

२४—श्री इन्द्र सिंह नयाल (अनुपस्थित)—क्या उपरोक्त लोगों में से कुछ ने ऐसी प्रार्थनायें की थीं कि उनको सरकारी खर्चों पर वेंसी हो बन्दूकें वापस कर दी जायें ?

24. Sri Indra Singh Nayal—(absent) Did several of the aforesaid persons apply for the restoration of similar guns to them at Government expenses ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हाँ, सरकार के पास कुछ ऐसे प्रार्थना-पत्र अवश्य आये थे जिनमें लड़ाई में चन्दों न देने के कारण जब्त किये गये हथियारों को वापस करने की प्रार्थना की गई थी और प्रत्येक को उचित रूप से विचार किया गया ।

Dr. Sampurnanand—Yes . Government did receive a few applications in which request had been made for restoration of firearms alleged to have been forfeited to Government on their refusal to contribute to the war fund and each case was decided on merits.

२५—श्री इन्द्र सिंह नयाल (अनुपस्थित)—क्या यह ठीक है कि उपरोक्त प्रार्थना-पत्रों पर अभी तक कोई आदेश जारी नहीं किये गये हैं ?

25. Sri Indra Singh Nayal—(Absent) Is it a fact that no orders have yet been passed in the aforesaid applications ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं ।

Dr. Sampurnanand—No .

२६—श्री इन्द्र सिंह नयाल (अनुपस्थित)—क्या सरकार इस बात के लिये तैयार है कि बन्दूकों की वापसी के प्रश्न को राजनीतिक पीड़ितों के मुआवजे के आधार पर माने ?

26. Sri Indra Singh Nayal (*absent*)—Is the Government prepared to treat the question of restoration of guns on the basis of compensation for political suffering ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां।

Dr. Sampurnanand.—yes.

२७—श्री इन्द्र सिंह नयाल (अनुपस्थित)—यदि नहीं, तो क्यों ?

27. Sri Indra Singh Nayal (*absent*)—If not, why ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—प्रश्न नहीं उठता।

Dr. Sampurnanand—Question does not arise.

२८—श्री इन्द्र सिंह नयाल (अनुपस्थित)—क्या नैनीताल जिले में सन् १९३९-४५ में बन्दूकों के लाइसेंस राजनीतिक कारणों से संसूख किये गये थे ?

28. Sri Indra Singh Nayal (*Absent*)—Where licenses of guns in the Naini Tal District 1939-45 on political grounds ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां, ऐसा मानने का आधार है।

Dr. Sampurnanand.—Yes, there is reasons to believe so.

२९—श्री इन्द्र सिंह नयाल (अनुपस्थित)—यदि हां, तो क्या सरकार लाइसेंसों की संख्या बताने की कृपा करेगी जो इस प्रकार रद्द किये गये थे और उनके नाम क्या हैं जिनके लाइसेंस रद्द किये गये ?

29. Sri Indra Singh Nayal (*absent*)—If so, will the Government please give the member of licenses thus cancelled and the names of persons whose licenses were thus cancelled ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इसका विवरण देना सम्भव नहीं है, क्योंकि जिला नैनीताल के इस सम्बन्ध के रिकार्ड नष्ट किये जा चुके हैं।

Dr. Sampurnanand—It is not possible to furnish these details as the district records in this connexion have since been weeded out.

३०—श्री इन्द्र सिंह नयाल (अनुपस्थित)—उपरोक्त लाइसेंसों और बन्दूकों में से कितनों को कांग्रेस सरकार ने वापस किया ?

30. Sri Indra Singh Nayal (*absent*)—How many of the aforesaid license and guns were restored by the Congress Government ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इस सम्बन्ध में ठीक सूचना जिला में रिकार्ड उपलब्ध न हो के कारण नहीं दी जा सकती है जैसा कि प्रश्न संख्या २९ के उत्तर में बताया गया है। जहाँ तक बंदूकें वापस करने का सवाल है ४ बन्दूकें सरकारी मालखाने के जब्त किये हुये हथियारों में से उन व्यक्तियों को उनके हथियारों के एवज में दी गई हैं जिनके हथियार स्वतन्त्रता के आन्दोलन में जब्त किये गये थे और २ व्यक्तियों को बीस बीस रुपये हर्जाना दिया जा चुका है।

Dr. Sampurnanand—The correct information in this connection cannot be supplied due to non-availability of records as pointed out in reply to question no. 29. So far as the question of restoration of guns is concerned, four have been ordered to be given to the persons concerned from forfeited and confiscated stocks in Government malkhanas in lieu of their firearms, forfeited from them in connexion with the country's struggle for freedom, and two persons have been given Rs.20 each as compensation for their weapons.

३१—श्री इन्द्र सिंह नयाल (अनुपस्थित)—क्या सरकार उनमें से बाकी को वापस करने को तैयार है ?

31. Sri Indra Singh Nayal (absent):—Is the Government prepared to restore the rest of them ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—सरकार प्रत्येक प्रार्थना-पत्र को उचित रूप से विचार करने को तैयार है।

Dr. Sampurnanand—Government are prepared to consider each case on merit.

३२—श्री इन्द्र सिंह नयाल (अनुपस्थित)—यदि नहीं, तो क्यों ?

32. Sri Indra Singh Nayal (absent):—If not, why ?

आ० सं० १

३३७-१०-

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—प्रश्न नहीं उठता।

Dr. Sampurnanand—Question does not arise.

चेयरमैन—जैसे एक बार पहले भी माननीय सदस्यों का इस तरह ध्यान आकर्षित किया है कि सवाल पूछने वाले सदस्य का कर्तव्य होता है कि वह प्रश्नों से समय पर यहां उपस्थित रहे, क्योंकि प्रश्नों के उत्तर देने में सरकार का काफी पैसा खर्च होता है तथा वक्त लगाया जाता है। जो मेम्बर सवालों का जवाब चाहते हैं जिस वक्त जवाब दिया जाता है उस वक्त उनकी यहां पर रहना चाहिये।

आगरा विश्वविद्यालय के उपकुलपति का चुनाव आर्डिनेंस द्वारा स्थगित किये जाने के संबंध में कार्य स्थगन प्रस्ताव

चेयरमैन—श्री राजाराम शास्त्री का कल एक एडजान्टेंट मोशन पेश हुआ था और उस वक्त यह तय हुआ था कि वह आज लिया जायगा। इनकी एडमिनिस्ट्रिलिटी के बारे में अगर सरकार को कुछ कहना है तो हम लोग को सुन लें तभी उसके बाद में निर्णय देंगे।

*श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—मैं जनाब से अर्ब कलंगा कि मैंने सूवर से गुना नहीं है कि वह क्यों जरूरी है।

†श्री राजाराम शास्त्री (विधान सभा निर्वाचित क्षेत्र)—श्रीमान् जी, पहले मैं बतला दूँ कि क्यों मैं इसे पेश करना चाहता हूँ तो फिर मिनिस्टर साहब को भी सहूलियत हो जायेगी।

चेयरमैन—श्रीमान् जी तोर से इस समय बहुत बहस नहीं होती है। लेकिन जब एक निश्चित, आवश्यक और जनहित के लिये महत्वशाली विषय पर बहस करने के लिये एडजान्टेंट मोशन को सूचना दी जाती है तो मुझे यह देखना होता है कि यह एक उचित विषय है या नहीं। अगर कोई आर्डिनेंस जारी किया जाता है तो वह बाह्य रूप से (prima facie) निश्चित और आवश्यक विषय होता है।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—हमारे रूल में है कि कौन अजेंट मामला होता है। जहां तक इस मामले का सवाल है तो इसके बारे में आर्डिनेंस जारी हो चुका है। अब उसका डिस्कशन आज हो या कल हो अगर उसके लिये मुझे यह मालूम होता है कि कोई अजेंसी बाकी नहीं है। अगर कोई एक्शन हो रहा है तो उसको रोकने के लिये अजेंसी हो सकती है लेकिन यह बात तो खत्म हो चुकी है।

मैं चाहता हूँ कि जो बहस हो वह कल हो जाय, दोतीन दिन के अन्दर बहस हो जायेगी। यह मामला जरूरी है या नहीं है इस पर भी बहस हो जायेगी। यह कोई ऐसा मंदर भी नहीं है।

श्री राजाराम शास्त्री—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि यह कोई अजेंट मंदर नहीं है तो मैं इस तरह आप का

*मंत्री जी ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

†सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री राजा राम शास्त्री]

ध्यान दिलाना चाहता हूँ। २८ तारीख को मैंने सरकार से एक सवाल के जवाब में पूछा तो उसने २९ तारीख को मुझे जवाब दिया कि मामला कांफीडेंशल है। वह मैं अंग्रेजी में पढ़ना चाहता हूँ।

The Education Minister regrets that he is unable to reply to the short notice questions nos. 1 to 4 proposed to be asked by Sri Raja Ram Shastri as the above matter is being confidentially considered by Government at this stage.

२९ तारीख को सरकार ने यह जवाब दिया और ३० तारीख को हमारे हाउस का सेशन हो रहा था तो हमको उस मामले पर विचार करने का मौका देना चाहिए था।

चेयरमैन—मैं समझता हूँ कि इस विषय पर चर्चा की जा सकती है।

श्री हर गोविन्द सिंह—अभी तो म्युनिसिपल बिल चल रहा है। उसके बाद इसको लिया जा सकता है।

चेयरमैन—एक तो यह है कि सब पेपर मेम्बर की टेबिल पर रख दिये गये हैं, उस मामले पर विचार किया जा सकता है और इस बिल को भी पास किया जा सकता है।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—Just after the present Bill which is under discussion.

चेयरमैन—मैं समझता हूँ कि काफी वक्त है।

श्री राजाराम शास्त्री—जो बिल आया है उस पर भी बहस हो सकती है।

चेयरमैन—आप उस आर्डिनेंस पर विचार करने के लिये जो मेज पर रख दिया गया है, एक अलग मोशन भी मूव कर सकते हैं और इस विषय पर जो बिल प्रस्तुत किया जायगा उसके सिलसिले में भी जो कुछ कहना चाहते हैं कह सकते हैं। अब चूँकि आपको ४ दिन के भीतर यह मौका मिल जावेगा कि आप उसके बारे में जो कुछ भी कहना चाहते हैं कह सकते हैं, इसलिये मैं समझता हूँ कि इस वक्त हाउस का समय इसमें न लिया जाय तो अच्छा हो। यों तो वह डेफिनिट मेटर आफ अर्जेंट पब्लिक इम्पोर्टेन्स (Definite matter of urgent public importance) है परन्तु इसके ऊपर आर्डिनेंस पर बहस करने के लिये प्रस्ताव को पेश होते वक्त भी बहस हो सकती है।

श्री हर गोविन्द सिंह—I think it is the ruling from the Chair that it is a definite matter of the public importance.

चेयरमैन—The House can proceed to consider the ordinance.

चूँकि इस आर्डिनेंस पर बहस करने के प्रस्ताव पर विचार हो सकता है, इसलिये मैं इसे हाउस के ऊपर ही छोड़ता हूँ कि वह इस प्रस्ताव पर बहस करे या आर्डिनेंस पर बहस करे।

श्री राजाराम शास्त्री—क्या ऐसा हो सकता है कि मैं इस प्रस्ताव पर विचार करने के लिये उसी समय प्रस्ताव पेश कर दूँ।

चेयरमैन—ऐसा नहीं, बल्कि आप नोटिस दे दें।

श्री राजा राम शास्त्री—तो फिर इसके लिये क्या मुझको टाइम देना पड़ेगा ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—इसके लिये यह जरूरी होता है कि पहले नोटिस देना पड़ता है, इसलिये टाइम का तो कोई सवाल इसमें नहीं पैदा होता है।

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक

श्री मोहनलाल गौतम (स्वशासन मंत्री)—अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात से बड़ी खुशी हुई कि इस सदन के सभी सदस्यों ने मेरे इस अर्नेजिंग बिल का हृदय से स्वागत किया है और जिस उत्साह से इस सदन में इस बिल का स्वागत हुआ और जो विधवात इस समय प्रकट किया गया, इस बात पर कि म्युनिसिपैलिटीज का चुनाव जल्दी होगा तथा जो दो चार शब्द मेरे लिये इस सम्बन्ध में कहे गये, उन सबके लिये मैं इस सदन को और सदन के सभी सदस्यों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। सलेक्ट कमेटी का जहाँ तक सम्बन्ध है वह तो श्री राजाराम जी ने पेश किया था और कुछ और सदस्यों ने भी उसका समर्थन किया था लेकिन मेरा अनुमान है कि श्री राजाराम जी अब उतने उत्साह से सलेक्ट कमेटी का मोशन नहीं चाहते हैं, जितना कि कल सुबह चाहते थे। वह इसलिये कि उनको अब अपने सभी संशोधनों को पेश करने का मौका मिल गया है और जो प्रश्न वह इस सदन के अन्दर उठाना चाहते थे और जो संशोधन पेश करना चाहते थे, वह पेश हो सकेंगे और उन पर विचार हो सकेगा। मेरा ख्याल है कि अब समय मिल जाने पर वह सलेक्ट कमेटी के लिये बहुत ज्यादा जोर नहीं देंगे और मेरा ख्याल है कि सलेक्ट कमेटी को रिफर किये जाने की बात गुलतफ़हमी पर भी आधारित है। क्योंकि जब श्री प्रभु नारायण जी ने उसका समर्थन किया तो उन्होंने इस आधार पर समर्थन किया कि सलेक्ट कमेटी को यह रिफर कर दिया जाय और जो १९३३ में एक कमेटी बनी थी और जिस कमेटी ने कुछ सिफारिशें उस समय की थीं, जिसके अध्यक्ष महोदय आप भी एक सम्मानित सदस्य थे, तो उस कमेटी की सिफारिशों को मिला कर एक नया बिल पेश हो सके और इस सदन में उस पर विचार हो, इसी ख्याल से श्री प्रभु नारायण जी ने उस सलेक्ट कमेटी के रिफरेंस का स्वागत किया था और समर्थन किया था और इसी तरह की कुछ बातें श्री कन्हैयालाल जी ने कहीं और उन सब के उत्तर में मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि सलेक्ट कमेटी को जब आप कोई चीज भेज दें तो आप यह बात मान लेते हैं कि जो उसके फन्डामेंटल प्रिन्सिपल हैं वे हमको स्वीकार हैं और सलेक्ट कमेटी का काम यह है कि वह उन बुनियादों को ले। तो इस बिल में जितना भी घटाने, बढ़ाने और उसकी भाषा इत्यादि को ठीक करने की बात है और उसके अंदर जो कमी है, उसको पूरा करना है, तो वे सब बातें तो फिज इन दि गैप की तरह हुई। लेकिन उस सलेक्ट कमेटी को इसमें घटाने और बढ़ाने का कोई अधिकार नहीं है और उसके लिये फिर हाउस के सामने लाना पड़ता है। इसलिये जब इतनी ही सीमित हद और दायरे तक उसको रखा जाता है और जो कि इस बिल में पहले से है, तो मेरा अन्दाज़ यह है कि इसके लिये जो समर्थक कल थे और वह चाहते थे कि इसको सलेक्ट कमेटी में भेजा जाय, वे भी अब अपने समर्थन में ढीले पड़ जायेंगे और जो भी बातें कल उन्होंने इसे सलेक्ट कमेटी में भेजने के लिये उठाई थी और जो कुछ भी उनका महसूस था तो वे शायद अब इस बात को मान लेंगे कि उसमें जो थोड़ा सा सवाल है वह इसको ठीक करने का है वह वहां जाकर चेंज नहीं हो सकता है। तो मेरा ख्याल है कि इस जरा सी बात के लिये यह सदन इसको ज्यादा समय तक रोकने के लिये तैयार नहीं है और इस बिल में जितनी भी बातें हैं और यहां उनको कहा गया है तो उनमें से अधिक शि बातों का समर्थन बड़े उत्साह से किया गया है और हर ओर से उसका स्वागत किया गया है और जितनी भी चुनाव की चीजें हैं उसमें कुछ भी परिवर्तन करने की और सुझाव रखने की इच्छा किसी भी सदस्य को नहीं रही। यह ज़रूर है कि इसमें जहां तक संख्या की बात है वह ५०, ६० या ४०, २० और १५ तक करने को कुछ सदस्यों ने कहा है और थोड़ा सा इसको संशोधित करने का सुझाव किया है। बाकी जितने प्रावीजनस हैं जिनमें कि इलेक्शन का सम्बन्ध है और खास कर जिसके लिये यह बिल लाया गया है, उसका सब लोगों ने स्वागत किया और उसमें किसी तरह के मतभेद की गुंजाइश भी नहीं थी और उन सारी चीजों में जो चुनाव के नियम बने हैं तो

[श्री मोहनलाल गैतम]

वह उसी आधार पर बने हैं जिनको कि सब पहले से मान चुके हैं और उन्हीं आधार पर चुनाव पिछली बार हुआ था। इसलिये इसमें मतभेद की कोई गुंजाइश भी नहीं है। इसके और भी हिस्सों का सबने स्वागत किया और इसके लिये जो असल की बात होगी और इसके समर्थन की जो बात है, उसका सबस्यों ने जिस उत्साह से स्वागत किया, वह तो कल प्रकट ही हो गया और उसके लिये मैंने उनको धन्यवाद भी दे दिया है। जहां तक इसके और धारार्य हैं उनमें भी जैसा कि हमारे डॉक्टर वृजेन्द्र स्वरूप साहब ने कहा और उनमें उन्होंने लगभग ५, ६ चीजों की ओर ध्यान दिलाया और कहा कि बेठीक हैं और सभी सबस्यों ने उन बातों पर कोई मतभेद नहीं प्रकट किया। उनमें एक एकाउन्ट्स आफिसर का भी सवाल था और एक्स्टेंशन उसमें सिर्फ दो साल के लिये हैं, तो इन चीजों का भी स्वागत सदन ने किया। अब सवाल रह जाता है उन २ या १ चीजों का जिन पर मतभेद है। सब से ज्यादा विरोध इस सदन में जिस बात का हुआ है और उसका कुछ लोगों ने समर्थन भी किया है वह मैट्रिक वाली शर्त है जो प्रेसीडेन्ट के लिये रखी गई है जैसा कि मैंने कल कहा था कि अब प्रेसीडेन्ट जनरल एनेक्शन से चुने जायेंगे और उनको वोटर्स के सामने आना पड़ेगा इसलिये चाहे वह व्यक्ति हो या किसी पार्टी का नामोनी हो उन सबको ख्याल रखना पड़ेगा कि जिसको हम खड़ा कर रहे हैं वह प्रेसीडेन्ट का काम चला सकती है या नहीं, उसमें काबिलियत है या नहीं, चाहे वह इन्टरम पास हो या न हो ऐसा न हो जैसा आज कल कहा जाता है कि अनपढ़ लोग यह गड़बड़ करते हैं और वह समझते भी नहीं हैं कि कहां दस्तखत करना है तो ऐसी बातें न हो सके। पहले तो मेम्बरों की राय का ही सवाल था प्रेसीडेन्ट के लिये और अब तो जनरल एनेक्शन होगा। पहले एक आदमी की राय पर ही अगर वह अड़ जाता था तो वह उसका एक ही वोट ऐसा होता था जिससे झंझट आ जाता था और भी कई कारण हो सकते थे लेकिन अब जनरल एनेक्शन से आयेंगे, इसलिये वह बातें अब न उठेंगी। मैं समझता हूँ कि इस पर भवन को विचार करने का मौका आयेगा और मुझे भी इस पर ज़िद नहीं करना है। एक बात वृजेन्द्र स्वरूप जी ने तथा और भी कई लोगों ने कही कि जो लोग पुलिस कस्टडी में हों या जेल खाने में हो उनको राय देने का अधिकार नहीं दिया गया इस पर उन्होंने आपत्ति उठाई। यह धारा मैंने उसी आधार पर रखी है जो असेम्बली को चुनाव के लिये तब से है, इसलिये मेरा विचार है कि इस पर कोई झंझट न होना चाहिये। इसमें एक दिक्कत एडमिनिस्ट्रेटिव प्वाइंट से भी हो सकती है अगर मौका दिया गया कि जो लोग पुलिस कस्टडी में हैं वह अपनी राय दें सकें तो उनको पुलिस कस्टडी में लाना होगा और वोट देना होगा तो इस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन को काफी डिफ़िकल्टी हो जाती है। इसलिये मैं इतना कहना चाहता हूँ कि यह कोई नई धारा नहीं है और जो असेम्बली एनेक्शन की धारा है वही यहाँ पर रख दी गई है। जहां तक हिन्दी पत्र में छपने की बात है इस बात से मैं सहमत हूँ कि किसी साहब ने एक पत्र निकाला उसमें जिम्मेदारी और गैर जिम्मेदारी से उन्होंने लिखना शुरू कर दिया और म्युनिसिपैलिटी के अधिकारियों को चिन्ता हो गई और उन्होंने उसकी कुछ इस्तहार और प्रोसीडिंग्स छापने के लिये दे दी और फिर वह पत्र उसको तारोक्त करने लगे। इससे मेरा ख्याल यह है कि जनरलिज्म का नाम ऊँचा नहीं होता है जनरलिज्म से मेरा भी सम्बन्ध रहा है और अब भी है लेकिन मैं समझता हूँ कि इस तरह की चीजें खुद आपस में जनरलिस्ट की ट्रेड यूनियन्स तक ले ले और ऐसी चीजों को प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिये। इसलिये इसको इसमें कैसा रखा जाय यह सोचने की बात है। अब सवाल यह है कि इसमें क्या होना चाहिये। अब जो कल तनाम बहस हुई उसमें यह बात कही गई है कि यह बिल अव्वर है और इसमें यह होना चाहिये जैसा कि मैंने कल कहा था कि इसमें चुनाव सम्बन्धी धारार्य हैं और कुछ जो जरूरी धारार्य हैं वह इसमें हैं यह पूर्ण बिल नहीं है एग्जास्टिव बिल आये आयेगा।

इसलिये बहुत सी चीजें जो इस सदन के सदस्यों ने कही हैं उन पर विचार कलंगा और जो अभी आगे आने वाला अमेंडिंग बिल होगा उसमें जो भी चीजें उचित समझी जायेंगी उनको स्थान देने का प्रयत्न किया जायेगा। इसलिये बहुत सी बातों का उत्तर देकर मैं सदन का समय नष्ट न करूंगा।

एक चीज इसके सिलसिले में श्री राजाराम जी ने बहुत जोर से कही और मैं भी यह समझता हूँ कि उन्होंने बहुत माकूल बात कही कि जब तक लोकल बाडीज के फाइनेन्सेज अच्छे नहीं होंगे तब तक लोकल बाडीज अच्छे तरह से नहीं चल सकतीं। लेकिन जो उन्होंने रास्ता बतलाया है वह शायद बहुत ज्यादा संघे बिना ही बतला दिया है। हमको इस पर बहुत ज्यादा विचार करना होगा। लोकल बाडीज दूर टैक्स लगाती हैं या नहीं, जितना टैक्स लगाती हैं वह असेज होता है या नहीं, जो असेज होता है वह रियलाइज होता है या नहीं, जो रियलाइज होता है वह खर्च ठीक से होता है या नहीं, इस सब पर हमको विचार करना होगा।

एक सवाल श्रीमती शिवराजवती जी ने भी उठाया है और उसको दूसरे स्वरूप में श्री राजाराम जी ने भी कहा कि रिजरवेशन है। रिजरवेशन के बारे में मैंने कल ही कहा था कि यह कॉन्स्टीट्यूशन को देखने की बात है कि यह कर सवतें हैं या नहीं। क्योंकि इससे मुक्तम बचती ही रहती है। इस समय एडल्ट फ्रैन्चाइज के समय में कोई खास रिजरवेशन नहीं है, और यह आशा की जाती है कि जब लोग मिल कर काम करेंगे। मजदूरों की तो काफी संख्या है, मैं समझता हूँ कि उनके प्रतिनिधि अपने क्षेत्र से काफ़ी चुने जायेंगे; जहाँ तक चुनाव का ताल्लुक है, जो श्री राजाराम जी ने दलील दी थी वह तो रिजरवेशन के बाद भी लापू होती है। जैसा कि एनेक्शन में पैने वाले ही चुने जा सकते हैं, अगर रिजरवेशन भी होता है तब भी चुनाव का खर्च तो होगा ही। इसलिये वह तो कामन फ्रैक्टर हैं ही, यह ठीक है कि कुछ हद तक वह लिमिटेड हो जाता है रिजरवेशन के बाद। इस मुश्किल को दूर करने के लिये तो इकनामिक डेनोकेन्सी का रास्ता ही ठीक रास्ता है। रिजरवेशन का रास्ता सरल भले दिखलाई दे लेकिन असली रास्ता यह नहीं है। सर्विसेज के बारे में जो प्रावधान है वह खास बजह से रखा गया है। हम लोगों ने और डिपार्टमेंट ने सर्विसेज के लिये कुछ रूलन आफ कंडक्ट बनाये थे। उसमें यह भी था कि कोई बोर्ड का इम्प्लायी, बोर्ड के लिये नहीं खड़ा हो सकता। यह चैलेंज हो गये हाईकोर्ट में और यह फैसला हुआ कि वृंकि ला में कोई प्रावधान नहीं है इसलिये इस तरह के रूलन गवर्नमेंट नहीं बना सकता। जो स्थल जाहिर किया गया है कि इम्प्लायीज की हालत सुधारने के लिये उनकी सिक्योरिटी आफ सर्विस होना चाहिये। मेरा ख्याल है कि वह इस अमेंडमेंट का उद्देश्य नहीं है। यह ठीक है कि अगर सर्विसेज अनाटेड नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है तो भी लोकल बाडीज नहीं चल सकतीं। वह एक लम्बा प्रश्न है और बाद में इस पर बहस होगी। आक्टूय के बारे में जो अमेंडमेंट आया है, जो बिल में प्रावधान है वह बहुत महत्व रखता है। इसलिये जैसा कि मैंने कल कहा कि चुंगी के संबंध में बड़ी शिकायतें हैं। टर्मिनल टेक्स का जहाँ तक संबंध है वह सेन्ट्रल का विषय है। उसमें हमको गवर्नमेंट आफ इंडिया से मंजूरी लेना पड़ेगी। तो हम सोच रहे हैं कि एक ऐसा सरल रास्ता निकाला जाय जिसमें टर्मिनल टेक्स की जो बातें हैं वे न आयें। उसके लिये थोड़ा सा यहां पर प्रावधान रखा गया है। इसकी शकल तैयार हो रही है। अभी एक सबसे बड़ा सवाल है उसकी मैं भी देखता हूँ। वह है सस्पेंशन आफ मेम्बर्स का। जहाँ तक उनके रिमूवल का संबंध है इसके लिये गवर्नमेंट को अधिकार है। कुछ साल पहले यह अधिकार म्यूनिसिपल बोर्ड को भी था और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को भी था। जहाँ तक प्रेसिडेंट के रिमूवल का संबंध है उसके बारे में भी मैं कह चुका हूँ। बहुत सी मिसालें हमारे सामने हैं जो कि यहां पर रखी जा सकती हैं। अगर पब्लिक सर्विसेज में कोई गलती करता है तो उस गलती को दूर करने की व्यवस्था होनी चाहिये। अगर किसी के खिलाफ कोई शिकायत है तो मामूली तौर पर उसको सस्पेंड कर दिया जाता है और उसके सिलसिले में इन्क्वायरी होती है। जो भी सजा हो। चाहे वह डिस्मिस हो या और कोई सजा उसकी मिले। एक साहब ने कहा कि सस्पेंशन होने से उसका बदनामी होती है। अगर किसी आदमी के बारे में शिकायत है कि

[श्री मोहनलाल गौतम]

उसने सपना गवन किया है तो उसका सस्पेन्शन होना जरूरी है तथा उसकी इन्क्वायरी ठीक तरह से होनी चाहिये। हमारे डिप्टी चेयरमैन साहब ने मिसाल दी कि सस्पेंशन जरूरी है और न्याय के लिये आवश्यक है कि तत्कालीन अर्द्धी तरह से हो तो जिसने गवन किया है या कोई दूसरी गलती की है उसको सस्पेंड कर दिया जाय। आप देखेंगे कि आसानी से यह अधिकार इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अगर आप समझते हैं कि न्याय जरूरी है तो आज की गवर्नमेंट चाहे किसी की हो और कल कोई दूसरी हो। आज की गवर्नमेंट को कोई अख्तियार नहीं देना चाहते हैं और कल के लिये कोई दूसरी चीज सोचें तो यह दूसरी बात है। अगर आप चाहते हैं कि इन्तजाम ठीक हो तो क्या आप का कहना ठीक है? यह इन्हेरेन्ट है। तमाम मेम्बरों को रिमूव करने का अख्तियार है, तो रिमूव करने से कौन सी ईमानदारी की खास जरूरत हो जायगी। इसलिये इसमें ईमानदारी बेईमानी का सवाल ही नहीं उठता है। यहां एक बड़ा सैद्धांतिक सवाल उठाया गया है और वह यह है कि वह एलेक्टड मेम्बर हैं इसलिये उनको यह अधिकार दे दिया जाय कि कोई उनको हटा न सके और उनके ऊपर कोई सुपरविजन न हो। श्री राजाराम जी को एक गलतफहमी यह हुई कि वह यह समझते हैं कि जब एक इफा मेम्बर चुना गया तो उसको कोई हटा नहीं सकता है चाहे वह काम करे या न करे, चाहे बेईमानी करता रहे या गवन करता रहे लेकिन वह हटा नहीं सकता है। इसका उत्तर एक सदस्य ने कज दिया था कि पिछली बार पार्लियामेंट के एक सदस्य को हटाया गया था। क्योंकि उन्होंने किसी काम के लिये सपना ले लिया था जो कि एक पार्लियामेंट के मेम्बर के लिये शोभा नहीं देता है। जब डिमोक्रेसी के अधिकार होते हैं तब कुछ चेक्स एंड बैलेंसेज जरूरी हैं। डिमोक्रेसी में कोई एक्स्टर्नल अथॉरिटी कुछ चेक्स एंड बैलेंसेज रखती है। डिमोक्रेसी में कोई ऐसा अधिकारी नहीं है जो रिमूव किया जा सके। प्रेसिडेंट आफ इंडिया को रिमूव किया जा सकता है, चीफ मिनिस्टर को रिमूव किया जा सकता है, पार्लियामेंट के मेम्बरों को रिमूव किया जा सकता है, लेजिस्लेचर्स के मेम्बर को रिमूव किया जा सकता है। किस रास्ते से वह रिमूव किये जा सकते हैं या उनको कौन रिमूव करे यह दूसरा सवाल है लेकिन यह समझ लेना कि जो एक इफा चुना गया वह वह ५ साल तक या ४ साल तक चलता रहे चाहे वह काम करे या न करे, चाहे वह बेईमानी करे या गवन करे तो यह बिल्कुल गलत उसूल होगा। इसलिये इस बात पर बहस हो सकती है कि कौन उसको रिमूव करे और किस तरीके से करे। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जहां तक सिद्धांत के रूप में उठाया गया वह गलत है। जब वह क्लोज आयेगा तो उस पर बहस हो सकती है। इस तरह से मैंने उन मोटी मोटी बातों का उत्तर दे दिया जो यहां पर उठाई गई हैं। मैं फिर एक बार सदन के उन सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस अमंडेड बिल का स्वागत किया है लेकिन मैं एक बात श्री कन्हैयालाल जी से निवेदन करना चाहता हूँ। उन्हें कुछ लोगों की मनोवृत्ति अच्छी नहीं दिखाई देती है। मुझे मालूम नहीं कि उनके ऐसा कहने में आब्जेक्टिव फॅक्टर था या सब्जेक्टिव फॅक्टर था। मैं ज्यादा इस पर कुछ नहीं कह सकता हूँ। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि कई बार मनुष्य खुद ही अपनी विचारधारा का शिकार बन जाता है और उसको तब सभी लोग गलत दिखाई देते हैं।

*श्री कन्हैया लाल गुप्त (अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र)—मेरा मोटिव पर अटक नहीं है।

श्री मोहन लाल गौतम—शब्द आपके यह थे “मनोवृत्ति निष्पक्ष नहीं दिखाई देती है।” यहां तो हिन्दी के विद्वान और विदुषी बड़े हुये हैं वह इसका मतलब बतलायेंगे लेकिन श्री कन्हैयालाल जी का जो टुंड था वह तो काफी कड़ा था। वह इस बात को जाहिर कर रहा था जते उनको संसार में किसी का विश्वास नहीं है। वह सब को ईमानदारी से दूर समझते हैं। सिक्रेटैरियेट के संबंध में जो उन्होंने कहा उसके संबंध में मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जितनी जानकारी मुझको इस बारे में है वह तो मैं कह नहीं सकता लेकिन अगर वह इस

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

हाउस के सदस्य न होते तो उत्तर देते। मैं खुश हूंगा कि अगर कोई गलत चीज मेरे सामने लाई जाय और मैं उसकी जांच करूं।

मैं उनकी जांच करूं तो उत्तर दूँ। यह तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि पिछले ५-६ महीने से देख रहा हूँ और मैं अपने सिक्रेटेरियट से खुश हूँ। इसका मुझे अभिमान है कि वह प्रच्छी तरह से काम कर रहा है।

श्री कन्हैया लाल गुप्त—मैंने सिक्रेटेरियट के बारे में जो कुछ कहा था उसका अवश्य आशय केवल इसलिये था कि इस बिल को देरी से लाया गया। मैं केवल यही शिकायत करना चाहता था और कोई दूसरी बात नहीं थी।

श्री मोहन लाल गौतम—ठीक है, इसका उत्तर मैं इस समय सदन के सामने नहीं दे रहा हूँ। कन्हैया लाल जी को समझा दूँगा। किन्तु प्रश्न से प्रश्न के प्रत्यक्ष को देखना पड़ता है। रुनोंदारी से जो समस्याएँ उत्पन्न होती हैं उसमें हजारों लाखों आदमियों का प्रश्न होता है उसकी प्रज्ञा से समय लग जाता है। इतना मैं कह सकता हूँ कि सिक्रेटेरियट पूरी कोशिश करता रहा और जितनी जल्दी हो सका सदन के सामने यह बिल लाया गया।

श्री गोविन्द सहाय (स्नातक निर्वाचन क्षेत्र)—Is the secretariat a personal property of the Hon'ble Minister.

चेयरमैन—I disallow this.

श्री मोहन लाल गौतम—अब इसलिये मैं यह समझता हूँ कि जो बिल मैंने आपके सामने रखा उस बिल में जो क्लॉज हैं उसमें अधिकांश सदस्य उनकी संपादित करते हैं। एलेक्शन भी आप चाहते हैं कि जल्दी हो। कोई सदस्य इस बात की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता कि एलेक्शन में देरी हो इसलिये मैं इसको सेलेक्ट कमेटी के सामने रखना उचित नहीं समझता हूँ और चाहता हूँ कि यह बिल कंसिडर किया जाये।

चेयरमैन—पहिले संशोधन सदन के सामने रखा जायेगा।

प्रश्न यह है कि सन् १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक को विशिष्ट समिति के सुपुर्वे किया जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

चेयरमैन—प्रश्न यह है कि सन् १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २

२—यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ (जिसे यहां आगे चल कर मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा ८ की उपधारा (१) में खंड (j) के बावजूद यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ की धारा ८ का निम्नलिखित नया खंड () के रूप में बढ़ा दिया जाय।

“(ff) making arrangements for preparation of compost manure from nightsoil and rubbish.” संशोधन।

श्री राम लगन सिंह (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—Sir, I beg to move that in clause 2, line 1, substitute the figure 7 for figure 8 and in lines 3 and 4 substitute (cc) for (jj).

बिल का क्लॉज वो जो है वह मैग्योर के बारे में है। आज कल हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या गल्ले की है और गल्ला अधिक पैदा करने के लिये यह आवश्यक

[श्री राम लगन सिंह]

है कि हम अधिक से अधिक नैन्थोर पैदा करें, और यह स्पष्ट है कि कम्पोज्ड मैन्थोर सब से अच्छी मैन्थोर मानी जाती है। सेक्शन ७ का म्युनिसिपल ऐक्ट जो है। वह बोर्ड के मैनेजेंटरी फंक्शन्स को डिफाइन करता है। जो फंक्शन बोर्ड का करने जरूरी हैं वह सेक्शन १ ले आउट करता है। मैं इस अमेंडमेंट के जरिये मंत्री महोदय से यह निवेदन कर रहा हूँ कि वह इस कम्पोस्ट को म्युनिसिपल बोर्ड के मैनेजेंटरी फंक्शन्स में कर दें।

*श्री प्रभु नारायण सिंह (स्थानीय संस्थाओं दिर्वाचन क्षेत्र)—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार का एक संशोधन मैंने भी दिया था। लेकिन चूंकि श्री राम लगन सिंह जी का संशोधन उस से मेल खाता है इसलिए मैं अपनी राय इस के तंत्र में इसी वक्त जाहिर कर देता हूँ। जैसा कि श्री राम लगन सिंह जी ने कहा कि सेक्शन ८ जो है वह मैनेजेंटरी है वह बोर्ड के डिस्क्रेशन पर उसके फंक्शन देता है। हम समझते हैं कि जब इस बिल में संशोधन किया जा रहा है तो यदि इसमें मैनेजेंटरी का प्राविजन न रखा गया तो यह उचित नहीं किया गया है। जहां तक नाइट स्वायल और रबिस की खाद बनाने का सवाल है वह ऐसा सवाल हो गया है कि आज म्युनिसिपैलिटी के अन्दर मैनेजेंटरी का तरीका रखा जाना चाहिये। जहां तक उत्पादन का सवाल है उससे काफी मदद मिल सकती है। इसके साथ साथ काफी बड़ी रकम भी बढ़ायी जा सकती है। अभी हम लोगों ने सुना कि सोराष्ट्र को एक महुआ म्युनिसिपैलिटी ने काफी रुपया इस काम से कमाया है। हमारे यहां यह होता है कि इलाहाबाद म्युनिसिपैलिटी को छोड़ कर, जहां कि यह चौख थोड़ी बहुत है हालांकि वहां भी पूरे तौर से नहीं होती है, अधिकांश म्युनिसिपल बोर्ड इस को खड़े या तालाब पाटने के काम में लाते हैं जब कि इस से काफी फायदेमन्द चीज हो सकती है। हमारे यहां तो इस पर कुछ खर्च नहीं किया जाता है लेकिन जापान में लोग मेहतरो से लेते हैं और इस चीज को लेते हैं। ऐसी हालत में जो संशोधन श्री राम लगन सिंह जी ने रखा है उस को माननीय मंत्री जी को मान लेना चाहिये। प्राविशियल सरकार की तरफ से हर म्युनिसिपैलिटी के लिये इस तरह की स्कीम बनानी चाहिये। म्युनिसिपैलिटियों में यह काम जल्द से जल्द शुरू किया जाय और इसके साथ ही यह ध्यान देना चाहिये कि यह चीज मैनेजेंटरी प्राविजन में रखी जाय नहीं तो बहुत से म्युनिसिपल बोर्ड ऐसा नहीं करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं फिर माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि वे इस संशोधन को मान लें।

श्री मोहन लाल गौतम—मुझे इसके सिद्धांत को मानने में कोई एतराज नहीं है लेकिन कुछ प्रैक्टिकल दिक्कतें हैं इसलिये इस समय स्वीकार नहीं कर सकता।

*श्री पूर्णचन्द्र विद्यालंकार (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—अध्यक्ष महोदय, इस संशोधन में कम्पोस्ट के बारे में कहा गया है। यह जो कम्पोस्ट का कूड़ा है वह किस की सम्पत्ति है इसके बारे में आजकल एक स्ट्रगल चल रहा है। म्युनिसिपल बोर्ड उस को अपने हाथ में कर रहे हैं। मेरी यह प्रार्थना है कि इस को बर्नात समय यह ध्यान दिया जाय कि यह भंगियों की सम्पत्ति है और म्युनिसिपल बोर्ड इसको न ले।

श्री राजा राम शास्त्री—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि इसने जो प्रैक्टिकल दिक्कतें आयेंगी तो वह कौन सी दिक्कतें हैं।

मैं यह जानना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि इस संशोधन को मानने में कुछ प्रैक्टिकल कठिनाई है तो हम उन कठिनाइयों को जानना चाहते हैं कि वह कौन-सी कठिनाई है जिसकी वजह से आप इतने महत्वपूर्ण संशोधन को मानने से मजबूर हैं। साथ ही साथ मैं

* सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

यह भी कहना चाहता हूँ कि अभी श्री पूर्ण चन्द्र जी ने जो बातें कही हैं उन की ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिये, क्योंकि एक नये संघर्ष होने का डर है। यह जो नाइट स्वायत्त होती है तो मेहतर समझते हैं कि यह उनकी सम्पत्ति है और म्युनिसिपैलिटी समझती है कि यह उनकी सम्पत्ति है। मैं समझता हूँ कि इस पर अच्छी तरह से विचार कर लेना चाहिये। माननीय मंत्री जी को कोई ऐसा तरिका निकालना चाहिये जिस से यह संघर्ष न हो।

चेयरमैन—माननीय मंत्री के अंतिम उत्तर देने से पहले अगर किसी सदस्य को बोलना है तो बोल सकते हैं।

श्री मोहन लाल गौतम—माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने अभी कहा कि जहाँ तक कम्पोस्ट बनाने का सवाल है वह एक बहुत ही अच्छा कार्य है और यह जितना हो सकता है होना चाहिये। इस संबंध में जो दिक्कतें आयें उनको दूर करना चाहिये इसी पर विचार करते हूँ। यह संशोधन रखा गया है। जहाँ तक कम्पोस्ट बनाने का सवाल है वह कोई भी म्युनिसिपैलिटी बना सकती है। लेकिन इस की पूर्ति करना ज्यादा तर थो मोर फूड कम्पेन और गवर्नमेंट आफ इंडिया की है। सब से पहले म्युनिसिपल बोर्ड के सामने जो दिक्कतें हैं वह यह हैं कि उस की आर्थिक हालत अच्छी नहीं है। इसके लिये उम्मीद है कि गवर्नमेंट आफ इंडिया आर्थिक सहायता देगी। जब उस को वहाँ से आर्थिक सहायता मिल जायेगी तो वह अपना कार्य अच्छी तरह से कर सकेगी। हमारी राज्य सरकार के पास इतना धन नहीं है कि वह इस को चला सके। म्युनिसिपैलिटीज की आर्थिक अवस्था अच्छी न होने की वजह से वह अपने स्कीम को अच्छी तरह से नहीं चला सकती है। इस वजह से श्री राम लगन जी ने जो संशोधन पेश किया है उसको मैं मंजूर नहीं करता हूँ।

मुझे इस बात का दुःख है कि इन्हीं कठिनाइयों की वजह से जो संशोधन श्री राम लगन जी ने पेश किया है वह माकूल होते हुये भी मुझे अस्वीकार करना पड़ रहा है।

चेयरमैन—The question is that in clause 2.....

श्री राम लगन सिंह—श्रीमान् जी, मैं अपना संशोधन वापस लेता हूँ।

चेयरमैन—अब चूंकि प्रश्न उपस्थित हो चुका है इसलिये आपके इस चीज के पेश करने में काफी देर हो गई है। इसलिये यह प्रस्ताव अब वापस नहीं लिया जा सकता है।

चेयरमैन—The question is that "In clause 2, line 1, substitute the figure 7 for figure 8 and in line 3 and 4 substitute (cc) for (j)."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और निम्नलिखित विभाजन के पश्चात् अस्वीकृत हुआ)

पक्ष में ६

श्री कुंवर गुरु नारायण
श्री नरोत्तम दास टंडन
श्री प्रभु नारायण सिंह

श्री बी० पी० बाजपेयी
श्री राजा राम शास्त्री
श्री हृदय नारायण सिंह

विपक्ष में ३५

श्री अब्दुल शकूर नज़मी
श्री उमानाथ बली
श्री कन्हैया लाल गुप्त

श्री मानपाल गुप्त
श्री मौलाना मोहम्मद नसीर
श्री राना शिवअम्बर सिंह

[चेयरमैन]

श्री जगन्नाथ
श्री ज्योति प्रसाद
श्रीमती तारा अग्रवाल
श्री निजामुद्दीन
श्री निर्मल चन्द्र चतुर्वेदी
श्री प्रताप चन्द्र आज़ाद
श्री प्रसिद्ध नारायण अन्नद
श्री प्रेमचन्द्र
श्री परमात्मानन्द सिंह
श्री पूर्णचन्द्र विद्यालंकार
श्री बद्रो प्रसाद कक्कड़
श्री बशीर अहमद
श्री अब्दुल मजीद
श्री महमूद अस्सलम खां

श्री राम किशोर
श्री राम किशोर शर्मा
श्री राम लगन सिंह
श्री रुकनुद्दीन खां
श्री लालता प्रसाद सोनकर
श्री लाल सुरेश सिंह
श्री विद्वनाथ
श्री शांति स्वरूप अग्रवाल
श्रीमती शांति देवी अग्रवाल
श्रीमती शांति देवी
श्रीमती शिवराजवती नेहरू
श्री शिवसरन लाल जौहरी
श्री सत्यप्रेमी उपनाम हरिप्रसाद
श्री सरदार संतोष सिंह
श्री एम० जे० मुकर्जी

श्री राजाराम शास्त्री—जैसा कि, माननीय अध्यक्ष जी, आप ने कहा है कि जो मेम्बर सवाल पूछते हैं और वह रहते नहीं हैं तो इस तरह से सदन का समय बरबाद होता है इसी तरह से जो प्रस्तावक महोदय हैं और वह अपने संशोधन पर खिलाफ राय देते हैं तो इस तरह से वह सदन का समय ही बरबाद करते हैं।

चेयरमैन—जब चेयरमैन खड़ा होता तो किसी अन्य सदस्य को नहीं खड़ा होना चाहिये। दूसरी बात यह है कि हर सदस्य को अपने संशोधन के पक्ष में या विपक्ष में वोट देने का अधिकार है। यह उसकी आत्मा जाने, उसकी तबियत जाने, कि वह क्यों वोट दे रहा है।

प्रश्न यह है कि खंड २ इस बिल का भाग बना रहे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ३

३—मूल अधिनियम की धारा ८ के बाद निम्नलिखित नई धारा ८-ए के रूप में रखी जाय:—

Definition 8-A. In this Chapter unless there is anything repugnant in the subject or context—

- (a) "Assembly Rolls" mean the electoral rolls prepared for the Assembly constituencies under and in accordance with the provisions of the Representation of the People Act, 1950;
- (b) "Director of Elections (Local Bodies)" means an officer appointed by the State Government in this behalf by notification in the Official Gazette."
- (c) "election" means an election to fill a seat on a Board;
- (d) "elector" in relation to a ward means a person whose name is for the time being entered in the electoral roll of that ward;
- (e) "Order" means an Order published in the official Gazette or in the manner prescribed;

यू० पी० ऐक्ट, २,
१९१६ में नई
धारा ८-ए का
बढ़ाया जाना।

(f) "Scheduled Castes" mean the castes specified in the constitution (Scheduled Castes) Order, 1950 ; and

(g) "Ward" means a ward provided by Delimitation Order under section 11-B.

श्री प्रभु नारायण सिंह—खंड ३ में प्रस्तावित नई धारा ८ के उपखंड ए को एए लिखा जाय और उससे पहले निम्नलिखित खंड ए के रूप में जोड़ दिया जाय—

"3(a) "Local Self-Government Board" means a board having the powers of supervision and control over local boards and consisting of :—

- (i) A whole time salaried President who should be a public man with considerable experience of local Self-Government to be appointed by Government;
- (ii) Four members to be elected by the Legislative Assembly;
- (iii) Two members to be elected by the Legislative Council;
- (iv) Six representatives of district and municipal boards to be appointed by Government for the first term and thereafter to be elected by unions of district and municipal boards which should be organised by the Local Self-Government Board, and
- (v) Eight nominees of Government including the following experts;
 - (1) The Inspector General of Civil Hospitals;
 - (2) The Director of medical and public Health services;
 - (3) The Superintending Engineer, Public Health Department;
 - (4) The Chief Engineer, Buildings and Roads;
 - (5) The State Town Planning Officer;
 - (6) The Director of Education.

Explanation—All elections to the Local Self-Government are to be held by single transfer vote.

इसमें एक नई डिफ़ीनेशन जोड़ी जा रही है। लेकिन लोकल सेल्फ़ गवर्नमेंट बोर्ड का मतलब क्या होगा और भी कई संशोधन के प्रस्ताव इस तरह के हैं।

मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि जिस तरीके से पुराना म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट हमारे सामने है उसको देखने से ऐसा मालूम होता है कि उससे हमारे स्वायत्त शासन की डिफ़ीनेशन जो कायम रहना चाहिये वह नहीं रह पाती। पुराने ऐक्ट के अनुसार ब्रिटिश शासन काल में सुपरविजन का अधिकार डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और कमिशनर को दिया गया था। सन् १९१६ के ऐक्ट के मुताबिक जो ऐक्ट कि अब भी बरकरार है उस में आज भी उसी तरीके की धाराएँ हैं जिससे आज भी सुपरविजन और कंट्रोल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और ऐसे लोगों के हाथ में है। पहली बात तो अग्र्यक्ष महोदय में यह समझता हूँ कि स्वायत्त शासन जो कि एडल्ट फ्रंचाइज के आधार पर चुने जाते हैं उन के अधिकारों पर आफीशल वर्ग की तरफ से ऐसा कंट्रोल न होना चाहिये जो ऊपर से लादा हुआ मालूम हो। इसीलिए मैंने यह सुझाव रखा कि म्युनिसिपल बोर्ड को सुपरवाइज करने के लिये एक लोकल सेल्फ़ गवर्नमेंट बोर्ड बनाना चाहिये, जिस का प्रेसीडेंट होल टाइम हो। इसके साथ ही साथ उसमें असेम्बली और काउंसिल के कुछ मेम्बर्स हों, म्युनिसिपल बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुने हुए प्रतिनिधि हों और साथ ही ऐसे एक्सपर्ट्स भी हों जो कि स्वास्थ्य के मामले में, इंजीनियरिंग के मामले में, एजुकेशन के मामले में, प्लानिंग के मामले में तथा अन्य मामलों में अच्छा ज्ञान रखते हों। एक सवाल हमारे सामने यह भी है कि प्राविशियल गवर्नमेंट और लोकल बाडीज का क्या कोऑर्डिनेशन हो। हम यह महसूस करते हैं कि आज के युग में जब हम इस बात को सोचते हैं कि अधिक से अधिक पावर्स डिसेन्ट्रलाइज्ड हों तो हम इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि जो प्राविशियल और सेंट्रल प्लानिंग का काम है वह प्राविशियल और सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होगा। लेकिन साथ ही साथ जब सीधे म्युनिसिपल बोर्ड बनेंगे उन के

[श्री प्रभु नारायण सिंह]

सिलसिले में यह जरूरी हो जायेगा कि जो प्राविन्शियल कार्य हम उचित समझें कि म्युनिसिपैलिटीज़ करे उन का कोऑर्डिनेशन एक दूसरे से होना चाहिये। इसलिये भी एक कमेटी की जरूरत है जो कि इस तरह के प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन को कर सके। इसके सिलसिले में कुछ बात याद रखने की जरूरत है। जैसा कि अभी सवाल उठा।

*श्री शांति स्वरूप अग्रवाल (अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र)—आन प्वाइन्ट आफ़ आर्डर, मुझे निवेदन यह करना है कि दूसरी धारा में यह अमेंडमेंट इस अधिनियम के जो सामने आ रहा है, नहीं रहता है। इससे यह हो जाता है कि उस मुख्य ऐक्ट का जिसमें अमेंडमेंट करने के लिये यह अधिनियम लाया जा रहा है और जो अधिनियम हमारे सामने है उसमें यदि कोई अमेंडमेंट लाया जाता है तो वह इसलिये कि इसकी मंशा से बहुत दूर न हो जाये। यह जो अमेंडमेंट लाया जा रहा है उससे इसके संबंध में कोई बात नहीं रहती बल्कि उससे बिल्कुल दूर हो जाता है जो कि इस अधिनियम की मंशा में नहीं है।

चेयरमैन—जो मूवर साहब हैं क्या वह बतला सकते हैं कि इस संशोधन का मूल अधिनियम और इस विधेयक से क्या संबंध है।

श्री प्रभु नारायण सिंह—अधिनियम से यह संबंध है कि जहां पर गवर्नमेंट शब्द आया है उसकी जगह पर हम लोकल सेल्फ़ गवर्नमेंट बोर्ड रखना चाहते हैं। उस लोकल सेल्फ़ गवर्नमेंट बोर्ड को हमने इक्सप्लेन किया है। जो अमेंडमेंट है वह इससे संबंधित है।

श्री प्रताप चन्द्र आज़ाद (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—आप का जो अमेंडमेंट है वह आउट आफ़ आर्डर है।

चेयरमैन—आप कोई दूसरी बात कहना चाहते हैं या वही बात जो पहले कही गयी है।

श्री प्रताप चन्द्र आज़ाद—मैं वही बात कहना चाहता हूं।

श्री मोहन लाल गौतम—यह एक ऐसा बड़ा सवाल है जो कि इस अमेंडमेंट बिल से ताल्लुक नहीं रखता है। उसको बैंक डोर से लाने की कोशिश की जाती है। अगर मैं इस अमेंडमेंट को मान लू तो यह कैसे फ़ंक्शन करेगा। केवल स्टेट गवर्नमेंट की जगह यह बोर्ड बना दिया जाय तो बग़ैर इसकी ड्यूटी डिफ़ाइन किये यह फ़ंक्शन कैसे करेगा। इस बिल की क्या शकल होगी। उनकी राइट और ड्यूटी क्या होगी। यह इतना महत्वपूर्ण सवाल है कि जिसके ऊपर काफ़ी विचार करने की आवश्यकता है इसलिये यह आउट आफ़ आर्डर है। अगर इसको मंजूर कर लिया जाय तो गवर्नमेंट के काम में बाधा पड़ेगी।

चेयरमैन—यह वैधानिक आपत्ति उठाई गयी है कि यह संशोधन बिल के स्कोप के बाहर है। उसके जवाब में मूवर साहब ने कहा है कि और धाराओं के संबंध में गवर्नमेंट की जगह पर लोकल सेल्फ़ गवर्नमेंट बोर्ड रखा जाय तो वह जायज़ है। इसलिये उसको यहां रखने के लिये उसको यहां पर डिफ़ाइन करना जरूरी होगा। माननीय मंत्री जी ने कहा कि अगर इसको एक्सेप्ट कर लिया जाय तो बिल का स्वरूप भयंकर होगा। बिल का स्वरूप क्या होगा इसको सदस्यों को समझना चाहिये। इसको समझ कर वे वोट देंगे। बिल का स्वरूप ठीक होगा या नहीं होगा इस प्रकार की आपत्ति अवैधानिक है।

अब सवाल यह है कि इसमें एक ऐसी संस्था का समावेश करना विधेयक के स्कोप के भीतर है या नहीं। जो बिल है उसमें एक ऐसी बाडी को इंटीग्रेट करना इस बिल के स्कोप के बाहर है। मैं इसलिये इस अमेंडमेंट की इजाज़त नहीं दे सकता।

श्री राजा राम शास्त्री—माननीय अध्यक्ष जी, यह हो सकता है इसके संबंध में और वही सवाल उठाया जाय। २४ दफ़ा जो आ रही है उसमें लिखा है कि गवर्नमेंट एकाउन्ट आफ़िसर

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

को नियुक्त करे। मेरा कहना है कि पब्लिक सर्विस कमीशन नियुक्त करे। मैंने तो केवल इसको डिफरेंशन के लिये ही पेश किया है दफा २४ में जहां गवर्नमेंट ने यह लिखा है कि वह एकाउन्ट्स आफिसर नियुक्त करेगी तो मेरा कहना है कि वह नियुक्त करने के बजाय पब्लिक सर्विस कमीशन से हो। तो उसको डिफाइन करने के लिये ही मैंने इसको पेश किया है।

चेयरमैन—आप एकाउन्ट्स आफिसर की नियुक्ति के लिये यह चाहते हैं कि उस की नियुक्ति किसी नई संस्था के द्वारा हो या आप यह चाहते हैं कि इग्जिस्टिंग पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा हो।

श्री राजा राम शास्त्री—मैं चाहता हूं कि इसकी नियुक्ति के लिये एक बाडी हो उसी को डिफाइन करने के लिये मैंने यह रखा है।

चेयरमैन—आप इस बात को छोड़ दीजिये। मैं तो यह जानना चाहता हूं कि आप नियुक्ति किसी वर्तमान संस्था द्वारा चाहते हैं या नई संस्था से चाहते हैं।

श्री राजा राम शास्त्री—मेरी मंशा तो नई बाडी के लिये ही है।

श्री प्रभु नारायण सिंह—गवर्नमेंट ने एक एकाउन्ट्स आफिसर नियुक्त करने की बात रखी है। यह इट सेल्फ एक नया आईडिम है। हम चाहते हैं कि एक नई बाडी से एकाउन्ट्स आफिसर को नियुक्ति हो।

चेयरमैन—राय तो हर एक आदमी अपनी रखता है लेकिन काम होगा मेरी राय के साथ। इसलिये मैं यह समझता हूं कि आप किसी नई बाडी द्वारा एकाउन्ट्स आफिसर की नियुक्ति के लिये नई संस्था बनाने के संबंध में संशोधन नहीं रख सकते हैं। आप इसको या तो वर्तमान कमीशन के द्वारा करा सकते हैं या बोर्ड के द्वारा लेकिन नई संस्था स्थापित करके इस विधेयक का स्कोप नहीं बढ़ा सकते हैं।

श्री प्रभु नारायण सिंह—प्रध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जब एक नया एकाउन्ट्स आफिसर नियुक्त होने जा रहा है तो यह एक नया आईडिम होगा जो अब तक ऐक्ट में नहीं था इसलिये यह भी सजेशन हो सकता है कि एक नई बाडी द्वारा उसकी नियुक्ति हो।

चेयरमैन—जब एक दफा खोलग हो गई तो बात खत्म हो जाती है। अगर आप को कुछ कहना है तो मेरे चेम्बर में मुझसे मिल सकते हैं।

प्रश्न यह है कि खंड ३ इस बिल का भाग बना रहे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ४

४—मूल अधिनियम की धारा ९ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय :—

9. Except as otherwise provided by section 10, a board shall consist of—

(a) a President : and

यू० पी०
ऐक्ट २,
१९१६ की
धारा ९ का
संशोधन।
Normal
composi-
tion of
the Board.

[खंड ४]

(b) the elected members who shall not be less than 15 and more than 50 as the State Government may, by notification in the official Gazette, specify.

चेयरमैन—प्रश्न यह है कि खंड ४ इस बिल का भाग बना रहे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड ५ और ६

यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ में नई धारा ६-ए का बढ़ाया जाना।
 Reservation of seats for Scheduled Castes.

५—मूल अधिनियम की धारा ६ के बाद निम्नलिखित नई धारा ६-ए के रूप में रक्खी जाय :—

9-A. (1) Seats shall be reserved for Scheduled Castes in each board.
 (2) The number of seats reserved under sub-section(1) shall bear as nearly as may be the same proportion to the total number of seats on the board as the population of the Scheduled Castes in the municipality bears to its total population as determined at the last census held under the provisions of the Indian Census Act. 1950.

यू० पी० ऐक्ट, २ १९१६ की धारा १० का संशोधन।

६—मूल अधिनियम की धारा १० के वर्तमान प्रतिबन्धनात्मक वाक्य के स्थान पर निम्नलिखित रक्खा जाय :—

“Provided that the provisions of this section shall not be applicable to a municipality which was already constituted under this Act on the day immediately preceding the commencement of the U. P. Municipalities (Amendment) Act, 1948, unless the municipality is one which, the State Government are satisfied, is subject to substantial seasonal variation of night population.”

चेयरमैन—धारा ५ के संबंध में श्री गोविन्द सहाय ने एक अमेन्डमेंट दिया है क्या वह यहां मौजूद हैं?

एक सदस्य—नहीं है।

चेयरमैन—प्रश्न यह है कि खंड ५ व ६ इस बिल का भाग बने रहें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ७

७—मूल अधिनियम की धारा १० के बाद निम्नलिखित नई धारा १०-ए के रूप में

यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ में नई धारा १०-ए का बढ़ाया जाना।

रक्खी जाय :—

10-A. (1) Except as provided in sections 31, 32-A or 47-A every board shall continue for 4 years from the date of notification issued in pursuance of section 13-G that the board has been constituted :

Provided that the State Government may, by notification in the official Gazette extend from time to time the term of all or any board,

so, however, that the total extension does not in the aggregate exceed two years.

(2) The term of a board shall begin from the date of notification issued in pursuance of section 13-G that the board has been constituted.

श्री सत्यप्रेमी उपनाम हरिप्रसाद—में अपना संशोधन मूव नहीं करना चाहता ।

श्री प्रभु नारायण सिंह—इसमें चूंकि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात आई है इसलिये मैं इसको मूव नहीं करना चाहता हूं । इसके बाद एक प्रताप चन्द्र आजाद का है शायद वह मूव करें ।

श्री पूर्णचन्द्र विद्यालंकार (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—मैं इसको मूव नहीं करना चाहता ।

श्री प्रभु नारायण सिंह—जो प्रताप चन्द्र आजाद ने अमेंडमेंट रखा था उसी के कुछ रूप में मेरा भी संशोधन है । मेरा संशोधन इस तरह से है:—

Sir, I beg to move that in the last line of the amended Section 10-A the words "One year" be substituted for "two years".

मैं चाहता हूं कि दो साल के स्थान पर एक साल का समय कर दिया जाये । यह जो संशोधन है मैं समझता हूं कि सदन के अधिकांश सदस्यों की यह राय है कि यह समय एक साल का कर दिया जाये । इसके संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि यह साफ तौर से कह दिया गया है कि बोर्ड का कांस्टीट्यूशन ४ साल के लिये होगा इसके बाद आगे चल कर यह कहा गया है कि यदि गवर्नमेंट उचित समझ तो बोर्ड का जीवन बढ़ाया जा सकता है और वह दो साल तक का हो सकता है मैं समझता हूं कि दो साल का समय जरूरत से ज्यादा है । यदि इक्सटेंशन की आवश्यकता पड़ ही जाती है तो उसको छः महीने का एक्सटेंशन दिया जाये और फिर अगर जरूरत समझी जाये तो छः महीने का समय और बढ़ा दिया जाये । लेकिन साल भर से ज्यादा पावर देना मैं उचित नहीं समझता । पहले तो मंत्री महोदय ने ही सरकार के ऊपर दो साल का अंकुश लगाया है । उन्होंने यह वाजिब समझा कि अगर सरकार के ऊपर अंकुश न लगाया जायेगा तो शायद यह समय बढ़ता ही चला जाये । लेकिन मैं समझता हूं कि दो साल का समय भी ठीक नहीं है । जब आप दो साल का प्राविजन बनाते हैं तो होता यह है कि जितने का प्राविजन होता है उससे बढ़ जाया करता है तो उससे यह होगा कि समय दो साल से भी अधिक लग जायेगा । इसलिये मैं यह उचित समझता हूं कि दो साल के बजाय एक साल का ही समय रखा जाये तो ज्यादा अच्छा होगा ।

श्री सत्यप्रेमी उपनाम हरिप्रसाद—इस धारा में मेरा भी एक संशोधन है जो इस संशोधन के पहिले है ।

चेयरमैन—मैंने पहले आपका नाम पुकारा था शायद आप उस समय नहीं थे । अब उसको बाद में ले लिया जायेगा ।

श्री मोहन लाल गौतम—जो संशोधन दो साल के बजाय एक साल को करने के लिये रखा गया है उसमें कोई खास दिक्कत तो नहीं है लेकिन यह देखने में आता है कि कई बार इस प्रकार की कठिनाइयां आ जाती हैं जो कि चुनाव करने में लगभग असंभव सा हो जाता है । जिस प्रकार से यह अमेंडिंग बिल बनाया गया है उसमें यह विचार धारा है कि चार साल का बोर्ड का जीवन काल हो और उसके बाद एक्सटेंशन किया जाये । यह एक सिद्धांत रूप में चलना चाहिये । अगर एक्सटेंशन किसी का होता है चाहे वह ६ महीने का हो या एक साल का हो जब तक कोई विशेष परिस्थिति नहीं होगी तब तक इक्सटेंशन नहीं होगा । यह विचार धारा इस बिल में रखी गई है । कई बार इस तरह की दिक्कतें आ गई हैं कि जहां चुनाव करना लगभग असंभव है तो इस चीज को सामने रख कर आखीर में यह डिस्क्रेसनरी पावर सरकार को दी

[श्री मोहन लाल गौतम]

गयी है। इसमें बहुत सी बातें आ जाती हैं अगर दो साल तक की मियाद है तो इसके माने यह नहीं है कि हर बोर्ड ६ साल तक रहेगा ही। ऐसी बातें हमारे दिमाग में नहीं हैं। एक और भी बात है कि किसी बोर्ड को सरकार एक्सटेंड नहीं करना चाहती है लेकिन परिस्थिति ऐसी हो जाती है और उस जगह की मांग होती है तो ऐसा करना पड़ेगा। यदि किसी स्थान में अकाल पड़ गया और उस समय डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का इलेक्शन कराना है तो लोग कहेंगे कि जितना रुपया इस में खर्च किया जा रहा है उतना भूखों को बांट दिया जाय। तो हमेशा सरकार इस का इस्तेमाल नहीं करेगी। इसमें जनता की मांग हो सकती है और सदन की मांग हो सकती है कि इस वक्त इलेक्शन न कराये जायें। इसलिये हम ने ज्यादा से ज्यादा २ साल रखा है। मैं चाहता हूँ कि आप इस को वापस ले लें क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं है।

श्री प्रभु नारायण सिंह—अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि जनरली ऐसा नहीं करेंगे कि हर बोर्ड की लाइफ ६ साल की हो। तो जहाँ तक उन के अश्वोरेस का सवाल है मैं समझता हूँ कि आपो चल कर उन के मंत्रित्व काल में यह चीज हमें देखने को मिलेगी कि आधा इन पर अमल हो रहा है या नहीं। लेकिन उसके साथ ही साथ जो उन्होंने दूसरी बात स्थानीय परिस्थिति की कही है कि कभी उस से भी चुनाव कराना कठिन हो जाता है और उन्होंने इसका एक उदाहरण भी दिया कि यदि किसी इलाके में सूखा पड़ गया तो म्युनिसिपल बोर्ड का चुनाव कराना मुश्किल होगा।

श्री मोहन लाल गौतम—मैंने म्युनिसिपल बोर्ड नहीं डिस्ट्रिक्ट बोर्ड कहा था।

श्री प्रभु नारायण सिंह—खैर उदाहरण के तौर पर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ही कहा हो तो ऐसा भी हो सकता है कि जब ये दो साल भी खत्म हो जायें और उस समय ऐसी हालत हो तो उस वक्त यदि इलेक्शन स्थगित कराने हों उसके लिये हाउस हमेशा तैयार रहेगा और किसी प्रकार का एतराज नहीं होगा। ऐसी हालत में मैं समझता हूँ कि एक साल का समय काफी है। यदि ४ साल के बाद इलेक्शन कराना मुश्किल हो जाय तो ६ महीने पहले एक्सटेंड करना चाहिये और फिर ६ महीने और करना चाहिए इससे ज्यादा नहीं होना चाहिये।

चेयरमैन—प्रश्न यह है कि “प्रस्तावित प्रतिबन्धात्मक वाक्य की प्रथम पंक्ति ५ में शब्द “two” के स्थान पर शब्द “one” रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री सत्य प्रेमी उपनाम हरि प्रसाद—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि खंड ७ की पंक्ति २ का शब्द “रक्खा” शब्द “रक्खी” से बदल दिया जाय।

चेयरमैन—प्रश्न यह है कि खंड ७ की पंक्ति २ का शब्द “रक्खा” शब्द “रक्खी” से बदल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

चेयरमैन—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ७ बिल का भाग बना रहे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

यू० पी० एक्ट
२, १९१६ की
धारा ११ और
१३ से १७ तक
का निकाला
जाना।

Delimitation
of wards.

खंड ८

८—मूल अधिनियम की धारा ११ और १३ से १७ तक निकाल दी जायें।

चेयरमैन—प्रश्न यह है कि खंड ८ बिल का भाग बना रहे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ६

६—मूल अधिनियम की धारा ११ के बाद निम्नलिखित नई धारायें ११-ए से ११-सी तक, १२-ए से १२-एच तक और १३-ए से १३-के तक रक्खी जायें।

DELIMITATION

11-A. (1) For purposes of elections to a board there shall be wards provided by Order under section 11-B.

(2) The representation of each ward shall be on the basis of population of that ward as ascertained at the last census and shall as far as possible be in the same proportion as the total number of seats for the municipality and its population."

11-B. (1) The State Government shall, by Order, determine—

(a) the wards in which each municipality shall be divided for purposes of elections to the board ;

(b) the extent of each ward ;

(c) the number of seats allotted to each ward ; and

(d) the number of seats, if any, reserved for the Scheduled Castes.

(2) The draft of the Order under sub-section (1) shall be published for objections for a period of not less than 15 days and a copy of the same shall be sent to the board or boards concerned for comments.

(3) The State Government shall consider any objections and the comments filed under sub-section (2) and the draft Order shall, if necessary, be amended, altered or modified accordingly and thereupon it shall become final.

11-C The State Government may, after consulting the board concerned, by a subsequent Order, alter or amend the final Order under subsection (3) of section 11-B.

ELECTORAL ROLLS

12-A. Except as provided in section 10, the election of the members of a board shall be on the basis of adult suffrage.

12-B. (1) There shall be an electoral roll for every ward which shall be prepared in accordance with the provisions of this Act under the supervision of the Director of Elections (Local Bodies).

(2) The Electoral Registration Officer shall, for purposes of preparation of the electoral rolls for the ward, adopt the Assembly rolls relating to the area comprised in the said ward and publish the same in the manner prescribed, and upon its publication it shall, subject to any alteration, addition or modification made under or in accordance with this Act, be the electoral rolls for the ward prepared in accordance with this Act.

यू० पी० ऐक्ट
२, १९१६ की
नई धारायें
११-ए से लेकर
११-सी तक
और १२-ए से
लेकर १२-एच,
१३-ए से लेकर
१३-के तक का
रक्खा जाना।

Delimita-
tion order.

Amend-
ment of
Delimita-
tion Order.

Elections on
the basis
of adult
suffrage.

Act XLIII
of 1950.

- (3) Where any addition, omission, alteration or other amendment is made under the Representation of the People Act, 1950, or the Rules framed thereunder, in the Assembly rolls relatable to the area of the ward, a similar amendment shall be made in the corresponding electoral roll of the ward.

Qualification
for electors.

- 12-C Subject to the provisions of section 12-D, every person who is qualified to be registered in the Assembly electoral roll relatable to the area comprised in the ward or whose name is entered therein shall be entitled to be registered in the electoral roll of the ward.

Disqualifi-
cations for
registra-
tion in an
electoral
roll.

- 12-D (1) A person shall be disqualified for registration in an electoral roll if he is disqualified for registration in the Assembly rolls.
(2) The name of any person who becomes so disqualified after registration shall forthwith be struck off the electoral roll of the ward in which it is included;

Provided that the name of any person struck off the electoral roll of a ward by reason of disqualification under sub-section (1) shall forthwith be reinstated in that roll if such disqualification is, during the period such roll is in force, removed under the provisions of this Act or under any other law authorising such removal.

Registra-
tion to be
in one ward
and in one
place.

- 12-E (1) No person shall be entitled to be registered in the electoral roll for more than one ward in the same municipality.
(2) No person shall be entitled to be registered in the electoral roll for any ward more than once.

Electoral
Registration
Officers.

- 12-F The electoral roll for each ward shall be prepared by an Electoral Registration Officer who shall be such officer of the State Government or of a local authority as the State Government may designate or nominate in this behalf.

Annual
revision of
electoral
rolls.

- 12-G The electoral roll for each ward shall be revised every year in accordance with the provisions of this Act.

Order re-
electoral
rolls.

- 12-H. The State Government may, by Order, make provisions in respect of the following matters concerning the electoral rolls, namely,—
(a) the date on which the electoral rolls first prepared and subsequently prepared under this Act shall come into force and their period of operation;
(b) the correction of any existing entry in the electoral rolls on the application of the elector concerned;
(c) the correction of clerical or printing errors in the electoral rolls;
(d) the inclusion in the electoral rolls of the name of any person—
(i) whose name is included in the Assembly rolls for the area relatable to the ward but is not included in the electoral roll of the ward or where name has been wrongly included in the electoral roll of some other ward; or
(ii) whose name is not so included in the Assembly rolls and who is otherwise qualified to be registered in the electoral roll of the ward;

- (e) annual revision of the electoral rolls;
- (f) custody and preservation of the electoral rolls; and
- (g) generally for all matters relating to the preparation and publication of the electoral rolls.

Conduct of Elections

- 13-A. Except as provided in section 31 or 31-A there shall be a general election to a board before the expiry of the term or extended term, as the case may be, of the board under section 10-A on such date or dates as the State Government may, by notification in the official *Gazette*, appoint in that behalf. General Elections.
- 13-B The Director of Elections (Local Bodies) shall supervise the conduct of elections under this Act. Conduct of elections to be supervised by the Director of Elections (Local Bodies).
- 13-C A person shall not be qualified to be chosen to fill a seat on a board unless— Qualifications for membership of the Board.
- (a) in the case of a seat reserved for the Scheduled Castes he is a member of any of these castes and is an elector for any ward in that municipality;
- 13-D A person, notwithstanding that he is otherwise qualified, shall be disqualified for being chosen as, and for being, a member of a board if he— Disqualifications for membership.
- (a) is a dismissed servant of the State or Central Government and is debarred from re-employment therein,
 - (b) is debarred from practising as a legal practitioner by order of any competent authority, or
 - (c) holds any place of profit in the gift or disposal of the board, or
 - (d) is disqualified under section 27 or 41, or
 - (e) is disqualified under section 146 of the Representation of the People Act, 1951.
 - (f) is in the service of the State or the Central Government or any local Authority, or is a District Government Counsel or an Additional or Assistant District Government Counsel or an Honorary Magistrate or an Honorary Munsif or an Honorary Assistant Collector;
 - (g) is unable to read and write Hindi or at least one of the regional languages of the State; or
 - (h) is in arrears in the payment of any tax or other dues in excess of one year's demand to which section 166 applies, or
 - (i) is suffering from leprosy, or
 - (j) is an undischarged insolvent;
- Provided that in cases of (a) and (b) the disqualification may be removed by an order of the State Government in this behalf.
- 13-E. (1) No person who is not, and except as expressly provided by this Act, every person who is for the time being entered in the electoral roll of any ward shall be entitled to vote in that ward. Right to vote.
- (2) No person shall vote at an election in any ward if he is subject to any of the disqualifications referred to in section 12-D.

- (3) No person shall vote at a general election in more than one ward and if a person votes in more than one such ward, his votes in all such wards shall be void.
- (4) No person shall at any election vote in the same ward more than once, notwithstanding that his name may have been registered in the electoral roll for that ward more than once, and if he does so vote, all his votes in that ward shall be void.
- (5) No person shall vote at any election if he is confined in a prison whether under a sentence of imprisonment or transportation or otherwise, or is in the lawful custody of the Police.

Method of
voting.

- 13-F. (1) In plural member wards every elector shall have as many votes as there are members to be elected, but no elector shall give more than one vote to any one candidate.
- (2) If an elector gives more than one vote to any one candidate in contravention of the provisions of sub-section (1), then, at the time of counting of votes, not more than one of the votes given by him to such candidate shall be taken into account and all other votes given by him to such candidate shall be rejected as void.

Order re-
garding
conduct of
elections.

- 13-G. The State Government may by Order, make provision with respect to the following matters concerning conduct of elections, that is to say—
- (a) issue of notifications for general elections ;
 - (b) the appointment, powers and duties of Returning Officers, Assistant Returning Officers, Presiding Officers and Polling Officers and clerks ;
 - (c) appointment of dates for nomination, scrutiny, withdrawal and polling ;
 - (d) the manner of presentation and the Form of nomination paper, the requirements for a valid nomination, scrutiny of nomination, and withdrawal of candidature ;
 - (e) appointment and duties of election agents, polling agents and counting agents ;
 - (f) procedure at general elections including death of candidate before poll, procedure in contested and uncontested elections, special procedure at elections in wards where seats are reserved for Scheduled Castes ;
 - (g) identification of voters ;
 - (h) hours of polling,
 - (i) adjournment of poll and fresh poll ;
 - (j) manner of voting at elections ;
 - (k) scrutiny and counting of votes including recount of votes and procedure to be followed in case of equality of votes and declaration of results ;
 - (l) the notification of the names of the members elected for the various wards of a municipality and the due constitution of the board ;
 - (m) return or forfeiture of deposits :

(n) manner in which votes are to be given by the Presiding Officers, Polling agents or any other person who being an elector for a ward is authorized or appointed for duty at a polling station at which he is not entitled to vote;

(o) the procedure to be followed in respect of the tender of vote by person representing himself to be an elector after another person has voted as such elector;

(p) the safe custody of ballot boxes, ballot papers and other election papers, the period for which such papers shall be preserved and the inspection and production of such papers; and

(q) generally on all matters relating to conduct of elections.

13-H. (1) Subject to the provisions of sub-section (2) and section 13-1, when the seat of a member elected to a board becomes vacant or is declared vacant or his election is declared void, the District Magistrate shall, in consultation with the board, by a notification in the official *Gazette*, call upon the ward concerned to elect a person for the purpose of filling the vacancy caused before such date as may be specified in the notification and the provisions of this Act and of the Rules and Orders made thereunder, shall apply, as far as may be, in relation to the election of a member to fill such vacancy.

Bye-elections.

(2) If the vacancy so caused be a vacancy in a seat reserved in any such ward for the Scheduled Castes, the notification issued under sub-section (1) shall specify that the person to fill that seat shall belong to the Scheduled Castes.

13-I. Where a vacancy occurs on a board by reason of death, resignation, removal or avoidance of an election of an elected member and the term of office of that member would, in the ordinary course of events, have determined within one year of the occurrence of the vacancy, the stat Government may direct that the vacancy be left unfilled until the next general elections.

Certain casual vacancies not to be filled.

13-J. (1) The provisions of sections 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 134, 135 and 136 of Chapter III of part VII of the Representation of the People Act, 1951 shall have effect as if—

Electoral Offences.

(a) the references therein to an election were a reference to an election held under this Act ;

(b) for the word "constituency " the word "ward" had been substituted ;

(c) in section 130 for the words "100 yards" the words "25 yards" had been substituted ; and

(d) in sections 134 and 136 for the words "by or under this Act or under the Representation of the People Act, 1950 (XLIII of 1950)," the words "by or under the U. P. Municipalities Act, 1916," had been substituted.

(2) If the Director of Elections (Local Bodies) has reason to believe that any offence punishable under section 129 or 134 or

under-clause (a) of sub-section (2) of section 136 of the said chapter has been committed in reference to any election to a board, it shall be the duty of the Director of Elections (Local Bodies) to cause such enquires to be made and such prosecutions to be instituted as the circumstances of the case may appear to him to require.

(3) No court shall take cognizance of any offence punishable under section 129 or under section 134 or under clause (a) of sub-section (2) of section 136 unless there is a complaint made by order of or under authority from the Director of Elections (Local Bodies).

Jurisdiction of Civil Courts.

13-K. (1) No Civil Court shall have jurisdiction—

- (a) to entertain or adjudicate upon any question whether any person is or is not entitled to be registered in an electors roll or record; or
- (b) to question the legality of any action taken by or under the authority of an Electoral Registration Officer or of any decision given by any authority appointed under this Act, for the revision of any such roll; or
- (c) to question the legality of any action taken by or any decision given by the Returning Officer or by any other officer appointed in this Act in connection with an election.

(2) No election shall be called in question except by an election petition presented in accordance with the provisions of this Act.

श्री प्रभु नारायण सिंह—श्रीमान् जी में प्रस्ताव करता हूँ कि प्रस्तावित धारा (11-B) में खंड २ की पंक्ति में अंक व शब्द “ 15 days ” के स्थान पर शब्द “ one month ” रख दिये जायें।

यह जोसेक्शन है वह खासतौर से इसलिये है कि स्टेट गवर्नमेंट हर एक म्युनिसिपल बोर्ड के कितने वार्ड्स हों इसका फैसला करेगी, उस वार्ड का क्या एक्सटेंड हो, उसमें कितनी सीट्स हों उसका भी फैसला करेगी। इसके साथ ही साथ शेड्यूल कास्ट के लिये जो रिजर्वेशन आफ सीट्स है उस का भी फैसला करेगी। इस आर्डर में लोगों को १५ दिन के अन्दर आब्जेक्शन, यदि कोई करना चाहे तो, करने का अधिकार है।

इसके अन्दर जो यह १५ दिन का समय रखा गया है यह बहुत ही थोड़ा समय है, क्योंकि इतने थोड़े से समय के अन्दर लोगों को अपना आब्जेक्शन पेश करने में बड़ी दिक्कत होगी। इस के साथ ही साथ इसमें सीट के रिजर्वेशन का बटवारा भी होगा जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, अगर उसमें किसी बात की ज़रूरत पड़ी तो यह १५ दिन का समय बहुत ही थोड़ा है इसलिये मैं समझता हूँ कि एक महीने का समय रख दिया जाय तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं समझता हूँ कि १५ दिन का समय बहुत ही थोड़ा है इसलिये इसको बढ़ा दिया जाय जो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री मोहन लाल गौतम—माननीय अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक सीट के बटवारे का संबंध है वह उसमें बहुत ही साफ कहा गया है और उसी के आधार पर यह रखा गया है अब इसमें हेर फेर की ज़रूरत नहीं है। मैं समझता हूँ कि इसमें देर करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि

ज्यादा देरी करना अच्छा नहीं है। मेरे ख्याल में १५ दिन का समय बहुत काफी है इसलिये समय को बढ़ाने की कोई खास जरूरत नहीं है, इसलिये इस संशोधन को मैं मंजूर नहीं कर सकता हूँ।

श्री प्रभु नारायण सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानता हूँ कि माननीय मंत्री को इनेक्शन के मामले में काफी तनुर्बा है, लेकिन इन सिलसिलों में हम लोगों को जो परेशानियाँ होती हैं उन का भी ध्यान रखना चाहिये। कौंसिल और असेम्बली में तो जल्दी मामूँल हो जाता है वह आकड़े ले सकते हैं। लेकिन म्युनिसिपल बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के लिये यह १५ दिन का समय बहुत ही छोड़ा है, इसलिये इस समय को बढ़ा दिया जाय तो ज्यादा अच्छा होगा।

चेयरमैन—प्रश्न यह है कि प्रस्तावित धारा (11—B) में खंड २ की तीसरी पंक्ति में अंक व शब्द “15 days” के स्थान पर शब्द “one month” रख दिये जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री कुंवर गुरु नारायण (विधान सभा निर्वाचित क्षेत्र)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन कलाज ६ में पेश करना चाहता हूँ :—

In the proposed section 13-D—

Delete the word “or” towards the end of (c) and add the following new paragraph (cc):

“(cc) Provided he relinquishes such place of profit within seven days of the acceptance of his nomination paper and proves to the satisfaction of the Returning Officer that he has done so, the disqualification under (c) shall not apply to him.”

श्रीमान जो नई धारा १३ (डी) है उसके सी में यह लिखा हुआ है ho'lds any place of profit in the gift or disposal of the Board। तो कोई डेफिनिशन नहीं दी गई है कि यह जो प्राफिट है, वह किस किस का प्राफिट होगा और तब वह शरूत डिस्क्वालिफाई किया जायगा। इसका परिणाम ऐसा होता है कि अगर डेफिनिशन दी होती कि कलां कलां किस के प्राफिट अगर होल्ड करता है तो साफ होता लेकिन अगर रिटर्निंग आफिसर के ऊपर ही बिल्कुल छोड़ दिया जाता है तो उसका नतीजा यह होगा कि उसमें अननेसेसरी डिले व लीडिंगेशन होगा। इसलिये यह चीज जरूरी थी कि प्राफिट्स की डेफिनिशन दी होती कि किन किन किस के प्राफिट होंगे जिन से वह डिस्क्वालिफाई हो जाता है तब तो कुछ ठीक था। लेकिन तो प्राफिट्स की कोई डेफिनिशन नहीं दी हुई है और यह चीज बिल्कुल वैग रखी गई है। इसका परिणाम यह होता है कि फिल्मजी ग्राउन्ड पर नामिनेशन पेपर खारिज होंगे और अननेसेसरी वेस्ट आफ एक्सपेंडीचर होगा। इसी उद्देश्य से मैंने यह संशोधन पेश किया है। मैं माननीय मंत्री जी से इतना कहता हूँ कि इससे मेरे संशोधन से इतना ही जायेगा कि ७ दिन पहले हर शरूत को अधिकार होगा कि वह उस जगह से जिनका कि वह प्राफिट होल्ड करता है अपना इस्तीफा दे दे और दु बि सैटिस्फैक्शन आफ रिटर्निंग आफिसर वह इस चीज को साबित कर दे कि ऐसा नहीं है। इसी चीज को दुरुस्त करने के लिये ही यह संशोधन है और उसमें माननीय मंत्री जी को कोई आपत्ति नहीं होगी।

श्री मोहन लाल गौतम—अध्यक्ष महोदय, श्री गुरु नारायण जी ने जिस परेशानी से बचने के लिये यह संशोधन रक्खा है, मेरा ख्याल है कि इससे और ज्यादा परेशानी इस संशोधन में पेश कर दी है। होल्ड्स ऐनी प्लेस आफ प्राफिट के बाद समझ में यह नहीं

[श्री मोहन लाल गौतम]

आया कि रिटर्निंग आफिसर को क्या दिक्कतें उसमें पेश हो सकती हैं और उससे बचने के लिये उन्होंने पूरा अधिकार रिटर्निंग आफिसर को दे दिया है। उसमें उन्होंने यह रक्खा है कि वी सेलैक्शन आफ रिटर्निंग आफिसर डेट हा है ज उन सो। एक ठेकेदार है तो इसके अन्दर यह रूलान कर दिया गया है। उसके पास और कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि वह अलग न ले और अलग लेना मेरे ब्याल से जरूरी नहीं है। वह अपने नाम से भी ठेका ले सकता है और बेनाम से भी ले सकता है जो ठेकेदार मेम्बर हो जाय वह किन्हीं और नाम से ठेका लेता है और अगर उसके पास पैसा है तो उसको परिमिशन भी मिल जाती है कि मेम्बर होने के बावजूद भी वह ठेकेदार हो सकता है। हम ऐसी मिसाल जानते हैं कि वह मेम्बर होने पर भी ठेका करते हैं तो यही सभी चीजें हैं जिनसे वह बचना चाहते हैं। यह जो प्राविजन रक्खा गया है कि होल्ड्स ऐनी प्लेस आफ प्राफिट, तो इसकी आवश्यकता थी और जितने भी इलेक्शन के क्लस हैं उनमें भी यही रक्खा गया है। इसलिये जिस परेशानी से आप बचना चाहते हैं तो आपका जो संशोधन है उससे और भी परेशानियां पैदा हो जायेंगी। इसलिये मैं इसको मंजूर नहीं करता हूं और दरखास्त करता हूं कि मूवर साहब अपने संशोधन को वापस ले लें।

श्री कुंवर गुरु नारायण—माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे तो बड़ा ताज्जुब हुआ यह सुन कर जो कुछ मंत्री महोदय ने कहा क्योंकि मैं समझता था कि कोई बड़ी बात इस संशोधन के विषय के लिये बतलाई जायेगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। मैं समझता था कि ऐसी बात बतलाई जायेगी जिससे कि प्राफिट की डेफिनिशन क्लियर हो जाये और इसके विपरीत माननीय मंत्री ने यह कहा है कि इस संशोधन को मान लेने से तो परेशानी और भी बढ़ जायेगी और उन्होंने इसके लिये त्रिफ एक ठेकेदार का एकजाम्पुल दिया है। इसमें सिर्फ एक ठेकेदार ही की चीज नहीं हो सकती है बल्कि और भी बहुत सी बड़ी चीजें हो सकती हैं। जब तक प्राफिट की डेफिनिशन साफ नहीं होगी। जो बिलकुल बेग है। मेरा संशोधन कहता है कि ७ दिन पहले हर शख्स इस्तीफा देता है रिटर्निंग आफिसर के सामने उसको साबित करता है, तो इसमें बहुत कम स्कोप नामजदगी का पर्जा खारिज होने का रह जाता है और उसको हटाने के लिये बल्कि कोई चान्स नहीं है। अब मान लीजिये कोई प्रेस का प्रोप्राइटर है और कोई लोकल बाडी है और उस प्रेस के प्रोप्राइटर से किसी बोर्ड ने छपाई का काम लिया और पहले से लेते रहे हैं, तो आप उसके लिये उस समय कह सकते हैं जब कि वह म्युनिसिपल इलेक्शन के लिये खड़ा हो, कि यह छपाई का काम करता है, इसलिये यह नहीं खड़ा हो सकता है। तो इसके लिये यदि वह यह साबित कर सकता है कि वह खड़ा हो सकता है, तो एक हफ्ता पहले उसे बोर्ड के काम से हटने का भी उसको इतना मौका मिलना चाहिये। तो वह खड़ा हो सकता है या नहीं, यह चीज साबित होनी चाहिये और मेरा संशोधन स्वीकार नहीं होगा तो यह चीज साबित नहीं होगी। तो इसमें यह चीज साफ होनी चाहिये। अगर ऐसा नहीं होगा तो इससे बहुत परेशानी हो जायेगी। और जो मैंने संशोधन पेश किया है, उससे लोगों को परेशानी नहीं होगी और यह चीज भी साफ हो जायेगी। इसमें प्लेस आफ प्राफिट की डेफिनिशन नहीं है इसलिये मैंने यह उचित समझा कि इस संशोधन को रखूं। पहले आपने यह चाहा था कि हर शख्स रिटर्निंग आफिसर के पास सबूत दे दे कि यह उसका सबूत है और अगर वह उसे मंजूर करे तो उसको माना जाय और अगर नहीं तो इसमें इन्टरप्रिडेशन दूसरे तरह के हो सकते हैं। मान लीजिये कि तीन महीने पहले किसी अन रजिस्टर्ड ठेकेदार ने ठेका ले लिया और इस पर कोई फरीक साबित करता है कि तुम खड़े नहीं हो सकते हो क्योंकि तुमको फिर काम मिलेगा। तो फिर बतलाइये कि क्या होगा अगर माननीय मंत्री जी मेरा यह संशोधन मंजूर नहीं करते हैं तो लोगों के इलेक्शन और नामजदगी या फ़िल्मजी ग्राउन्ड्स पर खारिज होगी। तो यह पता नहीं चलता है कि किस किस्म का प्लेस आफ प्राफिट बिल की धारा में आता है और किस किस्म का नहीं आता है।

चेयरमैन—The question is that—

In proposed section 13-D—

Delete the word “or” towards the end of (c) and add the following new paragraph (cc) :

“(cc) Provided he relinquishes such place of profit within seven days of the acceptance of his nomination paper and proves to the satisfaction of the Returning Officer that he has done so, the disqualification under (c) shall not apply to him.”

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री कुंवर गुरु नारायण—मैं आपकी आज्ञा से खंड ९ में यह संशोधन करना चाहता हूँ:—

Sir, I beg to move tha—

In the proposed section 13-D :

Add the following new paragraph immediately after (f) :

(f) “Is a member of any political organization or a member of any State Legislature or Parliament.”

श्रीमन्, यह जो संशोधन है म्युनिसिपैलिटीज के चुनाव में कान्स्टेबल करने के लिये किसी भी सदस्य को चाहे वह पालियामेंट का हो, स्टेट लेजिस्लेचर का हो या किसी भी पोलिटिकल आर्गनाइजेशन का हो यह संशोधन डिबैर करता है और इसीलिये यह रखा गया है। श्रीमन्, यह जो संशोधन है देखने में ऐसा मालूम होता है कि यह इम्प्रेसिडेंटियल है एबसर्ड है नहीं होना चाहिये लेकिन मैं यह समझता हूँ कि यह होना चाहिये और यह भी सही है कि आज कोई भी मुक्त ऐसा नहीं है जहाँ इन चुनावों में पोलिटिकल पार्टीज को मौका न हो कि वह अपने यहां पार्टीसिपेट न करती हो। लेकिन आज जो हालत में अपने देश की देखता हूँ तो यह ख्याल पैदा होता है कि जब तक स्वतंत्रता संग्राम चलता रहा तब तक तो जिस तरह से काम होता रहा वह ठीक था लेकिन उसके बाद आज ऐसी हालत है कि यह नहीं कहा जा सकता है कि जो सेवा का काम है वह ठीक तरह से हो सकता है। तजुबा यह है और होता यह है कि पोलिटिकल पार्टीज संस्थाओं को कैंचर कर लेती हैं और दलबन्दी पैदा हो जाती है और जो सेवा करने का भाव है वह खत्म हो जाता है और नतीजा यह होता है कि काम सफ़र करता है। मुझे भय है कि कहीं यह संस्थायें जो केवल सेवा के लिये ही हैं वह पोलिटिकल पार्टीज की लड़ाई में अखाड़े बन जायें। इसलिये इस ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ कि कम से कम अधिक समय के लिये नहीं तो जब तक आपके यहां शिक्षा की कमी है और राष्ट्र का चरित्र ऊंचा नहीं हो जाता है यानी ८ या १० साल के लिये इसको मान लीजिये और उसमें राजनैतिक पार्टियों का किसी प्रकार का दखल न हो और अगर आपने दखल देना बन्द न किया तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा।

मैंने इस संशोधन के द्वारा यह प्रार्थना की है कि पालियामेंट, या स्टेट लेजिस्लेचर के मेम्बर्स म्युनिसिपैलिटीज में इलेक्शन सीक न कर सकें। इसका मुख्य कारण यह है कि ज्यादातर मेम्बर्स को फुर्सत नहीं होती कि वह अपने कार्यों की देख-रेख कर सकें। कोई पालियामेंट का मेम्बर है, तीन चार महीने का सेशन होता है, तो होता यह है कि उन्होंने अपने किसी प्रभावशाली व्यक्ति को ज़िले में एलेक्ट करा दिया और उसी के प्रभाव में काम करने के लिये वाइस प्रेसीडेंट करा दिया। अब होता यह है कि प्रेसीडेंट साहब तो बाहर बंटे रहते हैं और उनकी गैरहाजिरी में वाइस प्रेसीडेंट साहब काम करते रहते हैं।

[श्री कुंवर गुरु नारायण]

इस तरह से काम सफ़र करता रहता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम म्युनिसिपल बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेशन को टोन अप करें तो बहुत जरूरी है कि राजनैतिक दलों को इनमें जगह न दें। इसी भावना से प्रेरित हो कर मैंने इस संशोधन को रखा है। मैं जानता हूँ कि आज जो हमारे देश की हालत है, हमारे देश की जो मारेलिटि है वह इतनी ऊँची नहीं है जितनी कि होनी चाहिए। इसलिये अगर हम आठ दस वर्ष तक रुक जायेंगे और इसमें भाग न लेंगे तो हमारी म्युनिसिपैलिटीज भी सुधर जायेंगी और जो आदमी रियल सर्विस करने के उद्देश्य से आते हैं उनको मौका मिलेगा कि वह इन जगहों पर पहुंच सकें।

मैं आशा करता हूँ कि माननीय मंत्री इस पर विचार करेंगे।

श्री प्रताप चन्द्र आजाद—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मेम्बर ने जो संशोधन रखा है, मुझे उसको पढ़ कर बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं यह समझता हूँ कि आज के संसार में शायद कोई भी कांसस और पढ़ा लिखा आदमी ऐसा न मिलेगा जो किसी न किसी पार्टी का मेम्बर न हो। खुद संशोधन रखने वाले जो माननीय मेम्बर हैं वह भी किसी न किसी पार्टी के मेम्बर हैं। अगर यह शर्त हम लगा दें तो मेरा ख्याल है कि हिन्दुस्तान में तो म्युनिसिपल बोर्ड की मेम्बरशिप के लिए चुनाव लड़ने के लिए हमको कोई आदमी न मिलेगा। हमको हिन्दुस्तान के बाहर से या और कहीं से आदमी लाने पड़ेंगे। इसके अलावा जो कुंवर साहब ने कहा कि पार्लियामेंट या किसी लेजिस्लेचर के मेम्बर को भी म्युनिसिपैलिटीज के इलेक्शन में खड़े होने न देना चाहिए। मैं समझता हूँ कि यह डिस्क्वालिफिकेशन एक नई चीज होगी। बहुत सी डिस्क्वालिफिकेशन्स तो इसमें हैं ही जैसे पनिश्मन्ट मिला हो या पुलिस कस्टडी में हो लेकिन यह नई डिस्क्वालिफिकेशन लगाई जाये तो मैं समझता हूँ कि यह बिल्कुल अजीब सी बात होगी। इसे नहीं होना चाहिये। अगर किसी जगह की जनता किसी कौंसिल या पार्लियामेंट के मेम्बर को म्युनिसिपैलिटी के लिए खड़ा करना चाहती है तो मैं समझता हूँ कि उनके ऊपर कोई बैरियर नहीं होना चाहिये। अब रही समय की बात, कुंवर साहब ने कहा कि समय उन्हें नहीं मिलता तो यह तो ऐसी बात है कि जो आदमी हरदिल अजीज होते हैं वह अगर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मेम्बर थे और कौंसिल के भी हो गए तो वह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से रिज़ाइन करवाये यह हो सकता है कि मेम्बर होने के बाद अगर कोई समझे कि उन्हें दो जगह पर काम करने के लिये समय नहीं मिलता है तो उसमें से एक जगह से रिज़ाइन कर दें। लेकिन जो हमारे कुंवर साहब न फ़रमाया है वह एक अजीब सी बात है और अनुचित बात है।

चेयरमैन—सदन की बैठक दो बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

[सदन की बैठक १ वज कर २ मिनट पर स्थगित हो गई और २ बजे डिप्टी चेयरमैन (श्री निज़ामुद्दीन) के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।]

श्री प्रभु नारायण सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन कुंवर गुरु नारायण ने डिस्क्वालिफिकेशन्स के सम्बन्ध में रखा है उस संशोधन को देखने से ऐसा मालूम होता है कि शायद उनकी यह मंशा है कि समाज की रचना वही कर सकता है जो किसी सामाजिक दर्शन को नहीं मानता है या उनके पास कोई सामाजिक दृष्टिकोण नहीं है। हम ऐसा महसूस करते हैं कि यह संशोधन कुंवर गुरु नारायण ने इस परेशानी में रखा है कि कांग्रेस में वह शामिल नहीं होना चाहते, सोशलिस्ट पार्टी से उनकी कुछ घबराहट है और ऐसी हालत में जो पुरानी पार्टी है वह म्युनिसिपैलिटी बोर्ड पर कब्ज़ा नहीं कर सकती है तो इन्हीं सब बातों को देखते हुये शायद उन्होंने यह संशोधन रखा है। ऐसी हालत में कुछ ऐसा मालूम होता है कि जो संशोधन इस समय आया वह बिना इस बात को ख्याल किये हुये

आया कि उनके जो पुराने तजुबे रहे हैं, उन्होंने म्युनिसिपल बोर्ड्स और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स में क्या क्या ग़ज़ब डरे, उसकी एक लम्बी कहानी है जिसकी मैं इस वक़्त नहीं कहना चाहता हूँ, किस तरह से म्युनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन चुने जाते थे, किस तरह से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन चुने जाते थे, किस तरह से पैसे खर्च किया जाता था। इन सब बातों का ज़िन्ना बहाल किये हुए हैं उन्होंने यह संशोधन रखा है। अगर यह सवाल ले ही लिया जाय कि जो व्यक्ति किसी पोलिटिकल पार्टी का मेम्बर हो वह न जाय तो मैं पूछता हूँ कि क्या फिर इस तरह के बोर्ड्स बहुत अच्छे बोर्ड्स हो जायंगे। हम तो ऐसा महसूस करते हैं कि अब मुल्क के अन्दर एक ऐसी हालत पैदा हो गई है कि जिसमें लोकतन्त्रात्मक व्यवस्था के अन्दर पोलिटिकल पार्टीज जो किसी कार्यक्रम में विश्वास रखती ह, ऐसे कार्यों को अपने हाथ में लें जिसमें वह अधिक से अधिक अच्छी तरह से ड्राइव कर सकें। कुंवर गुरुनारायण जी ने यह बली बही है कि दुनिया के मुल्कों में ऐसी बात नहीं है कि पोलिटिकल पार्टीज हिस्सा न लें लेकिन हमारे मुल्क में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि पोलिटिकल पार्टीज हिस्सा लें। यह दूसरी बात है कि पोलिटिकल पार्टीज से यह कहा जाय कि जो यह कहते हैं उसको पूरा करें इन्डोविजुवल्स के लिये यह सवाल उठता है कि चार वर्ष के लिये चुने गये और मुमकिन है सेकेंड टाइम से वह जाय या न जाय लेकिन अगर कोई पोलिटिकल पार्टी आती है तो उसके सिलसिले में यह होता चाहिये कि चार साल के लिये जो कार्यक्रम दिया उसको पूरा करें। चार साल के बाद उनकी यह कहना पड़ता है कि क्या क्या काम उन्होंने किया। अगर उन्होंने कुछ गड़गड़ी की तो फिर उन्हें चुने जाने का अधिकार नहीं है। आज ऐसी बात मालूम पड़ती है कि यदि आज की हालत में कुछ रद्दोबद्द हो और आने वाले मुल्क में दो बड़ी पार्टीज के रूप में पोलिटिकल डेमोक्रेसी देश की होगी ऐसी हालत में यह सवाल सीधा है कि जो कार्यक्रम बतलाये जायंगे उन सबकों को बहुत दिनों तक टाला नहीं जा सकता है। उसमें अवसरवादिता की गुंजाइश नहीं है। इस सन्ने में जो यह बात कही गई कि यदि कोई व्यक्ति पोलिटिकल पार्टीज का मेम्बर है तो वह म्युनिसिपल बोर्ड के लिये डिसक्वालीफ़ाईड है। प्रेसिडेंटशिप के लिये डिसक्वालीफ़ाईड है। साथ ही साथ यह बात कही गई कि असेम्बली और पार्लियामेंट के मेम्बरों को म्युनिसिपल बोर्ड के चुनाव के लिये नहीं खड़ा होना चाहिये तो इसके लिये मैं समझता हूँ कि हर एक पोलिटिकल पार्टी इस बात का ध्यान रखती है कि वह उस आदमी को जो इस प्रकार असेम्बली का मेम्बर होता है उसको म्युनिसिपल बोर्ड के लिये नहीं खड़ा किया जाता है जब तक कि उस व्यक्ति की सेवाओं की कोई खास आवश्यकता नहीं पड़ती है, और अगर इस मान में वह व्यक्ति खड़ा किया जाता है तो वह चुन कर आ जान पर म्युनिसिपल बोर्ड के लिये अच्छा ही साबित होता है। वह उसके स्तर को अपने अनुभवों से ऊंचा ही उठाने की कोशिश करता है। मैं समझता हूँ कि जो संशोधन कुंवर गुरुनारायण जी ने रक्खा है वह धिक्कुल मौजू नहीं है। और इसको बिल्कुल रिजेक्ट कर देना चाहिये। आज के युग में इस बात को सोचना भी मेरी समझ में ठीक नहीं है।

श्री राजा राम शास्त्री—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्री गुरु नारायण जी ने जो अस्ताव रक्खा है सबकुछ मैं उसको ठीक तरीके से समझ नहीं सका। मैं भी बहुत कुछ प्रभु नारायण जी की बात से सहमत हूँ। आज प्रभु नारायण इस बात को इसलिये रख रहे हैं, क्योंकि वह महसूस करते हैं कि जिस विचारधारा के आधार पर उन्होंने यह कहा है कि कोई राजनैतिक पार्टी इसमें हिस्सा न ले यह असंभव है। जिन लोगों ने खुद पार्टियां बनाई कई बार चुनाव लड़े अभी तक असेम्बली के मेम्बर बने रहे और वहां भी पार्टियां बनाये रहे, वही आज इसलिये यह कहें क्योंकि आज वह अकेले हैं यह ग़लत है। अगर आज वह एक ही की जगह पर दस होते तो ऐसा न कहते। राजनैतिक विचार के लोग अपने सिद्धान्त पर लड़ते हैं। आज अगर हम हार जाते हैं तो

[श्री राजाराम शास्त्री]

इसके माने यह नहीं है कि हम हिम्मत हार कर ऐसे प्रभाव लाना शुरू कर दें कि कोई पोलिटिकल पार्टी म्युनिसिपल चुनाव में हिस्सा ही न ले। अगर आज हम हार जाते हैं तो हमें फिर से अपने सिद्धान्तों के वास्ते लड़ना चाहिये। क्योंकि उसमें हम जनता का हित समझते हैं। हो सकता है कि कोई जमाना ऐसा आये कि जब ऐसा राज्य स्थापित किया जा सके जब कि किसी पार्टी का राज्य न हो लेकिन आज कल के डेमोक्रेसी के युग में सिवाय इसके कोई चारा नहीं है कि बिना किसी राजनैतिक पार्टी के काम किया जा सके। हाँ, यह हो सकता है कि किसी राजनैतिक पार्टी में कोई खराबी हो और उसका कार्यक्रम अच्छा न हो तो हम उससे कहें कि तुम्हारा कार्य देश की भलाई के लिये नहीं हो रहा है। यह बात तो हम कह सकते हैं। लेकिन एक राजनीतिक व्यक्ति स्वायत्त शासन में हिस्सा न ले यह चीज बिल्कुल गलत है। सचमुच में कुंवर साहब ने इस संशोधन का नम्बर एफ या जी रखा होता तो जैसा उसका नाम है वैसा कन्टेन्ड ठीक नहीं है। मैं सदन से कहना चाहता हूँ कि यदि वह संशोधन मान लिया जाय तो जो आजकल डेमोक्रेसी का आधार है वह बिल्कुल टूट जाता है। मैं यह मानता हूँ कि वास्तव में जो राजनैतिक पार्टियों की वर्किंग है उससे हमको बहुत निराशा होती है चाहे कांग्रेस पार्टी हो या सोशलिस्ट पार्टी हो। जब मेरे दिल में यह ख्याल होता है कि प्रत्येक चीज को पार्टी निगाह से सोचने लगते हैं चाहे सत्य बात कही गई हो तो इस प्रकार की कमी जरूर है। हमारी पार्टी राइट और दूसरा रोंग की जो भावना है वह बिल्कुल गलत है। यदि दूसरी पार्टी के विचार कितने ही अच्छे क्यों न हों लेकिन वह खराब हैं और अपनी पार्टी के विचार चाहे कितने ही खराब हों परन्तु बेठीक हैं। यह भावना बहुत ही खराब है। जब हम किसी पार्टी के वर्किंग को देखते हैं कि कितना वह समाज में काम करते हैं तो एक बात की अवश्य निराशा होती है। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि चूंकि हमारा देश अभी आजाद हुआ है और चूंकि सदियों से हम गुलाम रहे इसलिये हमारा राजनैतिक चरित्र गिर चुका है। हमें इसकी शिक्षा नहीं मिलती है और शिक्षा के ही रूप में सदाचार बढ़ता जाता है।

माननीय उपाध्यक्ष जी, जैसी सरकार होती है वैसा ही जनता का मारेल होता है लेकिन जैसी जनता होती है वैसी ही सरकार मिली है। आज यह कहना कि सरकार असमान से टपक पड़ी है यह ग़ज़त बात है। हम जिस समाज से निकलें उस समाज में केवल किसी व्यक्ति को दोष देने से काम नहीं चलेगा। हमारे समाज में जो आज जनता की विचारधारा है उससे ही प्रभावित हो कर वह चलती है। इसलिये मेरे दिल में यकीन हो गया है कि एक तरफ लगातार कोशिश करते हैं कि हुकूमत गलत काम न करे और सही तरीके अख्तियार करे क्योंकि यह उसका उत्तरदायित्व है कि वह जनता को सही चलाये लेकिन साथ ही साथ जनता का भी आचरण ठीक नहीं है। इसको राजनैतिक शिक्षित नहीं कहा जाता। वे डेमोक्रेसी की भावना से श्रोतप्रोत नहीं होंगे जब तक आप और हम जो आज हुकूमत का स्वरूप है उसको न बदल दें। स्वशासन ही ऐसी जगह है जिससे जनता शिक्षित होगी। एडमिनिस्ट्रेशन करने का एक तरीका वहां पर आता है। हमारा ख्याल है कि देहातों में जो ग्राम पंचायतें, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स और म्युनिसिपल बोर्ड्स हैं यदि इनकी आधार शिला मजबूत होगी तभी तो लखनऊ और दिल्ली की हुकूमत की शक्ति मिल सकती है। अगर ये कमजोर रहे तो ऊपर की हुकूमत सही ढंग से नहीं चल सकती। तो मैं वास्तव में स्वायत्त शासन को बहुत महत्व देता हूँ। मैं समझता हूँ कि अच्छे से अच्छा आदमी इसमें जाये। मैं महसूस करता हूँ कि आज कल राजनैतिक पार्टियों में जो लड़ाई है उससे समाज में कितने ही ऐसे व्यक्ति हैं जो राजनीति से दूर हटते जा रहे हैं। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जो लोग स्वतंत्र खड़े होते हैं अगर वह हुकूमत को मजबूत करना चाहते हैं और देश का नक्शा बदलना चाहते हैं तो मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति को चुन लेना चाहिये कि उसको किस राजनैतिक पार्टी में जाना है। ऐसे लोगों का कोई भी स्थान नहीं है जो किसी भी पार्टी से संबंध

नहीं रखते हैं। मैं साफ साफ कह देना चाहता हूँ कि ऐसे लोग बहुत खतरनाक होते हैं जो न कांग्रेस में हैं और न सोशलिस्ट में हैं और न हिन्दूमहासभा ही में हैं। वह लोग एक लुढ़कते हुए ढेले की तरह से हैं। ऐसी सूरत में मैं समझता हूँ कि राजनैतिक पार्टी चाहें श्रमजो या वही हो, एक पार्टी में रहना चाहिए। मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि लोकल बाडीज का मेम्बर असेम्बली और पार्लियामेंट का मेम्बर नहीं हो सकता है। जहाँ तक खराबियों का सवाल है वह राजनैतिक पार्टी में भी रह कर दूर की जा सकता है लेकिन सारी व्यवस्था को बदल देने के ख्याल को मैं ठीक नहीं समझता हूँ। मुझे कुंवर साहब से पूरी हमदर्दी है लेकिन मैं उनके इस संशोधन को ठीक नहीं समझता हूँ। मैं तो समझता हूँ कि अगर वह हिन्दुस्तान महासभा में ही रहते तो ज्यादा अच्छा होता। यह तो आरफन की तरह से मनोवृत्ति है। मेरे ख्याल में यह संशोधन ठीक नहीं है इसलिये इसका मान लेना ठीक नहीं है।

*श्री बन्नी प्रसाद कक्कड़ (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र) — जनाब डिप्टी चेरमन साहब, जो असेम्बलेंट इस वक्त कुंवर साहब ने पेश किया है उसके तीन मकसद हैं। एक तो पोलिटिकल आर्गनाइजेशन की मुखालिफत, दूसरे यह कि स्टेट या पार्लियामेंट का मेम्बर म्युनिसिपैलिटीज का मेम्बर नहीं हो सकता है। मुमकिन था कि मैं उनके इन दोनों ख्यालाओं की तारीफ करता लेकिन मैं पोलिटिकल आर्गनाइजेशन की मुखालिफत को नहीं मानता हूँ। यही एक आजादी का मकसद है और चिह्न है। पोलिटिकल आर्गनाइजेशन ही पोलिटिकल पार्टी की प्रीय है। अगर एक शहस इन्डिपेंडेंट अंग से म्युनिसिपैलिटीज में आता है तो उसकी कोई स्कीम नहीं होनी है और न अपना उसका कोई इरादा ही होता है।

लिहाजा इंडिपेंडेंट के लिये ऐसी कोई भी जगह नहीं होनी चाहिये और यह बड़े बुरा की बात है कि आपका पोलिटिकल आर्गनाइजेशन से इस कदर इखतलाफ है। आप भी ईश्वर चाहेगा तो जल्द ही किसी पोलिटिकल आर्गनाइजेशन में तशरीफ ले जायेंगे और तब खुद साबित कर देंगे कि नहीं अगर कोई इस प्रकार की संस्था होनी चाहिये तो वह पोलिटिकल आर्गनाइजेशन ही है जो म्युनिसिपल, स्टेट और पार्लियामेंट में काम कर सकते हैं। इन शब्दों के साथ मैं इस असेम्बलेंट की मुखालिफत करता हूँ।

श्री मोहन लाल गौतम — उपाध्यक्ष जी, मुझसे पहले बोलने वाले वक्ताओं ने मेरा काम बहुत ही हल्का कर दिया है। जो संशोधन पेश किया गया है उसमें लक्ष्य पोलिटिकल आर्गनाइजेशन है और अगर पोलिटिकल आर्गनाइजेशन में पोलिटिकल पार्टीज भी मिश्रित हैं तो यह भी सोचने की बात है कि वह म्युनिसिपल बोर्ड का मेम्बर कैसे हो सकता है क्योंकि वह भी पोलिटिकल आर्गनाइजेशन है और इस तरह से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और तमाम इस तरह की चीजें पोलिटिकल आर्गनाइजेशन हैं तो अगर यह सब पोलिटिकल आर्गनाइजेशन हैं तो फिर कुंवर साहब की क्या मंशा है। मुझसे पहले बोलने वाले हैं उन्होंने सल्लियत के लिये यह माने लगा दिये कि यह पोलिटिकल पार्टीज का मतलब है। अब अगर उनका मंशा पोलिटिकल आर्गनाइजेशन से है तब तो वह बहुत ही एबसर्ड बात कहते हैं। क्योंकि जब वह मेम्बर हो जायेगा तब भी वह पोलिटिकल आर्गनाइजेशन में आ जाता है। तो यह पोलिटिकल आर्गनाइजेशन का सवाल बड़ा टेढ़ा सा हो जायगा। जहाँ तक पोलिटिकल पार्टीज का मतलब है तो पहले बोलने वाले सभी सदस्यों ने साफ कर दिया है कि वह लोग जिनको कोई विचार-धारा नहीं है जिनका कोई सामाजिक स्तर नहीं है जिनको इसका पता नहीं है कि समाज में कैसे रहें, अच्छा हो या बुरा हो, वह उसमें आसानी पैदा करने के लिये कुछ कर सकता है तब इस तरह से सोचते हुए उनको बहुत हद तक पोलिटिकल पार्टीज में होना पड़ता है। अगर

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री मोहन लाल गौतम]

ऐसा हो भी कि कोई व्यक्ति अच्छा हो और पोलिटिकल पार्टी में न हो और इन तमाम बातों पर विचार भी करता हो तथा जो समाज में सुधार करना चाहता हो और वह इन्डोविजुअल होते हुये किसी भी पोलिटिकल पार्टी में न हो, लेकिन समाज में प्रगति तेजी से लाने के लिये वह दो चार आदमियों को अपने साथ ले लेता है क्योंकि इस तरह के कामों में प्रगति लाने के लिये इन्स्ट्रुमेंट्स की बड़ी आवश्यकता होती है और वह व्यक्तित्व के रूप में उसे प्राप्त होती है तो वही पोलिटिकल पार्टी का रूप धारण कर लेती है। अगर कोई ऐसा हो कि उसकी विचार धारा हो, और समाज का उस पर विश्वास हो तो उसे कुछ लोगों को लेकर काम करने की ज़रूरत पड़ती है और वही पोलिटिकल पार्टी बन जायेगी ऐसे लोग जो किसी पोलिटिकल पार्टी में न हों तो उनमें बहुत थोड़े ऐसे होते हैं जो कि बहुत ऊँचे दर्जे के हों, बहुत माकूल हों, उनकी विचारधारा अच्छी हो और उनकी धारणा भी अच्छी हो, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस तरह के बहुत कम लोग होंगे जो कि म्युनिसिपल इलेक्शन में काम करना चाहते हों। इसलिये उनका ध्यान पर कोई भी सवाल पैदा नहीं होता है। अब रह जाती है उन लोगों की बात जिनकी विचार धारा ही नहीं है, जिनका कोई संगठन नहीं है ऐसे लोगों के हाथ में लोकल बाडीज का इन्तज़ाम दिया जाय, ऐसा संशोधन के प्रस्तावक महोदय का ख्याल है। अब अगर वह इसकी रूपरेखा को अच्छी तरह से विचार करेंगे तो खुद ही इस नतीजे पर पहुँचेंगे कि उनका सवाल गलत है और वह खुद इससे सहमत नहीं होंगे। जो बिना पढ़े लिखे लोग हैं वही पार्टी और पार्टी बाजी का सवाल पैदा करते हैं और वह इस तरह की दलील दे सकते हैं। लेकिन पार्टी एक ऐसी चीज़ है कि जो कोई भी पार्टी में आयेगा वह सब कर्बानियां कर सकता है और तभी वह ऊँचे आदर्श से रह सकता है। अगर हम सिर्फ पोलिटिकल पार्टियों की कुछ खराबियों को देख कर ही इस नतीजे पर पहुँचते हैं तो यह गलत चीज़ है। बाकई पोलिटिकल पार्टी तो उन लोगों की देन है जिन्होंने कर्बानियां की हैं और जिन्होंने ऊँचे आदर्श समाज के अन्दर पैदा किये हैं। इसलिये बहुत से लोगों के लिये यही धर्म है क्योंकि जो समाज में एक परिवर्तन लाना चाहते हैं उन्होंने पार्टीज के रूप में धर्म ग्रहण कर रखा है या उनकी पोलिटिकल पार्टीज ने धर्म का रूप ग्रहण कर रखा है और उनका सबसे बड़ा धर्म यही है तो ऐसे लोगों को अलग करना कहां तक मुनासिब है यह सोचने की बात है और मैं इस से सहमत भी नहीं हूँ। इसके साथ ही एक प्रैक्टिकल सवाल भी आता है कि जो आज डेमोक्रेसी का रूप है और जो हमारी डेमोक्रेसी है, उसमें बगर मेजारिटो के कोई इस तरह का काम नहीं हो सकता है फिर चाहे वह म्युनिसिपैलिटी का हो या किसी और का हो। तो इसमें इन्डोविजुअल कुछ नहीं कर सकता है और चेयरमैन को भी इसमें बहुत सी दिक्कतें पैदा हो सकती हैं और उसकी समझ में यह नहीं आता है कि कितने उसके पक्ष में हैं और कितने विपक्ष में होंगे। तो अगर इन्डोविजुअल होंगे तो वह पहले से किसी बात को तय नहीं कर सकता है कि वह भी चेयरमैन के साथ किसी बात में होगा या नहीं। अगर यह बात हो जाय तो क्या कोई भी चेयरमैन म्युनिसिपल बोर्ड का चेयरमैन इस तरह से चल सकेगा। जैसे नमूने के तौर पर फ्रांस की मिसाल हमारे सामने आती है। वहां भी वस, बारह ऐसी पार्टीज हो जाती हैं और इस तरह से म्युनिसिपैलिटीज रोख बनती रहती हैं और बिगड़ती रहती हैं। तो कुंवर साहब इस बात को समझ गये होंगे कि अगर वह इन्डोविजुअल रहता है, तो इस तरह से म्युनिसिपैलिटीज चलेंगी कैसे। मैं यह मान सकता हूँ कि अगर उसमें बहुत पार्टीज न हों और उसमें सिर्फ कांग्रेस होती और सोशलिस्ट पार्टी होती तो, हम सबकी यही राय होगी कि उनकी जैसी हालत आज है उससे कहीं अच्छी हालत होती। तो इस तरह से पोलिटिकल पार्टीज का बिल्कुल अलग हो जाना और इन्डोविजुअल का रहना यह बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है और मैं समझता हूँ कि जिस तरह से यह अमैंडमेंट उसको मानने के बाद क्या अवस्था हो सकती है, और इन सब बातों को समझते हुये मैं आशा करता हूँ कि श्री कुंवर गुरु नारायण जो इस बात को समझ जायेंगे और अपने संशोधन को वापस ले लेंगे।

श्री कुंवर गुरु नारायण—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन मैंने अपना रखा था उस पर जो वाद विवाद हुआ, उससे मैं ऐसा समझता कि मेरी मन्शा इससे कुछ और है और मेरे माननीय सदस्यों ने इस पर कुछ और ही बहस की। क्या मेरी बात थी और उन्होंने किस तरह से अपने वायुमंडल दिए हैं। मैंने जिस वक्त संशोधन उपस्थित किया था उस वक्त मैंने साफ कहा था कि चाहे कोई भी शक हो, मगर जो यह कहता है कि पोलिटिकल पार्टीज का ग्रोथ न हो या उनका डेवलपमेंट न किया जाय, तो इस सब उसके विचार हैं। तो यह मैंने नहीं कहा था लेकिन मैंने इतना कहा था कि जब तक हमारे देश की स्थिति जब तक हमारे देश की विचार वारा इतनी नहीं उठ जाती है कि हम निर्णय लेकर एही बात को समझ सकें, तब तक हमको इस चीज पर विचार करना चाहिये। अब एही सिद्धांत की बात कि वह क्या हो। तो मैं कहता हूं कि पोलिटिकल पार्टीज के बराबर सिद्धांत है आज सोशलिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी के सिद्धांत में और उनके प्रिन्सिपल्स में कोई खास भेद नहीं है, तो फिर वह अलग अलग क्यों हैं। बहरहाल जब यह बात है तो हमें भी देखना है कि अपने देश को आज वस्तु-स्थिति क्या है। मैं यह बात श्री राजा राम जोसे ही जानना चाहता कि उनकी पार्टी के सिद्धांत और कांग्रेस पार्टी के सिद्धांत में क्या अन्तर है और वह क्यों आज अपनी एक अलग पार्टी बनाये हुये बैठे हैं। लेकिन सच बात यह है कि आज भारत में केवल मुख्य दो सिद्धांत हैं यानी समाज-वाद व साम्यवाद तो मैं उपाध्यक्ष महोदय, कहता हूं कि अब चुन के अन्दर देखना दो पार्टीज होगी और उनमें से एक कम्युनिस्ट पार्टी होगी और दूसरी बात कम्युनिस्ट पार्टी होगी और आज जो यह छोटी २ पार्टीज हैं जैसे कि जनसंघ, प्रजा पार्टी इत्यादि तो ये सब कहीं की भी नहीं रहेंगी और या तो ये कांग्रेस में मिल जायेंगे और या किसी दूसरे सिद्धांत के हो जायेंगे यानी कम्युनिस्ट। जब वह दृष्टिकोण होगा और जब हमारे सामने ऐसी परिस्थिति आयेंगी, तब देखना है कि क्या नतीजा होगा। आज सोशलिस्ट और कांग्रेस के एक ही सिद्धांत हैं फिर भी वे एक दूसरे से अलग २ हैं और आपस में लड़ते रहते हैं। तो आज जो वायुमंडल हमारे देश में है और जो डेमोक्रेसी का प्रचार चल रहा है तो पार्टियां आज सिर्फ यह चाहती हैं कि जो कुत्तियां हैं वे किसी तरह से सलामत रहें और सबका सिद्धांत है और वही ध्येय है। हर पार्टी का युद्ध होता है और नतीजा यह होता है कि जो जवता को सेवा होनी चाहिये नहीं हो पाती आफ्रिस के लिये लोग हर जगह लड़ते हैं। जब तक पोलिटिकल पार्टीज का स्तर ऊंचा न हो जाय तब तक उनको इन चुनावों में न जाने देना चाहिये आप इस चीज को थोड़े दिनों के लिये ही मान लीजिय मेरे कहने का मतलब यह है कि गांधी जी ने जैसे कहा था कि अब स्वतंत्रता संग्राम के बाद कांग्रेस को खत्म हो जाना चाहिये और कांग्रेस को पार्टी के रूप में नहीं रखना चाहिये तो उसके माने यह नहीं कि अब एलेक्शन नहीं हो सकते और कोई खड़ा नहीं हो सकता और कोई दूसरा तरीका नहीं निकल सकता। मैं तो यह कहता हूं और जो संशोधन मैंने रखा है उसका मंशा है कि जो राजनैतिक पार्टीज हैं वह अपने-अपने सिद्धांतों से कोसों दूर हो गई हैं केवल एक सिद्धांत रह गया है कि कैसे आफ्रिस मिले और पावर की जगहों पर बैठा जाय, इसलिये मैं चाहता हूं कि कम से कम ऐसी संस्थाओं में जहां सेवा करने का मौका होता है इन दलों को इन जगहों से अलग रखा जाय और इन संस्थाओं को लड़ाई का अखाड़ा न बनाया जाय तो ज्यादा बेहतर होगा। कुछ लोगों ने मेरे ऊपर भी कटाक्ष किया मैं तो कहना चाहता हूं कि मुझे तो कोई ब्रस्टेशन है नहीं आप लोगों को हो सकता है मैं तो इनडिपेन्डेंट हूं और मुझे कांसिल के चुनाव में भी कांग्रेस का सहयोग प्राप्त हुआ और आप लोगों की भी मदद मुझको मिली लेकिन इस वक्त यह प्रश्न तो है नहीं। प्रश्न तो इस समय यह है कि म्युनिसिपैलिटीज का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको जो टीन गिर रही है उसका मुख्य कारण यह है कि आज उसमें दलबंदी हो गई है इसीलिये मैं चाहता हूं कि इसको इन पोलिटिकल पार्टीज से अलग रखा जाय। अब रहा यह जो कहा गया कि मेम्बर्स जो पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर्स के हैं वह नहीं हो सकते, मुझे

[श्री कुंवर गुरु नारायण]

मालूम नहीं लेकिन मेरा ख्याल यह है कि कांग्रेस का एक सर्कुलर निकला है कि जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के प्रेसीडेंट हैं उनको हटना पड़ेगा। अपने स्थानों से या तो वह बोर्डों में रहे या लेजिस्लेचर्स में रहे। मैंने तो इसका अर्थ यह लगाया कि या तो आफिसर्स का बटवारा चाहते हैं या यह अर्थ है कि दोनों जगह सेवा कार्य नहीं हो सकता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि यह आदेश कांग्रेस का आफिस के बटवारे की वजह से नहीं हुआ है।

श्री मोहनलाल गौतम—सरकार ने नहीं किया है।

श्री कुंवर गुरु नारायण—सरकार ने नहीं किया है तो किसने किया है कांग्रेस की ही तो सरकार है। बहरहाल कान्सटीट्यूशन में तो इस तरह का प्रतिबन्ध है नहीं। लेकिन जहां तक मेरा इम्प्रेशन है वह यह है कि जो पार्लियामेंट के मेम्बर हैं या लेजिस्लेचर के मेम्बर हैं वह प्रेसीडेंट लोकल बाडीज के नहीं रह सकते हैं।

एक सदस्य—पार्टी का सर्वयूलर है।

पार्टी को प्रयत्न करते हैं। पार्टी की हुकूमत से प्रथम यह कैसे हो सकता है। मैं उसको प्रयत्न नहीं कर सकता हूँ। उनका ख्याल था कि मेम्बर रहते हुये ठीक तरह से सेवा नहीं कर सकते हैं। इसलिये जिस स्ट्रिप में मैंने यह संशोधन रखा है उसको गलत समझा गया मैंने यह कभी नहीं कहा कि इसको परमानेंटली किया जाय। अब रहा यह कि डेमोक्रेसी के अन्दर पोलिटिकल पार्टीज की प्रथ न हो तो मैं कहना चाहता हूँ कि डेमोक्रेसी के अन्दर बहुत से काम हो रहे हैं जिनको न होना चाहिये था। जैसे विलेज को पावर्स देने का सवाल है विलेज पंचायत बनाई गई और लैन्ड मैनेजमेंट कमेटी बनाई गई और उसके साथ-साथ सारे का सारा कंट्रोल ग्राम संस्थाओं से लेकर एक आफिसर्स को दे दिया जो कि सरकार का कर्मचारी होगा और लैन्ड मैनेजमेंट कमेटी का उत्तरदायीत्व उसके प्रति होगा न कि गांव सभा के प्रति (डेमोक्रेसी में तो यह भी शोभा नहीं देता) इस तरह की बहुत सी चीजें डेमोक्रेसी में होती रहती हैं जो कि शोभा नहीं देती। मैंने जो यह संशोधन रखा है वह सुझाव के रूप में रखा है कि अगर आप म्युनिसिपल बोर्ड्स को असली सेवा करने की बाडीज बनाना चाहते हैं तो इनको कुछ समय के लिये पार्टीज का अखाड़ा बनने से बचाइये। इसके बाद एक अर्मेडिंग बिल लाकर जब जनता में काफ़ी चरित्र आजाये और आप की पोलिटिकल पार्टीज में राइट टाइप आफ़ मोरेलिटी पैदा हो जाये तब आप इसको बदल सकते हैं। जो कुछ समझा गया, जो मैंने कहा था उसके लिये मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि समझ तो अपनी-अपनी होती है। श्री राजाराम जी ने अपनी तरह से समझा, आपने अपनी तरह से समझा लेकिन मैं यह ज़रूर कहूंगा कि अगर आपने म्युनिसिपैलिटीज को पार्टियों का अखाड़ा बनने दिया तो एडमिनिस्ट्रेशन संभल नहीं सकता।

श्री मोहन लाल गौतम—मुझे इसमें कोई खास बात नहीं कहना है। बस इतना ही मैं प्रस्तावक महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ कि यह समझना कि पोलिटिकल पार्टीज नहीं होंगी तो ऐसे इंडिविजुअल आ जायेंगे जो कि बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन चला सकेंगे। यह बहुत ग़लत आधार है। यह समझना कि पोलिटिकल पार्टीज हमेशा ग़लत काम करेंगी, उनको कोई जवाब नहीं देना है जनता के सामने और इंडिविजुअल्स बहुत जवाब देही के साथ काम करेंगे ग़लत होगा। पोलिटिकल पार्टीज के सामने एक फ्यूचर होता है उनको जनता के सामने जवाब देना पड़ेगा। कोई भी पोलिटिकल पार्टी यह नहीं समझ सकती कि चार साल के बाद हम खत्म हो जायेंगे, वह यह समझते हैं कि हमको चार साल के बाद फिर जनता के सामने आना पड़ेगा और जवाब देना होगा। लेकिन इंडिविजुअल्स के सामने कोई ऐसा प्रश्न नहीं है। वह

तो यही समझेंगे कि हम चार साल के लिये यहां आये हैं या उसके बाद क्या होगा यह कौन जानता है रहेंगे या जायेंगे ।

डिप्टी चैयरमैन—The question is that in the proposed section 13-D.

Add the following new paragraph immediately after (f) :

(ff) "is a member of any political organisation or a member of any State Legislature or Parliament"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री प्रताप चन्द्र आजाद—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन प्रस्तावित धारा (१३ D) के पार्ट (g) में शब्द 'हिन्दी' के बाद के सब शब्द निकाल दिये जायें । मैं चाहता हूँ कि यह क्लॉज सिर्फ इतना बना रहे "अनएबल टु रीड एन्ड राइट हिन्दी" इसका कारण यह है कि बाकी शब्दों को मैं सुपरप्लस समझता हूँ ।

हमारे स्टेट का जहां तक संबंध है वहां अब कोई दूसरी रिज्जल लैंग्वेज नहीं है । हिन्द लैंग्वेज आज हमारे स्टेट की भाषा है इसलिये मैं यह समझता हूँ कि हिन्दी के बाद जो शब्द लिखे गये हैं उनको निकाल दिया जाय । इसमें कोई ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है । मुझे आशा है कि माननीय मंत्री महोदय मेरे इस संशोधन को मान लेंगे ।

श्री मोहन लाल गौतम—मैं इस संशोधन को मानता हूँ कि इसमें हिन्दी के बाद के तमाम शब्द निकाल दिये जायें ।

श्री गोविन्द सहाय—अगर उसमें से कोई हिन्दी जानता है और अंग्रेजी पढ़ सकता है तो उसके बारे में क्या हो सकता है ?

श्री मोहन लाल गौतम—ऐसा कोई-कोई होगा । उसमें हिन्दी आप की रिज्जल लैंग्वेज है ।

श्री गोविन्द सहाय—जो हिन्दी नहीं जानते हैं उनके बारे में क्या होगा ?

श्री मोहन लाल गौतम—उर्दू के जानने वाले हूँ लेकिन उर्दू रिज्जल लैंग्वेज नहीं है । आप की जो डिफिकल्टी है वह पूरी नहीं हो सकती है ।

डिप्टी चैयरमैन—प्रश्न यह है कि प्रस्तावित धारा १३ (डी) के पार्ट (जी) में शब्द हिन्दी के बाद के शब्द हटा दिये जायें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री प्रताप चन्द्र आजाद—मैं प्रस्ताव करता हूँ कि प्रस्तावित धारा १३ (डी) की उपधारा (यच) में पहली रेक्ति में "any tax" के स्थान पर "Municipal tax" कर दिया जाय । यह संशोधन मैंने इसलिये रखा है कि अगर एनी टैक्स के शब्द रखे जाते तो उससे बहुत गड़बड़ होने का संभावना है । यह टर्म बहुत ही वाइडर है और इसमें कई तरह के टैक्स जैसे सेल्स टैक्स वगैरा सभी आजाते हैं । इस तरह से वह डिस्क्वालीफाई हो जाता है जो किसी प्रकार के टैक्स का भी देनदार है । तो इतनी बड़ी भयंकर कन्डीशन लगाना मैं समझता हूँ ठीक नहीं है । फिर इस विधेयक का संबंध म्युनिसिपल बोर्ड्स से है । इसलिये मैं यह म्युनिसिपल समझता हूँ कि एनी टैक्स की जगह म्युनिसिपल टैक्स कर दिया जाय और इसलिये मैं यह संशोधन रखा हूँ । मुझे आशा है कि माननीय मंत्री इसको स्वीकार करेंगे ।

श्री मोहन लाल गौतम—मुझे यह स्वीकार है ।

डिप्टी चैयरमैन—प्रश्न यह है कि प्रस्तावित धारा १३ (डी) की उपधारा एच में पहली पंक्ति में “any tax” के स्थान पर “municipal tax” रख दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री कुंवर गुरु नारायण—मैं इसको मूव नहीं करना चाहता ।

श्री प्रताप चन्द्र आज़ाद—मैं अपना यह अमंडमेंट मूव नहीं करना चाहता हूं ।

श्री प्रभु नारायण सिंह—मैं यह संशोधन रखता हूं कि प्रस्तावित धारा १३ ई के खंड ५ को बदल कर इस प्रकार पढ़ा जाय—

“No person shall vote at any election if he is convicted of a section which comes under the category of moral turpitude.”

मैं इस क्लोज से यह समझता हूं कि इसका काफ़ी मिस्यूज किया जायगा खास तौर से जो लोग इस बात में, इस सिद्धांत में यकीन करते हैं कि जब तक समाज की आर्थिक विषमता कायम है उसके खिलाफ़ उसका विरोध होना चाहिये और इसी सिलसिले में जब वे विरोध करते हैं तो उनकी मदद के लिये ला ऐन्ड आर्डर के नाम पर सरकार उनकी सहायता करती है । सरकार की कुछ ऐसी मंशा है कि जब मुल्क में लोकतन्त्रात्मक हुकूमत बन जाय तो ऐसी हालत में किसी भी अन्याय का मुकाबिला करने में सत्याग्रह की गुंजाइश नहीं रह जाती है । हम इस बात को समझते हैं कि इस मुल्क में अन्याय का मुकाबिला करने के लिये और खास तौर से जब मुल्क में सामाजिक विषमता अपने स्थान पर मौजूद है, सत्याग्रह का रास्ता अस्तित्व में रह सकता है और उस सिलसिले में बहुत से लोग जेलों में रह सकते हैं और इसी के साथ-साथ यह भी हो सकता है कि इलेक्शन से दो एक दिन पहले १५१ में भी बंद किया जा सकता है । तो ऐसी हालत में यदि यह सब क्लोज रखा जाय जिसमें यदि कोई मेम्बर जेल में कंफाइन हो तो बहुत ही खतरनाक हो जाता है । इसका बहुत ही मिस्यूज हो सकता है और यह भी हो सकता है कि वहां पर पार्टी इन पावर अपने अग्रेजीशन को क्रश करने के लिये कर्मचारियों से मिलकर इसका उपयोग करा सकती है । मारेल टरपीट्यूड में तो वह डिस्क्वालिफाई कर दिया जा सकता है ।

तो वह डिस्क्वालिफाई कर दिया जाये किसी म्युनिसिपल बोर्ड के मेम्बरशिप के लिये किसी भी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मेम्बरशिप के लिये या असेम्बली के मेम्बरशिप के लिये लेकिन केवल यह बात कि कोई भी व्यक्ति अगर वह जेल में हो चाहे वह वहां सत्याग्रह करके ही गया हो या किन्हीं दूसरे आधारों पर गया हो अगर उसका मारल टरपीट्यूट या नैतिक पतन से कोई खास संबंध न हो, ऐसी हालत में मैं समझता हूं कि इस सेक्शन में यह जोड़ दिया जाये कि उसका मारेल टरपीट्यूट के गिरने के संबंध में संदेस हुआ हो । ऐसी सूरत में यह हो सकता है कि कोई आदमी गलत तरीक़े से पकड़ा गया हो और जब तक मुकदमे का फैसला नहीं हो जाता है तब तक यह तभी नहीं होता है कि वह सही पकड़ा गया था या ग़लत पकड़ा गया था । तो ऐसी सूरत में यह एक बहुत बड़ा डर है कि जो आदमी कस्टडी में हो उसको वोट देने का अस्तित्व न होना चाहिये । हो सकता है कि ज्यादतियों की वजह से या कोई पार्टी इन पावर होने की वजह से कुछ बाधागर्दी कर सकती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिये कि उसका वोट देने का अस्तित्व ही न मिले । इसको मैं ग़लत समझता हूं । चाहे वह एक आदमी के वोट देने का सवाल हो चाहे १० के या १०० के । वह सब एक ही इम्पार्टेंस रखता है । ऐसा भी होता है कि कोई आदमी एक

वोट की वजह से हार जाता है या १० या २० वोट न मिलने के कारण भी हार जाता है। तो एक-एक वोट अहमियत रखता है। इसलिये मैं चाहता हूँ कि उसकी जगह पर यह संकलन कर दिया जाय।

श्री राजा राम शास्त्री—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्री प्रभुनारायण जी ने जो संशोधन पेश किया है मैं उसका समर्थन करना चाहता हूँ और जो कुछ उन्होंने कहा है मैं चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी उस पर गौर करें। इस १३ ई के पाचवीं धारा में जो यह चीज कही गई है कि अगर वह जेल में है स्पोर्टेशन में है लाफुल कस्टडी में है तो वह वोट नहीं दे सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि पहिले जब हम लोग जेल जाते थे और जेल में रहते हुये भी अगर वोट का मौका आता था तो हमसे वोट लिया जाता था। हम स्वतंत्रता से वोट दे सकते थे। आज हम यह महसूस करते हैं कि जो व्यक्ति जेल में है उस को वोट देने का राइट नहीं है लेकिन क्या आपने ऐसा सोचा इसकी वास्तविकता हमारे सामने नहीं आई है। लेकिन मैं जो श्री प्रभुनारायण सिंह जी ने ध्यान आर्पित किया, सोच रहा हूँ कि आजकल के जमाने में जब लोगों की हालत खराब हो जाती है और कितने ही लोग अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हुये जेल चले जाते हैं या कोई सत्याग्रह करके जेल चला जाता है तो उस हालत में यह कहाँ तक सही है। जब पिछली बार देवरिया में सत्याग्रह हुआ था तो ५,६ आदमियों को जेल हो गयी थी और इसी तरह से जब बल्लभपुर में सत्याग्रह हुआ तो कई सौ आदमी जेल चले गये थे। यह नहीं हो सकता कि किसी जमाने में जब आपने और हमने सत्याग्रह किया और अपनी आजादी की लड़ाई लड़ी तो उस वक्त आपने उस बात की इज्जत की और आपने उसको देश सेवा का काम समझा तथा उसको प्रतिष्ठा दी। लेकिन आज मैं मानता हूँ जो आपका उद्देश्य था वह आज नहीं रहा है। उसका दूसरा इन्टरप्रिडेशन लगा सकते हैं। चुनाव नजदीक आता है राजनैतिक पार्टियों में सरगमी शुरू होती है। मान लीजिये इसके पहले कोई सत्याग्रह हुआ और उसमें कई सौ आदमी अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हुये जेलखाने चले गये हों तो आपके इस कानून के मुताबिक उन व्यक्तियों को वोट देने का अधिकार नहीं रहा। साथ ही साथ मैं यह महसूस करता हूँ कि जब चुनाव नजदीक आता है तो राजनैतिक पार्टियों में सरगमी होती है। माननीय मंत्री जी और उनके दूसरे साथी मंत्री लोग तो ऊपर हो उपर जाकर भाषण देकर चले जाते हैं लेकिन जो लोग मुहल्लों में रहते हैं वे जानते हैं कि शासन किस तरह से होता है और सरकारी आफिसर इस में किस तरह से दबाये जाते हैं। झूठी रिपोर्ट लिखवाकर कैसे पुलिस से लोगों को गिरफ्तार कराया जाता है। यह सब बातें मिनिस्टर साहब तक नहीं पहुँचती हैं। आप ने आज के ही अब्बार में पढ़ा होगा कि हमारी ग्वालदोली में जो हमने अपने राइट की लड़ाई लड़ी थी उसमें कौसी झूठी रिपोर्ट लिखवा दी थी। आपको आश्चर्य होगा कि जितने भी वहाँ हमारे एक्टिव वर्कर्स थे वे सब गिरफ्तार कर दिये गये और जेलखाने में भेज दिये गये। वे वहाँ से छूट कर आ गये हैं और उन पर मुकदमा चला। जब उन पर मुकदमा चला तो वहाँ के मैजिस्ट्रेट ने लिखा है कि ऐसे गवाह पेश किये जाते हैं जो कि पुलिस की तरफ से पढ़ाये जाते हैं और सच्चे गवाहों को रोका जाता है। इस तरह की बातों को देख कर मैजिस्ट्रेट ने गुस्से में आकर सब को छोड़ दिया है। अब आप देखेंगे कि पुलिस के लोग किस तरह से दूसरे लोगों के इशारों पर चल कर जेलखानों में बन्द कर देते हैं। जो लोग जेल खानों में बन्द कर दिये जाते हैं भले ही वे दोषी साबित हो जायें वे सब अपने अधिकारों के लिये लड़ इसलिये उनको वोट देने का हक मिलना चाहिये। मैं महसूस करता हूँ कि जल्दी की वजह से कोई संशोधन नहीं ला सका लेकिन जो श्री प्रभुनारायण सिंह जी का संशोधन आया है कि जो व्यक्ति इस किस्म का काम करे वह वोट नहीं दे सकता वह ठीक है। मैं चाहता हूँ कि १३ डी के आखिर में इतना जरूर जोड़ दिया जाय कि जो मारेल ट्रिजिन्यूट हूँ वे कनविकट नहीं बन सकते। मुझे इस बात का पूरा अन्देश है और शर्म भी लगती है लेकिन जो सत्य बात है वह कहना चाहता हूँ इसमें मैं किसी पार्टी

[श्री राजा राम शास्त्री]

का माम नहीं लेता। लेकिन जो आजकल राजनैतिक पार्टियां हैं उनमें में आपको विश्वास दिलाता हूँ कि कुछ इस तरीके के लोग भी आ गये हैं जो पुलिस की निगरानी में रहे हैं या जो कालिल और गुन्डे माने जाते हैं वे आजकल राजनैतिक पार्टियों का जामा पहन रहे हैं।

आज भी देखेंगे कि मोहल्लों में ऐसे लोग सेक्रेटरी बने हुये हैं जिनका लाठी का जोर है तो यह चीज राजनीति में होती है। मैं आपसे कहता हूँ कि यह लोग दूसरे लोगों को परेशान करते हैं, किसी ने चरस या गांजा या रिवालवर रख दिया और पुलिस से मिलकर उसको पकड़वा दिया। मेरे कहने का मतलब यह है कि इस तरह की हरकत हो सकती है। ऐसा कन्डोडेट भी स्पुनि-सिपेलिटोज के लिए खड़ा हो सकता है। अगर एलेक्शन में ऐसी चीजें न हों तो मैं समझता हूँ और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि कोई भला आदमी खड़े हो कर देखे, उसकी श्रवण्य जीति होगी। ऐसे लोग जो गुन्डे हैं और राजनीतिक पार्टियों के प्रभाव से लड़ते हैं उनको कन्डोडेट नहीं बनाना चाहिये। एक तरफ तो सरकार को यह चीज करनी चाहिये कि जो ऐसे लोग हैं उनको टिकट नहीं दिया जायेगा। तो श्रवण्य ही शान्तिमय ढंग से चुनाव हो सकेंगे ऐसे लोग राजनैतिक पार्टियों का सहयोग लेकर अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं। मैं माननीय मंत्री जी को विश्वास दिलाता हूँ कि अगर वह ऐसे खतरनाक व्यक्तियों का सहयोग नहीं करेंगे तो देश का बहुत ही लाभ होगा। मैं समझता हूँ कि माननीय मंत्री जी श्री प्रभुनारायण जी के संशोधन को स्वीकार करेंगे।

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद (स्नातक निर्वाचन क्षेत्र)—माननीय डिप्टी स्पीकर साहब, श्री राजाराम शास्त्री जी ने जिन उसूलों को पेश किया है मैं उनका समर्थन करता हूँ। मैं नहीं समझता हूँ कि इस बलाज को रखने का क्या मन्तव्य है। अगर सरकार की यह मंशा है कि एक आदमी जो खराब है और उसको किसी जुर्म में सजा हो चुकी है और वह जेलखाने में है तो उस को बोट देने को आज्ञा न दी जाय, तो मैं समझता हूँ कि कुछ हद तक ठीक भी है। लेकिन अगर किसी का पोलिटिकल जुर्म है और उस को गिरफ्तार किया जाता है और उस को ग्राम इलेक्शन में बोट देने के अधिकार से वंचित किया जाता है तो यह नागरिक की आजादी पर आघात है। मैं तो समझता हूँ कि सरकार का उद्देश्य स्वतंत्रता की रक्षा करना है। इंग्लैंड में तो नागरिकों को स्वतंत्रता का बहुत ख्याल रखा जाता है। यदि कोई व्यक्ति हवीअस कापर्स ऐक्ट के अनुसार किसी जज के पास प्रार्थना पत्र ले जाय तो वह उसे स्वीकार करना पड़ेगा। छुट्टी में भी वह इंकार नहीं कर सकता। यदि करेगा तो उस पर ५०० पौंड प्रतिदिन जुर्माना होगा। यह नागरिक की आजादी का आदर्श है। हमारी सरकार को कोई ऐसा कार्य न करना चाहिये जिससे नागरिक की स्वतंत्रता में किसी प्रकार की बाधा उपस्थित हो और उसके अधिकार छीने जायें। हमारे देश में अभी ऐसी दलबन्दी नहीं हुई है अभी हम लोग इलेक्शन की विधि को अच्छी तरह से नहीं जानते हैं। अगर वहां पर यह हुआ कि जैसे शास्त्री जी हैं और उन्हें बोट ज्यादा मिलने की सम्भावना है तो चलो बन्द कर दो। किसी तरह से वारन्ट आ गया और उनको बन्द कर दिया गया। जब तक किसी को सजा नहीं हुई है तब तक बोट देने का अधिकार होना चाहिये। मेरे ख्याल में इस बलाज का दुरुपयोग हो सकता है और इससे नागरिक की स्वतंत्रता को बड़ा आघात पहुंच सकता है। दूसरी बात आप राजनैतिक वातावरण में देखते हैं, हमारे मंत्री जी कांग्रेस के प्रमुख नेता हैं उनको सब मालूम है कि ऐसी भी स्थिति आ सकती है कि किसी को सत्याग्रह करना पड़े और वह जेल में भेज दिया जाय। सत्याग्रह करना कोई ऐसा जुर्म नहीं है और वह चोरी, डकैती वगैरह जैसे घोर अपराधों में नहीं आता है। तब ऐसे व्यक्ति को बोट से वंचित रखना ठीक नहीं है। इसलिये जो संशोधन आपके सामने है वह बहुत जरूरी है और माननीय मंत्री जी को उसे मानने से कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

श्री मोहन लाल गौतम—उपाध्यक्ष जी, यह सदन सिद्धांत रूप में यह स्वीकार कर चुका है कि जो म्युनिसिपैलिटीज के चुनाव होंगे, वह असेम्बली के चुनाव के आधार पर होंगे और उनके इलेक्टोरल रोल भी वहीं होंगे तथा जो नियम हैं वह भी वहीं होंगे, इस चीज को सिद्धांत के रूप में मान चुके हैं। मेरा ख्याल है कि यदि रिप्रेजेंटेशन आफ् पीपुल्स ऐक्ट, १९५१ की ६२वीं धारा की उपधारा ५ को देखा जाय तो इसमें एक एक लवज वही है जो कि इसमें है और वह यह है—

“No person shall vote at any election if he is confined in a prison whether under a sentence of imprisonment or transportation or otherwise or is in the lawful custody of the police.”

और यही लपज इसमें भी है जिसके बारे में इस वक्त जवाब हो रहा है तो अगर बोटर लिस्ट एक ही हुई और फिर जैसे कि नियम होंगे वह अगर दो किस्म के हो गये तो फिर बोटर लिस्ट भी दो दो बनानी पड़ेगी और फिर जो आधार अभी तक था उसमें बदलाव करना पड़ेगा। एक व्यक्ति जो कि असेम्बली में बोट नहीं दे सकता था वह फिर म्युनिसिपल बोर्ड के इलेक्शन में बोट दे सकेगा और इस तरह से अपने आधार के अनुसार यह चीज बिल्कुल अलग हो जायेगी। मैं माननीय सदस्यों से पूछना चाहता हूँ कि जब यह प्रोविजन किया गया और जो पिछले बड़े-बड़े चुनाव हुए, जो कि इस वक्त पहले पहल इस देश में हुये और जैसा कि इतिहास के पंडित कहते हैं कि इतना बड़ा चुनाव संसार के इतिहास में अभी तक नहीं हुआ, तो उस वक्त किस प्रकार और किस तरह की ज्यादतियाँ हुई और इतने बड़े चुनाव में कितने लोगों को बोट से बंचित रखने के लिये गिरफ्तार किया गया। गवर्नमेंट के बारे में जो ऐसा विचार करते हैं कि उसने ऐसा किया हो तो वह बहुत ही संकुचित विचार के लोग हैं और इस वक्त यह ख्याल किया जा रहा है कि असेम्बली और पार्लियामेंट के चुनाव के समय में जो दिलचस्पी सरकार की थी उससे कम इसमें दिलचस्पी रखेगी और पक्षपात करेगी तो यह बात भी निराधार है। जब हम इतना बड़ा भारी चुनाव कर चुके हैं और जब यह बिल पेश किया गया था तो उस वक्त ला सेम्बर डाक्टर अन्वेदकर थे और मैं उनके अब तक के कामों से कह सकता हूँ कि वह गवर्नमेंट में नहीं रहना चाहते और न उन्होंने गवर्नमेंट के पक्ष में कोई इस तरह का बिल बनाया है जिससे कि गवर्नमेंट मजबूत बनने जा रही हो, वे भी कांग्रेस के खिलाफ लड़े थे फिर भी उनका कोई संकेत नहीं है कि जो प्राविजन रखा गया है वह किसी के खिलाफ था। इसलिये यह तो सदस्यों का एक भ्रम है और उनकी यह बात कोई ज्यादा वजन नहीं रखती है। क्योंकि हम उसके नियम पास कर चुके हैं और एक बड़ा भारी इलेक्शन भी कर चुके हैं और इस प्रकार का कोई दुषप्रयोग उसमें नहीं हुआ। इसलिये मैं यह आशा करूँगा कि इसको छोड़ न दिया जाय और जिस तरह से पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव ऐक्ट में है, उसके आधार पर यह रखा हुआ है।

श्री प्रभु नारायण सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो दलील माननीय मंत्री जी ने रखी वह दलील मुझे उचित नहीं मालूम होती। मैंने तो यह सोचा था कि इसमें एक बहुत बड़ी कमी है और उस कमी की तरफ ध्यान आकर्षित करने के बाद माननीय मंत्री जी इसको क़बूल कर लेंगे। लेकिन माननीय मंत्री जी ने अपनी राय जाहिर करते हुये कहा कि जो इलेक्टोरोल इसके लिये हैं, तो ये वही हैं जो कि असेम्बली कांस्टीट्यूएन्सी के लिये रोल बने थे और उसी को म्युनिसिपैलिटीज रोल में भी माना जायेगा। तो ऐसी सूरत में यदि इस सिद्धांत को मान लिया जाय क्योंकि फिर से रोल बनने में काफी दिक्कत पैदा होगी और उन्होंने नये रोल के तैयार करने में जो बात कही है, उसके लिये भी अपना ख्याल जाहिर किया। तो इतना कहने के बाद भी जो दलील उन्होंने दी या जो मेरे संशोधन के खिलाफ़ कहा तो वह शायद इस वक्त वजह से भी हो कि विरोधी पक्ष की तरफ़ से वाजिब सुझाव नहीं लाये जाते या उनकी यही मनोवृत्ति है कि उनके सुझावों को स्वीकार ही न किया जाय। तो जहाँ तक रोल का सवाल है, तो उसके लिये उन्होंने कहा कि असेम्बली के रोल पहले से तैयार हैं और नये तैयार करने में उनको तीन, चार महीने लगेंगे। तो उन्होंने कहा कि ला फ़ुली यह हो जायेगा। तो कुछ

[श्री प्रभु नारायण सिंह]

ऐसे लोग भी होंगे जो कि जमानतों पर हों, तो उनके लिये "एट दि निक आफ दि टाइम" यह बात हो सकती है। यदि दो दिन पहले वह गिरफ्तार होता है, तो क्या होगा। माननीय मंत्री जी ने यह सवाल उठाया कि पहले इतने बड़े चुनाव के सिलसिले में कोई इस तरह की दिक्कत पैदा नहीं हुई। लेकिन मैं उनको कैसे यकीन दिलाऊँ कि किस तरह की परेशानियाँ और कठिनाइयाँ हम लोगों के सामने आई हैं, उन को यहां पर अब जिक्र करना भी उचित नहीं है और उनको मैं कहना भी नहीं चाहता हूँ लेकिन मैं यह जरूर कहूँगा कि उनके आफिशियल्स ने मिलिट्री या दूसरे तरीके से किस तरह लोगों को परेशान किया और लोगों को गिरफ्तार करने का आर्डर करवाया। मगर वह बाद में इस वजह से गिरफ्तार नहीं हुये कि उसका बुरा असर उनके इलेक्शन में हो सकता था। इसमें सवाल यह है कि एक आदमी का वोट खराब होता है तो इससे यह भी गुंजाइश है कि आइन्दा भी उनका वोट खराब हो जाय। पिछली बातों को देखने के बाद तो हमें यह विचार करना होगा कि हम जो कानून बनाते हैं उस से किसी किस्म का खतरा तो नहीं रह जाता है। ऐसी सूरत में जो मंत्री महोदय ने दलील दी है वह मुझे उचित नहीं मालूम हुई। दूसरी बात जो कही गयी वह डाक्टर अम्बेदेकर के बारे में कहीं गयी कि वह बहुत ही योग्य और अनुभवी व्यक्ति थे और उन्होंने यह कानून बनाया था।

श्री मोहन लाल गौतम—यह मैंने नहीं कहा।

श्री प्रभु नारायण सिंह—मंत्री जी ने यह नहीं कहा तो शायद उन्होंने रूलस बनाने के सिलसिले में कहा हो कि उनसे बहुत मदद मिलती थी और उन्हीं के द्वारा रूलस बनाये जाते थे। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति जो रूलस बनाता है या कोई भी सरकार जो रूलस बनाती है, तो यह भी उसमें होता है कि वह उसको तब्दील कर सके। उसमें तब्दील हो सकती है। आज हमारे यहां क्लासेज हैं, असमानता है वर्ग संघर्ष है और इस तरह की कई बातें हैं, और इसमें कई ऐसे भी लोग हैं जो कि समझते हैं कि उनके लिये सत्याग्रह करना वाजिब है। तो इसमें तो पूरे मुल्क का सवाल हो जाता है। आप लोग उनको अधिकारों से वंचित करना चाहते हैं, यह उचित नहीं है।

यह सेंट्रल रूल है और प्राविन्शियल गवर्नमेंट उसको तब्दील नहीं कर सकती तब तो मैं सरकार से अपील करता और माननीय मंत्री जी से अपील करता कि सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील की जाय कि इसमें तरमीम की जाय। इसमें तो वह बात है नहीं यहां तो आपको अधिकार है कि आप इसको माने या न मानें। जब यह सदन के सामने बात आई है तो इसमें हम संशोधन भी कर सकते हैं इसलिये जो दलील के रूप में माननीय मंत्री जी ने बात कही वह मेरी समझ में नहीं आई क्योंकि एलेक्ट्रल रोल तो पहले से तैयार हो जायेंगे और अगर किसी का नाम नहीं है तब तो उसके वोट देने का सवाल ही नहीं उठता है तब ऐसी हालत में मैं यह वाजिब समझता हूँ अगर किसी का नाम नहीं है तो वह १० रुपया जमा करा के अपना नाम लिखवा लेगा लेकिन इससे आप को कोई परेशानी न होगी और जो सुझाव मैंने रखा है वह वाजिब है। अगर कोई बात ऐसी हो जो लोकतंत्र की व्यवस्था में दिक्कत पैदा करने वाली हो, या उसको कुचल रही हो और उसको ठोक करने के लिये कोई संशोधन विरोधी पक्ष की ओर से लाया जाय तो उसको मानने के लिये सरकार को गुरेज न करनी चाहिये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लोकतंत्र तभी प्रतिष्ठित हो सकता है जब पार्टी इन पावर के पास यह मनोवृत्ति हो कि वह वाजिब बातों को माने और उस पर अमल करने की कोशिश करे, नई ट्रेडिशन कायम करने की कोशिश करे। मैं समझता हूँ कि मेरा जो प्रस्ताव है वह ऐसा है कि इसको मानने में किसी को कोई एतराज नहीं हो सकता है। यह दूसरी बात है कि सरकार इसको न माने। लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि सरकारी पक्ष के बहुत से सदस्य इस बात से सहमत हैं और उन्होंने जब अपनी राय जाहिर की थी तो उस समय उन्होंने यह जाहिर किया था कि यह बात न होनी चाहिये और इसको निकाल दिया जाना चाहिये। मैं समझता हूँ कि उनके अन्दर डेमोक्रेटिक टेन्डेंसी अधिक होने से उन्हें इस प्रकार की विचार धारा रखनी पड़ी। मैं समझता हूँ कि जो उचित बातें हैं उनकी ओर

सरकार को ध्यान देना चाहिये केवल टेक्नीकल बातों को ही कह कर एक बात को नहीं खत्म कर देना चाहिये। जहाँ मौलिक अधिकार मारे जाते हैं वहाँ उनकी रक्षा होनी चाहिये। विदेश में तो इसकी ओर अधिक ध्यान दिया जाता है और इसे बहुत महत्वपूर्ण समझा जाता है। जब ऐसे संशोधन सरकार की ओर से नहीं स्वीकार किये जाते हैं तो सरकारी पक्ष की मनोवृत्ति में भी शंका होने लगती है हालांकि मैं यह बात नहीं कह सकता जब तक कि कोई सबूत न हो। लेकिन शंकायें तभी होती हैं जब ऐसे-ऐसे अमेंडमेंट नहीं माने जाते हैं। ऐसी सूरत में जो एक मौलिक बात होती है, जब कानून को बनाया जाता है, उस मोके पर देखा जाता है कि इसके मिस्यूज होने की गुंजाइश है या नहीं। इसी कसौटी पर कानून को कसा जाता है और अगर इस कसौटी पर कानून खरा नहीं उतरता तो कानून को ऐसा बनाया जाता है जिसमें इस कसौटी पर वह खरा उतर सके।

श्री मोहन लाल गौतम—उपाध्यक्ष महोदय, भाई प्रभुनारायण जी ने जरूरत से ज्यादा जोश में आकर एक व्याख्यान इस पर दिया कि कैसे डेमोक्रेसी चलना चाहिये। लेकिन उन्होंने अपने अमेंडमेंट के इम्प्लीकेशन्स नहीं समझाये। मैंने कहा था कि अगर यह अमेंडमेंट मंजूर होता है तो एलेक्ट्रल रोल्स दूसरे बनाने पड़ेंगे। अमेंडमेंट यह है—

“No person shall vote election if he is convicted of a section which comes under the category of moral turpitude.”

यह नहीं है कि जो मारल टरपीट्यूड में जेलखाने में होंगे वह निकलेंगे जो जेलखाने से बाहर निकल गये वह भी होंगे, और फिर एक दफ़ा मारल टरपीट्यूड में हो गये क्या वह भी दे सकेंगे। इसलिये दो लिस्ट्स हो जायेंगी और मारल टरपीट्यूड वाले अलग किये जायेंगे। दूसरी चीज़ यह है कि जिस रोज इलेक्शन्स हो रहे हैं उसी दिन जो जेल या पुलिस कस्टडी में होंगे उनके बारे में यह है। मैंने जैसा कि कहा यह तो असेम्बली के लिये जो रूल्स हैं उन्हीं के मुताबिक है। क्या आप आइन्दा ऐसी लिस्ट बनायेंगे कि कौन-कौन मारल टरपीट्यूड में है और कौन-कौन नहीं है और क्या इन सबको अधिकार देंगे। राजाराम जी ने कहा कि जब हम जेल में थे तब भी राय दिया करते थे। जेल में तो मैं भी रहा हूँ लेकिन मुझे तो याद नहीं कि मैंने कभी वोट जेल में रह कर दिया हो।

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद—जिसका नाम लिस्ट पर तो हो लेकिन वह पुलिस कस्टडी में हो उसका क्या होगा ?

श्री मोहन लाल गौतम—जिसका नाम लिस्ट में हो और वह पुलिस कस्टडी में हो तो वह भी डिप्राइव होगा वोट देने से। लिस्ट तैयार हो जाने के बाद भी इस तरीके को कुछ चीज़ें आ सकती हैं जो उसको डिप्राइव कर दें। मैं आपसे कहता हूँ कि अगर राय देने का अधिकार भी आप दे दें तो असल में वोट नहीं काउन्ट करता अगर नाजायज़ काम होता है। यह भी नहीं होता है कि हमेशा कांग्रेस की गवर्नमेंट ही दबाव डालती है। जो लोकल इम्प्लू-मेंटल आदमी हैं वह भी दबाव डालते हैं। मैं तो चाहता हूँ कि इलेक्शन्स फ़ेयर हों। इसलिये मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि इसको आप इसी तरह से रहने दें। जो असेम्बली में है वही यह है इसमें आपको कोई डिफ़ीकल्टी नहीं होगी। आपने बहुत कुछ हमला किया कि इस तरह से इलेक्शन्स हुये उस तरह से इलेक्शन्स हुये। इस वक्त उस पर बहस करने की जरूरत नहीं राजा राम जी ने यह कहा कि पोलिटिकल पार्टिज में बड़े २ गुंडे आ रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ज्यादा सक्सेसफुल गुंडे वही हैं जो अब तक सज़ा नहीं पाये और न जेल गये। वह कांग्रेस में ही आ रहे हों तो यही बात नहीं है। सब पोलिटिकल पार्टिज उनके लिये खुली हुई हैं। राजाराम जी को मालूम है और मुझको भी मालूम है, बहुत सी पोलिटिकल पार्टिज के जरिये से डकैतियां पड़ रही हैं। ऐसे अनडिजायरेबुल एलीमेंट्स बाइसे शर्म, हर

[श्री मोहन लाल गौतम]
 पोलिटिकल पार्टी के लिये हैं। लेकिन इन गुंडों से बचने के लिये कोई रास्ता आप नहीं बतला रहे हैं। इसका तो जवाब जनरल एलेक्टोरेट ही देगा। इस पर बहस काफ़ी हो चुकी है। मैं समझता हूँ कि अब इसे मंजूर किया जाये।

डिप्टी चैयरमैन—प्रश्न यह है कि प्रस्तावित धारा (13-E) के खंड (5) को बदलकर इस प्रकार पढ़ा जाय :

“No person shall vote at any election he is convicted of a section which comes under the category of moral turpitude.

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री प्रभु नारायण सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन पेश करता हूँ:—

“प्रस्तावित धारा 13-G(K) के बाद निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक वाक्य जोड़ दिया जाय :

Provided that the counting of votes will be done after two hours of the polling on the same day and place.

जो सेक्शन १३ (ई) है। जनरल एलेक्शन के सम्बन्ध में, एन्वाइंटमेंट्स आफ डेट, ऐण्ड नामिनेशन के सम्बन्ध में साथ ही साथ काउन्टिंग आफ एलेक्टोरेट्स के सम्बन्ध में है।

इसका मतलब यह है कि जो नियम सरकार ने काउंटिंग आफ वोट्स के सिलसिले में बनाया है वह काउंटिंग उस पोलिंग स्टेशन पर हो जाय। पिछले इलेक्शन में जो कुछ हुआ उसको देखने से यह धारणा मज़बूत हो जाती है कि जिन पोलिंग स्टेशनों पर पोलिंग होती है वहीं पर पोलिंग हो जाय तो बहुत अच्छा है। अबसर देखा गया है कि बीच ही में बाक्सेज टूट गये।

उससे हमारी दिक्कतें, हमारी परेशानी बहुत अधिक बढ़ गई। सरकार पर भी बहुत ज्यादा लांछन लगे, बहुत सी जगहों पर वोटों की चोरी हुई। मैं इस बहस में नहीं पड़ना चाहता कि वह बातें कहां तक ठीक हुई और कहां तक गलत हुई लेकिन यह जरूर हुआ कि सरकार पर भी लांछन लगाये गये। हम चाहते हैं कि सरकार इस बात से बरी रहे और उस पर लांछन न लगाये जायें। इसीलिये हमने यह जरूरी समझा कि हर पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग के दो घंटे के बाद काउंटिंग कराई जाय और फिर दूसरे दिन रिजल्ट एनाउंस कर दिया जाय। अभी असेम्बली में यह बिल नहीं गया है इसलिये भी इसको मान लिया जाय तो कोई एतराज की बात इसमें नहीं हो सकती है। अन्त में मैं यह चाहता हूँ कि काउंटिंग उन्हीं स्थानों पर २ घंटे के बाद हो जानी चाहिये जहां पर वोटिंग होती है।

श्री कुंवर गुरु नारायण—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा विचार इसमें कुछ कहने का नहीं था लेकिन जो संशोधन हमारे भाई प्रभु नारायण सिंह ने पेश किया मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूँ। जहां तक लेजिस्लेचर के एलेक्शन का सम्बन्ध है उसके बारे में आपको सब मालूम है। मैं उन बातों में अब नहीं जाना चाहता हूँ। उस वक्त तो यह दिक्कत हो सकती थी कि बहुत दूर दूर एरियाज पर पोलिंग स्टेशन्स होते थे और वहां पर अक्सर झगड़े भी हो जाते थे। वहां की सेचुरेशन गवर्नमेंट के बिआन्ड कंट्रोल हो जाती थी। इन्हीं ख्यालात को लेकर यह मुनासिब समझा गया कि केन्द्र में बाक्सेज लाये जायें और फिर काउन्टिंग हो। तो वहां तो यह ठीक हो सकता है लेकिन जहां तक म्युनिसिपैलिटी का ताल्लुक है मैं समझता हूँ कि सरकार को कोई अड़चन इस बात में नहीं होना चाहिये कि पोलिंग स्टेशन पर ही दो घंटे के बाद काउन्टिंग हो। वहां तो कोई गड़बड़ नहीं हो सकती है क्योंकि पोलिंग स्टेशन्स म्युनिसिपल एरिया के अन्दर ही होंगे। पिछले जो इलेक्शन्स लेजिस्लेचर के हुये उसमें सरकार को भी यह बात माननी पड़ी कि जो बाक्सेज जिस स्टाइल के सेक्शन

थे वह भी नहीं दिये गये और यह भी नहीं कहा जा सकता कि बेल्ट पेपर में गड़बड़ी नहीं हुई। गड़बड़ियाँ हुई हैं यह तो बिल्कुल खुली हुई बात है लेकिन अब इस पर बहस क्या है कि गड़बड़ी हुई या नहीं हुई। जो कुछ हुआ वह तो हो चुका। लेकिन मैं यह जरूर समझता हूँ कि इस बात को देखना चाहिये कि जहाँ तक बेल्ट बाक्ससेज का सम्बन्ध है उसमें ऐसा न होना चाहिये कि किसी भी व्यक्ति को कुछ संदेह हो और उसके हृदय में आशंका हो। बेल्ट बाक्ससेज की सैक्टिटी को रिजर्व करने को मैं उतना ही महत्व देता हूँ जितना कि प्रजातंत्र को ठीक तरीके से चलाने को देता हूँ। अगर इसकी सैक्टिटी खत्म हो जाती है तो मैं समझता हूँ कि लोगों में हिंसात्मक प्रवृत्ति उत्पन्न होने का भय है। बेल्ट बाक्ससेज की सैक्टिटी को हमें प्रिजर्व करना चाहिए और इसके प्रति काम्फाइडेंस हमको जनता के हृदय में बनाये रखना चाहिये। यह बहुत जरूरी बात है। इसीलिये म्युनिसिपल बोर्ड के सम्बन्ध में जो संशोधन प्रभु नारायण जी ने रक्खा है मैं उसका समर्थन करता हूँ क्योंकि म्युनिसिपैलिटीज शहरी एरिया में होती है और वहाँ यह तरीके आसानी से सम्भव हैं।

श्री प्रेम चन्द्र शर्मा (स्थानीय संस्थाएं निर्वाचन क्षेत्र)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो यह संशोधन रक्खा गया है और जिसके सम्बन्ध में बड़ी-बड़ी आशंकाएँ की गई हैं, मैं समझता हूँ कि बड़ी गलतफ़हमी पर की गई है। यह हमला गलत किया गया है। मैं समझता हूँ कि प्रान्त में और देश में जहाँ भी बेल्ट बाक्ससेज थे सब जगह पर तीन-तीन सील होती थी। इसके बाद कपड़े पर सील होती थी। जहाँ कहीं भी सील टूटी हुई मिली वहाँ पर रिपोर्टिंग कराई गई। यह बात कि बेल्ट बाक्ससेज में कुछ बेईमानी हो सकती है वही आदमी कह सकता है जिसने कि इसकी बाबत सुना है और जिसने कि बेल्ट बाक्ससेज देखे नहीं। इस बात का बहुत प्रोपेगंडा किया गया कि यह हुआ वह हुआ लेकिन किसी ने इस बात को साबित नहीं किया कि कोई बेल्ट बाक्स टूटा हुआ पाया गया हो। इस तरह का प्रचार तो बहुत हुआ और आपने भी जो बात कही वह प्रचार की बिना पर कही है। यह कहना कि उसी दिन दो घंटे के बाद बेल्ट पेपर्स काउंट कर लिये जायें और उनका रिजल्ट बता दिया जाये कैसे संभव हो सकता है। बड़ी बड़ी म्युनिसिपैलिटीज हैं यहाँ पर चेयरमैनशिप के लिये तीन या चार लाख वोट पड़ेंगे तो यह कैसे मुमकिन है कि वह तीन या चार लाख वोट उसी दिन गिन लिये जायें और रिजल्ट भी आउट कर दिया जाये। तो मेरे स्थान में जो यह संशोधन रक्खा गया है वह इम्प्रेक्टिकल है और गलत भी है। इसके सपोर्ट में जो भी बातें कही गईं वे गलत हैं। इन शब्दों के साथ मैं इसका विरोध करता हूँ।

श्री राजा राम शास्त्री—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्री प्रभु नारायण सिंह जी ने जो संशोधन पेश किया है उसका मैं समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूँ। यह मैं जरूर महसूस करता हूँ कि ऐसे मौके पर जिस ढंग से बहस हो रही है उसमें कुछ बातें आ गयी जिसमें कि पुराने इलेक्शन की बातें उठायी गई हैं। लेकिन मैं यह जरूर चाहता हूँ कि जिस दृष्टि से यह संशोधन पेश किया गया है उस पर ज़रा गौर किया जाय तो मेरा ऐसा स्थान है कि इस मौके पर जनता के बीच में जायें और लोगों की भावना को सुनें तो मैं यही कह सकता हूँ कि सिवाय कांग्रेस पार्टी के जो कि विजयी हुई है तथा जिसको हुकूमत भी है शायद ही कोई ऐसी राजनैतिक पार्टी होगी जो यह महसूस न करती हो या जहाँ जनता की ग्राम स्वाहिदा न हो कि अगर वोटिंग का कोई तरीका निकल आये तो ज्यादा अच्छा तरीका हो। मैं जरूर चाहता हूँ और मैं यह नहीं कहता कि पिछले इलेक्शन में ग्राम तौर से ऐसी चीज़ हुई है। लेकिन जिस विचार और दृढ़ता की भावना से यह बात कही गयी कि पिछले इलेक्शन में कितनी ही जगहों पर ऐसा वाक्या हुआ है कि बेल्ट बाक्ससेज टूटे हैं। मुझे इसका बड़ा भारी आश्चर्य हुआ और श्री प्रभु नारायण सिंह जी जब जवाब देंगे तो वे स्वयं बतलायेंगे कि जिस सीट से वे पार्लियामेंट के लिये लड़े वहाँ बाद में १८ जगह पर रिपोर्टिंग हुआ और वह

[श्री राजा राम शास्त्री]

रिपोर्लिंग इसी पर हुआ कि बेलेट बाक्स जटूटे हुए हैं। तो अब यह कहना कि कहीं ऐसा हुआ ही नहीं यह बड़े आश्चर्य की बात है। दूसरी आश्चर्यजनक घटना यह हुई कि यह खबर फंजी कि सीलड बाक्स भी खुल सकते हैं। हमारे यहां भी एक सरकारी अधिकारी ने मैजिस्ट्रेट के सामने यह बतलाया कि किस तरह से वह बाक्स खुल सकता है। एक तहसीलदार के सामने यह बाक्स खोला गया। मैंने मैजिस्ट्रेट से कहा कि यह क्या तमाशा है। सारे देश में तो यहाँ-तहाँ पीटा गया कि ये बाक्स खुल नहीं सकते हैं। मैंने उनसे कहा कि आपके सामने हम डेमोस्ट्रेशन देकर खोलना चाहते हैं तो उन्होंने हमको इसकी इजाजत नहीं दी। इसके बाद मैंने प्रान्तीय सरकार को लिखा लेकिन उन्होंने भी इजाजत नहीं दी और फिर दिल्ली को लिखा तो उन्होंने जवाब दिया कि प्रान्तीय सरकार को लिखो। लेकिन वह डेमोस्ट्रेशन नहीं हो सका। मैं नाम नहीं लूंगा परन्तु एक बात जरूर आपको बतलाऊंगा और वह यह है कि जिस दिन पोलिंग हो गयी उसके दो तीन दिन तक तो खूब बड़ी धूम रही कि मैं जीत गया लेकिन तीसरे दिन मालूम हो गया कि मैं हार गया हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, आपको बतलाता हूँ कि एक सरकारी आफिसर रात के समय मेरे पास आया और कहा कि शास्त्री जी यदि आप कहें तो मैं फलानी जगह से बाक्स जटूड़वा, दूँ तो वहाँ फिर से रिइलैक्शन हो जायेगा। आप जानते हैं कि इलैक्शन जीतने का हर्ष बड़ा तगड़ा होता है। तबियत में आई कि ऐसा कर दिया जाय क्योंकि हारता हुआ इम्मान जीतने के लिये क्या नहीं कर सकता। इसके अलावा थोड़ी सी वोट का सवाल था। १२ हजार और कुछ दूसरे साहब के आये थे। और ११ हजार और कुछ मेरे आये थे। रात भर मैं इस चीज को सोचता रहा कि इसे होने दिया जाय। लेकिन यह बड़े हिम्मत का काम है और मैंने इसे कतई मुनासिब भी नहीं समझा क्योंकि सब बतलाता हूँ मुझमें इसके लिये हिम्मत की कमी थी। मान लीजिये कोई बात ऐसी जनता में हो जाय कि शास्त्री जी की स्वीकृति से यह बात हुई है मैं तो जनता में मुँह दिखाने के लायक भी नहीं रह जाऊँगा। विजय और पराजय अलग चीजें हैं। लेकिन यह बात करना गलत है। मुझे ताज्जुब हुआ कि एक दूसरे सज्जन मेरे पास आये और कहा कि फलां साहब इतना पैसा मांगते हैं, आपको क्या राय है। उन सज्जन का यह पेशा हो गया था कि लोगों से पैसा लेते थे और ऐसी बातें करते थे। मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह कोई जहरी नहीं है कि अब ऐसी बातें न हों। जनता में कोई ऐसी खराब धारणा पैदा होने का मौका नहीं देना चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि किसी व्यक्ति की हार और जीत से कोई ऐसी ख़ास बात नहीं पैदा होती है जितना कि इन बातों से परिवर्तन होता है। मैं चाहता हूँ कि ऐसा वायुमंडल न पैदा हो जिससे प्रजातंत्र से जनता की आसता उठ जाये। एक पोलिटिकल पार्टी दूसरे की आलोचना करती है, सरकार की आलोचना करती है, लेकिन मैं इस बात को जनाता हूँ कि आज आप जिन कुर्सियों पर बैठे हैं उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप पर है। यह आप का पहला मौका है कि आप ऐसी परम्परा कायम करें जिससे प्रजा का प्रजातंत्र पर पूरा विश्वास हो जाय और प्रजातंत्र राज्य के लिये उसके दिल में एक अच्छी भावना पैदा हो जाय। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ वह यह है कि एक पोलिंग स्टेशन है, वहाँ पर दो ढाई हजार की पोलिंग है तो वह दो ढाई घंटे में खत्म हो जायगी अगर उसमें दो ढाई घंटे गिनने में और दे दिये जाय तो अच्छा होगा। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि एक माननीय सदस्य ने यहाँ तक कहा कि इसमें क्या हर्ज है कि अगर बाक्स को बोरे में बन्द कर दिया जाय, लेकिन उनकी बात को न माना गया। मैं तो समझता हूँ कि हार और जीत इतना महत्व नहीं रखती है जितना कि जनता का विश्वास कायम रखना होता है। जनता को इस बात का विश्वास होना चाहिये कि हमने जो वोट दिये हैं उनमें कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। मुझे आज अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि जनता में आज यह भावना पैदा हो गई है कि बोटिंग होते वक्त तो किसी को वोट ज्यादा दिये जाते हैं और वोट की गिनती होते समय किसी की जीत होती है

विजय और पराजय कोई महत्वपूर्ण चीजें नहीं हैं लेकिन जनता का प्रजातन्त्र पर विश्वास कायम रखना एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। जहाँ कहीं भी वोटिंग होती है तो सरकार को इस बात का एलान कर देना चाहिये कि उसकी गणना उसी वक्त होगी, अगर दो डार्ड हजार की वोटिंग है। ऐसी हालत में मैं माननीय मंत्री जी से यह नञ्च निवेदन करूँगा कि किसी व्यक्ति को किसी से कोई शिकायत करने का मौका नहीं मिलेगा। और हर जिले के लोगों को विश्वास हो जायगा कि जो नतीजा निकला वह सही निकला और बैलट बाक्स उस वक्त मौजूद थे। ऐसी हालत में माना कि आपकी विजय हुई तो वह जो विजय होगी उस विजय का मारेल असर जनता के ऊपर कई गुना अच्छा होगा वजाय इसके कि लोग बराबर यह महसूस करते चले जायें कि लीजिये साहब इस तरह से यह चीज की गई है। तो जो संशोधन पेश किया गया है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आम जनता की यही स्वाहिस है कि इस तरह से काउन्टिंग की जाय और यह स्वाभाविक है कि इस तरह से जनता पर अच्छा असर पड़ेगा। इसलिये मैं आशा करता हूँ कि यह सदन इस संशोधन को अवश्य स्वीकार करेगा।

श्री प्रताप चन्द्र आज़ाद—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन हमारे भाई प्रभु नारायण जी ने पेश किया है मैं तो समझता हूँ कि यह बिल्कुल इम्प्रेक्टिकेवल है। उनका यह कहना है कि चुनाव के दो घंटे के बाद ही काउन्टिंग शुरू हो जाय, मैं समझता हूँ कि यह किसी तरह से भी सम्भव नहीं हो सकता है। इलेक्शन जब होता है तो क्रायदा यह है कि सुबह ८ बजे से लेकर शाम के ५ या ६ बजे तक पोलिंग होती है और बीच में एक घंटे या दो घंटे का इन्टरवेल होता है, ५, ६ बजे चुनाव समाप्त होता है और दो तीन घंटे बक्से के ठीक करने में, सील करने में, उनकी सील देखने वगैरह में लग जाया करते हैं यह उसकी प्रैक्टिकल साइड है, और इस तरह से ८, ९ बज जाते हैं उनको काम खत्म करने में। अब आप यह उम्मीद करें कि ९ बजे के बाद वहाँ काउन्टिंग शुरू हो और सुबह चार बजे तक होती रहे तो यह किसी भी सूरत से मुनासिब और मुमकिन नहीं है। श्री राजाराम जी ने यह बताया कि हर पोलिंग पर एक हजार या दो हजार वोटर होंगे तो ऐसी बात नहीं है। हो सकता है कि जो छोटे-छोटे म्युनिसिपल बोर्ड हों उनमें एक हजार या दो हजार वोट हों, लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि जो बड़े-बड़े शहर हैं जैसे कि बरेली, इलाहाबाद, वगैरह उनमें वोट्स की संख्या कहीं अधिक होगी। मैं अपने जिले के बारे में ही कहता हूँ। बरेली शहर में वहाँ की पापुलेशन करीब दो लाख की है तो वहाँ किस तरह से वोट उसी समय काउन्ट हो सकते हैं।

श्री राजा राम शास्त्री—वहाँ पोलिंग स्टेशन एक ही नहीं होगा बल्कि कई होंगे।

श्री प्रताप चन्द्र आज़ाद—मैं मानता हूँ कि ऐसे शहर ज्यादा नहीं होंगे लेकिन फिर भी ४ या ५ हजार से कम एक पोलिंग स्टेशन की वोट नहीं हो सकती है अब अगर ४, ५ हजार वोटर हो गये तो किसी सूरत से यह सम्भव नहीं हो सकता है कि पोलिंग स्टेशन की वोटिंग की काउन्टिंग उसी समय हो जाय करे। काउन्टिंग के अन्दर जो प्रैक्टिकेवल साइड है उसी को ले लीजिये। काउन्टिंग के अन्दर यह नहीं होता कि बाक्स खोले और गिनना शुरू कर दिया जाय। उसके अन्दर सारी फार्मिलिटी करनी पड़ती है, जो एजेन्ट साहब होते हैं उनको दिखाना पड़ता है, सभी के सामने सील को तोड़ना पड़ता है और भी फार्मिलिटीज होती हैं जिन्हें कि पूरा करना होता है। फिर जो इलेक्शन का वातावरण होता है वह बड़ा हेटेड होता है, लोग हजारों की संख्या में जमा रहते हैं और फिर जो पोलिंग स्टेशन होता है वह इतना छोटा होता है कि उसमें सभी लोग आ सकें और शान्ति के साथ वहाँ पर काउन्टिंग शुरू हो, असम्भव है। जो पोलिंग स्टेशन होते हैं वे या तो छोटी छोटी धर्मशालायें होती हैं या किसी का अपना प्राइवेट हाउस होता है और वहाँ पर यह काउन्टिंग की जाय इतनी छोटी जगहों में यह सम्भव नहीं है कि इतने आदमियों के बीच में काउन्टिंग

[श्री प्रताप चन्द्र आजाद]

शुरू हो। मैं तो समझता हूँ कि किसी भी सूरत से यह संशोधन प्रैक्टिकेबल नहीं है। अभी आपने यह कहा कि निष्पक्ष कार्टिंग होनी चाहिये और बाद में फिर ऐसा हो, वंसाही, मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो हवाला दिया है कि फलों जगह में ऐसा हुआ वह सब बातें निर्मूल हैं और उनके अन्दर कोई सच्चाई नहीं है। जैसा कि अभी भाई राजा रामजी ने कहा कि फलों आदमी ने कहा कि मैं बक्स खोल सकता हूँ और देख सकता हूँ, तो इस तरह की बातें तो हम शुरू से ही सुनते आ रहे हैं कि कानपुर वाले कहते हैं कि लखनऊ में खोले गये, लखनऊ वाले कहते हैं कि इलाहाबाद में खोले गये और इलाहाबाद वाले कहते हैं कि बरेली में बक्से इस तरह से खोले गये। यह ऐसी बातें हम शुरू से ही सुनते आ रहे हैं और यह बिल्कुल ही निर्मूल हैं।

श्री राजा राम शास्त्री—लेकिन मैं जो कहता हूँ वह अपने जिले की बात कह रहा हूँ और वह बिल्कुल सही बात है और अपने आँखों देखी बात हम कह रहे हैं।

श्री प्रताप चन्द्र आजाद—मैं कम से कम अपने तजुबों से इस बात को भी सही नहीं मानता हूँ। जहाँ तक इलेक्शन का सम्बन्ध है, मैं जनाबवाला यह अर्ज करना चाहता हूँ कि जो भारत के बड़े-बड़े लीडर हैं, जैसे कि ग्यामा प्रसाद मुकर्जी आदि उन्होंने भी इस बात को एप्रोसियेट किया है कि जितनी निष्पक्षता एलेक्शन के अन्दर भारत में हुई है उतनी शायद कहीं पर भी नहीं हुई है और इतना फेयर इलेक्शन और कहीं नहीं हो सकता है। तो इसमें बड़े बड़े जिम्मेदार आदमी हैं और इस तरह के अधिकार लोगों के पास हैं। वैसे इलेक्शन में इस तरह की बातों को कह देना कि बक्से टूट गये और सील टूट गई, मैं समझता हूँ कि बहुत आसान है और ये सब बातें भी वही लोग उड़ाते हैं जो कि इलेक्शन में हार गये हों। इस तरह की बातों को उड़ाना कि बक्से टूट गये या सील टूट गई, यह हारे हुए लोगों का काम है और इस तरह की बातें आज ही क्या हमेशा होती रहेंगी। जहाँ तक इलेक्शन जीतने का सवाल है मेरा यह विश्वास है कि कांग्रेस ने ६८ या ६९ प्रतिशत चुनाव जीते और जब कि आज भी लोग इसके लिये कहते हैं कि हमने जब कांग्रेस को वोट दिया तो ये लाल टोपी वाले जो थोड़े बहुत हैं, वे अलेम्बली और कौंसिल में कैसे आ गये। हमारे भाई राजा-रामजी को एक बात का विश्वास नहीं होता कि देहात वालों ने या गांव वालों ने किस वोट दिया, इसके लिये मैं यह कह सकता हूँ कि उन्होंने वोट चाहे किसी को भी दिया हो मगर जब उनसे यह पूछा गया कि उन्होंने किसको वोट दिया है, तो फिर चाहे उन्होंने कांग्रेस को ही वोट क्यों न दिया हो, यह कह दिया कि उन्होंने वोट उन्हीं को दिया है। चाहे वह कांग्रेस के तरफ के ही क्यों न हों, मगर उन्होंने आपसे कह दिया कि वोट आपको ही दिया गया है। मैं अपने यहाँ की बात बतलाता हूँ कि मेरे यहाँ ८ बजे से चुनाव होने वाला था और दस बजे ही लोगों ने बाजार में इस तरह की खबर उड़ा दी कि कांग्रेस का कैंडीडेट हार गया। तो जब इस तरह की बातें और अफ़वाह लोग पहले से ही उड़ा देते हैं तो फिर सील टूट गई और बक्से टूट गये आदि बातें तो उनके लिये बहुत साधारण हैं और इलेक्शन में इन बातों पर ज्यादा ध्यान भी नहीं रखा जा सकता। इलेक्शन में ऐसी बातें होती हैं और होती रहेंगी चाहे फिर इलेक्शन के एक, दो घंटे के बाद ही आप कार्टिंग क्यों न कर लें। तो इसमें समय का कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं यह आशा करता हूँ कि प्रभु नारायण जी ने जो अपना संशोधन रखा है वे उसको वापस ले लेंगे क्योंकि इलेक्शन के अन्दर ये सब बातें असम्भव हैं।

श्री मोहन लाल गौतम—उपाध्यक्ष महोदय, इस संशोधन को रखने में श्री प्रभु नारायण जी ने इस बात की कोशिश की है कि बेल्ट बाक्स पर विश्वास बना रहे और कहीं इस तरह से लोग उसे बदलने का अख्तिार न ले लें। ठीक है, मेरा ख्याल है कि हर डेमोक्रेटिक स्टेट का यह फर्ज है कि वह इस बात की कोशिश करे कि लोगों पर और जनता पर उसका भरोसा रहे। जो यहाँ

कुछ बातें कही गई हैं कि बाक्स टूटे और टूट सकने हैं तो इन दोनों बातों में बड़ा फर्क है। क्योंकि अगर कोई होशियार जेब काटने वाला कहें कि हम तुम्हारी जेब अभी काट सकते हैं, तो उसके माने यह भी हो सकते हैं कि उसकी जेब काटी गई है। तो यह बहुत भ्रमिकल है। लोगों ने यह एलान किया है कि हम हार गये और वह हार गये और राजनैतिक पार्टियों में इसी आधार पर प्रस्ताव भी पास किये गये, लेकिन यह बात आज तक समझ में नहीं आई कि इतने हजारों वोटों का जो फर्क था वह कैसे हुआ। जिस तरह से काम हुआ वोट अलग अलग पड़े गार्ड्स रहे काफी बाक्स इकट्ठा हुये। उसमें यह कैसे हो सकता है कि हर एक पोलिंग स्टेशन पर बाक्स खुल जायें और दूसरे बक्सों में डाल दिये जायें और यह भी नहीं समझ में आता कि उस वक्त तक यह नहीं मालूम है कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है और कितने वोटों से हार रहा है तो किस तरह से वोट निकाले गये और कैसे दूसरे के बाक्स में डाले गये। यह एक आदमी का काम हो नहीं सकता है। तमाम सरकारी कर्मचारी थे अगर सब की कामन्तबीरेसी हो तब भी उनको क्या जेल का डर नहीं था और जो गार्ड थे उनकी भी मिलाता होता और यह भी नहीं कहा जा सकता है कि सबके सब कांग्रेस के लिये कोशिश करेंगे। मैं तो यह समझता हूँ कि यह एक भ्रम है और सच्चाई कुछ समझ में नहीं आ सकती है। लोग कह सकते हैं कि बाक्स खुल सकते हैं लेकिन इसके लिये कम से कम कितने लोगों की आवश्यकता पड़ेगी और यह काम बर्क आउट किया जाय यह मेरी समझ में नहीं आता। इसलिये मैं यह नहीं समझता कि किसी भी केस में ऐसा हुआ है, कि किसी का वोट निकाल कर दूसरे में डाल दिया गया हो। यह मैं आज तक समझ नहीं पाया हूँ अगर ऐसा होता तो बड़े-बड़े आदमी हार न जाते। बहुत से मिनिस्टर हार गये। जो मिसाल राजा राम जी ने दी उससे तो और भ्रम होता है। एक साहब आये और उन्होंने कहा कि बक्स खोल सकता हूँ, राजा राम जी सीधे-साधे आदमी हैं डेस्कानदार हैं वह यह नहीं समझ पाये कि वह पैसे लेने आया था और उनकी इलील से यह नहीं सीमित होता है कि वह खुले भी। इसलिये इस सिलसिले में जब वह सब पार्लियामेंट में हो रही थी तो उस समय जैसा कि एक सदस्य ने कहा कि विरोधी पक्ष के बड़े-बड़े लोग जैसे डा० अम्बेदेकर, डा० श्यामा प्रसाद मुखरजी आदि उन्होंने इस की प्रशंसा की कि जो चुनाव हुये हैं वह ऐसे ढंग से हुये हैं कि और कहीं नहीं हुये।

श्री राजा राम शास्त्री—मैंने भी असेम्बली में सरकार को बधाई दी थी।

श्री मोहन लाल गौतम—व्यववाद, नुस्खे पूरा विद्वानस है कि म्युनिसिपैलिटीज के इलेक्शन में आपके हारने की गुंजाइश न रहेगी। आप दूसरी तरफ प्रैक्टिकल साईड देखें एलेक्शन सुबह ८ बजे से शुरू होता है और इन्तजाम करने वाले को सुबह से ही आ जाना पड़ता है और पुलिस वालों को तो कहीं-कहीं रात से ही रहना पड़ता है क्योंकि झगड़े की संभावना हो जाती है। लोग वोटर्स को सोने ही नहीं देते हैं और पोलिंग शाम को ५ बजे तक होती है और उस समय भी ऐसा होता है कि कुछ लोग देर से आते हैं और वह परेशान होते हैं और पूछते हैं कि हमारा वोट लिया जायेगा या नहीं उनमें एक तरह का एक्साइटमेंट होता है और वह चाहता है कि हमारा वोट ले लिया जाय। वहां पर आपने बक्सों को अच्छी तरह से महफूज रखने और उन को ले जान का जो प्रश्न उठाया है उस के संबंध में मैं कहना चाहता हूँ कि उस वक्त वोटर्स मौजूद होते हैं। उन में एक्साइटमेंट मौजूद होता है उस एक्साइटमेंट में लोग तरह-तरह के नामुनासिब काम करने के लिये तैयार होते हैं। उस वक्त अगर वोटिंग हो जाये, तो आफिसर्स कुछ थके होते हैं, पुलिस वाल थके होते हैं, वहां जगह भी कोई ऐसी नहीं है जहां घेरा डालकर आप काम कर सकें। उस वक्त वोटिंग के सिलसिले में झगड़ा हो सकता है, और दूसरे किसम की गड़बड़ी हो सकती है। फिर आप कहेंगे कि हम तो जीत रहे थे, कांग्रेस वालों ने झगड़ा करा दिया। इसलिये काउन्टिंग ऐसी जगह पर होना चाहिये जो सुरक्षित हो। वहां कैंडीडेट्स या उनके एजन्ट्स जा सकते हैं और काउन्टिंग के समय मौजूद रह सकते हैं। जब तक यह न होगा तब तक बेल्ट बाक्सेज पर विद्वानस नहीं रहेगा। राजा राम जी ने कहा कि तीन दिन तक

[श्री मोहन लाल गौतम]

वह जीत रहे थे उसके बाद हारना शुरू किया। मुझे मिसालें मालूम हैं, शायद आपको भी मालूम होगा उपाध्यक्ष महोदय कि एलेक्शन समाप्त होने से थोड़ा पहले ही एक साहबान गले में माला डलवाकर जलूस के साथ यह कहते हुये निकल पड़े कि हम जीत गये और जब काउंटिंग हुई तब मालूम हुआ कि ५० वोट से हार गये। यह भ्रम थोड़ी देर तक पोलिंग के बाद भी रहता है। वाक्या यह है कि आज का वोटर भी इतना होशियार हो गया है कि वह पता भी नहीं देता। सब से कहता है कि हमने आपको वोट दिया है।

इसलिये मैं समझता हूँ कि मूवर साहब अपने संशोधन को वापस ले लें। मैं इसका विरोध करता हूँ।

श्री प्रभु नारायण सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो संशोधन रखा था उसका एक खास मकसद यह था कि काउंटिंग के सिलसिले में जितनी एहतियात बरती जा सके वह बरती जाये। जिस स्थान पर पोलिंग हो उसी स्थान पर दो घंटे के बाद काउंटिंग हो जाये जिससे कोई शूबहा की गुंजाइश न रहे। इस सिलसिले में जो दलीलें हमको मिलीं उस से यह मालूम हुआ कि सरकारी पक्ष के द्वारा शायद यह समझा गया कि एलेक्शन में वोट्स की बंगालिंग के संबंध में शिकायत की है। मैंने शायद यह बात नहीं कही थी। मैंने केवल यह बात कही थी कि पिछले एलेक्शन का तजुर्बा ऐसा है जिससे मालूम होता है कि बक्स टूट जाते हैं, खराब होने की वजह से और उसमें बंगालिंग होने की गुंजाइश है। इसके बाद यह सवाल उठता है कि साहब यह जो टूटने की बातें हैं यह सही नहीं हैं, और इस सिलसिले में बोलते हुये राजा राम जी ने उदाहरण के तौर पर जो बातें बताईं, सरकारी पक्ष के एकाध माननीय सदस्यों को शायद राजा राम जी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। खैर यह उनकी बात है। वह किसी भी माननीय सदस्य का कहना न करें। वे कोई स्टेटमेंट दें, इस बात का स्टेटमेंट दें कि यह बात ऐसी रही तो हमारे जैसे लोग उसे अवश्य मान लेंगे कि वे एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं और जिम्मेदारी के साथ कुछ कहते हैं। मैं यह जरूर कहना चाहता हूँ साफ तौर से कि पिछले एलेक्शन में जिस तरह से बाक्सेज बने वे डिफिनिट थे और बाक्सेज टूटे। खुद मेरी कान्स्टीट्यूएन्सी में जिस कान्स्टीट्यूएन्सी से मैं पार्लियामेंट के लिये खड़ा हुआ था वहां पर कांफ्रेंस कैन्डीडेट ने शिकायत की कि बाक्सेज टूटे हैं? इस तरह से १८ पोलिंग स्टेशनों पर फिर से पोलिंग हुआ। यह कहना कि बाक्सेज नहीं टूटे लेकिन कांफ्रेंस कैन्डीडेट के ही कहने से वहां पर ऐसा हुआ। मैंने कभी भी नहीं कहा कि तोड़े गये। हम लोगों ने इसलिये एतराज नहीं किया कि कपड़े में बाक्सेज रखे जाते थे और तौलिये में रखकर वे बाक्सेज पहुंचाये जाते थे। उस समय रिटर्निंग आफिसर जो थे उनसे माननीय मंत्री जी बात करें तो उनको मालूम होगा कि किस तरह से बाक्सेज उठाये जाते थे और किस तरह से गिने जाते थे। मेरा कहना है कि बाक्सेज टूटे। वे कैसे टूटे मैं इसको नहीं कह सकता जब कभी इस तरह का सवाल उठा कि बाक्सेज टूटने की वजह से हार जीत हुई तो हमने हमेशा वहां पर कहा कि जनता को जिस तरह से वोट देना चाहिये था नहीं दिया। अपने साथियों और अपने कार्यकर्ताओं को समझाते थे कि यह भावना पैदा हो कि सरकार या सरकार की पार्टी इस तरह की कोशिश नहीं कर सकती है कि बाक्सेज तुड़वाकर उसमें से कुछ बैलट पेपर निकाल ले क्योंकि इस तरह से जनता का मन डेमोक्रेसी से हट जायेगा। हमारी पार्टी के नेता श्री जयप्रकाश ने कहा था कि एलेक्शन फ़ेयर हुआ है। इसका मतलब यह था कि लोगों का मन और यकीन डेमोक्रेसी से उठने न पावे। इस वजह से कहा। तो हम कहना चाहते हैं कि पिछले एलेक्शन में ऐसी बातें हुईं जिसमें बाक्सेज टूटे। बाक्सेज कैसे टूटे इस बात को देखने के लिये सरकार इन्क्वायरी कमेटी बैठाये। गवर्नमेंट इन्क्वायरी कमेटी बैठाये और वह देखे कि बाक्सेज कैसे टूटे। बाक्सेज हमारी आंखों के सामने टूटे जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। पिछले एलेक्शन में जो हार जीत हुई उसको हम मान लेते हैं लेकिन बहुत से ऐसे सवाल हैं जो पेचीदे हैं। बाक्सेज के संबंध में हमारी तरफ से कोई एलिंगशन नहीं है पिछले एलेक्शन में बाक्सेज टूटे और बंगालिंग की गुंजाइश हुई थी। उस पोलिंग स्टेशन पर दो घंटे के बाद री काउन्ट किया जाय। हमारा मकसद इस अमेंडमेंट से यह है कि जो नियम बनाये जाय उस सिलसिले में ऐसी एहतियात बरती जाय

श्री प्रभु नारायण सिंह—मैं

डिप्टी चेयरमैन—ज्या सदन

(सदन की अनुमति)

डिप्टी चेयरमैन—प्रश्न यह है

(प्रश्न उपस्थित है)

और
इसमें

११—मूल अधिनियम की धारा

डिप्टी चेयरमैन—प्रश्न यह है

(प्रश्न उपस्थित है)

आप

१२—मूल अधिनियम की धारा

31. When a board is superseded, the following consequences shall follow—

(a) all members of the board shall be deemed to have resigned as from a date to be specified in the order, but without prejudice to their nomination :

(b) such person or persons as may be appointed in that behalf shall, until a new board is constituted, exercise and perform the duties of the board for all purposes, and

(c) a fresh board shall be appointed on the expiry of the period specified under section 10-A.

श्री प्रभु नारायण सिंह—श्रीम

कि प्रस्तावित धारा ३१ के अन्त में निम्नलिखित

“Provided that the maximum period shall not exceed more than six months”.

यह जो सेक्शन है इसमें गवर्नमेंट। बहुत चाहता है। इसके सम्बन्ध में किहू तक बोर्ड को अपने हाथ में लेने की बजाय अपने हाथ में नहीं लेना चाहिये। अमेरिका हाथ में लेती है सुपरसीड करती है है। मैं समझता हूँ कि डेमोक्रेसी ने मेरे से यह चाहता है कि जो सुपरसीड जाये। यदि कोई बोर्ड मुअत्तिल वि वजह होना चाहिये कि उसको गवर्नमेंट र से इ इन्दिश कर दी जाये।

किया
नहीं

जो संशोधन

होता है

सकता : “Place”

दिया ज

इ के किसी

के का सवाल

य में लेना

उत्तर सी में म्बर ने

बाद पि और उसके

रने जा रहे

वाक्य की होती है

“हूँ महमूस

more होना पड़ा।

रौर विचार

र ने कोई

र यह नहीं

कुछ क चीजों का

होती है।

कोई खी मानता

सामने है उसका

के बाद कोई म्युनि-

अब तीहीं है, तो

ही बहब से ज्यादा

दे सक अधिकार

जवाब दे

जाय तब

चली जाती

कि उसमें

तरह से

योग नहीं

31 व्याख्यान

जगहों पर

नियुक्त

कई मंत्रियों

हो सकता

shall हो सकता

with सकती है

वह बहुत

as m भी इसी

त सी बातें

जाता है।

1, तब से

ब माननीय

यू० पी०
एक्ट २,
१९१६ की
धारा ३१
में संशोधन
consequences of dissolution of board.

shall
with

as m

[श्री मोहन लाल गौतम]

वह जीत रहे थे उसके बाद हारना शुरू किया। मुझे मिसालें मालूम हैं, शायद आपको भी मालूम होगा उपाध्यक्ष महोदय कि एलेक्शन समाप्त होने से थोड़ा पहले ही एक साहबान गले में माला डलवाकर जलूस के साथ यह कहते हुये निकल पड़े कि हम जीत गये और जब कार्डिंग हुई तब मालूम हुआ कि ५० वोट से हार गये। यह भ्रम थोड़ी देर तक पोलिंग के बाद भी रहता है। वाक्या यह है कि आज का वोटर भी इतना होशियार हो गया है कि वह पता भी नहीं देता। सब से कहता है कि हमने आपको वोट दिया है।

इसलिये मैं समझता हूँ कि मूवर साहब अपने संशोधन को वापस ले लें। मैं इसका विरोध करता हूँ।

श्री प्रभु नारायण सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो संशोधन रखा था उसका एक खास मकसद यह था कि काउंटिंग के सिलसिले में जितनी एह्तियात बरती जा सके वह बरती जाये। जिस स्थान पर पोलिंग हो उसी स्थान पर दो घंटे के बाद काउंटिंग हो जाये जिससे कोई शूबहा की गुंजाइश न रहे। इस सिलसिले में जो दलीलें हमको मिलीं उस से यह मालूम हुआ कि सरकारी पक्ष के द्वारा शायद यह समझा गया कि एलेक्शन में वोट्स की बंगालिग के संबंध में शिकायत की है। मैंने शायद यह बात नहीं कही थी। मैंने केवल यह बात कही थी कि पिछले एलेक्शन का तजुर्बा ऐसा है जिससे मालूम होता है कि बक्स टूट जाते हैं, खराब होने की वजह से और उसमें बंगालिग होने की गुंजाइश है। इसके बाद यह सवाल उठता है कि साहब यह जो टूटने की बातें हैं यह सही नहीं हैं, और इस सिलसिले में बोलते हुये राजा राम जी ने उदाहरण के तौर पर जो बातें बताईं, सरकारी पक्ष के एकाध माननीय सदस्यों को शायद राजा राम जी की बात पर बिश्वास नहीं हुआ। खैर यह उनकी बात है। वह किसी भी माननीय सदस्य का कहना न करें। वे कोई स्टेटमेंट दें, इस बात का स्टेटमेंट दें कि यह बात ऐसी रही तो हमारे जैसे लोग उसे अवश्य मान लेंगे कि वे एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं और जिम्मेदारी के साथ कुछ कहते हैं। मैं यह जरूर कहना चाहता हूँ साफ तौर से कि पिछले एलेक्शन में जिस तरह से बाक्सेज बने वे डिफेक्टिव थे और बाक्सेज टूटे। खुद मेरी कान्स्टीट्यूएन्सी में जिस कान्स्टीट्यूएन्सी से मैं पार्लियामेंट के लिये खड़ा हुआ था वहां पर कांग्रेस कैंडीडेट ने शिकायत की कि बाक्सेज टूटे हैं? इस तरह से १८ पोलिंग स्टेशनों पर फिर से पोलिंग हुआ। यह कहना कि बाक्सेज नहीं टूटे लेकिन कांग्रेस कैंडीडेट के ही कहने से वहां पर ऐसा हुआ। मैंने कभी भी नहीं कहा कि तोड़ गये। हम लोगों ने इसलिये एतराज नहीं किया कि कपड़े में बाक्सेज रखे जाते थे और तौलिये में रखकर वे बाक्सेज पहुंचाये जाते थे। उस समय रिटर्निंग आफिसर जो थे उनसे माननीय मंत्री जी बात करें तो उनको मालूम होगा कि किस तरह से बाक्सेज उठाये जाते थे और किस तरह से गिने जाते थे। मेरा कहना है कि बाक्सेज टूटे। वे कैसे टूटे मैं इसको नहीं कह सकता जब कभी इस तरह का सवाल उठा कि बाक्सेज टूटने की वजह से हार जीत हुई तो हमने हमेशा वहां पर कहा कि जनता को जिस तरह से वोट देना चाहिये था नहीं दिया। अपने साथियों और अपने कार्यकर्ताओं को समझाते थे कि यह भावना पैदा हो कि सरकार या सरकार की पार्टी इस तरह की कोशिश नहीं कर सकती है कि बाक्सेज तुड़वाकर उसमें से कुछ बिलेट पेपर निकाल ले क्योंकि इस तरह से जनता का मन डेमोक्रेसी से हट जायेगा। हमारी पार्टी के नेता श्री जयप्रकाश ने कहा था कि एलेक्शन फ़यर हुआ है। इसका मतलब यह था कि लोगों का मन और यकीन डेमोक्रेसी से उठने न पावे। इस वजह से कहा। तो हम कहना चाहते हैं कि पिछले एलेक्शन में ऐसी बातें हुईं जिसमें बाक्सेज टूटे। बाक्सेज कैसे टूटे इस बात को देखने के लिये सरकार इन्क्वायरी कमेटी बैठाये। गवर्नमेंट इन्क्वायरी कमेटी बैठाये और वह देखे कि बाक्सेज कैसे टूटे। बाक्सेज हमारी आंखों के सामने टूटे जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। पिछले एलेक्शन में जो हार जीत हुई उसको हम मान लेते हैं लेकिन बहुत से ऐसे सवाल हैं जो पेचीदे हैं। बाक्सेज के संबंध में हमारी तरफ से कोई एलीगेशन नहीं है पिछले एलेक्शन में बाक्सेज टूटे और बंगालिग की गुंजाइश हुई थी। उस पोलिंग स्टेशन पर दो घंटे के बाद री काउंट किया जाय। हमारा मकसद इस अमेंडमेंट से यह है कि जो नियम बनाये जाय उस सिलसिले में ऐसी एह्तियात बरती जाय

कि कोई दिक्कत न हो। और किसी को इस माने में कि वॉलेट वाक्सेज टैम्पर विधे हुए हैं श्रुति न रह जाना चाहिये। अगर वॉलेट वाक्सेज के टैम्परविधि के संबंध में श्रुति बढ़ता जायगा तो लोगों का विश्वास डिमॉक्रेसी से उठता जायगा। हम भी उस रास्ते के खिलाफ हैं जिसके जरिये से आज कुछ पार्टीज हुकूमत को हाथ में लेना चाहती हैं और इसीलिये मैंने यह प्रस्ताव रखा था कि लोगों का विश्वास डिमॉक्रेसी से न हटने पावे। चूंकि मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया है कि वे और उनका डिपार्टमेंट इस बात को सोचेगा कि किस तरह से फ़ेयर एलेक्शन हो सकता है और जो दिक्कतें हैं वह दूर होंगी इसलिये मैं अपना अग्रेडमेंट वापस लेता हूँ :

डिप्टी चेरमैन—क्या सदन की अनुमति है कि यह संशोधन वापस लिया जाय।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

डिप्टी चेरमैन—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ६ इस बिल का भाग बना रहे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड—१०

१०—मूल अधिनियम की धारा २५ में से उपधारा (३) निकाल दी जाय।

यू० पी०
एक्ट २,
१९१६ की
धारा २५ का
संशोधन।

श्री प्रभु नारायण सिंह—मेरा प्रस्ताव यह है कि खंड १० निकाल दिया जाय।

श्री मोहन लाल गौतम—यह हमने जो अभी क्लोज ६ एक्सेप्ट कर लिया है उसमें इसके लिये १३-एच, में यह प्राविजन हो गया है कि—

13-H (1) Subject to the provisions of sub-section (2) and section 13-I, when the seat of a member elected to a board becomes vacant or is declared vacant of his election is declared void, the District Magistrate shall, in consultation with the board, by a notification in the official Gazette, call upon the ward concerned to elect a person for the purpose of filling the vacancy caused before such date as may be specified in the notification and the provisions of this act and of the rules and order made thereunder, shall apply. as far as may be, in relation to the election of a member to fill such vacancy.

13H (2). If the vacancy so called be a vacancy in any such ward for the Scheduled castes, the notification issued under sub-section (1) shall specify that the person to fill that seat shall belong to the scheduled castes.

तो यह प्रोसेज जो है कि किस तरह से बाई एलेक्शन होगा इसको हमने मंजूर कर लिया है।
२५- (३) में यह लिखा है।

“In the event of the court declaring a casual vacancy to have been created, it shall direct the board to take proceedings for filling the vacancy”.

तो जहां तक बैकेंसी को फ़िल करने का सवाल है वह १३ एच में आ गया है इसको अगर आप नहीं निकालेंगे तो यह दोनों चीजें नहीं हो सकती हैं और इस वक़्त जो प्रोसेज बैकेंसी को फ़िल करने का है उसको हम मंजूर कर चुके हैं इसलिये यह अग्रेडमेंट आर्डर में नहीं है।

श्री प्रभु नारायण सिंह—मैं अपने संशोधन को वापस लेता हूँ।

डिप्टी चेयरमैन—क्या सदन की अनुमति है कि यह संशोधन वापस लिया जाय।

(सदन की अनुमति से प्रस्ताव वापस लिया गया।)

डिप्टी चेयरमैन—प्रश्न यह है कि खंड १० इस विधेयक का भाग बना रहे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया तथा स्वीकृत हुआ।)

खंड ११

यू० पी० ऐक्ट,
२, १९१६
की धारा २६
और २६-ए
का निकाल
दिया जाना।

११—मूल अधिनियम की धारा २६ और २६-ए निकाल दी जायें।

डिप्टी चेयरमैन—प्रश्न यह है कि खंड ११ इस बिल का भाग बना रहे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १२

यू० पी० ऐक्ट
२, १९१६ की
धारा ३१-ए
का संशोधन।

१२—मूल अधिनियम की धारा ३१ के स्थान पर निम्नलिखित रक्खा जाय—

31. When a board is superseded under section 30, the following consequences shall follow—

(a) all members of the board including the President shall, on a date to be specified in the order, vacate their offices as such but without prejudice to their eligibility for re-election or re-nomination ;

(b) such person or persons as the State Government may appoint in that behalf shall, so long as the supersession of the board lasts, exercise and perform so far as may be, the powers and duties of the board and shall be deemed to be the board for all purposes, and

(c) a fresh board shall be constituted with effect from the date of expiry of the period of supersession as though the term fixed under section 10-A had expired.

Conse-
quences
of
superse-
ssion of
board.

श्री प्रभु नारायण सिंह—श्रीमान्, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेश करता हूँ कि प्रस्तावित धारा ३१ के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक वाक्य जोड़ दिया जाय :

“Provided that the maximum period of the supersession will not be more than six months”.

यह जो सेक्शन है इसमें गवर्नमेंट को सुपरसीड की पावर दी जाती है मैं यह कहना चाहता हूँ इसके सम्बन्ध में कि जो बोर्ड बनाने की बात है तो जहाँ तक बोर्ड को अपने हाथ में लेने की बात है उसको गवर्नमेंट को ६ महीने से ज्यादा अपने हाथ में नहीं लेना चाहिये। आज यह हो रहा है कि गवर्नमेंट जब कोई बोर्ड अपने हाथ में लेती है सुपरसीड करती है तो वर्षों तक उसे अपने हाथ में रखे रहती है। मैं समझता हूँ कि डेमोक्रेसी के तरीके से यह बात ठीक नहीं है। इसलिये मैं यह चाहता हूँ कि जो सुपरसीड किया जाये वह ६ महीने से ज्यादा न किया जाये। यदि कोई बोर्ड मुअत्तिल किया जाता है तो ६ महीने से ज्यादा अधिकार न होना चाहिये कि उसको गवर्नमेंट अपने हाथों में रखे। तो इसमें ६ महीने की बन्दिश कर दी जाये।

श्री मोहनलाल गौतम—यह जो अग्नेडमेट सूच किया गया है और जिस ज़रूरत से यह किया गया है वह मेरे ख्याल में अगर दूसरा सेक्शन भी इनके साथ में पढ़ लिया जाय तो एक हद तक वह बात पूरी हो सकती है। जो बोर्ड डिजाल्व किया जायेगा उसका तो एलेक्शन फ़ौरन करवाया जायेगा। लेकिन कुछ हालतें ऐसी हो सकती हैं कि फ़ौरन एलेक्शन न कराया जा सके और कुछ जांच वगैरह करने की ज़रूरत हो तो उसको सुपरसीड किया जायेगा और ऐसी हालत में ६ महीने काफ़ी नहीं होगा। डिजाल्व करने में तो फ़ौरन ही एलेक्शन कराया जायेगा और सुपरसीड करने में कुछ समय लग जायेगा। तो मेरे ख्याल में श्री प्रभु नारायण जी इसमें ज्यादा जोर न देंगे।

श्री प्रभु नारायण सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक सुपरसीड करने का सवाल है तो बोर्ड उस वक्त सुपरसीड किया जाता है जब इन्तज़ाम करने में कुछ गड़बड़ी होती है। इसलिये इस चीज़ को समझते हुये कि डिजाल्व करने के बाद फ़ौरन एलेक्शन होगा लेकिन जब सुपरसीड की बात आती है तब आप समझते हैं कि इसके इन्तज़ाम करने में कुछ गड़बड़ी हुई है। इसमें आपको जांच करने की ज़रूरत है, या कमियों को पूरा करने की ज़रूरत है। तो मैं इस बात को समझता हूँ कि आप ६ महीने के अन्दर पूरी इक्वायरी कर सकते हैं। तमाम आफ़िशल डिफ़ैक्ट्स जो हैं वह ६ महीने के अन्दर ऐडमिनिस्ट्रेटर पूरा कर सकता है। अगर आप उस अवधि को और बढ़ाना चाहते हैं तो क्या आप यह समझते हैं कि आपका ऐडमिनिस्ट्रेटर तो उसको पूरा कर सकता है, लेकिन चुना हुआ बोर्ड उसको पूरा नहीं कर सकता है। आप उसकी दिक्कतों को समझिये और जो दूर करने का सवाल है उसको दूर कीजिये। इसीलिये समझता हूँ कि इसको ६ महीने कर दिया जाये।

श्री मोहन लाल गौतम—मेरे ख्याल में अभी तक जो बोर्ड सुपरसीड किये गये हैं उनका नतीजा बेहतर हुआ है। खराब नहीं हुआ है। कितनी ही जगहों पर बोर्ड के सुपरसीड होने के बाद जनता ने उसका स्वागत किया है। कितनी ही जगहों पर जनता ने मांग की है कि हमारे यहां के बोर्ड को सुपरसीड किया जाय इसलिये कि वहां का इन्तज़ाम खराब है वह समझते हैं कि इस तरह से इन्तज़ाम नहीं चलना चाहिए। जहां तक ६ महीने की बात है तो भाई प्रभु नारायण सिंह जी यदि किसी बोर्ड के मेम्बर होते और उनके सामने ये दिक्कतें होतीं तो वह बिल्कुल इस तरह का संशोधन नहीं रखते। अगर कोई बोर्ड इनसोल्वेंट हो जाय या उस पर लाखों रुपया कर्जा हो जाय और उसको रिफ़ून्ड न कर सके तो क्या किया जाय। जब उनसे पूछते हैं कि आपने यह रुपया क्यों वापस नहीं किया तो वह कह देते हैं कि हमारे पास नहीं है। एक बोर्ड ऐसा है जिसने कई हजार रुपया जिस मद के लिये वसूल किया उसमें वह खर्च नहीं किया। पानी के लिये ही देखिये जो पानी का इन्तज़ाम करते हैं वह दूसरा है और जो टैक्स वसूल करते हैं वह दूसरा है। बहुत से अनअयाराइज कन्स्ट्रक्शन कर देते हैं। म्युनिसिपल बोर्ड के मेम्बर कहते हैं कि इनका बनाना मुश्किल है तो इस तरह से जो चुने हुये मेम्बर हैं वे परेशानी में पड़ जाते हैं। इसी आवार पर हमने इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को बनाया है हालांकि वह नामिनेटिड बाडी है।

(इस समय, ४ बजकर २७ मिनट पर, चैयरमैन ने सभापति का आसन ग्रहण किया।)

तो इस तरह की दिक्कतें आयेंगी जिनकी वजह से वह ६ महीने में पूरा नहीं हो सकता। या तो डिजाल्व करा के बोर्ड का फिर से इलेक्शन कर दिया जाय या उसको सुपरसीड कर दिया जाय और उसको अच्छा किया जाय। इन बातों को देखते हुये यह अग्नेडमेट ठीक नहीं है और इसको मंज़ूर नहीं करना चाहिए।

श्री प्रभु नारायण सिंह—माननीय मंत्री जी ने जो दलील दी है उससे मालूम होता है कि डिक्टेटरशिप से हर जगह काम कर दिया जाय तो अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है।

श्री मोहन लाल गौतम—आपने पहले इसको पेश किया और उसका जवाब दिया जा चुका है फिर यह दोबारा भी हो चुका है। अब आप तीसरी बार बोल रहे हैं।

श्री प्रभु नारायण सिंह—मुझे राइट आफ रिप्लाय मिलना चाहिए।

चेयरमैन—हमारे नियमों के मुताबिक यह मिनिस्टर साहब का अन्तिम उत्तर है, यदि वह पहले भी बोल चुके हों। पहले आपने इसे सूब किया है उसके बाद फिर आपने जवाब दिया है इसके बाद आप नहीं बोल सकते हैं।

प्रश्न यह है कि प्रस्तावित धारा ३१ के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक वाक्य जोड़ दिया जाय :

“Provided that the maximum period of the suppression will not be more than six months.”

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री राजा राम शास्त्री—मैं यह जानना चाहता हूँ कि यदि धारा ३१ पर कुछ कहना हो और यदि संशोधन गिर गया हो तो फिर उसके बाद कह सकते हैं या नहीं।

चेयरमैन—इसमें प्रक्रिया यह है कि अगर माननीय सदस्य चाहते हैं कि कोई खंड न रखा जाय तो उसके खिलाफ वोट दे सकते हैं। जब यह खंड सदन के सामने उपस्थित किया जायगा तो इसके विरुद्ध वोट दे सकते हैं। संशोधन पेश होने के बाद आप पूरे खंड पर डिस्कशन नहीं कर सकते हैं। उस पर तो डिस्कशन हो चुका है। अब तीसरी पढ़त में आप अपनी राय दे सकते हैं। इस वक्त आप संशोधन पर ही बहस कर सकते हैं। खंड पास किया जाय या न किया जाय इस पर आप केवल वोट दे सकते हैं।

प्रश्न यह है कि खंड १२ बिल का भाग बना रहे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १३

१३—मूल अधिनियम की वर्तमान धारा ३१-ए के स्थान पर निम्नलिखित

रक्ता जाय—

31-A. When a board is dissolved under section 30, the following consequences shall follow—

(a) all members of the board—

(i) but not the President, or

(ii) where the State Government so directs, the President also, shall on a date to be specified in the order vacate their respective offices but without prejudice to their eligibility for re-election or renomination: and

(b) the election or nomination of the members or the President, as may be necessary, shall be held or made, as the case may be,

(i) in a case referred to in sub-clause (i) of clause (a) above as though there had been casual vacancies and

(ii) in a case referred to in sub-clause (ii) of clause (a)

(b) above as though the term of the board fixed under section 10-A had expired.

यू० पी०
एक्ट २,
१९१६ की
धारा ३१
में संशोधन
consequences of dissolution of board.

खंड १४

अध्यक्ष नहोदय, धारा १३ में मैं जो संशोधन

यू० पी०एक्ट
२, १९१६ की
धारा ३४ का
संशोधन।

१४—मूल अधिनियम की है:—

(१) शब्द और त (१) में शब्द “may” और “Place”
शब्द और संख्या “sub-section”
और “the board concerned”.

(२) शब्द “said” से प्रायः यह है कि यदि किसी बोर्ड के किसी
के स्थान पर शब्द “sub-section” करने के लिये उसे सस्पेंड करने का सवाल

यू० पी०एक्ट
२, १९१६ की
धारा ३४ का
संशोधन।

१५—मूल अधिनियम के गवर्नमेंट यह पावर अपने हाथ में लेना

(१) उपधारा (१) प्रायः लेकिन लखनऊ में सरकार की और उसके
में शब्द “O” खिलाफ कोई प्रोसीडिंग शुरू करने जा रहे
direction issued by the board of any power
of any power वह बोर्ड के अन्दर अगर कोई खराबी होती है
enactment” ना चाहिये। ताकि मेम्बर को यह महसूस
१. उसके लिये उसको सस्पेंड होता पड़ा।

(२) उपधारा (२) उन गलतियों पर विचार करे और विचार
(क) शब्द “per” है कि वास्तव में हमारे मेम्बर ने कोई
“or the कोई ऐक्शन होना चाहिये। अगर यह नहीं
रख दिये तो और चीजों के बारे में किन्हीं चीजों का

(ख) शब्द “during” होती है और सभी जगह होती है।
executing हो सकती हैं और मैं यह भी मानता

१६—मूल अधिनियम में
हैं लेकिन गलती होने का जो जिक्र है उसका
तो मैं कहा जाता है। इस तरह से कोई म्युनि-
रखा जाय—

यू० पी०एक्ट
२, १९१६ की
धारा ३८ का
संशोधन।

Term of office of
members elected or
nominated to fill
casual vacancies.

“38. The term
nominated to fill
remainder of his
Term of office of members elected or nominated to fill casual vacancies.

चेयरमैन—प्रश्न यह है कि खंड उसके बाद जब मामला साफ हो जाय तब

(प्रश्न उपस्थित किया ही है तो आज एक चीज बनती चली जाती

ल जाते हैं और फिर कहा जाय कि उसमें

खंड से सुधार नहीं हो सकते हैं। इस तरह से

हो जाय जसा मन कहा तो दुरुपयोग नहीं

१७—मूल अधिनियम के जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अपने व्याख्यान

(१) उपधारा (१) जाती है कि डेमोक्रेसी का बहुत सी जगहों पर
“sub-section (3) of ससकी जगह पर वहां डिक्टेटरशिप नियुक्त
संख्या “sections 12-D मंत्री ने भी कहा है और दूसरे कई मंत्रियों

(२) उपधारा (४) दिया जाता है, तब अच्छा भी हो सकता
है तो उसका ठीक पालन भी नहीं हो सकता

रखा जाय—
है तो एक रोज यह बात हो सकती है

“(5) The State Government, any member, agents whom

(4) has been commenced यह भी देखा होगा कि डिक्टेटर भी इसी

any member who has been नहीं बनते हैं। तो कहने की बहुत सी बातें

order of suspension को अलग भावना से प्रवृत्त किया जाता है।

take part in any proceeding जब से डिक्टेटर नियुक्त किया, तब से

duties of a member.” लिये आज क्या तरीका होगा। जब माननीय

यू० पी०एक्ट
२, १९१६ की
धारा ४० का
संशोधन।

श्री प्रभु नारायण सिंह—माननीय मंत्री जी ने जो दलील दी है उससे मालूम होता है कि डिक्टेटरशिप से हर जगह काम कर दिया जाय तो अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है।

श्री मोहन लाल गौतम—आपने पहले इसको पेश किया और उसका जवाब दिया जा चुका है फिर यह दोबारा भी हो चुका है। अब आप तीसरी बार बोल रहे हैं।

श्री प्रभु नारायण सिंह—मुझे राइट आफ रिप्लाय मिलना चाहिए।

चेयरमैन—हमारे नियमों के मुताबिक यह मिनिस्टर साहब का अंतिम उत्तर है, यदि वह पहले भी बोल चुके हों। पहले आपने इसे मूव किया है उसके बाद फिर आपने जवाब दिया है इसके बाद आप नहीं बोल सकते हैं।

प्रश्न यह है कि प्रस्तावित धारा ३१ के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक वाक्य जोड़ दिया जाय :

"Provided that the maximum period of the suppression will not be more than six months."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री राजा राम शास्त्री—मैं यह जानना चाहता हूँ कि यदि धारा ३१ पर कुछ कहना हो और यदि संशोधन गिर गया हो तो फिर उसके बाद कह सकते हैं या नहीं।

चेयरमैन—इसमें प्रक्रिया यह है कि अगर माननीय सदस्य चाहते हैं कि कोई खंड न रखा जाय तो उसके खिलाफ वोट दे सकते हैं। जब यह खंड सदन के सामने उपस्थित किया जायगा तो इसके विरुद्ध वोट दे सकते हैं। संशोधन पेश होने के बाद आप पूरे खंड पर डिस्कशन नहीं कर सकते हैं। उस पर तो डिस्कशन हो चुका है। अब तीसरी पढ़त में आप अपनी राय दे सकते हैं। इस वक्त आप संशोधन पर ही बहस कर सकते हैं। खंड पास किया जाय या न किया जाय इस पर आप केवल वोट दे सकते हैं।

प्रश्न यह है कि खंड १२ बिल का भाग बना रहे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १३

१३—मूल अधिनियम की वर्तमान धारा ३१-ए के स्थान पर निम्नलिखित

रक्खा जाय—

31-A. When a board is dissolved under section 30, the following consequences shall follow—

(a) all members of the board—

(i) but not the President, or

(ii) where the State Government so directs, the President also, shall on a date to be specified in the order vacate their respective offices but without prejudice to their eligibility for re-election or re-nomination: and

(b) the election or nomination of the members or the President, as may be necessary, shall be held or made, as the case may be

(i) in a case referred to in sub-clause (i) of clause (a) above as though there had been casual vacancies and

(ii) in a case referred to in sub-clause (ii) of clause (a)

(b) above as though the term of the board fixed under section 10-A had expired,

यू० पी०
२,
की धा
और
का
दिया

यू० ए
२, १
बार
का

यू० पी०
एक्ट २,
१९१६ की
धारा ३१
में संशोधन
consequences of dissolution of board.

श्री प्रताप चन्द्र आज़ाद—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं संशोधन ३२ को मूख नहीं करना चाहता हूँ।

श्री प्रभु नारायण सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, वेरा संशोधन यह है कि प्रस्तावित धारा ३१ (A) के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक वाक्य लगा दिया जाय—

“Provided that fresh elections will be held within six months”.

इसमें मैं यह चाहता हूँ कि बोर्ड के डिजाल्व होने के ६ महीने के बाद चुनाव हो जाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इसमें माननीय मंत्री जी को कोई दिक्कत मंजूर करने में नहीं होगी। यह बोर्ड के सुधार के सिलसिले में ही कहा गया है कि बोर्ड के डिजाल्व होने के ६ महीने के बाद नया चुनाव होना चाहिए।

श्री मोहन लाल गौतम—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस संशोधन में कुछ भ्रम है इसलिये मैं धारा ३१-ए को पढ़ देना चाहता हूँ।

“In a case referred to in sub-clause (ii) of clause (a) above as though the term of the board fixed under section 10-A had expired”.

१०-ए—मैं दिया हुआ है कि जब बोर्ड का टर्म खत्म हो तो नया चुनाव हो। इसमें ६ महीने का सवाल ही नहीं उठता है।

श्री प्रभु नारायण सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूँ कि यह जो बोर्ड के डिजाल्व होने के बाद दो साल का टाइम रखा गया उसके क्या मान है। उसके बाद नया एलेक्शन होगा।

श्री मोहन लाल गौतम—इसके दो तरीके हैं एक तो वह है जो कि सुपरसीड हुये और बहुत ने उसमें हटा दिये गये और दूसरे ऐडमिनिस्ट्रेटर हुये। डिजाल्व के माने यह है कि ज्यों ही बोर्ड डिजाल्व हो फौरन ही इलेक्शन हो जाय ताकि दूसरा बोर्ड आ सके और उसका चार्ज ले सके और जिस वकत डिजाल्व होगा उस वकत ही इलेक्शन की तारीख मुक़र्रर होगी।

श्री प्रभु नारायण सिंह—यदि वह एक्स्पलेंशन हो जाय उस चीज का जो कि १३ (१) (बी) में दिया हुआ है इलेक्शन भी हो सकते हैं और नामिनेशन भी हो सकते हैं तो इसमें दोनों बात रक्खी गई है। अब यदि नामिनेशन की बात है तब तो मुझे अपने एमंडमेंट वापस करने में दिक्कत होगी, लेकिन अगर इलेक्शन की बात है तो क्या उसमें नामिनेशन का सवाल भी पैदा हो सकता है अगर यह बात है तो मैं अपना अमंडमेंट प्रेस करूंगा।

श्री मोहन लाल गौतम—जहां नामिनेशन है वहां नामिनेशन होगा और जहां इलेक्शन है वहां इलेक्शन ही होगा। नामिनेशन तो पापुलेशन के बारे में है वह तो दूसरी चीज है और वह नैनीताल वगैरह जैसे इलाकों के लिये ही है।

श्री प्रभु नारायण सिंह—तब मैं अपना अमंडमेंट वापस लेता हूँ।

चेयरमैन—क्या सदन की अनुमति है कि यह संशोधन वापस लिया जाय ?

(सदन की अनुमति से प्रस्ताव वापस लिया गया।)

चेयरमैन—प्रश्न यह है कि खंड १३ विधेयक का भाग बना रहे।

(प्रश्न उत्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १४-१६

यू० पी०एक्ट
२, १९१६ की
धारा ३४ का
संशोधन।

१४—मूल अधिनियम की धारा ३४ की उपधारा (४) में—

(१) शब्द और संख्या “sub-section (1)” के स्थान पर शब्द और संख्या “sub-section (1), (1-A) or (1-B)” रख दिये जायें; और

(२) शब्द “said” और “to” के बीच में शब्द “sub-section” के स्थान पर शब्द “sub-sections” रक्खा जाय।

१५—मूल अधिनियम की धारा ३५ की—

(१) उपधारा (१) में शब्द “enactment” और “the” के बीच में शब्द “or in carrying out any order made or direction issued by the State Government in exercise of any power conferred by this Act or any other enactment” रख दिये जायें।

(२) उपधारा (२) में :

(क) शब्द “performed” और “with in” के बीच में शब्द “or the order or direction is not carried out” रख दिये जायें; और

(ख) शब्द “duty” और “shall” के बीच में शब्द “or executing the order or direction” रख दिये जायें।

१६—मूल अधिनियम की वर्तमान धारा ३८ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय—

यू० पी०एक्ट
२, १९१६ की
धारा ३८ का
संशोधन।

Term of office of
members elected or
nominated to fill
casual vacancies.

“38. The term of the office of a member elected or nominated to fill a casual vacancy shall be for the remainder of his predecessor's term of office.”

चेयरमैन—प्रश्न यह है कि खंड १४, १५ और १६ बिल का भाग बने रहें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १७

१७—मूल अधिनियम की धारा ४० में—

यू० पी०एक्ट
२, १९१६ की
धारा ४० का
संशोधन।

(१) उपधारा (१) के खंड (बी) के शब्द और संख्या “sub-section (3) of section 14” के स्थान पर शब्द और संख्या “sections 12-D and 13-D” रखे जायें; और

(२) उपधारा (४) के बाद नई उपधारा (५) के रूप में निम्नलिखित रक्खा जाय—

“(5) The State Government may place under suspension a member, *agents* whom proceeding under sub-sections (3) and (4) has been commenced, until the conclusion of the enquiry and any member who has been so suspended shall not so long as the order of suspension continues to remain in force, be entitled to take part in any proceedings of board or otherwise perform the duties of a member.”

श्री राजा राम शास्त्री—माननीय अध्यक्ष महोदय, धारा १७ में मैं जो संशोधन पेश करना चाहता हूँ वह इस तरह से है :—

“प्रस्तावित उपधारा (५) की पंक्ति (१) में शब्द “may” और “Place” के बीच में निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जाय :

“If so desired by the majority of the board concerned”.

इस संशोधन को पेश करने का मेरा अभिप्राय यह है कि यदि किसी बोर्ड के किसी मेम्बर को उसकी किसी गलती के कारण दंडित करने के लिये उसे सस्पेंड करने का सवाल पैदा होता है तो मुझे यह मालूम होता है कि गवर्नमेंट यह पावर अपने हाथ में लेना चाहती है। बोर्ड को चाहे यह बात मालूम हो चाहे न मालूम हो कि उसके किसी मेम्बर ने कोई कसूर किया है और उसे दंड दिया जाय लेकिन लखनऊ में सरकार की ओर उसके विभागों को पता चल जाता है कि वे उसके खिलाफ कोई प्रोसीडिंग शुरू करने जा रहे हैं। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि सचमुच बोर्ड के अन्दर अगर कोई खराबी होती है तो उसका उत्तरदायित्व बोर्ड को ही लेना चाहिये। ताकि मेम्बर को यह महसूस हो जाय कि उसने फलां गलती की है और उसके लिये उसको सस्पेंड होना पड़ा। इसके अलावा जो म्युनिसिपल बोर्ड है वह भी उन गलतियों पर विचार करे और विचार करने के बाद अगर वह म्युनिसिपल समझता है कि वास्तव में हमारे मेम्बर ने कोई गलती की है और उसके खिलाफ कोई ऐक्शन होना चाहिये। अगर यह नहीं होता तो मुझे अंदेशा है कि इस तरह की ओर चीजों के बारे में किन्हीं चीजों का दुरुपयोग तो न होने लग जाय। पार्टीबंदी होती है और सभी जगह होती है। मैं मानता हूँ कि प्रजातन्त्रवाद में क्या गलतियाँ हो सकती हैं और मैं यह भी मानता हूँ कि मेम्बरों की आदर्श भावनायें नहीं हैं लेकिन गलती होने का जो जिक्र है उसका होना भी स्वाभाविक है जैसे कि और बातों में कहा जाता है। इस तरह से कोई म्युनिसिपल बोर्ड का मेम्बर गलती करता है और वहाँ का इन्तजाम अच्छा नहीं है, तो उसको चाहे कोई भी बात कहनी या करनी हो, तो मैं समझता हूँ कि सबसे ज्यादा मजबूत अथॉरिटी उसके लिये म्युनिसिपल बोर्ड ही है और उसी को यह अधिकार पहले मिलना चाहिये कि वह उस मेम्बर का सेन्सर करे। वह इस बात का जवाब दे कि उसने फलानी गलती की है और उसके बाद जब मामला साफ हो जाय तब उस पर ऐक्शन होना चाहिये। अगर ऐसा नहीं है तो आज एक चीज बनती चली जाती है और लोग गलतियों पर गलतियाँ करते चल जाते हैं और फिर कहा जाय कि उसमें सुधार तो किये जा रहे हैं, तो इस तरह से सुधार नहीं हो सकते हैं। इस तरह से उसका दुरुपयोग होगा। अगर ऐसी स्थिति हो जाय जसा मन कहा तो दुरुपयोग नहीं हो सकता है। यह बात इसलिये मैं कहता हूँ जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अपने व्याख्यान में कहा कि विभाग में यह भावना लोगों के आती जाती है कि डेमोक्रेसी का बहुत सी जगहों पर ठीक कार्य नहीं हो पा रहा है और अगर उसकी जगह पर वहाँ डिक्टेटरशिप नियुक्त कर दिया जाय तो ठीक है। इसको मुख्य मंत्री ने भी कहा है और दूसरे कई मंत्रियों ने भी कहा है कि जब इन्तजाम एक हाथ म दिया जाता है, तब अच्छा भी हो सकता है और कइयों के हाथ में इन्तजाम हो जाने से उसका ठीक पालन भी नहीं हो सकता है। अगर आप इसको मानते हैं तो मैं कहता हूँ कि एक रोज यह बात हो सकती है और आज जो १५ मंत्रियों के हाथ में जो शासन है, वह एक के हाथ में हो, तो वह बहुत ज़ब्तक सुधार सकता है। तो आपने यह भी देखा होगा कि डिक्टेटर भी इसी दुनिया में बनते हैं और डिक्टेटर कोई पैदाइशी नहीं बनते हैं। तो कहने को बहुत सी बातें कही जा सकती हैं हर चीज को यहाँ अलग अलग भावना से प्रदर्शित किया जाता है। डिक्टेटर के लिये भी कहा जाता है कि हमने जब से डिक्टेटर नियुक्त किया, तब से इन्तजाम ठीक हो गया। हमारे प्रजातन्त्र के लिये आज क्या तरीका होगा। जब माननीय

[श्री राजा राम शास्त्री]

मंत्रीजी यह चाहते हैं कि वे सब अधिकार अपने हाथ में लें और किसी भी मेम्बर के खिलाफ कोई शिकायत हो या उसने कोई गलती की हो, तो वे उसको सस्पेंड कर दें। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह कहता हूँ कि वे मेरे संशोधन को क्यों नहीं मानते हैं जब कि मैं कहता हूँ कि म्यूनिसिपल बोर्ड के अन्दर यह मसला पेश हो और वहाँ के मेम्बरों को तय कर लेने दिया जाय कि वे उसका सस्पेंशन करना चाहते हैं या नहीं। मेरे ख्याल से पहले जब वह उनके हाथ में रहे, उसके पश्चात् आप उसको अपने अधिकार में ले सकते हैं। आखिर वह चीज आपके सामने होती है तो उसके होने से यह होता है कि बोर्ड के मेम्बरों को यह मौका मिलता है कि वे उस काम को ठीक तरह से जिम्मेदारी को समझते हुये करें।

श्री मोहन लाल गौतम—अध्यक्ष महोदय, श्री राजा राम जी पहले तो यह विश्वास करते थे कि जो बात क्रान्तिकारी है वह ठीक है और अब वह डिक्टेटरशिप की बात में विश्वास करते हैं और डिक्टेटरशिप की अब आपकी स्वाहिश हुई है। लेकिन जो संशोधन उन्होंने पेश किया है कि जो मेजोरिटी अगर तय करे तो ही यह होना चाहिये। यह बात ठीक है कि अगर किसी के खिलाफ इन्क्वायरी होती है और अगर मेजोरिटी को वह मंजूर न हो, तब उसको मंजूर नहीं किया जा सकता है। मैं इस बात में इत्तिफाक करता हूँ कि उसमें म्यूनिसिपल बोर्ड की मेजोरिटी हो। जिस रोज एक मेम्बर को हटा कर मेजोरिटी यह कहती है कि उसको डिफेन्ड किया जाय, तो उस वक्त तक वह सस्पेंड कर दिया जाय। मेरा ऐसा ख्याल है यदि श्री राजा राम जी किसी म्यूनिसिपल बोर्ड में रख दिये जाय तो शायद वह ऐसे विचार न रखेंगे। मेजोरिटी भी उसमें इनवाल्ड हो और दूसरे मेम्बर भी हो सकते हैं मेजोरिटी की राय उस वक्त मांगना जिस वक्त प्रोसीडिंग्स चल रही हो, हो सकता है कि चेयरमैन भी इसमें इन्वाल्ड हो और दूसरे मेम्बर भी हो सकते हैं अगर उस वक्त मेजोरिटी के वोट पर रख दिया जायेगा तो मैं समझता हूँ कि अन्याय होगा। अब एक भ्रम है राजा राम जी को, वह दुरुपयोग शब्द का दुरुपयोग कर रहे हैं मैं बताता हूँ कि पहले शिकायत आयेगी उसके बाद इस्कूटनी होगी, चार्जशीट बनेगी, एक्सप्लेनेशन मांगा जायेगा और उसके जवाब को देखा जायेगा उसके बाद देखा जायेगा कि वह निकाला जा सकता है या नहीं। मैं आपको बताऊँ कि हाईकोर्ट में कई एक केसेज चल रहे हैं जिसमें लोगों ने कहा कि हमको गलत निकाला गया है लेकिन जब जजेज फाइल को देखते हैं तो उनको मालूम होता है कि ठीक निकाला गया है इसलिये इल्हाम शब्द का जैसे प्रयोग यहां किया गया है उस पर ही कोई काम नहीं किया जायेगा। यह गलतफहमी न हो कि किसी रिपोर्ट के आने पर वह निकाल दिया जायेगा बल्कि उसको भी अधिकार है कि वह अपनी ओर से लड़ सके और यह प्रेक्टेकेबिल भी नहीं है इसलिये मैं इसका विरोध करता हूँ।

श्री राजा राम शास्त्री—माननीय मंत्री जी ने सही सवाल उठाया है, और उनकी आशंका भी सही है। मैं डिक्टेटरशिप ही के खिलाफ रहा हूँ परन्तु मुझे आश्चर्य इस बात का है कि माननीय मंत्री जी को कब से डिक्टेटरशिप से प्यार पैदा हो गया है। मैं यह बात साफ कहना चाहता हूँ कि जब तक माननीय मंत्री जी सोशलिस्ट पार्टी में थे डिक्टेटरशिप के खिलाफ थे और मेरा अब विश्वास हो गया है जब से मैंने दुनिया की और पार्लियामेंट्स की वर्किंग को देखा है और साथ ही डिक्टेटरशिप को देखा है उसके बाद इसमें कोई शक नहीं कि मैं महसूस करता हूँ कि डिक्टेटरशिप की भावना गलत है और यह दूर होना चाहिये, और यह भावना मैंने ही यहां रखी है इसलिये मैं चाहता हूँ कि यह भावना पैदा न होने पाये। साथ साथ माननीय मंत्री जी ने कहा कि मेजोरिटी ही कोई गलत काम न कर बैठे तो मैं कहना चाहता हूँ कि इस नये बिल के मुताबिक हो सकता है। प्रेसीडेंट ग्राम पब्लिक से चुना जायेगा, कोई भी आदमी आ सकता है। मेजोरिटी सब की हो सकती है एक बात अच्छी है तो दूसरों के लिये भी हो सकती है और खराब है

तो दूसरों के लिये भी एक पार्टी को मैजोरिटी न होना। बताया यह स जो चाहे वह कर सक फिर भी इस सदन में ज कोई शलत काम मैजो मैजोरिटी क्यों न हो जिस तरीके से यहां यह है, उसी तरीके से यह काम करे।

चेयरमैन—प्रश्न
“may” और “place
“if so desired b
(प्रश्न

चेयरमैन—प्रश्न
(प्रश्न

१८—मूल अधि

१९—मूल अधि

२०—इस अधि
“Municipal Com

चेयरमैन—प्र
(प्रश्न

२१—मूल अधि
शब्द “and has
equivalent exam
दिष्ट जगह।

सका प्रभाव कुछ दूसरा
श्री राजा रा है। तो ऐसी हालत
शब्द “Government” की वार्निंग भी न बी
municipal or sin, राय कायम करके फौरन
उसके लिए यह जरूरी
इसमें जो शर्तों १५ दिन की नोटिस
अदर इक्विलेंट इ अधिकार होना चाहिये
निधि चुना है उसको
श्री मोहन कार के पास यह खबर
कर दें ताकि भवन उसको हटा दिया जाये तो
कुंवर गुरु नारायण जी प्रेसीडेंट की शिकायत
श्री राजा रा उसको हटा दिया जायेगा
चाहिये ताकि वह अपनी
चेयरमैन—के बाद ऐसा मौका ही
कि यह बात अपनी जगह
(सदस्य हैं।

श्री कुंवर गुनेडमेट कुंवर गुरु नारायण
माननीय अध्यक्ष हैं कि हम वार्निंग
बड़ी खुशी है कि जो हैं और उसको मौका दें कि
डिलीट कर दी जाय अगर किसी व्यक्ति की शिका-
लिये मैंने संशोधन रखके बाद भी वह फेल करता
गवर्नमेंट इस मूड में तब उसको मौका दिया
एक बात का जरूर तूँसे उसको आप १५ दिन
मेरे पास आये और लये कसूर होंगे, उनके
का मौका दीजिये। एक्सप्लेनेशन की यह बात
शर्माती क्यों है। इसको मुश्किल है। क्योंकि
तो अपना ही मूव करें। फर्स्ट स्टेप में तो उसको
निंग दी जाये और फिर जब

श्री मोहन ला है। जहां तक इसका
इसके लिये नहीं गया। वर नहीं होनी चाहिये कि
चेयरमैन—प्र का ऐसा मंशा नहीं है कि
किस तरह से हटाया जाये।

(प्रश्न हटाया तो जा सकता है
ऐसी बात नहीं है। अगर
उनको दूर किया जा सके
गि और वह एक्सप्लेनेशन
प्रेसीडेंट जीत भी गये।

यू० पी० ऐक्ट २,
१९१६ की धारा (१) मा।
४७-ए का संशोधन (२) विधेयक का भाग
the
रख आ।)

चेयरमैन—प्राजन चाहता हूं।

(प्रश्न

[श्री राजा राम शास्त्री]

मंत्री जी यह चाहते हैं कि वे सब अधिकार अपने हाथ में लें और किसी भी मेम्बर के खिलाफ कोई शिकायत हो या उसने कोई गलती की हो, तो वे उसको सस्पेंड कर दें। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह कहता हूँ कि वे मेरे संशोधन को क्यों नहीं मानते हैं जब कि मैं कहता हूँ कि म्यूनिसिपल बोर्ड के अन्दर यह मसला पेश हो और वहाँ के मेम्बरों को तय कर लेने दिया जाय कि वे उसका सस्पेंशन करना चाहते हैं या नहीं। मेरे ख्याल से पहले जब वह उनके हाथ में रहे, उसके पश्चात् आप उसको अपने अधिकार में ले सकते हैं। आखिर वह चीज आपके सामने होती है तो उसके होने से यह होता है कि बोर्ड के मेम्बरों को यह मौका मिलता है कि वे उस काम को ठीक तरह से जिम्मेदारी को समझते हुये करें।

श्री मोहन लाल गौतम—अध्यक्ष महोदय, श्री राजा राम जी पहले तो यह विश्वास करते थे कि जो बात क्रान्तिकारी है वह ठीक है और अब वह डिक्टेटरशिप की बात में विश्वास करते हैं और डिक्टेटरशिप की अब आपकी ख्वाहिश हुई है। लेकिन जो संशोधन उन्होंने पेश किया है कि जो मैजोरिटी अगर तय करे तो ही यह होना चाहिये। यह बात ठीक है कि अगर किसी के खिलाफ इन्क्वायरी होती है और अगर मैजोरिटी को वह मंजूर न हो, तब उसको मंजूर नहीं किया जा सकता है। मैं इस बात में इतिफाक करता हूँ कि उसमें म्यूनिसिपल बोर्ड की मैजोरिटी हो। जिस रोज एक मेम्बर को हटा कर मैजोरिटी यह कहती है कि उसको डिफेन्ड किया जाय, तो उस वक्त तक वह सस्पेंड कर दिया जाय। मेरा ऐसा ख्याल है यदि श्री राजा राम जी किसी म्यूनिसिपल बोर्ड में रख दिये जाय तो शायद वह ऐसे विचार न रखेंगे। मैजोरिटी भी उसमें इनवाल्ड हो और दूसरे मेम्बर भी हो सकते हैं मैजोरिटी की राय उस वक्त मांगना जिस वक्त प्रोसीडिंग्स चल रही हो, हो सकता है कि चेयरमैन भी इसमें इन्वाल्ड हो और दूसरे मेम्बर भी हो सकते हैं अगर उस वक्त मैजोरिटी के वोट पर रख दिया जायेगा तो मैं समझता हूँ कि अन्याय होगा। अब एक भ्रम है राजा राम जी को, वह दुरुपयोग शब्द का दुरुपयोग कर रहे हैं मैं बताता हूँ कि पहले शिकायत आयेगी उसके बाद इन्क्वायरी होगी, चार्जशीट बनेगी, एक्स्प्लेनेशन मांगा जायेगा और उसके जवाब को देखा जायेगा उसके बाद देखा जायेगा कि वह निकाला जा सकता है या नहीं। मैं आपको बताऊँ कि हाई कोर्ट में कई एक केसेज चल रहे हैं जिसमें लोगों ने कहा कि हमको ग़लत निकाला गया है लेकिन जब जजेज फाइल को देखते हैं तो उनको मालूम होता है कि ठीक निकाला गया है इसलिये इल्हाम शब्द का जैसे प्रयोग यहां किया गया है उस पर ही कोई काम नहीं किया जायेगा। यह ग़लतफहमी न हो कि किसी रिपोर्ट के आने पर वह निकाल दिया जायेगा बल्कि उसको भी अधिकार है कि वह अपनी ओर से लड़ सके और यह प्रेक्टेकेबिल भी नहीं है इसलिये मैं इसका विरोध करता हूँ।

श्री राजा राम शास्त्री—माननीय मंत्री जी ने सही सवाल उठाया है, और उनकी आशंका भी सही है। मैं डिक्टेटरशिप ही के खिलाफ रहा हूँ परन्तु मुझे आश्चर्य इस बात का है कि माननीय मंत्री जी को कब से डिक्टेटरशिप से प्यार पैदा हो गया है। मैं यह बात साफ कहना चाहता हूँ कि जब तक माननीय मंत्री जी सोशलिस्ट पार्टी में थे डिक्टेटरशिप के खिलाफ थे और मेरा अब विश्वास हो गया है जब से मैंने दुनिया की और पार्लियामेंट्स की वकिंग को देखा है और साथ ही डिक्टेटरशिप को देखा है उसके बाद इसमें कोई शक नहीं कि मैं महसूस करता हूँ कि डिक्टेटरशिप की भावना ग़लत है और यह दूर होना चाहिये, और यह भावना मैंने ही यहां रखी है इसलिये मैं चाहता हूँ कि यह भावना पैदा न होने पाये। साथ साथ माननीय मंत्री जी ने कहा कि मैजोरिटी ही कोई ग़लत काम न कर बैठे तो मैं कहना चाहता हूँ कि इस नये बिल के मुताबिक हो सकता है। प्रेसीडेंट ग्राम पब्लिक से चुना जायेगा, कोई भी आदमी आ सकता है। मैजोरिटी सब को हो सकती है एक बात अच्छी है तो दूसरों के लिये भी हो सकती है और खराब है

तो दूसरों को लिये भी हो सकती है। अगर वह कला याद कि इस सदन के अन्दर किसी एक पार्टी की मेजोरिटी है और वह सदैव ही यत्न करती जायेगी तो यह सही न होगा। बताइये यह सदन है इसमें एक पक्ष की काम तो मेजोरिटी है आप जो चाहें वह कर सकते हैं और दूसरी बात किसी की नहीं मानी जाती है लेकिन फिर भी इस सदन में जो एक या दो मेम्बर इस तरह हैं उनको ऐसी धारणा है कि यदि कोई यत्न करे मेजोरिटी करेगी तो वह उसको उल्लास कर सकते हैं और कोई भी मेजोरिटी क्यों न हो वह बात सामने जरूर आ जायेगी और मेम्बर उससे डरेगा। जितनी तरीके से यहाँ यह कहा जाता है कि विश्वास कीजिए मेजोरिटी अक्ल से काम करती है, उसी तरीके से यह हो सकता है कि म्युनिसिपल बोर्ड की मेजोरिटी भी अक्ल से काम करे।

चेयरमैन—प्रश्न यह है कि खंड १७ की उपधारा (५) की पंक्ति १ में शब्द में “may” और “place” के बोल में निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जायें :

“if so desired by the majority of the board concerned.”

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

चेयरमैन—प्रश्न यह है कि खंड १७ विधेयक का भाग बना रहे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १८-२०

१८—मूल अधिनियम की धारा ४१ में से शब्द “Co-option” निकाल दिया जाय।

यू०पी० ऐक्ट २,
१९१६ की
धारा ४१ का
संशोधन।

१९—मूल अधिनियम की धारा ४२ निकाल दी जाय।

यू०पी० ऐक्ट २,
१९१६ की धारा
४२ का निकाल
दिया जाना।

२०—इस अधिनियम और किसी और विधान में जो समस्त विशेष पर प्रचलित हो, शब्द “Municipal Commissioner” के स्थान पर “municipal member” रखे जायें।

शब्द “Municipal commissioner” के स्थान पर शब्द “municipal member” का रखा जाना।

चेयरमैन—प्रश्न यह है कि खंड १८, १९ और २० इस बिल का भाग बने रहें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २१

२१—मूल अधिनियम की धारा ४३ की उपधारा (४) में शब्द ‘years’ के बाद शब्द “and has passed the High School Examination or any other equivalent examination so declared by the State Government” रख दिये जायें।

यू०पी० ऐक्ट २,
१९१६ की
धारा ४३ का
संशोधन।

श्री राजा राम शास्त्री—मैं यह प्रस्ताव करता हूँ कि धारा २१ की चौथी पंक्ति में शब्द "Government" के बाद शब्द "or possesses suitable experience of municipal or similar work of public service" बढ़ा दिये जायें।

इसमें जो क्वालिफिकेशन्स रखी गई हैं वह "हाई स्कूल इग्जामिनेशन और एनी अदर इक्विवेलेंट इग्जामिनेशन" हैं...

श्री मोहन लाल गौतम—अध्यक्ष महोदय, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं निवेदन कर दूँ ताकि भवन का समय बच जाय कि हाई स्कूल की जो शर्त है उसके सम्बन्ध में कुंवर गुरु नारायण जी ने जो अमेन्डमेंट किया है वह मुझे मंजूर है। वह उसे मूव कर व।

श्री राजा राम शास्त्री—मैं अपना संशोधन वापस लेना चाहता हूँ।

चेयरमैन—क्या सदन की अनुमति है कि संशोधन वापस लिया जाय।

(सदन की अनुमति से प्रस्ताव वापस लिया गया।)

श्री कुंवर गुरु नारायण—मैं प्रस्ताव करता हूँ कि खंड २१ निकाल दिया जाय।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई तकरीर करने की तो जरूरत नहीं है, मुझे बड़ी खुशी है कि जो संशोधन है उसे मंजूर किया गया है। धारा २१ जो है बिल्कुल डिलीट कर दी जाय जो प्रेसिडेंटशिप के लिये मेट्रोकुलेशन पास की शर्त रखी गई है उसके लिये मैंने संशोधन रखा है कि यह कैंद हटा दी जाय। हमें मालूम हुआ है कि शायद गवर्नमेंट इस मूड में है कि वह इस संशोधन को स्वीकार कर लेगी। लेकिन मुझे दुःख एक बात का जरूर हुआ, वह मैं कहना चाहता हूँ कि एक गवर्नमेंट के मेम्बर साहब मेरे पास आये और उन्होंने कहा कि आप इसे मूव न कीजिये और उसको मूव करने का मौक़ा दीजिये। मुझे नहीं मालूम कि विरोधी पक्ष का सुझाव मानने में गवर्नमेंट शर्माती क्यों है। इसमें तो आप की ही प्रतिष्ठा बढ़ती है। फिर भी अगर आपकी इच्छा है तो अपना ही मूव करके मंजूर कीजिये। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं।

श्री मोहन लाल गौतम—जहां तक मुझे मालूम है गवर्नमेंट का कोई मेम्बर इसके लिये नहीं गया।

चेयरमैन—प्रश्न यह है कि खंड २१ बिल का भाग बना रहे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

खंड २२

यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ की धारा ४७-ए का संशोधन २२—(१) मूल अधिनियम की धारा ४७-ए की उपधारा (४) में से (१) शब्द "Co-opted" और "Co-option" निकाल दिये जायें और (२) शब्द "take place" के स्थान पर शब्द "be held or made, as the case may be, as though there had been casual vacancies" रख दिये जायें।

चेयरमैन—प्रश्न यह है कि खंड २२ बिल का भाग बना रहे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड—२३

२३—मूल अधिनियम की बारा ४८ में—

(१) उपधारा (२) में—

(क) खंड (१) के स्थान पर निम्नलिखित रक्खा जाय—

“(a) that there has been a failure on the part of the President in performing his duties, give him a warning or remove him from office as the State Government think fit, or” ; और

(ख) खंड (बी) में—

(१) उपखंड (१) में शब्द और संख्या “sub-section (3) of section 14” के स्थान पर शब्द और संख्या “section 12-D and 13-D” रखे जाय;

(२) उपखंड (v) के बाद निम्नलिखित तथा उपखंड (vi) के रूप में रक्खा जाय—

“... guilty of gross misconduct in the discharge of his duties”; और

(२) उपधारा (२) के बाद निम्नलिखित नई उपधारा (३) के रूप में रक्खी जाय—

“(3) The State Government may place under suspension a President against whom action is proposed under sub-clause (vi) of clause (b) of sub-section (2) until the proceedings are over and where a President has been so suspended he shall not for so long as the order of suspension continues be entitled—

(a) to exercise the powers or perform the duties of President imposed upon him by or under this Act or any other enactment for the time being in force; and

(b) to take part in any proceedings of the board”.

श्री कुंवर गुरु नारायण—मैं निम्नलिखित संशोधन पेश करना चाहता हूं।

Delete sub-clause (a) of clause 23.

मैं यह मानता हूं कि इस में जो क्लॉज है उससे प्रेसीडेंट रिमूव हो सकता है बिना किसी प्रकार की वारनिंग बिये। जब कभी कोई ऐसी परिस्थिति पैदा हो, जब प्रेसीडेंट को हटाना हो तो उसके लिये वारनिंग देने की जरूरत है इसलिये मैंने संशोधन किया है। मैं समझता हूं कि इस पर कोई ज्यादा वाद-विवाद नहीं होगा।

श्री मोहन लाल गौतम—इस प्रश्न पर कल काफ़ी बहस हो चुकी है। मैंने भी कल एक मिसाल दी थी वह यह कि एक जगह यह साबित हो गया था कि म्युनिसिपल बोर्ड का चेयरमैन रिश्वात लेता है और हमारे कानूनी मशविरों की यह राय हुई कि चूंकि पहले वारनिंग नहीं हुई है इसलिये हम उसको अलग नहीं कर सकते हैं। अब जहां तक अलग करने का सम्बन्ध है यह बात ठीक है। अलग चेयरमैन उस समय किया जाना

पृ० पी० ऐक्ट २,
१९१६ की बारा
४८ का संशोधन

[श्री मोहन लाल गौतम]

चाहिये जब काफी उसके खिलाफ वजूहात हों। अब और ज्यादा जरूरी होगा क्योंकि वह जनरल बाडी से चुना हुआ होगा। जब इस प्रकार की चीज है और कोई रिश्तत ले रहा है। कोई साहब चेयरमैन हैं और उनके खिलाफ कोई शिकायत आयी और यह मालूम हो कि उन्होंने बेईमानी की है फिर भी आप अपने आप को देखें, पहली वार्निंग दें। दो चार दफा रिश्तत लेने का मामला चलता है और एक दफा पकड़ा जाता है तो उसको वार्निंग दे दें। अगर उसके बाद फिर पकड़ा जाय तो उसका रिमूवल हो तो इसको सदन नहीं चाहता है। जो पहला लफ्ज था वह इन परसिस्टेंस आफ फेल्योर का है वह इसमें से निकल गया है। उसका रिमूवल भी हो सकता है और उसको वार्निंग भी हो सकती है। अगर निकाल दिया गया तो पहले जो हालत थी वही हालत रहेगी। जो दिक्कतें मैंने सदन के सामने पेश की हैं उनको हल करने का रास्ता हमारे सामने नहीं है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि कुंवर गुरु नारायण जी अपने संशोधन को वापस ले लें।

श्री राजा राम शास्त्री—माननीय अध्यक्ष जी, श्री गुरु नारायण जी ने जो संशोधन पेश किया है वह काफी महत्वपूर्ण है। इस तमाम विधेयक का आधार यह है कि अब बालिग सत्ताधिकार पर चुनाव होंगे और बालिग सत्ताधिकार के आधार पर बहुमत से चुना हुआ व्यक्ति प्रेसीडेंट हुआ करेगा। अब सवाल यह है कि अगर गवर्नमेंट यह समझती है कि प्रेसीडेंट कोई गलती करता है तो उसको वार्निंग देकर रिमूव किया जा सकता है। मैं समझता हूँ कि अभी तक जिस तरह से धांधली चल रही है उसका अब जमाना खत्म हो गया। अब हमारे वर्क करने का सेट अप दूसरा है। इन सब बातों को देखते हुये मेरा ख्याल यह है कि आज कल के जमाने का कोई भी प्रेसीडेंट जो सारे शहर के बहुमत का कमाण्ड करता है और जनता की मेजोरिटी से प्रेसीडेंट चुना जाता है तो यह गवर्नमेंट के लिये इतना आसान न बना देना चाहिये कि यहाँ से फरमान भेज दिया गया और वह रिमूव कर दिया गया। हमारा ख्याल है कि यह बहुत बड़ी ताकत गवर्नमेंट अपने हाथ में ले रही है। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट के हाथ में यह ताकत न होनी चाहिये कि वह प्रेसीडेंट को जब चाह निकाल दे। यह चीज कहने में बहुत सरल मालूम देती है लेकिन मैं वड़े ही अबब से कहना चाहता हूँ और मेरा ऐसा ख्याल है कि यह जो आम जनता द्वारा चुने हुये प्रेसीडेंट होंगे वह ऐसे होंगे जैसा कि आज तक का आपका तजुर्बा है कि किस तरह से स्पेनिशिल बोर्ड में धांधली हुआ करती है। अब जो पार्टियों का संगठन होगा उसमें मेरा ख्याल है कि जो जनता के प्रतिनिधि होंगे वह बहुत ही सजग होंगे। अब व्यक्तिगत चुनाव का जमाना नहीं रहा। अब तो अगर किसी पैसे वाले को कोई बात करनी होगी तो वह राजनैतिक पार्टी को लेकर भले ही आ जाय। हमारा ख्याल है कि अब राजनैतिक पार्टी आ सकती है। इन्डीविजुअल्स नहीं आ सकते हैं। तो जो प्रतिनिधि जायेंगे वह स्वतः ही जागरूक होंगे। इसलिये मैं आशा करता हूँ कि गवर्नमेंट इस तरह की ताकत हाथ में न लेगी।

श्री कुंवर गुरु नारायण—अभी मुझे भी कुछ कहना है तो क्या कल के लिये यह रखा जायगा या आज ही हो जायगा।

चेयरमैन—इस संशोधन पर वाद-विवाद तो कम से कम आज ही खत्म होना चाहिये अभी १० मिनट तक और हम बैठ सकते हैं।

श्री कुंवर गुरु नारायण—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन अभी इस भवन के सम्मुख है, मैं समझता था कि उसमें ऐसी कोई विवाद की बात नहीं होगी जिसके कारण मंत्रिमंडल को इसको मंजूर करने में कोई कठिनाई हो। अभी राजा राम शास्त्री ने कहा कि पहले जो चेयरमैन हुआ करते थे और अब जो होंगे उनमें

बहुत अन्तर हो गया है। उस समय अंग्रेजों की हुकूमत थी, उसका प्रभाव कुछ दूसरा था और आज हमारा देश स्वतंत्र है और उसका वातावरण दूसरा है। तो ऐसी हालत में वह एक बात दूसरी थी और यह बात दूसरी हुई। प्रेसीडेंट को वारनिंग भी न दी जाये और फोरन हो गवर्नमेंट बगैर वारनिंग दिये हुये अपनी राय कायम करके फोरन ही बरखवास्त कर दे यह अनुचित है। जहां तक सम्प का सम्बन्ध है उसके लिए यह जरूरी नहीं है कि उसको ६ महीने का समय दिया जाये बल्कि उसको १५ दिन की नोटिस देकर गवर्नमेंट उसको डिसमिस कर सकती है। लेकिन उसको अधिकार होना चाहिये कि जिस व्यक्ति को जनता ने विश्वास देकर अपना प्रतिनिधि चुना है उसको अपनी बात कहने का मौका देना चाहिये। किसी प्रकार से सरकार के पास यह खबर आई कि उसने ऐसी गड़बड़ी कर दी है तो एकदम से उसको हटा दिया जाये तो इसका नतीजा यह होगा कि बाज लोग बगैर कसूर के किसी प्रेसीडेंट की शिकायत कर देंगे कि उसने यह गलती की है और उसकी बिना पर उसको हटा दिया जायेगा ऐसी हालत में उसको एक्सप्लेनेशन देने का मौका भी होना चाहिये ताकि वह अपनी बात को कह सके और ही सकता है कि उसकी बात सुनने के बाद ऐसा मौका ही न आये कि वह हटाया जाये। ऐसी हालत में मैं समझता हूं कि यह बात अपनी जगह पर महत्व रखती है और इसीलिये मैं इसको प्रेस करना चाहता हूं।

श्री मोहन लाल गौतम—मैं यह समझता हूं कि यह अमैंडमेंट कुंवर गुरु नारायण जी ने किसी गलतफ़हमी की वजह से रक्खा है। उनका यह ख्याल है कि हम वारनिंग दें और फिर १५ दिन के बाद उसको हटा दें। वारनिंग दें और उसको मौका दें कि वह अपना एक्सप्लेनेशन दे सके। तो यहां तो कोशिश यह है कि अगर किसी व्यक्ति की शिकायत आती है तो उसको वारनिंग दी जाती है और अगर उसके बाद भी वह फेल करता है तब उसके खिलाफ चार्जशीट फ़ेम की जाती है और तब उसको मौका दिया जायेगा। अगर एक बार आप उसको वारनिंग देते हैं तब कैसे उसको आप १५ दिन के बाद रिमूव कर सकते हैं। उसके तो जब बाद में नये कसूर होंगे, उनके जवाब होंगे तब वह रिमूव किया जा सकेगा। इसलिये यह एक्सप्लेनेशन की यह बात तो नहीं है। अभी इस वक्त जो पोजीशन है वह तो काफी मुश्किल है। क्योंकि पहले तो आप कहते हैं कि पहली मर्तबा तो उसको वारनिंग दी जाये। फ़र्स्ट स्टेप में तो उसको वारनिंग दी जाये। जब कई बार वह रिश्वत ले चूके तब उसको वारनिंग दी जाये और फिर जब कई बार रिश्वत ले तब उसको रिमूव करें। यह पोजीशन है। जहां तक इसका संबंध है कि राजा राम जी ने कहा कि गवर्नमेंट को ऐसी पावर नहीं होनी चाहिये कि उसको हटाया जा सके तो यह तो बात ही दूसरी है। मूवर साहब का ऐसा मंशा नहीं है कि उसको हटाया न जा सके बल्कि उनका मंशा यह है कि उसको किस तरह से हटाया जाये। इस बात को तो वह मानते हैं कि हटाया जा सकता है। तो वह हटाया तो जा सकता है लेकिन कंडीशन्स का सवाल है। मैं समझता हूं कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि काम ठीक से चले और जो शिकायतें आये उनको दूर किया जा सके तो मैंने तो पहले भी कह दिया है कि चार्जशीट फ़ेम होगी और वह एक्सप्लेनेशन देगा। ऐसे कई कैसेज हाई कोर्ट में भी गये और वहां से प्रेसीडेंट जीत भी गये। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि इसका दुरुपयोग होगा।

चेयरमैन—प्रश्न यह है कि खंड २३ का उपखंड (ए) विधेयक का भाग बना रहे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री कुंवर गुरु नारायण—श्रीमान् जी, मैं इस पर विभाजन चाहता हूं।

चेयरमैन—लेकिन इस पर तो राय ली जा चुकी है।

सदन का कार्यक्रम

श्री कुंवर गुरु नारायण—कल क्या बिजनेस होगा यह हमें बतला दिया जाय।

चेयरमैन—यह बिल तो लिया ही जायेगा और इसके अलावा अगर बक्षत रहेगा तो जो विधेयक गवर्नमेंट प्रस्तुत करना चाहे वह लिया जायेगा।

श्री हर गोविन्द सिंह—कल आगरा यूनीवर्सिटी बिल लिया जायेगा।

श्री कुंवर गुरु नारायण—इसमें ४८ घंटे की नोटिस की जरूरत होती है इसलिये यह परसों लिया जाय और कल बाकी दिन में नान आफिशियल काम लिया जाय।

इलाहाबाद यूनीवर्सिटी कोर्ट के लिए चुनब

चेयरमैन—पहले तो मुझे यह घोषणा करनी है कि इलाहाबाद यूनीवर्सिटी कोर्ट के लिये दो नामजदगियां आई हैं। एक श्री निजामुद्दीन साहब की है और दूसरी श्री प्रताप चन्द्र आजाद की है। सिर्फ यही दो नामिनेशन आये हैं इसलिये मैं घोषित करता हूँ कि श्री निजामुद्दीन और श्री प्रताप चन्द्र आजाद इलाहाबाद यूनीवर्सिटी कोर्ट के मेम्बर चुने गये।

आगरा यूनीवर्सिटी (पूरक) विधेयक, १९५२ ई०

श्री हर गोविन्द सिंह—मैं आपकी आज्ञा से आगरा यूनीवर्सिटी (पूरक) विधेयक सन् १९५२ ई० को पुरस्थापित करता हूँ।

सदन का कार्यक्रम

चेयरमैन—इस बिल का इंट्रोडक्शन (Introduction) हो गया है। अब सवाल यह है कि अगर कल म्युनिसिपैलिटी बिल पूरा हो जाने के बाद समय मिले तो क्या सदन आगरा यूनीवर्सिटी बिल को लेना पसन्द करेगा। वह कल के एजेन्डा पर रहेगा और अगर सदन पसन्द करेगा तो वह लिया जायेगा और यदि पसन्द नहीं करेगा तो नहीं लिया जायेगा।

श्री कुंवर गुरु नारायण—नान आफिशियल डे कब रहेगा। यदि माननीय मंत्री कल ही कार्य खत्म कर दें तो परसों क्या होगा।

चेयरमैन—हम लोगों के नियम के अनुसार बृहस्पतिवार नान आफिशियल डे है अगर बृहस्पतिवार को सदन की बैठक होती है तो नान आफिशियल बिजनेस लिया जायेगा। अगर नहीं होती है तो फिर नहीं लिया जायेगा। अगर कल ही काम खत्म हो जाय और सदन यह तय करे कि परसों न बैठना चाहे तो नहीं लिया जायेगा। अगर सदन तय करे तो परसों नान आफिशियल बिजनेस लिया जायेगा। सब सदन के ऊपर निर्भर है।

श्री कुंवर गुरु नारायण—मैं माननीय लीडर आफ दि हाउस से कहना चाहता हूँ कि इस यूनीवर्सिटी बिल को परसों लिया जाय और कल नान आफिशियल डे हो जाये तो ज्यादा अच्छा होगा। हम लोगों को भी बिल पर विचार करने के पहले काफी मौका मिल जायेगा।

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो आज म्युनिसिपलटी बिल है पहले इसको समाप्त कर दिया जाय, इसके बाद यूनीवर्सिटी बिल लिया जाय क्योंकि उसमें कोई खास बात नहीं है। इसलिये उसमें कोई खास तैयारी की भी जरूरत नहीं है, जैसा कि कुंवर साहब ने कहा कि इसमें तैयारी की जरूरत है।

चेयरमैन—इस बात पर बहस नहीं हो रही है।

श्री राजा राम शास्त्री—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो विधेयक पेश हुआ है अगर उस पर किसी माननीय सदस्य को संशोधन देने हों तो वह कब दे।

चेयरमैन—वह उसी वक्त दे सकता है।

श्री राजा राम शास्त्री—माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बात में यह कहना चाहता हूँ कि जो २४ घंटे का रूल है उसी के मुताबिक यह बिल क्यों न लिया जाय।

चेयरमैन—यह बिल परतों ही लिया जायेगा। कल यूनीवर्सिटी बिल पर पहले बहस होगी उसके बाद जो वक्त रह जायेगा उसमें अगर कोई माननीय सदस्य अपना नान ऑफिशल रिज्योल्यूशन पेश करना चाहेंगे तो उस पर डिस्क्शन होगा।

कौंसिल कल ११ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(कौंसिल की बैठक ५ बजकर १५ मिनट पर ५ नवम्बर को ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गई।)

लखनऊ;
नवम्बर ४, १९५२

श्यामलाल गोविल,
सेक्रेटरी,
लेजिस्लेटिव कौंसिल,
उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौंसिल

बुधवार ५ नवम्बर, १९५२

—:०:—

उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौंसिल की बैठक कौंसिल हाल, विधान भवन, लखनऊ, में दिन के ११ बजे चेयरमैन (श्री चन्द्रभाल) के सभापतित्व में हुई।

उपस्थित सदस्य (५१)

अब्दुल शकूर नजमी, श्री
अम्बिका प्रसाद बाजपेयी, श्री
ईश्वरी प्रसाद, डाक्टर
उमानाथ बली, श्री
एम० जे० मुकर्जी, श्री
कन्हैया लाल गुप्त, श्री
कुंवर गुरु नारायण, श्री
कृष्ण चन्द्र जोशी, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
जगन्नाथ आचार्य, श्री
जमीलउर्रहमान क़िदवई, श्री
ज्योति प्रसाद गुप्त, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेलू राम, श्री
नरीत्तम दास टंडन, श्री
निजामुद्दीन, श्री
निर्मल चन्द्र चतुर्वेदी, श्री
पन्ना लाल गुप्त, श्री
पूर्ण चन्द्र विद्यालंकार, श्री
प्रताप चन्द्र आज़ाद, श्री
प्रभु नारायण सिंह, श्री
प्रसिद्ध नारायण अनंद, श्री
प्रेम चन्द्र शर्मा, श्री
बद्री प्रसाद कक्कड़, श्री
बशीर अहमद, श्री
बलभद्र प्रसाद बाजपेयी, श्री

बालक राम वैश्य, श्री
बाबू अब्दुल मजीद, श्री
महमूद अस्लम खां, श्री
मानपाल गुप्त, श्री
राजा राम शास्त्री, श्री
राना शिवअम्बर सिंह, श्री
राम किशोर रस्तोगी, श्री
राम किशोर शर्मा, श्री
रक्तुद्दीन खां, श्री
लल्लू राम द्विवेदी, श्री
लालता प्रसाद सोनकर, श्री
वंशीधर शुक्ल, श्री
विश्वनाथ, श्री
वीर भान भाट्ट
ब्रज लाल वर्मा
शांति दे
शांति दे
शांति स्वरूप अग्रवाल
शिवराजवती नेह
श्याम सुन्दर ल
सत्यप्रेमी
सभापति
सरदार
सैयद
हयात

निम्नलिखित मंत्री

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम (वित्त मंत्री)
श्री हर गोविन्द सिंह (शिक्षा मंत्री)

प्रश्नोत्तर

बरेली कालेज, बरेली में विभिन्न फीसों का लिया जाना

आ० सं० १
तारीख
१५-१०-५२

१—श्री प्रताप चन्द्र आजाद (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—(क) क्या यह सच है कि बरेली कालेज में इन्टरमीडियेट क्लासों में मासिक शुल्क के अतिरिक्त बिल्डिंग फीस (building fees) भी ली जाती है जब कि बिल्डिंग फीस लेना बोर्ड आफ इन्टरमीडियेट तथा हाई स्कूल के नियमों के विरुद्ध है ?

Education
Minister

(ख) यदि यह सच है तो सरकार इसके विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री हर गोविन्द सिंह (शिक्षा मंत्री)—(क) यह सत्य है कि बरेली डिग्री कालेज के इन्टर कक्षाओं के विद्यार्थियों से एक रुपया मासिक बिल्डिंग फीस ली जाती है। माध्यमिक शिक्षा परिषद का फीस के नियमों से कोई संबंध नहीं है।

(ख) शासन ने डिग्री कालेजों में उक्त फीस लेने की विशेष आज्ञा अस्थायी रूप से दे रखी है, इसलिये उक्त कालेज के विरुद्ध किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उत्पन्न होता।

श्री प्रताप चन्द्र आजाद—क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १९४७ में एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कोई ऐसा आदेश निकाला था जिसमें बिल्डिंग फीस लेना नाजायज करार दिया था ?

श्री हर गोविन्द सिंह—यह जवाब तो दिया गया है कि यह किसी नियम के विरुद्ध नहीं जाता है।

श्री प्रताप चन्द्र आजाद—मेरा कहना यह है कि सन् १९४७ में शिक्षा विभाग ने एक सरकार निकाला था जिसमें कुछ फीस निर्धारित की गई थीं और कुछ को नाजायज करार दिया गया था ?

श्री हर गोविन्द सिंह—किन संस्थाओं के बारे में यह था ?

श्री प्रताप चन्द्र आजाद—हाईस्कूल और इन्टरमीडियेट क्लासेज के बारे में ?

श्री हर गोविन्द सिंह—बरेली कालेज सरकारी नहीं है वह तो आगरा यूनिवर्सिटी के नीचे है।

श्री प्रताप चन्द्र आजाद—लेकिन बरेली कालेज में जो हाईस्कूल और इन्टर क्लासेज हैं उनका संबंध तो आगरा यूनिवर्सिटी से नहीं है ?

श्री हर गोविन्द सिंह—२७ अप्रैल, १९४५ में यह सरकार निकला कि आगरा यूनिवर्सिटी के जो अफिलियेटेड कालेज हैं वे अपने यहां यह फीस लगा सकते हैं।

आ० सं० २
तारीख
१५-१०-५२

२—श्री प्रताप चन्द्र आजाद—(क) क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बरेली कालेज में छात्र शुल्क (tuition fees) के अतिरिक्त और कौन कौन सी फीस ली जाती है और इनमें से कौन कौन सी फीस बोर्ड आफ इन्टरमीडियेट तथा हाई स्कूल के नियमों के विरुद्ध है ?

(ख) क्या सरकार के पास इस संबंध में बरेली कालेज के विद्यार्थियों का कोई प्रस्ताव आया है जिसमें उन्होंने इस प्रकार की फीस के विरुद्ध सरकार का ध्यान आकर्षित कराया है ?

(ग) यदि हां, तो सरकार ने उस संबंध में क्या कार्यवाही की ?

श्री हर गोविन्द सिंह—(क) मासिक शिक्षा शुल्क के अतिरिक्त बरेली डिग्री कालेज के प्रत्येक विद्यार्थी से निम्नलिखित अन्य फीसों भी ली जाती हैं :—

र० आ० पा०

(१) महंगाई फीस	०-६-० प्रतिमास
(२) बिल्डिंग फीस	१-०-० ”
(३) पुस्तकालय	१-०-० वार्षिक
(४) गैम्स	६-१२-० ”
(५) कामनरूम तथा मेगजिन फीस	२-६-० ”
(६) यूनिफ़ॉर्म फीस	२-०-० ”
(७) पंखा फीस	१-६-० ”

जैसा ऊपर कहा गया है माध्यमिक शिक्षा परिषद् का फीस के नियमों से कनेक्ट संबंध नहीं है। उपर्युक्त फीसों में कोई फीस किसी सरकारी नियम के विरुद्ध नहीं है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री प्रताप चन्द्र आजाद—मैं माननीय मंत्री से यह पूछना चाहता हूँ कि जो ७ फीस आपने लिखा है उनके अलावा एक इमर्जेंसी फीस भी ली जाती है ?

श्री हर गोविन्द सिंह—इसकी मुझे सूचना नहीं है।

श्री प्रताप चन्द्र आजाद—क्या माननीय मंत्री इसकी सूचना जानने की कोशिश करेंगे ?

श्री हर गोविन्द सिंह—यदि माननीय सदस्य इस के संबंध में प्रश्न पूछने का कष्ट करेंगे तभी सूचना एकत्रित की जायेगी।

सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्ट्री की सिफारिशें

प्र० स० १३

तारीख

१५-१०-५२

३—श्री कन्हैया लाल गुप्त (अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र)—(क) सेंट्रल मिनिस्ट्री आफ एजुकेशन की हाल की सिफारिशों, कि अध्यापकों को वेतन के सरकारी स्कूलों का दिया जाना प्राइवेट स्कूलों और संस्थाओं को सहायता देने में एक शर्त रखी जाये, की अमल में लाने के लिये सरकार क्या कार्रवाई करने का इरादा रखती है।

(ख) क्या सरकार “स्केल्स आफ पे आफ प्राइमरी एण्ड सेकेंडरी स्कूल टीचर्स इन स्टेट्स इन इंडिया, १९५१” के प्रकाशन में की गयी सिफारिशों में से किसी को भी अमल में लाना चाहती है ? यदि हाँ, तो वह कौन सी है ?

O. N. 13

Date

15-10-52

3. Sri Kanhaiya Lal Gupta—(teachers Consti tuency) (a) What steps do the Government intend to take to implement the recent recommendations of the Central Ministry of Education that adoption of Government scales of pay for teachers should be recorded as one of the conditions for grants in-aid to private schools and institutions ?

(b) Do the Government intend to give effect to any of the recommenda-
tions made in the Publication “Scales of pay of Primary and Secondary
School Teachers in States in India, 1951” ? If so, what are they ?

श्री हर गोविन्द सिंह—(क) सहायता प्राप्त स्कूलों के अध्यापकों को राजकीय स्कूल के अध्यापकों वाले वेतन-क्रम देना संभव नहीं है, परन्तु यह सुझाव कि स्वीकृत वेतन-क्रम को लागू करना सहायता देने की एक शर्त समझी जाय, पहले से ही कार्यान्वित कर दिया गया है। सरकार से अनुदान लेने के लिये सरकार द्वारा स्वीकृत अनिवार्य वेतन-क्रम लागू करना अनुदान देने की एक शर्त रखी गयी है।

(ख) कोई और सुझाव नहीं दिया गया है। उल्लिखित प्रकाशन में जो सुझाव हैं वे केन्द्रीय सरकार के शिक्षा मंत्रालय की संस्तुति नहीं कही जा सकती। अतएव यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

Sri Har Govind Singh:—(a) It is not possible to adopt Government scales of pay for aided School teachers but the alternative suggestion of making the adoption of approved scales of pay one of the conditions for grant-in-aid has already been implemented by making the adoption of Mandatory Scales of pay approved by Government, a condition for continuance of grant-in-aid.

(b). No other suggestions have been made and as the suggestions in the publication are not recommendations of the ministry of Education the question does not arise.

आ० सं० १४
तारीख
१५-१०-५२

४—श्री कन्हैया लाल गुप्त—क्या एडेड सेकेंडरी स्कूलों के अध्यापकों को छुट्टी के मामले में वह ही विशेषाधिकार हैं जो कि सरकारी स्कूलों के अध्यापकों को प्राप्त हैं। यदि हां, तो क्या सरकार इसके लिये कार्रवाई करने का इरादा रखती है कि यह पालिसी सब स्कूलों में समान रूप से अमल में लायी जाय ?

O. N. 14
Date
15-10-52

4. Sri Kanhaiya Lal Gupta:—Are the teachers in Aided Secondary Schools entitled to the same leave privileges as those in Government Schools? If so, do the Government intend to take steps to see that this policy is uniformly carried out in all the schools?

श्री हर गोविन्द सिंह—मामला विचाराधीन है।

Sri Har Govind Singh:—The Matter is under consideration.

श्री कन्हैयालाल गुप्त—इस संबंध में सरकार अपना फैसला कब तक देगी ?

श्री हर गोविन्द सिंह—यह कहना बहुत मुश्किल है। मामला विचाराधीन है और जितनी जल्दी हो सकेगा किया जायेगा। कोई दिन निश्चित नहीं किया जा सकता है।

श्री कन्हैया लाल गुप्त—सरकार के सामने क्या दिक्कतें हैं जिन कारणों से सरकार को फैसला करने में देरी हो रही है ?

श्री हर गोविन्द सिंह—यह तो एक बहुत बड़ा व्योरा हो जायगा। अगर माननीय सदस्य मेरे पास आयें तो मैं उनको बतला दूंगा।

आ० सं० १५
तारीख
१५-१०-५२

५—श्री कन्हैया लाल गुप्त—(क) क्या यह ठीक है कि इस प्रदेश के बहुत से हायर सेकेंडरी स्कूलों में अध्यापकों को वह वेतन नहीं दिया जा रहा है जो सन् १९४७ ई० में लाजिमी तौर पर निश्चित किया गया था ?

(ख) क्या यह ठीक है कि कुछ मामलों में अध्यापकों को उस रकम से कम दिया जाता है जिसके लिये वह वेतन रजिस्टर पर अपने हस्ताक्षर करते हैं ?

(ग) यदि हां, तो ऐसे अध्यापकों की संख्या क्या है ?

(घ) सरकार ने इस प्रकार कम वेतन देने वाली संस्थाओं के खिलाफ क्या कार्यवाही की है और इस प्रदेश से इस प्रकार के भ्रष्टाचार को दूर करने के लिये सरकार क्या कदम उठाना चाहती है।

O. N. 15

Date

15-10-52

5. Sri Kanhaiya Lal Gupta: (a) Is it a fact that in many Higher Secondary Schools in this State teachers are not being given the pay scales as mandatorily fixed in the year 1947 ?

(b) Is it also a fact that in some cases teachers are paid lesser amounts than what they are required to sign on the pay register ?

(c) If so, what is the number of such teachers ?

(d) What action has the Government taken against such defaulting institutions and what steps do the Government propose to take to root out this corrupt practice from the State ?

श्री हरगोविन्द सिंह—(क) सूचना एकत्रित की जा रही है ।

(ख) सूचना एकत्रित की जा रही है ।

(ग) सूचना एकत्रित की जा रही है ।

(घ) सूचना एकत्रित की जा रही है ।

Sri Har Govind Singh: (a) The information is being collected.

(b) " "

(c) " "

(d) " "

६—श्री कन्हैया लाल गुप्त—(क) हायर सेकेंडरी स्कूलों को सहायता देने के लिये क्या आधार रखा गया है ।

आ० सं० १६

तारीख

१५-१०-५२

(ख) क्या यह ठीक है कि ऐसी संस्थाओं को जो पुरानी हैं और जिनमें विद्यार्थियों और अध्यापकों की अधिक संख्या है, नयी और छोटी संस्थाओं की अपेक्षा कम रकम मिलती है ?

(ग) क्या सरकार का वर्तमान तरीके में सुधार करने का कोई विचार है ?

6. Sri Kanhaiya Lal Gupta : (a) What is the basis for grant-in-aid as given to Higher Secondary Schools ?

O. N. 16

Date

15-10-52

(b) Is it a fact that older institutions with greater number of students and teachers receive lesser amounts in comparison to newer and smaller institutions ?

(c) Do the Government have any idea of rationalizing the present system ?

श्री हरगोविन्द सिंह—पैरा ३७७ एजुकेशन कोड के आधार पर उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान दिया जाता है ?

(ख) सूचना एकत्रित की जा रही है ।

(ग) जी हां ।

Sri Har Govind Singh : (a) The Higher Secondary schools are given grants-in-aid according to para. 377 of the Education Code.

(b) The information is being collected.

(c) Yes.

श्री कन्हैया लाल गुप्त—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो जवाब पढ़ा गया है वह भ्रम था इसलिये क्या माननीय मंत्री जी उसको फिर पढ़ने की कृपा करेंगे ?

श्री हरगोविन्द सिंह—पैरा ३७७ एजुकेशन कोड के आधार पर उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान दिया जाता है ।

श्री कन्हैया लाल गुप्त—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रांट-इन-रेड सिस्टम को रिवाइज करने के लिये जो कमेटी बैठी थी उसकी रिपोर्ट पर सरकार क्या विचार कर रही है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—वह रिपोर्ट सरकार के पास आ गई है । सरकार उसकी बेखुशाल कर रही है कि उस पर कितना धन व्यय होगा ।

अध्यापकों और विद्यार्थियों के लिये सेनेटोरियम के संबंध में सरकार की योजना

आ० सं० १७
तारीख
१५-१०-५२

७—श्री कन्हैया लाल गुप्त—(क) सरकार अपनी इस योजना, कि अध्यापकों और विद्यार्थियों के लिये सेनेटोरियम स्थापित किया जाय, को कार्यान्वित करने के लिये क्या कदम उठा रही है ?

(ख) उस कमेटी का क्या विधान होगा जो इस योजना को चलायेगी ? क्या इस कमेटी में इस बात को देखने के लिये कि इस योजना से उन्हीं लोगों को लाभ होता है जिनके लिये वह बनायी गयी है, अध्यापकों और विद्यार्थियों का भी प्रतिनिधित्व होगा ?

(ग) इस योजना के लिये आर्थिक रेकरिंग और नान-रेकरिंग तखमीने क्या हैं और उस पर होने वाले खर्चे को बरदाश्त करने के लिये क्या रकम रखी गयी है ।

O. N. 17
Date
15-10-52

7. Sri Kanhaiya Lal Gupta : (a) What steps the materialization of their scheme of establishing a sanatorium for the teachers and the students ? Education Minister

(b) What will be the constitution of the committee that will run the scheme? Will the teachers and students have a representation on it to ensure that in reality those people benefit by the scheme for whom it was meant ?

(c) What are the financial recurring and non-recurring estimates of the scheme and the provisions to cover the expenditure ?

श्री हर गोविन्द सिंह—(क) शय रोगियों की चिकित्सा के लिये शासन निम्नलिखित स्थानों पर लगभग ३०० बेड्स (Beds) की व्यवस्था करने का विचार कर रही है । इन में से ७५ प्रतिशत बेड्स (Beds) अध्यापकों तथा विद्यार्थियों के लिये सुरक्षित रखे जायेंगे:—

- (१) ५० बेड्स गेठिया, नैनीताल में;
- (२) ६४ कस्तूरबा टी० बी० क्लिनिक, लखनऊ में;
- (३) ४६ बेड्स लाजपत राय हस्तपाल, कानपुर में;
- (४) २९ बेड्स डाकपथर, देहरादून में, और
- (५) १०० राज्य के पूर्वी भागों में ।

(ख) इस योजना को कार्यान्वित करने के लिये किसी समिति के नियुक्ति का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है । इसलिये यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) अनावर्तक व्यय का तखमीना लगभग १५ लाख रुपया है, जो इस योजना के लिये एकत्रित धन से वहन होगा । आवर्तक व्यय का तखमीना पहले वर्ष में सात लाख रुपया (आवर्तक) का है, जो शासन के चिकित्सा विभाग की ओर से वहन होगा ।

Sri Har Govind Singh : (a) Government propose to establish 300 beds for T. B. patients at the following places. Out of these 75 per Cent. beds will be reserved for teachers and students:

- (1) 50 beds at Gathia, Nainital;
- (2) 64 in Kasturba T. B. Clinic, Lucknow;
- (3) 46 at Lajpat Rai Hospital, Kanpur;

(4) 29 at Dakapthar (Dehara Dun), and

(5) 100 beds in a sanatorium to be established in the eastern part of the State.

(b) The question does not arise as it has not yet been proposed to constitute a committee to run the Scheme.

(c) Non-recurring cost of the entire scheme is estimated to be about 15 lakhs which will be met out of the collected funds. The recurring cost of the scheme, to be met by Government in the Medical Department is estimated at Rs.7 lakhs in the first year.

श्री कन्हैया लाल गुप्त—क्या सरकार राज्य के पूर्वी भागों में नये सेनेटोरियम बनाने का इरादा रखती है ?

श्री हर गोविन्द सिंह—इसके संबंध में प्रयत्न किया जा रहा है। अगर संभव हो सकेगा तो किया जायगा। इसके संबंध में कोई निश्चित बात नहीं कही जा सकती है कि क्या योजना है।

श्री कन्हैया लाल गुप्त—क्या सरकार को यह बात ज्ञात है कि इस सेनेटोरियम के लिये जो चन्दा अध्यापकों और विद्यार्थियों से उगाया गया था उस समय जिला अधिकारियों ने इस बात का वायदा किया था कि इस योजना को कार्यान्वित करने के लिये ऐसी समितियाँ होंगी जिनमें उनके प्रतिनिधि होंगे ?

श्री हर गोविन्द सिंह—संभव है कि ऐसा हो, लेकिन मुझे इसकी कोई सूचना नहीं है परन्तु मैं समझता हूँ कि ऐसी समितियाँ कोई अधिक कार्य नहीं कर सकती हैं।

१० सं० १८
तारीख
१-१०-५२

८—श्री कन्हैया लाल गुप्त—उत्तर प्रदेश के स्कूलों के बारे में क्या सरकार निम्नलिखित सूचना देने की कृपा करेगी :—

(१) स्वीकृत हायर सेकेंडरी स्कूलों की संख्या जिनमें :

- (क) कक्षा ११ है, और
- (ख) कक्षा ११ नहीं है,
- (ग) इम्दादी, और
- (घ) गैर इम्दादी।

(२) कुल गैर सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूलों में निम्नलिखित प्रकार के अध्यापकों की संख्या :

- (क) पोस्ट-ग्रैजुएट टीचर जो इन्टर क्लासों को पढ़ाते हैं,
- (ख) ग्रैजुएट टीचर जो इन्टर क्लासों को पढ़ाते हैं,
- (ग) ट्रेन्ड ग्रैजुएट टीचर,
- (घ) ट्रेन्ड अन्डर ग्रैजुएट टीचर,
- (ङ) जे० टी० सीज०
- (च) सी० टीज०,

(अ) अनसवालिफाइड—(क) हेड्स और (ख) असिस्टेंट मास्टर्स की संख्या जो (अ) एक वर्ष से कम काम कर रहे हों और (ब) एक वर्ष से अधिक काम कर रहे हों ?

S. No. 18
Date
15-10-52

8. Sri Kanhaiya Lal Gupta; Will the Government please supply the following information regarding the schools in Uttar Pradesh:

- (i) The number of recognised Higher Secondary Schools having (a) Class XI, (b) without Class XI, (c) Aided, (d) Unaided ?
- (ii) The number of following categories of teachers in all non-Government Higher Secondary Schools :
 - (a) Post-Graduate teachers teaching Inter classes,
 - (c) Trained Graduate teachers,
 - (d) Trained under-graduate teachers,
 - (e) J. T. Cs.,
 - (f) C. Ts.,
- (g) The number of unqualified (a) Heads, (b) Assistant Masters working for (i) less than one year (ii) more than one year ?

श्री हर गोविन्द सिंह—

(१) (क) सूचना एकत्रित की जा रही है ।	(i) (a) The information is being collected.
(ख) " " " "	(b) " " " "
(ग) " " " "	(c) " " " "
(घ) " " " "	(d) " " " "
(२) (क) सूचना एकत्रित की जा रही है ।	(ii) (a) " " " "
(ख) " " " "	(b) " " " "
(ग) " " " "	(c) " " " "
(घ) " " " "	(d) " " " "
(ङ) " " " "	(e) " " " "
(च) " " " "	(f) " " " "
(छ) " " " "	

श्री कन्हैयालाल गुप्त—ब्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्न संख्या ८ के (१) (२) में जो यह कहा गया है कि सूचना एकत्रित की जा रही है वह सूचना कब तक मिल जायगी ?

श्री हर गोविन्द सिंह—जो सूचना मांगी गई है उसके एकत्रित करने में डिपार्टमेंट को काफी समय लग सकता है और जिस प्रकार की सूचना चाहिये उसमें जितना भी समय लगेगा, कम ही होगा ।

प्रत्येक वर्ष एल० टी० पास करने वालों की संख्या

आ० सं० १६ ६—श्री कन्हैया लाल गुप्त—(क) एल० टी० किये हुये लोगों की वास्तविक संख्या क्या तारीख है जो कि प्रत्येक वर्ष ट्रेनिंग कालेजों से पास होकर निकलते हैं और राजकीय स्कूलों की वार्षिक १५-१०-५२ मोजूदा जरूरतें क्या हैं ?

(ख) क्या सरकार जे० टी० सीजे० के संबंध में उपरोक्त सूचना देने की कृपा करेगी ?

S. No. 19
Date
15-10-52

9. Sri Kanhaiya Lal Gupta : (a) What is the real number of L. Ts. the training colleges produce every year and what is the present annual requirement of the State Schools ?

(b) Will the Government supply the above information regarding J. T. Cs.

श्री हर गोविन्द सिंह—

(क) सूचना एकत्रित की जा रही है।

(ख) " "

Sri Har Govind Singh: (a) and (b) The information is being collected.

असन्तुष्ट अध्यापकों की अपीलें

१० सं० २०

तारीख

१५-१०-५२

१०—श्री कन्हैया लाल गुप्त—हायर सेकेंडरी स्कूलों के ऐसे असन्तुष्ट अध्यापकों की संख्या क्या है जिनकी दावदारी के लिये अपीलें (क) ६ महीने या (ख) एक वर्ष से अधिक सरकार या आर्बिट्रेशन बोर्ड के सामने पड़ी हुई हैं ?

O.N.20

Date

5-10-52

10. Sri Kanhaiya Lal Gupta:--What is the number of aggrieved Higher Secondary School teachers whose appeals for redress are lying with the Government or Arbitration Board for more than (a) six months, (b) one year

श्री हर गोविन्द सिंह—सूचना एकत्रित की जा रही है।

Sri Har Govind Singh: The information is being collected.

बोर्ड आफ हाई स्कूल ऐण्ड इन्टरमीडियेट एजुकेशन, उत्तर प्रदेश द्वारा
परीक्षकों की नियुक्ति

१० सं० २१

तारीख

१५-१०-५२

११—श्री कन्हैया लाल गुप्त—(क) क्या यह ठीक है कि पिछले कुछ वर्षों से बोर्ड आफ हाई स्कूल ऐण्ड इन्टरमीडियेट एजुकेशन, यू० पी० ने कुछ ऐसे परीक्षकों को नियुक्त किया है जो कि इस प्रयोजन के लिये उण्युक्त योग्यता नहीं रखते हैं और जिन्होंने नियमों के अधीन इसके लिये कभी भी प्रार्थना-पत्र नहीं दिया ? (देखिये बोर्ड का रिजोल्यूशन सं० १६, दिनांक २० दिसम्बर, १९४३।)

(ख) यदि हां, तो सन् १९५२ ई० में ऐसे परीक्षकों की संख्या क्या थी और सरकार उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करना चाहती है जो इस अनियमितता के लिये जिम्मेदार थे ?

(ग) क्या सरकार सन् १९५३ ई० की परीक्षाओं के लिये अयोग्य परीक्षकों की जगह पर योग्य परीक्षकों को रखने के लिये प्रभावपूर्ण कदम उठाने का इरादा रखती है ?

O.N.21

Date

5-10-52

11. Sri Kanhaiya Lal Gupta:--(a) Is it a fact that for the last several years many examiners have been appointed by the Board of High School and Intermediate Education, Uttar Pradesh who are not qualified for the purpose and who had never even filed their applications for it as required under rules (vide resolution no. 16, dated December 20, 1943 of the Board) ?

(b) If so, what was the number of such examiners during the examinations for the year 1952 and what action do the Government intend to take against those responsible for the irregularity ?

(c) Do the Government intend to take effective steps to replace unqualified examiners by those qualified for the examinations of 1953 ?

श्री हर गोविन्द सिंह—(क) अयोग्य व्यक्ति कोई नियुक्त नहीं किये गये। ऐसे व्यक्ति अवश्य नियुक्त किये गये जिन्होंने आवेदन-पत्र नहीं भेजे।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

Sri Har Govind Singh:--(a) No unqualified persons have been appointed. Such persons have, however, been appointed who did not apply for it,

(b) Question does not arise.

(c) Question dose not arise.

श्री कन्हैया लाल गुप्त--क्या सरकार यह अनुचित नहीं समझती कि कुछ ऐसे व्यक्ति नियुक्त किये गये हैं जिन्होंने आवेदन-पत्र नहीं दिया था, जब कि इस प्रकार के आवेदन-पत्र दिया जाना आवश्यक है?

श्री हर गोविन्द सिंह--बहुत से ऐसे सम्मानित व्यक्ति होते हैं जो आवेदन-पत्र नहीं देते हैं, इसलिये ऐसे व्यक्तियों का नियुक्त होना कोई अनुचित नहीं है।

श्री कन्हैया लाल गुप्त--क्या सरकार को मालूम है कि बोर्ड के नियमों के अन्तर्गत केवल विशेष व्यक्ति ही नियुक्त किये जा सकते हैं, जब कि कुछ साधारण व्यक्तियों को भी एक्जामिनर नियुक्त किया गया है?

श्री हर गोविन्द सिंह--ऐसा तो मुझे मालूम नहीं है, शायद माननीय सदस्य को मालूम होगा परन्तु इतना अवश्य है कि यह बिना आवेदन-पत्र के ही नियुक्त हुये हैं।

श्री कन्हैया लाल गुप्त--यदि ऐसे नियम बहुत बड़ी संख्या में प्रस्तुत किये जा सकें तो क्या सरकार आवश्यक कार्यवाही करने के लिये तैयार है?

चेयरमैन--इस तरह के हाईपोथेटिकल क्वेश्चन (hypothetical questions) नहीं पूछे जाने चाहिये, इसलिये मैं इस प्रश्न को पूछने की आज्ञा नहीं देता।

उत्तर प्रदेश म्यूनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक, १९५२--(जारी)

खंड २३

२३--मूल अधिनियम की धारा ४८ में--

(१) उपधारा (२) में--

(क) खंड (ए) के स्थान पर निम्नलिखित रक्खा जाय--

“(a) that there has been a failure on the part of the president in performing his duties, give him a warning or remove him from office as the State Government think fit, or”; और

(ख) खंड (बी) में--

(१) उपखंड (१) में शब्द और संख्या “sub-section (3) of section 14” शब्द और संख्या के स्थान पर “section 21-D and 13-D” रखे जाय।

(२) उपखंड (v) के बाद निम्नलिखित नया उपखंड (vi) के रूप में रक्खा जाय।

“(vi) been guilty of gross misconduct in the discharge of his duties”; और

यू० पी०
एक्ट २,
१९१६ की
धारा ४८
का संशोधन।

(२) उपधारा (२) के बाद निम्नलिखित नई उपधारा (३) के रूप में रक्खी जाय:-

“(3) The State Government may place under suspension a President against whom action is proposed under sub-clause (vi) of clause (b) of sub-section (2) until the proceedings are over and where a President has been so suspended he shall not for so long as the order of suspension continues the entitled—

(a) to exercise the powers or perform the duties of a President imposed upon him by or under this Act or any other enactment for the time being in force; and

(b) to take part in any proceedings of the board,.

*श्री राजा राम शास्त्री (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि खंड २३ के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक वाक्य बढ़ा दिया जाय:

“Provided that any suspension or removal will take place only when demanded by the majority of the board concerned”.

इसके संबंध में मुझे ज्यादा नहीं कहना है क्योंकि मैंने इस संबंध में कल काफी कह दिया है। इस वक्त सिर्फ यह चाहता हूँ कि कल जो बहस श्री गुरुनारायण जी के संशोधन पर हो रही थी कि गवर्नमेंट ने अपने हाथ में पावर ले ली है, तो अगर बाई मेजरिटी आफ वोट म्युनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन के खिलाफ शिकायत करते हैं तो उसमें भी चेयरमैन को जवाब देने का मौका रहना चाहिये। पहले सरकार जांच करके मालूम कर ले कि वास्तव में इसके खिलाफ कार्य करना जरूरी है और अगर साबित हो जाता है कि उसका वाकई कसूर है तभी उसके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिये। कहीं उसके साथ भी सरकारी कर्मचारियों वाला बर्ताव न हो कि जिसने चाहा और जब चाहा निकाल दिया। इसी से संबंधित मेरा यह संशोधन है।

श्री मोहन लाल गौतम (स्वशासन मंत्री)—इस पर कल काफी बहस हो चुकी है जैसा कि श्री राजा राम जी ने कहा व जो दलील उन्होंने दी है मैंने उसका भी जवाब दे दिया है और वह सदन के सामने है। जहां तक बोर्ड की मेजरिटी का सवाल है, उसको हमेशा यह अधिकार है, और यह कोई नई चीज नहीं है। इसके अलावा जो अधिकार इस अमेंडमेंट में दिये गये हैं और जिसका जिक्र कि इस अमेंडमेंट में है उसको अगर गवर्नमेंट उचित समझे, तभी हो सकता है और तभी वह हटाया जा सकता है। यह दोनों चीजें वैसे साथ ही साथ चल सकती हैं और जहां तक राजाराम जी की बात का संबंध है वह तो विधान में है ही। इसलिये मैं समझता हूँ कि इस अमेंडमेंट की कोई आवश्यकता नहीं है।

*श्री प्रभु नारायण सिंह (स्थानीय संस्थाएं निर्वाचन क्षेत्र)—अध्यक्ष महोदय, श्री माननीय मंत्री जी ने जवाब देते हुये कहा कि यह तो विधान में पहले से है ही, तो मैं उनसे यह जानना चाहूंगा कि अगर आज जनरल एंडेंट फ्रंटवाईज से चुना हुआ प्रेसीडेंट होगा, तो उस पर अगर वोट आफ नो कान्फीडेंस (vote of no Confidence) रखा जायेगा, तो उसमें बोर्ड के मेम्बरों के लिये क्या होगा। क्योंकि इस समय मैं समझता हूँ कि ऐसा कोई प्रावीजन इस बिल के अन्दर नहीं है कि उस पर वोट आफ नो कान्फीडेंस बोर्ड का रह सकता है। इस चीज का प्रावीजन नहीं है। यदि यह प्रावीजन इस बिल में है, तो इसके साथ ही साथ यह बात और भी साफ तौर से हो जाती है जबकि विधान में यह दिया हुआ है। तो इसके होने के बाद यह बात जरूरी हो जाती है कि जब कोई आदमी एंडेंट फ्रंटवाईज और जिम्मेदार लोगों से चुनकर वहां आया है और बोर्ड के पास यह पावर हो, तो यह चीज और भी अच्छी हो जाती है। तो इसके लिये इतना ही आवश्यक है कि यदि वह प्रावीजन इस बिल के अन्दर है कि वह वोट आफ नो कान्फीडेंस से हटाया जाना है,

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री प्रभु नारायण सिंह]

तो राजा राम जी ने जो प्रस्ताव रखा है, इससे यह बात और भी मजबूत हो जाती है। यदि यह बात होगी तो वहाँ जो बोर्ड का बहुमत है, उसके द्वारा यह बात होगी और आज जो प्रेसीडेंट चुना हुआ है और वह एडेल्ट फ्रैन्चाईज से वहाँ आया है, तो जब तक उन सेम्बरों की ऐसी राय नहीं हो जाती है, तब तक उसकी डिगनिटी डिफेम नहीं होनी चाहिये और बोर्ड की जब राय हो तभी उस पर ऐक्सन लिया जाना चाहिये। जहाँ तक जेनरल एलोक्यूट और चुनाव की बात है और उसमें जो बोर्ड के प्रेसीडेंट होने की बात है, तो वह पहले भी जेनरल एलोक्यूट से होता था और इसी तरह से जो अब प्रेसीडेंट होंगे वे भी जेनरल एलोक्यूट और चुनाव से होंगे जो प्रेसीडेंट डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के होते थे उनको डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अन्दर चुनाव द्वारा चुना जाता था। आजकल थोड़े से ऐसे प्रेसीडेंट हो गये हैं जिनके केस में ऐसा न हुआ हो। कुछ को बोर्ड ने चुना हुआ है, लेकिन जो अन्य बोर्ड हैं उनमें जेनरल चुनाव किया गया था। खैर यह चीज किसी तौर से भी हो, मैं यहाँ उस पर बहस नहीं करता, लेकिन इसके लिये और कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का वह प्रेसीडेंट हो जब तक कि उनकी पावर सेपरेट न करदी जायें। तो इस चीज को भी मेजारिटी के पास जाना चाहिये और मेजारिटी का उस पर कान्फीडेंस होना जरूरी है। इसलिये आज तक जो भी कानून है डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मामले में, वह बिना मेजारिटी के, इस तरह का नो कान्फीडेंस मोशन पास नहीं कर सकती है। अगर मेजारिटी नो कान्फीडेंस पास करे तो चेयरमैन हटाया जा सकता है। अगर स्पूनिसिपलिटिज के चेयरमैन के विरुद्ध मेजारिटी नो कान्फीडेंस का प्रस्ताव करती है तो वह भी हटाया जा सकता है। जिस बात के लिये यह अमंडमेंट है वह प्रावीजन तो पहले से ही मौजूद है। स्पूनिसिपल बोर्ड का चेयरमैन जिसको अब प्रेसीडेंट कहेंगे गवर्नमेंट हटा सकती है। पहले तो मेजारिटी हटा ही सकती थी, लेकिन इसके अलावा अगर फेल्योर आफ ड्यूटी एंड ग्रास मिसकन्डक्ट हो, तो ऐसी हालत में गवर्नमेंट हटायेगी। यह प्रावीजन अलग है। जैसे एक बोर्ड है और उसका एक चेयरमैन है। नाम में नहीं लूंगा वाक्य के तौर पर कहता हूँ। वह रिश्तत लेता है और स्टाफ के लोग उसके खिलाफ लिख कर भेजते हैं और कहते हैं कि अगर इन्क्वायरी की जाय तो हम लोग उस रिश्तत को साबित कर सकते हैं। अब जब उसके खिलाफ तहकीकात की जाती है तो मुलाजिमान को हिम्मत नहीं है कि चेयरमैन के खिलाफ गवाही दे सके और जब तक कि उसको अस्थायर रहता है वह अपना कागज ठीक कर लेता है और गड़बड़ी भी करता है। यह भी देखने में आया है। मेजारिटी में ऐसा होता है कि चेयरमैन के हटने से स्पूनिसिपल बोर्ड का ऐडमिनिस्ट्रेशन खराब हो जाता है। और जब वह चुना जाता है अगर हटा दिया जाय तो कुछ सुरक्षित भी होती है वह फिर खड़ा नहीं होता है इसलिये तमाम बातों को देखने से हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि सिर्फ मेजारिटी ही पर डिपेंड रहना काफी नहीं है। इसलिये २ बातें रखी गई हैं। फेल्योर आफ ड्यूटी एंड ग्रास मिसकन्डक्ट ऐसा न होगा कि किसी साहब ने मिनिस्टर साहब से कह दिया और वह किसी पार्टी फीलिंग के कारण हटा दिया जायेगा। मैं कल भी कह चुका हूँ कि बहुत से मामले हाई कोर्ट में पेश हो चुके हैं और फाईल्स देखी जा चुकी हैं और जितने केसेज हुये सब बहाल रहे इसलिये आप समझ लीजिये कि जो प्रोसेस है वह ठीक है और इस अमंडमेंट से कोई फायदा न होगा। इन शब्दों के साथ मैं इसको अपोज करता हूँ।

चेयरमैन—प्रश्न यह है कि खंड २३ के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक वाक्य बढ़ा दिया जाय :

“Provided that any suspension or removal will take place only when demanded by the majority of the board concerned.”

श्री प्रभु नारायण सिंह—मैं प्रस्ताव करता हूँ कि प्रस्तावित धारा ४८ की प्रस्तावित उपधारा (३) के अन्त में निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़ दिया जाय :

“*Explanation*—The proceedings of inquiry shall be finished within 3 months of the date of suspension and a fresh election if necessary, be held within the next three months.”

मैं चाहता हूँ कि दफा २३ जो इस अर्मेंडिंग बिल में है, उसके दूसरे हिस्से में यह एक्सप्लेनेशन बढ़ा दिया जाय। दफा २३ खासतौर से ग्रामरीजिनल ऐक्ट की दफा ४८ है। इस सिलसिले में मैं यह चाहता हूँ कि इस सस्पेंशन की जो इन्क्वायरी हो वह तीन महीने के अन्दर खत्म हो जाये। और साथ ही साथ यदि यह साबित हो जाये कि सस्पेंशन किया जाना चाहिए तो इस फैसले के तीन महीने बाद ही चुनाव भी हो जाना चाहिए। यह संशोधन मैंने इसलिए रखा है कि ऐसा अक्सर देखा जाता है। एकाध उदाहरण भी मेरे सामने है कि जब एकाध चेयरमैन के ऊपर नो कांफिडेंस पास हुआ तो उसको गजब करने में करीब तीन महीने या चार महीने की देर लगी। मेरे कहने का यह मतलब नहीं है कि हमारे माननीय मंत्री जी की वजह से उसमें देर लगी। यह सम्भावना हो सकती है कि यह चीज मिनिस्टर की एविलिटी और इन्टेग्रिटी पर डिपेंड करे कि वह कैसे मसले को डिस्पोज़ आफ़ करता है लेकिन इसके साथ ही कोई न कोई प्रतिबन्ध जरूर होना चाहिये कि इन्क्वायरी जल्द से जल्द समाप्त हो जाये। नहीं तो कोई प्रतिबन्ध न होने की वजह से सालों इन्क्वायरी चलती रह सकती है। यदि सालों इन्क्वायरी चलती रहती है तो वह बोर्ड जिसका चेयरमैन सस्पेंड होता है वर्षों तक दूसरा प्रेसिडेंट प्रतिष्ठित करने से महरूम रहेगा। इसलिये मैं चाहता हूँ कि इन्क्वायरी तीन महीने के अन्दर खत्म हो जाये और यदि फैसला यह होता है कि उसको हटा देना चाहिये तो जिस ताराख को यह फैसला होता है उसके तीन महीने के अन्दर चुनाव हो जाना चाहिये।

श्री मोहन लाल गौतम—जहां तक इन्क्वायरी को तीन महीने में खत्म करने की बात है, वैसे तो यह बड़ी सधी-सादी बात मालूम पड़ती है लेकिन इससे बड़े खतरनाक नतीजे निकल सकते हैं। अगर किसी एक्ज्यूड को मालूम हो कि कानून यह है कि तीन महीने के बाद इन्क्वायरी खत्म हो जायेगी तो इसका बहुत बुरा नतीजा निकल सकता है। अगर उस एक्ज्यूड ने डिलेइंग टैक्टिक्स की और हाई कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में गया और तीन महीने में इन्क्वायरी खत्म नहीं हुई तो कितने अच्छे तरीके से आपने उस एक्ज्यूड को मौका दे दिया कि चाहे जितने सीरियस चार्जज उसके खिलाफ़ हों फिर उसके खिलाफ़ इन्क्वायरी नहीं हो सकती। और एक दफा इन्क्वायरी करने के बाद फिर दोबारा इन्क्वायरी कर सकेंगे या नहीं, यह भी सोचने की बात है। मेरा खयाल है कि नहीं कर सकेंगे। किसी वजह से अगर इन्क्वायरी नहीं हुई और डिलेइंग टैक्टिक्स उसने इस्तेमाल किया तो आप उसको बरी कर देते हैं और फिर आपके हाथ कट जाते हैं और आप उसके खिलाफ़ कुछ नहीं कर सकते। मैं इस बात से सहमत हूँ कि इन्क्वायरी अगर हो तो जल्द से जल्द हो। कोई आदमी अगर सस्पेंड हो तो यह न हो कि वह वर्षों तक सस्पेंड ही रहे। कोई आदमी अगर सेट साइड हुआ है तो चुनाव भी जल्द से जल्द हो जाना चाहिये। पिछली बातों को अगर आप देखेंगे तो मालूम होगा कि कितने ही प्रेसिडेंट्स ने इस्तीफ़ा दिया है, उनके इस्तीफ़ा देने के बाद ही कितनी जल्दी चुनाव हुये हैं, शायद हफ्ते दो हफ्ते में चुनाव हो गये हैं। अगर कोई खास मिसाल उनके सामने हो तो मैं यह कह सकता हूँ कि अगर देर होती है तो देर न होना चाहिये लेकिन इस तरीके पर बंधन लगाने से बहुत सी खराबियां हो सकती हैं।

श्री गोविन्द सहाय (स्नातक निर्वाचन क्षेत्र)—इन्फ़ारमेशन के तौर पर मैं यह

श्री मोहन लाल गौतम—आप इनफ़ारमेशन नहीं दे रहे हैं। आप तो अपनी राय दे रहे हैं।

श्री प्रभुनारायण सिंह—जहां माननीय मंत्री जी निर्णय की बात कहते हैं कि इन्क्वायरी जल्दी से जल्दी ख़त्म कर देनी चाहिये। यदि सचमुच वे इससे इत्फ़ाक़ करते हैं तो इस समय आर्डिनरी कोर्स में इस अमैंडमेंट को मंजूर कर लें तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। मंत्री जी ने जो कुछ कहा उसको मैं ठीक समझता हूं। यदि मेरे शब्द बढ़ा दिये जायें और इस संशोधन को मान लिया जाय तो मंत्री जी को लाभ ही होगा।

श्री मोहन लाल गौतम—इससे मुकदमेबाजी बढ़ सकती है और कोई दूसरा इससे फायदा नहीं होगा।

चेयरमैन—The question is that the following explanation be added after the proposed sub-section (3) of section 48.

“Explanation—The proceedings of enquiry shall be finished within three months of the date of suspension and a fresh election, if necessary, be held within the next three months”.

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

चेयरमैन—प्रश्न यह है कि खंड २३ बिल का भाग बना रहे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २४

यू० पी० एक्ट
२, १९१६ की
धारा ५७ का
संशोधन।

२४—मूल अधिनियम की धारा ५७ में उपधारा (२) के बाद निम्नलिखित नई उपधारा २-ए के रूप में रखी जाय :

“(2-A) Every board shall, if so required by the State Government employ in addition to or in place of the Accountant, an Accounts Officer nominated by the State Government either separately local or jointly with one or more than one board or any other authority on the terms and conditions as may be prescribed by the State Government from time to time.”

श्री कुंवर गुरु नारायण (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—I beg to move that in the proposed section (2-A), line 1 and 2, Delete the words “If so required by the state Government” and in lines 2 and 3 delete the words “or in place of.”

श्रीमान् जी, इस संशोधन के रखने का मेरा अभिप्राय यह है कि सरकार ने एकाउन्ट्स आफिसर रखने के लिये निश्चय किया है। एकाउन्ट्स आफिसर म्यूनिसिपल बोर्ड रखे। सरकार ने जो यह धारा संशोधित की है उसमें उन्होंने यह लिखा है कि हर बोर्ड एकाउन्ट्स आफिसर रखेगा। तो मेरे कहने की मंशा यह है और मैं समझता हूं कि सरकार ने जो यह एकाउन्ट्स आफिसर को रखने के लिये जो कदम रखा है वह बहुत ही ठोस कदम है। म्यूनिसिपैलिटीज़ में जो बहुत सी गड़बड़ी होती है और भ्रष्टाचार होता है वह रक सकता है। मैं चाहता हूं कि जब सरकार ने एकाउन्ट्स आफिसर रखने के लिये निश्चय किया है तो फिर यह चीज़ हटा दी जाय कि सरकार कहीं पर रखे और कहीं पर न रखे। मैं चाहता हूं कि यह कम्पलसरी कर दिया जाय। इससे बोर्ड का काम अच्छा होगा जो गबन होता रहा है उससे छुटकारा मिल जायेगा। इसमें और कोई विशेष बात नहीं है। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार करेंगे।

श्री मोहन लाल गौतम—जहां तक इस संशोधन का सम्बन्ध है, उन्होंने इस बात को मान लिया है कि एकाउन्ट्स आफिसर की जरूरत है। जो हिसाब में गड़बड़ी होती है वह इससे दूर हो जायेगी। प्रश्न इस समय इतना ही है कि क्या इस समय एक साथ में कानून पास करके तमाम बोर्डों को कह दें कि हर एक बोर्ड एकाउन्ट्स आफिसर रखे। जिस तरह से आपने संशोधन को रखा है वह यह है कि मजबूरन सब को रखना पड़ेगा। लेकिन एकाउन्ट्स आफिसर वहीं रखा जा सकता है जब तक गवर्नमेंट जरूरी न समझे। हर एक म्युनिसिपल बोर्ड की आर्थिक व्यवस्था अच्छी नहीं है। एकाउन्ट्स आफिसर को हर जगह रखने का बात की जायेगी तो या तो बहुत थोड़ी तनख्वाह वाले हों जायेंगे या वे सब रख नहीं पायेंगे। वह चीज जो माननीय गुरु नारायण जी चाहते हैं कि वहां का हिसाब किताब बेहतर हो तो मैं चाहता हूं कि उसका रास्ता निकाला जाय। इरादा यह है कि कुछ म्युनिसिपल बोर्ड्स में शुरू में एकाउन्ट्स आफिसर रखे जायें और उनका तजुर्बा देखा जाय और फिर दूसरे म्युनिसिपल बोर्ड्स की आर्थिक अवस्था देख कर जहां-जहां जरूरी समझा जाय वहां एकाउन्ट्स आफिसर रख दिये जायें। उद्देश्य वही है कि एकाउन्ट्स सही हों। अगर कुंवर गुरुनारायण जी के संशोधन को हम मंजूर कर लेते हैं तो मुसीबत और मुश्किल हो जायेगी। इसलिये मुझे अफसोस है कि मैं इसको मंजूर नहीं कर सकता।

श्री कुंवर गुरु नारायण—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो अभी विचार माननीय मंत्री ने प्रकट किये हैं मैं तो एकाउन्ट्स आफिसर से यह मतलब समझा था कि एकाउन्ट्स आफिसर इन म्युनिसिपल बोर्ड्स के एकाउन्ट्स को सुपरवाइज करेंगे और एकाउन्ट्स तो होंगे ही। यह चीज तो इस धारा में लिखी हुई है कि एकाउन्ट्स आफिसर रखे जायेंगे। यह चीज साफ तौर से इसमें दी हुई है कि ज्वाइन्टली या सेपरेटली म्युनिसिपल बोर्ड्स द्वारा रखे जायेंगे। पर यह कोई अनिवार्य नहीं है कि हर म्युनिसिपल बोर्ड्स में एकाउन्ट्स आफिसर रखे ही जायें लेकिन एकाउन्ट्स आफिसर का तात्पर्य मैं यह समझा कि वह एकाउन्ट्स के सेक्शन को सुपरवाइज करेंगे। यह मैं अभी तक समझा था। मैं चाहता हूं कि एकाउन्ट्स आफिसर हर हालत में जरूर रखे जायें। मैं समझता हूं कि यही उद्देश्य भी इन एकाउन्ट्स आफिसरों के रखने का है। बहरहाल, मेरा यह सुझाव है फिर जैसा आप उचित समझें, करें।

श्री मोहन लाल गौतम—एकाउन्ट्स आफिसर की जितनी जिम्मेदारी कुंवर गुरुनारायण ने समझा है, उससे वह कुछ अधिक है। यह भी हो सकता है कि बड़ी-बड़ी म्युनिसिपैलिटीज में एकाउन्ट्स आफिसर रखे जायें और छोटी में न रखे जायें। लेकिन एकाउन्ट्स आफिसर, जो खर्च करने की बात है, उसको देखेगा और अगर चेयरमैन भी किसी में कुछ खर्च करता है तो इस पर भी वह राय जाहिर कर सकता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि करीब-करीब वह एक एकाउन्टेन्ट की ही जिम्मेदारी लेता है और सिर्फ सुपरविजन का ही काम उसका नहीं रहता है। इसलिये मैं इसको मंजूर नहीं करता हूं।

चेयरमैन—The question is that in the proposed section (2-A), line 1 and 2, the words "if so required by the State Government" be deleted and in lines 2 and 3 the words "or in place of" be deleted.

... (प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री राजा राम शास्त्री—Sir, I beg to move that in the proposed section (2-A) line 2 the words "in consultation with the board concerned" be inserted between the words "Government" and the word "employ."

चेयरमैन—यह अपने संशोधन का एक भाग प्रस्तुत कर रहे हैं पूरा संशोधन नहीं प्रस्तुत कर रहे हैं।

श्री मोहन लाल गौतम—मेरा तो यह ख्याल है कि यह अमेंडमेंट आउट ऑफ आर्डर है क्योंकि इसमें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जिक्र है। आधा हिस्सा है और आधा नहीं है तो इस तरह का अमेंडमेंट मूव नहीं किया जा सकता है।

चेयरमैन—मैंने कल यह रूलिंग दी थी कि इस विधेयक में किसी नई व्यवस्था का आयोजन नहीं किया जा सकता। जहाँ तक उसका ताल्लुक है वह विधेयक के स्कोप के बाहर है लेकिन किसी संशोधन का अगर कोई हिस्सा विधेयक के स्कोप के अन्दर हो तो उसको प्रस्तुत किया जा सकता है। इसलिये इसमें से जितना प्रस्तुत किया जा सकता है वह प्रस्तुत किया जा रहा है।

श्री हर गोविन्द सिंह—Does it mean that we can break the amendment in two parts, accept the one and leave the other ?

चेयरमैन—We can break the amendment in two parts. If the Chair has ruled that one part is out of order, it does not mean that the other part also becomes automatically out of order. If, of course, it is so joined that one part cannot be separated from the other, then the other part would also become out of order. Does the Minister mean that the two parts cannot be taken separately ?

श्री हरगोविन्द सिंह—Sir, I think the amendment stands as a whole and cannot be taken in parts. If the mover had meant that any amendment can be broken into parts, he should have given notice of two amendments.

चेयरमैन—If an amendment relates to one clause, then a number of items that relate to that particular clause can be added in one amendment and it is quite within the competence of the House to accept one part and reject the other. It is not necessary that the amendment should be accepted as a whole and a part can be accepted.

श्री मोहन लाल गौतम—If that is your order, Sir, that the House can accept a part of the amendment and reject the other part of the amendment, would you put the amendment before the House for voting in parts separately, or would you put the to entire amendment before the House. How can the House accept a part and reject the other, unless the Chair puts the amendment in parts.

चेयरमैन—It is within the competence of the Chair to put any amendment in the manner it thinks best. If necessary, the Chair can divide the amendment before putting it before the House.

श्री राजाराम शास्त्री—माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ी खुशी है कि मुझे यह मौका मिला कि मैं अपने पहिले संशोधन को पेश कर सकूँ।

मैं यह चाहता हूँ कि शब्द "Government" और "employ" के बीच में शब्द "in consultation with the board concerned" जोड़ दिया जाये। इस संशोधन को पेश करने का मेरा मतलब यह है कि एकाउन्ट्स आफिसर जो गवर्नमेंट नामिनेट (नियुक्त) करेगा उसकी बाबत इस तरह की संभावना हो सकती है कि गवर्नमेंट किसी को एकाउन्ट्स आफिसर नामिनेट करती है और बोर्ड उसको ठीक नहीं समझता तो ऐसी हालत में एकाउन्ट्स आफिसर को किस का कान्फीडेंस गेन करने की जरूरत है म्युनिसिपल बोर्ड का या गवर्नमेंट का। अगर एकाउन्ट्स आफिसर को बोर्ड में काम करना है तो म्युनिसिपल बोर्ड का कान्फीडेंस गेन करना बहुत जरूरी है। मुझे ऐसा आभास होता है कि कई जगहों पर इक्जीक्यूटिव आफिसर के बारे में झगड़ा हो चुका है। म्युनिसिपल बोर्ड नहीं चाहता है कि यह

आफिसर रखा जाय लेकिन सरकार उसको रखना चाहती है तो इस तरह से दोनों में जगड़ हो जाता है। मैं चाहता हूँ कि जो एकाउन्ट्स आफिसर आप रखना चाहते हैं उसके बारे में यह मुविजा हो कि आप उसको बोर्ड को सलाह से रखें। मैं यह नहीं कहता कि सरकार उस को न रखे लेकिन जिस बोर्ड में रखा है उसकी राय की भी जरूरत है। मेरा संशोधन स्पष्ट है वह माननीय मंत्री जी की समझ में आ जायेगा और वह इसे स्वीकार भी करेंगे।

श्री मोहन लाल गौतम—यह जो एकाउन्ट्स आफिसर को अप्वाइन्ट करने का मकसद है और जिस के बारे में श्री कुंवर गुरु नारायण जी काफी बोल चुके हैं उस का मतलब ही खत हो जायेगा अगर राजाराम जी का संशोधन मंजूर हो जाये। यद्यपि उन के संशोधन का एक हिस्सा आउट आफ आर्डर हो गया लेकिन उनके ख्याल से ऐसा जाहिर होता है कि वह सेलेक्टेड बाइ दि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पब्लिक सर्विस कमीशन (Selected by the local self-Government Public Service Commission) से चाहते हैं। वह बोर्ड के ऊपर उसका सेलेक्शन रखना चाहते हैं। जब आप बोर्ड को सेलेक्शन की फाइनल अप्रारिटी देते हैं तो बोर्ड उसको किसके बाड़ी के लिये सेलेक्ट करेगा। ऐसा करना शलत होगा। जब बोर्ड को यह अधिकार रहेगा तो बोर्ड जिसे चाहता है उसी का नाम सजेस्ट करेगा क्योंकि हमारे देखने में आया है कि बोर्ड में सिफारिश सिर्फ उन लोगों की होती है जिन को वह जानते हैं या जो उस शहर के होते हैं। जब इस तरह से अप्वाइन्टमेंट बोर्ड के हाथ में हो जायेगा तो जो खराबी वह दूर करना चाहते थे, नहीं हो सकती इसलिये मैं इसे मंजूर नहीं कर सकता।

श्री प्रभु नारायण सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन राजाराम जी ने रखा है उसका मैं समर्थन करता हूँ। मैं यह बात साफ कर देना चाहता हूँ कि आज यह चीज साफ तौर से है कि पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में यह दृष्टि कोण बन चुका है कि उसे इम्पारशियल होना चाहिये। इसलिये यहाँ भी हम चाहते हैं कि वह पब्लिक सर्विस कमीशन से अप्वाइन्ट किया जाय। चूंकि इस अमेंडमेंट का कुछ हिस्सा आउट आफ आर्डर हो गया है लेकिन हम जरूर महसूस करते हैं कि यदि पब्लिक सर्विस कमीशन से अप्वाइन्टमेंट की बात मान ली जाय तो मैं समझता हूँ कि राजाराम जी भी अपने संशोधन को वापस ले लेंगे। यदि आप इसे नहीं मानते हैं तो यह संशोधन जरूर मान लेना चाहिये कि बिना बोर्ड की राय के किसी तरह से अप्वाइन्टमेंट नहीं होना चाहिये।

श्री निजामुद्दीन (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)—माननीय चेयरमैन साहब, राजा राम साहब ने जो संशोधन पेश किया है मेरा ख्याल है कि इस में दो दिक्कतें हैं। पहला यह कि जिस परपज के लिये यह आफिसर मुकर्रर करना है वह चला जाता है। जैसा कि ऊपर आ चुका है कि जहाँ पर जरूरत होगी वहीं यह आफिसर रखा जायेगा। उस के माने यह है कि जिस बोर्ड की हालत पर कुछ शक होगा या उसकी हालत खराब हो गयी हो और वहाँ का अकाउन्ट ठीक न हो रहा हो और गड़बड़ी हो रही हो तो ऐसी जगह पर उस की जरूरत पड़ेगी। वहाँ पर ऐसा आफिसर रखा जायेगा जो जाकर उस बोर्ड की हालत को देख सके। अगर आप बोर्ड से मशविरा करते हैं तो उसका नतीजा यह होगा कि जो सरकार का मकसद है वह नहीं हो सकता। ऐसी हालत में वे कभी नहीं चाहेंगे कि ऐसा आफिसर हमारे यहाँ रखा जाय जो कि खर्चे को देखे। तो जो चीज शास्त्री जी इस कानून में रखना चाहते हैं उस की जरूरत नहीं है। जब आप समझते हैं कि वह बिलकुल इन्डीपेंडेंट हो और किसी के पक्ष में न हो तो यह शर्त लगाना शलत है। माना कि वहाँ का चेयरमैन नहीं चाहता है कि ऐसा आफिसर रखा जाय लेकिन सरकार उस को रखना चाहती है तो इससे यह मतलब निकलता है कि अकाउन्ट्स आफिसर न रखा जाय। ऐसी सूरत में मैं कहूँगा कि आप ने जो यह संशोधन "in consultation with the board concerned" रखा है, शलत है।

श्री राजाराम शास्त्री—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ कि सरकार की तरफ से जो संशोधन पेश हुआ उस का उद्देश्य यह है कि सरकार उसको नामिनेट करे। हमारा मंशा यह था कि सरकार उसको नामिनेट न करे बल्कि कोई दूसरी ताकत उसको नामिनेट करे तो फैसला ज्यादा इम्पार्शल होगा। इसके लिये यह कहा गया कि पब्लिक सर्विस कमिशन इस काम को करे तो ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि अगर उसको कोई दूसरी ताकत करेगी तो ज्यादा अच्छा फैसला दे सकेगी।

चेयरमैन—प्रश्न यह है कि प्रस्तावित उपधारा (२) की पंक्ति २ में शब्द "Government" और शब्द "employ" के बीच शब्द "in consultation with the Board concerned" बढ़ा दिये जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

चेयरमैन—प्रश्न यह है कि खंड २४ बिल का भाग बना रहे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २५-२७

यू० पी० ऐक्ट २,
१९१६ की धारा
६०-बी का संशोधन

२५—मूल अधिनियम की धारा ६०-बी में से शब्द "Education" निकाल दिया जाय।

यू० पी० ऐक्ट २,
१९१६ की धारा
६४ का संशोधन।

२६—मूल अधिनियम की धारा ६४ में शब्द "Executive officer" के बाद एक क्लॉज जोड़ दिया जाय और उसके बाद शब्द "Accounts officer" रखा जाय।

यू० पी० ऐक्ट २,
१९१६ की धारा
६८ का संशोधन।

२७—मूल अधिनियम की धारा ६८ की उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय।

"(1) A Board may, by special resolution, and if so required by the State Government, shall, appoint the principal officers of its technical departments such as Civil Engineer, Assistant Civil Engineer, Electrical Engineer, Assistant Electrical Engineer, Water Works Engineer, Assistant Water Works Engineer, Electrical and Water Works Engineer, Assistant Electrical and Water works Engineer qualified Overseer or Sub-Overseer and also Secretary and Superintendent or Lady Superintendent of Education."

चेयरमैन—प्रश्न यह है कि खंड २५, २६ और २७ बिल का भाग बने रहें।
(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २८

यू० पी० ऐक्ट २, १९१६
की धारा ६९ का संशोधन।

२८—मूल अधिनियम की धारा ६९, धारा ६९ की उपधारा (१) के क्लॉज में परिगणित की जायगी और उसके बाद निम्नलिखित उपधारा (२) के रूप में जोड़ दिया जाय:

"(2) The State Government may suspend any officer appointed under sub-section (1) of section 68 pending decision of an appeal and may alter, amend or vary the order of the board."

श्री राजाराम शास्त्री—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि प्रस्तावित उपधारा (२) निकाल दी जाय।

इस धारा में यह कहा गया है कि अगर म्युनिसिपल बोर्ड समझता है कि किसी आफिसर ने गलती की है तो उसको किसी प्रस्ताव के जरिये से या किसी और जरिये से दंड दे सकते हैं। किन्तु गवर्नमेंट फिर से यह पावर लेना चाहती है कि वह चाहे तो उसके हुक्म को बदल सकती है, संशोधित कर सकती है और जैसा चाहे कर सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका परिणाम यह होगा कि जो बोर्ड के आफिसर होंगे, उनकी निगाह बोर्ड की अपेक्षा सरकार की तरफ ज्यादा रहेगी। ऐसी भी परिस्थितियां हो सकती हैं कि अगर म्युनिसिपल बोर्ड ने अपने किसी आफिसर को दंडित किया और सरकार की तरफ से कोशिश होती है कि नहीं, हम इस आर्डर को बदलते हैं, तो निश्चित बात है कि सरकारी आफिसर यह समझने लगेगा कि उसको पूरा अधिकार है और फिर वह बोर्ड के हर मामले में दखलअन्दाजी करना शुरू कर देगा।

दूसरा इसका परिणाम यह होगा कि जब सरकार को अधिकार होगा तो आफिसर जिसको कि दंडित किया गया है वह बोर्ड की कोई परवा न करके सरकार के पास दंड धूप करेगा और फिर अगर कोई बात बोर्ड और सरकार के बीच में पैदा हो गई तो ऐसे मौके पर सरकार सारी ताकत अपने हाथ में लेना चाहती है और इस तरह से बोर्ड के हाथ से ताकत निकल जाती है। अगर बोर्ड को दंडित करने का अधिकार नहीं रहेगा तो इससे कोई अच्छी भावना आप नहीं पैदा करेंगे। इस बात को देखते हुये मुझे यह कहना है कि जहां पर सरकारी डिपार्टमेंटों का सवाल आता है तो डिपार्टमेंट अगर किसी आफिसर को सजा देता है तो हम लोग डिमांड करते हैं कि उस मामले को अदालत के सामने पेश किया जाय, वहां तो सरकार यह कहती है कि सरकारी कर्मचारियों के बीच में और सरकार के बीच में हम किसी को फौसले को मानने के लिये तैयार नहीं हैं और जो जजमेंट सरकार ने किया है वह ठीक ही किया है। लेकिन अगर बोर्ड अपने किसी आफिसर को दंडित करना चाहता है तो उसके लिये हुक्मत पावर अपने हाथ में करना चाहती है। मैं समझता हूं कि यह तरीका उचित नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर सरकारी कर्मचारियों को दंडित करने के लिये वही व्यवस्था रखिये जैसे कि लैबर वगैरह में इस ऐक्ट को देखने से मुझे यह भालूम पड़ता है कि सरकार ऐसा महसूस कर रही है कि जो ऊंचे बोर्ड हैं, उनकी ताकत अधिक से अधिक अपने हाथ में सीमित कर दिया जाय और इतने से ही ऐडमिनिस्ट्रेशन अच्छा हो जायेगा। लेकिन आप यकीन मानिये, इससे जितनी भी ऐसी संस्थाएं हैं, वह शक्तिहीन हो जायेंगी। अगर इसी प्रकार उनकी ताकत छिनती चली जायेंगी। इस तरह के संशोधन करने से भी उनका प्रबन्ध अच्छा नहीं होगा। इसलिये मैं यह चाहता हूं कि यह दफा निकाल दी जाय।

श्री मोहन लाल गौतम—माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस है कि श्री राजाराम जी ने या तो धारा को अच्छी तरह से पढ़ा नहीं है या अगर पढ़ा है तो वह समझे नहीं हैं। इसमें यह चीज नहीं है कि गवर्नमेंट डिसमिस करने का अधिकार अपने हाथ में लेना चाहती है। जो सवाल है वह यह है कि बोर्ड ने किसी के खिलाफ कार्यवाही की तो उसकी अपील सरकार के पास आयेगी जैसा कि अब भी होता आया है और वही चीज कन्टीन्यू करेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो इस चीज को माननीय सदस्य अपने दिमाग से निकाल दें कि सरकार पावर्स को रिजर्व करना चाहती है। अपील सुनने की जो पावर अभी तक सरकार को है वह अपील सुनने की पावर ज्यों की त्यों मौजूद रहेगी सिर्फ इतना है कि इस चीज में जो अपील आई है कि किस बिना पर बोर्ड में सजा मिली है तो उतने समय के लिये सरकार सस्पेंड कर सकती है। मसलन वाटर वर्क्स के हेड क्लर्क के खिलाफ अपील आई, तो अगर गवर्नमेंट उचित समझती है कि उसको सस्पेंड रक्खा जाय ताकि वह कोई कागजात वगैरह इधर से उधर न कर दे और किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो जाय तो जब तक उसका फौसला होता है सिर्फ उतने देर तक के लिये सरकार ने सस्पेंड करने का अधिकार लिया है और यह उचित ही है। बाकी जितनी बातें हैं वह पहले की तरह से जारी रहेंगी। इसलिये मैं समझता हूं कि प्रस्तावक महोदय अपना संशोधन वापस ले लें तो ठीक हो।

श्री राजाराम शास्त्री—माननीय अध्यक्ष जी, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि हुकूमत जितनी पावर अपने हाथ में ले रही है, मंत्री जी को वह कम ही मालूम पड़ रही है। इतना समझते हुये भी वह हम को बता रहे हैं कि हम इसको समझे नहीं हैं। मान लिया जाय कि अपील आपके पास आई और आप उस पर विचार कर रहे हैं, तो जब तक उस पर फैसला न हो जाय और पावर आपके हाथ में है कि आप चाहे तो उसे बदल दें, आल्टर कर दें या उसमें अमेंडमेंट कर दें और जिस तरह से चाहें उस पर फैसला कर सकते हैं। तो जब अपील हो रही है और उस पर सुनवाई हो रही है, तो उस वक्त यह बात करना मुनासिब नहीं है यह बात मेरी समझ में नहीं आती है। मैं आपके सामने यह बतलाना चाहता हूँ कि बाद में इसका क्या असर पड़ सकता है। आपके हाथ में जब ऐसी पावर होगी कि अपील हो और उसकी सुनवाई हो, तो फिर उसपर इन्फ्लूएन्स डालने की कोशिश की जायेगी। मान लीजिये किसी मौक़े पर कोई चीज़ आई और माननीय मंत्री जी किसी को फैसले में इन्ट्रस्टेड हैं और म्युनिसिपल बोर्ड के मेम्बर ऐसा समझते हैं, तो वह ठीक से नहीं हो सकता है। इस तरह से बीच में पावर लेने से आप किसी चीज़ को घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं और अपने हाथ में और भी पावर इस किस्म की ले सकते हैं।

श्री मोहन लाल गौतम—हम इस तरह से पावर नहीं ले रहे हैं, यह आपको गलत-फहमी हो गई है।

श्री राजा राम शास्त्री—अगर यह पावर आपके अन्दर पहले से है, तो इसमें फिर अमेंडमेंट करने की जरूरत क्या है। जिस वक्त अपील हो रही है, सुनवाई हो रही है, तो उसके बीच में आप पावर न लें। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अपील के बीच में आप कोई चीज़ घटाना और बढ़ाना चाहें, यह तो मुझे मुनासिब नहीं मालूम होता है। जो इस तरह की छोटी संस्थाएँ हैं, अगर आप उनकी ताकत मानते हैं और आपने उनकी अधिकार दिया है तो उनकी ताकत को फिर आप मत लीजिये। अगर किसी ने गलती की है तो उसको बंडित करने का और सजा देने का अधिकार और इस तरह की पावर उन्हीं के हाथ में होनी चाहिये। अगर आप अपने हाथ में यह पावर लें लेते तो यह बहुत गलत काम होगा।

चेयरमैन—प्रश्न यह है कि खंड २८ बिल का भाग बना रहे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २६

२६—मूल अधिनियम की धारा ७३ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"73. (1) The power to appoint, grant leave of absence, punish, dismiss or control any servant on the educational establishment of the board—

- (a) on or drawing a salary not exceeding Rs.40 p.m. or in a city Rs.50 p.m.;
- (b) on or drawing a salary exceeding Rs 40 p.m. but not exceeding Rs.50 p.m. or in a city Rs.50 p.m. but not exceeding Rs75 p.m., and
- (c) any other servant other than the Superintendent or Lady Superintendent of Education,

shall be exercised—

- (i) in the case of (a) and (b) above by the Superintendent or Lady Superintendent of Education, as the case may be, and where there is no such Superintendent or Lady Superintendent, by the Education Committee Subject to such conditions or restrictions as may be imposed by the board:

Provided that in the case of appointments of employees under clause (b), where these powers are to be exercised

यू० पी० ऐक्ट
२, १९१६ की
धारा ७३ का
संशोधन

Appointment
etc. of ser-
vants on the
educational
establishment

by the Superintendent or Lady Superintendent, all such appointments shall be subject to the approval of the Chairman, Education Committee;

(ii) in the case of (c) above by the Education Committee of the board subject to such conditions or restrictions as the board may by resolution imposed in his behalf.

(2) An appeal—

(a) in the case of an order of dismissal or removal or any other punishment passed by the Superintendent or Lady Superintendent shall lie to the Chairman of the Education Committee;

(b) in the case of an order of dismissal or removal passed by the Education Committee to the State Government; and

(c) in the case of an order of any other punishment passed by the Education Committee to the Prescribed Authority.

(3) The appeal shall be presented within one month of the date on which the order of punishment is communicated to the person in respect of whom the order has been passed."

श्री प्रताप चन्द्र आज़ाद—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं द्वारा २६ में निम्नलिखित संशोधन पेश करना चाहता हूँ:

"In the proposed Section 73—

(1) in sub-clauses (i) and (ii) of sub-section (1) the word "Chairman" shall be inserted *between* the words "the" and "Education".

(2) for the existing sub-section (2) the following shall be substituted—

(2) An appeal—

(a) in the case of an order of dismissal or removal or any other punishment passed against servants mentioned in clauses (a) and (b) of sub-section (1)—

(i) by the Superintendent or Lady Superintendent, to the Chairman, Education Committee;

(ii) by the Chairman, Education Committee to the President of the Board;

(b) in the case of an order of dismissal or removal passed against servants mentioned in clause (c) of sub-section (1) by the Chairman, Education Committee, to the State Government; and

(c) in the case of an order of any other punishment against servants mentioned in clause (c) of sub-section (1) by the Chairman, Education Committee to the prescribed authority."

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधन मैं इस क्लॉज में करना चाहता हूँ, वह यदि देखा जाय तो बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन है। इस संशोधन में मैंने यह रखा था कि जो यह विधेयक यहाँ पर प्रस्तुत किया गया था, उसके अन्तर ४० रुपये तक के एज्यूकेशन डिपार्टमेंट के एम्प्लोईज की बात है। जो म्यूनिसिपल बोर्ड के एज्यूकेशन डिपार्टमेंट के इम्प्लोईज हैं और जो ४० रु० या ४० रु० से लेकर ५० रु० तक या ५० रु० से लेकर ७५ रु० तक वेतन पाने वाले हैं उनका अप्पॉइन्टमेंट, छुट्टी, पनिसमेंट आदि का अस्तित्व जो था वह सुपरिन्टेंडेंट और लेडी सुपरिन्टेंडेंट के हाथ में था और जहाँ यह लोग न हों वहाँ यह अधिकार एज्यूकेशन कमेटी को दिया गया है। एज्यूकेशन कमेटी १० या १२ सदस्यों की एक जमात होती है।

[श्री प्रताप चन्द्र आज़ाद]

अक्सर देखा यह गया है कि कोई आदमी ग़लती करता है और उसको पनिश करने का सवाल आता है और चेयरमैन एजुकेशन चाहता है कि इसको पनिश किया जाय। लेकिन होता यह है कि मेम्बरों को कनवेंस किया जाता है और २ या ४ मेम्बरों को कनवेंस करने के बाद चेयरमैन एजुकेशन नाकाबिल बना दिया जाता है कि वह कोई पनिशमेंट दे सके इसलिये इसमें जहाँ पर एजुकेशन डिपार्टमेंट लिखा है मैंने चेयरमैन कर दिया है जिससे चेयरमैन इम्पारशियली किसी इम्प्लाय को जो ग़लती करता है उसको पनिश कर सके। इस सम्बन्ध में मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ और जहाँ तक मुझे मालूम है, मैं अपने जिले की एक मिसाल देता हूँ। एजुकेशन डिपार्टमेंट में एक योग्य मास्टर थे, सब से ज्यादा सीनियर थे उनका जब कनफरमेंस का सवाल आया और हेडमास्टर की जगह का सवाल आया तो प्रोपेगेन्डा उस मास्टर के खिलाफ़ मेम्बरों के बीच किया गया और जो जूनियर मास्टर था उसको हेडमास्टर बना दिया गया हालांकि उसको चेयरमैन भी चाहता था और इन्स्पेक्टर आफ़ स्कूल्स भी चाहते थे। इस तरह से जो सीनियर था उसके बजाय जूनियर मास्टर हेडमास्टर बना दिया गया। इसलिये मैंने यहाँ चेयरमैन का शब्द बढ़ाया है। दूसरी बात यह है कि जो अपील का सम्बन्ध है उसमें यह रखा गया है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट डाइरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट को की जायेगी और म्यूनिसिपल बोर्ड को छोड़ दिया गया है इसलिये मैंने इसमें यह कर दिया है कि जहाँ पर अपील सुपरिन्टेंडेंट और लेडी सुपरिन्टेंडेंट को होगी वहाँ पर चेयरमैन एजुकेशन कमेटी कर दिया जाय और क्लार्क ए, बी के सम्बन्ध में ऐसा कर दिया है जहाँ चेयरमैन एजुकेशन कमेटी है वहाँ पर जहाँ इम्प्लाइज एजुकेशन डिपार्टमेंट को चेयरमैन कमेटी डिस्मिस करे वहाँ उनकी अपील प्रधान बोर्ड को जाय। वहाँ पर सेक्शन १०० में जो दूसरे नौकरान आते हैं उनके सम्बन्ध में यह कर दिया गया है कि अगर चेयरमैन एजुकेशन कमेटी के ज़रिए से उनको पनिशमेंट मिलता है तो उसकी अपील स्टेट गवर्नमेंट से कर सकते हैं और दूसरे किस्म के पनिशमेंट के आर्डर, डिस्मिसल और रिमूवल के अलावा, अगर चेयरमैन एजुकेशन कमेटी पास करे तो उसकी अपील प्रेस्काइन्ड अप्रारिटी के पास की जा सकती है। प्रेस्काइन्ड अप्रारिटी, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, कमिशनर या जिसको मिनिस्टर साहब या लोकल सेल्फ़ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट नामिनेट करे, होगी। यह मैंने इसलिए कर दिया है जिससे नाजायज़ दबाव और बेजा असरात डालकर जो बातें हो जाती हैं वह न हो सकें। यह अमेन्डमेंट मैंने इसलिए किया है कि जो आदमी मिसयूज करता है उसको पनिशमेंट और जो अच्छा काम करता है उसको प्रमोशन मिले। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी मेरे संशोधन को ज़रूर मानेंगे।

श्री मोहनलाल गौतम—इस रूप में मुझे यह संशोधन स्वीकार है।

चेयरमैन—The question is that “In the proposed section 73—

(1) in sub-clauses (i) and (ii) of sub-section (1) the word “Chairman” shall be inserted *between* the words “the” and “Education”.

(2) For the existing sub-section (2) the following shall be substituted—

(2) An appeal—

(a) in the case of an order of dismissal or removal or any other punishment passed against servants mentioned in clauses (a) and (b) of sub-section (1)

(i) by the Superintendent or Lady Superintendent, to the Chairman, Education Committee;

(ii) by the Chairman, Education Committee to the president of the Board;

- (b) in the case of an order of dismissal or removal passed against servants mentioned in clause (c) of sub-section (1) by the Chairman, Education committee, to the State Government; and
- (c) in the case of an order of any other punishment against servant mentioned in clause (c) of sub-section (1) by the Chairman, Education Committee to the prescribed authority."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

चेयरमैन—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड २६ बिल का भाग बना रहे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ३०-४५

३०—मूल अधिनियम की धारा ७४ में (१) शब्द "on" और अक्षर "a" के बीच में शब्द "or drawing" रखे जायं, और

यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ की धारा ७४ का संशोधन।

- (2) शब्द "Subject in the case of dismissal or removal to an appeal to the State Government which must be presented to the State Government within one month of the date upon which the order of dismissal or removal is communicated to the person in respect of whom the order is made"

के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय—

"Provided that an appeal shall lie—

(a) in the case of dismissal or removal, to the State Government; and

(b) in the case of any other punishment, to the Prescribed Authority;

and shall be presented to the State Government or the prescribed authority, as the case may be, within one month from the date on which the order appealed against is communicated to the person concerned."

३१—मूल अधिनियम की धारा ७६ में—

(१) खंड (ए) और (बी) में शब्द "servant" के बाद शब्द "on" के स्थान पर शब्द "or drawing" रख दिये जायं;

यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ की धारा ७६ का संशोधन।

(२) शब्द but और each के बीच में आये हुये शब्द "in such case" निकाल दिये जायं; और

(३) शब्द "punishment" के बाद कामा रखा जाय और उसके बाद शब्द "in respect of servants mentioned in clauses (a) and (b) above" रख दिये जायं।

३२—मूल अधिनियम की धारा ६३ में—

(क) शब्द "the Superintending Engineer, Public Health Department" के स्थान पर शब्द "Chief Engineer, Local Self-Government Engineering Department" रख

यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ की धारा ६३ का संशोधन।

दिये जायं, और

[खंड ३२]

(ख) शब्द “the Director of Public Health or Assistant Director of Public Health” के स्थान पर शब्द “The Director of Medical and Health Services or the Assistant Director of Medical and Health Services” रख दिये जायें।

यू० पी० ऐक्ट २,
१९१६ की धारा
६४ का संशोधन।

३३—मूल अधिनियम की धारा ६४ की उपधारा (३) के स्थान पर निम्नलिखित रक्खा जाय :—

“(3) Every resolution passed by a board at a meeting, shall, as soon the reafter as may be, be published in a local paper published in Hindi and where there is no such local paper, in such manner as the State Government may, by general or special order, direct.”

यू० पी० ऐक्ट २,
१९१६ की धारा
१२८ का संशोधन।

३४—मूल अधिनियम की धारा १२८ की उपधारा (१) में वर्तमान खंड (viii) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

“(viii) an octroi on goods or animals brought within the municipality for consumption, use or sale therein;”

यू० पी० ऐक्ट २,
१९१६ की धारा
१८०-ए का संशोधन

३५—प्रतिबन्धात्मक वाक्य को छोड़ कर धारा १८०-ए की उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दी जाय—

“(1) Notwithstanding anything contained in this Act or any bye-law made thereunder, the construction of, or any addition to, any building of public entertainment or any addition there to shall not, except with the previous approval of the State Government, be sanctioned by a board, if the site of, or proposed for such building is—

(a) within a radius of one furlong from—

(i) any residential institution attached to a recognised educational institution such as a college, a high school or girls school, or

(ii) a public hospital with a large in-door patient ward; or

(iii) an orphanage containing one hundred or more inmates; or

(b) in any thickly populated residential area which is either exclusively residential or reserved or used generally for residential as distinguished from business purposes; or

(c) in any area reserved for residential purposes by any housing or planning scheme or otherwise under any enactment”

यू० पी० ऐक्ट २,
१९१६ की धारा
२८२ का संशोधन।

३६—मूल अधिनियम की धारा २८२ की उपधारा (१) में शब्द “the Director of public Health” के स्थान पर शब्द “the Director of Medical and Health Services” रख दिये जायें।

३७—नूल अधिनियम की धारा २६६ की उपधारा (२) में खंड (बी) के बाद नए खंड (सी) के रूप में निम्नलिखित रखवा जाय—

यू० पी० ऐक्ट २,
१९१६ की धारा
२६६ का संशोधन।

“(c) for the appointment of an *ad hoc* committee to advise the Board—

(i) on the preparation of a master plan for the municipality and its execution; and

(ii) on the lay out of public streets, residential and non-residential areas.”

३८—नूल अधिनियम की धारा २६७ की उपधारा (१) में—

यू० पी० ऐक्ट २,
१९१६ की धारा
२६७ का संशोधन।

(१) खंड (जी) के मद (१) में शब्द “Chairman” के स्थान पर शब्द “President” रख दिया जाय।

(२) खंड (के) में शब्द “the” और शब्द “period” के बीच में शब्द “conditions of service including” रख दिये जायें।

३९—नूल अधिनियम की धारा ३०१ में शब्द “Commissioner” के स्थान पर शब्द “Prescribed Authority” रख दिये जायें।

यू० पी० ऐक्ट २,
१९१६ की धारा
३०१ का संशोधन।

४०—नूल अधिनियम की धारा ३२७ में शब्द “in his division” के स्थान पर शब्द “within his or its jurisdiction” रख दिये जायें।

यू० पी० ऐक्ट २,
१९१६ की धारा
३२७ का संशोधन।

४१—नूल अधिनियम की अनुसूची १ में—

(१) स्तम्भ १ में से संख्या १३ और स्तम्भ २ में से उसके सम्बन्ध में इन्दराज निकाल दिया जाय;

(२) स्तम्भ २ में धारा ६८ के सामने वर्तमान इन्दराज के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय;

यू० पी० ऐक्ट २,
१९१६ की अनुसूची
१ का संशोधन।

“To appoint Civil Engineer, Assistant Civil Engineer, Electrical Engineer, Assistant Electrical Engineer, Water Works Engineer, Assistant Water Works Engineer, Electrical and Water Works Engineer, Assistant Electrical and Water Works Engineer, qualified Overseer or Sub-Overseer, Secreatary, Suprintendent or Lady Superintendent of Education.”

(३) धारा २११ और २१७ (१) (३) के सामने के इन्दराजों के बीच में निम्नलिखित रख दिया जाय—

“212-A. To control and regulate the construction of any building or street and drains beyond municipal limits, upto a distance of two miles.”

४२—नूल अधिनियम की अनुसूची २ में—

(१) धारा ७१ और ७६ के सामने दूसरे स्तम्भ के इन्दराजों में से शब्द “permanent” और “inferior” के बीच में आया हुआ शब्द “and” निकाल दिया जाय;

(२) धारा २०३ (३) के सम्बन्ध में इन्दराज निकाल दिया जाय; और

यू० पी० ऐक्ट २,
१९१६ की अनुसूची
२ का संशोधन।

[खंड ४२]

(३) धारा २०४ के सामने दूसरे स्तम्भ में इन्दराज के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय—

“To receive application for permission to lay out and make a street.”

य० पी० ऐक्ट २,
१९१६ की अनुसूची
७ का संशोधन

४३—मूल अधिनियम की अनुसूची ७ में—

(१) स्तम्भ १ में संख्या “9(1)” के स्थान पर संख्या “9” रख दी जाय;

(२) स्तम्भ १ में संख्या “16(2)” के स्थान पर संख्या “13-D” रख दी जाय;

(३) स्तम्भ २ में शब्द “Sub-Section” के स्थान पर शब्द “Section” रख दिया जाय;

(४) धारा 13-D और २२ से सम्बद्ध इन्दराज के बीच में 13-I के सामने नये इन्दराज के रूप में निम्नलिखित रख दिया जाय—
“13-I to direct that a casual vacancy be left unfilled till the next general elections.”

(५) धारा ३४ (२) के सामने दूसरे स्तम्भ के इन्दराज में शब्द “Commissioner” के स्थान पर शब्द “Prescribed Authority” रख दिये जायें।

(६) धारा ४० (२) के सामने दूसरे स्तम्भ के इन्दराज में शब्द “under clause (d), (e) or (f) of sub-section(1)” के स्थान पर शब्द और संख्या “under clause (c), (d) or (e) of sub-section (1)” रख दिये जायें;

(७) स्तम्भ १ में संख्या ५७ और ५८ के बीच में संख्या और अक्षर 57(2-A) रख दिये जायें और उसके सामने स्तम्भ २ में निम्नलिखित इन्दराज रखा जाय—

“To nominate Accounts Officers and to lay down the terms and conditions of their service.”

(८) धारा ६०-ए और ६५ के सामने के इन्दराजों के बीच में निम्नलिखित नया इन्दराज रखा जाय—

“60-B. To direct that in any municipality the Principal Officers of the Electrical, Public Works, and Water Works Department shall with reference to their departments exercise the power under clause (e) of sub-section (1) of section 60;”

(९) धारा ७३ और ७४ के सामने के इन्दराज में शब्द “President” के बाद शब्द “or Chairman, Education Committee” रख दिये जायें, और

(१०) धारा ३२७ और ३३७ के सामने के इन्दराजों के बीच में निम्नलिखित नया इन्दराज रखा जाय—

“336-A. To direct that during the transition period, the Act shall have effect subject to certain adaptations, alterations and modifications.”

४४—मूल अधिनियम की अनुसूची ८ में—

(१) धारा १५८ (२) के सामने तीसरे स्तम्भ में शब्द और संख्या “Rs.100” के स्थान पर शब्द और संख्या “Rs.500” रख दिये जायें; यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ की अनुसूची ८ का संशोधन

(२) धारा २४८ के सामने तीसरे स्तम्भ में शब्द और संख्या “Rs.20” के स्थान पर शब्द और संख्या “Rs.50” रख दिये जायें।

४५—(१) कठिनाइयों को विशेषकर ऐसी कठिनाइयों को जो मूल अधिनियम के उपबन्धों से इस अधिनियम द्वारा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों पर संक्रमण होने से सम्बन्धित हो दूर करने के लिये राज्य सरकार आज्ञा द्वारा निर्देश कर सकती है कि उक्त प्रकार से संशोधित मूल अधिनियम इस अधिनियम के प्रारम्भ से ठीक बाद के बारह मास की अवधि में ऐसे अनुकूलन के साथ सप्रभाव होगा जैसा वह उचित और आवश्यक समझे, चाहे वह अनुकूलन परिष्कार के रूप में हो अथवा घटाने या बढ़ाने के रूप में। अनुकूलन

(२) उपधारा (१) के अधीन दी गई प्रत्येक आज्ञा जितना शीघ्र हो सके राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखी जायगी।

चेयरमैन—प्रश्न यह है कि खंड ३० से ४५ तक बिल का भाग बने रहें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

प्रस्तावना व खंड १

कुछ प्रयोजनों के निमित्त यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ को यू० पी० ऐक्ट, संशोधित करने का २, १९१६।

विधेयक

कुछ प्रयोजनों के निमित्त, जो यहां पर आगे चल कर प्रतीत होंगे यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ को संशोधित करना आवश्यक है; अतएव यू० पी० ऐक्ट २, १९१६।
निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है—

१—(१) इस अधिनियम का नाम उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज संक्षिप्त नाम तथा (संशोधन) अधिनियम, १९५२ होगा। प्रारम्भ।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

श्री सत्य प्रेमी उपनाम हरि प्रसाद (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १ के आदि में (१) से प्रथम “१” बढ़ा दिया जाय।

चेयरमैन—यह छपाई की गलती है। यह सचिवालय में ठीक की जा सकती है।

प्रश्न यह है कि प्रीपेम्बुल और खंड १ बिल का भाग बने रहें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री मोहन लाल गौतम—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि सन् १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश म्यूनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक को पारित किया जाय।

अध्यक्ष महोदय, इस समय आप की आज्ञा से मैं इतना निवेदन कर दूँ कि मुझे इस बिल से जैसा इस समय वह इस भवन में संशोधित हो चुका है, बहुत संतोष है। यह एक ऐसा जरूरी अर्मेन्डिंग बिल था जिसके लिये मैं इस कोशिश में था कि जल्दी से जल्दी इस भवन के सामने आये ताकि यह भवन उस पर अपनी राय दे सके और म्यूनिसिपैलिटीज का चुनाव जल्दी हो सके। इस भवन ने बहुत सहानुभूति पूर्वक इसमें सहयोग दिया है और मुझे इस बात को कहने में संकोच नहीं है। जब कभी बातें संशोधन के रूप में इस भवन में आयीं वे अपने अपने विचार से बहुत अच्छी तरह से और साफ तौर से रखी गयी थीं। जहाँ कहीं मतभेद होता है तो उसमें कोई नियम का सवाल नहीं है बल्कि विचारने का भेद हो सकता है मैं सदन के सभी सदस्यों को इसके लिये धन्यवाद देता हूँ। संशोधन छोटे मोटे हुये और उस पर बहुत विचार हुआ। अभी एक संशोधन रखा गया था जिसमें मैट्रिक की शर्त थी, वह हटा दिया गया है। उसका श्रेय कुंवर गुरु नारायण जी के अर्मेन्डमेंट को है। कम से कम यह साबित हो गया कि अगर अपोजीशन कोई माकूल बात कहे तो उसको हमें मंजूर करने में हरगिज हिष्कना नहीं चाहिये। कुंवर गुरु नारायण जी ने जब इस अर्मेन्डमेंट को रखा था तो मैं कह सकता हूँ कि तमाम लोगों में से कुछ ही लोग इसके पक्ष में थे कि यह शब्द रहे लेकिन अधिकांश सदस्य जो बोले थे, वे इसके विरोधी थे। उन्होंने इस संशोधन को रद्द कर दिया। दूसरा संशोधन एज्यूकेशन के इम्प्लाइज के एपोइंटमेंट और डिस्मिसल के बारे में था। वह भी मंजूर हो गया है। बाकी जो छोटे मोटे अर्मेन्डमेंट हुये उनका जिक्र यहां पर करने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार से यह जो संशोधित अर्मेन्डिंग बिल सदन के सामने है उसके लिये मैं प्रार्थना करता हूँ कि वह पारित किया जाय।

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद (स्नातक निर्वाचन क्षेत्र)—श्रीमान् अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। परन्तु जिस दिन माननीय मंत्री जी ने यह बिल सदन में उपस्थित किया था मैं यहां नहीं था इसलिये दो चार बातें बिल के विषय में अवश्य कहूंगा। यह बिल का तृतीयवाचन है, लम्बी चौड़ी बहस की कोई आवश्यकता नहीं है। मंत्री जी ने यह बताया है कि किस परिस्थिति में यह बिल इस सदन के सामने लाया गया है। बिल को मैन पढ़ा है। बिल में जो संशोधन हुये हैं वह अधिक नहीं है, दो तीन संशोधन सरकार ने स्वीकार किये हैं, जब कि ६० संशोधन दिये गये थे। इससे मालूम होता है कि मंत्री जी को विशेषतया ख्याल परिस्थिति का है। बिल की जैसी रूप रेखा आरम्भ में थी करीब-करीब वही अब है। बिल को जब मैंने पहले पहल पढ़ा तो मुझे यह ख्याल हुआ कि लोकल सेल्फ विभाग में इस बिल के सिद्धान्त पर अधिक विचार नहीं किया गया और न इस परिस्थिति का ख्याल रखा गया कि हमारा देश किस हालत में है। अब हमारा देश स्वतंत्र है। इस बिल के पढ़ने से यह मालूम होता है कि वही अंग्रेजी जमाने की शैली क्रायम रखी गई है। कौमा फुलिस्टाप आदि में ही संशोधन किया गया है। कोई ऐसा महत्वपूर्ण परिवर्तन इसमें नहीं किया गया जिससे नागरिक जीवन का स्तर ऊंचा उठता या जिससे बोर्ड और अच्छी तरह से काम करते। मैं समझता हूँ कि मंत्री जी के विभाग में सिद्धान्त रूप से इस प्रश्न पर अधिक विचार नहीं किया गया और जो संशोधन इस बिल में किया गया है वह बहुत ही मामूली है।

स्वायत्त शासन विभाग के दो लक्ष्य हुआ करते हैं। एक तो यह कि जनता को शिक्षा दे कि पालियामेंट्री गवर्नेमेंट किस तरह की होती है और दूसरी बात यह है कि हमारे नागरिक जीवन को ऊंचा उठाने का प्रयत्न करें। मैं देखता हूँ कि इसमें ऐसी कोई बात नहीं रखी गई है कि जिससे नागरिक जीवन ऊंचा उठ सके या स्वायत्त शासन विभाग और अधिक अच्छी तरह से

काम कर सके। यह सुनकर मुझे प्रसन्नता हुई कि मंत्री जी ने कहा कि यह एक खास कारण से बिल लाया गया है और वह कारण है कि हमको जल्दी ही म्युनिसिपैलिटीज का चुनाव कराना मेरी समझ में इस बिल पर दो तरह से विचार किया जा सकता है। चूंकि यह बिल अभी असेम्बली जाने को है और इसके पश्चात् मंत्री जी एक दूसरा बिल लाने वाले हैं तो मैं इस बात को आवश्यक समझता हूँ कि दो चार विचार आपके सामने रख दूँ। पहला विचार सिद्धान्त का है। हमारी गवर्नमेंट ने एक कमेटी नियुक्त की थी जिसका नाम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कमेटी था। उसमें नौकरियों की बाबत बहुत कुछ कहा गया था परन्तु बिल को पढ़ने से ऐसा मालूम होता है कि मंत्री जी के विभाग ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। म्युनिसिपल बोर्ड्स का कर्तव्य क्या है। १९१६ से जो चीज चली आ रही है वही अब भी कायम रखी गई है। इसमें संशोधन हमको करना पड़ेगा। दूसरी बात सरविसेज की है। लोकल सेल्फ कमेटी ने यह सिफारिश की थी कि म्युनिसिपल सरविसेज में एक बहुत हो अहम तब्दीली होनी चाहिये। उसने इन्टर चेंज यानी अदल-बदल के लिये कहा था। इसकी भी कोई व्यवस्था बिल में नहीं की गई है। आज भी बोर्डों में पुरानी रीति से काम हो रहा है। पेशाधिकारी अकारण ही पञ्च्युत कर दिये जाते हैं। सोन्थोरिटा आफ् टेन्थोर पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है।

मैं समझता हूँ कि इस बात की बड़ी आवश्यकता है कि सरकार म्युनिसिपल सर्विसेज को अधिक सुरक्षित बनाये जिससे लोग काम दिलवशीले करें और उनके काम में एकी-शिष्टेति अर्थात् मजबूती आ सके। तीसरी बात फाइनेंस की है। फाइनेंस के बारे में मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ही विचार नहीं किया गया। गवर्नमेंट आफ् इंडिया ने एक इन्क्वायरी कमेटी नियुक्त की थी १९४८ में, और उसने यह सुझाव बोर्डों के सुधारने के लिये रखा था कि इन की आय बढ़ानी चाहिये, और यह भी कहा था कि गवर्नमेंट जो नियंत्रण रखती है टैक्सेज लगाने की शक्ति पर, वह ठीक से कार्यान्वित नहीं होता, उसकी ठीक से करना चाहिये बोर्ड्स को टैक्स लगाने की आजादी देना चाहिये जिससे उन्हें अपने उत्तरदायित्व का ज्ञान हो। गवर्नमेंट चाहती यह कर सकती है कि उनके टैक्सेज की मिनिमम और मैक्सिमम तादाद नियत कर दे। उनका कहना यह था कि —

“So far as powers of taxation were concerned the Provincial Government did not, as a rule, grant wider powers as recommended by the Decentralization Commission and endorsed by the Government of India in their Resolution of 16th May 1918. Generally every fresh proposal for taxation, for reduction or abolition of an existing tax continued to be subject to previous sanction of the Provincial Government.”

और उन्होंने अपने शब्दों में यह कहा था—

“The position, therefore, to day is that in matters of finance the control of the Provincial Governments over local bodies is very substantial.”

मेरा कहना यह है कि आर्थिक समस्या महत्व रखती है। आप रोड देखते हैं और अन्नबारी में पढ़ते हैं कि तमाम बोर्डों की दशा खराब हो रही है। इसके बारे में गवर्नमेंट को अधिक विचार करना चाहिये और जो गवर्नमेंट की फाइनेंस कमेटी थी उसकी सिफारिशों पर अधिक ध्यान देना चाहिये। चौथी बात नियंत्रण और निरोधन की है। मेरे मित्र प्रभु नारायण जी ने अपने संशोधन के द्वारा यह सुझाव दिया था कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोर्ड बनाया जाये और वह लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की देख भाल करे और उसकी निगरानी भी किया करे। यह सुझाव लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कमेटी ने भी दिया था। उसने कहा था कि इस प्रकार का एक बोर्ड लखनऊ में स्थापित होना चाहिये। इसके द्वारा बोर्डों का निरीक्षण होना चाहिये। जब मंत्री जी नया बिल लायें तब यह बतलाने की कृपा करें

[डाक्टर ईश्वरी प्रसाद]

कि लोकल सेल्फ बोर्ड लखनऊ में बन सकेगा या नहीं। और उसके बनने से कुछ अच्छाई की आशा है या नहीं। यह सिद्धान्त की बात है जो विचार करने के योग्य है। मंत्री जी ने बतलाया कि यह बिल बहुत अच्छा है और मैं उनसे सहमत हूँ कि इसमें बहुत सी अच्छी अच्छी बातें हैं। जैसे एकाउन्ट्स आफिसर्स की नियुक्ति, चुनाव जल्दी कराने की बात, यह सब बातें ऐसी हैं जिनके लिये मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। परन्तु बिल में दोष भी हैं जिनकी ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। वो एक मोटी मोटी बात मैं कहना चाहता हूँ। मैंने मंत्री जी को सुना और धाराओं को गौर से पढ़ने के बाद मुझे यह मालूम होता है कि प्रवृत्ति सरकार की इस समय केन्द्रीयकरण की ओर है। मंत्री जी ने कहा कि हमारी परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि वह हमको मजबूर करता है कि हम संशोधनों को स्वीकार न करें। वह क्या परिस्थिति है उसकी मंत्री जी बतलायेंगे। प्रतिदिन हम देखते हैं कि म्यूनिसिपल बोर्ड सुपरसीड हो रहे हैं। कानपुर बोर्ड की सुपरसीड होने की तैयारी हो रही है। यहाँ सरकार की आँखों के नीचे लखनऊ का म्यूनिसिपल बोर्ड सुपरसीड कर दिया गया है। क्या गवर्नमेंट समझती है कि स्वायत्त शासन में जनतंत्र का सिद्धान्त असफल हो रहा है। तो क्या इसका उपाय सरकार ने अधिकाधिक मात्रा में केन्द्रीयकरण ही समझा है। उसको रोकना पड़ेगा। जहाँ तक मैं समझता हूँ सरकार को यह आभास रहा है कि ये संस्थाएँ ठीक से काम नहीं कर रही हैं। इसलिये हमको ऐसा करना चाहिये। आप इस बात पर विचार करें कि केन्द्रीय करण से क्या इस बीमारी का उपाय हो सकता है। जैसा कि आपने कहा और जैसा कि कई धाराओं से प्रकट होता है कि सरकार की शक्ति बढ़ेगी। आपने इस विधेयक में अध्यक्ष और सदस्य दोनों को हटाने और मुअत्तिल करने की व्यवस्था की है। जब अध्यक्ष जनता द्वारा चुना जायेगा तो जब आप उसको हटा देंगे या सस्पेंड करेंगे तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। बोर्ड के शासन कार्य में कठिनाई होगी। मेम्बर को भी सस्पेंड करना खराब है इससे उनके आत्म-सम्मान को आघात पहुँचेगा। बेहतर तो यह है कि अगर कोई चेयरमैन या प्रेसीडेंट कसूर करता है, घूस लेता है या ऐसा गलत कार्य करता है जिससे बोर्ड की प्रतिष्ठा में बट्टा लगता है तो उसको आप शीघ्र अलग कर दीजिये लेकिन उसको मुअत्तिल करना ठीक न होगा। धारा ६७ और ६८ में भी संशोधन किये गये हैं। मैं समझता हूँ कि वे भी ठीक नहीं हैं।

टेक्निकल आफिसर के बारे में हमारे मित्र राजाराम जी ने आपका ध्यान आकर्षित किया है। कुछ आफिसरों को नियुक्त किया जायेगा। सरकार के कहने से बोर्ड इनको नियुक्त करेगा और फिर सरकार को उन्हें सस्पेंड करने का भी अधिकार होगा। लेकिन जब अपील की जायेगी और उसमें जो आर्डर म्यूनिसिपल बोर्ड का होगा उसमें रद्दोबदल भी करने का अधिकार होगा। हमने ऐसा कहीं सुना नहीं कि जब अपील आपके यहाँ है तो उसके बीच में कैसे रद्दोबदल हो सकते हैं। मैं समझता हूँ कि यह संशोधन ठीक नहीं है। शिक्षा के सम्बन्ध में जो धाराएँ इसमें रखी गई हैं वह भी अनुचित हैं। अध्यापकों का सम्मान मंत्री जी ने इस प्रकार किया है कि जो ७५ रुपये तक वेतन पाने वाले हैं उनको बरखास्त करने का अधिकार सुपरिन्टेंडेंट और लेडी सुपरिन्टेंडेंट को दे दिया जायेगा।

श्री मोहन लाल गौतम—ऐसा नहीं है।

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद—कुछ अध्यापक ऐसे होंगे जिनका इसमें वर्णन है और कुछ ऐसे नौकर हैं जो शिक्षा विभाग में काम करते हैं उनको सुपरिन्टेंडेंट और लेडी सुपरिन्टेंडेंट

बरखास्त कर सकेंगे। इसको मैं ठीक नहीं समझता। सुपरिटेण्डेंट और लेडी सुपरिटेण्डेंट बोर्ड में ऐसे होते हैं कि वे किसी भी अध्यापक के दबाव में आकर बरखास्त कर सकते हैं। अध्यापन की उचित व्यवस्था होनी चाहिये और अध्यापकों की सुरक्षा का पूर्ण उपाय बांछनीय है।

दूसरी बात मैं चुंगी (octroi) के बारे में कहना चाहता हूँ। इसका जिक्र अभी तक किसी मेम्बर ने नहीं किया है। इसके सम्बन्ध में यह है कि यह टैक्स रखने के काबिल नहीं है। इसके बारे में बहुत कुछ विचार हो चुका है। सन् १९०८ में हमारी गवर्नमेन्ट ने एक कमेटी नियुक्त की थी उसमें कहा गया था :

(1) Abolition of octroi in those towns in which it would be replaced by direct taxation, for instance by a tax on circumstances and property.
... आवश्यक है।

इसके बाद १९२४-२५ में एक इंडियन टैक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी नियुक्त हुई। उसने भी कहा कि—

“Octroi and terminal tax in the form in which they are so far levied in India offend against all canons of justice their collection and the system of refunds usually form an essential feature of octroi and put the person paying the tax to a great amount of inconvenience.”

Sir Joseph Stamp summed up as follows:—

“In my judgment both theoretically and on the result of experience, no country can be progressive that relies to any extent upon octroi.

“The declared policy of U. P. Government was to abolish octroi but ever since terminal tax became a central subject, this policy has been thwarted and octroi is resuming its former place of importance in local finances.”

कमेटी में अन्त में यह कहा कि चूंकि स्थिति इस प्रकार की है कि इसे जारी रखना पड़ेगा परन्तु प्रबन्ध नये प्रकार से होना चाहिये। मैं मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि वह इन बातों पर गौर करें और देखें कि कौन सी खराबी है और उसको दूर करने की क्या कोशिश हो सकती है। इसके अलावा मैं सिनेमा के सम्बन्ध में भी कुछ कहना चाहता हूँ। सिनेमा के लिए यहां पर जो कानून बना है वह उचित नहीं है। इसमें आपने २२० गज के फासले पर सिनेमा बनाने की इजाजत दी है। मैं इसको ठीक नहीं समझता हूँ। मेरठ में एक जगत टाकीज है जो शिक्षा संस्था के निकट है वहां पर लड़के खाली घंटे में जाते हैं। सिनेमा एक ऐसी चीज है जिसका प्रभाव लड़कों पर अच्छा नहीं पड़ता है। इन पर सरकार को अधिक नियंत्रण लगाना चाहिये। यह भी देखना चाहिये कि एक नगर में जनसंख्या के हिसाब से कितने सिनेमा गृहों की आवश्यकता है।

स्वायत्त शासन के कला-विज्ञान सम्बन्धी कर्तव्य भी हैं। प्रसिद्ध पुरुषों के व्याख्यानो द्वारा नागरिकों के ज्ञान की वृद्धि कराना भी उसका ध्येय होना चाहिये। इस सम्बन्ध में हमें इंग्लैण्ड की संस्थाओं से शिक्षा मिलती है। वहां अनेक उपायों से नागरिक जीवन के आदर्श उत्कृष्ट करने की चेष्टा की जाती है। यही हमारे देश में होना चाहिये। मुझे पूर्ण आशा है कि अब जो मंत्री महोदय दूसरा बिल प्रस्तुत करेंगे वह व्यापक होगा और उसमें इन सब बातों का समावेश होगा जो आज इस सदन के सम्मुख कही गई हैं। स्वायत्त शासन की स्कीम ऐसी होनी चाहिये जिससे जनता को लाभ हो। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

श्री गोविन्द सहाय—माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा इरादा इस बिल पर बोलने का नहीं था और न कोई मेरे में इस पर बोलने का इतना उत्साह ही था। मैंने यहां पर जो कुछ सुना उसके सुनने के बाद मेरे दिल में यह ख्याल पैदा हुआ कि मैं भी कुछ कहूँ। मैंने इस बिल को

[श्री गोविन्द सहाय]

काफी गौर से पढ़ा और पढ़ने के बाद मैंने यह महसूस किया कि यह बिल काफी निरस है। इस बिल को पढ़ने से मैंने यह ज़रूर महसूस किया है कि मंत्री महोदय ने बहुत ज़रूरी तरीके से यह महसूस किया है कि चुनाव हो जाना चाहिए। अन्दरूनी तरीके से पार्टी ने भी इस बात पर जोर दिया है कि अब चुनाव हो जाने चाहिये। चूंकि मंत्री जी ने वादा किया है कि अब चुनाव होने चाहिए इसलिए अब वह पूरा कर रहे हैं। अपने वादे को पूरा करने के लिए और चुनाव कराने के लिए आप यहां पर यह बिल लाये हैं। बिल में सिर्फ़ अगर मगर पुट और बट वगैरा में ही सरकार ने संशोधन किये हैं जिस पर कोई बहस नहीं हो सकती है। चूंकि हर चीज़ को देखने का एक नज़रिया होता है, अगर उस नज़रिये से इस बिल को देखा जाय, जैसा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की यह नीति थी कि वह जितना हो सके उतनी ताकत अपने हाथ में ले ले, वही हालत आज हमारी सरकार की हो रही है। हमारे मंत्री महोदय, एक बहुत अच्छे वकील भी हैं, काफी तज़रबेकार हैं, इसलिए वह इस बिल को जिस ढंग से लायें हैं, उसके लिये मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। लेकिन जहाँ तक बिल का ताल्लुक है, हम यह समझ कर आगे चले थे कि जिस लीडरशिप के हाथ में आज मुल्क को चलाने की जिम्मेदारी है, जिसके हाथ में मुल्क आगे जाता है उसके साथ-साथ उसकी जिम्मेदारी यह भी है कि वह मुल्क के लोगों को भी आगे ले जाय। मैंने आनरेबिल मिनिस्टर साहब की स्पीच सुनी और उसकी सुनने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुँचा कि आज के लीडरशिप का मकसद इस मुल्क को क्लासलेस सोसाइटी बनाना है और इस मुल्क को डेमोक्रेसी की तरफ़ ले जाना है और इस देश की डेमोक्रेसी को कामयाबी पर पहुँचाना है। कुदरतन मुझे ऐसा महसूस होता है कि उनके जितने भी अमल होंगे, जितने भी कारनामे होंगे और जितने भी रवये होंगे, उन सब का एक ही मकसद होगा कि लोगों में जिम्मेदारी की भावना पैदा करने के लिये, उनकी जम्हूरियत की तरफ़ ले जाने के लिये और उनको अपनी जिम्मेदारी को अहसास कराने के लिये एक ही रास्ता है और वह रास्ता सेन्ट्रलाइजेशन का अपनाया जाना है। मैं तो यह कहूँगा कि भले ही आप अपनी कसरत राय से इस बिल को पास कर लें लेकिन जो इसका बुनियादी असर होगा वह यह होगा कि आप उन तमाम मकसदों को, जिसकी रूपरेखा आपने दिखाई है, उनको अपने ही पैरों के नीचे रौंद रहे हैं। जब मैं यह सुनता हूँ कि इस मुल्क में डेमोक्रेसी का तज़ुबा हो रहा है और उसी तज़ुबे की बिना पर पहला एलेक्शन हो चुका है और अब यह आपका दूसरा इलेक्शन होने जायेगा, तो मुझे ताज़्जुब होता है कि यह कैसा डेमोक्रेसी का तरीका अस्तियार किया जाता है। मुझे इलेक्शन के बारे में कुछ नहीं कहना है। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि इस मुल्क को आगे ले जाने की जिम्मेदारी किस की है, जम्हूरियत को कितने लोग हैं जो हमदर्दों की नज़र से देखते हैं। लोगों का यह ख्याल है कि इस किस्म की जम्हूरियत के मुक़ाबिले में तो डिक्टेटरशिप कहीं अच्छी थी। इस तरह की भावना पैदा कराने की किस की जिम्मेदारी है। इस तरह से आपकी जम्हूरियत निकम्मी साबित हुई। जम्हूरियत में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वह यह है कि जो हमारी लोकल सेल्फ़ गवर्नमेंट है, जो म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं और इसी किस्म की दूसरी संस्थाएँ हैं उनको किस तरह से तैयार करें। उनको भी कुछ मौका दिया जाता है कि वे अपनी जिम्मेदारी को महसूस करते हुये चले।

जो स्पीच आनरेबिल मिनिस्टर साहब ने बो है उससे तो मुझे निराशा ही होती है। पहले जब कि श्री ए० जी० खेर, लोकल सेल्फ़-गवर्नमेंट के मिनिस्टर थे उस वक़्त उन्होंने वाटर वर्क्स यूनियन में बोलते हुये कहा था कि गुड गवर्नमेंट ज्यादा ज़रूरी है लोकल सेल्फ़ गवर्नमेंट से। म्यूनिसिपैलिटीज़ के बारे में दलील देते हुये उन्होंने कहा था कि इसमें आई० सी० एस० रूल का होना ज़रूरी है और दूसरी तरफ़ अभी एक अवज़ार में साठ रोज़ पहले आनरेबिल मिनिस्टर, गौतम साहब की स्पीच मैंने पढ़ी। उसमें यह कहा गया था कि अगर थंचायतें ठीक तरह से अपना काम नहीं करेंगी तो गवर्नमेंट उनको अपने हाथ में ले लेगी। इसके बारे में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि क्या इस तरह से लोगों में सेन्स आफ़ ड्यूटी पैदा किया जा सकता है, क्या

कानून के जोर पर लोगों में डेमोक्रेटिक भावना का संचार किया जा सकता है। यह है आपका डेमोक्रेटिक तरीका और इस तरह से आप डेमोक्रेसी का तजुरबा करने जा रहे हैं। इस तरह से लोगों में जो तजुरबा इस डेमोक्रेसी का पैदा हुआ है वह यही है कि आज वह कहते हैं कि इस डेमोक्रेसी से तो डिक्टेटरशिप बढ़कर है और अच्छी है। आपका मकसद है कि म्युनिसिपैलिटीज की पावर को इस तरह से खत्म करके आप अपने हाथ में लेना चाहते हैं और इस तरह से डिसेन्ट्रलाइजेशन का तरीका अपना कर हर चीज को असल में लाना चाहते हैं। आपको तो चाहिये यह था कि उनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी छोड़ देते जिससे वह शहरों की हालत को ठीक करते, वहाँ के लोगों में पैट्रियाटिक भावना पैदा करते और उनको इस का बिल बनाते कि वह अपने कर्तव्य का ठीक ठीक तरह से पालन कर सकते हैं। यह तो उनकी जिम्मेदारी है कि लोगों के अन्दर इन्सानियत की कूबत पैदा करें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और उनको अपनी जिम्मेदारी से महकम करते हैं तो जो आपका डेमोक्रेसी का तजुरबा है वह कामयाब नहीं हो सकता है। आपका जो तरीका है वह सोशल डेमोक्रेसी का एक बड़ा ही खतरनाक अन्जाम पैदा करता है। मैंने अपना एक अमॅडमेंट पेश करने की कोशिश की थी लेकिन मैं यह समझा था कि उसका नम्बर देर में आयेगा और इसीलिये उसे पेश न कर सका। लेकिन जो मेरा अमॅडमेंट था वह बड़ा ही रीएक्शनरी था, इसको मैं खुद ही कहता हूँ और उसमें मुझे हिचक नहीं है। वह मैंने इस लिये पेश करना चाहा था कि आपको मालूम हो जाता कि लोगों के अन्दर आपने एक खराब भावना इस बिल से पैदा कर दी है। मेरा संशोधन सिर्फ इतना ही था कि जहाँ आपने सिड्यूल्ड कास्ट के लिये रिजरवेशन रक्खा है उसी तरह से मुसलमानों के लिये हो। आप ताज्जुब करेंगे कि मैंने यह कैसा संशोधन पेश किया लेकिन मैंने इसको जानबूझ कर ही रक्खा है। क्योंकि जो आपका तरीका है वह नेशनलाइजेशन पैदा करने का है, उसमें माइनारिटी का विशेष ख्याल रक्खा गया है और इस तरह से नेशनलिज्म के नाम पर आपने कास्ट सिस्टम को बढ़ाया है और इस तरह से लोगों को सोचने का मौका दिया है कि डेमोक्रेसी के अन्दर इस तरह की भी चीज हो सकती हैं। इस तरह से इन चीजों का क्या परिणाम होगा, वह परिणाम सामने प्रत्यक्ष मौजूद है।

इसके लिये मैंने इसीलिये अमल की बात कही है। इसके अन्दर आपने उन लोगों को नहीं रखा है और आज उन माइनारिटीज में मुसलमान लोग आते हैं। इस कानून से हटकर भी आप उन मुसलमानों के भाव देखिये जो कि इस मुल्क में रहते हैं और मिलिटरी साहब भी इस चीज को देखते हैं। इसमें एक कम्युनिटी की बात नहीं है, बल्कि व्यवहार की है मगर आप इसमें न जाइयें, और आप अपने तरीके से उनके नेशनलिज्म को भी पैदा नहीं कर पाये हैं। अगर आपको वोट लेने हों, तो इस काम के लिये आपको कई ऐसे आदमी मिल जाते हैं। जिन्ना साहब ने भी पहले इसके लिये कहा था और उसकी वही आवाज थी। आपको देखना यह है कि उसकी आदर्श बातें क्या हैं और इन सब बातों का उसपर क्या असर पड़ता है। आप क्या, सेंट्रल क्या स्टेट सबहों में रिजरवेशन डिमांड करते हैं। आप समझ सकते हैं कि मुसलमान उस समय किन हालात में इसपर कैसे राजी हुए थे। अगर आप मुसलमानों के लिये भी इसमें कुछ सीटें रख दें, तो वह किसी एक पार्टी की तरफ नहीं रहेंगे। आप इसको देखें कि यह मेरा सुझाव प्रैक्टिकल हल हो सकता है। कम्युनिटीज के अन्दर खराबियाँ होती हैं लेकिन उसके लिये किसी खास को दोष नहीं दिया जा सकता है।

दूसरी बात जो है, वह मैं क्वालिफिकेशन के बारे में कहना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ कि वह हिन्दी पढ़ना, लिखना या उर्दू पढ़ना या लिखना जानता हो, लेकिन आपकी राय यह है कि वह हिन्दी पढ़ना ही जानता हो। मैं कहता हूँ कि इस तरह से तो लोगों को और भी संदेह हो सकता है और यह मुनासिब भी नहीं है। वह लिट्रेट हो, हिन्दी और उर्दू को जवान समझ लेता हो। जब तक वह हिन्दी और उर्दू न जानता हो, उसके लिये यह हो सकता है। वैसे इसमें कई किस्म के इन्टरप्रिटेशन हो सकते हैं। उसमें काफी लोग गलत समझ सकते हैं। जब माइनारिटी का सवाल होता है, तो हमें किसी की नियत पर शक नहीं करना चाहिये।

[श्री गोविन्द सहाय]

इनको महसूस करते हुये मैं समझता हूँ कि हमें देखना चाहिये कि उसमें कितनी काबिलियत है और वह किस कदर किसी बात को समझ सकता है। आज हमारे लीडरशिप का कोई मोटो नहीं है और सबकी जिन्दगी बिल्कुल एमलेसली चल रही है और उनमें कोई डेफिनिट एम नहीं है। इस बात को कहने में मुझे कोई भी संकोच नहीं है। जहाँ तक सेल्फ गवर्नमेंट है तो वह उतनी ज्यादा जरूरी नहीं है उसूलो तौर पर भी सेल्फ गवर्नमेंट को गुड गवर्नमेंट में तब्दील किया जा सकता है और गुड गवर्नमेंट की जो बुनियादे हैं वे इसमें लाई जा सकते हैं। वैसे चाहे जो भी गवर्नमेंट हो, वह गलती करती है। तो इसके लिये गवर्नमेंट स्पुनिसिपैलिटी से भी कह सकती है कि वह पूर्ण तरीके से सुधरी हुई हो। इसी तरह से मैं कहता हूँ कि वे भी अच्छी हो सकते हैं। यदि गवर्नमेंट अच्छी है, तो आपको यह सोचना चाहिये कि नीचे की गवर्नमेंट जो है वह भी अच्छी हो और उसको भी आपको सुधारना है। अगर ऊँचे की गवर्नमेंट अपनी बुराई को दूर कर सकती है तो नीचे की गवर्नमेंट को भी अपनी बुराई को दूर करना चाहिये। इस तरह से एक दूसरे को आपस में समझने का भी मौका मिलता है।

मैं माननीय श्री मोहन लाल गौतम जी को जानता हूँ और जहाँ तक उनकी राजनीतिक विचार धारा है, उसको भी मैं जानता हूँ और मैं यह भी मानता हूँ कि उनकी जिन्दगी ऐसी है कि वे जिन बातों को मानते हैं उन पर चाहते हैं कि दूसरी जगह भी अमल हो। इसीलिये उन्होंने इस बिल में एक जो क्लॉज रखा है, वह यह है कि जो प्रेसिडेंट हो वह हाई स्कूल पास होना चाहिये। मुझ खुशी है कि उन्होंने इस बात को समझा कि उस जगह पर एक पढ़ा लिखा योग्य व्यक्ति होना चाहिये। इस बात को समझते हुये ही उन्होंने चाहा कि एक जिम्मेदार व्यक्ति को वहाँ पर होना चाहिये और इसके लिये उन्होंने इस सेक्शन में तब्दीली की और इसको पंत जी ने भी मान लिया। इसके लिये यहाँ जो भी अमेंडमेंट पेश किया गया वह स्वीकार किया गया। मैं आपकी इस बात में तारीफ करते हुये भी यह कह सकता हूँ कि आपने मिनिस्टर होने पर जिस बात का अनुभव किया और जिसे उचित समझा वह किया लेकिन फिर भी आपका यह स्टेप गलत हुआ है। वैसे आप जो कुछ करना चाहें कर सकते हैं। मैं भी आपसे इसके लिये कहूँगा कि आपने जो मिनिमम क्वालिफिकेशन्स हाई स्कूल की रखी हैं, तो उसमें देखना यह है कि उसमें काबिलियत क्या और कितनी है। तो अगर इस तरह से एक जगह के लिये आपने मिनिमम क्वालिफिकेशन्स हाई स्कूल रखा है, तो मैं कहूँगा कि आप हर जगह के लिये चाहे वह डिप्टी मिनिस्टर्स की जगह हो या दूसरी जगह हो, उनके लिये भी मिनिमम क्वालिफिकेशन्स रखनी चाहिये। एक आदमी जो कि फाईलों को समझता नहीं है, उसको कैसे किसी रेस्पॉसिबिल पोस्ट में रख दिया जाता है। तो हमारे यहाँ जो सरविसेज होनी चाहिये, तो उसके लिये लोगों को भी मजबूत होनी चाहिये। उसकी अकल मजबूत होनी चाहिये, तभी वह सरविसेज पर हाबी हो सकता है। आप ने इन्ट्रेंस क्वालिफिकेशन रखी थी एक प्रोग्रेसिव कदम था लेकिन वाक्यात से आप उसको नहीं कर सकते थे इसका मुझे अफसोस है और आप के साथ हमदर्दी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कोशिश करेंगे और जिन बातों की ओर यहाँ पर इशारा किया गया है जैसे डा० ईश्वरी प्रसाद जी ने कहा है कि आखिर आप मुल्क को किधर ले जाना चाहते हैं। आपने जम्हूरियत के खिलाफ नफरत पैदा कर दी है, आप को सामने मैं, आदमी लाकर खड़ा कर सकता हूँ आप मेरे साथ चले, मैं दिखलाऊँगा कि हर आदमी यह कहता हुआ नजर आयेगा कि साहब इस राज्य में जस्टिस नहीं हो सकता आज बाँर सफाईश के काम नहीं हो सकता अगर यह वाक्य न हो तो आप मुझको हाईएस्ट पनिशमेंट दे सकते हैं। आज की और लीडरशिप के बारे में क्या कहा जा सकता है लीडरशिप इमानदार होनी चाहिये उसकी इमानदारी का अंतर दूसरों पर भी पड़ता है। आज डेमोक्रेसी के केस को ठेस पहुँच गई है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर आप कोई कदम ऐसा उठाएँ जिससे मुल्क की तरक्की हो और जो बुराईयाँ हैं वह दूर हों तो आप का साथ दूँगा और मेरा उससे कोई मतभेद न होगा। इन बातों की ओर मैंने इशारा किया है मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उन पर ध्यान देंगे और एक सही बिल लायेंगे।

श्री सरदार संतोष सिंह (नाम निर्देशित) —माननीय चेयरमैन साहब, इस अमेंडिंग बिल पर काफी बहस हो चुकी है मगर मुझे अनुशंस है कि जिस बात को मैं कहने जा रहा हूँ उस बात का जिक्र किसी ने नहीं किया है। इसमें इन्डस्ट्री को कितनी प्रकार का रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया है। रिप्रेजेंटेशन (representation) न देना नाइन्साफी करना है क्योंकि हर एक म्युनिसिपैलिटी में वाटरवर्क्स होते हैं और बिजली घर होते हैं उसमें सुपरिटेण्डेंट, असिस्टेंट सुपरिटेण्डेंट होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं और दूसरे लोग भी होते हैं तो उन पर कोई सुपरवाइज करने वाला नहीं होता है और जो बात वह चेयरमैन से कह देते हैं वह उसको मानना होता है। इसलिये इन्डस्ट्री से ताल्लुक रखने वाला एक आदमी उस बोर्ड में होना चाहिये जो उन बातों को और नज़र रख सके। मैं मिसाल के तौर पर यह कहना चाहता हूँ कि वाटर वर्क्स का एक इंजीनियर आता है और कहता है कि फ़नां वाल्व खराब हो गया है और इतने रुपये की ज़रूरत है और देखा यह गया है कि वह चीज खराब नहीं होती है, पर वह बन सकती है तो इस तरह से एक "वे आफ़ चीटिंग" (way of cheating) है इसलिये यह कहना चाहता हूँ कि इन्डस्ट्रीज का भी रिप्रेजेंटेशन अवश्य होना चाहिये। माननीय मंत्री जी को यह करना चाहिये कि वह इन्डस्ट्रीज को ज़रूर रिप्रेजेंटेशन दें। अगर वह उनको रिप्रेजेंटेशन देंगे तो मेरे ख्याल में काफी सयदा म्युनिसिपैलिटी का बच जायगा और अइन्दा म्युनिसिपैलिटी के अन्दर करप्शन होने का जो ख्याल है वह भी हट जायेगा। मुझे पहले कई साहबान इस मानले पर बोल चुके हैं लिहाज़ा मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता, मैं सिर्फ़ इन्डस्ट्रीज के बारे में कहने के वास्ते उठा था और मुझे उम्मीद है कि मंत्री साहब इस तरफ़ ध्यान देंगे और जल्द से जल्द इसका भी इस बिल के अन्दर नाम आयेगा।

श्रीमती शिवराजवती नेहरू (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र) —माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जो कुछ इस बिल के मातहत कहना चाहती थी वह मैंने पहले आपकी मार्फ़त सरकार से कहा था। अब तीसरी रीडिंग है और मैं इस समय भी आपकी मार्फ़त सरकार से दो चार बातें कहना चाहती हूँ। डाक्टर ईश्वरी प्रसाद साहब ने कहा है कि इस बिल में परिवर्तन नहीं हुआ है, पहले की तरह ही यह बिल आया है केवल कुछ अगर-मगर का परिवर्तन कर दिया गया है। परन्तु मुझे कहना है कि इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया है। इसमें पहले स्त्रियों को रिप्रेजेंटेशन दिया जाता था वह अब इसमें नहीं है। अगर मैं इस बात को मान लूँ जैसा कि मिनिस्टर साहब ने कहा है कि सेन्टर से पास हो चुका है कि स्त्रियों को रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया जायगा तो मेरा ख्याल है कि नामिनेशन देने की मनाही सेन्टर ने की होगी। नामिनेशन जब विधान सभा में होता है तो क्या वजह है कि म्युनिसिपैलिटी से नामिनेशन हटा दिया जाय। यदि आप समझते हैं कि स्त्रियाँ पुरुषों को समान हो गयी हैं तो मैं इसको मानने के लिये तैयार नहीं हूँ। आज भी हमारे देश में स्त्रियों की हालत शिड्यूल्ड कास्ट से भी ज्यादा खराब है और आज अपने पद के लिये इतना ज्यादा संघर्ष है कि जो उदारता पहले पुरुषों में थी वह आज पुरुषों में नहीं है और वह कोई भी स्थान स्त्रियों को देने के लिये राजी नहीं होते। यदि आज सरकार स्त्रियों को टिकट दे भी तो पुरुष न देने देंगे। जहाँ तक आज पेसा खर्च करने का सवाल है मैं यह कहूँगी कि पेसा भी आपके देश में आज स्त्रियों के पास नहीं है, उनकी कोई निजी सम्पत्ति नहीं होती वह पेसे के लिये भी पुरुषों पर निर्भर करती हैं। उनके कार्यकर्ता भी पुरुष ही होंगे। आज स्त्री कार्यकर्ता भी नहीं हैं इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फ़त सरकार से यह प्रार्थना करती हूँ कि वह इस विषय पर ध्यान दें और स्त्रियों के लिये दो या तीन सीट नामिनेशन के लिये ज़रूर रखें।

दूसरी बात, अध्यक्ष महोदय मैं आपकी मार्फ़त यह कहना चाहती हूँ जैसा कि गोविन्द सहाय जी ने कहा, कि मुसलमानों को भी रिप्रेजेंटेशन दिया जाय क्योंकि उनको रिज़रवेशन नहीं दिया गया तो जो हमारी सरकार उनके साथ नाइन्साफी कर रही है उसका वह मुकाबिला नहीं कर सकेंगे। मुझे उनकी यह बात अजीब मालूम हुई। हमारी सरकार ने, जब असेम्बली का चुनाव हुआ, जब सेन्टर का चुनाव हुआ तो कितना न्याय उनके साथ किया कि मुसलमानों को उनकी तादाद से ज्यादा सीटें दीं। हमको इस बात के लिये अपनी सरकार पर गर्व है।

[श्रीमती शिवराजवती नेहरू]

इसलिये सरकार पर यह इलजाम लगाना कि वह अल्प संख्या वालों के साथ किसी किस्म की नाइन्साफ़ी कर रही है या मजहबी लिहाज से कोई भेद भाव कर रही है यह तो सारे देश को भ्रम में डालना है। ऐसी बातें करना देश के लिये नुकसान देह है। वह भी हमारे देश के भाई हैं उनको अपने देश का ख्याल होना चाहिये और ऐसी बातें उनको असेम्बली या असेम्बली के बाहर नहीं कहना चाहिये जिससे हमारे देश में बेचैनी पैदा हो और हिन्दुस्तान की एक बड़ी कम्प्यूनिटी के दिल में ख्याल हो कि हमारी सरकार उनके साथ नाइन्साफ़ी कर रही है। इन चन्द शब्दों को कहने के बाद अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करती हूँ।

चेयरमैन—काँसिल दो बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

[काँसिल १ बजे अवकाश के लिये स्थगित हो गई और २ बजे डिप्टी चेयरमैन (श्री निजामुद्दीन) के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।]

श्री राजाराम शास्त्री—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस समय म्यूनीसिपल संशोधन विवेक पर तृतीय वाचन हम कर रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से केवल इतना कहूँगा कि चाहे कोई संशोधन हम भले ही इस भवन में पास न करा पायें हों लेकिन जो बातें कही गईं उनको वह ध्यान में अवश्य रखेंगे। मैं यह जरूर महसूस करता हूँ कि जो पावर्स आपको दी गई हैं उन पावर्स का आप अपनी पूरी शक्ति के साथ सदुपयोग करने में ही इस्तेमाल करें किसी तरह से उनका दुरुपयोग न होने पावे। इसीलिये कहा जाता है कि अगर ताकत अच्छे हाथों में होती है तो उसका सदुपयोग होता है और अगर बुरे के हाथों में जाती है तो उसका दुरुपयोग होता है। मेरा विश्वास है कि माननीय मंत्री जी एक अच्छे ख्यालात के व्यक्ति हैं और वह चाहते हैं कि उनके विभाग का सही माने में सुधार हो। हमारी जनता की भी यही भावना है। जो शासन म्यूनीसिपल बोर्ड्स का अभी तक दुआ है, उससे जनता परेशान रही है और वह चाहती है कि सही माने में सुधार किया जाय। दूसरी तरफ यह भी धारणा लोगों की होती चली जा रही है कि जनता को अधिकार मिलें और वह स्वयं ही अपने पैरों पर खड़ा होना सीखे और सही ढंग से चल कर देश की उन्नति करे। मेरा अपना ख्याल यह है कि वह देश का सुधार भी चाहती है और यह भी चाहती है कि अपनी शक्ति से अपना भी सुधार करे। मेरा विश्वास है कि हम सभी इस बात को मानते हैं कि इस देश को बुरी तरफ ले जाने से बचाने का केवल एक ही रास्ता है और वह यह है कि जनता का विश्वास प्रजातंत्रवाद की तरफ बढ़े।

मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूँ और आशा करता हूँ कि माननीय मंत्री जी मेरी उस बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे। मैंने उस वक्त कहा था कि सरकार इन तरह की ताकत हाथ में न ले कि निर्वासित व्यक्तियों को अपने पदों से हटा दिया जाय। उस मौके पर कुछ लोगों ने हमारी बात का गलत मतलब लिया। इस सदन के सदस्य जब निजामुद्दीन साहब बोल रहे थे तो उन्होंने कहा था कि राजाराम जी यह चाहते हैं कि कोई मेम्बर कितना ही नुकसान करे लेकिन उसको सजा न मिलनी चाहिये। मैं समझता हूँ कि हमारी यह बात गलत ढंग से समझी गई और गलत ढंग से पेश की गई। मैंने कई बार इस सदन में कहा कि अगर मैं दुनिया में किसी से डरता हूँ तो वकीलों से डरता हूँ जो सही बात को गलत करते हैं और गलत को सही करते हैं। तो मैं उपाध्यक्ष जी, यह कहूँगा कि मेरी संज्ञा कतई यह नहीं है कि प्रेसीडेंट या मेम्बर अगर कोई गलती करे तो उसको सजा न देनी चाहिये। मैं सिर्फ यह चाहता हूँ कि सजा कौन दे और गलती हुई या नहीं इसका कौन फैसला करे। मेम्बर या प्रेसीडेंट गलती करता है तो जिस बोर्ड का वह प्रेसीडेंट है और मेम्बर है वही बोर्ड ही फैसला करे और सजा देने का अधिकार भी उसी को होना चाहिये। साथ ही साथ मैं यह भी बिलकुल साफ़ कह दूँ कि बैसे तो मैं रिजर्वेशन का

ज्यादा कायल नहीं हूँ। मैं जानता हूँ कि एक आदमी को पास एक वोट है। उसको खुली आजादी है कि वह जिसको चाहे वोट दे लेकिन मैं मजदूरों के मामले में इसका कायल ज़रूर हूँ मैंने जो मजदूरों की बात उठाई थी उनके बारे में मेरा अपना विश्वास है कि जो अब की चुनाव हुआ उसमें सबसे बड़ी दो तीन बातें सामने आईं। एक तो यह कि साम्प्रदायिकता की जड़ें नहीं हों। उसी और दूसरे पैसे वाले जो यह समझते थे कि वह पैसे के बल पर एलेक्शन जीत लेंगे वह भी इस इलेक्शन में झुक गये। कानपुर में कई लखपती और करोड़पती भी पिछले एलेक्शन में खड़े हुये थे और उनका प्रोपेगेन्डा इतनी जोर के साथ शुरू हुआ कि हम तो घबड़ा गये थे कि कैसे इनके मुकाबिले में खड़ा हुआ जायेगा। तो मैं यह तो नहीं मानता कि पैसे वाले जीत सकते हैं लेकिन खतरा यह है कि जैसा कि प्रजातंत्र देशों में होता है कि पैसे वाले डाइरेक्ट तो नहीं खड़े होते लेकिन वह अपनी पार्टी खड़ी कर देते हैं। वह उस पार्टी को जिताने की कोशिश करते हैं और अक्सर कामयाब भी हो जाते हैं। पूंजीपति दूसरे को मंत्री बनवा देते हैं और उनसे अपना काम करवाते हैं। यह जो कहा गया कि पूंजीपति हार गया, तो वह हार तो ज़रूर गया लेकिन वह दूसरे दरवाजे से घुस आया। आप यह न समझियेगा कि मैं आपको कह रहा हूँ, मैं अपने को भी कह रहा हूँ और अगर मैं कांग्रेस को कहूँ तो कोई खराब बात नहीं है। तो मेरा कहना यह है कि यह जो एलेक्शन आयेगा उसमें मजदूर पूंजीपति का मुकाबिला नहीं कर पायेगा। मैं रिजर्वेशन की बात मानता तो नहीं हूँ और अगर मैं इस सिद्धांत को मानता होता तो मैं इस आशय का कोई संशोधन भी रखा होता लेकिन मैं चाहता था कि मजदूरों को अगर दो एक सीट रिजर्व कर दी जाती तो ठीक होता। हो सकता है, जैसे मान लीजिये कि कानपुर में चुनाव हुआ और मजदूर जीत नहीं सका तो अगर ट्रेड यूनियन के लिये दो तीन सीटें रिजर्व कर दी जाती तो अच्छा होता। मुझे यह विश्वास है कि अभी मजदूर यूनियन में वह हिम्मत नहीं है कि वह पूंजी वर्ग का मुकाबिला कर सके।

जो श्रीमती शिवराजवती नेहरू जी ने कहा था कि औरतों का भी रिजर्वेशन होना चाहिये तो मैं इसके लिये तैयार नहीं हूँ। मैं इस बात पर विश्वास करता हूँ कि जितना इक्सप्लाइडेशन महिलाओं ने आदमियों का किया है उसना किसी ने न किया होगा। सर्व के धन पर, विभाग पर सभी जगह पर उनकी हुकूमत होती है। दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं बची जिसको कि इन्होंने नहीं उलटा। फिर भी कहती हैं कि मर्दाने हमें गुलाम बनाकर रखा। यहां पर जितने माननीय सदस्य हैं वे अधिकांश ऐसे होंगे जो कि हुकूमत का मुकाबिला कर सकते हैं लेकिन अपने घरों में उनकी क्या दशा होती है यह सभी जानते हैं। इस तरह कहने का बराबर एक फैशन चल पड़ा है। जब कभी उन को अधिकार मांगना होता है तो कहते हैं कि मरदों ने हमारा शोषण किया है, यह गलत बात है। बिना किसी रिजर्वेशन के भी उनकी ताकत बढ़ी हुई है। आज कोई पार्टी नहीं है कि जिस में इन का हाथ न हो लेकिन क्या होता है कि हज़ार बार कहने पर भी ये लोग स्वयं आगे नहीं बढ़ते हैं। इसलिये हम पर इस प्रकार का दोष न दिया जाय कि पुरुष हम को खड़ा नहीं होने देते। मैं कहना चाहता हूँ कि उनको अब हमारे सहारे खड़ा न होने दिया जाय। इस तरह की मांग करना बिल्कुल गलत है। यदि स्त्रियां पुरुषों के बल पर इस तरह का अधिकार मांगती हैं तो वह गलत चीज है।

इसी तरह श्री गौविन्द सहाय जी की बात पर हमें बड़ा आश्चर्य हुआ। वह खुद भी कह रहे थे कि इससे रिप्रेजेंटरी बातें हो सकती हैं। मैं इस बात को मानता हूँ कि माइनारिटी का ख्याल रखना चाहिये लेकिन इसी बात के ऊपर हमारे देश का बटवारा हुआ है। मजहब के नाम पर जब यहां पार्टियां बनीं तो उसका यह नतीजा हुआ कि हमारा देश बंट गया। हम समझते हैं कि हमारे देश के बटवारे के बाद हमारी आंखें खुली होंगी कि भविष्य में हम ऐसा नहीं करेंगे। हमारे गौविन्द सहाय जी इन्कलाबी देश चीन से अभी लौटकर आए हैं। सचमुच में हमें यह आशा थी कि वह इस तरह के संदेश लायें जिस से हम अपने देश को भी आगे चलायें। लेकिन आपको ख्याल होगा कि हिन्दुस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी ने पाकिस्तान बनाने में काफी हाथ बटाया था। जो उन्होंने कहा कि माइनारिटी को भी रिजर्वेशन मिलना चाहिये उससे

[श्री राजाराम शास्त्री]

भले ही मुसलमान खुश हो जायें लेकिन देश का भला नहीं हो सकता। हो सकता है कि वोट लेने के लिये रिजर्वेशन किया जाय मगर मैं इसका सख्त विरोध करता हूँ कि मुसलमानों के लिये और स्त्रियों के लिये रिजर्वेशन रखा जाय। लेकिन सत्य बात कहने से भी बाज न आऊंगा अच्छा हुआ कि उन्होंने अपना संशोधन इस तरह का सदन के सामने नहीं रखा। अगर वह इसे पेश करते तो कोई मुनासिब बात नहीं होती। मैं माननीय मंत्री से अन्त में इतना जरूर कहूंगा कि आप ने जो रिजर्वेशन की बातें नहीं मानी हैं वह ठीक किया है। मैं इस को पसन्द करता हूँ। मैं विद्वान् करता हूँ कि अगले १० साल के बाद जो शेड्यूलकास्ट का रिजर्वेशन है वह भी खत्म हो जायेगा। मैं जानता हूँ कि थोड़े दिनों के बाद वह भी शक्तिशाली हो जायेंगे। फिर तो न मर्द और न औरत का सवाल होगा और न हिन्दू व मुसलमान का सवाल होगा। जो योग्य होगा और अच्छा होगा, उसको जनता चुनेगी। अभी तो शेड्यूल कास्ट के लिये आर्थिक दृष्टि से रखा गया है।

आखिर मैं, माननीय मंत्री जो से अपील करूंगा कि आपको इतना जरूर ख्याल रखना होगा कि निर्वाचित प्रेसिडेंट और मेम्बरों को हटाने का जो अधिकार रखा है वह समझदारी से इस्तेमाल किया जायेगा। आपके हाथ में इसके लिये ताकत दी गयी है वह ताकत कोई खराब नहीं है। इसलिये हमें पूर्ण आशा है कि जो कानून हम पास करने जा रहे हैं उसका सदुपयोग होगा। हम निश्चित रूप से आपको बधाई देते हैं कि आपने चुनाव कराने के लिये इस बिल में कहा है। इसके साथ ही साथ इस बात की भी बधाई देते हैं कि आप ने इस सदन में किये गये प्रत्येक क्रिटिसिज्म को अच्छी तरह से टेक अप (take up) किया है।

*श्री ह्यातुल्ला अंसारी (नाम निर्दिष्ट) — जनाब डिप्टी चैयरमैन साहब, मुझे अफसोस है कि इस वक्त जनाब गोविन्द सहाय जी मौजूद नहीं हैं वरना उन्होंने जो कुछ तकरीर की है उससे मैं कुछ फायदा उठाता क्योंकि उनकी तकरीर का आधा हिस्सा उन्हीं के खिलाफ जाता है। उन्होंने साफ-साफ यहां पर कहा कि हमें जो कुछ करना चाहिये वह एक उसूल को मद्देनजर रखकर एक मुसतकबिल, भविष्य को सामने रखकर करना चाहिये। उन्होंने यह भी कहा कि हिन्दू मुसलमानों को सीट का अलग-अलग रिजर्वेशन होना चाहिये। इस उसूल से दिल में एक बदख्याल पैदा होता है।

“कैसे तीरन्दाज हो सीधा तो कर लो तीर को”

मैं पुरानी बहस को याद दिलाना चाहता हूँ जिसमें अलग अलग इन्तखाब होने का जिक्र है। मैं तो समझता हूँ कि तादाद के मुताबिक रिजर्वेशन आफ सीट होना चाहिये। इस सिलसिले में मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ। अब्दुल गफ्फार खां पंजाब की हदसे खड़े हुए, पंजाब की हद पर सिर्फ वही एक घराना था। उनके लिये तमाम फिस्केवाराना बातें हुई और बहुत सी उनके खिलाफ तकरीरें की गईं। तरह तरह की बातें उनके खिलाफ कही गईं। चूंकि वह पाकिस्तान के करीब था, इसलिये जितनी बातें पाकिस्तान में होती थीं उन सब का गुनाहगार उन्हीं को करार दिया गया, गोया कि वह मुसलमानों के रिप्रेजेंटेटिव हैं। नतीजा यह हुआ कि इन्तखाब हुआ और जो कुछ अन्जाम हुआ वह सबके सामने आया। इसी तरह से ५० पी० में भी लोगों का ख्याल था। सोशलिस्ट पार्टी का भी ख्याल था और लोगों का भी ख्याल था कि जिन सीटों से मुसलमान खड़े हुये हैं वह तो हाथ से गईं। यहां पर भी इन्तखाब हुआ और उसका जो शानदार नतीजा हुआ वह सब लोगों ने देखा ही है। मुसलमानों की सीटों का जो कुछ नतीजा हुआ, वह सबके सामने आ ही गया। यहां पर इन्तखाब में दो बातों का डर था एक तो यह था कि जिन सीटों से मुसलमान खड़े हुये हैं, वह हाथ से गईं और दूसरे यह डर था कि मुसलमान उम्मीदवारों को जनता वोट भी नहीं देगी। इस इन्तखाब होने के बाद इन सब बातों का सबूत मिल गया है। मैं समझता हूँ कि यह जो रिजर्वेशन आफ सीट का सवाल है,

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

वह मुसलसल गतल है। श्री गोविन्द सहाय जी काफी तजुबेकार हैं और उन्होंने इस बात को देख लिया है कि लोग इस बात को नहीं देखते हैं कि वह हिन्दू है या मुसलमान है बल्कि पार्टी को देखते हैं कि वह किस पार्टी से ताल्लुक रखता है। वोट हिन्दू या मुसलमान को नहीं दिये जाते हैं बल्कि वोट पार्टी को दिये जाते हैं। जहां भी वोट की फहरिस्त आती है, तो इस बात को बिलकुल साफ कर दिया है, इनमें कोई गुंजाइश नहीं है। जो पुरानी सियासत थी, उसमें खीरू के अलावा एक बात और भी थी और वह यह कि हम करना क्या चाहते हैं और किस चीज को अमल में लाते हैं। यह एक बहुत बड़ा सवाल होता है। इस सिलसिले में मैं मौलाना मुफ़्त अहमद की बनावी हुई किताब है जिसमें साफ-साफ दिया हुआ है कि किस तरह से इन्तखाब किया जाता है वह मैं उठाकर पढ़ देना चाहता हूँ।

“इंगलिस्तान के एक मशहूर लिबरल स्थाल के अंग्रेज मि० विलियम्स फोर्ड ने हिन्दुस्तान की कौंसिलों और असेम्बलियों को देखकर कहा था कि यहां तो बर्जियों और मेम्बरों का काम यह है कि वह ग्रीहवों और मुनाफे के कामों को आपस में तकसीम करते रहते हैं और उन्हें फिरकेवाराना इन्तखाब में नफेग्राम्मा के कामों से मुस्तगनी और बेपरवाह कर दिया है। वजह यह है कि मौजूदा हालत में हिन्दू उम्मीदवार मेम्बरों को उस वक्त ज्यादा वोट मिलते हैं जब वह यह जाहिर करे कि वह उनके मजहब और कल्चर की हिफाजत के लिये मुसलमानों से लड़ेंगे। इसी तरह मुसलमान उम्मीदवार मेम्बर को ज्यादा वोट यह कहकर मिलते हैं कि वह हिन्दू से लड़ेंगे। यह हालत इस कदर बढ़ गई है कि उम्मीदवारों की खुशबस्ती से अगर इन्तखाब के करीब कोई हिन्दू मुस्लिम फिज्द हो जाता है तो दोनों का काम आसान हो जाता है। मुस्तसर यह कि वोटर्स और मेम्बरों के दरमियान फिरकावाराना या जुदागाना तरीके इन्तखाब की वजह से मुनाफा की तकसीम अमलन इस तरह हो गई है कि अबाम के हिस्से में तो मजहबी इस्तिलाफात का वजह से सर फूटना और इबादतखानों की तौहीन तनज्जुली है और मेम्बरों के हिस्से में जुमलये अक्साम के दुनियाबी मुफावाद आते हैं।”

यह हालत है हमारी सियासत की। मगर पूरे सियासत के माने से तो यह नुकते निगाह पैदा होता है और वह यह कि मुसलमान महसूस करता है कि हमको हिन्दू चुनकर लेना है और हिन्दू भी महसूस करता है कि हमको मुसलमान चुनकर लेना है, हालांकि दोनों की अक्सरियत और अक्लियत का मुकाबिला नहीं रह गया है। लेकिन पुरानी जहिनियत अभी तक है। यह सियासत तो चलती है और जब यह चली तो हम और बातों को भूल जाते हैं। और वह यह कि हमको किसानों के लिये क्या करना है, गरीब लोगों के लिये क्या करना है, सोसाइटियों के लिये क्या करना है। अगर इस तरीके से देखा जाय तो सब खत्म हो जाता है और अगर उसी तरीके की सियासत चलती रही तो दूसरे अन्दाज से उसका नकशा ही बदल जायेगा। अब जब कि एक तरफ हम कबूल करते हैं कि इलेक्शन हो जायें तो अच्छा होता कि श्री गोविन्द सहाय जी इसकी तरफ इशारा न करते। बहुत बिलचस्प बात यह है कि बिलकुल तो यह ठोक होता इन्हीं लरुजों में कहा गया है कि मुसलमानों के लिये सीट रिजर्व की जाय। इसी तरह से पाकिस्तान की पार्लियामेंट में हिन्दू मेम्बरों ने कहा है कि हिन्दुओं के लिये सीट का रिजर्वेशन नहीं होना चाहिये। वहां आपको मालूम होगा कि हिन्दुओं के लिये रिजर्वेशन आफ सीट्स है क्योंकि वहां उनकी माइनारिटी है और वहां सारी लड़ाई रही है कि यह रिजर्वेशन खत्म किया जाय क्योंकि वह थोड़े से आदमी हैं। वह अगर बोलते हैं तो उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है इसलिये उनकी अलग न रक्खा जाय। आज वहां कसरत है मुसलमानों की और उनकी लड़ाई भी देखने के काबिल है, वहां उनका फिरकेवाराना रंग है, वहां आजकल यह चलता है कि कादियानियों की रिजर्वेशन आफ सीट दिया जाय क्योंकि वह कहते हैं कि इनका मुसलमानों से कोई ताल्लुक नहीं है। मगर वह लड़ रहे हैं कि हमको अलग न किया जाय। तो वहां जो लड़ाई लड़ी जा रही है, उसका ख्याल रखते हुये श्री गोविन्द सहाय जी ने भी बिलकुल उन्हीं अलफाज में कहा है कि मुसलमानों को सीट का रिजर्वेशन दिया जाय। जैसा कि यहां पर कहा गया है कि गवर्नमेंट ने सब अख्तियार ले लिये और वह कर दिया, यह कर दिया, यह सब देखने के बाद एक ऐसा ढंग निकल गया कि सारी सियासत कम्यूनल झगड़े में बंट गयी और गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकी।

[श्री हयातुल्ला अंसारी]

एक चीज और कही गई है और वह मेरे दोस्त गोविन्द सहाय जी ने कही है। उन्होंने यह कहा कि मुसलमान जो कांग्रेस के साथ हैं वह शो बॉय (show boy) हैं। वह चाहे भले ही इस चीज को कहें कि मुसलमान उस वक्त कांग्रेस में नहीं थे और मुसलमान उसी वक्त कांग्रेस में आये जब कि इनामात बंट रहे थे, लेकिन यह बात गलत है। मुसलमान उस वक्त भी कांग्रेस में थे जब कि वे जेलों में गये जब कि उन्होंने तकलीफें सहें और जब कि उन्होंने हर तरह से कांग्रेस का साथ दिया। तो उनका यह कहना कहां तक ठीक हो सकता है। मुसलमान तीस साल से उसमें हैं और उसकी सियासत में उसने हिस्सा लिया है और अब तक वह उन्हीं के साथ चलती रही है और उसमें काम करती रही है, चाहे वह मुसलमानों की तरफ से कम्यूनल करार दे दिये गये हों। बाद में जब मुस्लिम लीग आई तो उसने इन मुसलमानों की भी काम्यूनल करार किया। और उन मुसलमानों से हमेशा एक्जिलाफ किया, फिर भी आप ऐसी बातें कहते हैं तो इस तरह से आज मुसलमानों को शो बॉय कहना बिल्कुल गलत है। यह कोई मामूली बात नहीं है, इससे बहुत बुरा असर पड़ता है और उन मुसलमानों को शो बॉय कहना आपकी सरासर गलती है। अगर आप इस बात की इन्क्वायरी करेंगे तो यह खुद अपना एक सबूत रखता है। ऐसी बात तो सिर्फ़ फिरकेवाराना लोग ही कह सकते हैं और आप इस तरह की बात कह कर जबरदस्ती फिरकेवाराना लोगों को भड़काना चाहते हैं और फिरकेवाराना फसाव को उठाना चाहते हैं। अगर आप एक नज़र से देखिये तो मैं पूछता हूँ कि मुसलमानों की सीटें क्यों अलग होनी चाहिये। इस तरह से हिन्दुओं के दिल में और भी बुरी भावना पैदा हो सकती है और उसमें बहुत सी खराबियां पैदा हो सकती हैं। तो मेरा कहना यह है कि इस तरह से चीजें तक्सीम नहीं होनी चाहिये। बंटे दुनियां में बहुत सी चीजें हैं जो कि तक्सीम नहीं होती हैं। गंगा नदी आज तक्सीम नहीं हो सकती है, जमुना नदी तक्सीम नहीं हो सकती है। किसी जगह का कच्चा तक्सीम नहीं हो सकता है। इस तरह से और भी बहुत सी चीजें हैं जो कि उगती हैं और जो कि आज बहुत बड़ी हुई भी हैं, मगर वे भी तक्सीम नहीं हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर आलू तक्सीम नहीं हो सकता है, पपीता तक्सीम नहीं हो सकता है और गुलाब भी तक्सीम नहीं हो सकता है। लेकिन तारीफ़ यह है कि यहां वह चीज भी तक्सीम हुई है। तो जो सही तौर से अपने को फिरकेवाराना समझते हैं, वे ही इन चीजों को तक्सीम कर सकते हैं।

आज इसकी सबसे बड़ी मिसाल उर्दू जवान की है। वह आज मुसलमानों की जवान कहलाई जाती है हालांकि इसके लिये पूरी तवारीख़ भरी हुई है और उसको देखा जा सकता है कि वह मुसलमानों की जवान नहीं है। आज मुसलमानों के यानी उर्दू के सबसे बड़े अख़बार यहां मिलाप और प्रताप हैं। मिलाप के तीन एडिशन निकलते हैं। तो आप इन दोनों अख़बारों का मुकाबला कीजिये तो आपको इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं मिलेगी जिससे पता चले कि यह मुसलमानों के लिये ही है। और दूसरे भी अख़बार हैं, तो इस तरह से उनमें उर्दू की जो बात कही गई है वह रुपये में एक आना के बराबर है। कोई मुसलमान और दूसरे अख़बारों को नहीं पढ़ता है और एक-दो अख़बारों में इस तरह की शिकायतें भी रहती हैं। ये आप नहीं कह सकते हैं कि इन अख़बारों को मुसलमान ही पढ़ते हैं। उसके अन्दर कोई कम्यूनल बातें नहीं होती हैं। तो आज इस तरह की बात को कह देना कि उर्दू मुसलमानों की जवान है, यह बिल्कुल गलत है और इसके लिये तवारीख़ भी देखी जा सकती है। आज तवारीख़ को देखने के बाद यह कोई नहीं कह सकता है कि उर्दू मुसलमानों की जवान है। इस तरह की निगाह लोगों की बदलनी चाहिये और लोगों को यह महसूस करना चाहिये कि वे ऐसी ग़ैर जिम्मेदाराना बात न कहें। इससे फिरकापरस्ती और भी बढ़ सकती है। और लोग यहां पर जो भी बात कहते हैं उसकी पूरी-पूरी तस्वीर नहीं खींचते हैं। इस किस्म की चीज से ख़तरा भी पैदा हो सकता है। इस तरह

से जो भी बात यहां कही गई हो उससे मुझे डर होता है कि लोगों को इससे बहुत नुकसान न पहुंच जायें। मुझे अफसोस है कि इस समय वह साहब मौजूद नहीं हैं, नहीं तो मैं उनको बतलाता कि हकीकत में उनकी बहस क्या थी, उन्होंने क्या कहा था और अगर वे उसका सही अन्दाजा लगाना चाहें, तो वे इस बात को देखें कि मैंने क्या कहा है।

श्री प्रतापचन्द्र आज़ाद—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह विधेयक आज जो कौंसिल ने पास किया है उसे मैं यह समझता हूँ कि हमारे राज्य में डेमोक्रेसी का द्योतक है और सही मानी में अगर हम इस बिल के अनुसार शहरों में चुनाव करायें तो मैं यह समझता हूँ कि इस बिल के अन्दर वह तमाम चीजें मौजूद हैं जो एक प्रजातन्त्र के उसूल में हो सकती हैं। मैं बिना शक यह कह सकता हूँ कि अगर इस बिल को देखा जाय तो मालूम होगा कि यह बिल म्यूनिसिपैलिटीज के अन्दर एक अच्छी खासी क्रान्ति पैदा करता है और पुरानी तारीख को बदलने का एक नया रास्ता दिखाता है। डेमोक्रेसी के अन्दर २, ३, ४ सूरतें हुआ करती हैं और उन पर अगर कोई कानून या बिल पुरा उतरता है तो सही मानी में डेमोक्रेसी वहां कामयाब हो सकती है। पहली सूरत प्रजातन्त्र के लिये यह होती है चुनाव की व्यवस्था इस प्रकार की हो जिससे उसके अन्दर निष्पक्षता की झलक दिखाई दे। इस बिल का जहां तक सम्बन्ध है उसके अन्दर नई चुनाव व्यवस्था है यानी एलेक्ट्रल रोल बनने से लेकर और जिस एथारिटी के हाथ में यह काम दिया गया है वह काफी निष्पक्ष व्यक्ति के हाथ में दी गई है। दूसरी चीज प्रजातन्त्र की कामयाबी के लिये जरूरी जो होती है वह यह कि बिना किसी जांत-पांत के भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति जो बालिग हो उसको पूरा अधिकार हो कि वह अपनी राय को स्वतंत्रता के साथ इस्तेमाल कर सके। तो मैं यह भी देखता हूँ कि इस बिल के अन्दर वह बात भी मौजूद है और रिजर्वेशन आदि जो डेमोक्रेसी के दुश्मन हैं वह इसमें नहीं हैं; जहां तक स्त्री और पुरुषों का सम्बन्ध है वह भी मैं समझता हूँ कि ठीक नहीं है इसलिये कि इन चीजों को अब आप कब तक चलने देंगे कि यह हिन्दू है और यह मुसलमान है, यह स्त्री और यह पुरुष है हमें तो अब ऐसा एटमास-फियर लाना है जिसके अन्दर रह कर हम अपने को एक सोसाइटी महसूस करें। हर औरत और आदमी के एक ही अस्तित्व है वह जहां चाहे खड़ी हो सकती है और जहां चाहे वोट दे सकती है। किसी प्रकार की कोई अड़चन नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि आदमी खड़ा हो तो औरत वोट न देगी और ऐसा भी नहीं है कि औरत के खड़े होने पर पुरुष वोट न देंगे। इसलिये मैं समझता हूँ कि यह प्रथा अब और अधिक दिनों तक नहीं चलने देना चाहिये।

तीसरी चीज जो डेमोक्रेसी ढांचे के लिये ध्यान में रखने के काबिल है वह यह है कि उस ढांचे के जो कर्मचारी हों उनके जो राइट हों उनकी पूरी रक्षा होनी चाहिये सो भी इस बिल के अन्दर पूरी तरह से मौजूद है। कमेटी का झमेला खत्म करके उसमें भी ऐसा कर दिया है कि जैसा अभी संशोधन में था। कहीं पर सुपरिंडेंट, कहीं पर चेयरमैन एजुकेशन कमेटी, कहीं पर प्रेसीडेंट बोर्ड। इस बात का बहुत जोर दिया गया और वह यह कि हमारे बहुत से साथियों ने कहा कि एक लोकलसेल्फ गवर्नमेंट बोर्ड बनाना चाहिए और उन्होंने इसको अहमियत इसलिए और भी ज्यादा जाहिर की कि इस लोकलसेल्फ गवर्नमेंट बोर्ड के जरिए से जो भी कर्मचारी अपाइन्ट होंगे उनके साथ निष्पक्ष तौर से न्याय होगा। मैं समझता हूँ कि म्यूनिसिपल बोर्ड की डेमोक्रेसी और म्यूनिसिपल बोर्ड के अस्तित्वारात् को यह चीज बटल करती है। जब हम म्यूनिसिपल बोर्ड से को बनाते हैं, जब हम जनता को यह अस्तित्वारात् देते हैं कि अपनी राय से म्यूनिसिपल बोर्ड के प्रधान को चुने, जब हम जनता को यह अस्तित्वारात् देते हैं कि वह अपनी राय से मेम्बरों का चुनाव करे उसके बाद हम यह शक करने लगें कि जो जनता द्वारा प्रधान चुना जायेगा या जो मेम्बर चुने गए हैं, उनका जो बोर्ड बनाया गया है वह वहां के कर्मचारियों के साथ पूरे तौर से न्याय नहीं करेगा और उनके साथ अन्याय करेगा तो मैं समझता हूँ कि यह चीज डेमोक्रेसी के विपरीत है। जब हम इतने बड़े बोर्ड को चुनकर बैठाते हैं, जिसको सारे शहर की जनता का विश्वास हासिल होता है उस पर हम तुरन्त अविश्वास प्रकट करें और यह कहें कि इसके हाथ बांधने के लिए कोई लोकलसेल्फ

[श्री प्रताप चन्द्र आजाद]

गवर्नमेंट बोर्ड होना चाहिए जो सारे कर्मचारियों की नियुक्ति करते तो मैं समझता हूँ कि यह बात मुनासिब न होगी। जो बात गरीब अमीर वाली बार-बार कही जाती है उस बात को इतनी बार कहे जाने के बावजूद भी मैं नहीं समझा और आज उन्होंने एक बात और कह दी कि इतने बड़े चुनाव में धन के बल पर लोग चुने जाते हैं।

श्री कुंवर गुरु नारायण—मैं समझता हूँ कि कोई नई चीज कही जाय, या जो प्वाइन्ट्स डिस्कस होने को रह गए हों उन्हीं को कहा जाय तो ज्यादा अच्छा होगा। राजाराम जी ने जो कहा उसका जवाब आप दें, गोविन्द सहाय जी ने जो बात कही उसका जवाब कोई दूसरे सज्जन दें, तो इस तरह तो बेकार में समय नष्ट होता है।

श्री राजाराम शास्त्री—पहले आप एक नमूने की स्पीच कर दें।

श्री प्रतापचन्द्र आजाद—मैं तो चुनाव के सम्बन्ध में ही बात कर रहा था। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज कर रहा था कि जहाँ तक एडल्ट फ्रीचाइज के अन्दर चुनाव का सम्बन्ध है मैं यह समझता हूँ कि इसमें रुपया देकर वोट हासिल करना संभव नहीं है। एक शहर में जहाँ कि दो लाख, तीन लाख वोटर्स हैं, एक प्रधान जो कि तीन लाख वोट हासिल करने के लिए अपना नामिनेशन कराता है चाहे वह किसी पार्टी का हो, चाहे वह कितना ही मालदार क्यों न हो लेकिन मैं समझता हूँ कि यह सम्भव नहीं कि तीन चार लाख वोटर्स को रुपया देकर कोई आदमी वोट हासिल करे। तीन चार रुपया प्रति आदमी देकर भी अगर वोट हासिल करे तो भी मैं समझता हूँ कि कम से कम १५, २० लाख रुपया अगर खर्च करे तब शायद इस बात का इरादा कर सकता है कि मैं रुपया देकर वोट हासिल करूँ। पिछले जो जनरल एलेक्शन हुये उनमें हो सकता है कि दूसरी बहुत सी बुराइयाँ रही हों लेकिन मेरा अपना यह विचार है कि बुराइयों के साथ किसी भी विरोधी बल के माननीय सदस्य ने यह बात नहीं बताई कि रुपये के लालच से वोटर तोड़े गए। जहाँ लाखों की संख्या में वोटर होते हैं वहाँ पर इस प्रकार रुपया पैसा देकर वोट को हासिल करना मैं समझता हूँ कि यह चीज सम्भव नहीं है।

मजदूर वाली बात और गरीब वाली बात जिसको अभी श्री राजाराम शास्त्री जी ने कहा था लेकिन उन्होंने कोई सुझाव नहीं दिया है कि उस मजदूर का प्रतिनिधित्व पेश करने के लिये उसके अन्दर क्या होना चाहिये। रिजर्वेशन की बात जहाँ तक सम्भव है मैं समझता हूँ कि यह डेमोक्रेसी के प्रिन्सिपल के खिलाफ है। मुझे खुशी हुई कि इसको आपसेन में नहीं रखा गया है। चाहे वह कांग्रेस गवर्नमेंट हो, चाहे वह सोशलिस्टों की गवर्नमेंट हो, चाहे कोई गवर्नमेंट हो। जब कभी नामिनेशन करते हैं तो वे अपने नुक्तये निगाह से करते हैं। मैं बिला शक यह भी कह सकता हूँ कि ज्यादातर जो नामिनेशन होते हैं वे उसी पार्टी के होते हैं जिस पार्टी की गवर्नमेंट होती है। इस वजह से फेयर चुनाव और निष्पक्ष एलेक्शन के लिये मैं यह समझता हूँ कि यह निहायत जरूरी था। नामिनेशन का जो यह सिस्टम है उसको समाप्त होना चाहिये। माननीय मंत्री जी के भाषण के बाद मैं इस नतीजे पर पहुँचा कि वे बातें जो चुनाव के लिये बनेंगी उनमें आ जायेंगी या जब अगला म्युनिसिपल बोर्ड का बिल पास होगा उसमें पूरा हो जायेगा। एक दो बात ऐसी हैं जिसको मैं सुझाव के तौर पर पेश करना चाहता हूँ। मुझे इस प्रकार की पूर्ण आशा है कि रूल्स बनते समय इसको ध्यान में रखा जायेगा। एलेक्शन के सम्बन्ध में हम गरीब और अमीर के भेद को मिटाना चाहते हैं तो हमें एक बात पर अवश्य ध्यान देना चाहिये। जिस तरह से जनरल एलेक्शन में हुआ कि चुनाव में कोई आदमी सवारी का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। तांगा, लारी इस प्रकार की सवारियों का प्रोहिबिशन जनरल एलेक्शन में म्युनिसिपल बोर्ड का जो एलेक्शन हो, उसके अन्दर एक प्रोसेड्योर बनाना चाहिये कि किसी प्रकार की सवारी कोई कैंडीडेट न इस्तेमाल करे। जो धनी वर्ग के लोग हैं वे चुनाव में सवारी इस्तेमाल कर

सकते हैं और गरीब जनता सवारी इस्तेमाल नहीं कर सकती है। जो सवारी इस्तेमाल करता है वह बोर्डर्स को जल्दी ला सकता है और जो सवारी नहीं ला सकता है, उसके बोर्डर बाद में आते हैं इससे उसको नुकसान पहुँचता है। जब रूल्स और प्रोसेड्योर बनेगा तो उसमें इस बात का ध्यान रखा जायेगा।

पिछले जनरल एलेक्शन में देखा गया कि पालियामेंट और असेम्बली के चुनाव में बिलेट पेपर एक ही स्थान पर मिलता था। अक्सर जो मतदाता थे उन्होंने ऐसा किया कि दोनों बिलेट पेपर एक ही बक्से में डालते थे। बिलेट बाक्स जो थे वे एक ही स्थान पर रखे गये थे इसलिये इस चुनाव में भी यह सम्भावना हो सकती है कि मस्टी मेम्बर का आदमी पाँच पेपर लाये लेकिन वह ज्यादा पढ़ा लिखा न होने के कारण और ज्यादा समझदार न होने कारण उन तमाम पेपरों को एक ही बिलेट बाक्स में डाल सकता है। इससे गड़बड़ी हो सकती है। मैं सुझाव के तौर पर यह अर्ज करना चाहता हूँ कि जहाँ तक हो सके या तो सिंगिल मेम्बर कान्सटीट्यूएन्सी बनाई जाय और यदि ऐसा सम्भव न हो तो कम से कम यह जरूर हो कि बिलेट पेपर्स के बक्स इस प्रकार से इतनी दूर-दूर रखे जाय कि एक मेम्बर एक बक्स में एक ही बिलेट डाल सके।

तीसरी चीज में यह कहना चाहता हूँ कि इसके अन्दर जो प्राविजन सस्पेंशन का रखा गया है, मैं माननीय मंत्री जी के भाषण सुनने के बाद यह समझा हूँ कि वह जरूर आवश्यक था लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि इसका इस्तेमाल उसी हालत में किया जाय जब इसकी बहुत ही खास जरूरत आ पड़े और इसको इस तरह से न बनाना चाहिये जैसा कि रिमूवल का है।

अब आखिर में मैं रिजर्वेशन के सम्बन्ध में कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। जहाँ तक श्री गोविन्द सहाय ने रिजर्वेशन के सम्बन्ध में इम्फैसिस की। मैं तो यह समझता हूँ कि शायद आज हमारे मुसलमान भाई जो इस हाउस के मेम्बर हैं या इस हाउस के मेम्बर नहीं हैं बाहर हैं उनकी भी अगर राय ली जाय तो मेरा अपना विचार है कि आज हिन्दोस्तान और पाकिस्तान बनने के बाद रिजर्वेशन और सेपरेट एलेक्टोरेट के नतीजे और उनसे होने वाली बर-बादियों को देखने के बाद ६६ फीसदी मुसलमान ऐसे हैं जो एक राय होकर यह कहेंगे कि रिजर्वेशन आफ सीट ही भारत के डुबोने का कारण है। आज हिन्दोस्तान के अन्दर जितनी खराबियाँ हैं और कम्यूनलिज्म है, यह सारी खराबियाँ जो अमल में आईं उनका कारण सेपरेट एलेक्टोरेट और रिजर्वेशन आफ सीट ही है। श्री गोविन्द सहाय की इस बात को सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ लेकिन मैं समझता हूँ इसमें उनका भी दोष नहीं है। उन्होंने कहा कि माननीय मंत्री जी का यह बिल मुझे ऐसा मालूम होता है जैसे एमलेस आदमी को यह नहीं दिखाई पड़ता है कि वह कहाँ जाय। श्री गोविन्द सहाय के सम्बन्ध में भी मुझे ऐसा ही मालूम पड़ता है। उन्हें आज यह नहीं मालूम होता है कि वह क्या कहें और क्या न कहें। रिजर्वेशन आफ सीट का जब एबालिशन हुआ था तो वह भी कांग्रेस में थे, कांग्रेस में ही नहीं थे बल्कि गवर्नमेंट पार्टी के एक जिम्मेदार आदमी थे। उस समय इन्होंने इसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाई। आज मैं इस आवाज के उठने का एक ही कारण समझता हूँ। जैसे डूबनेवाले को एक तिनके का ही सहारा होता है उसी तरह से आज वह हिन्दुओं के नाम पर, मुसलमानों के नाम पर यह आवाज उठा रहे हैं ताकि मुसलमान भाई यह समझें कि आखिर उन्होंने उनके लिये कुछ कहा तो। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि वह उनको खुश करना चाहते हैं। उन्हें यह नहीं मालूम कि आज मुसलमान भी उस चीज से उतना ही चिढ़ता है जितना हिन्दू। और आज कोई भी आदमी जो समझदार है वह इस बात को नहीं चाहता है कि रिजर्वेशन आफ सीट्स के नाम पर कोई चीज बाकी रहे। इसलिये मैं समझता हूँ कि यह रिजर्वेशन आफ सीट्स का मसला बिलकुल आउट आफ डेट है। इसलिये मैं समझता हूँ कि बिल हर प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अन्त में मैं आशा करता हूँ कि इस बिल के अनुसार जहाँ तक हो सके जल्द से जल्द चुनाव हो जिससे जो बातें इस बिल के अन्दर रखी गई हैं वह अमली रूप में

[श्री प्रताप चन्द्र आजाद]

आवें। और जो हमारे म्यूनिसिपल बोर्ड हैं वह एक डेमोक्रेटिक म्यूनिसिपल बोर्ड बन सकें। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ।

श्री प्रभु नारायण सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, संशोधनों के बाद जो बिल हमारे सामने आया है, उसको देखने से ऐसा मालूम होता है कि लोकतंत्र की परम्परा को कायम करने की जो बहुत चर्चा होती रही है इस बिल से उस परम्परा की भावना झलकती नहीं है। जहाँ तक सवाल इस बात का है कि नया बिल ला करके और तमाम मसलों को हल किया जायेगा जो कि स्वायत्त शासन के सिलसिले में पूर्ण होंगी इसको देखते हुये यदि इस बिल में ऐसे संशोधन हुये होते जिसमें कि केन्द्रीयकरण की जो प्रवृत्ति है वह कम हुई होती तो उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल का स्वागत इस माने में भी हुआ होता कि आज एलेक्शन करने के साथ ही साथ जो यह बिल थोड़ा स्वायत्त शासन की सीमा जो सीमित है उसमें और चाहे नियंत्रण किये गये हों लेकिन लोकतंत्र की भावना को ठेस नहीं पहुंचाया गया। संशोधन जो कि इस बिल में हो सकते थे आसानी से वह नहीं किये गये। आज वह बिल १९१६ की तरह का हमारे सामने है। जिस तरह से कि अंग्रेजों के शासन काल में बोर्डों का नियंत्रण जिला अधिकारियों के हाथ में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के हाथ में, कमिश्नरों के हाथों में रहा है वह अधिकार उनके हाथों में वैसे ही है और उसके साथ ही साथ सरकार नियंत्रण म्यूनिसिपल बोर्डों के ऊपर पा रही है बनिस्बत इसके कि स्वायत्त शासन का ख्याल करते हुये लोकतंत्र की परम्परा का ख्याल करते हुये शक्ति को विकेंद्रीकरण किया गया होता। यह कहा जा सकता है कि जब पूरे बिल को लायेंगे तो उसमें यह सब बातें रहेंगी लेकिन मैं ऐसा महसूस करता हूँ, बड़े-बड़े परिवर्तनों का ख्याल करते हुये कि छोटे-छोटे परिवर्तन को मान लिया जाता जो कि इस स्वायत्त शासन के सम्बन्ध में लाये गये थे। इस सिलसिले में यह जो बिल हमारे सामने है, उसको देखते हुये उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इतना ही कहना है कि आज सरकार को अधिक से अधिक इस बात की कोशिश करना चाहिये कि जब वह ताकत अपने हाथ में लेते हैं तो उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि वह कम से कम ताकत का सेंट्रलाइजेशन करे। मुझे यह बात कहते हुये दुःख होता है कि बनारस के म्यूनिसिपल बोर्ड के सिलसिले में सरकार की नीयत किस तरह की रही है। उससे इस प्रकार की मनोवृत्ति दिखाई पड़ती है कि सरकार की संज्ञा कहीं ऐसी तो नहीं है कि इस कानून को जिससे शक्ति केन्द्रीयकरण होता है उसका दुरुपयोग है। इसी सिलसिले में उपाध्यक्ष महोदय, मैं जिक्र करना चाहता हूँ कि बनारस कांग्रेस कमेटी हर साल म्यूनिसिपल बोर्ड के टाउन हाल में प्रदर्शनी करती है। इस सिलसिले में बनारस म्यूनिसिपल बोर्ड का बनारस कांग्रेस कमेटी पर २६ सौ रुपया बाकी है। उसके साथ ही साथ बनारस म्यूनिसिपल बोर्ड में एक कमरा कांग्रेस कमेटी ने तीन साल से कब्जे में ले रखा है लेकिन आज तक बावजूद कोशिश करने के भी वह कमरा म्यूनिसिपल बोर्ड खाली नहीं करा पाया है। अभी कल ही बोर्ड की मीटिंग में जो डिस्कशन हो रहा था वह इस सिलसिले में था कि बनारस में राजनैतिक सम्मेलन होने जा रहा है उसके लिये कांग्रेस कमेटी ने म्यूनिसिपल बोर्ड का ग्राउन्ड मांगा है। वहां पर जो इसकी बहस हुई उसको देखने से यह बात मालूम हुई है कि सरकार से इस बात के लिये इजाजत मांगी गई है कि बूक कांग्रेस कमेटी ने तीन साल से वह २६ सौ रुपया नहीं दिया है, इसलिये हम को कांग्रेस कमेटी पर मुकद्दमा करने की छूट दी जाय। मैं यह उदाहरण इसलिये दे रहा हूँ कि किस तरह से पार्टी के नाम पर केन्द्रीयकरण होतें हुये भी ऐसी हकतलफी होती है इस सिलसिले में उपाध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि.....

श्री एम० जे० मुकरजी (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—On a point of order Sir. This is beyond the scope of the Bill। यहां तो कांग्रेस का उदाहरण दे रहे हैं।

डिप्टी चेयरमैन—वह तो आप बोर्ड की पावर के बारे में कह रहे हैं।

श्री प्रभु नारायण सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम चाहते हैं कि इसमें पावर का भित्तिपत्र न हो इसलिये यह कह रहा हूँ। मैं बनारस कांग्रेस कमेटी का उदाहरण दे रहा था कि वह हर साल एक नया स्मारक बनाकर इस म्युनिसिपल हाल में छोड़ जाती है। वह तो इस तरह से कार्य करती है लेकिन जब उस पर मुकदमा चलाने के लिये स्वायत्त शासन विभाग से इजाजत मांगी जाती है तो वह इजाजत नहीं मिलती है और उसको हक नहीं दिया जाता है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि जिस तरह से नियंत्रण की बात है उसको देखते हुये हम इस बात को कहना चाहते हैं कि आज जो केन्द्रीयकरण की मनोवृत्ति है उस के लिये यह बिल हमारे सामने है। यदि इस के अन्दर विकेन्द्रीयकरण की मनोवृत्ति होती तो हम समझते कि यह लोकतंत्र का परिचायक है। हमारे माननीय सदस्य यहां पर खड़े होते हैं और इस बिल को लोकतंत्रवाद की आदर्शवादी कसौटी पर कसना चाहते हैं। हमें यह देख करके आश्चर्य होता है। अडल्ट सफरेज से चुनाव होने जा रहा है यह बात ठीक है, इसके साथ ही साथ रिजर्वेशन आफ सीट्स भी नहीं है लेकिन यह इस बिल को खसूसियत नहीं है वह तो १९४८ के बिल में आ गया था। आज जो बिल हमारे सामने है उसमें हम सोचते हैं कि कम से कम जो छोटे-मोटे मुद्दे हमने दिये हैं वे मान लिये गये होते तो इस में जो नौकरशाही का इलेक्टोरेट बाडी पर नियंत्रण है वह कम हो गया होता। इसमें सरकार का नियंत्रण है उसकी जगह पर किसी ईम्पाशियल बाडी का होता जिसमें कि उसके भी प्रतिनिधि होते। यह छोटी सी बात मान ली गयी होती तो हम समझते कि लोकतंत्र परम्परा का ब्याल किया गया है। उसके साथ ही साथ जब हम देखते हैं कि आज किसी भी बोर्ड को सुपरसीड कोने की कोई सीमा नहीं है तो भी हमें चिन्ता होती है कि लोकतंत्र मर्यादा का कहां ब्याल हो रहा है? इस बिल को देखने से ऐसा मालूम होता है कि जैसा अंग्रेज कहा करते थे कि हिन्दुस्तानी अभी शासन के योग्य नहीं हैं इसलिये वे शासन नहीं दे रहे हैं। जो बहस के सिलसिले में दलीलें दी गयी हैं उनसे यह मालूम होता है कि केन्द्रीयकरण इसलिये कर रहे हैं क्योंकि ये बोर्ड ठीक तरह से चला नहीं सकेंगे। तो यह दलील ऐसी ही है।

इसी के साथ-साथ इस बिल में कुछ कमियों को दूर किया गया है। प्रेसीडेंट के संबंध में जो एजुकेशनल क्वालीफिकेशन की बात रखी गयी है वह बहुत ही अच्छी है। उसके लिए जो संशोधन आया है वह बहुत ही अच्छा है चाहे वह कांग्रेस पार्टी के अधिक त्रिरोध की वजह से माननीय मंत्री जी ने इसको माना है या और कोई वजह से माना है। मैं समझता हूँ कि यह बात इस बिल में बहुत अच्छी है। मैं बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहता हूँ। मैं चन्द बातों की तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। इलेक्शन के रूलस बनाते वक्त आपको इस बात पर ध्यान रखना चाहिये कि इलेक्शन के संबंध में जो शुबहात और शंकाये पैदा हो गईं उनको दूर किया जाय। वॉलेट बाक्स पर लोगों का विश्वास रहे और प्रजातंत्र से भी लोगों का विश्वास न उठे। इसी के साथ-साथ गोविन्द सहाय जी ने रिजर्वेशन आफ सीट के लिए भी कहा। चूंकि अब थर्ड रीडिंग के वक्त इस का कोई सवाल ही नहीं उठता है, इसलिये अब इसका कोई सवाल ही उठाना बेकार है। लेकिन इस के साथ हम यह भी अपना हक समझते हैं कि हम भी इस पर अपनी राय जाहिर कर दें। गोविन्द सहाय जी ने जिस तरह से अपनी राय जाहिर की है वह बहुत ही खतरनाक और भयंकर तरीका है। आज मुल्क जिस परिस्थिति और वातावरण में है उसके आधार पर आप मुल्क को कम्युनिज्म की तरफ लिये जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि खराबियों को दूर करने के लिये उन्होंने जो यह सीट का रिजर्वेशन बताया है वह ठीक नहीं। हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे के वक्त सोशलिस्ट पार्टी ने इसकी मुखातिफत इस बिना पर की थी कि अगर हिन्दुस्तान और पाकिस्तान बनता है तो हिन्दू और मुसलमानों में एक जदो-जहद पैदा हो जायगी और धार्मिक आधार पर एक समाजवादी व्यवस्था पैदा हो जायगी। सोशलिस्ट पार्टी ने पाकिस्तान और हिन्दुस्तान के बंटवारे का विरोध किया था मैं देखता हूँ कि आज फिर इस तरह से रिजर्वेशन आफ सीट के सवाल को पैदा करना किसी तरह से

[श्री प्रभु नारायण सिंह]

भी ठीक नहीं है। मैं समझता हूँ कि इस ज़माने में वर्ग संघर्ष करना ठीक नहीं है। आज कल इस तरह से नारे लगाने से देश को हानि होने का खतरा है। हर एक का अपना प्रोग्राम होता है और उसी के आधार पर वह चलता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरी कांग्रेस सरकार से इस बात की शिकायत है कि जिस तरीके से जनरल इलेक्शन और दूसरे मौकों पर उन्होंने मुसलमानों को इस बात का डर दिखलाया कि यदि तुम कांग्रेस को वोट नहीं दोगे तो तुम मुल्क के साथ गद्दारी करने वाले समझे जाओगे तो इस तरह की जो बातें जाहिर की गई हैं वह न होनी चाहिये थीं। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस को भी अपने प्रोग्राम के आधार पर मुसलमान जनता के पास या किसी जनता के पास पहुंचना है और सोशलिस्ट पार्टी और दूसरी पार्टियों को भी इसी आधार पर जनता के पास पहुंचना है तो आज यह रिजर्वेशन का सवाल उठाना उचित नहीं है। यदि मुसलमानों के लिये रिजर्वेशन आफ़र सीट का सवाल उठता है तो कल फिर सिक्खों के रिजर्वेशन का सवाल पैदा होगा और परसों ईसाइयों के रिजर्वेशन का सवाल उठ सकता है। इस तरह से एक अज़ीबो गरीब शक्ल देश में पैदा हो जायेगी। श्री गोबिन्द सहाय जी हाउस में नहीं हैं लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि कोई भी माननीय सदस्य यदि हाउस में अपनी राय जाहिर करे तो उनको समझना चाहिये कि उनकी राय का कितना दुष्परिणाम और व्यवस्था को बदलने की गुंजाइश होगी मैं तो कहता हूँ कि वह केवल राय ही नहीं है बल्कि उसका एक भयंकर परिणाम भी हो सकता है अगर हम उनकी ज़िम्मेदारी को सोचते हैं। इन शब्दों के साथ मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो बिल इस सदन के सामने है उसको देखते हुये जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया कि यह लोकतंत्र की मनोवृत्ति का परिचायक है। माननीय मंत्री जी ने चूँकि यह आश्वासन दिया है कि वह दूसरा अर्मेडमेंट बिल इस सदन के अन्दर लाने वाले हैं या दूसरे सदन के अन्दर लाने वाले हैं, मैं अधिक कुछ न कह कर सिर्फ़ उनसे यह रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कांग्रेस सरकार का जो रवैया अब तक रहा है यदि वही रवैया रहा तब तो मुझे उम्मीद नहीं है कि कोई अर्मेडमेंट बिल इस संबंध का आयेगा। तब भी कोई एक आध कलाज को सुधारने की बात होगी और उसमें भी यही कहा जायेगा कि सदन के सामने यह बात रखी गई है उसमें इस किस्म की दिक्कत है इसलिये इसको इस वक्त पास कर दिया जाय और फिर दूसरा अर्मेडमेंट बिल आयेगा और इसी तरह की दूसरी बातें कही गई और बेकार का आश्वासन दिलाया गया तो कोई फ़ायदा इससे नहीं होगा। लेकिन मेरा विश्वास है कि जिस उत्साह से उन्होंने इस कार्यभार को लिया है उससे कम से कम मैं इस खतरे को नहीं समझता हूँ कि सन् १९३४ में कमेटी बनाई और उसके बाद सन् १९४० में रिपोर्ट आई और फिर १९४६ में कांग्रेस गवर्नमेंट आई और काफ़ी दिनों के बाद सन् १९५२ में इस सिलसिले का बिल कुछ बदलाव के साथ पेश किया गया तो अगर उस बिल में इसी तरह नौकरशाही की मनोवृत्ति रही तब तो किसी भी माने में इस सदन को वह मंज़ूर नहीं करना चाहिये। यदि इस इलेक्शन में ज्यादा देर न दी गई होती तो मैं समझता हूँ कि मैं कभी भी इस बिल को मानने के लिये तैयार नहीं होता इसलिये इन्हीं आबजर्वेशन के साथ कि यह बिल निकट भविष्य में सामने आयेगा, मैं इस बिल का स्वागत करता हूँ।

*श्री बद्री प्रसाद कक्कड़ (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—जनाब डिप्टी चेयरमैन साहब, निहायत खुशी का मौक़ा है कि एवाम के हर दो जानिब से इस बिल की खूबियों का काफ़ी अहसास हुआ और उसके ज़मीर में अपने ख़यालात के बमूजिब ख़यालात जाहिर किये हैं। मैं यह जानता हूँ कि मैं क्या हूँ, मैं डेमोक्रेसी का कायल हूँ। लेकिन जब दिलोदिमाग पर हरकत देखता हूँ तो उनकी हालत अजीब ही दिखलाई देती है, उनके ख़यालात कुछ अजीब रंग रखते हैं, कुछ अजीब ख़याल पैदा करते हैं। जहाँ तक बद्री प्रसाद कक्कड़ का सवाल है तो वह लोकल इन्स्टीट्यूट्स यानी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और म्युनिसिपल बोर्ड आज़ादी के बाद रहना या उनके रखने की कोशिश करने पर कतई एतमाद नहीं करता है। क्योंकि यह एक खिलौना था दिल बहलाने का और उस गवर्नमेंट का जिसने हमें गुलामी की जंजीरों में बांधकर बहुत से दिल बहलाने के

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया

खिलौने दिये, तो उनमें जो इन्स्टीट्यूशन्स थे, वेपे ही लोकल बाडीज थे और उनमें इसी का काम था। हमें इसी के इन्तजाम की कूबत करार दे दी गई और हमसे कहा कि तुमको इस बात का मौका है कि तुम अपने मुल्क का खुद इन्तजाम करो। चूँकि उसका गुलामी से ताल्लुक था, लिहाजा उससे वे गुलामाना हरकतें पैदा करना चाहते हैं। जब मैं अपने ह्याल की तरफ और जमाने की हरकतों की तरफ देखता हूँ कि मुझे खुद भी बहुत परेशानी होती है। मैं यह समझा करता हूँ कि यह करेण्डन क्यों पैदा होता है और वह भी एक छोट्टे से जिले में हुआ करता है। इसके लिये सिर्फ़ दो दलीलें हैं। उनमें से एक म्युनिसिपैलिटीज और दूसरा कलेक्ट्रेट है। इनके यहां तनख्वाहें इतनी कलाल होती हैं कि गुजर होना मुश्किल है और जब तनख्वाहें इतनी कलील होती हैं, तो नीयत भी उनकी बद हुआ करती है। लेकिन चूँकि मैं डेमोक्रेसी का कायल हूँ, इसलिये आज भी यह कहने का अख्तियार रखता हूँ कि जिस कवर आज म्युनिसिपैलिटीज और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को अपने इन्तजाम करने के लिये अधिकार दिये जा रहे हैं, वे भी बहुत कम हैं और अगर इससे भी ज्यादा हों तो और भी अच्छा और बेहतर है। हालाँकि जमाने की रंगत, रफतार, रंगोनियों और तब्दीलियों का एहसास सब करते हैं और हमें लखनऊ के जिनदा मिसाल से सबक लेना चाहिये, क्योंकि पारसाल लखनऊ म्युनिसिपल बोर्ड का इन्तजाम मंने खुद देखा जोकि अब एक आई० सी० एस० के तुपुर्व किया गया है, तो आप देखेंगे कि उसके काम में और उसके इन्तजाम में पहले से बहुत ज्यादा अच्छाई आ गई है। और पहले से कितना ज्यादा अच्छा इन्तजाम हो गया है। लिहाजा मुझे इस बात पर एतमाद होता है कि अगर म्युनिसिपैलिटीज में कहीं खराबी होती है, तो उनका सुपरसेशन करने के अलावा और कोई दूसरा इलाज नहीं है। मैं इस बात पर कायल हो जाता हूँ। मुमकिन है कि कोई दूसरा ऐसा एहसास न करता हो और वह दूसरी राय रखता हो लेकिन उसके लिये मुझे कोई ज़िद नहीं है। अभी मेरे भाई श्री गोबिन्द सहाय जी ने जोकि एक पार्लियामेन्टरी सेक्रेट्री पहले रह चुके हैं और जिनके बारे में मैं भी पहले बहुत वाजिब ह्याल रखता था, जो तकरीर की, तो मुझे दो चीजें याद आईं। मैंने जिस वक़्त उनकी जवान मुबारक से रिजर्वेशन की बात सुनी तो तबियत परेशान हो गई। मैं अपनी तकरीर से कोई एजिटेशन नहीं पैदा करना चाहता अगर वह मौजूद होते तो जिस वक़्त वह असेम्बली में थे और मैं काउन्सिल में था तो उस वक़्त की याद दिलाता और जो स्पीचें दोनों जगहों पर मुस्लिम लीग की तरफ़ से हुई थीं उनको दिखाता जिसका नतीजा पार्टीशन हुआ और जो सब पर रोशन है। एक मिसाल देता हूँ रोशन आरा और उसकी गुलामा का एक शेर है। उसकी गुलामा ने कहा—

“अज कज्जा आईने चीनी शिकश।”

उसने कहा कि तेरा कीमती अईना फूट गया उसके जवाब में उसने कहा—

“खूब शुद सामान खुद बीनी शिकश”

अच्छा हुआ साज सगार का सब सामान जाता रहा। तो आज क्या हो गया इधर हिन्दुस्तान और उधर पाकिस्तान। जनाब ने मालूम नहीं मौजूदा एलेक्शन में देखा या नहीं कि मुसलमानों की किस तरह की दिलशिकनी रही या किस तरह का शाक पहुँचा, पहुँचा तो जनाब को, इसके क्या मानी। मैं अपने जिले का एक छोट्टा सा किस्सा बताता हूँ। ७५ हजार की कांस्टीट्यूंसी थी उसमें मिनिस्टर अब्दुल रऊफ़ खड़े हुये थे। उसमें तादाद मुसलमानों की ५ हजार की थी जिनके खिलाफ़ फतेहपुर की निहायत बेहतरीन हस्ती थी मैं उसका नाम नहीं लूंगा लेकिन उसमें शिकस्त हुई। अभी हमारी एक सदस्या श्रीमती शिवराजवती नेहरू जी जो औरतों की एसोसियेशन की रूह खरवाँ हैं उनके ऐसे ह्याल वाली औरतों के दिल में भी रिजर्वेशन की बात हो यह समझ में नहीं आता है। कल हुजूर, बिल्कुल सच है, मैंने तफ़रीहान दस्तबस्ता उनसे अज किया था कि अब आप लोग परदे से बाहर आ गई हैं तो उन्होंने निहायत खूबी से एक शेर की तरफ़ इशारा किया—

“पूछा जो उनसे आप का परदा वह क्या हुआ।

कहने लगीं कि अक्ल पे मर्दों के पड़ गया।”

[श्री बट्टी प्रसाद कक्कड़]

जनाब, बहुत अच्छा ख्याल उन्होंने मुझे दिलाया। लेकिन मैं उनको शायर इकबाल की जानिब याद दिलाऊंगा। कबल इस को कि मैं याद दिलाऊँ, मैं बतलाना चाहता हूँ कि शोअरा अपने ख्याल में कुछ अजब उमंग रखते हैं और उसकी उमंगों में पहेलियाँ रहती हैं। उन पहेलियों में आप धोखा मत खाइये। इकबाल साहब फरमाते हैं:—

तुम्हारी तहजीब अपने खंजर से आप ही खुदकशी करेगी।

जो शाख नाजूक पे आशियाँ बनेगा नापायदार होगा।

देवियाँ मुझे माफ़ करें मैं किसी बदगुमानी और बद ख्याली से नहीं कह रहा हूँ न उनकी जात पर कोई हमलावर ही हूँ लेकिन अपने स्वतंत्र विचार रखते हुये मैं आपके सामने अर्ज करता हूँ। आज जो मुल्क में बच्चों की यह दशा है इस की वजह सिर्फ़ इनका कारमंसबी से अलग हो जाना और भूल जाना है।

यह चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो एक दिमाग़ को हरकत देती हैं और सच्चे विचार की तरफ़ रागिब करती हैं। आप अपना काम करें और हम अपना काम करें। दुनिया की तरक्की में कम से कम अपने सूबे की तरक्की में शामिल और मशगूल हो जायें। मेरे ख्याल से अगर कुछ भी उनकी दिल शिकमी हुई हो तो मैं माफी का ख्वास्तगार हुंगा। जनाबवाला मेरे भाई साहब कुछ और रिजर्वेशन चाहते हैं लेकिन वह खुद ही कायल हैं।

जनाबआली आक्ट्राय भी अपनी अहमियत रखता है अगर मेरे ख्याल से जनाब मिनिस्टर साहब अपने ख्याल को बाबस्ता करें तो यकीनन इस नतीजे पर पहुँचेंगे कि छोटे जिलों को सबसे बड़ी उनके बिजनेस में हानि पहुँचती है उस आक्ट्राय की वजह से। इस आक्ट्राय का जितना बिजनेस है सब ख़तम कर दिया। ऐसी सूरत में अपने मुशीरकार के जरिये से यह कोशिश करना चाहिये कि बिजनेस तरक्की करे। जब बिजनेस तरक्की करेगा तो मुल्क भी तरक्की करेगा। आज इंगलिस्तान अगर इस कदर ताकत में है तो सिर्फ़ अपनी तिज़ारत और बिजनेस की बदौलत। आखिर में एक चीज़ है लैंग्वेज की। मेरे एक दोस्त ने फ़रमाया और मैं भी उसी तरीक़े को इस्तेमाल करते हुये खुद अर्ज करता हूँ। हमारे सदन का विचार है the language must grow and it should not be enforced upon. इन चन्द शब्दों के साथ मैं इस बिल का दिल से स्वागत करता हूँ।

श्री ज्योति प्रसाद गुप्त (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)—उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं इस विषय पर कुछ अपना विचार प्रकट करना चाहता हूँ, इसके संबंध में हमने अनेक तकरीरें सुनीं। कुछ ऐसे भावों का प्रदर्शन भी यहां हुआ है। जिनको कि मैं शरारती कह सकता हूँ। उसके संबंध में बहुत काफ़ी इस सदन में कहा जा चुका है। मैं तो उसके संबंध में केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस शरारत की भावना में उनका कोई अधिक दोष नहीं है। यह तो १९१६ के क़ानून का असर है जिसमें अल्प संख्याओं को पृथक निर्वाचन अधिकार देने की गलती की गई थी। इस म्युनिसिपल ऐक्ट के अन्दर मुसलमानों के लिये सेपरेट एलेक्टोरेट का प्राविजन किया गया था उसका जो नतीजा हुआ वह सभी जानते हैं उसके बारे में अधिक कहने की ज़रूरत नहीं है। उसका नतीजा तो हम आज तक भुगत रहे हैं कितना रक्तपात हुआ, लाखों घर से बेघर हुये और करोड़ों रुपये की सम्पत्ति की हानि हुई। यदि इतने से संतुष्ट न होकर कोई सदस्य इस भवन में उसही शरारती भावना का पुनः प्रदर्शन करे तो उसका नतीजा वही होगा जो हम आज तक भुगत रहे हैं अन्यथा इस विषयक के संबंध में जो यहां पर कहा गया है उसको दोहरा कर मैं सदन का समय नहीं लेना चाहता हूँ। परन्तु एक दो बातें ऐसी हैं जिनके संबंध में मैं अपना विचार रखना चाहता हूँ।

प्रेसीडेंट और मेम्बर्स के सस्पेंशन के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। इस अधिकार को डेमोक्रेटिक सिद्धांतों के प्रतिकूल उस पुरानी अंग्रेजी मेन्टलिटी का प्रदर्शन बताया गया है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि इस किस्म के अधिकार हर कानून में मिलेंगे। हम देखते हैं कि हर कानून में कुछ सेफ गार्ड रखे जाते जिनके द्वारा सरकारी कर्मचारियों को संरक्षण दिया जाता है जिससे उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। प्रेसीडेंट व सदस्यों के सस्पेंशन अधिकार भी एक प्रकार का सेफगार्ड है। यदि वह अपने कर्तव्यों का ठीक प्रकार से पालन न करें तो कानून में ऐसी व्यवस्था होनी ही चाहिये कि उनको जांच के दौरान में मुअतल किया जा सके। यदि इस प्रकार का प्राविजन ऐक्ट में होता है तो नियमों का ठीक प्रकार से पालन होने की अधिक सम्भावना होती है। इस प्राविजन के न होने का यह नतीजा है कि बोर्डों में अनेक खराबियाँ चल रही हैं और सुधार का कोई प्रबंध गवर्नमेंट नहीं कर सकी है। इसलिये यह कहना कि यह डेमोक्रेसी के खिलाफ है और हम इस तरह से डेमोक्रेसी का खून करते हैं सर्वथा भलत है सेफ गार्ड जरूरी है। अगर कानून के अंदर उसके लिये प्राविजन न हो तो ठीक तरह काम चलना मुश्किल हो जायेगा।

दूसरी चीज जिसकी तरफ मैं तबज्जह दिलाना चाहता हूँ वह यह है कि हमको यह नहीं समझ लेना चाहिये कि इस प्रस्तावित कानून से हमारे जो म्युनिसिपल बोर्ड्स हैं उनकी सारी खराबियाँ दूर हो जायेंगी। मुझे तो वाकई उस वक्त ताज्जुब हुआ जब यह विधेयक हाउस के सामने आया, क्योंकि मेरी तो यह धारणा थी कि गवर्नमेंट शायद कोई ऐसा विधेयक लायेगी जिसके द्वारा जितने भी नागरिक जीवन के अंग हैं उन सबको सुव्यवस्थित करने का प्रबंध किया जायगा लेकिन ऐसा मालूम होता है कि इतना समय उनके पास नहीं था कि वह पूरा कानून बना सकते और चूंकि एलेक्शन की जल्दी थी इस लिये यही कानून संशोधन के रूप में रखना पड़ा। जरूरत इस बात की है कि एक पूरा म्युनिसिपल ऐक्ट बनाया जाय जिससे बोर्ड्स की जितनी खराबियाँ हैं वह दूर की जा सकें। बहुत सी चीजें आज इतनी पुरानी हो गई हैं कि उनको बदलने के सिवाय और कोई चारा नहीं है सब से बड़ी कठिनाई जो आज बोर्ड्स को है वह फाइनेन्सेज की है। केवल दो ही चीजों से बोर्ड्स को आमदनी होती है एक आक्टूआई और दूसरा हाउस टैक्स। इसके अलावा और भी छोटे-छोटे टैक्सेज हैं जिनसे कुछ आमदनी हो जाती है लेकिन मेन इन्कम का सोर्स आक्टूआई और हाउस टैक्स है। इन दोनों से इतनी आमदनी नहीं होती है कि बोर्ड्स का काम ठीक प्रकार चलाया जा सके। जहाँ तक आक्टूआई का संबंध है, बहुत सी आय तो आक्टूआई रिफंड की शक्ल में निकल जाती है। इसलिये हमें देखना है कि बोर्ड्स के फाइनेन्सेज का इंतजाम ठीक कैसे हो। हाउस टैक्स और आक्टूआई के अलावा आय के और भी साधन होने चाहिये। इन्टरटेनमेंट टैक्स, सेल्स टैक्स का भी एक हिस्सा बोर्ड्स को मिलना चाहिये। जो राज्य सरकार को म्युनिसिपल रकबे से प्राप्त होते हैं। बेहिकिल्स टैक्स का प्राविजन तो कानून में है लेकिन उसके साथ-साथ यह भी लिखा है कि मोटरों पर टैक्स नहीं लगाया जा सकता। यह किस आधार पर रखा गया है वह मैं नहीं समझ पाया। इस प्राविजन को पढ़ कर सुनाने की जरूरत नहीं है परन्तु यह तीन चार चीजें हैं जिनको अगर ठीक तरीके से देखा जाय तो बोर्ड्स उनके पाने के हकदार हैं। यह भी देखने की जरूरत है कि और क्या जरिये बोर्ड्स की आमदनी के हो सकते हैं।

साथ ही और भी अनेक बातें हैं जिनका जिक्र दफा ७ और ८ में किया गया है। बोर्ड्स के कर्तव्य तो बहुत लम्बे-चौड़े हैं लेकिन उनको पूरा करने के लिये बोर्ड्स के पास साधन कहां हैं। इसलिये इन कर्तव्यों को निर्धारित करने में यह देखना चाहिये कि बोर्ड्स को किस चीज को प्रायर्टी देना चाहिये। आज जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम म्युनिसिपैलिटीज के सामने है वह गरीबों को मकान प्रोवाइड करने की है। गरीबों के रहने का प्रबंध कैसे किया जाये जो कि आज बड़ी तकलीफ में रहते हैं। मैं

[श्री ज्योति प्रसाद गुप्त]

अपने शहर की बाबत कह सकता हूँ कि वहाँ पर सोहराबगट इत्यादि अनेक ऐसे स्थान हैं जहाँ पर गरीब लोग रहते हैं और ज्यादातर लेबर क्लास वहाँ पर रहती है। उस एरिया में न तो सफाई का ठीक इन्तजाम है न गलियों में खरन्जे हैं और न वहाँ पर लालटेन जलती हैं और सबसे बड़ी शहर की आबादी उन्हीं हिस्सों में रहती है। हमारी तबज्जह शहर की सिविल लाइन्स की तरफ तो जाती है, वहाँ पर जाती है जहाँ पर बड़े-बड़े लोग रहते हैं, पैसे वाले रहते हैं, लेकिन उन गरीब लोगों के रहने की जगहों की तरफ कतई नहीं जाती। हमको जहाँ अपने बोर्ड्स के फंक्शन नियत करने हैं वहाँ हमको देखना होगा कि किस चीज को प्रायर्टी देना है। इसी तरह से बेकारी (un-employment) अनइम्प्लायमेंट को प्रॉब्लेम है। एजुकेशन की प्रावलेम छोटे उद्योग-धंधों की समस्या है जो छोटी-छोटी काटेज इंडस्ट्रीज शहरों में हैं उनको भी सहायता देना है, उनको सुविधायें भी बेनी हैं। मैं यह नहीं कहता कि बोर्ड छोटी-छोटी इंडस्ट्रीज स्वयम् कायम करे, उसमें पैसा लगाये लेकिन वह कुछ सुविधायें तो दे ही सकते हैं। जैसे खादी है करघों का उद्योग है और दूसरी तरह की इंडस्ट्रीज हैं। हमारे यहाँ एक इंडस्ट्री है जिसमें कंचियाँ और रेजस बनाये जाते हैं। वह इतनी विस्तृत इंडस्ट्रीज है जिसके १५-२० हजार आदमी काम करने हैं। ऐसी इंडस्ट्रीज को तो सहायता दी ही जा सकती है। उनको कई तरह से सहायता पहुँचाई जा सकती है। परन्तु कानून में इस के लिये कोई प्राविजन नहीं है। इसको भी हमको देखना होगा मैं आपका ज्यादा वक्त न लेकर सिर्फ यह कहना चाहता हूँ कि सरकार जल्द से जल्द इस १९१६ के पुराने ऐक्ट को नया रूप दे। उसमें अभी तक २१ अमेंडमेंट पैबंद की तरह से लग चुके हैं जैसे कि पुराने कपड़े में जगह-जगह पैबन्द लगे रहते हैं वही इस ऐक्ट की शकल हो रही है। मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट एक मुकम्मिल कानून बनाये जिसमें सारी चीजों को सामने रखे और तब ही अपने नागरिक जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। मैं इसके साथ ही साथ यह भी कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से यह बिल यहाँ प्रस्तुत हुआ है ऐसा नहीं होना चाहिये। कानून का मसविदा पहिले से पब्लिस होना चाहिये ताकि लोग अपनी राय दे सकें, यह बतला सकें कि उनकी मांग क्या है। प्रस्तावित कानून को देख कर वह बता सकें कि उसमें क्या तस्मीम और होनी चाहिये। अगर ऐसा मौका हो तो अच्छे-अच्छे मुझाव हो सकते हैं। इसलिये मेरी दरखवास्त है कि नये बिल को तैयार करके इसको पहिले पब्लिस किया जाये और पब्लिक और बोर्ड्स की राय मांगी जाये। सब लोकल बाडीज की ओपीनियन मांगी जाये तो शायद ऐक्ट बनाने में अधिक सुविधा हो, और भी अनेक बातें हैं जिनके संबंध में कुछ कहना चाहता था लेकिन इस वक्त थोड़ी ही बातें कहूँगा। लोकल बोर्ड की सर्विस के मुताल्लिक भी यह एक प्रश्न है कि उनकी सिक्योरिटी का क्या इंतजाम हो। इन सर्विसेज की जरूर सिक्योरिटी होनी चाहिये। हम रोजाना देखते हैं कि बोर्ड के चेयरमैन इक्जीक्यूटिव आफिसर और वाटर वर्क्स के सुपरिन्टेन्डेंट इत्यादि में झगड़ा चलता रहता है। चेयरमैन के दिल में जो आता है वह सुपरिन्टेन्डेंट इत्यादि जैसे बड़े कर्मचारियों को सस्पेंड कर देते हैं फिर वर्षों तक झगड़े चलते हैं। चेयरमैन तथा इक्जीक्यूटिव आफिसर में भी कसमकस चलती रहती है। इस तरह की बहुत सी बातें हैं जिनके कारण हमें सर्विसेज के बारे में भी गौर करना होगा कि उनकी सिक्योरिटी कैसे हो। आया वह सर्विसेज प्राविशलाइज की जाय या उनका कोई दूसरा ऐसा इंतजाम हो कि वे एक बोर्ड से दूसरे बोर्ड में ट्रांसफर हो सकें। यह सब चीजें ऐसी हैं जिनका नये कानून बनाते वक्त ध्यान रखना होगा। अब मैं आप का अधिक समय न लेकर सिर्फ यह कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट अब नया म्युनिसिपल बिल बनाने में जल्दी करे। साथ ही जो कारपोरेशन का बिल वह बनाना चाहती है उसको भी साथ-साथ रख दें ताकि दोनों को सामने रख कर ठीक राय निश्चित हो सके। यह भी देखना होगा कि कहां-कहां और किन स्थितियों में कारपोरेशन कायम हो सकता है। अभी तक तो जो प्रपोजल है वह कानपुर और लखनऊ में कारपोरेशन बनाने का है। वह कोई

सीक्रेट चीज नहीं है। हो सकता है कि उस कारपोरेशन की क्या पावर हो और अन्य क्या प्राविजन उसमें हों यह सीक्रेट हो सकता है। लेकिन यह बात तो सभी जानते हैं कि सरकार लखनऊ और कानपुर में कारपोरेशन बनाने का इरादा रखती है। खैर इस बात को छोड़ दीजिये कि किस शहर में कारपोरेशन बनाना चाहिये। अगर कारपोरेशन व म्युनिसिपल बिल साथ-साथ आ जाय तो दोनों की रूप रेखा हमारे सामने होगी और उस वक्त यह समझने में दिक्कत नहीं होगी कि कारपोरेशन और म्युनिसिपैलिटी में कितना अन्तर है अतः मेरा सुझाव है कि यदि सरकार उचित समझे तो ऐसा जरूर करे। इस बिल के बारे में बहुत कुछ कहा गया है मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता, क्योंकि उससे हाउस का समय व्यर्थ नष्ट होगा।

श्रीमती तारा अग्रवाल (नाम निर्देशित)--माननीय उपाध्यक्ष जी, वास्तव में मेरी बोलने की इच्छा नहीं थी क्योंकि महिलाओं के लिये बहिन शिवराजवती नेहरू ने काफी कह दिया था इसलिये मेरे बोलने की आवश्यकता नहीं थी। किन्तु आज जिस तरह पूर्व वक्ताओं की स्पीचों को सुनकर नारी जाति के अधिकारों पर कुठाराघात किया गया मेरा जी हुआ कि अवश्य चन्द शब्द कहूँ। जिस प्रकार से इस हाउस की विचारधारा है और माननीय सदस्यों की राय है उस से यह जाहिर हो जाता है कि वास्तव में नारियों को अधिकार देने के लिये कितने लोग सत्यक हैं। जो लोग विधान को बनाने वाले हैं और वे लोग जो कि कानून को बनाने वाले हैं जब उनके सामने नारियों के अधिकार का प्रश्न आता है तो इस तरह से नारियों की मजाक करते हैं। वह बराबर इस तरह की भावना व्यक्त करते हैं जिससे मालूम होता है कि वास्तव में वह नारी को क्या समझते हैं। यदि वे क्षण भर के लिये नारी की भावना में हो कर के विचार करें तो उन को मालूम होगा कि नारी की वास्तविक स्थिति क्या है। आज ही नहीं बल्कि पिछले एलेक्शन के नामिनेशन और रिजर्वेशन के ऊपर श्री राजा राम शास्त्री जी ने मुखालिफत की है उसको मैं कुछ ठीक नहीं समझती हूँ। उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह से संविधान में किसी तरह का अन्तर करना वाजिब नहीं है। अगर आप रिजर्वेशन और नामिनेशन में कोई अन्तर नहीं चाहते हैं तो उसी तरह से लाल टोपी और गांधी टोपी में भी कोई अन्तर नहीं होना चाहिए। इस प्रकार के अन्तर से जनता की भावना और विचार धारा बदलती रहती है। कानपुर म्युनिसिपल बोर्ड की जो हालत है उस हालत को देखकर मैंने मंत्री महोदय से सलाह की थी कि जिस तरह से शेड्यूल कास्ट के लिये यह आवश्यकता समझी जाती है कि रिजर्वेशन आफ सीट हो, उसी तरह से आज महिलाओं के लिये सीट को रिजर्वेशन की जरूरत है। शेड्यूल कास्ट में यह बात समझी जाती है कि वह लोग अशिक्षित हैं, उन को समाज में बराबर लाने का प्रयत्न किया जाता है। मैं आप को विश्वास दिलाती हूँ कि उसी प्रकार से आज महिलाओं की भी हालत है। महिलाओं की मेजारिटी पहले दो परसेंट अधिक थी परन्तु अब आप लोगों के शाप से एक परसेंट कम हो गई है। महिलायें किसी तरह से भी पुरुषों से वोट देने में कम नहीं हैं लेकिन फिर भी उनको मौका नहीं दिया जाता है। आप देखें कि इस इलेक्शन में ४३१ सीट असेम्बली में हैं और ७२ सीट हमारे यहां कौंसिल में हैं। कौंसिल की बात तो छोड़िये, यहां पर महिलाओं की कुछ तादाद भी है परन्तु असेम्बली में ४३१ मेम्बरों के बीच में केवल ११ महिलायें ही हैं। मैंने वहां की बहिनों से बात चीत करी तो मालूम हुआ कि बहुत संघर्ष के बाद हम को यह सीटें मिली हैं। जिस तरह से आज समाज में महिलाओं के लिये भावनायें हैं। उसी प्रकार से हमारे बड़े-बड़े नेताओं की भी भावनाएं हैं। मुझे यह सुनकर बड़ा दुख हुआ कि आज भी हमारे समाज की भावनायें स्त्री समाज के लिये ऐसी हैं। अब भी समाज स्त्री जाति को एक अच्छी दृष्टि से नहीं देखती है। मैं माननीय मंत्री जी से इस बात की प्रार्थना करूंगी कि महिलाओं का स्वापशन होना चाहिये

[श्रीमती तारा अग्रवास]

और उसमें कम से कम तीन से लेकर १० महिलायें होनी चाहिये। कानपुर में जो म्युनिसिपल बोर्ड है वहां की शिक्षा संस्था में जब अध्यापकों के वेतन का सवाल आता है तो वहां पर जो एक महिला है उस को वेतन लेने में बहुत कठिनाई पड़ती है। जहां बोर्ड में रुपया आया वहां पुरुषों को पहले बंट गया और जब महिलाओं का सवाल आया तो यह कहा गया कि कल जब रुपया आयेगा तो महिलाओं को दे देंगे। क्योंकि वह जानते हैं कि अगर पुरुषों को नहीं देते हैं तो हो सकता है कि एक संघर्ष पैदा हो जायेगा किन्तु महिलाएं तो सीधी सादी हैं, दबबू हैं और अगर उनको दो तीन महीने भी न देंगे तो उनसे किसी प्रकार के आंदोलन का भय नहीं है। यह हालत तो जब है कि जब वहां अभी केवल एक ही महिला सदस्या है।

छात्राओं की शिक्षा के संबंध में मैं यह कहती हूँ कि जब तक महिलाओं का प्रतिनिधित्व बोर्डों में नहीं रहेगा तब तक उनकी शिक्षा का ठीक-ठीक इन्तजाम करना असम्भव-सा हो जायेगा। जो छात्राएँ हैं वही कल को स्त्री होंगी तो उनकी जो भी भावनाएँ होंगी वह छात्राओं के हित के लिये होंगी लेकिन जो पुरुषों की भावनाएँ होती हैं वह सिर्फ अपने ही लिये होती हैं और अपने ही हित को ध्यान में रखते हैं। जैसे कि राजा राम जी ने बड़े जोरदार शब्दों में अपनी परेशानियाँ बयान की हैं। उससे तो यही मालूम होता है कि वास्तव में राजाराम जी अपने घर में गुलाम की जिन्दगी बिता रहे हैं। उनकी स्त्री एम० ए० पास है और सब तरह से काबिल है। मैं तो यह कहती हूँ कि अगर आज राजा राम जी कुछ भी न करें तो अपनी स्त्री के वेतन पर ही अपनी जिन्दगी बसर कर सकते हैं फिर वह किस तरह से कह सकते हैं कि उनको परेशानियाँ होती हैं। मैं नहीं समझ पाती कि इस तरह की भावनाएँ किस तरह से माननीय सदस्यों के दिल में पैदा हो जाती हैं। मैं तो समझती हूँ कि अपने घर के अन्दर आज यदि आप नौकर रखें तो उस नौकर के लिये भी इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि अगर हमने घुड़क दिया या उसको तेज नजर दिखलाई तो फौरन घर से चला जायेगा और अगर चला गया तो घर का काम सब पड़ा रह जायेगा। लेकिन स्त्री के लिये यह भावना होती है कि अगर उसको छोड़ दिया या उसको मारेंगे तो कोई परेशानी की बात नहीं है। क्योंकि वह समझते हैं कि स्त्री की जिन्दगी केवल उनके रोटी कपड़े पर ही निर्भर है और अगर हम निकाल देंगे तो यह रोटी कपड़ा भी नहीं माँग सकती है। तो आज स्त्रियों की जो स्थिति है वह समाज के विधान पर निर्भर है राज्य के विधान पर नहीं। इन तमाम बातों को देखते हुये यह मालूम होता है कि विधान बनाने वाले केवल थोड़े से पुरुष ही ठेकेदार हैं और उन्होंने अपने हित के लिये ही विधान बनाया है। मैं तो यह कहती हूँ कि ८० वर्ष का बूढ़ा १२ वर्ष की बालिका से शादी कर सकता है लेकिन उसके ऊपर तो कोई प्रतिबन्ध नहीं है और अगर कहीं १२ वर्ष की बालिका बिधवा हो जाती है तो समाज के अन्दर उसके लिये कोई चारा नहीं है और उसका कोई भी लिहाज विधान के अन्दर नहीं है। जब कि उसकी यह दशा समाज में है और विधान में है तो बगैर रिजर्वेशन के स्त्रियाँ बोर्ड में अपना प्रतिनिधित्व पा सकें। मैं समझती हूँ कि यह बिल्कुल असंभव है। इसके लिये चाहे हमें पार्लियामेंट में पुकार करनी पड़े कि स्त्रियों के लिये भी कानून में कुछ परिवर्तन किये जायें या उनके लिये रिजर्वेशन का सवाल रक्खा जाय जब तक आप लोगों की भावनाएँ नहीं तब्दील होती हैं या महिलाओं को जब तक शिक्षा नहीं दी जाती है और सभी महिलायें जब तक शिक्षित नहीं हो जाती हैं ताकि वह अपने अधिकारों को समझ सकें, तब तक मैं समझती हूँ कि यह असंभव सी बात है कि उनका कोई भी प्रतिनिधित्व समाज में हो सकता है।

एक बात और कह कर मैं अपनी स्पीच खत्म करूँगी। हमारे भाई कक्कड़ साहब का कहना है कि हमारी महिलाओं को गृह के कार्य में दक्ष होना चाहिये और उनको उसी में अपना कर्तव्य

समझना चाहिये। मैं उनसे पूछती हूँ कि अगर हम भी आप की तरह इस कौंसिल भवन में बँठी हुई हैं किन्तु इसके साथ ही अपने घर का कार्य भी करती रहती हैं और अपने बच्चों का लालन-पालन भी करती हैं और उसमें भी अपनी जिम्मेदारी को समझती हैं तो इसमें उनको क्या अपेक्षा हो सकती है ? हम अपने घर का कोई भी इन्तजाम हो, उसको पूरा करने के लिये भी तैयार रहती हैं और जो घरों के अन्दर बच्चों का लालन-पालन है उसको भी पूरा करती रहती हैं, और बाहर के कार्य में भी हिस्सा लेती हैं तो भी पुरुषों को सन्तोष नहीं होता है। मुझे प्रकट होना है कि इतना करने पर भी जब किसी के पुत्र को निस्वर फर्जा का पुत्र है कड़कर पुकारा जाता है तो उस समय हम लोगों की क्या दशा होती है, अगर फिर भी हमको उस बात की तनिक भी चिन्ता नहीं रहती है और हम उसमें भी गर्व अनुभव करती हैं।

श्री मोहन लाल गौतम—मलावार में स्त्री का नाम लेकर ही पुत्र को बुलाया जाता है।

श्रीमती तारा अग्रवाल—यह हो सकता है जो कि वंत्री महोदय ने कहा है। लेकिन मैं कहती हूँ कि किसी स्त्री का नाम पुकारने में भी अतिशय प्रयत्न कहा जाता है। मैंने एक बार इसके लिये कहा कि आप मुझे तारा अग्रवाल कह कर पुकारिये। हमको अपने नाम से भी वंचित रखा जाता है और उसकी जगह पर भी पुत्र का ही नाम दिया जाता है। तो जब आज इस तरह की भावनायें लोग रखने लगे हैं और महिलाओं को इस दृष्टि से देखते हैं, तो हम लोगों की उन्नति कैसे हो सकती है ? किसी लेखक ने इसी के बारे में स्त्री की प्रशंसा करते हुये यह लिखा था कि स्त्री पृथ्वी है और पृथ्वी लाखों के चापों से चुबली जाती है, अगर वह फिर भी उनको हटा कर दूर नहीं कर देती है बल्कि वह सब को अपने में समेट लेती है और उनका स्वागत करती है। मैं ये सब बातें इस लिये कह रही हूँ कि आज पुरुषों के हृदय में नारी के प्रति जो भावनायें हो गयी हैं, वे दूर हो जानी चाहिये। आज जो विधान बनाया गया है, उसमें भी नारी और पुरुष का कोई भेद नहीं रखा गया है। इसी तरह से विधान बनाने वाले को दोनों को सेपरेट नहीं करना चाहिये और जहाँ तक हाँ सके पुरुषों को नारी का सपोर्ट करना चाहिये। इन्हीं भावनाओं को स्थान में रखते हुये आज कोई बिल बनाना चाहिये जिससे कि नारी के अधिकारों पर कुठाराघात न हो। मेरी बहिन शिवराजवती नेहरो ने ठीक बात कही कि आज पुरुष यह सोचने लगे हैं कि स्त्रियाँ भी हम लोगों की जगहों पर काम करने लग गई हैं, इसलिये अब उनमें कोई खास भेद नहीं होना चाहिये। यह बात मैंने पिछले इलेक्शन में देखी। जब किसी जगह के लिये कोई स्त्री खड़ी होना चाहती थी तो उस जगह पर पुरुष को खड़ा कर दिया गया और यह कह दिया गया कि उनके खड़े होने से हारने की सम्भावना है और वे स्त्रियों को कन्धे पर उठा कर कहाँ तक ले जाते फिरेंगे। ऐसी भावनायें आज पुरुषों में नहीं होनी चाहिये। क्योंकि आप चाहते हैं कि चाहे उस जगह पर एक अंगूठा लगाने वाला आ जाय, अगर एक पड़ी लिखी, एम० ए० या बी० ए० पास नारी नहीं आनी चाहिये। विधान परिषद् में भी मيم्बरों की भावनायें इसी तरह की हो गयी हैं। इसलिए इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करती हूँ और जो थोड़ी बहुत बातें मैंने कह दी हों, और उनसे किसी को बुरा लगा हो, तो उसके लिये मैं उनसे क्षमा चाहती हूँ।

श्री विश्वनाथ (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—उपाध्यक्ष महोदय, आज विधेयक जिस पर विचार हो रहा है, उसपर मैं भी अपना थोड़ा सा विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। शुरू से अन्त तक इस विधेयक की जो बातें हैं वे बहुत महत्वपूर्ण हैं और जितनी बुद्धिमानी के साथ इसमें सुधार किये जा सकते थे, किये गये हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं है। दुख है कि हमारे कुछ भाइयों को इस बिल में लोकतन्त्रात्मक भावना नहीं दिखाई देती है परन्तु कुछ बातें ऐसी हैं कि चाहे वह कितनी भी सुन्दर हों परन्तु कुछ लोगों को दूसरे रूप में दिखाई देती हैं। काफी बहस के बाद और विचार-विनिमय के बाद श्री राजा राम जी ने दो बातें कहीं, और बहुत सुन्दर ढंग से कहीं, लेकिन मैं उनसे सहमत नहीं हूँ उन्होंने कहा कि मजदूरों की स्थिति ऐसी नहीं है कि वह

[श्री विश्वनाथ]

साधारणतः चुनाव में आ सकें, इसलिये कुछ समय के लिये ट्रेड यूनियन को कुछ सीट्स रिजर्व कर दी जायें। मेरा कहना यह है कि अगर सीट्स रिजर्वेशन का सवाल किसी भी ट्रेड यूनियन के लिये या किसी भी संस्था के लिये उठाया गया तो जैसा कि राजा राम जी ने श्री गोविन्द सहाय जी के प्रस्ताव पर कहा है वैसे ही शायद इस पर भी कहा जाने लगे। वास्तव में जिस प्रकार से मुस्लिम लीग को सीट्स अलग दे कर देश की दुर्दशा की गई है ठीक उसी प्रकार से अनेक स्वार्थ के वर्गों को प्रतिनिधित्व दे कर के हम इन संस्थाओं के बीच युद्ध का अखाड़ा खड़ा कर देंगे और उसके साथ ही यह होगा कि जो लोग प्रतिनिधि हो कर जायेंगे, वह अपने दल के लोगों को खुश करने के लिये उचित और अनुचित बातों का कोई ध्यान न रख कर सिर्फ उन्हीं के स्वार्थ की बातें करेंगे। लेकिन मैं तो कहता हूँ कि यदि इन संस्थाओं को या यूनियनों को ऊंचे उठाना है तो उनके लिये भी अच्छा होगा कि उनको कोई रिजर्वेशन न दिया जाय। मान लीजिये थोड़ी देर के लिये, कि ट्रेड यूनियन को अधिकार दे दिया जाता है तो आगे चल कर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव में किसानों के प्रतिनिधियों की मांग आयेंगी और उसके बाद बड़ी संख्या में जो खेतिहर मजदूर हैं उनके लिये यही सवाल उठेगा जो कि अव्यवहार्य होगा, अतः मेरे ख्याल से इन सब बातों को छोड़ कर किसी को भी विशेष प्रतिनिधित्व न दिया जाय यही हित कर होगा। क्योंकि इस तरह से हर आदमी को सेवा के बल पर ऊपर उठने का अधिकार होगा और यही एक सुन्दर तरीका है।

एक बात आप ने और कही थी कि छोटे लोग चुनाव में पहुंच न सकेंगे और ऐसा हो सकता है कि शोषक लोग आ जायें और मंत्री भी बन जायें उसकी उनको काफी चिन्ता है। ठीक है, ऐसा होना सम्भव है लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है सिर्फ कहने से ही तो यह दिक्कत और कठिनाई हल नहीं होती। इसके लिये कोई रास्ता ढूँढ़ना होगा। निश्चय ही इतनी भयानक विषमता जो देश में है वह न रहनी चाहिये। यह खतरनाक है और कष्ट दायक भी है। परन्तु इस भयानक विषमता को दूर करने के लिये क्या तरीका होना चाहिये यह भी सोचना है। आज तक हमने किसी भाई के मुँह से यह नहीं सुना, कि जो धनी वर्ग हमारे देश का है उसके प्रति हमारा क्या विचार होना चाहिए। यदि हम शांतिमय क्रांति करना चाहते हैं और धनियों का महत्व कम करना चाहते हैं, तो सब से पहले हमको यह करना होगा कि धनियों के प्रति उपेक्षा की भावना रखनी होगी। समाज में उनको ऊंची प्रतिष्ठा न देनी होगी। आज मैं देखता हूँ कि हर दल के लोग धनियों की ऊँच करते हैं, इज्जत करते हैं। मुझको तो प्रत्यक्ष अनुभव है। मैंने देखा है कि अच्छे २ समाजवादी, एक धनी आदमी चाहें वह कांग्रेस की ही विचार धारा का क्यों न हो, अगर वह बीमार हो कर अस्पताल में जाता है तो कतिपय लोग उसको देखने तथा सेवा करने के लिये जाते हैं। लेकिन अगर एक गरीब आदमी अस्पताल में जाता है तो कोई उसकी सेवा करने नहीं जाता। इसलिये हमको एक भावना बनानी होगी, कि धनियों के प्रति क्या व्यवहार हो, क्या न हो, तभी देश के लोगों की मनोवृत्ति बदलेगी। अगर आप चाहते हैं कि विषमता दूर हो, तो सब से पहले गरीबों को अपनार्य, बिना उस स्तर पर आये, जिस पर कि गरीब हैं, आप गरीबों का कल्याण, उनकी उन्नति नहीं कर सकते। आज कल लोग गरीबों को जो उकसाते हैं उस से वह वर्ग संघर्ष भले पैदा कर दें परन्तु वह उनको ऊपर नहीं उठा सकते।

जाके पांव न फटी बेवाई, सो का जाने पीर पराई।

जो गरीबों की वास्तविक सेवा करना चाहते हैं उनको गरीबी का अनुभव करने के लिये गरीबों के स्तर पर उतरना होगा। अपने पांव में बेवाई फाड़ नो होगी। यही रास्ता है गरीबों को ऊपर उठाने का। यह रास्ता नहीं है कि इनको अलग प्रतिनिधित्व देकर संस्थाओं में बिठा दिया जाये। जिस से कई वर्ग के लोग एक जगह इकट्ठा हो कर आपस में तू तू में करें। यह भी कहा गया कि नामिनेशन आदि के सभी अधिकार हटा दिये जायें परन्तु बौड़ा सा अंकुश रखा गया है। लेकिन उस अंकुश के लिये भी बार-बार कहा जा रहा है कि कहीं उसका दुरुपयोग न हो। मुझे तो ताज्जुब जब हुआ जब मेरी पार्टी के लोग भी ताकीद करने की हिम्मत कर गये। मेरा निवेदन

है कि जब कभी संक्रमण काल होता है तो बहुतों की मनोवृत्ति में उच्छ्वस खलता आ जाती है। भावनायें कुछ विकृत हो जाती हैं। गरमी के बाद सरदी का मौसम शुरू होता है तो बड़े जोरों का बुखार आता है। इस तरीके से सर्दी खत्म होती है और गर्मी का मौसम आता है तब भी बहुत लोग बीमार रहते हैं। जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, राज्य ने जिनके ऊपर काफी उत्तरदायित्व दिया है कि राज्य को अंचा उठाये, जब तक हमारा स्तर उस अंचाई पर न आ जाय कि जिससे सही चीज को समझ सकें तब तक चन्द दिनों के लिये उनके हाथ में अंकुश भी रखना होगा। अध्यापक बच्चों को पढ़ाता है और उसके हाथ में डंडा होता है कि बच्चे डरें और अपना काम पूरा करें। उसका दुरुपयोग शायद ही अध्यापक किसी अवसर पर करता है उसी तरीके पर हमको और आप को समझना है और समझना चाहिये। इतने बड़े उत्तर प्रदेश के राज्य में जिस पर जनता अटूट विश्वास रखती है जो कि चुनाव से जाहिर हो चुका है। एक बड़े जिम्मेदार आदमी के हाथ में एक छोटा सा अंकुश दिया गया है। उससे ज्यादा इम्पाशियल कौन हो सकता है। मैं समझता हूँ कि इससे सुन्दर व्यक्ति कोई दूसरा मिल नहीं सकता है। कोई दूसरी संस्था नहीं मिल सकती है।

बहिन तारा देवी अग्रवाल ने भी कुछ कहा है। जिसके विषय में मेरा कहना है, ये दोनों ही एक दूसरे के अविच्छिन्न अंग हैं और स्त्री पुरुष का संबंध यह एक ऐसी चीज है जिसको मनो-वैज्ञानिक ही भली भाँति समझते हैं। दो व्यक्ति को जब एक साथ रहना होगा, और आजीवन एक ही साथ रहना हो तो निश्चित बात है कि दोनों व्यक्तियों में से किसी एक को यह सहस्र करना होगा कि हम थोड़ा सा झुक जाय और आपस में से किसी एक को बड़ा समझें, उसकी बातों को सहन करें, उससे थोड़ा दब कर रहें। एक जरा झुक जाय, तभी वह साथ रह सकते हैं और साथ रहना दोनों के लिये लाजमी भी है ताकि सृष्टि का सृजन होता रहे। इसलिये दोनों में इस किस्म का समझौता होना आवश्यक है। उन अंशों में जहाँ तक बहन तारा देवी का कहना है कि पुरुष चाहे ८० वर्ष के हों लेकिन वह तीन शादी कर सकते हैं लेकिन औरतें नहीं कर सकती हैं तो मेरा कहना यह है कि बहुत से पुरुष ऐसे हैं जो इस पक्ष में हैं कि औरतों की भी पुनः शादी होनी चाहिये और जो शादी ८० वर्ष के लोगों की होती है वह नहोनी चाहिये। उन्होंने कहा कि पुरुष उन्हें दबाया करते हैं जिसके विषय में मैंने ऊपर निवेदन कर दिया है। अगर वह बिल-कुल बराबरी समझते हैं तो वह साथ कभी नहीं रह सकते हैं। इसलिये थोड़ा १६, २० होना पड़ता है। यही तरीका साथ-साथ रहने का है। जब कोई सवाल होता था कि क्या कारण है कि कांग्रेस मुसलमानों से दबती है तो मैं तो कहता था कि जैसे स्त्री पुरुष दोनों एक साथ रहते हैं उसी प्रकार से हमको भी मुसलमानों को साथ में रखना है, उनको सर पर रखना है। एक को थोड़ा सा दबना पड़ेगा और दूसरे का लिहाज करना पड़ेगा। यह हमारी सदा से नीति रही है। हो सकता है कि अब इसे गलत साबित किया जाय लेकिन मैं तो कहता हूँ कि दुनिया इस चीज को गलत नहीं साबित कर सकती है। शताब्दियों की तपस्या के बाद एक रास्ता निकाला गया था। यदि स्त्री पुरुष के अधिकार को ले लेती है तो फिर पुरुष को ही स्त्री बनना पड़ेगा। तभी संसार चलेगा और सृष्टि रहेगी।

डिप्टी चेरमैन—अब कुल ४५ मिनट हैं और कई सदस्यों को बोलना है। अगर उस विधेयक को आज खत्म करना है तो आप लोग थोड़े वक्त में तकरीर खत्म कर दिया करें।

श्री मोहन लाल गौतम—मैं तो कम से कम आध घंटा जवाब के लिये चाहूंगा।

श्री प्रभू नारायण सिंह—यह न हो कि घंटों पाठ होता रहे।

श्री अब्दुल शक्र नजमी (स्थानीय संस्थाएं निर्वाचन क्षेत्र)—माननीय डिप्टी चेरमैन, यह म्युनिसिपैलिटीज का जो अग्नेन्डिंग बिल पेश है उसमें फर्स्ट रीडिंग से थर्ड रीडिंग तक इतना कहा गया है और सुना गया है कि मैं कोई खास जरूरत नहीं समझता था कि अपने विचार

[श्री अब्दुल शकूर नजमी]

पेश करूँ लेकिन कुछ माननीय सदस्यों ने इस बिल को आधार बना कर जो नुकते निगाह रखा है उसकी वजह से मैं बोलने पर मजबूर हुआ। वैसे तो मैं यह समझता था, मुझे अफसोस है कि श्री गोविन्द सहाय जी यहाँ पर मौजूद नहीं हैं, कि वह चीन से आये हैं कोई इन्कलाबी बात कहेंगे, इन्कलाबी मुझाव पेश करेंगे जिससे कि उनका सब प्रगतिशीलता की तरफ जाता हुआ जाहिर होगा क्योंकि वह अपने को प्रगतिशील पोज करते हैं लेकिन उन्होंने जो बातें रखी हैं उनसे तो मुझे कुछ ऐसा महसूस होता है कि वह कोई रिऐक्शनरी तो नहीं हैं। उन्होंने तीन बातें रखी हैं। पहिले तो यह कहा कि बिल को देखने से यह महसूस होता है कि हम सेंट्रलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं और उसमें डेमाक्रेसी की रोशनी नहीं दिखाई पड़ती है। हुकूमत के सामने कोई आइडियालोजी नहीं है और लोगों की मुसीबतें दूर करने का इसमें कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ता है। दूसरी बात उन्होंने यह कही जैसा कि जिन्ना साहब ने कहा था कि आज भी कांग्रेस के साथ कुछ मुसलमान हैं जो शो ब्वायज की तरह हैं। तीसरी बात उन्होंने कहा कि मुसलमानों का रिजर्वेशन होना चाहिये। इसी आखिरी चीज पर मैं कुछ अर्ज करूँगा। इसके लिये दलील उन्होंने यह दी थी कि आज भी वह माइनार्ट्स में हैं उसकी मिसाल में उन्होंने पिछले एलेक्शन को पेश किया था। उन्होंने कहा मुसलमानों को डराकर धमकाकर उनसे वोट लिया गया। मैं किस तरह से कहूँ कि उन्होंने यह बात होश में कहीं है या नहीं। यह चीज जिसका उन्होंने जिक्र किया सन् १९०६ में लार्ड मिंटो ने मुस्लिम लीग की नौब डाली थी और उस वक्त से लेकर १९१६ में जब कि मुसलमानों को सेपरेट एलेक्टेड दिलाया गया था तमाम तरह की इसके खिलाफ दलील दी गयी थी। जो लोग इसके खिलाफ थे वह कहा करते थे कि यह निकम्मेपन की स्कीम है। मैं आप से अर्ज करूँ कि मिलजुल कर काम करने से सब लोगों में एक तरह की हिम्मत पैदा होती है कंपटीशन करने की, मिलजुल कर यह सोचने की कि कैसे बेकारी की समस्या हल की जाये, मैं अपनी बात सफाई के साथ पेश करना चाहता हूँ। जैसे हमें यह देखना है कि हमारे देश की जरूरतें क्या हैं अगर हम यह चाहते हैं कि हमारे सोचने की ताकत मिले कि हम अपनी बेकारी कैसे दूर करें, लोगों को रोजगार कैसे मिले, हमारी शिक्षा का ढंग क्या होना चाहिये अगर हमको इस तरह की बातें सोचनी हैं तो हमको उस तरह की बातें नहीं सोचना चाहिये जैसी कि बाबू गोविन्द सहाय ने कही हैं। हम सब भाई-भाई हैं। मैं भाई-भाई का अलफाज इसलिये इस्तेमाल कर रहा हूँ कि हम एक ही मुहल्ले में रहते हैं साथ-साथ काम करते हैं और साथ ही साथ एक तरह से सोचते भी हैं। मैं किस तरह से कहूँ कि वह सही दिमाग से बातें कर रहे थे या नहीं। वह यहाँ पर मौजूद नहीं हैं। गांव के जो पुराने लोग हैं वह बतलाते हैं कि जब एक गांव की लड़की चाहे वह किसी हिन्दू की हो चाहे किसी मुसलमान की हो, किसी दूसरे गांव में ब्याही जाती थी तब उस गांव का हिन्दू और मुसलमान दोनों ही उस गांव का पानी छोड़ देते थे और कहते थे कि इस गांव का पानी पीना पाप है क्योंकि इस गांव में हमारे गांव की लड़की ब्याही है। लेकिन जब यह सेपरेट एलेक्शन हुआ तब से क्या-क्या ग़ज़ब हुआ, क्या-क्या आफ़तें ढाई गयीं और कितना खून खराबा हुआ यह किसी की आंखों से छिपा हुआ नहीं है। प्रभुनारायण जी ने तो उनकी बातों का जवाब दूसरे ही ढंग से दिया था उन्होंने कहा था कि शायद बाबू गोविन्द सहाय इस तरह की बातें कह कर मुसलमानों का फ़ैवर (favour) गेन (gain) करना चाहते हैं। लेकिन मैं तो कहूँगा कि वह जो बातें कह रहे हैं वह इसलिये कि एलेक्शन में उन्हें कुछ कड़वे तर्जबे हूये हैं और शायद उसी से आसुदा हो कर वह इस तरह की बातें कर रहे थे। उन्होंने जिन्ना साहब की बात कही कि कांग्रेस में कुछ शो ब्वायज हैं। इसलिये यह कोई बुनियादी चीज नहीं है।

दूसरी चीज जो जिन्ना साहब ने कही थी उसको उन्होंने भी कहा। मैंने उनके लफ्जों को नोट किया था। वे इस वक्त हाउस में नहीं हैं, नहीं तो वे भी सुन लेते। जिन्ना साहब ने कहा था कि जो मुसलमान कांग्रेस में हैं, वे कांग्रेस शो बाय हैं। मुझे उनका यह फिकरा अच्छी तरह से याद है। जब एक बर्फ मौलाना आज़ाद कांग्रेस के प्रेसीडेंट थे, उस वक्त गांधी जी ने जिन्ना

साहब से उनकी मुलाकात के लिये बुलाया। वे किसी तरह से भी उनसे मुलाकात करने के लिये तैयार नहीं होते थे। जिन्ना साहब ने उस वक्त मौलाना अज़ाद के लिये यह कहा कि वह तो कांग्रेस के शो वाय हैं, मैं उनसे बातचीत नहीं करना चाहता हूँ। बाबू गोविन्द सहाय जी कई दफे इटावा गये हैं उनसे मेरी बातचीत भी हुई है, लेकिन कभी उन्होंने इस तरह की बात नहीं कही, मालूम नहीं आज किस तरह से उन्होंने इनको शो वाय कह दिया। आज जब उनके मुँह से यह शब्द निकला तो हमें बड़ा भारी आश्चर्य हुआ। - आप को याद होगा कि जब यहाँ पर ब्रिटिश सरकार मुस्लिम लीग के साथ थी, तो उस वक्त जो मुसलमान कांग्रेस के साथ थे उनके ऊपर किस तरह से मुसीबतें आई हैं वह किसी से छिपा नहीं है। यह बात किसी के कहने से आज ठक नहीं सकती। यह कोई बात नहीं कि आज उन्होंने इस बारे में अपनी राय बदल दी हो।

जो सीट के रिजर्वेशन का सवाल है, उसके लिये उन्होंने कहा कि हम डेमोक्रेसी की तरफ न जाकर सेन्ट्रलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। वह कहते हैं कि इस सरकार के पास कोई ऐसा असला नहीं जिससे लोगों की तकलीफें दूर हो सकती हों। हर मुल्क में डेमोक्रेसी है लेकिन आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं उसके साथ साथ हमें कदम उठाना है। मिसाल के तौर पर मैं दो मुल्कों की मिसाल पेश करना चाहता हूँ। फ्रांस में एक बहुत बड़ा इन्कलाब आया। उस के बाद अब तक उसके १२ या १३ विधान बदल चुके हैं। अभी १९४६ में दो दफे उसका विधान बदल चुका है। वहाँ यह हुआ कि प्राबिस को कितनी पावर दी जाय, पार्लियामेंट को कितनी पावर दी जाय और लोकल बाडीज को कितनी पावर दी जाय। उस वक्त वहाँ के लोकल बाडीज को जो ताकत दी गयी उससे इतना ज्यादा सत्यानाश हुआ कि फिर से विधान को बदलना पड़ा। वह भी एक डेमोक्रेटिक मुल्क है। आज की हालत और वक्त का तकाजा है कि अगर आप चाहते हैं कि नीचे वालों को ताकत दी जाय तो किस हद तक दी जाय, यह देखना है। कहीं ऐसा न हो जाय कि इससे लोगों में सेक्टरिज्म आ जाय या जो अभी तक हमारे यहाँ कम्युनलिज्म है वह चीज कहीं पावर में न आ जाय। कहीं इसके पीछे कोई जज्बा हो सकता है। हमें यह करना चाहिये जिससे लोगों की ज़रूरतें पूरी हों और उनको पूरा करने के लिये कौन सी कोशिश की गयी है। माननीय डिप्टी चैयरमैन साहब, आज सभी लोग यह जानते हैं कि उनके हक्क क्या हैं लेकिन यह नहीं जानते हैं कि हमारा फर्ज क्या है। डेमोक्रेसी में जहाँ हमारे हक्क हैं वहाँ हमारे कुछ फर्ज भी हैं। हमारे अन्दर काम करने का एक हौसला होना चाहिये। मैं केवल गवर्नमेंट के लिये नहीं कहता बल्कि डेमोक्रेसी में यह भी है कि जनता का क्या फर्ज है और उसका क्या कर्तव्य है। डेमोक्रेसी का फर्ज क्या है, आज हमको यह समझने की आवश्यकता है, ज़रूरत है। हमको आलोचना करने के साथ साथ यह भी समझना है कि हमारा फर्ज और कर्तव्य क्या है। जनाब वाला, मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि आज यह हालत है कि अगर लालबाग में कोई एक्का एकसीडेंट हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी सारी कांग्रेस सरकार पर रखी जाती है। सियासत से लोगों का विश्वास, लोगों का इत्मीनान जाता रहा है। उनके दिमागों में आज गलत भावनाएं, गलत तयाल पैदा कर दिये गये हैं। हम लोगों का फर्ज है कि लोगों में डेमोक्रेसी के लिये, प्रजातंत्र के लिये विश्वास दिलायें। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का स्वागत करता हूँ।

श्री एम० जे० मुकर्जी—जनाब डिप्टी चैयरमैन साहब, वक्त बहुत कम है इसलिये मैं चन्द शब्द कहना चाहता हूँ। एक तो यह बात है कि जिस तरह के बयानात यहाँ पर श्री गोविन्द सहाय जी ने दिये वह ठीक नहीं हैं। माई नारीटीज के लिए मैं इस तरह की बातों को खराब समझता हूँ। मसीही जमाअत ने १९३८ में इस बात का फैसला किया था कि रिजर्वेशन आफ सीट और सेपरेट एलेक्शन दोनों ठीक नहीं हैं। हमारा विश्वास था कि मेजरिटी पार्टी हमारी सहायता करेगी। हमारे सामने यह सवाल था कि इस वक्त बहुत सी पार्टी हैं हम किस पार्टी को वोट दें जो सरकार को आसानी से चला सके। इसलिये हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया। जो कुछ मैं कहना चाहता हूँ वह यह कि ऐसे जिम्मेदार शब्दों के मुँह से ऐसी बातें नहीं निकलनी चाहिये थीं। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वह यह है कि हाउस में इस

[श्री एम० जे० मुकर्जी]

बिल पर तीन दिन से बहस हो रही है, म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट को लाने की जरूरत सब ने महसूस की। इस विधेयक को लाने की जो सब से बड़ी जरूरत थी कि चुनाव चल्द से चल्द हो जाय।

(इस समय, ४-३० मिनट पर, चैयरमैन ने सभापति का आसन ग्रहण किया।)

डाक्टर साहब और दूसरे भाइयों ने इस पर अपने ख्यालात को काफी जाहिर किया है। माननीय मंत्री जी उन सब बातों को अच्छी तरह से देखेंगे और उनका ख्याल भी रखेंगे। बहुत से माननीय सदस्यों ने सस्पेंशन की भी मूखालिफत की में समझता हूँ कि उनके ख्यालात ठीक नहीं हैं। सस्पेंशन बहुत जरूरी है क्योंकि जब तक किसी अफसर का सस्पेंशन नहीं किया जायगा उस वक्त तक किसी मामले की तहकीकात ठीक तरह से नहीं हो सकती है। अभी तो हमें डिमाक्रेसी के उसूलों को सीखना है, इस मामले में हम लोग अभी बच्चे हैं। जैसे हिडोनिक प्रिन्सिपल में प्लेजर और पेन होता है।

चैयरमैन—What has this Bill to do with the Hedonic theory of pleasure and pain ?

श्री एम० जे० मुकर्जी—मुझे अब कुछ ज्यादा नहीं कहना है। इसके बाद मैं अपने भाषण को समाप्त करता हूँ।

श्री पन्ना लाल गुप्त (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बलोजर मूव करना चाहता हूँ क्योंकि अब बहस काफी हो चुकी है।

*श्री शान्ति स्वरूप अग्रवाल—(अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत थोड़ा सा कहना है। इस बिल के लिये मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूँ।

परन्तु एक विशेष बात जो कि मेरे मस्तिष्क में थी, वह मैंने निजी रूप से मंत्री जी के सम्मुख भी रख दी है और मुझे यह कहना है कि उसकी ओर भी ध्यान रखा जाय। यह बिल सदन के सामने इस आशय से रखा गया है कि चुनाव जल्दी से जल्दी हो जाय और इसकी ओर डाक्टर ईश्वरी प्रसाद जी ने जरा सा संकेत मात्र किया था। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि वह सरकार का ध्यान म्युनिसिपल बोर्डों में शिक्षा की दशा की ओर दिलाना चाहता हूँ। यदि इन शिक्षालयों की ओर अच्छी तरह से लोग ध्यान दें तो उनकी आंखों से पानी आने लगेगा। शहरों में जो स्कूल हैं बच्चे उनको छोड़-छोड़ कर हाई स्कूल की दूसरी स्कूलों में जाकर दाखिल होते हैं तो मेरा आशय केवल यही है कि जब म्युनिसिपल ऐक्ट जो दूसरा आने वाला है आयेगा तो उसमें अवश्यमेव ही इन स्कूलों की शिक्षा प्रणाली की ओर भी ध्यान दिया जायेगा ताकि वहां की जो सोचनीय दशा है वह ठीक हो सके। मुझे मालूम है कि जो अवस्था इस वक्त म्युनिसिपल स्कूलों की है उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पर है और एजुकेशन डिपार्टमेंट पर है। इन स्कूलों के अध्यापकों के ऊपर और स्कूलों की सोचनीय दशा को ठीक करने लिये खर्च का जिक्र करते हुये माननीय मंत्री जी से यह मालूम हुआ कि यदि आज हम उनके वेतन पर विचार करने लगेंगे तो तुरन्त एक करोड़ रुपया चाहिये और सवा दो करोड़ रुपया वार्षिक खर्चा और बढ़ जायेगा। इसीलिये उसे पूरा करने के लिये उनके पास भी रुपया नहीं है लेकिन जब यह बिल वास्तव रूप में सदन के सामने आयेगा तो मैं आशा करता हूँ कि उनके वेतन का सवाल भी माननीय मंत्री जी अपने ध्यान में रखेंगे।

*श्री सभापति उपाध्याय (नाम निर्देशित)—अध्यक्ष महोदय, मैं हिन्दी और संस्कृत के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। गीतम जी एक ऋषि थे उन्होंने संस्कृत शास्त्र की लिखा है.....

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

चेयरमैन—म्युनिसिपैलिटीज बिल और संस्कृत शास्त्र में बहुत अन्तर है।

श्री सभापति उपाध्याय—मैं उसी बात पर आता हूँ। गौतम जी ने एक संस्कृत का शास्त्र बनाया और आज हमारे माननीय मंत्री गौतम जी ने इसको बनाया। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस बात पर दिलाना चाहता हूँ कि म्युनिसिपैलिटीज के अन्तर्गत शिक्षा का भी प्रबन्ध है और वहाँ पर हिन्दी, संस्कृत, उर्दू, पाश्चिम, आदि के पढ़ाने की व्यवस्था की जाती है लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि संस्कृत भी एक भाषा है और इसकी ओर ध्यान नहीं दिया गया है.....

चेयरमैन—यह चीज तो इस समय असंगत है।

श्री मोहन लाल गौतम—माननीय अध्यक्ष महोदय, थर्ड रीडिंग के समय जो-जो बातें इस सदन के माननीय सदस्यों ने कही हैं, उन पर सब का उत्तर मैं कहाँ तक दे पाऊँगा, यह मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन संक्षेप में जो जो बातें कही गयी हैं थोड़ा-थोड़ा सब का जवाब देने का प्रयत्न करूँगा। यह सौभाग्य की बात है कि डा० ईश्वरी प्रसाद जी जैसे विद्वान इस सदन में हैं जिन्होंने जिन्दगी भर अध्ययन किया है और शिक्षा दी है और मेरा विचार है कि उन्होंने इस विषय में भी काफी अध्ययन किया है। इसलिये हमें खुशी है इस बात की कि जब-जब भी ऐसे प्रश्न इन सदन के सामने आयेंगे, उनकी राय हमारे लिये उपलब्ध होती रहेगी। उन्होंने जब यह कहा कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ने उन सिद्धान्तों पर विचार नहीं किया तो मेरा ख्याल है कि उनका मतलब यह था कि उन सिद्धान्तों के अनुसार इस बिल में कोई संशोधन नहीं किये गये तो इसके लिये तो मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूँ कि जिन सिद्धान्तों का इससे संबंध है, उनको लेने का प्रयत्न नहीं किया गया है लेकिन विचार नहीं किया गया है, यह कह कर उन्होंने हमारे ऊपर ज्यादती की है। जो उन्होंने सिद्धान्त बनाये हैं कि इस तरह से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को चलाना चाहिये, यानी जनता को शिक्षित करे, नागरिकों के जीवन को ऊँचा बनाये, तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि इन सब बातों को जब कि नया बिल सदन में आयेगा उस वक्त इनको सामने रख कर उन पर विचार किया जायेगा और जहाँ तक हो सकेगा उनको कसौटी पर कसने की कोशिश की जायेगी।

मैंने जब पहले यह बिल रखा था उस वक्त कह दिया था कि एक नया बिल लाने के लिये समय चाहिये और उसको पास करने के लिये समय चाहिये। इसलिये यह बिल सदन के सामने रखा गया और जिस चीज का सदन ने चारों ओर से स्वागत किया है। सिवाय श्री गोविन्द सहाय को छोड़ कर और सभी ने इसका स्वागत किया है, और उन्होंने इसके लिये क्या-क्या कहा यह पता लगाना तो बहुत मुश्किल है। सभी लोगों ने इस बात का भी स्वागत किया है कि चुनाव चल्दी हो जायें। इसलिये इन तमाम बातों पर इस समय में जाना भी नहीं चाहूँगा और जो बातें डाक्टर ईश्वरी प्रसाद साहब ने कही हैं और जिन बातों को उन्होंने हमारे सामने रखा है, तो उनमें सबमें इस समय जाना उचित भी नहीं है। कुछ लोगों ने इसमें बहुत से दोषों का जिक्र किया है, उनको मैं एक, एक करके आप के सामने बतलाने की कोशिश करूँगा।

एक बात जिसकी बहुत बड़ी चर्चा इस सदन में हुई है, वह यह है कि सेन्ट्रलाइजेशन की मनोवृत्ति हमारे उसमें पैदा हो रही है। मुझे एक भी मिसाल ऐसी नहीं बतलायी गयी जिससे कि हममें सेन्ट्रलाइजेशन की मनोवृत्ति पैदा हुई हो। एक चीज एकाउन्ट्स आफिसर्स के नियुक्त करने के बारे में थी, उसका स्वागत किया गया। एक दूसरी बात ससपेंशन और रिमूवल के बारे में थी। ससपेंशन और रिमूवल में बरों और चेयरमैन का पहले भी था और अब भी है। और जितनी पहले की चीजें थीं, वही अब भी हैं। तो उसमें डिसेन्ट्रलाइजेशन की बात तो ठीक है, मगर यह कहना कि इसमें हम नई चीजें रख रहे हैं या उसमें सेन्ट्रलाइजेशन कर रहे हैं, यह उचित नहीं है। क्या किसी मेंबर को रिमूव करने या किसी चेयरमैन को रिमूव करने की बात नहीं है और यदि इसके लिये जरूरी समझा जाता है तो पहले उसको ससपेंड किया जाता है और मामलों की तहकीकात की जाती है। अगर तहकीकात ठीक हो, तब इस तरह की

[श्री मोहन लाल गौतम]

पावर इस्तेमाल की जाती है और इस बात को मैं नहीं समझता हूँ कि जब रिमूवल का अधिकार है, तब किसी को सस्पेंड करना तो एक छोटी सी बात है और यह उसका एक छोटा सा अंग है। तो इसके लिये जो दिक्कतें आयी हैं या आती हैं, उनको दूर करना हमारा फर्ज है। अगर किसी मेम्बर के खिलाफ़ इस तरह की शिकायत होती है और स्टाफ़ यह करता है तो, उसके लिये और क्या रास्ता रह जाता है कि उसको अलग किया जाय। तो उसको अलग करने से पहले जब सस्पेंड किया जायेगा और उसके खिलाफ़ तहक़ीकात होगी तो जब बाद में उसकी ज़रूरत समझी जायेगी, तभी उसको रिमूव किया जायेगा। यही बात उसमें हो सकती है। जब इस तरह के अधिकार की बात है, तो यह आप कैसे कह सकते हैं कि हमारी मनोवृत्ति किसी पर हमला करने की है।

इस बिल के जो कुछ अमली बातों का जिक्र हुआ है, मैं अब उसकी ओर आता हूँ। मैंने अब तक जो कुछ कहा उससे तो यह पता चल ही जाता है कि हमने बोर्ड की सेन्ट्रलाइजेशन की कोई कोशिश नहीं की है, इसलिये ऐसी बातें कहना उचित भी नहीं है। अब बोर्ड के सुपरसेशन की बात है। कानपुर के बोर्ड का डाक्टर साहब ने जिक्र किया। मैं उस चीज़ के बारे में बतलाता हूँ और उसमें जो कुछ लिखा पढ़ी हुई है, उसको भी बतलाता हूँ। उन्होंने कानपुर के डेवलपमेंट बोर्ड और म्युनिसिपल बोर्ड के बारे में कहा। कानपुर म्युनिसिपल बोर्ड के पास वाटर वर्क्स का चार्ज नहीं है और यह चार्ज कानपुर डेवलपमेंट बोर्ड के पास है और यही वहाँ वाटर सप्लाई करता है जब कि इसके चांजेंज म्युनिसिपल बोर्ड वसूल करता है और म्युनिसिपल बोर्ड उसका उतना रुपया नहीं देता है। इस तरह से १६,१७ लाख म्युनिसिपल बोर्ड के पास आता है और वह डेवलपमेंट बोर्ड को रुपया नहीं देता है। इस तरह से डेवलपमेंट बोर्ड का रुपया उसके ऊपर बाँकी रह जाता है। इसमें रुपये वसूल होने की बात है। अब तक म्युनिसिपल बोर्ड के पास उसका ११ लाख रुपया देना था और जब उसने म्युनिसिपल बोर्ड को इसके लिये धमकी दी कि अगर वह रुपया नहीं देगा, तो उनका काम बन्द हो जायेगा। तो म्युनिसिपल बोर्ड ने साढ़े सात लाख रुपया डेवलपमेंट बोर्ड को दिया और अब केवल इस तरह से साढ़े तीन लाख रुपया उसको देना बाँकी रह गया है। तो डेवलपमेंट बोर्ड के शिकायत करने पर यह बात हुई और अगर एक दिन भी डेवलपमेंट बोर्ड वहाँ वाटर सप्लाई करना बन्द कर दें, तो कानपुर ऐसी जगह में आप समझ सकते हैं कि क्या हालत पैदा हो सकती है और इस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन में भी असर आ सकता है। इस तरह से कानपुर के बारे में जो यह बात है, उसके लिये लिखा पढ़ी भी हुई और किसी तरह से वहाँ का काम चलाया गया और उसके एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ़ ध्यान दिया गया। मैं एक जगह की म्युनिसिपैलिटी में गया वहाँ मेरे पास कुछ व्यापारी आये उन्होंने कहा कि हमारा रिफ़ंड का रुपया नहीं मिला है और वह बहुत ज्यादा है। मैंने चेयरमैन से पूछा कि क्या बात है। उसने कहा कि हाँ, रुपया है लेकिन खर्च हो गया है इसलिये नहीं दिया गया। लेकिन मैं आप से कहता हूँ कि वह तो अमानत का रुपया था उसको आप को खर्च करने का क्या अधिकार था जो आप ने खर्च कर लिया। जिस डेमोक्रेसी का भरोसा आप को है वह वहाँ पर मौजूद है एडल्ट फ़्रन्चाइज से चुन कर आयी है। यह मैंने एक मिसाल आप को दी है। आप यह कर सकते हैं कि यह सदन और असेम्बली दोनों यह तै कर दें कि सरकार को कोई दखल न हो इन बातों में अगर कोई जिम्मेदारी ले ले एडमिनिस्ट्रेशन की तो मैं कहूँगा कि ठीक है लेकिन जब हम यहाँ पर डेमोक्रेसी के अन्दर एडल्ट फ़्रन्चाइज से चुन कर आये हैं तो जनता को हम क्या जवाब देंगे जब वह कहती है कि कानून आप ने बनाया है और आप उसको बदल सकते हैं। तो यह बात आप के सोचने की है और आप विद्वानों के लिये यह बात सोचने के लिये छोड़ता हूँ। आप कोटेशन १९३८ का देते हैं तो उस समय इररिसपानसिबिल सरकार थी। उस पर आपका कोई अंकुश नहीं था उस वक्त टसिल थी उन में जो यहाँ चुने जाते थे और उनमें जो नामीनेट होते थे लंदन से लेकिन अब डेमोक्रेसी का जमाना है और मैं तो यह कहूँगा कि यह हाउस तो अनडेमोक्रेटिक है और जो असेम्बली है उसके सामने आप मेहरबानी कर के यह बात न कहियेगा। सेन्ट्रलाइजेशन और डीसेन्ट्रलाइजेशन की बात तो दूसरी है।

श्री राजा राम शास्त्री—क्या यह सदन अनडेमोक्रेटिक है ?

श्री मोहन लाल गौतम—यह इतना रेस्पान्सिबिल नहीं है जितना असेम्बली । इसलिये मैं चाहता हूँ कि जो आज प्राविन्सियल गवर्नमेंट बनी है वह डेमोक्रेटिक है और एडल्ट-फ्रन्चाइज से बनी है । इसलिये यह कहना कि म्युनिसिपैलिटीज डेमोक्रेसी से बाहर है तो मैं कहूँगा कि गलत है । क्योंकि आप वहाँ सवाल कर सकते हैं । अगर किसी ने कोई गलती की हो तो आप उसको निकाल सकते हैं । आप सेंट्रलाइजेशन पर चाहे जितनी ही बहस कर लीजिये वह ठीक है लेकिन डेमोक्रेसी के नाम पर यह चीज नहीं आती है । इसमें छोटी सी चीज नौकर शाही की आ जाती है । मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि पहले जो डी० एम्स० थे और उनके प्रति जो आप के ब्याल थे वह उस वक्त की सरकार थी जो इररेस्पान्सिबिल थी लेकिन आज वह सवाल उठता नहीं है । यह बात दूसरी है कि कोई खराबी है लेकिन आज वह रेस्पान्सिबिल गवर्नमेंट के नौकर हैं और उन पर यह कहना कि उन पर अंकुश नहीं है, यह ठीक न होगा । इसलिए जैसा कि पहले कहा जाता था वह बात उनके प्रति आज कहना मुनासिब न होगा और उस तरह की नौकर शाही आज की नहीं है ।

अगर अंकुश नहीं है तो उसमें लेजिस्लेचर का भी कसूर है, गवर्नमेंट का भी कसूर है, जो ऐसे आदमियों को चुना । लेकिन नौकरशाही पर अंकुश रखने का अधिकार जनता को है । इसलिये ऐसा अधिकार डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को देना अनुचित न होगा ।

डाक्टर साहब ने एजुकेशन के ब्याल से क्या कहा था, मैं ठीक उसको समझ नहीं पाया । लेकिन जो असेम्बलें एजुकेशन के संबंध में हुआ है शायद वह उन को नापसंद हो लेकिन दूसरी तरफ जो उन्होंने बात कही वह सीक्योरिटी आफ सार्विस की है । यह चीज बड़ी भारी है । सार्विसेज का ताल्लुक एलेक्ट्रेड बाडीज से क्या होगा इस पर हम को विचार करना होगा । यहाँ तो आप ने अलग कर दिया है, म्युनिसिपैलिटीज के बारे में भी आप को सोचना होगा । एजुकेशन कमेटी किसी का ट्रान्सफर करे या डिस्मिस करे उसकी खराबियाँ हम को मालूम हैं । हालाँकि आज जो आप का शक है, वह यह है कि इस गवर्नमेंट के पास जो ताकत है वह ले ली जाये और म्युनिसिपैलिटीज को दे दी जाय । मैं कहूँगा कि यह बहुत दूरदर्शिता का स्लोगन नहीं है । आप सार्विसेज के ट्रान्सफर और डिस्मिसल का अधिकार अगर कमेटीज को दे देंगे तो सीक्योरिटी आफ सार्विस न हो सकेगी । दूसरी तरह से जैसा कि लोगों ने सजेशन दिया है वैसा किया जाये तब तो दूसरी बात है । लेकिन स्टेट गवर्नमेंट से ज्यादा न्याय मिलेगा ।

आवृत्त के बारे में डाक्टर साहब ने गवर्नमेंट आफ इंडिया की लोकल फाइनेंस इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट तक तो मुझ को सुना दिया कि यह ठीक नहीं है । लेकिन उसके बाद एक दूसरी जिल्द निकली है और वह यह है कि “उत्तर प्रदेश लोकल बाडीज ग्रांट्स एंड कमेटी” उसकी एक रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने इस बात पर गौर किया है । जो लोकल फाइनेंस इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट गवर्नमेंट आफ इंडिया की थी निकली और यह जो कमेटी थी इसकी रिपोर्ट देर में आई । इसलिये इस पर विचार नहीं किया । उस पर विचार करने के बाद जो भी रिकमेंडेशन की वह यह थी :—

The imposition of octroi should be made compulsory in all the municipalities in addition to the terminal-tax levied by the Government of India. The existing defects of the octroi system can be minimised if not removed altogether by applying to octroi as far as possible the basis and methods adopted at present for assesment and collection of terminal-tax in the municipalities where the collecting agency is their own staff and not the railways.

We, therefore, recommend that the refund system as it exists at present should be abolished. It is considered that this system can be modified by substituting the words “consumption, use and sale” therein for the words

[श्री मोहन लाल गौतम]

"consumption or use therein occurring in the definition of octroi in Section 128 of the Municipalities Act.

The Government should prescribe a model schedule of rates for the guidance of Municipal Boards having due regard to the present income of the various Municipal Boards from indirect taxation, their additional requirements, the existing rates of different commodities, incidences and trade factors, etc."

यह रिपोर्ट तो अभी निकली है कोई डेढ़ दो महीने हुए और परसों आई है।

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद—When was the Committee appointed?

श्री मोहन लाल गौतम—I do not remember exactly when the Committee was appointed but the report of this Committee was sent to Government in December, 1951.

चेयरमैन—This can be enquired into afterwards. We have got very little time left.

श्री मोहन लाल गौतम—इस खतरे के बारे में एकाध मेम्बर साहब ने खास कर कक्कड़ साहब ने कहा कि ऐसा होना चाहिये। जिससे व्यवसायियों को सहूलियत हो और व्यापार बढ़े यह तो खासतौर से दिमाग में रखा गया है। जहाँ तक गोविन्द सहाय की स्पीच का ताल्लुक है बहुत से लोगों ने जवाब दे दिया है। मैं कहूँगा कि उन्होंने बहुत मिस्चिवियस स्पीच दी है।

चेयरमैन—आर्डर, आर्डर।

श्री मोहन लाल गौतम—अध्यक्ष महोदय, मैं कह सकता हूँ कि मैंने अन-पार्लियामेंटरी शब्द का प्रयोग भले किया हो लेकिन उन्होंने बहुत ज्यादा खतरनाक स्पीच दी। उन्होंने इतनी खतरनाक बात कही है कि जिसका नतीजा खराब निकलेगा। अगर मुसलमानों के लिये रिजर्वेशन होगा तो उनकी रिजर्वेशन आफ सीट काफी नहीं होगी। रिजर्वेशन आफ सीट के साथ सेपरेट एलेक्टोरेट भी होंगे और इसका स्लोगन कम्युनल होगा, नेशनल नहीं होगा। पिछले एलेक्शन में वे एक मुसलमान के खिलाफ खड़े थे और मुसलमान से हारे हिन्दू मेजारिटी ने उनको वोट नहीं दिया और मुसलिम मेजारिटी ने भी उनको वोट नहीं दिया, किया इस समाज की जनता को टुकड़े-टुकड़े कर दिया जाय। मुसलमान का इन्टरेस्ट क्या है और हिन्दू का इन्टरेस्ट क्या है, इससे उनका कोई ताल्लुक नहीं है। इस समाज का टुकड़ा हो जिससे कि वे कम्युनिज्म का रास्ता खोल सकें। जिस जगह से होकर अभी वे आये हैं उसका सही एजेंट बन सकें, और मैं कुछ अधिक नहीं कहना चाहता हूँ। उन्होंने यह भी कहा कि इन लीडरों के सामने कोई उद्देश्य नहीं है। ठीक है। चन्द महीनों से कोई उद्देश्य नहीं रहा लेकिन किसी उद्देश्य से वे भी हमारे साथ रहे और मिनिस्ट्री में आये। ६ वर्ष की जो कोशिश है उसको देखकर उनको परेशानी होती है। उसमें उनका कितना हिस्सा है। जब तक वे मिनिस्ट्री में थे तब तक उनको कोई नक्स नहीं दिखायी दिया था लेकिन आज उनको बहुत नक्स दिखाई देता है। इसकी वजह यह है कि परिस्थितियाँ बदल गयीं। एक बात और है। पार्टी की राय से हमको चीजें करनी हैं इसलिये उस पार्टी को पूरा अधिकार है कि वह हमारी राय को बदल दे। उनको खासतौर से अधिकार है। पार्टी का प्रेसर कोई बुरी चीज नहीं है।

सरदार संतोष सिंह ने जैसा कहा कि इंडस्ट्रीज के लिये भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिये। तो यह बात ठीक नहीं है। श्रीमती तारा अप्पवाल जी ने कहा है कि उन्हें मिसेज अप्पवाल क्यों कहा जाता है।

लेकिन अगर प्यारे लाल जी को इन्ट्रोड्यूस किया जायगा तो यही कहा जायगा कि तारावती के हसबेन्ड हैं। एक बार डाक्टर काटजू साहब के साथ था तो वहाँ मुझे उन्होंने सरोजनी नायडू के हसबेन्ड से इन्ट्रोड्यूस किया तो यही कहा कि यह सरोजनी नायडू के हसबेन्ड हैं। मैंने करीब-करीब सब चीजों का जिक्र किया है। ज्योति प्रसाद ने कहा कि बिल बम्बशेल की तरह आगया वरना पहले यह चाहिये था कि बिल सरकुलेट कर दिया जाता। यह जो उनका सजेशन है, यह उस वक्त तक मूल्तबी कर देना पड़ेगा जब तक उनको कोई बिल पारित न करना पड़े। मोटर वेहिकल्स टैक्स के बारे में उन्होंने कहा तो उसमें तो बड़ी दिक्कतें होंगी।

एक बात मैं और कहना चाहता हूँ। एजुकेशन कमेटी वगैरह की बातें ऐसी हैं जिनके बारे में मैं आज कुछ नहीं कह सकता हूँ क्योंकि आगे आने वाले बिल के लिये मैं कोई कमिट-मेंट नहीं करना चाहता हूँ। मैंने एक दूसरा बिल लाने की बात कही थी। माननीय सदस्यों ने उसका स्वागत किया और इच्छा प्रगट की कि वह जल्दी आये। मेरी भी कोशिश है कि वह जल्दी से जल्दी आ जाये। वह बिल यह है कि म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के लिये कई एक्ट्स होंगे और अब कारपोरेशन बिल इस वक्त तैयार हो रहा है। उनके कुछ मूल सिद्धांतों पर हम बातचीत कर चुके हैं। हमारी कोशिश यह है कि वह बिल हम जल्द सदन के सामने लायें अब जो कारपोरेशन बिल होगा उसमें म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के सभी सिद्धांतों पर विचार होगा। बोर्ड्स को क्या अधिकार होगा, क्या सर्विसेज को अधिकार होगा, इन सब चीजों पर कारपोरेशन बिल में हम विचार करेंगे। उन सब पर विचार करने के बाद हम इस पोजीशन में होंगे कि एक म्युनिसिपल बिल लावें। अंत में, मैं सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस बिल का स्वागत किया है और इसको जल्दी पास किया है।

चेयरमैन—प्रश्न यह है कि सन् १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक को पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

चेयरमैन—कल के लिये आगरा यूनिवर्सिटी सप्लीमेंट्री बिल रहेगा। कौंसिल कल ११ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(कौंसिल, ५ बजकर ४ मिनट पर, ६ नवम्बर को ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गई)

लखनऊ,

५ नवम्बर, १९५२ ई०

श्याम लाल गोविल,
सेक्रेटरी,

लेजिस्लेटिव कौंसिल, उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौंसिल

६ नवम्बर, १९५२

उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौंसिल की बैठक, कौंसिल हाल, विधान भवन, लखनऊ, में
दिन के ११ बजे चेयरमैन (श्री चन्द्रभाल) के सभापतित्व में हुई।

उपस्थित सदस्य (५०)

अब्दुल शकूर नजमी, श्री
अम्बिका प्रसाद वाजपेयी, श्री
ईश्वरी प्रसाद, डाक्टर
उमानाथ बली, श्री
एम० जे० मुकर्जी, श्री
कन्हैयालाल गुप्त, श्री
कुंवर गुरुनारायण, श्री
गोविंद सहाय, श्री
जगन्नाथ आचार्य, श्री
जमीलुर्रहमान किदवाई, श्री
ज्योति प्रसाद गुप्त, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेलराम, श्री
नरीत्तम दास टंडन, श्री
निजामुद्दीन, श्री
निर्मलचन्द चतुर्वेदी, श्री
पन्नालाल गुप्त, श्री
पूर्णचन्द्र विद्यालंकार, श्री
प्रतापचन्द्र आज्ञाद, श्री
प्रभु नारायण सिंह, श्री
प्रसिद्ध नारायण अन्नद, श्री
प्रेमचन्द्र शर्मा, श्री
बद्री प्रसाद कक्कड़, श्री
बशीर अहमद, श्री
बलभद्र प्रसाद वाजपेयी, श्री

बालक राम वैश्य, श्री
बाबू अब्दुल मजीद, श्री
महमूद अस्लम खां, श्री
महादेवी वर्मा, श्रीमती
मानपाल गुप्त, श्री
राजा राम शास्त्री, श्री
राना शिवशम्बर सिंह, श्री
राम किशोर रस्तोगी, श्री
लालता प्रसाद सोनकर, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
विश्वनाथ, श्री
बीरभान भाटिया, डाक्टर
ब्रजलाल वर्मन, श्री (हकीम)
ब्रजेन्द्र स्वरूप, डाक्टर
शांति देवी, श्रीमती
शांति देवी अग्रवाल, श्रीमती
शान्ति स्वरूप अग्रवाल, श्री
शिवराजवती नेहरू, श्रीमती
श्याम सुन्दर लाल, श्री
सत्य प्रेमी उपनाम हरिप्रसाद, श्री
सभापति उपाध्याय, श्री
सरदार संतोष सिंह, श्री
सैयद मोहम्मद नसोर, श्री
हयातुल्ला असारी, श्री
हरगोविन्द मिश्र, श्री

निम्नलिखित मंत्री भी उपस्थित थे:

श्री हर गोविन्द सिंह (शिक्षा मंत्री)

आगरा यूनीवर्सिटी (अनुपूरक) विधेयक, १९५२

श्री हर गोविन्द सिंह (शिक्षा मंत्री)—मैं प्रस्ताव करता हूँ कि सन् १९५२ ई० के आगरा यूनिवर्सिटी (अनुपूरक) विधेयक पर विचार किया जाय ।

श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, यह छोटा सा विधेयक जो कि भवन के सामने प्रस्तुत है अपना एक महत्व रखता है । इसका कारण यह है कि समाज में जितने भी व्यक्ति हैं उनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षा संस्थाओं से संबंध है और इस कारण मैं समझता हूँ कि इस विधेयक का महत्व है । दूसरे यह कि कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हमारे सामने उपस्थित हुईं जिनके कारण एक आर्डिनेंस जारी करना पड़ा । निस्संदेह यह सत्य है कि शिक्षा संस्थाओं में एक आर्डिनेंस का जारी करना कुछ बहुत मेल नहीं खाता और मैं आप के सामने और आप के जरिये भवन के सदस्यों के सामने यह स्वीकार करने को तैयार हूँ कि शायद इससे और अप्रिय काम मुझे अपने कार्यकाल में नहीं करना पड़ा, लेकिन मैं फिर भी समझता हूँ कि इस प्रश्न के दो पक्ष हो सकते हैं । लेकिन मैं अपनी जगह पर संतुष्ट हूँ कि यह आवश्यक था और यदि यह नहीं किया जाता तो शायद इससे स्थिति और बिगड़ सकती थी । मैं यह भी समझता हूँ कि शायद इसी से प्रभावित हो कर हमारे मित्र श्री राजाराम जी ने एक काम रोको प्रस्ताव भी दिया था । मैं थोड़ा सा इतिहास इस का बतला दूँ ।

पहले हमारे सम्मुख कुछ अल्प-सूचक प्रश्न आये । उस समय कैबिनेट के सामने यह प्रश्न था कि आर्डिनेंस पास किया जाय या न किया जाय । इसलिये मैं मजबूर था और मैंने इस पर यही लिखा कि यह एक गोपनीय प्रश्न है, जिसको हम इस अवसर पर बतलाने के लिये तैयार नहीं हैं । पर मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मेरी इच्छा कदापि यह नहीं थी कि मैं इस भवन को बंचित रखूँ उस आर्डिनेंस पर बहस करने से । लिहाजा जब आर्डिनेंस पास हुआ तो उसके दूसरे ही दिन चूँकि मेरे दिल में संदेह हुआ कि आर्डिनेंस पर बहस हो सकती थी या नहीं । मेरा अपना ख्याल है कि शायद इस पर बहस नहीं हो सकती इसलिये यह आवश्यक समझा कि एक विधेयक के रूप में आर्डिनेंस को इस भवन के सामने रखूँ जिससे भवन को अपने विचार प्रकट करने का अवसर मिले । तो मैं भवन के सदस्यों को और विशेष कर श्री राजाराम जी को आपके द्वारा यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जहाँ तक गवर्नमेंट का संबंध है उसकी इच्छा कदापि यह नहीं थी कि इस भवन को आर्डिनेंस पर अपने विचार प्रकट करने के लिये अवसर न मिले । आर्डिनेंस की क्या आवश्यकता आ पड़ी यह भी मैं बतला देना चाहता हूँ । आगरा यूनीवर्सिटी ऐक्ट के बमूजिब जो इस समय वर्तमान वाइस चांसलर हैं उनका कार्यकाल १२ दिसम्बर को खत्म हो जाता है ।

१२ दिसम्बर तक एक वाइस चांसलर को नियुक्त करने की आवश्यकता हो जाती है । वहाँ पर कायदा यह है कि एक इक्जीक्यूटिव कौंसिल है जो तीन आदमियों का नाम सेनेट में भेजती है । सेनेट में सदस्यों की संख्या बहुत है, बहुमत से यह सेनेट तीन आदमियों का नाम चुन कर चांसलर के पास भेज देती है और उसी में से एक की नियुक्ति अनिवार्य हो जाती है । मुझे जो सूचना मिली है वह यह मिली है कि नवम्बर के पहले हफ्ते में मीटिंग होने वाली है जिसमें तीन व्यक्तियों का नाम सेनेट में चुन कर भेजा जाने वाला है । हमारे सामने केवल दो रास्ते थे, इसमें संदेह नहीं कि इस आर्डिनेंस के पास होने के पूर्व सरकार ने यह निश्चय कर लिया था कि आज आगरा यूनीवर्सिटी की जो दशा हो रही है उसके मुताबिक सरकार को एक अर्मेन्डिंग बिल पास करना होगा । तो हमारे सभी यूनीवर्सिटियों की दशा अच्छी नहीं है । इलाहाबाद यूनीवर्सिटी में एक कमेटी बठी है जो सब बातों की छानबीन कर रही है । जब तक उस कमेटी की रिपोर्ट नहीं आ जाती है उस वक्त तक सरकार यह नहीं बता सकती है कि उसमें संशोधन की क्या

आवश्यकता है। आगरा यूनीवर्सिटी की हालत को देखते हुये सरकार ने यह तय कर लिया है कि एक असेम्बली बिल की आवश्यकता है। उस समय असेम्बली का सेशन नहीं हो रहा था इस कारण यह बिल लाना नामुमकिन था। इलेक्शन से पहले इस बिल का दोनों हाउसों से पास हो कर अधिनियम बनना बहुत मुश्किल था। इसलिये यही तरीका था कि इलेक्शन होने दिया जाय और जब बिल पास हो जाये तो उस के बमोजब एक दूसरा इलेक्शन हो, दूसरा रास्ता हमारे सामने यह था। अध्यक्ष महोदय, आपने देखा होगा कि आजकल अखबारों में कितनी तरह की बातें निकलती हैं। एक तरफ तो यह कहा जाता है कि बिल पास हो जाने पर चुनाव उसके बाद भी हो सकता है। हो सकता है कि मैं गलती पर हूँ। पर मैंने यही सोचा कि चुनाव हो जाने के बाद इसमें फिर रद्दोबदल करना उचित नहीं होगा। इसलिये वाइस चांसलर का कार्य-काल बढ़ा दिया गया कि जब तक यह बिल पास नहीं होने सोचा एक आदमी जो तीन वर्ष से काम कर रहा है एक वर्ष या कुछ दिनों के लिये और काम करता रहेगा तो कोई गड़बड़ी का संभावना नहीं है। बिल पास हो जाने के बाद जिस प्रकार भवन सम्मेलन चुनाव हो जायेगा। मैं समझता हूँ कि हमारे इस कार्य से हमारी नियत पर कोई धब्बा नहीं आ सकता।

हमने भी शुद्ध हृदय से केवल इसी भावना से प्रेरित होकर इस चीज को आपके सामने रक्खा है। हमारी शिक्षा संस्थाओं में जो दोष फैल गये हैं, उनको किस प्रकार से हटाना चाहिये, यह एक प्रश्न है। इन शिक्षा संस्थाओं के ऊपर ही हमारे देश का भविष्य निर्भर है, हमारे समाज का सारा संगठन निर्भर है, उसकी ओर से आँख मूंदी नहीं जा सकती। इस संबंध में उन पत्रों को यदि आपने पढ़ा होगा और मैं समझता हूँ कि आपने अवश्य ही पढ़ेंगे, तो आपने देखा होगा कि कुछ में यह कहा गया है कि डेमो-क्रसी का खून हो रहा है। मैं इस संबंध में भी कुछ कहना चाहता हूँ। मेरा अपना मत है कि शिक्षा संस्थाओं में और कम से कम शिक्षा क्षेत्र में डेमोक्रेसी का वह स्थान नहीं होना चाहिये और मैं भी नहीं जिसकी कि कुछ सज्जन कल्पना करते हैं। जो राज-संस्थाएँ हैं उनका प्रजातंत्रवाद में स्थान होना चाहिये और वह इसलिये कि जब एक नागरिक, असेम्बली, काँसिल या पार्लियामेंट में वोट देता है तो वह राज्य या स्टेट को ताकत देता है और वह स्टेट को ताकत दे करके उनकी रक्षा भी करता है। इसके बदले में स्टेट उसको कोई अधिकार नहीं देती। लेकिन जब स्टेट किसी व्यक्ति या किसी संस्था को अधिकार देती है तो उस समय उसके लिये यह भी लाजिमी हो जाता है कि वह उन अधिकारों की निगरानी भी करे कि कहीं उन अधिकारों का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है। जैसे कि एक दृष्टांत से मैं आपको बताऊँ कि इंग्लैण्ड के ही कांस्टीट्यूशन को मैं लाजिये। शायद इंग्लैण्ड के डेमोक्रेटिक कांस्टीट्यूशन में किंग का सबसे ऊँचा स्थान है लेकिन यदि आप देखें तो उसको कोई फ़ोडम आफ् स्पीच नहीं है, उसको वोट देने का अधिकार भी नहीं है। आज एक आदमी जो कि साधारण नागरिक होता है, वह कुछ भी कह सकता है, लेकिन आपका प्राइम मिनिस्टर जो चाहें नहीं कह सकता, उसके ऊपर प्रतिबन्ध है। वह वही कह सकता है जो ठीक हो। कहने का अर्थ यह कि अधिकार स्टेट की ओर से दिये जाते हैं वहाँ स्टेट के ऊपर यह भी जिम्मेदारी हो जाती है कि वह यह देखे कि उन अधिकारों का दुरुपयोग नहीं हो रहा है। इस संबंध में मैं आपको आचार्य नरेन्द्र देव जी का विचार पढ़ कर सुनाना चाहता हूँ। एक यूनीवर्सिटी कमेटी बनी थी वह उसके एक मॅम्बर थे और बाद को उसके चेयरमैन भी हुये, तो उन्होंने बड़े अच्छे शब्दों में कहा है कि :

“The only vote properly so called is the vote cast by the citizen voter at a general election. By that vote the primitive layman gives his final verdict on all policies and programmes. All other votes—specially votes given for example to members of services and professions—are not votes at all. They are in the nature of professional advice. Democracy as such has nothing

[श्री हर गोबिन्द सिंह]

to do with the constitution of the Agra University Act. Professional opinion was collected but in the wrong manner. Opinion which should have remained advisory made itself final by the elimination of public men."

इससे स्पष्ट है कि यह आरोप कि डेमोक्रेसी का खून हो रहा है, मैं समझता हूँ कि गलत है। डेमोक्रेसी और अटोनामी में फ़र्क है। यदि आप कहें कि न्याय विभाग में हाई कोर्ट के जजेज में, सर्विसेज में, पुलिस में और सेना में डेमोक्रेसी से काम लिया जाय तो यह नामुसकिन है। हर एक क्षेत्र तथा हर एक संस्थाओं को डेमोक्रेसी के आधार पर स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती।

सरकार इन संस्थाओं को डेमोक्रेसी के आधार पर स्वतंत्रता नहीं दे सकती और न वह कभी यह चाहेगी कि डेमोक्रेसी की आड़ में स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया जाय। लेकिन अटोनामी एक दूसरी चीज़ है। अटोनामी में समझता हूँ और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि कम से कम सरकार ने यूनिवर्सिटी अटोनामी की रक्षा में कोई हस्तक्षेप नहीं किया है। कम से कम जब तक मैं एजुकेशन मिनिस्टर हूँ मैं इसके लिये कोशिश करूँगा कि यूनिवर्सिटी की अटोनामी सुरक्षित रहे। लेकिन हमको फिर भी समझ लेना चाहिये कि अटोनामी है क्या चीज़ ? मैं समझता हूँ कि क्या अटोनामी यही है कि किसी तरह से भी हो, आप चलकर मैं इसके बारे में बतलाऊँगा। अपने व्यक्तित्व स्वार्थ सुरक्षित रहें। आपको यह जानकर ताज्जुब होगा और आपके हृदय को दुख होगा यह मैं जानता हूँ और मुझे भी उसके लिये दुख होता है कि हमारी शिक्षा संस्थाएँ तेज़ी से गिरती जा रही हैं। यह कोई बड़ी खुशी की बात मेरे लिये नहीं है। आप इसको समझते हैं और मैं भी समझता हूँ लेकिन इस समय अवस्था ऐसी आ गई है और मैं यह स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि आपके एजुकेशन मिनिस्टर होने की नाते इस चीज़ का दुरुपयोग मुझसे नहीं देखा जा सकता चाहे वह आगरा यूनिवर्सिटी हो, या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, और वह चाहे इन्टरमीडियट बोर्ड आफ एजुकेशन हो। जहाँ तक इस प्रकार की संस्थायें हैं और जहाँ इस प्रकार का शासन दिखलाई पड़ेगा, या देखा जाता है कि अधिकारों का दुरुपयोग हो रहा है वहाँ मेरा कर्तव्य हो जाता है कि मैं आपत्ति करूँ और उसको रोकूँ और कहूँ कि उसमें घांछली नहीं हो सकती और भरसक उसके सुधारने का प्रयत्न करूँ। अब हमको यह अच्छी तरह से समझ लेना चाहिये कि अटोनामी है क्या चीज़। इन संस्थाओं के लिये हमें पब्लिक सपया देती है। और पब्लिक उनसे ऐसी आशा रखती है कि उनका भविष्य इन्हीं लोगों के हाथ में होगा। वह यह आशा रखती है कि उनके बच्चों को जो शिक्षा दी जायेगी, उससे उनका भविष्य उज्ज्वल होगा। जहाँ तक उसके प्रबंध का सवाल है, उसकी रक्षा का सवाल है, सुचारु रूप से इन संस्थाओं को चलाने का सवाल है और दूसरी बातों का सवाल है तो इन सब के लिये शिक्षा संस्थाओं को पूरी स्वतंत्रता मिलनी चाहिये। लेकिन यदि वे इन कार्यों को नहीं समझती हैं और इनका पूर्ण रूप से प्रतिपालन नहीं करती हैं तो उस समय अटोनामी का कोई स्थान नहीं है। अटोनामी में भी साथ ही साथ यह बात है कि अगर किसी को कोई अधिकार दे दिये जाते हैं, तो उसके साथ ही कई उत्तरदायित्व भी हो जाते हैं और उन अधिकारों के साथ ही साथ अपने उत्तरदायित्व को भी देखना चाहिये। दोनों के समन्वय को शिक्षा क्षेत्रों में अटोनामी का नाम दिया जाता है। अस्तु उन आदेशों को समझाते हुये उनको यह देखना चाहिये कि उनका भविष्य किधर जा रहा है और उनके बालकों की शिक्षा का ह्रास तो नहीं हो रहा है। अगर हम यह देखते हैं कि घन की कितनी आवश्यकता है और वह कहाँ से एकत्रित हो, और दूसरे आदेशों को भुला देते हैं तो हम अटोनामी के आदर्श को भूल जाते हैं जैसा कि मैंने पहले कहा था कि आप विश्वास रखें जब तक यह बात नहीं होगी, उनके भविष्य और उनके आदर्शों पर ध्यान नहीं दिया जायेगा, तब तक यह उचित नहीं हो सकता कि अटोनामी की आड़ में इनको हमारे राष्ट्र को ध्वस्त करने

का अधिकार दिया जाय। अब प्रश्न होता है कि फिर क्या किया जाय। आगरा यूनीवर्सिटी के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ जैसा कि मैंने पहले कहा वह एक बड़ी दुखद कहानी है और वह इतनी दुखद कहानी है कि आप स्वयं रो पड़ेंगे। सन् १९३२ में एक कमेटी नियुक्त हुई थी मैं आपको दावत देता हूँ और आशा करता हूँ कि आप इस रिपोर्ट के प्रत्येक पक्ष को पढ़ें तो मैं विश्वास करता हूँ कि आप पढ़ते जायेंगे और आपकी आँख आँसु गिराती जायेंगी, यह यूनीवर्सिटी की बसा हो गई है। मैं आपको बताऊँ कि किस तरह से वहाँ बोट कनेक्ट किये जाते हैं। इस यूनीवर्सिटी में प्रेजिडेंट की बड़ी संख्या है, बो सी के करीब लोग सीनेट्स में हैं, १५० के करीब कैकली आफ आर्ट्स में हैं। और ६० के करीब कैकली आफ साइन्स में हैं, इस प्रकार बहुत सी संस्थायें हैं। ३४ आइवी एक्जामिनेट की लिस्ट में हैं और हर कालेज के लोग ३ या ४ सीनेट के मेम्बर होते हैं और होता क्या है मुझे पढ़ कर ताज्जुब हुआ। आगरा यूनिवर्सिटी में प्रेजिडेंट ऑफ स्टूडन्ट्स ने जब एक माइली यूनिवर्सिटी के प्रमुखताली गुट को ५० दफा दे या ७ मेम्बरों को सीनेट के चुनाव में बोट दिलावे तो उसको एल एक्जामिनेटिव एक्जामिनरशिप मिलती है। बो सी क्या और २२ मेम्बर दे तो उसको वेक्टर युक्त प्रेकाइज हो जाय। ऐसे ही उदाहरण हैं कि अभी फिक्साव प्रेस में किस्की नहीं और प्रेसकाइज हो गई। मैं आपको क्या बताऊँ उन्होंने यह भी बताया कि एक्जामिनेट्स का हाल यह है उस कमेटी ने लिखा है कि हमको एक्जामिनेट्स की लिस्ट नहीं मिलती है, अगर लिस्ट मिल जाय तो उसमें बड़ी-बड़ी बातें निकलेंगी, लेकिन एक आइवा है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूँ और न लूँगा, अगर नाम से लूँ तो आपकी सज्ज में आ जायेगा कि वह किसी प्रकार भी इस काबिल नहीं है कि उसको एम० ए० का एक्जामिनर बनाया जा सके। लेकिन उसमें उन्होंने लिखा है कि एक्जामिनर जो वहाँ बनाये जाते हैं वह इसलिये नहीं बनाये जाते हैं

श्री गोविन्द सहाय (स्नातक निर्वाचन क्षेत्र)—आप नाम बता दीजिये तो अच्छा होगा।

श्री हर गोविन्द सिंह—नाम मैं कह चुका हूँ कि नहीं बताऊंगा।

चेयरमैन—जो लोग मीज नहीं हैं उनका नाम लेकर किसी प्रकार का आक्षेप करना उचित नहीं है।

श्री हर गोविन्द सिंह—उन्होंने लिखा है कि कमेटी की रिपोर्ट में कि एक्जामिनर इसलिये नहीं बनाये जाते कि सचमुच वह काबिल हैं या उस सबजेक्ट के ज्ञाता हैं बल्कि इसलिये कि उनका प्रभाव है और उनके पास वोट हैं। एक ने तो यह लिखा कि एक साल वहाँ पेपर का लोकेज हो गया सन् २७ में और उस पर एक प्रस्ताव पास किया गया लेकिन कुछ नहीं किया गया। मैं आपको बताऊँ कि यह रिपोर्ट यही से शुरू होती है कि आगरा यूनिवर्सिटी में एक गुट है, वह एक पेंकट के नाम से मशहूर है और उसका मेम्बर होना हर एक के लिये जरूरी है अगर वह मेम्बर नहीं होता है तो उसके कालेज के लड़के फेल होंगे। होता यह है कि एक कालेज हमारा है और हम पेंकट के मेम्बर हैं एक्जामिनेशन पेपर हम जानते हैं और अपने लड़कों को हम हिन्ट दे देते हैं तो हमारे लड़के बावजूद इसके कि हमारा शिक्षा का स्तर नीचा है पास हो जाते हैं और एक अच्छा कालेज टूट जाता है इसलिये कि उस कालेज में लड़के आते हैं, क्योंकि एक्जामिनर वहाँ के होंगे और उनको पास होने का मौका मिलता है। आपको ताज्जुब होगा कि इस खानबीन में मुझे एक उदाहरण ऐसा मिला कि एक दफा एक सीनेट के मेम्बर साहब एम० ए० की परीक्षा में बैठे। एक्जामिनर ने जो उनको मार्क्स दिये उससे वह फर्स्ट डिवीजन में नहीं आ सके। एक्जामिनर बदल दिया गया, दूसरे एक्जामिनर से काफी जंचवाई गई और वह फर्स्ट क्लास में पास हो गये। यही नहीं, एक दफा किसी प्रमुख व्यक्ति के रिश्तेदार फर्स्ट डिवीजन में नहीं आ सके। नतीजा यह हुआ कि हर एक लड़के के ५ नम्बर

[श्री हर गोविन्द सिंह]

बढ़ा दिये गये जिससे वह भी फर्स्ट डिब्बोजन में आजायें। कहा यह गया कि फेल होने वाले लड़कों का नम्बर ज्यादा था इसलिये ऐसा किया गया। मैंने तो कभी ऐसा नहीं सुना था कि अगर फेल होने वाले लड़कों को संख्या अधिक हो तो इस प्रकार मार्क्स बढ़ाये जाते हों। हां पास मार्क्स बढ़ा दिये जाते हैं। मैं आपको बतलाऊं कि कभी-कभी १४ हजार रुपये एकजामिनेशन फीस में एक आदमी को मिलते हैं। यदि टीचर को १४ हजार रुपये एकजामिनेशन फीस में मिल जाये तो भला वह गुटबंदी क्यों न कायम रखेगा। यह मालूम हुआ कि स्कूटनी रेलवे के वेटिंग रुम्स में ही जाती है। मैं अभी आपको इन्टरमीडियेट बोर्ड का हाल बतलाऊं, डा० ईश्वरी प्रसाद साहब ने अपनी बजट की स्पीच में कहा था कि इन्टरमीडियेट बोर्ड में क्लार्क्स स्कूटनाइजर्स होते हैं।

डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद (स्नातक निर्वाचन क्षेत्र) — एकजामिनर्स होते हैं ?

श्री हर गोविन्द सिंह — हां एकजामिनर्स भी होते होंगे। मैं उस वक्त समझा कि बात गलत होगी इसलिये मैंने उसका खंडन भी नहीं किया था बाद को मैंने लिस्ट भेगाई। मुझे अफसोस है, शर्म भी है कि हमारे वफ़्तेर के सौ सौ स्कूटनाइजर्स और टेबुलेटर्स होते हैं जिनको हजार हजार, बारह-बारह सौ, चौदा-चौदा सौ रुपये मिल जाते हैं और उन्हीं के जरिये से सब करप्शन होता है। मैं इसको भी छिपाना नहीं चाहता कि जो गुट आगरा यूनीवर्सिटी में है वह गुट हमारे इन्टरमीडियेट बोर्ड में भी है। एक साहब ने अखबार में लिखा था कि आगरा यूनीवर्सिटी के बाद इलाहाबाद यूनीवर्सिटी पर प्रहार होगा, इन्टरमीडियेट बोर्ड पर प्रहार होगा। मैं इस भवन में आपके सम्मुख कहना चाहता हूं कि जरूर होगा और यह चीज हम चलने न देंगे। इसमें हमारी जिम्मेदारी है, हमारे देश की जिम्मेदारी है। जहां तक भी संभव होगा हम इसके लिये प्रयत्न करेंगे। मैं समझता हूं कि हमारा और आपका यह फर्ज है कि हम और आप इसको देखें। मैं आप के सम्मुख एक अभियुक्त कि भांति खड़ा होने के लिये तैयार हूं। मैं चाहता हूं कि यदि हम गलती करें तो आप हमारी निन्दा करें। हम एक ऐसे स्थान पर हैं कि हमको निन्दा से कभी न डरना चाहिये। हम तो चाहते हैं कि आपसे हमको सुझाव मिलें और उन सुझावों से हम कार्य करें। लेकिन एक बात का मैं आप से जरूर अनुरोध करूंगा कि हमारा हृदय अपनी इन शिक्षा संस्थाओं की कुरीतियों को देख कर रो रहा है। मैं आप से अनुरोध करता हूं कि आप हमारे इस दुख में भाग लें और यह प्रयत्न करें कि कम से कम इन शिक्षा संस्थाओं से यह कुरीतियां चली जायें। मैं कहने का अधिकारी तो नहीं हूं लेकिन आप समझ लीजिये कि जिस कमेटी में सी० जे० महाजन मेम्बर हों, देव ईंगलिश डिपार्टमेंट के हेड, मेम्बर हों, इस पार्टी बंदी के कारण उस कमेटी का चेयरमैन एक एसिस्टेंट टीचर बना दिया जाये। जिस कमेटी में महादेवी वर्मा हों जिस कमेटी में हजारी प्रसाद द्विवेदी हों, उस कमेटी का चेयरमैन ऐसा आदमी बना दिया जाये जिसका सज्जेश्वर भी शायद हिन्दी न हो, यह कहां तक उचित है ?

महादेवी वर्मा जी अभी दो दिन, तीन दिन हुये मेरे पास आयीं। उन्होंने कहा कि भाई जी आप जो चाहें मेरे प्रति करें लेकिन मैं अब उस इन्टरमीडियेट बोर्ड की मीटिंग में नहीं जाऊंगी। आप कौंसिल की मेम्बरी चाहें ले लें लेकिन अब मैं फिर उसकी मीटिंग में नहीं जाऊंगी। फिर भी कहा जाय कि हम डेमोक्रेसी का खून कर रहे हैं, हम आटोनामी कर खून कर रहे हैं। आप ही इसका निर्णय करें।

मैं क्या बताऊं अगर मैं सब कहने लगूं तो यह एक बड़ी गाथा हो जायगी। आप नरेन्द्रदेव कमेटी की रिपोर्ट पढ़ लीजिये और उसके पढ़ लेने के बाद यदि आप इस निर्णय पर आयें कि हमने आगरा यूनीवर्सिटी अर्बैंडमेंट बिल लाने में गलती की तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं अपने बिल को और आर्डिनंस को वापस ले लूंगा और इस बात को होने दूंगा जिस प्रकार से इन शिक्षा संस्थाओं में भी लूट खसोट जारी है, वह वैसे ही जारी रहेगी, पर यह एक बड़ा भारी काम है। किस और से काम शुरू करूं और कहां वह समाप्त होगा, यह नहीं मालूम। इसी संबंध में अखबारों में निकला था और आक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की बात कही गयी थी। मैंने सोचा कि

कैम्ब्रिज में क्या होता है जरा जानूँ तो। मैंने देखा तो यूनीवर्सिटी वहाँ विन्डुल टीचर्स के हाथ में है। बड़ा अच्छा है लेकिन वहाँ होता क्या है। वहाँ के एक साहब ने वहाँ की यूनीवर्सिटी प्रांट कमेटी की बात लिखी है। उनसे मैंने पूछा कि आप के यहाँ शिक्षा विभाग में शाषण होता है तो उन्होंने कहा कि क्या तुम पागल हो गये हो। मैंने कहा कि क्या यहाँ एजामिनरशिप के लिये मेन्स्युपुलेशन नहीं करते तो वे हँस पड़े और कहा कि उसके लिये तो हम को उससे अनुरोध करना पड़ता है। मेरे पास एक साहब ने कम से कम १२ लड़कों की एक लिस्ट भेजी है उन्होंने राज्यपाल के पास भेजी थी। लड़के हाई स्कूल में थर्ड क्लास, इंटरमीडियेट में थर्ड क्लास, बी० ए० में थर्ड क्लास हैं, लेकिन एन० ए० में उनको फर्स्ट क्लास फर्स्ट मिला है। आगरा कालेज के एक प्रोफेसर के निस्वत एक शिकायत थी। मैंने उनकी निस्वत एक बंड निर्णय किया और आगरा कालेज की लिखा कि उनको यह बंड मिलना चाहिये। डा० एन० कं० सेठी ने मेरे पास एक पत्र लिखा, उस पत्र को मैं यहाँ नहीं लाया हूँ उन्होंने लिखा है कि जो बंड आपने दिया है वह आगरा यूनीवर्सिटी का जो हालत है उसके अनुसार ठीक है। लेकिन जो अनुरोध है, उससे मालूम पड़ता है कि बंड अधिक है। आप आगरा यूनीवर्सिटी के उन व्यक्तियों को देखें जिनके हाथ में वहाँ का सारा प्रबन्ध है और जो आगरा यूनीवर्सिटी को चलाते हैं वे इससे भी बड़े-बड़े अपराध करते हैं और साथ ही यह समझते हैं कि हम अपराध नहीं करते हैं, इसलिये मैं समझता हूँ कि जो आपने बंड निश्चित किया है उसको न करें।

कहा जाता है कि वहाँ डेनोक्रेसी है। एक कालेज के प्रिंसिपल ने लिखा है कि वह डेनोक्रेसी क्या है। वहाँ तो हर एक चीज का नामिनेशन है। फर्क सिर्फ यह है कि उस कालेज को अप्रोलिपेशन न मिलेगा जो इस गुट में शरीक नहीं होता है तो यह अवस्था एक विश्वविद्यालय की हो रही है। इसमें सरकार ने जल्दी की, यह आक्षेप भी आप नहीं लगा सकते हैं। सन् १९३८ ई० की कमेटी की रिपोर्ट आपके सामने है। कमेटी की रिपोर्ट जब शायी हुई तो आगरा यूनीवर्सिटी ने एक बड़ा भारी विरोध का पत्र लिखा, यह नहीं कि इस बात का प्रयत्न किया हो कि उन नृटियों को दूर करें बल्कि इस बात का प्रयत्न किया कि बड़े कड़े शब्दों में विरोध करें। मुझे इस बात में तनिक भी संदेह नहीं है कि जो अवस्था सन् १९३८ में थी उससे कई गुना अधिक खराब आज है। अगर १४ वर्ष के बाद सरकार कुछ हस्तक्षेप करना चाहती है तो भवन यह नहीं कह सकता है कि हस्तक्षेप करना अनुचित है। यह आक्षेप हम पर नहीं लगाया जा सकता है। इसमें कोई जल्दी भी नहीं की गई है और हम आपको बतावे कि सरकार उत्सुक भी केवल इसलिये है कि हम यह चाहते हैं कि किसी प्रकार से यह हमारा संस्था ठीक हो, सुन्दर हो, आदर्श हो और इसमें हम आपका सहयोग चाहते हैं।

श्री कुंवर गुरु नारायण (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—अध्यक्ष महोदय, आगरा यूनीवर्सिटी सलोजेन्टो विधेयक जो आज इस भवन को सम्मुख लाया गया है, उस पर जो विचार माननीय मंत्री जी ने रखे और जो परिस्थिति बतलाई उसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है कि इस प्रकार की व्यवस्था जिस इन्स्टीट्यूशन में हो उसके प्रति कड़ी से कड़ी कार्यवाही करना चाहिये। ओन्स, मुझे तो दुब आज इस बात का है और मैं चार्ज करता हूँ इस हाउस के अन्दर गवर्नमेन्ट की फार दि निगलैस्ट आक ड्यूटी कि उनके पास जब सन् १९३८ की रिपोर्ट मौजूद है वह क्यों बुरावाप रहे और कोई कार्यवाही उन्होंने क्यों नहीं की? तेरह चौदह वर्ष के अन्दर कितना भ्रष्टाचार फैल सकता है और कितने स्टूडेंट्स ऐसे पढ़ कर निकले होंगे जिनसे आज देश को नुक्सान हुआ है, उसका सारा का सारा उत्तरदायित्व सरकार पर है। यह कहने की तो मैं हिम्मत नहीं करता पर मुझे बड़ा ताज्जुब भी है कि जो पुराने शिक्षा मंत्री थे वह एक बहुत ही विद्वान और योग्य पुरुष थे और मुझे इस बात का ताज्जुब है कि उन्होंने आज तक यूनीवर्सिटी ऐक्ट को क्यों नहीं बेंज किया और इस भ्रष्टाचार को पनपने देते रहे और लामोश रहे और इस चीज को अपने हाथ में नहीं लिया, जहाँ तक इसका संबंध है कि जो वहाँ पर भ्रष्टाचार फैला हुआ है जैसा कि मंत्री जी ने बतलाया, उससे कोई भी यह नहीं चाहेगा कि वहाँ जो ऐडमिनिस्ट्रेशन

[श्री कुम्बर गुरु नारायण]

हैं उसमें कोई न कोई संशोधन इस प्रकार का न किया जाये। लेकिन एक प्रश्न हमारे सामने उठता है और मैं यह समझता हूँ कि आर्डिनैस जो माननीय राज्यपाल महोदय का जारी हुआ वह गलत हुआ। यह पावर जो है वह एक इमरजेंसी पप जेज के लिये होती है, इस समय हमें इस बात पर भी विचार करना है कि जब थोड़े ही दिन हुये हमारे विधान सभा की बैठक हो रही थी और यह चीज सरकार के दृष्टिकोण में, मस्तिष्क में बहुत दिन से है तो उस समय यह आवश्यक था कि सरकार अपनी स्कीन एक प्रमोडिंग बिल में लाकर इसको चेंज कर सकती थी। लेकिन एकाएक विधान सभा के खत्म होते ही उसके बाद आप आर्डिनैस को जारी कर देते हैं, यह समझ में नहीं आया। आर्डिनैस का जारी करना तो बहुत कम इस्तेमाल होता है। जब सरकार के पास इतना समय था तो कम से कम ऐसी शिक्षा संस्थाओं के बारे में एकदम से आर्डिनैस जारी कर देना, यह ठीक है कि यह जारी हो सकता था और मैं यह भी मानता हूँ कि यह विल्कुल कांस्टीट्यूशनल है लेकिन अनडिप्लोमेटिक था। जब म्युनिसिपल ऐक्ट तीन दिन के अन्दर आकर यहाँ ले जल्दी में पास कराया जा सकता है और चुनाव कराया जा सकता है, तो कोई ऐसी बात नहीं पैदा होती कि जब विधान सभा चल रही थी तो उसमें जाते और इसको पास कराने में कोई दिक्कत होती। इसके बाद बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात पैदा हो जाती है इस प्रजातंत्र युग में आज यह कि सरकार ने आर्डिनैस जारी करके जो भिदाव बढ़ा दी है डाइस चांसलर की, तो जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है वह कैसे खत्म होगा। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अपनी स्पीच में बतलाया कि उस यूनिवर्सिटी में एक प्रकार की गुटबन्दी है, तो फिर यह प्रश्न उठता है कि एक गुट को हटाकर उसकी जगह पर दूसरा गुट के लाने से गुटबन्दी कैसे खत्म होगी और हमारे समाज से गुटबन्दी कैसे दूर होगी। क्या एक गुट को हटाने से गुटबन्दी दूर हो जायेगी। आपके ऊंचे दर्जे के आफीसर जो हैं और जो कि शिक्षा में विशेषज्ञता रखते हैं उन्होंने क्या उपाय सोचा कि जिससे गुटबन्दी खत्म हो जावे। बात यह है कि प्रजातंत्र के युग में यह स्वाभाविक है कि हर संस्था में गुटबन्दी होती है। अब यह है कि वह गुट अपना काम अच्छी तरह से चलाता है या गलत तरीके से चलाता है, दूसरी बात है। लेकिन जब तक आप में प्रजातंत्र की हुकूमत का भाव रहता है तो उस वक़्त तक यह भी है कि हम इस प्रकार का अगर कार्य करेंगे तो इस बात को आशंका हो सकती है और जनता के हृदय में यह बात पैदा हो सकती है कि यह एक प्रकार की डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट है। जब जी में आये उसको हटा दिया और जब जी में आया उसको कायम रखा। ऐसी हालत में इस गुट को हटाने से तो केवल लाभ नहीं होगा। सैद्धांतिक तरीके से किसी गुट को आप हटा नहीं सकते तो ऐसी हालत में जो भ्रष्टाचार और कर्पण है उस को दूर करने के प्रयत्न का प्रबन्ध अधिक प्रजा-तांत्रिक तरीके से होना चाहिये। यदि माना कि आप आज यह अमैजमेंट लाते हैं और उसके द्वारा इस गुट को इस समय हटा दें लेकिन आइन्दा कोई गुट होगा वह भी ऐसा कर सकता है। इसलिये जब तक कोई न कोई चीज सैद्धांतिक तरीके की सरकार निश्चित नहीं करती है तो फिर कैसे सुधार हो सकता है? इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री जी इस पर जरा विशेष ध्यान दें और उनको सोचना पड़ेगा कि कौन सा तरीका ऐसा हो सकता है जिससे हम यूनिवर्सिटियों की अटोनामी को रखते हुये प्रजातंत्र राज्य में उसके उसूलों को मानते हुये इन चीजों को दूर कर सकते हैं उसके साथ ही साथ मुझे इस बात का भी डुल है कि चूंकि माननीय मंत्री जी को बहुत डुल हुआ कि आगरा यूनिवर्सिटी में ऐसा हुआ लेकिन उन्होंने कहा कि जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं उन सब की हालत इस प्रकार की हो रही है। तो इस तरह से जो एक जनरल रिमार्क दिया गया उस से ज़रूर डुल हुआ है। क्योंकि मैं लखनऊ विश्वविद्यालय की एक्जीक्यूटिव कौंसिल का मेम्बर हूँ और मैं जानता हूँ कि सभी विश्वविद्यालयों में इस प्रकार की बात नहीं है। हमारे विश्वविद्यालय में जो वातावरण है वह बहुत ही स्वस्थ और अच्छा है। इस तरह से एक विश्वविद्यालय की नज़ीर लेकर कहना ठीक नहीं है।

श्री हर गोविन्द सिंह—आन एण्डाइन्ट आफ इक्स्प्लेनेशन सर। मैंने दो विश्वविद्यालयों का नाम लिया था और उनमें लखनऊ का नाम नहीं आता है।

श्री कुंदर गुरु नारायण—आपने कहा था कि सभी विश्वविद्यालयों की ऐसी हालत है। और जो इस वक़्त विचार करने की जरूरत है वह यह है कि हमको क्या करना चाहिए। आज चीज जितना आज फिटिसिज़न हो रहा है कि ताहद एक संस्था जो कि लागू की बनाई गई है और हर तरह से एक्जीक्यूटिव कॉमिटी का काम कर रही है उसकी ज़रूरतें हट सकती हैं। ऐसा लगता है कि इसके लिये कोई इकोनॉमिक तरीका मानकी प्रतिपादन करना पड़ेगा। कोई ऐसा तरीका प्रतिपादन करना पड़ेगा ताकि जनता को हानि न हो। मैं यह जानता हूँ कि आज डाक्टर ईश्वरी प्रसाद जी इसका समर्थन करेंगे कि सरकार को आर्डिनंस जारी करना ठीक है। लेकिन इस प्रसार की चीज की कि किंतु समय चाहिए सरकार को प्रतिपादन से कि जिस मूड को चाहिए हमारे साथ सभी कहेंगे कि यह चीज प्रशासन को बिना है। राजनीति प्रशासन को दिखाता है कि सामान रखने के रूप में ऐसी चीजें करना चाहिए जिससे हम कुछ हमें जो की मिला पाए और वहाँ का कार्य अच्छी तरह से फिर चलता सभी। वहाँ तक इस विधेयक का संबंध है मैं तो यह समझता हूँ कि जो इसमें यह अवधि बढ़ायी गयी वाइस चान्सेलर की इच्छा से ही जाया नहीं हो सकती। मैं कल से काम इन राय का हूँ।

मेरी राय यह है कि अगर वाइस चान्सेलर उक्त मूड का इलेक्शन हो जाय तो भी अनेक दिनों से आप इस चीज को भी पूरा का पूरा बहल सकते हैं और किसी प्रकार से जाई बात नहीं हो सकती है। अन्त में मैं यह भी कहूंगा कि आर्डिनंस जारी करने से या प्रस्ताव विधेयक लाने से एक तरह की भावना जलकर जनता में पैदा हो गई कि कोई नहीं कह सकता है कि सरकार की नियत कब बदल जाय साथ ही साथ यह बात भी जरूर लोगों के दिमाग में पैदा होती है कि सरकार जब चाहे यूनीवर्सिटी पर आर्डिनंस लागू कर सकती है और हर चीज को खदोल कर सकती है। इस बात से थोड़ी सी ठेस भी जरूर पहुँचती है। अगर सरकार इस कार्य को एक वैधानिक व व्यावहारिक तरीके से करती तो ज्यादा अच्छा होता। सरकार जो जो प्रोजेक्ट एक्शन है वह ठीक नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

*श्री राजा राम शास्त्री (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र) — माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की ख़शी है कि आज यह विधेयक इस सदन में पेश है। जिस वक़्त मुझे यह मालूम हुआ कि सरकार कोई आर्डिनंस पेश करना चाहती है उसी वक़्त मेरी यह ख़ाहिश पैदा हुई कि अच्छा होता यदि ये सारी बातें सदन के सामने पेश होतीं। इसलिये मैंने इस संबंध में शार्ट नोटिस स्वंचन् भी दिये। मुझे उस समय ताज़्जुब हुआ जब मुझे यह जवाब मिला कि माननीय विचारधीन है और बहुत कान्फ़िडेंसल विचार हो रहा है। मैं माननीय मंत्री जी के भाषण को बहुत गौर से सुन रहा था। सन् ४७ में यह सरकार आई और मैं यह समझता हूँ कि आगरा यूनीवर्सिटी की हालत उस वक़्त भी ऐसी ही थी। एक दम से कोई हालत खराब नहीं हो सकती है धीरे धीरे हालत खराब हुई है। हाँ, यह जरूर हो सकता है कि सन् ४७ के बाद इसकी हालत और खराब हो गई हो। अगर इसकी हालत खराब थी तो सरकार को चाहिये था कि उसकी हालत को सुधारती लेकिन उसने उसमें कोई सुधार नहीं किया बल्कि और भ्रष्टाचार बढ़ गया और आज हालत यह है कि उसकी हालत बहुत ही गिर गई तो सरकार को यह विधेयक लाना पड़ा। माननीय मंत्री जी को इसकी हालत मालूम थी कि ठीक नहीं है तो सरकार को अपने राज्यकाल में सुधारना चाहिये था। आज जो नक़्शा आगरा यूनीवर्सिटी का हमारे सामने है, वह बहुत ही भयंकर है और उस स्थिति को बहुत जल्द सुधारने की आवश्यकता है। वहाँ पर जो खराबियाँ हैं उनको सरकार को दूर करना चाहिये। इस समय यदि सारे सूबे पर निगाह दौड़ाई जाय, सार्वजनिक संस्थाओं पर निगाह दौड़ाई जाय तो यह सब चीजें ऐसी नहीं हैं कि यह सब चीजें यहाँ पर हुई और मिनिस्ट्रान सोते रहे और सन् ५७ में मिनिस्टर महोदय कहने लग जाय कि रिपोर्ट आई है और उस पर विचार करना है। आज हमारे देश की यह दशा है, राज्य की यह दशा है और मिनिस्टर कहने लग जाय कि इस दशा को देख कर सभी सदस्य आंभू बहायें। अगर आपको भ्रष्टाचार

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री राजा राम शास्त्री]

सचमुच में अखरता है और आप देखते हैं कि भ्रष्टाचार है तो उसका जो रोकने का स्थायी उपाय है उस पर वास्तव में आपको विचार करना चाहिये। यह नहीं कि अचानक कोई घटना हुई और तब आपका दिल तिलमिलाया कि देश को बचाओ और कोई उपाय आप ढूँढ़ने लगे तो आर्डिनेंस के जरिये से वह चीज भवन के अन्दर आ गई। मैं मानता हूँ कि गवर्नमेंट ने इस बात पर ख्याल किया लेकिन जैसा कि आपने कहा कि सन् १९३८ में कमेटी बनाी विद्वान पुरुषों ने विभाग लड़ाये कि किस तरीके से यूनीवर्सिटी का प्रबन्ध सही किया जाय। मगर जब यह रिपोर्ट आई उसके कई दिनों के बाद आपको यह आवश्यकता पड़ी कि उसमें लाल पत्ते लगायें, हरे पत्ते लगायें कि उसमें क्या बात आवश्यक है, यह सब चीजें तो सही हैं। सन् १९३८ में जब कमेटी बनाई गई, मालूम नहीं कब रिपोर्ट निकली होगी, गवर्नमेंट के सामने सारे वाक्यात रहे होंगे लेकिन आज तक गवर्नमेंट ने सारी चीजें नजरअन्दाज की। आपके भाषण को सुनने के बाद मेरे विभाग में यह असर पड़ा कि आज एक मिनिस्टर आता है और कहता है कि हमने यह खराबी दूर की है मगर दूसरा मिनिस्टर उसको शायद दे रहा था, वह उसका खराब प्रबन्ध किये हुये था तो दोनों में कौन सी बात सही हो सकती है। या तो जिनके हाथों में यह प्रबन्ध किया गया उन्होंने काफी भ्रष्टाचार किया और बड़ी देर के बाद सरकार ने यह समझा कि यह भ्रष्टाचार राज्य के अन्दर बन्द होना चाहिये। यह चीज मैंने आगरा यूनीवर्सिटी के उस ग्रुप की बाबत कही है जो कि प्रबन्ध करता है। लेकिन जब गवर्नमेंट ऐसे मामलों पर भी आँख बन्द कर सकती है या न गलीजेंट हो सकती है, तब देश का क्या हाल होगा, यह आप स्वयं ही सोच सकते हैं। तो यह बात नहीं होनी चाहिये जो मंजूदा माननीय मंत्री जी हैं मैं उनसे जरा यह कहना चाहता हूँ कि इन घटनाओं से सबक लीजिये। जो बात आपको पहले ही मालूम हो जानी चाहिये थी उसका पता आपको ३० अक्टूबर को चला, हमारे प्राइम मिनिस्टर, जिसकी निगाह बहुत दूर तक होनी चाहिये और उसको सभी चीजों का पता होना चाहिये फिर यह मैं कैसे मान लूँ कि आपको पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है और अचानक २९ तारीख को आपको मालूम हुआ कि घटना होने जा रही है अब उसका उपाय ढूँढ़ना चाहिए और जो आपका सख्त से सख्त ब्रह्मास्त्र था आपने उसका प्रयोग किया और आर्डिनेंस के रूप में इसकी यहाँ पेश किया। आर्डिनेंस, अध्यक्ष जी, एक गम्भीर बात के लिये होना चाहिये। असेम्बली और कौंसिल सेशन में नहीं हैं अचानक देश में घटना हो गई है, राज्य खतरे में है और ऐसे मौके पर इस ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल होना चाहिये। लेकिन यूनीवर्सिटी के वाइस चान्सलर का चुनाव होने जा रहा है, जिसके बारे में कि माननीय मंत्री जी को पहले ही ज्ञान होना चाहिये था कि अब वाइस चान्सलर की मियाद खत्म हो गई है और कब चुनाव होने जा रहा है। आपको इसका पहले से ही उपाय निकालना चाहिये था कि क्या सचमुच आर्डिनेंस के अलावा कोई उपाय हो सकता था या नहीं हो सकता था। मुझे मौजूदा मंत्री महोदय से शिकायत है कि यदि इतने गम्भीर मसले का उनको पहले पता नहीं होता तो किस तरीके से अचानक पहली तारीख को उनको आर्डिनेंस जारी करना पड़ा। पहली तारीख को लेजिस्लेचर प्रेरण किया गया और पहली तारीख को ही आर्डिनेंस जारी किया गया। मेरे दिल में तो यह ख्याल होता है कि इस आर्डिनेंस को पेश करने के लिये ही लेजिस्लेचर को प्रेरण किया गया वरना शायद उसको प्रेरण करने की नीयत ही न आती।

श्री हर गोविन्द सिंह—सही है।

श्री राजा राम शास्त्री—सही है तो तब तो और भी कमाल की बात है। मेरा मकसद तो सभी बातों को भवन के अन्दर कहने का यह है कि हुकूमत काम करने के मौकों पर तो सोती रही और अचानक ही जब पता चला तो आर्डिनेंस जारी कर दिया। अगर आगरा यूनीवर्सिटी के वाइस चान्सलर के चुनाव की बात न आई होती, तो इसके प्रेरण करने की नीयत नहीं आती। मैं ही क्या माननीय मंत्री भी इस बात को मानते हैं कि सचमुच में यह शुभ है कि चीज है और आपने भी इसको स्वीकार किया है कि इस काम को करने की आशा नहीं थी और यह काम जो हुआ है वह अच्छा काम नहीं था। मैं उनसे कहता हूँ कि खैर अब जो हुआ सो हुआ

लेकिन वे इसने एक सबक हासिल करें। और आइन्दा के लिये अपने डिपार्टमेंट को यह बात बतला दें जिससे इस बात की नौबत फिर न आने पाये और वह भविष्य में इस तरह का कोई कदम नहीं उठाये तो मैं समझूंगा कि जो गलत काम हुआ उसको उन्होंने मान लिया। अब खयाल में यह बात आती है कि आखिर जैसे भी किया गया यह तो पुराने वाइस चांसलर की बात है और अब एक नया वाइस चांसलर बनने जा रहा है या उसका चुनाव करने जा रहे हैं, तो इसमें जरूर करण्ट ग्रुप का हाथ होगा और अब शायद वे यह समझने लगे हैं कि अगर करण्ट ग्रुप ने कोई काम ऐसा किया नहीं कि इससे हमारे सूबे में पता नहीं क्या हो जायेगा। तो आखिर उस करण्ट ग्रुप का नामिनी जो है, उसकी एक साल तक मिथाद बढ़ाने के लिये ही लेजिस्लेचर को प्रोत्साहित करके उसे एक आर्डिनेंस जारी करना पड़ा। इस तरह से किसी दूसरे डिपार्टमेंट की बात होती तो कहा जाता कि फजाने का। ऐडमिनिस्ट्रेशन करण्ट है और इससे बहुत नुकसान होने लगा है और इसके लिये एक कानून पास होना चाहिये और उसको जारी करना चाहिये। मगर जब यहां इस तरह से करण्ट ग्रुप मौजूद है, तो उसके लिये उल्टी बात की जा रही है। गवर्नमेंट के यहां इस तरह से तो उल्टी गंगा बह रही है। अब तो शिक्षा संस्थाओं में भी करण्ट ग्रुप हो गये हैं।

श्री हर गोविन्द सिंह—उसने नहीं किया है।

श्री राजा राम शास्त्री—अगर ऐसी बात है, तो मैं इसके लिये कुछ नहीं कहता हूँ, क्योंकि मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं जानता हूँ। लेकिन जो वाइस चांसलर वहां पर बनाया गया तो.....

श्री हर गोविन्द सिंह—वह बात भी नहीं है।

श्री राजा राम शास्त्री—खैर, मिनिस्टर साहब को इसके बारे में ज्यादा पता होगा। हाउस के अन्दर वे उन सब बातों को नहीं बतलाना चाहते होंगे, अकेले में जब मुझे बात होगी, तब वे शायद सब बातें खोल दें। लेकिन मुझे डाल में कुछ काला जरूर मालूम होता है। जनाब अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा भवन की विदवास दिलाता हूँ कि पहले के जो वाइस चांसलर हैं उनसे मेरा कोई संबंध नहीं है और जो उनकी जगह पर दूसरे चुने जाने वाले हैं, न उनसे मेरा कोई वास्ता है, बल्कि यों मैं कहूँ कि आगरा यूनीवर्सिटी से ही मेरा कोई वास्ता नहीं है। सिर्फ दिलचस्पी इस बात की थी कि जब हाउस यहां पर पहले बैठा हुआ था तब मिनिस्टर साहब ने इस बात को क्यों नहीं कहा। वैसे जो वाइस चांसलर इस वक्त के हैं, उनके खिलाफ मेरे अन्दर न कोई इस तरह की भावनाएँ हैं और न जो अब आने वाले हैं उनके प्रति मुझे कोई खास हमदर्दी है। लेकिन जिस ढंग से यह चीज की गई है, वह ठीक नहीं है। साथ ही साथ हमारे मिनिस्टर साहब ने यह भी बतलाया कि उनके लिये भी यह बहुत डिफिकल्ट हो गया था और उन्होंने बहुत परेशानी के साथ इस बात का फैसला किया है। तो मैं कहता हूँ कि उनके ऐडमिनिस्ट्रेशन में ऐसा नहीं होना चाहिये और फिर सब जगह ऐसा हो रहा है। सबमुत्र इस सदन के अन्दर जो मैं बहुधा कहा करता हूँ कि आज जो ऐटमासफियर सब जगह देखा जाता है, वह यही है कि म्युनिसिपल संस्थाओं में ऐसी बात होती है, तो तभी उसका सुपरसेशन होता है। तो अब यही बात शिक्षा संस्थाओं पर भी आ रही है और उनका इन्तजाम भी वैसे ही होता चला जा रहा है। फिर आप कहते हैं कि जब तक वे लखनऊ में बैठे हुये हों, उनको यह बात न मालूम हो तब तक कैसे वह सुधार हो सकता है। जो डेमोक्रेटिक सिद्धान्त है और गवर्नमेंट आज कहती है कि वह डेमोक्रेसी का पालन कर रही है, तो यह बात गलत है। डेमोक्रेसी में हमारे पास ऐसे योग्य व्यक्ति हों, हर ओर से उसकी सुव्यवस्था देखी जाय, मगर यह बात नहीं है और अच्छे शासन के लिये डेमोक्रेसी में इस बात की जरूरत है। म्युनिसिपल बोर्ड में डेमोक्रेसी फैल रही है, शिक्षा संस्थाओं में डेमोक्रेसी बिल्कुल फेल्टोर रही, तो एक दुर्हमत्त में डेमोक्रेसी हो सकती है मगर आज आम तौर से देखा जाय तो लोगों की मनोवृत्ति इस डेमोक्रेसी की तरफ से क्या हो गई है। आज डेमोक्रेसी खराब होती जा रही है और हमारे हिन्दुस्तान में डेमोक्रेसी फेल्टोर होती चली जा रही है। अगर इन्डोविजुअल का राज्य

[श्री राजा राम शास्त्री]

हो तो उसके लिये दूसरी बात हो सकती है। अब तक तो हमारा देश गुलामी में रहा और एंडमिनिस्ट्रेशन से लेकर जितनी संस्थाएँ हैं चाहे राजनैतिक पार्टियाँ हों इसमें शक नहीं कि नैतिक पतन इतना अधिक था जिसकी वजह से मैं मानता हूँ कि यह खराबियाँ हैं और जब हम इस निगाह से देखते हैं तो मेरा बूढ़ विद्वान है कि जो बात आगरा यूनिवर्सिटी के बारे में कही गयी है कि वहाँ भ्रष्टाचार है, वहाँ पैसा कमाया जाता है, शिक्षा के नाम पर शोषण होता है और जितनी मजबूती के साथ माननीय मंत्री ने कदम उठाया उतनी मजबूती से मैं कहना चाहता हूँ कि आप और लगभग संस्थाओं को आँख उठा कर देखें, अपने डिपार्टमेंट को देखिये, हुकूमत को देखिए आप स्वयं अपने आचरण को देखिये, हमारी और अपनी खुद की पार्टी को देखिये और अकेले मकान में जहाँ आप और आप का परमात्मा हो उस समय सोचिये तो मेरा दावा है कि मिनिस्टर साहब विद्वान करते होंगे कि आगरा यूनिवर्सिटी ही नहीं आप निगाह उठा कर देखिये जिसका मैं जिक्र यहाँ भवन में बराबर करता रहता हूँ कि हमारे राज्य भर में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, अपराध बढ़ रहे हैं, लेकिन मुझे ख़ुशी है कि जो बातें हम हमेशा कहा करते थे सरकार के डिपार्टमेंट के बारे में राज्य के बारे में, आज पास पलट गया और आगरा यूनिवर्सिटी की शिक्षाल खड़ी हो गयी। जो बलीले मिनिस्टर साहब प्रबंध के बारे में पेश कर रहे थे उसी तरह से हुकूमत के डिपार्टमेंट्स के बारे में मैं इस भवन के सामने कहा करता था और हर मिनिस्टर डिफेंड करता था अपनी व्यूरोक्रेती को अपने डिपार्टमेंट के बारे में और यहां के सदस्य लोग भी डिफेंड करते थे कि कहां अपराध बढ़ रहे हैं और कहां भ्रष्टाचार है यह तो अपोजीशन वाले ही कहते रहते हैं। लेकिन आज मेरा दावा है कि मिनिस्टर साहब की आज की पहली स्पीच सुनने के बाद भवन की रंगत आप देखियेगा कि जो माननीय मंत्री ने कहा है वह सच है, आगरा यूनिवर्सिटी में भ्रष्टाचार है और अगर किसी डिपार्टमेंट की पोल खोल दी जाय

श्री हर गोविन्द सिंह—जहाँ भ्रष्टाचार होगा वहीं कहा जायेगा, जहाँ नहीं होगा उसको कैसे कहा जा सकता है ?

श्री राजा राम शास्त्री—ठीक है, कुछ जगह दिखाई देता है और कुछ जगह नहीं दिखाई देता है। एक जगह भ्रष्टाचार आपको दिखाई पड़ गया है और आप उस पर आँसू गिराते हैं और आपके दिल में दर्द होता है। सच है दूसरी जगह आप को दिखाई नहीं देता है लेकिन जिस तरह से आपको दर्द पैदा होता है उसी तरह से जब हम लोगों को किसी जगह भ्रष्टाचार दिखाई देता है तो हमारे भी दिल में दर्द उठता है तो उस समय आपको क्यों नहीं फील होता है। आप इस बात को मान कर चलिये कि जिस तरह से आपको दर्द होता है उसी तरह से हमको भी होता है। मैं एक बात और कहता हूँ और जरूर कहूंगा कि आपने फैसला कर दिया है कि जहाँ भ्रष्टाचार होगा उसको समाप्त किया जायेगा। जिस दृढ़ता से और मिनिस्टर्स डिफेंड करते हैं उस तरह से नहीं बल्कि माननीय मिनिस्टर साहब ने साफ कह दिया कि आज आगरा यूनीवर्सिटी की तरफ आँख उठी या किसी भी शिक्षा संस्था के अन्दर कोई भ्रष्टाचार पाया गया या दिखाई दिया चाहे वह इंटरमीजियेट बोर्ड ही हो मैं इसी दृढ़ता से काम करूंगा और यह भी ठीक बात है जैसा मैंने अखबारों में देखा कि उन्होंने यह बात उठाई है कि जो कार्य आगरा यूनीवर्सिटी के साथ सरकार कर रही है और जो कदम उठाया गया है कल को इलाहाबाद यूनीवर्सिटी और लखनऊ यूनीवर्सिटी की तरफ निगाह उठेगी और बोर्ड आफ इंटरमीजियेट एजुकेशन पर भी यही मुसीबत आ रही है। हमें ख़ुशी है कि आज मंत्री जी ने मजबूती से यह बात कही कि जहाँ यह बात होगी वहाँ हम ऐसा काम करेंगे। मैं इतना ही चाहता हूँ कि जो कुछ आपने कहा है और जो कुछ आप करने जा रहे हैं आगरा यूनीवर्सिटी के संबंध में तो उसके खिलाफ कोई कुछ नहीं कह सकता है। लेकिन मैंने सिर्फ गवर्नमेंट की ही तरफ की बात सुनी है और मैं चाहता था कि या तो डा० ईश्वरी प्रसाद जी का भाषण हो जाता या डा० ब्रजेन्द्र स्वरूप जी की स्पीच हो जाती तो हमको दूसरे पक्ष का भी ज्ञान हो जाता कि दरअसल बात क्या है। क्योंकि उनका उससे टच है। तो भवन को भी सोचने का मौका मिल जाता कि उसका क्या इलाज किया जा रहा है तथा जो

बुराईयां हैं, उसके लिये जो कड़ुवा इलाज किया जा रहा है, वह कहां तक ठीक है। हमारा केवल यही कहना है कि जिस बूढ़ता के साथ सरकार आगरा यूनिवर्सिटी पर क़दम उठा रही है उसी तरह से वह अपने और डिपार्टमेंट्स पर भी निगाह रखेगी।

इसी मज़बूती के साथ आप को यह एलान करना चाहिये कि इस राज्य के किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अगर हमें भ्रष्टाचार दिखलाई पड़ेगा तो हम अपने किसी सेक्रेटरी को या किसी कर्मचारी को स्पेयर न करेंगे। यह मज़बूती अगर शासन के अन्दर आये तो लोग डरेंगे। वनां हो यह रहा है कि आप इस भवन के अन्दर जितनी तकरीरें देते हैं तो उनको सुन कर दूसरे लोग यह सोचते हैं कि मिनिस्टर लोग भवन के अन्दर ही इस तरह की बातें करते हैं लेकिन जब सफ़ाई का समय आता है तो नाना प्रकार की बातें पैदा होती हैं। मुझे खुशी है कि आगरा यूनिवर्सिटी के मसले को लेकर बहुत मज़बूती के साथ बातें की गईं और यह क़दम उठाया गया और यह मामला भवन के सामने आ गया। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इसकी जितनी भी सफ़ाई कर सकते हों, करें। मैं समझता हूँ कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी जांच के लिये अगर आप एक कमीशन नियुक्त कर सकें तो और भी अच्छा होगा। केवल एक को कमर-बार बनाकर काम करने से ज्यादा फ़ायदा न होगा। मैं चाहता हूँ सन् १९३० की रिपोर्ट अगर पुरानी हो गई है तो दूसरा कमीशन बनाइये और उसकी रिपोर्ट पर विचार कीजिये और तत्सम यूनिवर्सिटीज़ के लिये नियम बनाइये और जो यूनिवर्सिटी उन नियमों की पाबन्दी करें उनको तो आप सहायता दीजिये और जो न करें उनको दंड दीजिये। मैं समझता हूँ कि यह विधेयक एक बुराई को दूर करने के लिये पेश किया गया है, इसको ज़रूर पास किया जाना चाहिये।

श्री प्रताप चन्द्र आज़ाद (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—अध्यक्ष महोदय, यह विधेयक जो माननीय शिक्षा मंत्री ने पेश किया है, मैं यह समझता था कि एक बड़ा सीधा साधा छोटा सा विधेयक है और शायद उसमें कोई ज्यादा कंट्रोवर्सी की बात न पड़ेगी किन्तु जब मैंने इस पर बहस सुनी तो वह सारी बातें जो वक्तन-फ़वक्तन आगरा यूनीवर्सिटी के संबंध में मेरे दिल में आती रही हैं वह फिर दोबारा नई हो गईं और मैंने यह भी देखा कि वह बातें जो यहां बताई गई हैं उनको मैं बहुत ज़माने से देख रहा हूँ। जब मैं आगरा यूनीवर्सिटी का एक विद्यार्थी था तब से देख रहा हूँ। ज्यादातर बातें तो कानपुर से होती रही हैं। हालांकि कानपुर का आगरा यूनीवर्सिटी से कोई अधिक संबंध न होना चाहिये। कानपुर आगरा से कम से कम २०० मील होगा, लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर से ज्यादा करीब है। लेकिन यह सारी वबा जो फैली है वह कानपुर से ही फैली है मैं यह देख रहा हूँ और मैं एक मुद्दत से देख रहा हूँ कि आगरा यूनीवर्सिटी के अन्दर पार्टीबाजी है। कानपुर के एक सज्जन हैं जो इसको आर्गनाइज कर रहे हैं और इस पार्टीबाजी में ऐक्टिव पार्ट ले रहे हैं। अगर वे इसको छोड़ दें तो आगरा यूनीवर्सिटी के अन्दर जो ऐसी दशा है वह शायद न हो। आगरा यूनीवर्सिटी शायद उस रद्दी दजे को न पहुंचे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा यह अर्ज करना चाहता हूँ कि आगरा यूनीवर्सिटी आज से नहीं, एक मुद्दत से एक ऐसा अड़डा पार्टीबाजी का बना है जिसको कहते हुये मुझे स्वयं लज्जा आती है। माननीय मंत्री जी ने जो कुछ बताया है वह रिपोर्ट के जरिये से ही बताया है।

श्री हर गोविन्द सिंह—लखी हुई बातों से बताया है।

श्री प्रताप चन्द्र आज़ाद—लेकिन मैं आपकी खिदमत में देखी हुई बातें अर्ज करना चाहता हूँ कि उसके अन्दर क्या बुराईयां हैं। आगरा यूनीवर्सिटी के अन्दर जब सीनेट के लिये इलेक्शन होता है तो कानपुर से एक लिस्ट आउट होती है ३४ मेम्बरों की।

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद—३० मेम्बरों की लिस्ट होती है।

श्री प्रताप चन्द्र आजाद—जो लोग वोटर्स होते हैं, बदकिस्मती से मैं भी उनमें से एक हूँ, उनके पास एक ३० मेम्बरों की लिस्ट आती है उसके साथ यह भी होता है कि अगर आप इस लिस्ट पर वोट देंगे तो मैं आपको यह करा दूंगा, मैं आपको मेम्बर बना दूंगा और आपको ऐक्जामिनर बना दूंगा। मेरे पास भी वह लिस्ट आई। एक दो सज्जन और भी यहां पर बैठे हैं उनके पास भी लिस्ट आयी होगी कि इन आदमियों को आपको वोट देना है। अगर आप इन आदमियों को वोट देंगे तो आप भी सीनेट के मेम्बर हो जायेंगे। मैंने कहा कि मैं ऐसी चीज नहीं चाहता। मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि हो सकता है कि यहां पर दो एक सज्जन उस ग्रुप के हों। हमारे माननीय मेम्बर श्री एम० जे० मुकर्जी यहां पर मौजूद नहीं हैं।

चेयरमैन—जहां तक हो सके सदस्यों को चाहिये कि अनावश्यक किसी व्यक्ति पर आक्षेप न करें। कानपुर का इस तरह से जिक्र किया जाना मैं उचित नहीं समझता।

श्री प्रताप चन्द्र आजाद—आगरा यूनीवर्सिटी के अन्दर जो सीनेट का चुनाव होता है उसका ढंग क्या है। कौन लोग उस सीनेट में लिये जाते हैं। मुझे मालूम है कि एक सज्जन जो कितने ही वर्षों से उस सीनेट के मेम्बर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि शायद वे जिन्दगी भर रहे। एक साल से वे मेम्बर नहीं हुए हैं यह भी मैं आप से अर्ज करूँ कि उसका कारण क्या है। आगरा के एक मुख्य कर्मचारी ने कहा क्योंकि उन के किसी भाई का मामला था प्रमोशन का, उसके सिलसिले में उन्होंने कहा कि उसको सपोर्ट करो तो उन्होंने इन्कार कर दिया और कहा कि यह मामला बिल्कुल ऐसा है जिसको मैं बैडसाफी समझता हूँ। तो उसके बाद ३० वाली लिस्ट में उनका नाम भी नहीं आया और वह इस तरह से खत्म हो गया। यह बात कि आगरा यूनीवर्सिटी के अन्दर इलेक्शन होता था यह गलत है। यहां तो एक अजीब तरह का इलेक्शन होता है। इसके अलावा जो मुख्तलिफ कालेजेज के प्रिंसिपल और जो प्रोफेसर्स होते हैं उनको यह हिदायत होती है कि आप १०-१०, १५-१५ मेम्बर बनावें। मेरे सामने ऐसी मिसाल मौजूद है। बरेली में कुछ सीनेट के मेम्बर बनाये गये। यह इसलिये बनाये जाते हैं कि वह ३० वाली फेहरिस्त के नामों को ही सपोर्ट करें। इसके अलावा जो आगरा यूनीवर्सिटी के मातहत दूसरे डिग्री कालेजेज हैं उनके संबंध में भी आपको बतलाऊं। इस सीनेट की तरह वहां पर भी पार्टीबाजी कायम कर देते हैं, चाहे वह बरेली हो, चाहे वह शाहजहांपुर हो और चाहे वह मुरादाबाद हो। हर एक जगह पर दो पार्टियां हैं। एक तो ग्रुप जो इन पावर है और एक वह पार्टी है जो यह कहती है कि हम हर राइट और रांग के मामले को सपोर्ट नहीं करना चाहते हैं। उसका नतीजा क्या हो रहा है। २४ कालेजेज बचे हों तो बचे हों वरना हर कालेज के अन्दर मुकद्दम-बाजी चल रही है, दोनों पार्टियों के अन्दर गालीगलौच होता है, अखबारों में एक दूसरे के खिलाफ निकलता रहता है। यह सब चीजें चल रही हैं। यह सब बातें जो आज चल रही हैं इन सबका एक कारण है कि आगरा यूनीवर्सिटी की व्यवस्था इतनी रद्दी हो गई है कि वह एक कारबीकल की तरह से हो गई है, वह एक फोड़ा हो गया है जो और छोटे छोटे फोड़े पैदा कर रहा है। इसका और कोई इलाज नहीं है सिवाय इसके कि वह चाक किया जाय। बहुत सी बातों का मैं जिक्र नहीं करना चाहता हूँ इसलिये कि मैं यह समझता हूँ कि वह इस काबिल नहीं है कि इस भवन में बतलाई जावे लेकिन फिर भी अध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि मैंने यह देखा है कि बहुत सी जगह डिग्री कालेजेज के अन्दर आगरा यूनीवर्सिटी के अन्दर का जो ग्रुप इन पावर है वह एम० ए० के कलासेज उन सज्जेक्ट्स में खोल देता है उन प्रोफेसर्स के लिये जिनको उन्हें फेवर करना होता है। अभी एक कालेज में एम० ए० का क्लास खोला गया उस सज्जेक्ट में जिसमें केवल दो स्टूडेंट्स थे, एक फाइनल में और एक प्रिवियस में। जब फाइनल का स्टूडेंट पास हो गया और प्रिवियस का फाइनल में आया तो प्रिवियस में कोई नहीं रह गया। इस तरह से एक साल तक कोई स्टूडेंट नहीं रहा। इस तरह से इस यूनीवर्सिटी का रुपया बरबाद किया जाता है। ऐक्जामिनर्स के लिये मैं क्या अर्ज करूँ। मैं नाम नहीं ले सकता हूँ। एक फोटोग्राफर साहब ऐक्जामिनर हैं। जो उनसे १० ग्रुप खिचवा ले वही पास हो जाता है। इसलिये मैं समझता हूँ कि यह बिल तो अब से पहले ही आ जाना चाहिये था और जब माननीय

मंत्री ने यह देखा कि पानी सर के ऊपर से चला गया और दूसरा कोई इलाज नहीं रहा तब यह विधेयक आया। बाहर से आदमी तब इलाज करता है जब वह बिल्कुल मायूस हो जाता है, निराश हो जाता है और जब समझने लगता है कि अब यह ठीक होने का नहीं तब वह कोई चीज बाहर से करता है। अभी जब कुंवर साहब कह रहे थे कि वाइस चांसलर उस पार्टी का था जो कि पार्टी इन पावर थी तो फिर क्या वजह है कि उनको फिर से रखा जाता है जब कि उनकी पार्टी में खराबियां हैं। मेरा कहना यह है कि वाइस चांसलर को इसलिये उनकी पार्टी हटा रही थी कि वह अपनी पार्टी से इतिफाक नहीं करते थे और उन्होंने कुछ बातों में पार्टी के कहने के मुताबिक डिटो नहीं किया। वह उस पार्टी के इशारों पर चलने के लिये तैयार नहीं हुये। वाइस चांसलर ने जब देखा कि खराबियां हैं और अगर मैं पार्टी की हर बात को मानता हूं तो जिम्मेदारी मेरे ऊपर आती है तो उन्होंने पार्टी की कुछ बातों को मानने से इंकार कर दिया। तब पार्टी वालों ने यह कोशिश की कि उनको हटा दिया जाये। मैं अधिक समय न लेकर यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह जो विधेयक सदन में आया है वह बिल्कुल समझानुसूल है। मैं आशा करता हूं कि जल्दी ही सरकार आगरा यूनीवर्सिटी के संबंध में संशोधन दिल पेश करेगी। और अगर वह जल्दी न पेश हुआ तो मैं समझता हूं कि आगरा यूनीवर्सिटी के गिरे हुये खंडहर भी नजर न आयेंगे। मैं सरकार से आशा करता हूं कि वह जल्दी ही संशोधन दिल पेश करे। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

*श्री बन्नी प्रसाद कक्कड़ (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)--जनाब चेरमैन साहब, मैं इस मौके को गनीमत समझकर जनाब का शुक्रिया अदा करता हूं कि जनाब ने मुझको यह संज्ञा दिया कि मैं अपने ह्यालाल को इस बिल के ऊपर रखूं। जनाब के खूबसूरत यह भी कह देना चाहता हूं कि मैं किसी का नाम लेना ठीक नहीं समझता हूं। जनाब मिनिस्टर साहब जिस वक़्त अपनी स्पीच दे रहे थे मेरे दिल में कुछ खतरनाक बात सुनकर जिनके बारे में मैं खुद अपना इल्म रखता था और दिलजोश कर रहा था। उस वक़्त मेरे और जनाब के कोलीग मरहूम श्री एहसानुर्रहमान क्रिदवई की याद आई। वह शायर थे और उन्होंने एक शेर मुझे सुनाया था।

सैयाद लग ही जायगी एक दिन क़फ़स में आग,

बैठा हूं मुंतज़िर दिले सोजा लिये हुये।

मैं इस बात को जिस वक़्त श्री राजाराम साहब तक्रारीर कर रहे थे उस वक़्त नुन रहा था। जब उनके अफ़्फ़ाज़ पर घौर करता हूं तो मुझे ह्याल आता है “Marriages and Government are series of compromises.”

“Sunshine without shade, pleasure without faith and happiness without sorrow were not life at all.”

मैं जनाब के सामने एक वाक़या पेश करना चाहता हूं। जनाब भी सन् ३७,३८ और ३९ में इस ऐवान में मौजूद थे मैं बदकिस्मती से या खुशकिस्मती से आगरा यूनीवर्सिटी की सीनेट का मेम्बर गवर्नमेंट का नामनी था। लेकिन हुज़ूर को खुशख़बरी सुनाऊं कि आज तक मैंने सीनेट का दरवाज़ा तक नहीं देखा और सीनेट की मीटिंग तक की इत्तिला नहीं हुई। जनाबवाला, यहाँ किस तरह से लड़के पास किये जाते हैं, किस तरह से वोट हासिल की जाती हैं और किस तरह से पालिटिक्स लाया जाता है इसका खामियाजा बहुत खराब है। मुझे अब ताज़्ज़ुब होता है कि हमारे बच्चों में इस तरह की खराबी क्यों है। उनका हुस्न है, उनकी यह खूबियां हैं जो इन बच्चों में पैदा होती हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि वह क्यों हैं? मैं बदकलाम से बचना चाहता हूं, इसलिये इन अफ़्फ़ाज़ में अर्ज करना चाहता हूं। मैं ऐसी यूनीवर्सिटियों को जिनका काम बच्चों को गुमराह करना है, पहला शस्त्र हूं, जो कि वोट देने के लिये तैयार हूं कि इनको बन्द कर दिया

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री बन्नी प्रसाद कक्कड़]

जाय । मैं इस बुरे काम को लिये यूनीवर्सिटियों को नहीं चाहता हूँ । मैं जनाब को इत्तिहा देना चाहता हूँ और मुमकिन हो कि जनाब को मालूम हो कि जो यू० पी० का इन्टरमीजियेट बोर्ड है उसके लिये जिस वक्त दोबारा मुझे से पूछा गया कि क्या आप इसका मेम्बर होना पसन्द करते हैं तो मैंने साफ़ जवाब दिया कि मैं इससे फेड अप हो गया हूँ इसलिये नहीं चाहता हूँ । मुझे एक मर्तबा का ख्याल है, डाक्टर इबादुर्रहमान जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ और रखता हूँ, वे बहुत काबिल आदमी थे उन्होंने एक मर्तबा अपनी स्पीच में कहा कि हम कक्कड़ साहब से एक शेर सुनेंगे । मैं उस समय परेशानी में था लेकिन मुझे एक शेर याद आ गया जिसके माने ये थे कि आप इसको डाइरेक्टर हैं आपका फ़र्ज है और यह हकीकी फ़र्ज है कि इस चीज को जो बोर्ड में हो रही है उसको बन्द कर दिया जाय । मैं दबी जवान में कहना चाहता था कि इस गिरो-हबन्दी को दूर कर दिया जाय । मेरी दरखास्त है कि दरअसल गवर्नमेंट की खास तवज्जह इस जानिब में होनी चाहिये । जो सख्ती यूनीवर्सिटियों की जानिब है वही सख्ती इन्टर बोर्ड की गिरोहबन्दी को क़श करने के लिये होनी चाहिये । मुझे इन्टरमीजियेट बोर्ड में ऐसी गुट-बन्दी देखकर ताज्जुब हुआ । मुझे उम्मीद है और कबी उम्मीद है कि मिनिस्टर साहब जो स्मिष्ट रखते हैं वह निहायत मुबारक है । मैं तबक्को करता हूँ कि वह इस चीज को दूर करेंगे और अगर यह बुराई दूर नहीं हुई तो जितनी एजुकेशन है वह बेकार हो जायगी, जो तालीम हम बच्चों को दे रहे हैं उससे उनकी कोई फायदा नहीं होगा । जब मैं तालिबइल्म था तो मुझे यहां तक नहीं मालूम था कि मेरा मुमतहिन कौन है लेकिन आज बाजारों और स्टेशनों पर इस बात की चर्चा होती है कि मुमतहिन कौन है । मेरे कहने का मतलब यह है कि किस जगह पर कौन मुमतहिन है । पहले यह कायदा था कि आधा नम्बर भी नहीं बढ़ सकता था, लेकिन आज १०-१० और १२-१२ नम्बर बढ़ जाते हैं । जब मिनिस्टर साहब अपनी तज़रीर दे रहे थे तो उन्होंने फरमाया कि इन्टरमीजियेट बोर्ड में क्लर्कों के जरिये लोगों को हर बात का पता चल जाता है । पहले तो मुझे इस बात पर यकीन नहीं आता था लेकिन आज मिनिस्टर साहब के कहने पर यकीन आ गया है । मुझे इस वक्त अपने पुराने मरहूम दोस्त बाबू कन्हैया लाल की बात याद आ गई कि वह कहा करते थे कि अब नम्बर बढ़ाये जाते हैं उस वक्त तो मैं मैं इस बात को सच्च नहीं मानता था लेकिन आज इस बात को ठोक समझता हूँ । आज मरहूम की बातों का सच्चा नक़्शा सामने आ जाता है । जनाब चैयरमैन साहब, मैं आपके जरिये से जनाब मिनिस्टर साहब से दरखास्त क़रूंगा कि उनको आजकल की तालीम को दुस्त करना चाहिये । ऐसा करने से बच्चों को भी फायदा होगा और मूलक की भी तरक्की होगी । इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का स्वागत करता हूँ ।

श्री गोविन्द सहाय—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एजुकेशन मिनिस्टर की स्पीच को काफी गौर से सुन रहा था, उन्होंने इस बिल को पेश करते हुये, एजुकेशन के अन्दर जो बुरा-इयां हैं और जिस तरह से वह उसको दूर करने का इरादा रखते हैं ज़िक्र किया और मुस्तलिक तरीके से उन्होंने भ्रष्टाचार की भी चर्चा की है । आज उन्होंने इस बात को महसूस किया है कि एजुकेशन में तब्दीली होनी चाहिये और हमको इसमें कोई जबर्दस्त चेन्ज करना होगा । मुझे आज उनकी बातों को सुनकर ताज्जुब हुआ । उन्होंने रिपोर्ट पढ़कर सुनाई । जो वाक्यात गुज़र गये हैं तो वह बातें आखिर हमारे पुराने मिनिस्टर साहब ने नहीं सोचा या उनकी राय में यह बातें कोई अहमियत ही नहीं रखती थी । उनको इन बातों की उस वक्त ज़रूरत ही नहीं महसूस हुई या उन्होंने इस को ज़रूरी ही नहीं समझा । आज कल करप्शन इतना बढ़ गया है कि हर शख्स इसका शिकार हो रहा है और हर एक यही कहता है कि करप्शन हमारे जरिये से नहीं शुरू होता है बल्कि दूसरी जगह से होता है । यह एक नयी हवा फैल गयी है और लोग एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते हैं अपने को कोई नहीं देखता है । यह सवाल इतना आसान नहीं है कि महज़ आप कोई बिल लाकर या किसी बिल में तब्दीली करके या कोई क़ानून पेश करके दूर कर सकते हैं । इन तमाम बातों को देखते हुये मुझे जब कभी सोचने का इत्तिफ़ाक़ होता

है तो मेरे दिमाग में यही बात आती है कि आज दुनिया में हमारा मुल्क इतना बदनर्था है कि यहां के लोगों का यानी हमारी जनता का चरित्र बहुत गिर गया है। किसी भी कम्पनी में यह बात हमेशा मानी जाती है कि अगर मुल्क में सबसे पहले किसी का चरित्र गिरता है तो लीडरों का चरित्र सब से पहले गिरा माना जाता है और जिन लीडरों का चरित्र गिर जाता है उनको सबसे पहले सजा मिलनी चाहिये। क्योंकि आधुनिक लीडरशिप का लोगों के कैरेक्टर पर असर पड़ता है। यह वही मुल्क है जिसके अन्दर महात्मा गांधी ने मिट्टी के आदमी में हिम्मत पैदा की, आदमियों के अन्दर त्याग की भावना पैदा की और मुल्क के लिये लोगों को दिलों में मुहब्बत पैदा की, लोग अपने मुल्क के लिये मर मिटने को तैयार थे। लेकिन आज उस मुल्क की जब हम हालत देखते हैं तो हम से से हर एक की आंखों में आंसू आते हैं। आज यहां का चरित्र सर रहा है। मैं तो कहता हूँ कि इसकी जिम्मेदारी आवकी, वमरी, सब की है। जब किसी मुल्क का लीडरशिप का फाल होता है तो सारा मुल्क निरना है, अगर बच्चा राज करता है तो मारे कम्पनी का मारे ल ऊंचा होता है। लीडरशिप के साथ-साथ जो चीज होती है वह देश के ऊपर बहुत गहरा असर पैदा करती है। सिर्फ इतना कहना ही काफी नहीं है कि हम जनता की उन्नति चाहते हैं, हम जो कुछ भी चाहते हैं वह जनता की मोशन एजुकेशन को ऊंचा करने के लिये चाहते हैं, तो इतना ही कहने से देश की हालत अच्छी नहीं हो जाती है या सिर्फ बिल के जरिये से कोई चीज पेश करना ही काफी नहीं है। सिर्फ इतना ही कहना काफी नहीं होता कि लोग ईमानदारी से रहें, बल्कि उनको ईमानदार बनाने के लिये आपको वह सब उपाय करने चाहिये जो किसी भी मुल्क में एक ईमानदार आदमी बनाने के लिये अप-मायें जाती हैं। अगर आप उन सभी बातों को करेंगे जो कि एक ईमानदार आदमी होने के लिये जरूरी हैं तो लोगों में ईमानदारी का जूझ पैदा होने लगेगा और मुल्क का हर बच्चा-बच्चा ईमानदारी की ओर झुकेगा। इसलिये मैं अवब म कहूंगा कि मुझे कोई किसी क्रिस्म का मुगलतान नहीं है और मैं जोरदार शब्दों में कहूंगा कि इन संस्थाओं में बड़ा करण्डन है। तो केवल ला को तब्दील करने से ही वह दूर नहीं हो सकता है। पिछले सात सालों में मुझे नई प्रेरणा के प्रेरित लोगों से मुलाकात करने का इतिहास हुआ है और उनकी बातों का सुनने का भी इतिहास मुझे हुआ है। बड़ी प्रेरणा से वे व्यक्ति उठे और बड़ी-बड़ी भावनायें लेकर आगे बढ़े मगर जब उनको कोई उम्मीद न रही कि उनकी वह भावनायें कभी भी पूरी होंगी तो निराश हो गये। मैं आन-रेबिल मिनिस्टर साहब से इतना ही चाहूंगा कि जो बात उन्होंने कही है कि इसमें सबका कदम आगे होना जरूरी है और उनकी जिम्मेदारी का जो कदम उठेगा उससे सूबे की तालीम सुधर जायेगी तो कम से कम मैं यह चाहूंगा कि लड़कों की शिक्षा इतनी अच्छी हो जाय कि उनके दिमाग खुल जाय और उनको मुल्क के बारे में जानकारी हो। आजकल जिस तरह का स्टुक्चर शिक्षा का है उससे तो लड़कों का दिमाग कभी नहीं खुल सकता है। इसमें जो आपने सिस्टम बनाया है वह आप पर हावी हो गया है और आप ने इन्सानियत को भुना रक्खा है। जो दो एक बातें मैंने कही हैं मैं नहीं चाहता था कि इस तरह की बातें कहूँ लेकिन मजबूरन मुझे ऐसा कहना पड़ता है जब कि मैं लड़कों की हालत को देखता हूँ। इसके अलावा आज जो शिक्षा का सुधार हो रहा है वह यह है कि आज एक हाई स्कूल का लड़का उतना बोध नहीं रखता है जितना कि पहले के छुठों और सातवीं कक्षा के लड़के रखते थे। उन्हें अपने मुल्क के बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। मुझे ताज्जुब होता है कि किसी भी बोर्ड के अन्दर या किसी स्कूल के अन्दर लड़कों को बाहरी ज्ञान नहीं कराया जाता है। इसलिये मैं यह चाहूंगा कि जो सुझाव देता हूँ उसके ऊपर कम से कम गौर तो किया जाय और मुझे सुझाव के तौर पर यह कहना है कि शिक्षा इस तरह की हो कि जिससे लड़कों को अपने देश के अलावा और देशों का भी ज्ञान हो, उसे देश से मोहब्बत हो और वह देश की हर प्राबल में हिस्सा लेकर अच्छी तरह से उसे समझ सके। लेकिन आपने इस नजर से इस चीज को नहीं रखा है आपने कोई इस क्रिस्म की चीज इसमें नहीं रखी है, बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि आपने इस प्राबल को टच भी नहीं किया है।

श्री हर गोविन्द सिंह—ऐसी बात तो नहीं है।

श्री गोविन्द सहाय—अगर ऐसी बात नहीं है तो मुझे खुशी है कि आपने इस चीज को स्वीकार तो कर लिया । इसके अलावा मैं अपने कांग्रेसी मित्रों से भी कहना चाहता हूँ कि जो कुछ भी सुझाव की बात मैं कहता हूँ वह यह है कि आप पापुलर गवर्नमेंट में होते हुये भी इस चीज की ओर ध्यान नहीं देना चाहते हैं । ताज्जुब की बात है कि हमारे डाक्टर सम्पूर्ण-नन्द जी को भी इस बात का पता नहीं रहा कि हमारे देश में क्या हो रहा है । जो सुझाव हम देते हैं आप उसकी मारेलिटी को देखिए तो मालूम होगा कि उसके अन्दर कुछ तत्व हैं फिर आपको उन सुझावों को मानने में क्या दिक्कत होती है । इस तरह खाली कहने से ही कोई भी मसला हल नहीं हुआ करता है । अगर आप इसकी अमली जामे की ओर निगाह नहीं देते हैं तो भले ही आप एक नहीं १० आर्डिनेन्स पास करा लें, मुझे इममें कोई एतराज नहीं है कि आप नें आर्डिनेन्स क्यों बनाया, मुझे कानूनी बातों में पड़ने की आवश्यकता भी प्रतीत नहीं होती है, इससे कोई फायदा नहीं होगा और आपकी शिक्षा से लड़कों के दिमाग में कोई तरक्की नहीं होगी । इस जेनरेशन के लिये नहीं बल्कि आगे आने वाले जेनरेशन के लिये तो यह बात हो जाय और वे डेमोक्रेटिक एटमीसफियर में अपने को महसूस करें और इस तरह से डेमोक्रेसी उनके लिये मददगार हो । बहुत लोग डेमोक्रेसी को माने समझते नहीं हैं और वे उसके माने यह लगाते हैं कि उसका मतलब इलेक्शन से है और वे यह समझते हैं कि डेमोक्रेसी बगैर इलेक्शन के पूरी नहीं हो सकती है । लेकिन डेमोक्रेसी को माने जो मॅथोड बहुत समझता है वह यह है कि डेमोक्रेसी में एज्युकेशनल पैटर्न हो । तो आज जो एज्युकेशन का सिस्टम चल रहा है उससे हमारे मुल्क में डेमोक्रेसी क्या रह सकती है और इस सूबे में भी करोड़ों लोगों को इस बात की एज्युकेशन मिल रही है । डेमोक्रेसी में जो बात महत्व की है और उसमें जो बात हम करना चाहते हैं और जो में उचित समझता है वह यह है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में कश्चर होना चाहिये, डेमोक्रेसी से लोगों को रहन-सहन के तरीके सीखने चाहिये, डेमोक्रेसी में लोगों को कुछ आउट लुक आफ लाईफ होना चाहिये । लेकिन जनता इलेक्शनबाजी को डेमोक्रेसी कहती है और इस तरह से आप भी असेम्बली में लोगों को सीटें देते हैं और वे मेम्बर बन जाते हैं । सारे समाज के लोग इसको इसी छयाल से लेते हैं और वे डेमोक्रेसी के बारे में यही छयाल रखते हैं । मैं भी पहले कांग्रेस में था और उससे बाहर हुये मुझे तीन साल हो गये हैं लेकिन मैं इस बात को जानता हूँ । मैं इसलिये नहीं कहता कि इस बात का मुझ पर कोई असर होता है, लेकिन जो बात में साफ और ठोक समझता हूँ उसको यहां कह देता हूँ । लेकिन जिस तरीके से यहां मेम्बरों को कमेटीयों के लिये सीटें दी जाती हैं, वह तरीका नहीं होना चाहिये । तो इस तरह के ट्रेडिशनस चले आ रहे हैं और इन ट्रेडिशनस से तरक्की नहीं हो सकती है । हमें लोगों को विजिन आफ एंगिल्स को बदलना है, उनके स्टैंडर्ड को ऊंचा करना है और उनके मारेल को उठाना है । आगरा यूनीवर्सिटी के लिये जब यह बात उठाई गई, मैं इसके लिये उनसे हमददी रखता हूँ और इसका मुझे अहसास है । इस तरह से जितनी भी ऐसी करण्ट चीजें हैं, उनको खत्म करने की कोशिश करनी चाहिये । मैं कहता हूँ कि मिनिस्टर आफ एज्युकेशन जो भी इस तरह का बड़ा काम करना चाहते हैं और अगर वे उसमें कामयाब हो गये, तो इससे बड़ा कन्ट्रिब्यूशन और दूसरा नहीं है । लेकिन मैं बड़े अदब से आपसे कहना चाहूंगा कि आपको चारों तरफ की चीजों को देखने को जरूरत है और खास तौर से एज्युकेशन को सुधारने को जरूरत है । मैं यह चाहता तो नहीं था कि चीन का नाम यहां पर लूँ, लेकिन जब मैं कोई ऐसी बात देखता हूँ, तो मुझे उसके लिये हुक्मत से कहना पड़ता है । लेकिन कल जब मैं चला गया था अपना स्पीच देकर, क्योंकि मुझे लखनऊ यूनीवर्सिटी में स्पीच देने जाना था, तो मिनिस्टर साहब ने मेरे बारे में यह जिक्र किया था कि मैं तो चीन का एजेंट हो गया हूँ । लेकिन जो चीन की अच्छी बातें होती हैं वे मुझे कहनी पड़ती हैं । मैं कहता हूँ कि चीन एज्युकेशन में आपसे भी पिछड़ा हुआ था मगर मैंने वहां देखा कि उनके यहां जो एज्युकेशन लड़कों को दो जातो है, उसमें दिमाग के झकाव को देखा जाता है कि वह किधर है । इस तरह से वहां थ्योरी और प्रैक्टिस के आब्जेक्टिव को मिलाया जाता है और देखा जाता है कि उनका दिमाग किस ओर विकसित हो सकता है और उनकी सोशल और इकोनोमिक कान्शेस देखी जाती है । इसी तरह से उनको शिक्षा दी जाती है और वह तरीके पहले

से बदलें हुये हैं। अगर आप इंग्लैंड में जायें जहाँ कि सबसे बड़ी डेमोक्रेसी की जिम्मेदारी है, वहाँ की तालीम स्पोर्ट्स पर बढ़ रही है। उनको उस दिशा की ओर ही ले जाया जाता है और उसमें काम-याब होते हैं। जब हमारा मुल्क गिर रहा है तो हमको भी चोट लगती है। हमें खुशी है कि आपने सन् ३८ को कमेटी को रिपोर्ट को देखा और आप के आँसू निकले। ये आँसू खत्म न हो जायें बल्कि एक टोस पैदा हो जिससे जो काम आपने शुरू किया है वह पूरा हो और आपको सबका सहयोग प्राप्त हो।

*श्री शान्ति स्वरूप अग्रवाल (अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र)—माननीय अध्यक्ष महोदय, लगभग सभी सदस्यों ने इस बिल को प्रशंसा की है। शिक्षा पं जो खराबियाँ हैं और जो इस समय यूनीवर्सिटीज की हालत है उस पर बोलने का तथा अपनी राय जाहिर करने का अवसर आज इस सदन में प्राप्त हुआ है। मैं तो यह कहूँगा कि आज जो बातें कही गयी हैं वह पहला ही दिन है जो यहाँ कही गयी हैं और किसी भी देश में ऐसी बातें शिक्षा संस्थाओं के प्रति नहीं कही गयी हैं। मैं मानता हूँ कि शिक्षा संस्थाएँ और विश्वविद्यालय हमारे देश के गौरव के स्थान हैं, किसी भी देश की संस्कृति और जो वहाँ का समाज है वह सब यूनीवर्सिटीज पर निर्भर है। किसी भी देश का कल्याण और जो उसका भविष्य होना है वह यूनीवर्सिटीज पर ही निर्भर होता है और यह सरस्वती (गाडेस आफ लरनिंग) के प्रतीक हैं और वहाँ के अध्या-चार के बारे में इस तरह के सार्वजनिक स्थान में वर्णन किया जाना वास्तव में जो शिक्षा से संबंध रखते हैं उनके लिये दुख की बात है। आज जो दशा है वह किसी से छिपी नहीं है जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा कि सन् ३८ से पहले और उसके बाद और आज तक जो हालत है वह रिपोर्ट से भी मालूम होता है और लोगों को भी मालूम है तथा वह माननीय मंत्री जी के सामने इस वक्त आई। प्रेजिडेंट के बारे में जैसा कि हमारे माननीय प्रधान मंत्री पं० नेहरू जी और पं० पंत जी ने कहा और गार्जियन्स भी जानते हैं लेकिन उनको अपने वक्त्रों को यूनीवर्सिटीज में भेजना पड़ता है और वहाँ से निकलने के बाद वह किसी भी काम करने के लायक नहीं रह जाते हैं। मैं विस्तार से इन बातों का उल्लेख नहीं करूँगा जिधर आँख उठाकर आप देखें हर जगह यही बात देखने को मिलेगी। हमारे विद्यालय सिर्फ परीक्षा लेने के लिये ही नहीं बनाये गये हैं, वहाँ पर विद्यार्थी २४ घंटे रह कर शिक्षण प्राप्त करता है वहाँ की दशा मैं अपनी आँखों से देखी है। मैं प्रान्त की लगभग सभी प्रकार की संस्थाओं से संबंधित हूँ। इसलिये मैं कह सकता हूँ कि मैंने अपनी आँखों से देखा है। जिस कालेज के छात्रावास में दो सौ छात्र होते हैं वहाँ के वाडन साहब को या सुपरिन्टेन्डेंट साहब को यह पता नहीं होता कि हमारे छात्रावास में कौन-कौन विद्यार्थी हैं। जब कोई विद्यार्थी किसी प्रकार का आज़ा लेने के लिये उनके सामने उपस्थित होता है तो वह उससे पूछते हैं कि क्या तुम इसी छात्रावास में रहते हो। जब किसी छात्रावास के सुपरिन्टेन्डेंट या वाडन को यह भी पता न हो कि हमारे छात्रावास में कौन-कौन विद्यार्थी रहते हैं तो वह वाडन अपने छात्रावास के छात्रों के चरित्र के संबंध में और उनकी पढ़ाई के संबंध में क्या ज्ञान रख सकता है। यूनीवर्सिटीज के संबंध में, बीच में इन्टरमीडियट बोर्ड के संबंध में आयेगा मैं उसे छोड़ दूँगा, यूनीवर्सिटीज का जो रिकगनीशन है, मुझे इस बात का पता है कि आज डिग्री कालेजों भी धर्मशालाओं में मौजूद हैं। इन धर्मशालाओं में जहाँ बैठने का स्थान ठीक तरह से नहीं है, जहाँ यात्रियों के आने से किसी और प्रकार की व्यवस्था की जाये वहाँ डिग्री कालेज चल सकते हैं। क्यों चल सकते हैं? क्योंकि वहाँ पैसे का बल है। यूनीवर्सिटीज के सिलसिले में भी मैं कहूँगा कि वहाँ भी पैसे का प्रभाव है। जहाँ भीतर से लक्ष्य पैसा है वहाँ बाहर से भी पैसा ही लक्ष्य रहता है। जब किसी डिग्री कालेज के रिकगनीशन का सवाल उठता है तब भी यह कहा जाता है कि इतने लाख रुपया होना चाहिये। वहाँ के प्रबंधकर्ता कैसे हों इसकी देख-भाल को कोई आवश्यकता नहीं होती। जब इस प्रकार के कालेजें खुलने प्रारम्भ होते हैं, जब उनकी जड़ में पैसा ही है तो वहाँ जो और चीजें होती हैं वह भी स्वाभाविक रूप से पैसे की ही तरफ चली जाती हैं। सरकार का हस्तक्षेप यूनीवर्सिटीज में हुआ है। जिस तरह से सब

*सदस्य ने अपना भाषण श्रुद्ध नहीं किया।

[श्री शान्ति स्वरूप अग्रवाल]

को प्रसन्नता है, मुझे भी प्रसन्नता है, और मैं समझता हूँ कि अपने बच्चों में जो लोग भी अच्छी बातें देखना चाहते हैं, तथा स्वयं शिक्षा संस्थाओं की ओर भी माननीय मंत्री जी को इस बात के लिये बधाई मिलेगी कि उन्होंने एक मजबूत कदम इस ओर उठाया है। अभी हाल में जो फर्षावाबद में झगड़ा हो गया था वहाँ की दो शिक्षा संस्थाओं को एकदम बन्द करने का काम भी ऐसा ही था जैसा कि यूनीवर्सिटीज के लिये आर्डिनेंस जारी करना है। छोटी शिक्षा संस्थाओं के लिये रिकगनीशन छीनना, ग्रांट बन्द करना ऐसा था जैसे यूनीवर्सिटीज की ग्रांट बन्द करना। इसी प्रकार जब यहाँ के कालेज के संबंध में कोई स्टेप गवर्नमेंट ने लिया, यद्यपि उसके लिये शोर भी मचा परन्तु जो लोग इस बात के लिए इच्छुक थे कि विद्यार्थी आज जिस दशा में हैं उससे निकलकर ठीक रास्ते पर आवें उनको प्रसन्नता हुई। यहाँ एक बड़े सिद्धांत पर आघात अवश्य हो रहा है। सरकारी हस्तक्षेप शिक्षा संस्थाओं में कम से कम और अगर हो सके तो बिल्कुल ही न हो। मैं इस सम्बन्ध में आश्रम आदर्शों का मानने वाला हूँ और मैंने प्रारम्भ से लेकर अब तक इन्हीं आदर्शों पर वर्क किया है। शिक्षा संस्थाएँ जब तक आश्रम के आदर्शों पर न चलकर पैसे के आदर्श पर चलेगी तब तक सरकारी हस्तक्षेप की पूरी सम्भावना रहेगी। सरकार के हस्तक्षेप वाली नीति के अनुसार जो शिक्षक कार्य करेगा वह परतंत्र होगा और उसका मस्तिष्क उसी प्रकार का होगा। वह पैसे से विक सकता है। शिक्षक का मस्तिष्क पैसे से और सरकार से स्वतंत्र होना चाहिये। इस समय ऐसी परिस्थिति आ गई है जिसकी वजह से विरोध करने वाले भी समर्थन करते हैं। बहुत दिन से सेकेंडरी असोसियेशन की मांग रही है कि सभी शिक्षा संस्थाओं को नेशनलाइज होना चाहिये। अगर सभी शिक्षा संस्थाएँ सरकार के अन्दर चली जायेंगी तो शिक्षक स्वतंत्र नहीं रहेगा। वह अपने मस्तिष्क को बेचकर काम करेगा और जैसा सरकार चाहेगी वैसा वह काम करेगा। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट का जमाना था तो उस वक्त शिक्षक को वही करना पड़ता था जैसा वह चाहती थी। जो शिक्षक ब्रिटिश गवर्नमेंट की भगाने में लगे थे वे चुपके-चुपके काम करते थे। ऐसा न हो कि सरकार का आधिपत्य इतना बढ़ जाय कि शिक्षक को मस्तिष्क बेचना पड़े, अगर ऐसा होगा तो तमाम शिक्षक नष्ट हो जायेंगे। इस समय सरकार के सामने दो रास्ते हैं या वह अव्यवस्था को अच्छी तरह से बढ़ने दे या उस लांछन को लेकर आगे आये और उनको दूर करने की कोशिश करे। मैं आप के द्वारा अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का ध्यान न तात्पूर्वक एक विशेष बात की ओर दिलाना चाहता हूँ। उसको बतलाने के बाद मैं अपनी बात को समाप्त करूँगा। वह बात यह है जो आज हमारी दशा है वह केवल यूनिवर्सिटी की वजह से नहीं है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आकर सबसे पहले काम यह किया कि शिक्षा की दशा को बिगाड़ा। जिस देश की शिक्षा बिगड़ जायेगी उस देश का भविष्य अंधेरे की ओर चला जायेगा। उन्होंने यह काम किया कि सेकेंडरी एजुकेशन को अपने हाथ में लिया। जब फिर जरूरत पड़ी तो यूनिवर्सिटी को छु लिया। शिक्षा को इस तरह से अंग-भंग कर दिया जैसे किसी रोगी को अच्छा करने के लिये उसके अंग का विच्छेद कर दिया जाता है। मैं उनकी बतलाऊंगा प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन और यूनिवर्सिटीज एजुकेशन बना करके तमाम शिक्षा के शरीर को काटकर विभाजित किया है। इन बातों की ओर आपका ध्यान यहाँ भी और बाहर भी आकर्षित कर दिया जा चुका है, आप विस्तृत रूप से देखेंगे तो आप को मालूम होगा कि शिक्षा के सारे विभागों की दशा भयानक हो गई है। इसलिये एक कमेटी हो और वह इस पर विचार करे। इस भवन में मैं दूसरी बार अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा माननीय मंत्री जी का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ। वह ऐसा करे कि शिक्षा के सभी अंगों पर विचार करके उनकी खराबियों को दूर करे।

चेयरमैन—सदन की बैठक २ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(सदन की बैठक १ बजे अवकाश के लिये स्थगित हो गयी और २ बजे चेयरमैन के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

डाक्टर ब्रजेन्द्र स्वरूप (स्नातक निर्वाचन क्षेत्र) —माननीय चेयरमैन साहब, चूंकि मेरी तबियत खराब थी इसलिये मैं नहीं चाहता था कि इस पर कुछ बोलूँ मगर चूंकि कुछ तकरीरें ऐसी हुईं जिससे मैं समझता हूँ कि मुझे कुछ कहने की आवश्यकता है। सबसे पहले मैं अपने मिनिस्टर साहब को यह यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मेरा हरगिज यह मंशा नहीं है कि किसी की नियत पर हमला करूँ और न मैं आगरा यूनीवर्सिटी से ज्यादा इन्टरेस्टेड हूँ। मैंने तकरीरें सुनीं। मुझे एक अफसोस जरूर हुआ कि तकरीरों में कुछ ऐसे पर्सनल हमले हुये जो कि इस हाउस में कम से कम नहीं होने चाहिये थे। यह बिल तो एक छोटा सा बिल है और उसकी निस्वत तमाम बातें कहने की जरूरत भी नहीं थी। मिनिस्टर साहब ने एक दुखभरी तकरीर की और मैं समझता हूँ कि कोई ऐसा दिल न होगा जिसमें दर्द न उठा हो और कौन सी आंख होगी जिसमें नमी न आ गई हो, मगर मैं समझता हूँ कि मिनिस्टर साहब की तकरीर जो है वह एक तरफा मामलात पर मुबनी करती है। मुझे कुछ मामलात मालूम हैं लेकिन मैं उनका जिक्र करना नहीं चाहता। यह ठीक है कि आगरा यूनीवर्सिटी क्या तमाम यूनीवर्सिटीज में रिकार्ड्स की जरूरत है। और जहां तक रिकार्ड्स का ताल्लुक है जैसा कि और लोगों ने कहा है मैं भी रिकार्ड्स चाहता हूँ। मगर मेरा यह ख्याल है कि आगरा यूनीवर्सिटी में जो बातें की गईं वह कम से कम मैं कहने के लिये तैयार नहीं हूँ कि वह सब सही हुई हैं। अगर आगरा यूनीवर्सिटी की बाबत कुछ मालूमात गवर्नमेंट के पास थीं तो गवर्नमेंट का सबसे पहिला स्टेप जो होना चाहिये था वह यह होना चाहिये था कि चांजेंज लगाकर यूनीवर्सिटी के पास भेजते और उसके बाद कोई और कार्यवाही करते।

मसलन कहा गया कि किसी ऐक्जामिनेर को १४ हजार रुपये बतौर रिनुमरेशन दिया गया। जहां तक मेरी मालूमात है आज तक कोई ऐसा वाक्या नहीं आया है।

श्री हर गोविन्द सिंह—जी हां, आगरा यूनीवर्सिटी ने अपने एक ऐक्जामिनेर को १४ हजार रुपये रिनुमरेशन के बतौर दिये हैं।

डाक्टर ब्रजेन्द्र स्वरूप—यह कभी नहीं हो सकता।

श्री हर गोविन्द सिंह—आई बैंग योर पाइंडन। १४ हजार नहीं बल्कि १३, ५६६ है। नाम भी लिखा है कि किस को दिया गया है अगर आप कहें तो उसको दे दूंगा।

डाक्टर ब्रजेन्द्र स्वरूप—मेरे इल्म में यह कभी नहीं आया है। इसका ज्यादा से ज्यादा रिकार्ड जो है वह ५ हजार है। मगर मेरा जहां तक ख्याल है १४ हजार किसी को नहीं मिला है इसमें कोई मिसअन्डरस्टैंडिंग हो सकती है। मेरे दोस्त आजाद साहब ने कानपुर का खास तौर से जिक्र किया है। मुझे नहीं मालूम कि उनका किससे मतलब है। मैं वहां के ग्रेजुएट की तरफ से यूनिवर्सिटी का मेम्बर भी नहीं रहा। मैं तो कानपुर डी०ए० बी० कालेज का प्रेसीडेंट रहा। मैं नहीं समझता कि कैसे उन्होंने यह बात कह दी। बहरहाल मैं आजाद साहब को मुबारिकबाद देता हूँ कि उन्होंने हिम्मत दिखलाई। उन्होंने बहुत सी लानतें दी हैं। मैं समझता हूँ कि वे लानतें नहीं दे सकते हैं। कम से कम मैं यह समझता हूँ कि आज तक किसी ने ऐसी लानतें नहीं दी हैं और न किसी की हिम्मत ही हुई है। उन्होंने मुझसे एक लिस्ट के बारे में कहा। मेरे पास कोई लिस्ट नहीं आई है। उन्होंने हमारे कानपुर के लिये बहुत कुछ कहा है। उन्होंने कहा कि यहां के लोगों की आगरा यूनीवर्सिटी में मेजारिटी है। लेकिन कानपुर से ग्रेजुएट कान्सिडरेंस से आगरा यूनीवर्सिटी के लिये सिर्फ ५ या ६ आदमी चुने जाते हैं। इन बातों को देखते हुये मिनिस्टर साहब गौर करें और एक्तरफा इत्तिला पर फंसता न करें। मगर मैं जानता हूँ कि आगरा यूनीवर्सिटी में बहुत से ईविल हैं परन्तु वह सभी यूनीवर्सिटीयों में हैं और उनको

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[डाक्टर ब्रजेन्द्र स्वरूप]

निकालना गवर्नमेंट का फर्ज है। अब गवर्नमेंट जाग उठी है। लेकिन उन्होंने जो कदम उठाया है उससे वह किसी तरह से ठीक नहीं हो सकता। मैं भी एक लौय्यर हूँ और लौय्यर की हँसियत से गवर्नमेंट को आगाह करना चाहता हूँ कि जो स्टेप आपने लिया है वह ठीक नहीं है। आपने जो आर्डिनेंस निकाला है वह अनवारेन्टेड है और वह इसलिये कहता हूँ कि मैंने आज तक कोई ऐसी मिसाल नहीं देखी है जिसमें किसी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ने यूनिवर्सिटियों के मुतालिक इस तरह का आर्डिनेंस निकाला हो। मैं समझता हूँ कि यह पहिला स्टेप है। जैसा कि मेरे कई दोस्तों ने भी बताया है कि यह आर्डिनेंस अनवारेन्टेड है, आर्डिनेन्स उस सब्जेक्ट मैटर के लिये निकाला जाता है जिस पर कि स्टेट लेजिस्लेचर लेजिस्लेशन करने का अख्तियार एकदम रखता हो। पहला सवाल जो मेरे सामने आया है वह यह है कि मैं कोई प्वाइन्ट ऑफ आर्डर रेंज नहीं करना चाहता हूँ, मगर मैं गवर्नमेंट के इल्म में यह जरूर लाना चाहता हूँ कि वह जो स्टेप ले रहा है वह क्वैश्चनेबिल है, इसलिये मैं समझता हूँ कि मैं अपनी राय का इजहार कर दूँ, बाकी मिनिस्टर साहब को अख्तियार है कि वह इस पर विचार करें कि यह कहाँ तक सही है। जहाँ तक आगरा यूनिवर्सिटी का ताल्लुक है उसकी मैं थोड़ी सी हिस्ट्री आप लोगों के सामने कह देना चाहता हूँ। आगरा यूनिवर्सिटी सन् १६२६ ई० में स्थापित हुई। यह इस गज से स्थापित की गई थी कि जो कालेज में मध्य प्रदेश और ग्वालियर वर्ग रहें थे उनको सुभीता मिल सके और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को भी कुछ रिलीफ मिल सके। उसकी जिम्मेदारी को कम करने के लिये यह यूनिवर्सिटी कायम की गई थी। अजमेर, भोपाल, मध्य प्रदेश, विन्ध्याचल और यू०पी० इन पांच स्टेट्स के कालेजों के लिये। यह यूनिवर्सिटी अजमेर, भोपाल और विन्ध्याचल स्टेट में प्राविन्शियल सरकार को अख्तियार नहीं दिया गया है, वहाँ पर यूनियन को अख्तियार है। जहाँ तक इन स्टेट का ताल्लुक है इसमें कोई शूबहा नहीं है।

While the Union Government has power to make laws for the whole or any part of the territory of India, the legislature of a state may make laws only for the state there of.

The power of a state would confine to the territory of the State.

जनाबवाला, मैं आपको इजाजत से आर्टिकल २४५ पढ़ना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मिनिस्टर साहब इस पर गौर करें। इससे वह यह न समझें कि मेरा मतलब ख्वामख्वाह उनके काम में रुकावट डालना है। मैं कानून में कोई रुकावट नहीं डालना चाहता हूँ। अब मैं मिनिस्टर साहब का ध्यान आर्टिकल २४५ की तरफ दिलाना चाहता हूँ।

245. Subject to the provisions of this Constitution, Parliament may make laws for the whole or any part of the territory of India, and the legislature of a State may make laws for the whole or any part of the State.

No law made by Parliament shall be deemed to be invalid on the ground that it would have extra territorial operations.

साफ तौर पर उसका मंशा यह है कि स्टेट लेजिस्लेचर को इसमें कोई हक नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई शूबहा नहीं है कि इस स्टेट को जो लेजिस्लेटिव पावर है, वह जो भी टैरीटरी इस स्टेट के अन्दर है उसी के मुतालिक कानून बना सकती है। जहाँ तक आगरा यूनिवर्सिटी का ताल्लुक है मैं यह कह सकता हूँ कि इससे उसका कोई भी भला नहीं हो सकता है। जो चीज स्टेट के बाहर हो उसके मुतालिक कानून नहीं बना सकती है। जिस लिहाज से आप आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट ला रहे हैं या उसमें सप्लीमेंटरी पेश कर रहे हैं तो उसका असर इस स्टेट पर भी पड़ता है। इसलिये मैं बहुत अदब से अर्ज करना चाहता हूँ कि आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट को अमेंड करने का तरीका इसमें नहीं है जैसा कि मैंने अर्ज कर दिया कि इसमें बहुत सी स्टेट ऐसी शामिल हैं जिसमें कानून बनाने का आपको कोई हक नहीं है।

अब मैं थोड़ा सा आर्डिनेंस के मुताल्लिक अर्ज करना चाहता हूँ। यों तो मैंने पहले ही अर्ज कर दिया है कि स्टेट लेजिस्लेचर को किसी ला बनाने का पावर नहीं है और गवर्नर को भी यह हक हासिल नहीं है कि वह किसी स्टेट के मुताल्लिक ला बनवाये जिसके लिये उसको कोई भी अख्तियार हासिल नहीं है। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि जैसा कि आर्टिकल २४५ में लिखा हुआ है कि जब कोई ऐसी जरूरत महसूस हो सकती है जो कि वाकई इस किस्म की हो जिसमें कि इनीडियेट ऐक्शन लेना हो तो उसके लिये नामल कोर्स एडाप्ट करना ठीक नहीं है और वह उसके खिलाफ पड़ता है। जहाँ तक नामल कोर्स का ताल्लुक है उसके मुताल्लिक श्री राजा राम शास्त्री जी ने अपनी तकरीर के अन्दर अच्छी तरह से बयान कर दिया है और अच्छी तरह से अपने विचार जाहिर कर दिये हैं। इसलिये मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि नामल कोर्स में मशीनरी को आगे दिक्कत हो सकती है। आप यह तरीका उस वक्त भी अख्तियार कर सकते थे जब कि प्रेजेन्ट मशीनरी चालू थी और उसी समय इस इलेक्शन का मसला भी रखा जा सकता था। उसका नतीजा साफ तौर पर यह होता कि जैसे ही लोकल बाडीज का काम समाप्त हो जाता तो उसके साथ साथ वाइस चांसलर का भी चुनाव खत्म हो सकता था। क्या वजह थी कि यह आर्डिनेंस इस भवन के अन्दर आता और उस मशीनरी को ३ या ४ महीने के लिये और रक्खा जाता। मैं बड़े अदब से अर्ज करना चाहता हूँ कि यह क्यों नहीं पहले ही ख्याल किया गया कि कब उनकी सविस खत्म हो रही है और उसके ठीक एक या दो रोज पहले आपके दिल में ख्याल आया कि आगरा यूनिवर्सिटी को रिफार्म किया जाय। मैं समझता हूँ कि कम से कम दोतीन हफ्ते पहले से पेपर में यह बात छन रही थी कि आगरा यूनिवर्सिटी के लिये यह बिल आ रहा है। मुझे तो यह मालूम होता है कि माननीय मंत्री जी को यह मालूम हुआ कि आर्डिनेंस ही लाया जाय क्योंकि बिल उस वक्त तक नहीं आ सकता जब तक कि कैबिनेट उसको मंजूर न कर ले। मुसकिन हूँ कोई और तरीका हो जिस वजह से यह सोचा गया कि एक आर्डिनेंस निकाल दें और आर्डिनेंस निकालने के बाद आप अपनी शक्ति का इस्तेमाल जिस तरह से चाहें कर सकते हैं तो यह ठीक नहीं है। यह तरीका ठीक नहीं है और इसमें फर्क पैदा हो जाता है और इससे लोग रिड्रेस हो जाते हैं। आपने इसमें रिड्रेस करने की कोशिश की है। इस समय मौजूदा वाइस चांसलर मिस्टर महाजन थे और इसमें कोई शक नहीं कि वे इसी ग्रुप के थे मगर जिन खराबियों के खिलाफ आपको शिकायत थी और जैसा कि अभी आजाद साहब ने भी कहा है कि वे उसी ग्रुप को विलिंग करते थे। तो कम से कम क्या वे इसको मानने के लिये तैयार नहीं हैं कि वे पहले उसी ग्रुप को विलिंग करते थे और अब जरूर वे आज कांग्रेस में शामिल हो गये हैं और इस वक्त से उनका ख्याल यह हो गया है। वे गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहेंगे इसलिये कि आज वे मेजारिटी ग्रुप के हो गये हैं। आज तो मेजारिटी रूल इसी प्रकार से चलता है और आज जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, वह मेजारिटी से चलती है। अगर आजाद साहब कांग्रेस पार्लियामेंटरी बोर्ड के मेंबर हैं तो वह उसकी मदद में जरूर कहेंगे। लेकिन डेमोक्रेसी का हफ है और उसका तरीका है, वह यह है कि मेजारिटी जो है, वह तो कंट्रोल करेगी ही और आप मेजारिटी को माइनारिटी में रिड्यूस कर सकते हैं। मैं यह नहीं कहता हूँ कि यूनिवर्सिटियों में जो खराबियाँ हैं वे दूर न हों मैं चाहता हूँ कि वे खराबियाँ अवश्य दूर हो जायें लेकिन मैं यह भी चाहता हूँ कि वहाँ प्रोपोजिनेट रिप्रेजेन्टेशन होना चाहिये जिसमें कि माइनारिटी को भी यह हक हो जाय और जो तीन मेंबर इक्जीक्यूटिव मेंबर से होते हैं उसमें भी माइनारिटी को हक हो। इस समय यू०पी० के सभी यूनिवर्सिटियों की हालत खराब है, इसमें कोई शक भी नहीं है लेकिन जहाँ तक माइनारिटी की लिस्ट ईश्य होती है, उसके लिये ऐसी मेन्टलिटी नहीं होनी चाहिये। इसमें भी कोई शक नहीं है कि हमें उसकी खराबियों को दूर करना है।

एक बात यह है कि आजाद साहब को कानपुर का ख्याल आया, आपने उसके बारे में जो कहा, पता नहीं वह कहां सुना, मालम नहीं आजाद साहब को ऐसी मालूमात

[डाक्टर व्रजेन्द्र स्वरूप]

कानपुर के बारे में कहाँ से हो गई। शायद सुपरसेशन की वजह से वे इस किस्म की बातें करते हों। वैसे मैं समझता हूँ कि इस मौके पर आर्डिनंस पास करने की कोई जरूरत नहीं थी। जैसा कि मैंने आपसे अर्ज किया कि मामूली कोर्स में इसके लिये ऐसा नहीं करना था और यहाँ पर एक बिल बाद में लाया जा सकता था। और तीन चार महीने तक अब तक जैसे चलता रहा था, चलने दिया जाता और उसी पुराने ऐक्ट से काम हो जाता। यह बात जरूर थी कि पहले ५ नवम्बर को वाइसचांसलर का इलेक्शन होने वाला था तो उस में बहुत गलत फहमी मालूम होती है। वाइस चांसलर का टर्म १२ दिसम्बर को खत्म होता है तो ४ दिसम्बर तक इस के लिये हो सकता था। अमेडमेंट बिल हो सकता था। मामूली कोर्स में यही ठीक था और इसके लिये बाद में असेम्बली बुलाई जा सकती थी और उसको वहाँ पर पेश कर सकते थे।

मेहरबानी करके आप इस डिपार्टमेंट को भी ऐसा न बना दें जो आर्डिनंस से छल किया जाय बल्कि जो कानून आप बनावें वह खाली एक यूनिवर्सिटी के लिये न हो। आज खराबियाँ सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी में नहीं हैं बल्कि आप देखें तो तमाम यूनिवर्सिटीज में आपको मिलेंगी। मैं देखता हूँ कि इस बिल में टर्म आफ प्रेजेंट वाइस चांसलर का जो बढ़ाया गया है ३ साल के अलावा है। मैं समझता हूँ कि किसी खास शख्स के लिये यह तरमीम न होनी चाहिये थी लेकिन तरमीम जो हो वह जनरल होनी चाहिये। यह किसी खास शख्स के खिलाफ न होना चाहिये था इसका मतलब यह है कि मौजूदा जो वाइस चांसलर हैं उनको सरकार का कान्फिडेंस नहीं है और उम्मीद थी कि वह जीत जायेंगे इसलिये यह किया जा रहा है। मैं जानना चाहता हूँ कि मौजूदा वाइस चांसलर में क्या खराबी थी। मैं तो यह कहता हूँ कि गवर्नर को यह अधिकार था कि उसको कन्फर्म करे या न करे। आखिर मैं यह कहना चाहता हूँ कि खराबी पैदा होने का अद्वेश जो बताया गया है उस पर तो मुझे कुछ कहना नहीं है मगर मैं यह जरूर चाहता हूँ कि आपको उनका जवाब तलब करना चाहिये था, उनको नोटिस देना चाहिये था और एक्सप्लेनशन लेना चाहिये था, यह नहीं जैसा कि आपने आर्डिनंस पास कर दिया। या आपने कह दिया कि यह मामला कन्फिडेंशल है आपको मेदान में ओपेनली आना चाहिये था, आपको इन्क्वायरी बिठानी चाहिये थी। अब मैं थोड़ा सा कमेटी के मुताल्लिक कहना चाहता हूँ कि सन् ३८ में जो कमेटी बिठाई गई थी उसको बैठे १२ साल हो गये लेकिन अभी हाल ही में राधा कृष्णन कमेटी बंठी थी और उसकी सिफारिशें मौजूद हैं। वह एक एक्सपर्ट कमेटी थी, उसने पूरी तरह से यूनिवर्सिटी की जांच की थी लेकिन उस पर कुछ नहीं किया गया। जहाँ तक अटोनामी की बात कही गई तो मैं यह समझता हूँ कि इसका मतलब जैसा सरकार चाहती है वैसा लगा लेती है। इसी तरह से डेमोक्रेसी क माने आप जैसा चाहते हैं वैसा लगा लेते हैं। मैं तो यह कहता हूँ कि यह ठीक है कि बेजा ऐडमिनिस्ट्रेशन को नहीं चलने देना चाहिये लेकिन मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट इस बात को महसूस करेगी कि जहाँ तक यूनिवर्सिटी का ताल्लुक है वह एक अटोनामस बाडी है। और कहीं भी ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सिटी अफेयर्स से गवर्नमेंट इन्टरफियर करती हो। इन चंद अफाज के साथ मिनिस्टर साहब की खिदमत में यह अर्ज करूँगा कि मेहरबानी करके आप एक तरफ की बातें सुन कर कुछ न कीजिये बल्कि आप दूसरे फरीकें को भी जवाब देने का मौका दीजिये और जो स्पेसिफिक इन्स्ट्रक्शंस आप ने जाहिर किये हैं, जो मौजूदा तरीका बोर्ड आफ इक्जामिनर्स का है, किस तरीके से नम्बर बढ़ाये गये मुझे नहीं मालूम है, यह तो आप यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से पूछ सकते हैं। जितने मामले हैं इक्जीक्यूटिव कौंसिल में आते हैं, वाइस चांसलर को मालूम होना चाहिये। अगर वाइस चांसलर भी उसी पार्टी के थे तो उन के खिलाफ आपने क्या एक्शन लिया। मैं वाइस चांसलर का टर्म बढ़ाने के खिलाफ नहीं हूँ, मैं वाइस चांसलर की जात पर हमला नहीं करता, ए० बी० सी० कोई भी वाइस चांसलर हो। मैं सिर्फ चाहता यह हूँ कि नार्मल कोर्स इस्तेमाल किया जाये। मेरा ह्याल है कि रिसीवर मुकर्रर करने का इरादा था और चांसलर ने भी कहा था, मगर हमने उसको पसंद नहीं किया।

श्री हर गोविन्द सिंह—आपने क्या कहा, क्या आप से चांसलर ने निर्मिबल मुकदमा करने को कहा था ।

डाक्टर ब्रजेन्द्र स्वरूप—मुझे नहीं कहा । उनसे कहा जिसकी तरफ गानिवन इशारा आजाद साहब ने किया है ।

चेयरमैन—You should not mention the chancellor.

डाक्टर ब्रजेन्द्र स्वरूप—I withdraw my words.

*श्री प्रभु नारायण सिंह (स्थानीय संस्थायें निर्वाचित क्षेत्र)—माननीय अध्यक्ष महोदय, आगरा यूनिवर्सिटी बिल जो इस सदन के सामने प्रस्तुत है वह एक आर्डिनंस के बराबर हमारे सामने मौजूद है । इस बिल में उद्देश्य और कारणों को बतलाने हुये यह कहा गया है कि इस ऐक्ट को बनाने की जरूरत इसलिये पड़ी कि आगरा यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन में पिछले कई बरसों से खराबी दिखलाई पड़ रही है । एडमिनिस्ट्रेशन की कठिनाई पर बोलते हुये मिनिस्टर साहब ने यह जाहिर किया कि उस कठिनाई को समझने हुये भी २६ तारीख को आर्डिनंस के रूप में इलेक्शन को रोकने की जरूरत पड़ी । पहली गिकायत तो हमारी सरकार से बराबर यह रही है और आज भी यह गिकायत है कि सरकार अक्सर सोया करती है । उसको जब इलहाम होता है तब किसी कार्य को करने की मोचनी है और ऐसा ही इस बिल के सिलसिले में मालूम होता है । जहां तक आर्डिनंस का सवाल है अध्यक्ष महोदय, आर्डिनंस उस समय जारी किया जाना चाहिये जब किसी कम्प्युनिटी का जीवन खतरे में हो और कम्प्युनिटी को चलाने में कठिनाई हो । जिस तरह में आर्डिनंस का इस्तेमाल किया गया और आर्डिनंस के खिलाफ जो हमारी भावना थी उसको ध्यान में रखते हुये मैं समझता हूं कि आर्डिनंस बनाने का जो अधिकार है उसका इस्तेमाल किया गया है । अध्यक्ष महोदय डेमोक्रेटिक कनवेंशन चाहें किसी तरह से बने लेकिन इसकी जिम्मेदारी जो पार्टी पावर में होती है उसके ऊपर होती है । इस हालत में जब हम इस बात को देखते हैं कि आज जिन लोगों के हाथ में सरकार है जब कि दुनिया के सभी डेमोक्रेटिक कंट्री में आर्डिनंस का यह तरीका नहीं रहा है तो हमारे यहां जो डेमोक्रेती बनाने वाले लोग हैं, जिन्होंने कि हमेशा आर्डिनंस के खिलाफ लड़ाई की वे अपने मुक्त में इस ट्रेडिशन को कायम करना चाहते हैं । वे आर्डिनंस के जरिये से अपना काम चलाना चाहते हैं । मैं ऐसा सोचता हूं कि सरकारी पक्ष में दो ऐसे सदस्य थे जो आगरा यूनिवर्सिटी के संबंध में बहुत जानकारी रखते थे । उनके तजुर्बात वहां के संबंध में बहुत थे । उन्होंने उन बातों को मंत्री महोदय के सामने रखा होगा । आज ही नहीं रखा होगा पहले भी रखा होगा इसके बावजूद भी बिल कि शक्ल में यह बात न आकर आर्डिनंस की शक्ल में आयी जब एडजर्नमेंट मोशन आया तो उस समय हाउस सेशन में था । कांस्टीट्यूशन में लिखा है कि जब असेम्बली और काउंसिल सेशन में हो तो आर्डिनंस प्रोमलगेट नहीं किया जाता है लेकिन ऐसा किया गया । मैं तो समझता हूं कि कोई भी हाउस यदि उस समय सेशन में हो तो उस हालत में उस हाउस का कन्फीडेंस आर्डिनंस जारी करने के संबंध में लेना चाहिये था ।

श्री हर गोविन्द सिंह—आर्डिनंस पहली तारीख को ईश्वर हुआ और आप तीन तारीख को आये ।

श्री प्रभु नारायण सिंह—आर्डिनंस २६ तारीख को जारी किया गया । मुझे नहीं मालूम था लेकिन डाक्टर साहब की स्पीच को सुना तो मालूम हुआ कि आगरा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं इस हालत में अध्यक्ष महोदय, आज आर्डिनंस के

* सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया ।

[श्री प्रभु नारायण सिंह]

बाद यह बिल सदन के सामने आया और जो तकरीर माननीय मंत्री जी की हुई उसको सुनने के बाद यह मालूम हुआ कि मंत्री महोदय के पास रिपोर्ट आयी होगी और कोई सूचना होगी जिसके आधार पर उन्होंने यह बात रखी है। यदि वे बातें सही हैं तो जरूर तकलीफ की बात है। इस सिलसिले में जो बिल सदन के सामने आया है उसको पहले ही आना चाहिये था। जहां तक बिल का सवाल है और उसकी स्प्रिट का सवाल है, उससे हमारा विरोध नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ जो स्प्रिट मंत्री महोदय ने दिखाई है या सरकार ने प्रदर्शित की है अगर यही स्प्रिट कायम रखी जाय तो मैं समझता हूं कि जो आज हमें आंसू बहाने पड़ रहे हैं वे नहीं बहाने पड़ते। आज जब जनता आवाज लगाती है किसी के खिलाफ कि पार्टी के अन्दर किस तरह से टिकट दिया जाता है, किस तरह से पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज और डिप्टी मिनिस्टर्स के खिलाफ शिकायत होती है लेकिन इन सब बातों के बावजूद उनको मिनिस्टर्स बनाया जा रहा है। ऐसी हालत में यदि उस स्प्रिट का ध्यान रखा जाय तो हम इस बात का स्वागत करेंगे कि कम से कम आजादी मिलने के ५ वर्ष बाद नई दिशा में चलने की कोशिश हो रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो बिल हमारे सामने है और जो स्प्रिट माननीय मंत्री जी ने दिखाई है उसका अपनी सरकार से हर क्षेत्र में पालन कराने की कोशिश करेंगे।

श्री ज्योति प्रसाद गुप्त (स्थानीय संस्थाएँ निर्वाचन क्षेत्र)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो विधेयक इस समय हमारे सामने उपस्थित है उसकी आवश्यकता के संबंध में माननीय मंत्री की स्पीच के बाद कुछ और कहने की जरूरत नहीं है। जिस रिपोर्ट का हवाला देकर आगरा यूनिवर्सिटी के संबंध में जिन वाक्यात का उन्होंने इजहार किया है उसके बाद मेरे लिये जरूरी नहीं कि मैं उसके संबंध में कुछ कहूं। जो सज्जन अभी तक बोले हैं उन सब ने ही स्वीकार किया है कि आगरा यूनिवर्सिटी में बुराईयां हैं और उनको दूर करना जरूरी है। मुझे पूर्व वक्ता ने कहा है कि जैसी खराबियां और जगह हैं उसी तरह की आगरा यूनिवर्सिटी में हैं और उसके लिये जो स्टेप गवर्नमेंट ले रही है वह लेना जरूरी है। मुझे तो विशेषकर डाक्टर व्रजेन्द्र स्वरूप ने जो कानूनी आपत्ति उठाई है उसके संबंध में कुछ कहना है। सबसे पहले तो उन्होंने यह फरमाया कि यह आर्डिनेंस अनवारेन्टेड और अनप्रिंसीडेन्टेड है। डाक्टर साहब बहुत ही अच्छे लॉय्यर हैं और हम उनकी कद्र करते हैं लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि जिन शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया है वह किस तरह से मुनासिब कहे जा सकते हैं। आर्डिनेंस जारी करने के लिये जो शर्त रखी गई है उन शर्तों के अनुसार यह तो कहा जा सकता है कि वह समयानुकूल नहीं है अर्थात् अनअपारचून है लेकिन यह नहीं कहा जा सकता है कि अनवारेन्टेड और अनप्रिंसीडेन्टेड हैं। इमर्जेंसी की देखते हुए मिनिस्टर्स की सलाह से गवर्नर आर्डिनेंस जारी करती है। यह तो कहा जा सकता है कि वह इनएप्रोप्रियेट है अर्थात् जो राय इसके संबंध में हुई वह ठीक नहीं है लेकिन इसको अनवारेन्टेड कहना ठीक नहीं है और अनप्रिंसीडेन्टेड भी नहीं कहा जा सकता है। अगर इमर्जेंसी है तो फिर यह जायज ही कहा जायगा। हां यह हो सकता है कि शायद डाक्टर साहब का यह मंशा रहा हो कि यह आर्डिनेंस एजुकेशन डिपार्टमेंट से संबंध में रखता है इसलिये अनप्रिंसीडेन्टेड है। जहां तक मुझे मालूम है अभी तक कोई आर्डिनेंस एजुकेशन के संबंध में जारी नहीं हुआ है लेकिन उसके माने यह नहीं है कि अगर आज तक मौका नहीं आया है तो आवश्यकता होने पर भी आर्डिनेंस जारी नहीं किये जावें। आज तक कोई आवश्यकता नहीं थी इसलिये वह नहीं किया गया और आज जरूरत पड़ी तो आर्डिनेंस निकाला गया तो वह अनवारेन्टेड और अनप्रिंसीडेन्टेड नहीं कहा जा सकता। आर्डिनेंस के लिये जो जरूरत है वह यह है कि इमर्जेंसी हो, लेजिस्लेचर का सेशन न हो और अगर गवर्नमेंट यह समझती है कि ऐसी कोई इमर्जेंसी है अर्थात् किसी काम की निहायत जरूरत है तो आर्डिनेंस निकाला ही जा सकता है। मेरी समझ में नहीं आता कि आर्डिनेंस के शब्द को क्यों इतना बुरा समझा जाता है, आर्डिनेंस तो उस स्थिति में लगाया जाता है जब लेजिस्लेचर

का सेशन न हो और गवर्नर को सेंटिसफैक्शन हो कि किसी काम को करने की तुरन्त ही जरूरत है। इसको इन शब्दों में कहा गया है।

“Whereas the Governor is satisfied that circumstances exist making it necessary to promulgate the Agra University Ordinance for purposes as hereinafter appearing.” जब ऐसी स्थिति उपस्थित हो कि लेजिस्लेचर का सेशन न हो और गवर्नर यह निश्चित करे कि सरकारमस्टासेज ऐसे हैं कि आर्डिनेंस निकाला जाये तो यह निकाला जा सकता है। इसमें कोई ऐतराज की बात नहीं है। यह कहना कि यह अनवारेटेड है गलत चीज है। यह कहा गया है कि यह मौका नहीं था कि आर्डिनेंस निकाला जाये तो मिनिस्टर साहब ने साफ तौर से बतलाया है कि जब मालूम हुआ कि ५ नवम्बर को मीटिंग हो रही है जिसमें कि चुनाव होने वाला था तो इसके सिवाय क्या चारा था। क्या हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते और जब अर्मेंडिंग बिल पास होता तब उसके ऊपर कुछ कार्यवाही करते। गवर्नमेंट ने यह मुनासिब समझा कि इलेक्शन रोक दिया जाये और तब अर्मेंडिंग बिल लाया जावे। इसके अन्दर कौन सा ऐसी चीज है जो आव्रजेक्शनबुल है। कहा जाता है कि आर्डिनेम्सेज जारी करना अनडेमाक्रेटिक है। डेमाक्रेनी के अन्दर यह चीज साफ तौर से आजाती है कि जरूरत के लिहाज से अगर लेजिस्लेचर का सेशन न हो रहा हो तो आर्डिनेंस लागू किया जा सकता है। अगर गवर्नमेंट इनको न करती तो वह अपनी ड्यूटी को अन्जाम न देती अपने फरायज को ठीक प्रकार से अन्जाम न देती। अगर गवर्नमेंट ने आर्डिनेंस जारी न किया होता और वाद को कार्यवाही करती तो यह ऐतराज किया जाता कि गवर्नमेंट ने अपने फर्ज को अन्जाम ठीक से नहीं दिया है। अगर इलेक्शन होने के बाद कोई ऐक्शन लिया जाता तो यह ऐतराज किया जाता कि पहिले से ऐक्शन क्यों नहीं लिया गया। ऐतराज करने वाले तो हर तरह से ऐतराज करते हैं। तो इसलिये गवर्नमेंट ने अपने ह्दयाल के वमुजिब जो चीज ठीक समझी उसके लिये उन्होंने आर्डिनेन्स निकालने का फैसला किया। गवर्नर साहब हमारे एक बहुत ही माने हुये वकील हैं और उसमें यह भी लिखा हुआ है कि गवर्नर इससे सेंटिसफाइड है।

चेयरमैन—गवर्नर पर यहां डिस्कशन नहीं होता है।

श्री ज्योति प्रसाद गुप्त—जहां तक इस आर्डिनेंस का ताल्लुक है वह अनवारेटेड नहीं कहा जा सकता और न अनडेमाक्रेटिक ही कहा जा सकता है। ऐतराज का जहां तक सबाल है वह तो हर जगह उठ सकता है।

दूसरी बात जो मेरे काबिल दोस्त डाक्टर ब्रजेन्द्र स्वरूप ने कही वह यह कही कि इस स्टेट लेजिस्लेचर को यह अल्लियार नहीं है कि वह आगरा यूनीवर्सिटी ऐक्ट के अन्दर कोई संशोधन करने के लिये कानूनी कार्यवाही कर सके। उसके लिये उन्होंने यह आग्रहमेंट दिया है कि क्योंकि आगरा यूनीवर्सिटी के अन्दर इस स्टेट के अलावा और भी जगह के कालेजेंज शामिल हैं इसलिये कोई टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन इस लेजिस्लेचर को नहीं है कि वह इस तरह का कानून बना सके। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ जब मैंने उनसे यह बात सुनी। मैंने आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट को शुरू से आखिर तक पढ़ा इस गरज के लिये क्योंकि पहले भी इस तरह का एक आर्टिकल पेपर में निकला है। मुझे इस ऐक्ट के अन्दर एक भी ऐसा सेक्शन नहीं मिला जिसमें टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन का तज्जकिरा हो। किसी भी सेक्शन में किसी दूसरी स्टेट का जिक्र नहीं है। सिर्फ शुरू में जब यह ऐक्ट सन् १९२६ में बना था जो उसका प्रिम्बुल है उसमें तथा आव्रजेक्ट और रीजन्स में खासतौर से कहा गया है कि यह ऐक्ट इसलिये बनाया जा रहा है कि चूंकि इला-हाबाद यूनीवर्सिटी पर काफी बोझ है इसलिये उसको हल्का करना। उसमें कहा गया है कि इलाहाबाद तो रेजीडेन्शियल यूनिवर्सिटी है इसलिये यह आगरा यूनीवर्सिटी रेजीडेन्शियल

[श्री ज्योति प्रसाद गुप्त]

नहीं होगी और उसके साथ असोशियेटेड कालेजेज होंगे। उनको लेकर यह यूनीवर्सिटी बनायी जा रही है। चुनावों साफ़ तौर से लिखा है।

“Its object was to set the authority of the Allahabad University free to act as a unitary, teaching and residential University by releasing it of the responsibility of controlling the quality and character of the teaching given in to name by the associated colleges and placing such a responsibility upon the affiliated University at Agra.”

सब कानूनों के अन्दर टेरीटोरियल जूरिसडिक्शन निर्धारित होता है। उसमें लिखा हुआ है “The Act shall apply to the whole of the United Provinces or Uttar Pradesh” अथवा जिस भाग पर उस लागू करना हो वह लिखा होता है। लेकिन इस आगरा यूनीवर्सिटी ऐक्ट के अन्दर कोई टेरीटोरियल जूरिसडिक्शन लिखा नहीं है। हाँ यह है कि जो असोशियेटेड कालेजेज हैं उनका एफिलियेशन इस यूनीवर्सिटी के साथ होगा। आप शुरु से आखिर तक ऐक्ट को पढ़ जाइये किसी भी जगह पर आप को राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिन्ध्य प्रदेश और भूपाल जहाँ के कालेज उसके साथ असोशियेटेड हैं कहीं भी उनका नाम नहीं मिलेगा कोई राइट किसी गवर्नमेंट को इस ऐक्ट के अन्दर किसी नामिनेशन या रिप्रेजेन्टेशन का नहीं दिया गया है। केवल एक जगह पर एज मैनेजर आफ इन्स्टीट्यूशन के रूप में यह अधिकार दिया हुआ है। ऐसी सूरत में यह कहना कि इस लेजिस्लेचर को अख्तियार नहीं है कि वह इसमें अमैन्डमेंट कर सके, मैं ठीक नहीं समझता हूँ। जिस कौंसिल या लेजिस्लेचर ने इस को बनाया है वही इसके अन्दर तरमीम कर सकती है। किसी दूसरी स्टेट या लेजिस्लेचर को उससे कोई संबंध नहीं है। यह आगरा यूनीवर्सिटी ऐक्ट सन् १९२६ ई० में पास हुआ था। इसको बने हुये काफ़ी अर्सा हो चुका है। इसके बाद इसमें सन् ३३, ३६, ४६ और दो अमैन्डमेंट सन् ४७ में हुये थे। लेकिन इस तरह का कोई ऐतराज आज तक किसी ने नहीं किया और न किसी को कोई ऐतराज करने का मौक़ा ही था। यह चीज़ साफ़ है कि जिस स्टेट ने या जिस लेजिस्लेचर ने कानून बनाया है वही उसमें तरमीम भी कर सकती है। इस पर तो कोई ऐतराज ही नहीं हो सकता है। डाक्टर ब्रजेन्द्र स्वरूप ने संविधान की धारा २४५ को भी पढ़ कर सुनाया मैं समझता हूँ कि उस क्लॉज का कोई ताल्लुक नहीं है। यहाँ पर लिस्ट दो जो हैं उस में तो कुछ दिया हुआ ही नहीं है कि इस क्रिस्म का सवाल उठ सके। मैं समझता हूँ कि उनको इस क्रिस्म का कोई हवाला देने की ज़रूरत ही नहीं थी। अमैन्डमेंट के संबंध में जो कुछ कहा गया उसके लिये मैं कह चुका हूँ कि यह शब्द किसी तरह से भी ऐप्लायी नहीं करते हैं। आगरा यूनीवर्सिटी ऐक्ट में कहीं पर भी किसी स्टेट को किसी क्रिस्म का कोई राइट नहीं दिया गया है। हाँ अगर उत्तर प्रदेश सरकार चाहे तो यूनीवर्सिटी से इन्सप्लेनेशन मांग सकती है। उनको उचित हिदायत दे सकती है ऐसा प्रावधान ऐक्ट में है जो किसी दूसरी स्टेट को नहीं दिया गया है। आर्डिनेन्स का जहाँ तक ताल्लुक है उसके संबंध में कोई बहस करना मैं समझता हूँ केवल वक्त ख़राब करना है। मेरा ख़्याल है कि आर्डिनेन्स के बारे में हमारे काफ़ी भाई बोल चुके हैं अब उसमें ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का स्वागत करता हूँ।

*श्री कन्हैया लाल गुप्त (अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र)—माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत बिल के बारे में आज सुबह से काफ़ी इस सदन के सामने कहा जा चुका है और इसके औचित्य और अनौचित्य के बारे में भी काफ़ी प्रकाश डाला जा चुका है। मुझे इस संबंध में निवेदन करते हुये पहली बात जो कहनी है वह यह है कि आज मुझे बहुत खुशी है माननीय मंत्री जी के उस भाषण पर, जो कि इस सदन के अन्दर आज सुनने को मिला है। पिछले महीनों में बहुत दफ़ा शिक्षा के बारे में प्रश्नों के उत्तर में या अन्य प्रकार से हम माननीय मंत्री जी के मुख से

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

बहुत सी बातें शिक्षा प्रणाली के बारे में सुनते रहे हैं और मुझे यह मंजूर करना पड़ता है कि अधिकतर उनकी ओर से सरकार की शिक्षा प्रणाली के बारे में जो इशारा हमें मिला है वह निराशाजनक ही रहा है। परन्तु आज उनका जो भाषण हमें सुनने को मिला है, मैं कह सकता हूँ कि वह बहुत ही प्रशंसनीय और अत्यन्त ही सराहनीय है। कोई भी अध्यापक इस भाषण को सुनने के बाद आज खुश हुये बिना नहीं रह सकता है और उनकी सराहना किये बगैर नहीं रह सकता है। हालाँकि उसकी खुशी उस चेतावनी से खत्म हो जानी चाहिये जो कि अभी श्री गोविन्द सहाय जी ने दी है। उन्होंने बतलाया कि इस सदन के अन्दर पिछले वर्षों में जो भी मंत्री महोदय आते रहे हैं उन्होंने पहले आते ही बड़ी ही लगन के साथ सोचा और यह दिखलाया है कि वह मुहकम के अन्दर परिवर्तन करेंगे और उसमें तरक्की करके उसे आगे ही बढ़ाने की चेष्टा करेंगे। मगर इन्हीं कारणों से वह अपने मनसूबों में कामयाब नहीं हो पाये हैं परन्तु फिर भी आज शिक्षा मंत्री के भाषण के अन्दर, स्पष्ट रूप से उनके शब्दों के माफ़ि उनकी आत्मा की झलक दिखलाई पड़ती है और उसको देखने के बाद कोई यह नहीं कह सकता है। कोई इस बात को मानने के लिये तैयार नहीं होगा कि शिक्षा को पूरी दूरी तक ले जाने के लिये कांशिश नहीं की जा रही है, यह तो उनके भाषण से स्पष्टतः झलकता है और इन बातों से हमें भरोसा है कि जो कुछ भी बुराइयाँ हैं उनको निकाल कर के फेंकेंगे तो यत्न कम मार्क की बात नहीं है। इस भाषण के लिये मैं इन्हें हार्दिक धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ।

अब माननीय अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक इस बिल का संबंध है मैं समझता हूँ कि इस पर विचार करने के लिये दो ही तरीके हो सकते हैं। एक तो यह है कि इस बिल का उद्देश्य क्या है और कहां तक वह उचित है और जो तरीका उसको प्राप्त करने का सोचा जा रहा है वह कहां तक ठीक है और आया वह इन चीजों से प्राप्त भी हो सकेंगे या नहीं। दूसरे जहां तक उसकी आवश्यकता का सवाल है तो माननीय मंत्री जी ने साफ़-साफ़ अपने भाषण में बतला दिया है कि आगरा यूनीवर्सिटी की आज क्या हालत है और किस तरह से वह और यूनीवर्सिटियों के नाम को कलंकित कर रहा है। किस तरह से वहां के अध्यापक और दूसरे-दूसरे लोगों को यह दशा हो गयी है कि आज वह अपने वर्ग और अपने पद के बारे में शलतक़ुमी नंदा कर रहे हैं। इन बातों को मैं दोहराना नहीं चाहता। उसके लिये स्पष्ट उदाहरण देते हुये साबित कर दिया है। मैं भी उस विश्वविद्यालय का १५ वर्ष पहले एक विद्यार्थी था। जिस समय मैंने यूनीवर्सिटी छोड़ी उस समय वहां बुराईयाँ इस हद तक नहीं थी परन्तु बहुत हल्के रूप में यह चीज उस वर्ष शुरू हो चुकी थी। पहले मैं इसलिये कह रहा हूँ कि उस समय भी पेपर आउट होने की सम्भावना शुरू होने लगी थी लेकिन आज उसकी वह हालत हो गयी है कि वाकई वह एक पतनावस्था को पहुँच रहा है। डाक्टर ब्रजेश्वर साहब यहां पर इस समय मौजूद नहीं हैं। उन्होंने अपने भाषण में यह फरमाया था कि बहुत सी बातें जो माननीय मंत्री महोदय की तरफ से कही गयी हैं, वे अतिरंजित हैं और आज़ाद साहब ने जो बातें कही हैं वे सच्चाई के माने पर ठीक-ठीक नहीं बैठेंगी। मैं आज़ाद साहब की बात के बारे में अदब से अर्ज करना चाहता हूँ कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है और सुना है। उनके आधार पर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वे बातें अतिरंजित हार्गिज नहीं हैं और आज़ाद साहब की इस बात पर कि कोई लिस्ट निकलती है और उसके आधार पर कार्य होता है और जिसको डाक्टर साहब ने कहा था कि ग़लत है, तो मैं इस बात को जानता हूँ क्योंकि मेरे कई साथी डिग्री कालेज में प्रिन्सिपल हैं और फ़ैलटोच में भी हैं, और उन्हीं के इन्फ़ार्मेशन पर मैं कह सकता हूँ कि ये बातें ठीक हैं। यह भी ठीक है कि इस तरह से लिस्ट बनती है और उन्हीं के आधार पर चुनाव होता है। इस तरह के दो एक अनुभव मैं स्वयं रखता हूँ और अध्यक्ष महोदय, आप की अनुमति से सदन से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि आजकल यूनीवर्सिटी में पी० एच० डी० की डिग्रियाँ रिश्त के आधार पर मिलती हैं और आप समझ सकते हैं कि जिस यूनीवर्सिटी में पी० एच० डी० की डिग्री रिश्त के आधार पर मिलती हो, वहां की यूनीवर्सिटी सेक्या उम्मीद की जा सकती है। मैं खुद एक बात बतलाता हूँ जो कि मेरे सामने घटी।

[श्री कन्हैया लाल गुप्त]

दस साल का अर्सा हुआ मैं भी कोई परीक्षा देने के लिये उस यूनीवर्सिटी में गया था, तो डिग्री कालेज के एक प्रोफेसर ने अपने किसी विद्यार्थी को अपना पर्चा आउट कर रखा था और दूसरे प्रोफेसर ने दूसरे सब्जेक्ट का पर्चा दूसरे विद्यार्थी को आउट कर रखा था। तो इस तरह से दोनों प्रोफेसरों ने दोनों को अलग-अलग पूरे के पूरे पर्चे आउट कर रखे थे और उन दोनों ने विद्यार्थियों से कह दिया था कि वे किसी दूसरे कालेज के विद्यार्थियों को ये पर्चे न बतलायें। वे दोनों एक दूसरे से पूरा पर्चा हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। मैं भी वहीं एक कालेज के होस्टल में ठहरा था और मैंने देखा कि एक कालेज का विद्यार्थी उन दोनों से यह जानने के लिये कि क्या पर्चा है, बिल्कुल भिखारी के वेश में वहां वेश बदल कर आया। इस तरह से वहां के विद्यार्थी और प्रोफेसर करते थे, मैं उनका नाम यहां नहीं लूंगा लेकिन यह चीज मैंने खुद अपनी आंखों से देखी है। अध्यक्ष महोदय, मैं तो एक अध्यापक हूं और अध्यापकों में जब आज ऐसी बात होती है तो मेरा सिर शर्म से झुक जाता है। माननीय डाक्टर साहब ने इसके खिलाफ जो बातें कही हैं कि यूनिवर्सिटी की हालत आज उस हद तक खराब नहीं हुई है जिस हद तक कि माननीय मंत्री महोदय ने अपन भाषण में कहा है, मैं उनसे सहमत नहीं हूं। उन्होंने यह भी कहा है कि जरूरत इस बात की थी कि गवर्नमेंट इसके लिये पहले कोई इन्क्वायरी कराती और इस तरह से इन्क्वायरी कराने के बाद सरकार के लिये खुला रास्ता था कि वह इस पर ऐसा क्रदम उठाती। मगर मैं उनसे यह कहूंगा कि आज जो स्थिति है वह इतनी स्पष्ट है और जितने उदाहरण माननीय मंत्री महोदय ने दिये हैं और उसके लिये सरकार ने जो भी क्रदम उठाया है वह उचित है और उसके लिये कोई भी इन्क्वायरी इस स्टेज पर की जाय, यह ठीक बात नहीं जंचती है। इस हद तक उसकी बुरी हालत हो गयी है कि वह सड़ रहा है और उसमें से बदबू आ रही है। तो इन्क्वायरी कमेटी के लिये यह कोई मौका नहीं था। मिनिस्टर साहब ने जो १४ हजार रुपये की बात कही वे एक एक्जामिनेर को दिये गये थे, तो मेरे लिये उसको गलत समझने की कोई सम्भावना नहीं है और मिनिस्टर साहब ने ठीक ही कहा होगा। सन् ५१-५२ में उनके बजट में ४२ हजार रुपये की रकम सिर्फ टी० ए० और डी० ए० में हो खर्च कर दी गयी है और वहां सिर्फ इसके लिये इतना रुपया खर्च किया जाता है। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस समय इस बात को न लेकर यह कहूंगा कि स्थिति स्पष्ट है। अब सवाल यह है कि जो तरीका सरकार ने अख्तियार किया है उससे वह पूरा होगा या नहीं। मैं समझता हूं कि इस प्रश्न का उत्तर देना मुश्किल है, यह निर्भर करेगा उस बिल पर जो बाद में सरकार लायेगी। मैं समझता हूं कि सरकार को बहुत होशियारी के साथ उस समय काम करना होगा। आटोनामी की जहां तक बात है मैं तो कहूंगा कि वह दिन अफसोस का दिन होगा जब यूनीवर्सिटी सरकार के इशारे पर चलगी। लेकिन मैं यह कहता हूं कि जिस समय वह बिल बने सरकार इस बात का ध्यान रखे कि आटोनामी खतरे में न पड़ जाय और मंत्री जी इस बात का ध्यान रखें कि कंट्री का कैरेक्टर गिर गया है और वीकनेसज बहुत है और ऐसा चेक सरकार रखेगी जिससे ऐसी बात न हो जाय। जिससे आज आगरा यूनीवर्सिटी कलंकित हो रही है, वह बाकी रहे। साथ ही साथ मैं यह कहूंगा कि सरकार के सामने सन् ३८ की कमेटी, जो आचार्य नरेन्द्र देव जी की अध्यक्षता में बनाई गई थी और राधा कृष्णन कमीशन की रिपोर्ट है वह मौजूद है। जब बिल बने तो उसमें इन सब बातों को ध्यान में रखा जायेगा।

एक बात और कही गयी कि आर्डिनेन्स जारी किया गया है वह सही है या गलत है, मैं इस पर कह कर के कुछ ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं। लेकिन मैंने जब इसको देखा और आगरा यूनीवर्सिटी ऐक्ट को देखा और अखबार को भी पढ़ा तो मुझे भी ऐसा प्रतीत होने लगा कि शायद इसकी लोगल पोजीशन कुछ ऐसी हो गयी है जिससे कोई रिवीजन उठ सकता है। लेकिन सरकार के पास लोगल एडवाइजर्स हैं और मुझे ला का ज्ञान नहीं है इसलिये मैं उन पर छोड़ता हूं कि वे देखेंगे कि लोगल पोजीशन क्या है। लेकिन मैं तो यह कहूंगा कि मनुष्य को हर समय लोगल रास्ता ही न देखना चाहिये जिससे भला होता हो उस मंशा को

भी सामने रखना चाहिये। यह एक सिद्धान्त है मनुष्य ला को तब देखता है जब वह अपने को धर्म और नैतिकता में पूरा नहीं पाता है। मैंने तो उसकी लॉगल पोझीशन नहीं देवी बल्कि उसकी मंशा क्या है यह देखा है और जब मैंने माननीय मंत्री जो की स्पोच सुनी कि क्यों आर्डिनेन्स निकाला गया तो उस समय मैंने यह सोचा कि जिस मंशा से यह किया गया है वह ठीक किया गया है। हो सकता है कि ऐसा करने से सरकार के ऊपर कोई बदनामी हो और जब मैंने मंत्री जी से सुना कि अगर ऐसा न किया जाय तो यह नतीजा निकलता। इसलिये जो किया गया उसमें जनता का हित था, शिक्षा का हित था, इसलिये ऐसा किया गया। लॉगैलिटी की बात ज्यादा यहां न कह कर मैं यह कहूंगा कि भविष्य में हमें देखना है और सरकार इस की तरफ ध्यान रखे। साथ ही साथ आर्टोनामी की जहां तक हो सके रिस्पेक्ट करने की कोशिश करें।

इसके बाद अध्यक्ष महोदय, एक बात जो कि मुझे आप की मार्फत सरकार से कहना है और जिसको मैं समझता हूं कि वह इस से ज्यादा महत्वपूर्ण है। बात यह है कि अब वक्त आ गया है जब कि सरकार को साफ तौर से सहसूस करना चाहिये कि शिक्षा को जो रोग है वह कितना व्यापक है और किस गहराई पर उसकी जड़ें पहुंच चुकी हैं। मंत्री जो ने आज तक जब बोर्ड के ऊपर अपनी अंगुली रखी और कुछ इलाहाबाद यूनीवर्सिटी और बोर्ड के बाबत उन्होंने कहा, उसमें मुझे कोई बेहद खुशी हुई। कुछ दिन पहले मैंने बातचीत के सिलसिले में एक दिन बोर्ड का जिक्र किया था तो मुझे सुनने की मिला था कि बोर्ड स्टैंचुअरो वाडो है उसके संबंध में हम कुछ ज्यादा करना पसन्द नहीं करते। परन्तु मुझे खुशी हुई जब कि आज मंत्री जी ने कहा कि चाहे वह बोर्ड हो, इलाहाबाद यूनीवर्सिटी हो या कोई शिक्षा संस्था हो अगर उसके अन्दर बुराई घुस चुकी है तो हम उस बुराई को दूर करने के लिये हर उपाय करेंगे। लेकिन साथ ही साथ मुझे डर है कि माननीय मंत्री जी जो नए ही इस पोर्टफोलियो में आयें हैं शायद शिक्षा का बुराईयों को उस हद तक नहीं पहचान पायें हैं जो उसके अस्तित्व में आ गई हैं। खास तौर से मैं अपने सवाल के जवाब में जो कल दिये गये थे उनको तरफ ध्यान दिलाऊंगा। मैंने सवाल किया था कि पिछले वर्षों में कितने इक्जामिनर्स ऐसे हुये हैं जो अनक्वालोफाइड थे और जिन्होंने ऐप्लीकेशन तक नहीं दी थी।

चेयरमैन—बोर्ड की बात फिर कहियेगा।

श्री कन्हैया लाल गुप्त—अच्छा अध्यक्ष महोदय, तो जो जवाब उन्होंने दिया था उससे मुझे लगा कि अब तक बोर्ड की बीमारी के बारे में उनको जानकारी नहीं हो पाई है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वह भी इस फोर्डे स कम सड़ा हुआ नहीं है और शायद उसे इसमें भी बड़े नस्तर को जरूरत है। उन्हें एक नस्तर उसी समय लगा देना चाहिय था लेकिन उस समय शायद वह चूक गये। खैर आगे वह इसको तरफ ध्यान देने की कोशिश करेंगे ऐसी मुझे आशा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आप के द्वारा सरकार से यह कहूंगा कि शिक्षा का रोग इतना जबरदस्त है कि इस तरह के थोड़े लगाने से इसका इलाज नहीं हो सकता। जब प्राय-रिटरी का सवाल आता है तो एज्युकेशन को बहुत पीछे ढकेल दिया जाता है।

श्री हर गोविन्द सिंह—बहुत पीछे नहीं ढकेला जाता।

श्री कन्हैया लाल गुप्त—आप अगर बहुत पीछे नहीं ढकलते तो मुझे बहुत खुशी है। लेकिन अब तक बजट के समय यही देखा जाता रहा है कि फूड प्रोडक्शन के लिये गुंजाइश है, इर्रिगेशन के लिये गुंजाइश है लेकिन एज्युकेशन का नम्बर बहुत बाद में आता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप इन चीजों को करें। लेकिन इन्सान जो है “मैन डज नाट लिव बाई ब्रेड एलोन” (man does not live by bread alone) मैन डज नाट लिव टु ईट (man does not live to eat)। जिस समय एज्युकेशन पहली या दूसरी प्रायोरिटी पायेगा उस समय इस प्रांत के निवासियों का चरित्र इतना गिर चुका होगा, उस समय आप देखेंगे कि हमने किस के खाने के लिये व्यवस्था की थी। मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि वह फूड पैदा करने को और ध्यान जरूर दें लेकिन साथ ही साथ शिक्षा को भी उचित स्थान दें।

चेयरमैन—मुझे सदन को यह खबर देना है कि आज कौंसिल को प्रोरोग (prorogue) किया जायगा इस लिये सदस्य इस बात का प्रयत्न करे कि पौने पांच बजे तक यह बिल पास हो जाय। मैं मामूली तौर से सदस्यों को इन्टरप्ट (interrupt) करना नहीं चाहता। लेकिन अब इसके बाद १५ मिनट से ज्यादा किसी सदस्य को समय न मिलेगा।

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बिल इस सदन के सामने प्रस्तुत है उस पर बहुत कुछ बाद विवाद हो चुका है। मेरे लिये सदन का समय अधिक लेना उपयुक्त नहीं है। आपने भिन्न-भिन्न सज्जनों से सुन लिया कि यूनिवर्सिटी के सुधार के लिये क्या करना आवश्यक है। सरकार का और हमारा क्या कर्तव्य है। मैं यूनिवर्सिटी का अध्यापक हूँ परन्तु आप समझते हैं कि कभी कभी परिस्थितियाँ मनुष्य को मजबूर कर देती हैं कि उसको अपनी संस्थाओं के विरुद्ध भी कुछ कहना पड़ता है। जो कुछ मैंने यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी के अध्यापकों के बारे में सुना उससे मेरा मस्तिष्क नीचा होता है, कोई ऐसा अध्यापक नहीं होगा जिसको इन बातों को सुन कर खेद न होगा। मुझे मंत्री जी के भाषण को सुन कर बहुत प्रसन्नता हुई, मंत्री महोदय ने कहा कि शिक्षा संस्थाओं और आर्डिनेंस में मेल नहीं खाता साधारणतया शिक्षा संस्थाओं के बारे में आर्डिनेंस जारी नहीं किये जाते परन्तु परिस्थिति कठिन है इसलिये आर्डिनेंस का उपयोग किया गया है। दूसरी बात यह है कि यूनिवर्सिटियों को बड़ा आश्वासन मिलेगा कि सरकार की मन्तव्य किसी प्रकार से उनकी स्वतंत्रता पर प्रहार करने की नहीं है। यूनिवर्सिटियों को माननीय मंत्री जी के भाषणों को सुन कर बड़ी शंका हुई थी और तरह-तरह के विचार हो रहे थे परन्तु मैं समझता हूँ कि आपने उस सभी विरोध को शांत कर दिया यह कहकर कि सरकार की इच्छा यूनिवर्सिटियों की स्वतंत्रता पर प्रहार करने की नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि मेरा संकल्प है कि शिक्षा संस्थाओं में जहाँ कहीं खराबी होगी उनको दूर करने में किसी प्रकार की कोताही नहीं करूँगा। आप नये शिक्षा मंत्री हैं। आप के मुख से यह बात सुनकर बहुत खुशी हुई। परमात्मा आप को साहस दे। आपको लड़ना पड़ेगा उन शक्तियों के साथ जिनको कि अंग्रेजी भाषा में वेस्टेड इन्टरेस्ट (vested interests) कहते हैं। पग-पग पर आप को कठिनाई उठानी पड़ेगी परन्तु हमें आशा है कि आप विचलित नहीं होंगे।

इस सदन में और बहुत से भाषण हुये। मुख्यतः दो पहलू हैं जिनपर गौर करना है। एक पहलू तो यह है कि आर्डिनेंस क्यों जारी किया गया, उसकी आवश्यकता थी या नहीं, वैधानिक दृष्टि से सरकार को आर्डिनेंस जारी करना चाहिये था या नहीं, कानूनी मिसाल बहुत सी दी गयी हैं जिनके विषय में मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा पहलू अष्टाचार का है। अष्टाचार के संबंध में माननीय मंत्री जी ने आचार्य नरेन्द्र देव कमेटी की रिपोर्ट पढ़कर बहुत कुछ सुनाया है जिसके दोहराने की आवश्यकता नहीं है। मैं यह प्रार्थना करूँगा कि सदन को विशेष ध्यान देकर देखना चाहिये कि इस वक्त यूनिवर्सिटियों की क्या हालत है। होमियोपैथिक औषधि देने से काम चलेगा कि नहीं। मेरी सम्मति में स्थिति ऐसी है कि जिसमें कड़वी दवा दिये बिना काम नहीं चलेगा और न किसी प्रकार का सुधार हो सकेगा।

मेरे मित्र श्री राजा राम जी और प्रभुनारायण सिंह ने और गुरु नारायण जी ने जो आपत्ति की है वह वैधानिक आपत्ति की है। आपने यह स्वीकार किया है कि यदि यूनिवर्सिटी में ऐसा अष्टाचार है तो इसको फौरन बन्द करना चाहिये और राजा राम जी ने तो यहां तक कहा कि सरकार पर भी उसका उत्तरदायित्व है। वैधानिक दृष्टि से मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है कि आर्डिनेंस और शिक्षा संस्थाओं में मेल नहीं खाता है लेकिन विशेष परिस्थितियों में हमको ऐसा करना पड़ा है। दूसरी बात आपने कही कि अभी तक खराबियाँ मौजूद हैं और वह दूर क्यों नहीं की गई, नरेन्द्र देव कमेटी की रिपोर्ट को प्रकाशित हुये बहुत समय व्यतीत हुआ। अब तक कार्यवाही क्यों नहीं हो सकी। हमारे भूतपूर्व शिक्षा मंत्री श्री सम्पूर्णानन्द जी ने बहुत प्रयत्न इस दिशा में किया था कि यूनिवर्सिटीज का

सुधार हो और उन्होंने कई बड़ी-बड़ी कमेटियाँ बनाई थीं। परन्तु एक-एक यूनिवर्सिटियों के मामलों में हस्तक्षेप करने को इच्छा न उनको थी और न सरकार को ही थी। यूनीवर्सिटियाँ विद्या के मंदिर में हैं। इनमें सरकार आवेश में कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझती है। सरकार ने इलाहबाद यूनिवर्सिटी के लिये भी एक कमेटी बनाई है। उस का काम बराबर जारी है और रिपोर्ट की प्रतीक्षा हो रही है यदि उसमें ऐसी ही खराबियाँ होंगी तो सर्वेज का चाक इस्तेमाल करना होगा। श्री गोविंद सहाय जी ने कहा कि एजुकेशन का स्ट्रक्चर अर्थात् रूप ही बदलना चाहिये। हमारे मंत्री जी एक कालिज में गये बहुत जोर शोर से दावत का प्रबंध हुआ और वहाँ के एक सज्जन ने कहा कि उनका कालेज प्रांत का सबसे बड़ा कालेज है। मंत्री महोदय ने दावत मिलने पर भी यही कहा कि आपका कालिज अनुशासन हीनता में भी सबसे बड़ा है। और यह भी कहा कि शिक्षा का सारा ढांचा बदलने की आवश्यकता है। तो काम उनका नहीं बना सारा खेल बिगड़ गया। डाक्टर ब्रजेन्द्र स्वरूप जी ने यह कहा है कि सरकार को नोटिस देना चाहिये था। सरकार इस मामले में बहुत तहकीकात कर चुकी है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि आगरा यूनिवर्सिटी से मेरा २५ वर्ष का संबंध है, मैं आगरा में पैदा हुआ, वहीं मैंने शिक्षा प्राप्त की और सात आठ वर्ष आगरा कालिज में अध्यापक भी रहा। मुझे भी विश्वास है की अब सुधार होना चाहिये। यह कोई नई बात नहीं है। सरकार बराबर उद्योग कर रही है। पहले नरेन्द्रदेव कमेटी नियुक्त हुई थी। उसके बाद विश्वविद्यालयों में प्रतिनिधियों की कमेटी बनी। तत्पश्चात् चांसलर महोदय की अध्यक्षता में एक वाइस चांसलरों की कमेटी नियुक्त हुई। इन सब ने विचार कर लिया है। सब इस नतीजे पर पहुँची है कि आमुली उपायों से काम न चलेगा।

विरोध इन सुझावों का कहीं से नहीं हुआ है। आगरा विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर महोदय ने कोई विजिप्ति नहीं निकाली है, न कार्यकारिणी का कोई विशेष अधिवेशन विरोध करने को बुलाया गया है। हमारे गण्यमान अध्यापकों ने भी इस नीति का विरोध नहीं किया है। केवल एक नगर से वकीलों ने कानूनी विवाद आरम्भ किया है।

अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि विश्वविद्यालयों पर हमारे देश का शासन निर्भर है। अंग्रेजी में कहा जाता है—“University is the microson of the state.” यूनीवर्सिटी के आदर्शों और विचारों की झलक शासन में आती है। इसलिये सरकार का कर्तव्य है कि वह इनके दोषों का निवारण करे और ऐसी नीति निर्धारित करे जिससे इनका सुचारु रूप से शासन हो। इसमें आपत्ति करना व्यर्थ है। मुझे पूर्ण आशा है कि विचारशील विद्याप्रेमी इस कार्य में हाथ बटावेंगे और सरकार के साथ सहयोग करेंगे।

मैं निवेदन करूँगा कि सदन इस विषय पर शान्तिपूर्वक विचार करे। इस बात की आवश्यकता है कि आगरा यूनीवर्सिटी अमेंडिंग बिल शीघ्र यहाँ पर आये। सरकार ने बड़े विचार के साथ यह काम किया है। अगर सरकार चाहती तो अपने बहुमत के जोर से इस छोटे से बिल को ५ मिनट में पास करवा लेती। परन्तु उसने ऐसा नहीं किया है। इससे कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हो रहा है केवल वाइस चांसलर का दर्म बढ़ा दिया गया है। इस चुनाव में बड़े दोष आ गये हैं। सर राधाकृष्णन् कमीशन ने लिखा है कि वाइस चांसलर का चुनाव एक prolonged intrigue for power हो गया है। उसने यह भी कहा है कि जो इस पद के लिये बहुत इच्छुक हो उसे कभी न बनना चाहिये। मैं आशा करता हूँ कि सदन मंत्री जी से सहमत होगा और उन्हें इस कार्य में अपना सहयोग प्रदान करेगा।

श्री हर गोविन्द सिंह—श्रीमान अध्यक्ष महोदय, मैं इस भवन का बड़ा आभारी हूँ कि उसने एक छोटे से विधेयक का स्वागत किया। जो थोड़ी बहुत बातें कही गईं वह केवल इस प्रश्न पर कि यह अधिनियम आगरा यूनीवर्सिटी अमेंडिंग बिल आज से बहुत पहिल आ जाना चाहिए था। इस सम्बन्ध में मैं थोड़ा इतिहास आपको बतला देना चाहता हूँ। सन् १९३८ में जैसा मैंने कहा था कि आगरा यूनीवर्सिटी कमेटी की

[श्री हर गोविन्द सिंह]

नियुक्ति हुई। उसके बाद सन् १९४१ में उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी। इसके बाद सन् ४२ आया तो उस समय के लिये भी यह तो नहीं कहा जा सकता कि सरकार ने रिपोर्ट को कार्यान्वित करने में कोई हिंसा हुआ किखाया। इसके बाद सन् ४६ का इलेक्शन आया। इसके बाद एक कमेटी नियुक्त की गई जो इस बात की जापबील करने लगी कि क्या क्या संशोधन करना चाहिये। उस बीस में गवर्नमेंट आफ इंडिया ने राधाकृष्णन् कमीशन की नियुक्ति की। उस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सन् ४९ में दी। तो अब इन आंकड़ों के होते हुए मैं पूछूँ कि क्या संसद में सरकार के ऊपर यह आरोप लगाया जा सकता है कि उसने जानबूझकर बेरी थी। जैसा अभी डाक्टर ईश्वरी प्रसाद ने कहा कि वह कोई ऐसा बिल नहीं था जिसकी जरूरी में पास कर दिया जाता। यदि आप इस रिपोर्ट को पढ़ें, समाचार-पत्रों में देखें, आज का जो समाचार-पत्र छारू है और अगर आप उनको पढ़ें तो आप देखेंगे कि विधिवत रूप में यह नहीं कहा जा सकता कि कौन सी नीति अपनायी गयी होगी। एक तरफ तो यह कहा जाता है कि हमारी यूनीवर्सिटियों की हालत इतनी खराब हो गयी है कि सरकार को अपने हाथ में ले लेना चाहिये। राधाकृष्णन् कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा है कि इसमें तो कोई अन्वेष्ट नहीं कि विध्वंसिआलयों की हालत बड़ी खराब हो गयी है, वहाँ एक नया ब्लाक पैदा हो गया है जिसका टीचर पोजिटिवियन उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा है। उन्होंने कहा है कि वह टीचर पोजिटिवियन इस किंग में रहता है कि किस प्रकार स्वयं बनो-पाजोन करे और अपने भित्तों को या अपने रिश्तेदारों को दूसरी यूनीवर्सिटी में अच्छी जगह दिलायें। लेकिन जब उनके सम्मुख यह प्रश्न आया कि वाइस चांसलर कौन हो उसकी नियुक्ति का अधिकार चांसलर को दिया जाय कि जिसे वह चाहे नियुक्त कर दे, तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि हम इसको नहीं जानते इसलिये कि इसमें ऐसा भालूम होता है कि वह कौंसिल आफ डिस्पेंसर है। हम हताश हो गये हैं और हम किसी प्रकार उनको सुझ नहीं सकते। उन्होंने कहा कि चांसलर के पास एक वाइस चांसलर को नाम भेजा जाय और बता ही सुझाव नरेन्द्र देव कमेटी ने भी दिया। सब सुझावों को देखने के बाद और उनसे कोई निष्कर्ष निकालना तथा अपनी हालत को उसके मिलान करना और फिर उससे रास्ता निकालना यह इतनी कठिन है, जो आज असम्भव है। यदि भाई राजाराम जी को यह संदेह हुआ कि गवर्नमेंट इन विध्वंसिआलयों के लिये कुछ नहीं करना चाहती तो मैं समझता हूँ कि उसका कोई आधार नहीं है। समय की कमी के कारण और किन्हीं और कारणों से तथा इससे दूसरे काय जो जरूरी थे जिनका निबटारा बहुत आवश्यक था इस बिल को इतना जल्दी जाना असम्भव था। मैं स्वयं बताऊँ कि उन्हीं आधार पर जिनका जिक्र डाक्टर ईश्वरी प्रसाद जी ने किया है कि जो हमारे आचार्य जी के सभापतित्व में कमेटी बनी थी उन्हीं आधार पर अमैजिनिबिल का ड्राफ्ट तैयार किया है। लेकिन अभी भी मैं नहीं कह सकता कि उसकी जो धारायें हैं वह ऐसी हैं जिस पर बड़ा संकेत हो सकता है। इसमें सरकार को कोई डेर करने का विचार नहीं है लेकिन वह मसला इतना ऊँचा है कि उसमें एक प्रकार से निश्चय कर लेना असम्भव है। तो इस स्थिति में वह बिल नहीं आ सका। हम चाहते थे कि असेम्बली और कौंसिल को इसका अवसर दें कि वह अपने विचार इस आग्रह विध्वंसिआलय के बारे में प्रकट करें। मगर कुछ दिक्कतें थी कि वह बिल न ला सके। अगर वह लाते तो हो सकता था कि हम इस एक क्लॉज के बिल को न लाते कि वाइस चांसलर का टर्म एक वर्ष के लिये बढ़ा दिया जाय। अगर यह आर्डिनेंस वाइस चांसलर के टर्म को बढ़ाने का न जारी किया होता तो थोड़े दिनों बाद वही स्थिति आ जाती जिसकी ओर फर्हयालाल जी ने ध्यान आकर्षित किया है। उस रिपोर्ट में कहा गया है कि आगरा यूनीवर्सिटी में जिस रोज एक इलेक्शन खत्म होता है उसी रोज से यानी तीन वर्ष पहले से दूसरे इलेक्शन को तैयारी हो जाती है। तो आज इलेक्शन हो जाने से उसका फिर आग्रह कर देना था। जिस प्रकार की गुटबन्दी होती है और जिस प्रकार इलेक्शन की तैयारी होती है आज उसका हम एक बीजारोपण कर देते। इस तरह इलेक्शन

एक वर्ष के लिए और टाल दिया गया है। तब रिपोर्ट की रीढ़ के अंगुष्ठ काट दिया गया था। लिया जायेगा और फिर एक विल भवन के सामने रखा जायेगा। आर्डिनंस जारी करने की आवश्यकता इसमें दी हुई है। जहाँ तक लिस्ट काटलानुक्त है, मुझे समझता है कि आज डा० ब्रजेन्द्र स्वरूप जी न कुछ ऐसी बातें कही हैं जिनकी मुझे उम्मीद नहीं थी। मैं इस सदन का पहले भी एक सदस्य रह चुका हूँ और आज भी एक सिंसिपल की हैसियत में बराबर उनको देखता आया हूँ। जो चीज नुस्खरहोनी है, ठीक होती है और पवित्र होती है उसका डाक्टर साहब ने हमेशा समर्थन किया है। लेकिन आज मुझे लगती जाती भी सुनकर बहुत दुःख हुआ। जिस तरह से एक वकील एक कमजोर सुनने को तो लेता है वही बात वही देता है, उसी तरह से आज डा० साहब ने इस सदन में पेश की है। उनकी रणनीति का अधिकांश भाग सिर्फ इस बात के लिए था कि यह आर्डिनंस पारित हो सके। यू० पी० लेजिस्लेटर को कोई अधिकार नहीं है कि वह इस तरह का रिपोर्ट लाये। मुझे अफसोस है कि वह इस वक्त यहाँ पर मौजूद नहीं हैं। साहब उनकी सविनय आज नहीं है इस कारण से वह चले गये हैं। लेकिन मैं यह उचित समझता हूँ कि जब कोई बात तो उसका जवाब सुनने के लिये आखीर तक बैठा रहे। मैं उनकी पता देना चाहता हूँ कि इन्होंने जितनी भी कानूनी रायें हो सकती थीं वह ज ली गई है। इतने बाद यह निष्कर्ष लिया गया है कि यह विल यहाँ पर पेश किया जाय। आर्डिनंस की दायरे उस वक्त जबरन रही हो या न रही हो लेकिन अब डा० साहब की रणनीति के सुनने के बाद मेरे विभाग में कोई संदेह नहीं रहा है और मैं समझता हूँ कि अब इसकी बहुत जल्दी जल्दी है। जैसा कि उन्होंने बतलाया तो उसके अनुसार ४ या ५ महीने बाद अर्बोरेट में इस भवन को तामने आता और उसके बाद एक सुकड़मा लड़ा जाता और इन तरह से सुकड़मे बाजी होती तो काफी बक्त लग जाता। तब जाकर एक बाइन चॉसपर की नियुक्ति होती। अगर आप का यह प्लान है तो अब उसके जरिये से प्लान बन हो जाता है। डाक्टर साहब स्वयं एक वकील हैं और वह हर बात को अच्छी तरह से समझते हैं और साथ ही साथ वह यूनीवर्सिटी की भी हालत को अच्छी तरह से जानते हैं। एक इन्वेंचरी करने की बेड़ी और उसने एक रिपोर्ट दी, उसने यह कहा कि विल बहुत जल्द लागू कर दिया जाय। साथ ही साथ राज्यपाल महोदय ने दो आदमियों की एक कमेटी नियुक्त की जो एक नदरे कालेजों में घूम कर देखे कि वहाँ की क्या हालत है। वह रिपोर्ट एक तो कलमेरे पास आई और एक अभी आई है। उनसे यह सिद्ध है कि यूनीवर्सिटी के बारे में जितनी बातें कही थीं सब सत्य हैं। यह कहना कि मैंने कोई एक तरफा बात सुनी है, यह बिल्कुल सत्य है। मेरे ऊपर जो कुछ भी आक्षेप लगाया जाय लेकिन यह कहना निर्मूलक है। मैंने कहा है कि विभाग जब कि मेरे एक मित्र ने कहा कि श्री महोदय न जो बात सुनी है, वह एक तरफा बात सुनी है, तो मैंने उन्हें वहीं टोक दिया कि मैंने सुनने पर बात नहीं कही है और जो कुछ भी मेरी सूचना है वह मैंने आपके सम्मुख रखी है और यह कुल लिखित है और यह प्रमाणित है, लेकिन यह कहना कि एक तरफा बात मैंने सुनी, तो मैं ब्रजेन्द्र स्वरूप जी की विस्मय दिलाता हूँ कि वह कम से कम यह न सोचें कि हम इतने नीचे स्तर पर उतर सकते हैं कि किस विभाग का मैं मंत्री हूँ उसी विभाग के लिये इतनी बातें कहूँ और इस प्रकार से कहूँ तो यह मेरे लिये लज्जा की बात है, सरकार के लिये लज्जा की बात है, भले ही यूनीवर्सिटी के लिये लज्जा की बात न हो और यूनीवर्सिटी के लिये तो लज्जा की बात है भी नहीं, क्योंकि वह तो नुकड़ना करने की सोच रही है। यदि आप यह समझते हैं कि नहीं, मैं तो यूनीवर्सिटी के बारे में कुछ नहीं करना चाहता था और एकाएक एक दिन पहली तारीख को मैं उठा और मैंने सोचा कि नहीं यूनीवर्सिटी का एक आर्डिनंस निकल जाना चाहिये, तो यह तो कोई कम्पलीमेंटरी बात नहीं है। लेकिन जो साहब इसको कहते हैं, उनके लिये भी यह कम से कम कम्पलीमेंटरी नहीं है। उनको इस बात की सोचना चाहिये कि जो आदमी एक स्थान पर नियुक्त है, चाहे काबिल हो या नाकाबिल हो, लेकिन वह अपनी जिम्मेदारी को समझता है और क्या उसको करना चाहिये, कितना उसको करना चाहिये और किस प्रकार से उसको हर तरह से अपने को

[श्री हर गोविन्द सिंह]

सेटिसफाई करना चाहिये, वह यह अच्छी तरह से जानता है और इसीलिये मैंने आपसे पहले ही कहा कि मैं इसमें विश्वास भी नहीं करता कि भवन से कोई बात छिपाई जाय और किसी से कोई बात छिपानी भी नहीं चाहिये, मैं डेमोक्रेसी के लिये इसको भी एक अंश समझता हूँ। इसलिये मैंने बहुत साफ कहा कि जब मुझे मालूम हुआ और मुझे पहले से ही मालूम था कि १२ तारीख दिसम्बर को प्रेजेन्ट वाइस चांसलर की टर्म खत्म होती थी और मैं यह समझता था कि अगर बिल तैयार हो जायेगा और हम दोनों भवनों से इस बिल को पहले ही पास करा लेंगे, लेकिन जब उसमें गुत्थियां दिखाई दीं जब यह देखा गया कि यह इतना सरल नहीं है और जब यह देखा गया कि हमें कम से कम इसमें लोगों की राय भी लेनी चाहिये और अगर मुमकिन हुआ तो इसको कहीं सेलेक्ट कमेटी को भी भेजना पड़े, तो यह दिखाई दिया कि यह किसी तरह से भी सम्भव नहीं है। जब एकजीक्यूटिव कमेटी के नियम बनाये जाते हैं तो उससे पहले ही हम इस बिल को पुरा कर लें, तब हमने यह काम किया जैसा कि मैंने पहले ही कह दिया है कि हमें आर्डिनंस की शरण लेनी पड़ी।

एक बात यह कही गई कि आर्डिनंस में यह क्यों किया गया कि प्रेजेन्ट वाइस चांसलर की टर्म को बढ़ा दिया गया, श्री राजाराम जी ने इस पर आपत्ति की। मैं इसमें भी कोई बात छिपाना नहीं चाहता। प्रेजेन्ट वाइस चांसलर जो हैं वह ३ वर्ष वाइस चांसलर रह चुके हैं और एक वर्ष और रहेंगे या तब तक रहेंगे जब तक कि बिल पूरा नहीं हो जाता, तो इस बिल का विरोध उन के लिये किसी प्रकार भी लाभकर नहीं है, कोई उनका स्थिर स्वार्थ नहीं हो सकता कि यूनीवर्सिटी में जो संशोधन आये, उसका विरोध करें। क्योंकि ३ वर्ष हो चुके और थोड़े दिन के लिये, जब तक कि बिल नहीं बन जाता तब तक यह और रहते हैं, तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन अगर कोई और वाइस चांसलर बना दिया जाय तो वह बिल के पास होने पर ही हो सकता है। मैंने पहले ही आपसे कहा था कि नरेन्द्र देव कमेटी की रिपोर्ट निकल जाने के बाद ही यह किन्हीं कारणों से नहीं हो सका कि उस यूनीवर्सिटी के क्षेत्र में लोगों ने यह महसूस किया हो कि हम अभी तक चलत रास्ते पर थे, हम भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन देते थे और इसलिये हमको अपना काम ठीक करना चाहिये। बल्कि उन्होंने प्रोटेस्ट किया और बड़ा भारी प्रोटेस्ट किया। तो इस तरह से जो स्थिति पैदा हो सकती थी और तीन, चार महीने बाद जो यहां आपत्ति होती, उसके लिये हमने यही ठीक समझा कि आर्डिनंस द्वारा उसके टर्म को एक वर्ष के लिये या उतने समय तक के लिये जब तक कि यहां बिल पास न हो, बढ़ा दिया जाय। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी जैसा कि श्री राजाराम जी ने कहा कि उनको यह पहले नहीं मालूम था और वह कांग्रेस में होते तो शायद ऐसा हो सकता था। मगर जैसा कहा गया है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। वह समझते हैं और उन्होंने ऐसा कह दिया और जैसा कि मैंने आपको बतलाया उस वक्त छोटा सा कारण यही था, जिससे कि इसको करना पड़ा। मुझे यह सन्तोष है कि किसी यूनीवर्सिटी ने इस बिल का विरोध नहीं किया और कहीं दूसरी जगह से भी इसका विरोध नहीं किया गया है। आप समाचारपत्रों में देखिये और जिन्होंने देखा है उनको यह बात मालूम है। मैं पहले इस बात को नहीं जानता था कि लेकिन अगर यूनीवर्सिटी के सम्बन्ध में जब मुझे बहुत से कागजात पढ़ने को मिले, तो मैंने उनके दस्तखतों से देख लिया और समझ लिया कि इसमें उनका कितना स्वार्थ है और इसीलिये वे इस चीज का विरोध कर रहे हैं। उसमें कुछ लोगों के बेनिफिट और स्वार्थ की बात थी लेकिन मुझे इस बात का सन्तोष हुआ कि एज्यूकेटेड क्लास की तरफ से इस चीज का विरोध नहीं किया गया और यूनीवर्सिटी और छात्रों ने इसका समर्थन किया। इन सब बातों को कहते हुये अन्त में मैं यह समझता हूँ और आशा करता हूँ कि भवन इस बिल का स्वागत करेगा और इसको अधिनियम बना देगा।

चेयरमैन—प्रश्न यह है कि सन् १९५२ ई० के आगरा यूनीवर्सिटी (अनुपूरक) विधेयक पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

चेयरमैन—हमारी कौंसिल की यह प्रथा रही है कि जब किसी संशोधनों की सूचना नहीं होती तो तीसरी रीडिंग फौरन ले ली जाती है और विधेयक को खंड प्रति खंड सदन के सामने नहीं रखा जाता।

श्री हर गोविन्द सिंह—मैं प्रस्ताव करता हूँ कि सन् १९५२ ई० के आगरा यूनीवर्सिटी (अनुपूरक) विधेयक को पारित किया जाय।

***श्री बंशीधर शुक्ल** (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत कम समय लूंगा। यहां पर डाक्टर ब्रजेन्द्र स्वरूप द्वारा वैधानिक आपत्ति उपस्थित की गई है, उसके सम्बन्ध में मैं दो शब्द कह कर समाप्त कर दूंगा। उन्होंने इस भवन के सदन धारा २४५ संविधान का उद्धरण दिया। उन्होंने यह कहा कि हमारे स्टेट को इस सम्बन्ध में अधिकार प्राप्त नहीं है। मुझे खेद है कि वे इस समय उपस्थित नहीं हैं, मैं यह भी जानता हूँ कि वे बहुत तजुबकार हैं और मैं उनके मुकाबिले में जूनियर हूँ। मैं धारा २४६ पढ़ कर सुनाता हूँ, उसके सब सेक्शन ३ के अनुसार यह विधेयक और आर्डिनेंस पूर्ण रूप से वैधानिक है। इस में पढ़ कर सुनाता हूँ।

“(3) Subject to clauses 1 and 2 the legislature of any State, specified in Part A or B of the I Schedule, has exclusive power to make laws for such State or any part thereof with respect to any of the matters enumerated in List II in the VII Schedule in this constitution referred to as the State List.”

उत्तर प्रदेश का तजकिरा पार्ट ए में है, आर्डिनेंस ११ में दिया हुआ है :—

“Education, including universities, subject to the provisions of entries 63, 64, 65 and 66 of List I and entry 25 of List III.”

६३, ६४, ६५, ६६ जो दिया हुआ है उसका सम्बन्ध पार्लियामेंट के लेजिस्लेशन से है। धारा ६३ में बनारस, अलीगढ़ और दिल्ली की यूनीवर्सिटी का जिक्र है, धारा ६४ में सार्विन्टिफिक और टेक्नीकल एजुकेशन का जिक्र है, धारा ६५ में प्रोफेशनल और टेक्नीकल ट्रेनिंग का जिक्र है और धारा ६६ में वोकेशनल इन्स्टीट्यूट्स का जिक्र है। लिस्ट थर्ड आर्डिनेंस २५ पर वोकेशनल ट्रेनिंग का जिक्र किया गया है। इसलिये मेरी समझ में नहीं आता कि जिस प्रकार अधिकार इस भवन को नहीं है कि वह कोई कानून बना सके। इसके अलावा यह साफ है जैसे किसी की जमींदारी है और वह दूसरी तहसील में है लेकिन वह जानता है कि जहां उसका हैब आफिस है या कार्यालय है वह उसको अधिकार है कि वह कोई मुकद्दमा लड़ सकता है। इसी तरह से अन्तर्राष्ट्रीय कानून होते हैं जैसे कोई एक कम्पनी है और उसका हैब आफिस किसी एक खास जगह होता है और उसकी सब ब्रांचें दूसरे मुल्कों में होती हैं इसी तरह जब वे कोई चीज अपने लिये पास करते हैं तो वह सब मुल्कों के लिये लागू हो जाती है। इसके अलावा मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो कालेज इसक नीचे है और वह उस एक्ट से गवर्न होते हैं और उन्होंने उसको मान लिया है तो फिर जो अमेन्डमेंट होगा तो उसको भी उन्हें मानना होगा। इस दृष्टिकोण से वह वैधानिक है।

* सबस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

चेयरमैन—प्रश्न यह है कि सन् १९५२ ई० के आगरा यूनीवर्सिटी (अनु-
पूरक) विधेयक* को पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

सत्रावसान

चेयरमैन—I have received the following communication from the Governor.

“In exercise of the powers conferred by sub-clause (a) of clause 2 of Article 174 of the Constitution, the Governor is pleased to prorogue the Uttar Pradesh Legislative Council with effect from the close of its meeting on November 6, 1952.”

The Council stands prorogued.

(इस समय, ४ बजे, विधान परिषद् का सत्रावसान हो गया।)

लखनऊ,
६, नवम्बर १९५२

श्यामलाल गोविल,
सेक्रेटरी, लेजिस्लेटिव कौंसिल,
उत्तर प्रदेश।

* विधेयक के लिये देखिए नत्थी “क” आगे पृष्ठ ३६ पर।

नृत्यी "क"

आगरा यूनीवर्सिटी (अनुपूरक) विधेयक १९५२

आगरा यूनीवर्सिटी ऐक्ट, १९२६ के अनुपूरण के लिये

विधेयक

प्रस्तावना १२ दिसम्बर, १९४६ से प्रारम्भ होने वाले कार्यकाल के लिये
यू० पी० अधिनियम निर्वाचित वाइस-चांसलर के कार्यकाल को बढ़ाकर आगरा यूनीवर्सिटी
८, १९२६। ऐक्ट, १९२६ का अनुपूरण करना उचित और आवश्यक है;

इसलिये निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त शीर्षनाम, १—(१) यह अधिनियम आगरा यूनीवर्सिटी (अनुपूरक) अधिनियम,
प्रारम्भ और १९५२ कहलायगा।
समाप्ति।

(२) यह ३० अक्टूबर, १९५२ से प्रचलित माना जायगा।

(३) यह ३१ दिसम्बर, १९५३ को निष्प्रभाव हो जायगा और
यू० पी० जेनरल क्लॉजेज ऐक्ट, १९०४ की धारा ६ के उपबन्ध इस प्रकार
लागू होंगे मानो यह अधिनियम उस समय किसी उत्तर प्रदेश ऐक्ट द्वारा
निरस्त (रिपील्ड) किया गया था।

यू० पी० अधिनियम २—आगरा यूनीवर्सिटी ऐक्ट, १९२६ की धारा ६ की उपधारा (२)
८, १९२६ की धारा (जिसका सम्बन्ध वाइस-चांसलर के कार्यकाल से है) १२ दिसम्बर, १९४६
६ (२) का संशोधन। से प्रारम्भ होने वाले कार्यकाल के लिये निर्वाचित वाइस-चांसलर के
विषय में इस प्रकार सप्रभाव होगी मानो शब्द "shall be three years"
के स्थान पर शब्द "shall continue until the 31 st day of
December 1953" रख दिये गये हों।

अध्यादेश का निरस्त। ३—उत्तर प्रदेश आगरा यूनीवर्सिटी अध्यादेश, १९५२ एतद् द्वारा
निरस्त (रिपील) किया जाता है।

संबेह निवारण। ४—संबेह निवारण के लिये एतद् द्वारा घोषित किया जाता है कि जब
तक इसके विपरीत व्यवस्था न की जाय, इस अधिनियम के समाप्त होने पर
आगरा यूनीवर्सिटी ऐक्ट, १९२६ की धारा ६ की उपधारा (२) इस प्रकार
सप्रभाव होगी मानो वह इस अधिनियम या उक्त अध्यादेश द्वारा कभी भी
अनुपूरित अथवा परिष्कृत नहीं की गई थी।

उद्देश्य और कारण

पिछले कुछ वर्षों में आगरा यूनीवर्सिटी ऐक्ट के अधीन कार्य संचालन में कुछ कठिनाइयों का अनुभव हुआ है। इसलिये सरकार का विचार इस अधिनियम में निम्न भविष्य में बहुत कुछ संशोधन करने का है। जिस प्रवृत्ति के लिये वर्तमान वाइस-चांसलर का निर्वाचन हुआ था वह १२ दिसम्बर, १९५२ को समाप्त होने को है और साधारणतः अगले कार्यकाल के लिये नया निर्वाचन होना चाहिये। ऐसे समय पर जब कि मूल अधिनियम में बहुत से संशोधन करने का विचार हो, नया निर्वाचन करने में अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिये राज्यपाल ने आगरा यूनीवर्सिटी ऐक्ट, १९२६ में कुछ प्रयोजनों के निमित्त संशोधन करने के लिये एक अध्यादेश प्रचारित किया जिससे वाइस-चांसलर का कार्यकाल दिसम्बर, १९५३ के अन्त तक बढ़ा दिया गया। किन्तु विधान मंडल के पुनः समवेत होने से छः सप्ताह की समाप्ति पर अध्यादेश समाप्त हो जायगा। इस अधिनियम से अध्यादेश के उपबन्धों को अधिनियमित करने की व्यवस्था की जा रही है।

हर गोविन्द सिंह,
शिक्षामंत्री।

उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौंसिल

की
कार्यवाही

की

अनुक्रमणिका

खण्ड २८

‘अ’

अब्दुल शकूर नजमी, श्री—
उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन)
विधेयक, १९५२। अं० ७, पृ०
३११, ३१२, ३१३।

‘इ’

इन्द्र सिंह नयाल, श्री—
“देखिये प्रश्नोत्तर।
सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश विक्री
कर (संशोधन) विधेयक, अं० ४,
पृ० १२२, १३१।

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश
जमींदारों के ऋण कम करने का
विधेयक। अं० ३, पृ० ७८, ७९।

संकल्प कि प्रदेश में माध्यमिक कक्षाओं
में सैनिक शिक्षा अनिवार्य कर दी
जाय। अं० २, पृ० ३९, ४०, ४१।

‘ई’

ईश्वरी प्रसाद, डाक्टर—
आगरा यूनिवर्सिटी (अनुपूरक) विधेयक,
१९५२। अं० ८, पृ० ३२६, ३३३,
३५२, ३५३।

उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन)
विधेयक, १९५२। अं० ७, पृ०
२८४, २८५-२८६, २८७, ३१८।

प्रस्ताव कि काशी के घाटों के सम्बन्ध
में शीघ्र कार्य आरम्भ किया जाय।
अं० २, पृ० ५८, ५९, ६०।

सदन का कार्यक्रम। अं० ४, पृ० १३७।
अं० ६ पृ० ३५४।

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश
जमींदारों के ऋण कम करने का
विधेयक। अं० ३, पृ० ८४, ८५-
८७, ८८।

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश फायर
सर्विस (संशोधन) विधेयक।
अं० ४, पृ० १३३, १३४।

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश विक्री
कर (संशोधन) विधेयक। अं० ४,
पृ० १२२, १२९।

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश म्युनिसि-
पैलिटीज (संशोधन) विधेयक।
अं० ६, पृ० २३०, २३३।

संकल्प कि प्रदेश में माध्यमिक कक्षाओं
में सैनिक शिक्षा अनिवार्य कर
दी जाय। अं० २, पृ० ३०,
३१, ३२।

‘ए’

एम० जे० मुकजी, श्री—
उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन)
विधेयक, १९५२। अं० ७, पृ०
३००, ३१३, ३१४।

[एम० जे० मुकर्जी]

संकल्प कि उत्तर प्रदेश में अनाथालयों तथा विधवा आश्रमों का प्रबन्ध सरकार अपने हाथ में ले ले।
अं० २, पृ० २१, २२, २३।

संकल्प कि प्रदेश में माध्यमिक कक्षाओं में सैनिक शिक्षा अनिवार्य कर दी जाय। अं० २, पृ० ३५, ३६।

‘क’

कन्हैया लाल गुप्त, श्री—

आगरा यूनिवर्सिटी (अनुपूरक) विधेयक, १९५२। अं० ८, पृ० ३४८, ३४९-३५१।

“देखिये प्रश्नोत्तर”।

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश फायर सर्विस (संशोधन) विधेयक। अं० ४, पृ० १३४, १३५, १३६।

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक। अं० ४, पृ० १३२।

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक। अं० ५, पृ० १७७, १७८-१८३, १८४। अं० ६, पृ० २००, २०१।

कार्यक्रम—

सदन का—। अं० १, पृ० १०, ११-१२। अं० २, पृ० ६१। अं० ४, पृ० १३७। अं० ६, पृ० २५४, २५५।

कुंवर गुरु नारायण, श्री—

आगरा यूनिवर्सिटी (अनुपूरक) विधेयक, १९५२। अं० ८, पृ० ३२७, ३२८, ३२९।

आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट को संशोधित करने के विषय में जानकारी की प्रार्थना। (जानकारी की प्रार्थना की) अं० ४, पृ० ११७।

उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक, १९५२। अं० ७, पृ० २७०, २७१, २९८।

“देखिये प्रश्नोत्तर”।

सदन का कार्यक्रम। अं० १, पृ० १०, ११, १२। अं० २, पृ० ६१। अं० ४, पृ० १३७। अं० ६, पृ० २५४।

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारों के ऋण कम करने का विधेयक। अं० ३, पृ० ६८, ६९, १०४, १०५।

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन) विधेयक। अं० ४, पृ० १२०, १२१, १२२, १२३, १२७।

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक। अं० ५, पृ० १६२, १६३-१६५, १६६।

अं० ६, पृ० २१७, २१८, २१९, २२०, २२५, २२६, २२८, २३४, २३५, २५०, २५१, २५२, २५३।

संकल्प कि प्रदेश में माध्यमिक कक्षाओं में सैनिक शिक्षा अनिवार्य कर दी जाय। (प्रस्तुत किया)। अं० २, पृ० २५-२६, २७, ४८-४९, ५०।

कुंवर महावीर सिंह, श्री—

देखिये प्रश्नोत्तर।

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारों के ऋण कम करने का विधेयक। अं० ३, पृ० ७२, ७३, ७४, ९७, ९८, ९९, १०२, १०९।

केदार नाथ खेतान, श्री—

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारों के ऋण कम करने का विधेयक। अं० ३, पृ० ८०, ८१।

“न”

गिरधारी लाल, श्री—

प्रस्ताव कि काशी के घाटों के सम्बन्ध में शीघ्र कार्य आरम्भ किया जाय। अं० २, पृ० ५८, ५९।

गोविन्द सहाय, श्री—

आगरा यूनिवर्सिटी (अनुपूरक) विधेयक, १९५२। अं० ८, पृ० ३२५, ३३६, ३३७-३३८, ३३९।

[गोविन्द सहाय, श्री]

उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन)
विधेयक, १९५२। अं० ७, पृ० २६९,
२८७, २८८-२९०।

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश
म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक
अं० ६, पृ० २०१, २२७।

“च”

चरण सिंह, श्री—

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश
जमींदारों के ऋण कम करने का
विधेयक। (विचार प्रस्तुत किया)
अं० ३, पृ० ६६, ६७, ६८, ७६, ८७, ८८,
८९-९२, ९३, ९५, ९६, ९७, ९८, ९९,
१००, १०२, १०५, १०६, १०७, १०८,
११०, १११, ११२।

चुनाव—

इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कोर्ट के
लिये-----। अं० ६, पृ० २५४।

चेयरमैन—

आगरा यूनिवर्सिटी (अनुपूरक)
विधेयक, १९५२। अं० ८, पृ० ३२५,
३३४, ३४०, ३४५, ३४७, ३५१, ३५२,
३५७, ३५८।

आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट को संशोधित
करने के विषय में जानकारी की
प्रार्थना। अं० ४, पृ० ११७।

आगरा विश्वविद्यालय के उप-कुलपति
का चुनाव आर्डिनंस द्वारा स्थगित
किये जाने के सम्बन्ध में कार्य स्थगन
प्रस्ताव। अं० ६, पृ० १९५, १९६।

आगरा विश्वविद्यालय के उप-कुलपति
का चुनाव आर्डिनंस द्वारा स्थगित
किये जाने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन
प्रस्ताव की सूचना। अं० ५, पृ०
१४५, १४६।

इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कोर्ट के लिये
चुनाव। अं० ६, पृ० २५४।

इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कोर्ट के लिये
दो सदस्यों के चुनाव का प्रस्ताव।
अं० ४, पृ० १३७।

उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन)
विधेयक, १९५२। अं० ७, पृ० २६८,

२७०, २७१, २७२, २७४, २७६,
२७८, २७९, २८३, २९२, ३१४,
३१५, ३१८, ३१९।

प्रस्ताव कि काशी के घाटों के सम्बन्ध
में शीघ्र कार्य आरम्भ किया जाय।
अं० २, पृ० ६०, ६१।

सदन का कार्यक्रम। अं० १, पृ० १०,
११, १२। अं० २, पृ० ६१। अं०
४, पृ० १३७। अं० ६, पृ० २५४,
२५५।

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश जमीं-
दारों के ऋण कम करने का विधेयक।
अं० ३, पृ० ८१, ११२।

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश फायर
सर्विस (संशोधन) विधेयक। अं०
४, पृ० १३५, १३६।

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश बिक्री
कर। (संशोधन) विधेयक। अं० ४,
पृ० १२२, १२३, १२६, १२७,
१३२, १३३।

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश म्यु-
निसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक।
अं० ५, पृ० १५०, १५१, १५२,
१६२, १८७। अं० ६, पृ० २०१,
२०३, २०४, २०६, २०७, २०८,
२०९, २१०, २११, २१७, २१९,
२२०, २४४, २४५, २४६, २४८,
२५०, २५२, २५३।

संकल्प कि उत्तर प्रदेश में अनाथालयों
तथा विधवा आश्रमों का प्रबन्ध
सरकार अपने हाथ में ले ले। अं०
२, पृ० २१, २३, २४।

सत्रावसान। अं० ८, पृ० ३५८।

“ज”

जमीलुर्रहमान किवदई, श्री—

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश
जमींदारों के ऋण कम करने का
विधेयक। अं० ३, पृ० ९७।

जानकारी—

आगरा यूनिवर्सिटी, ऐक्ट को संशोधित
करने के विषय में—को प्रार्थना।
(अनुमति नहीं दी गई)। अं० ४,
पृ० ११७।

ज्योति प्रसाद गुप्त, श्री—

आगरा यूनिवर्सिटी (अनूपूरक)
विधेयक, १९५२। अं० ८, पृ० ३४६,
३४७, ३४८।

उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशो-
धन) विधेयक, १९५२। अं० ७,
पृ० ३०४, ३०५-३०६, ३०७।
देखिये “प्रश्नोत्तर”।

‘ड’

डिप्टी चैयरमैन—

उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन)
विधेयक, १९५२। अं० ७, पृ०
३०१, ३११।

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश जमीं-
दारों के ऋण कम करने का विधेयक।
अं० ३, पृ० ८८, ९३, ९७, ९९,
१००, १०२, १०५, १०७, १०८,
१०९, ११०।

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश म्यु-
निसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक।
अं० ६, पृ० २२७, २२८, २३४,
२४१, २४२।

संकल्प कि प्रदेश में माध्यमिक कक्षाओं
में सैनिक शिक्षा अनिवार्य कर दी
जाय। अं० २, पृ० ३८, ५३।

‘त’

तारा अग्रवाल, श्रीमती—

उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन)
विधेयक, १९५२। अं० ७, पृ०
३०७, ३०८, ३०९।

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश जमीं-
दारों के ऋण कम करने का विधे-
यक। अं० ३, पृ० ७४, ७५।

‘न’

नरोत्तम दास टंडन, श्री—

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश
म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधे-
यक। अं० ५, पृ० १७५, १७६।

निजामुद्दीन, श्री—

उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशो-
धन) विधेयक, १९५२। अं० ७,
पृ० २७३।

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश म्यु-
निसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक।
अं० ५, पृ० १६१, १६२।

‘प’

पन्ना लाल गुप्त, श्री—

उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशो-
धन) विधेयक, १९५२। अं० ७,
पृ० ३१४।

परमात्मानन्द सिंह, श्री—

देखिये “प्रश्नोत्तर”।

सदन का कार्यक्रम। अं० १, पृ० १२।
सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश फायर
सर्विस (संशोधन) विधेयक। अं०
४, पृ० १३६।

संकल्प कि प्रदेश में माध्यमिक कक्षाओं
में सैनिक शिक्षा अनिवार्य कर दी
जाय। अं० २, पृ० २९, ३०।

पूर्ण चन्द्र विद्यालंकार, श्री—

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश
म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन)
विधेयक। अं० ६, पृ० २०२,
२०९।

प्रताप चन्द्र आजाद, श्री—

आगरा यूनिवर्सिटी (अनूपूरक)
विधेयक, १९५२। अं० ८, पृ०
३३३, ३३४, ३३५।

उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन)
विधेयक, १९५२। अं० ७, पृ०
२७७, २७८, २९७, २९८, २९९,
३००।

देखिये “प्रश्नोत्तर”।

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश जमीं-
दारों के ऋण कम करने का
विधेयक। अं० ३, पृ० ६९, ७०।

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश म्युनि-
सिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक।
अं० ५, पृ० १५६, १५७-१६०,
१६१। अं० ६, पृ० २०६, २२०,
२२७, २२८, २३७, २३८, २४५।

संकल्प कि प्रदेश में माध्यमिक कक्षाओं
में सैनिक शिक्षा अनिवार्य कर दी
जाय। अं० २, पृ० ३८, ३९।

ब्रभु नारायण सिंह, श्री—

आगरा यूनीवर्सिटी अनुपूरक विधेयक,
१९५२। अं० ८, पृ० ३४५,
३४६।

उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन)
विधेयक, १९५२। अं० ७, पृ०
२६७, २६८, २६९, २७० २७३,
३००, ३०१, ३०२, ३११।

प्रस्ताव कि काशी के घाटों के सम्बंध
में शीघ्र कार्य आरम्भ किया जाय।
अं० २, पृ० ५४, ५५।

सदन का कार्यक्रम। अं० १, पृ०
११।

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश
जमींदारों के ऋण कम करने का
विधेयक। अं० ३, पृ० ७०, ७१,
७२, ९५, ९६, ९९, १००, १०१,
१०३, १०४, १०५, १०६, १०७,
१०८, १११।

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश विक्की
कर (संशोधन) विधेयक। अं० ४,
पृ० १२३, १२४, १२५, १२६,
१२७, १२८, १२९।

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश म्युनि-
सिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक।
अं० ५, पृ० १६६, १६७-१६८,
१६९। अं० ६, पृ० २०२, २०५,
२०६, २०७, २०९, २१०, २१६,
२१७, २२०, २२१, २२८, २२९,
२३१, २३२, २३३, २३४, २४०,
२४१, २४२, २४३, २४४, २४५।

संकल्प कि प्रदेश में माध्यमिक कक्षाओं
में सैनिक शिक्षा अनिवार्य कर दी
जाय। अं० २, पृ० ४४, ४५,
४६।

प्रश्नोत्तर

इन्द्र सिंह नयाल, श्री—

नैनीताल में बन्दूक के लाइसेंसदारों
से जबरदस्ती चन्दा वसूल किया
जाना। अं० ६, पृ० १९२, १९३,
१९४, १९५।

पनबिकियों की नाली से बिजली पैदा
होना। अं० १, पृ० ५, ६।

बरेली—हव्वाली रोड एन गवर्नमेंट
रोडवेज की दमे। अं० ६, पृ० १९०—
१९१, १९२।

कन्हैया लाल गुप्त, श्री—

अध्यापकों और विद्यार्थियों के निम्ने
सेनेटोरियम के सम्बन्ध में सरकार
की योजना। अं० ७, पृ० २६२,
२६३, २६४।

असतुष्ट अध्यापकों की स्थिति। अं०
७, पृ० २६५।

बोर्ड आफ हाई स्कूल ऐन्ड इन्टर—
मीडियेट एज्युकेशन, उत्तर प्रदेश
द्वारा परीक्षकों की नियुक्ति। अं०
७, पृ० २६५, २६६।

म्युनिसिपल और टाउन एरिया
कमेटियों के चुनाव। अं० ४,
पृ० ११५।

प्रत्येक वर्ष एल० टी० पास करने
वालों की संख्या। अं० ७, पृ०
२६४, २६५।

सेट्रल एज्यूकेशन मिनिस्ट्री की रिफ—
रिजें। अं० ७, पृ० २५९, २६०—
२६१, २६२।

कुंवर गुरु नारायण, श्री—

उत्तर प्रदेश में आचार्य विनोबा भावे के
भू-दान यज्ञ में दी गई भूमि।
अं० २, पृ० १४-१६, १७।

मिनिरिट्रल जगहों पर शर्तों के लिये
परीक्षा। अं० १, पृ० ४।

सन् १९४६ से बिना पब्लिक सर्विस
कमीशन को सूचित किये हुये की
गई नियुक्तियां। अं० १, पृ० २-३,
४।

सूचना विभाग की नियुक्तियां। अं० ५,
पृ० १४४, १४५।

कुंवर महावीर सिंह, श्री—

केन कॅनल डिबीजन, बांदा में हिसाब-
किताब में देरी। अं० ५, पृ०
१४२-१४३, १४४।

ज्योति प्रसाद गुप्त, श्री—

उत्तर प्रदेश में मुह्तारों और रेवेन्यू
एजेंटों की संख्या। अं० २, पृ०
१७-१८, १९।

पन्ना लाल गुप्त, श्री—

१५ अगस्त को प्रदर्शन। अं० ६, पृ० १९२।

फतेहपुर जिले में चोरियों और डकैतियों की संख्या। अं० ६, पृ० १६२।

परमात्मा नन्द सिंह, श्री—

प्रदेश के पंचायत राज्य निरीक्षकों की संख्या—वृद्धि। अं० ४, पृ० ११५, ११६।

प्रताप चन्द्र आजाद, श्री—

तहसील आंवला, जिला बरेली के कच्चे मार्ग। अं० ३, पृ० ६४।

बरेली कालेज, बरेली में विभिन्न फीसों का लिया जाना। अं० ७, पृ० २५८, २५९।

राम नन्दन सिंह, श्री—

महाराजा बनारस का अपने राज्य का सर्वोच्च सत्ताधारी होना। अं० ५, पृ० १४४।

विलीन काशी राज्य क्षेत्र की ग्राम पंचायतों के रुपयों की वापसी। अं० ४, पृ० ११४, ११५।

ब्रज लाल वर्मन (हकीम), श्री—

नये मकान बनाने वालों को बिजली का कनेक्शन। अं० १, पृ० ६, ७-८, ९।

प्रदेश के मुख्य तीर्थ स्थानों को अर्द्ध बनाने की योजना। अं० ४, पृ० ११६, ११७।

शिव सुमरन लाल जौहरी, श्री—

एल० एच० आयुर्वेदिक कालेज, पोलीभीत। अं० ३, पृ० ६४, ६५, ६६।

प्रस्ताव—

आगरा विश्वविद्यालय के उप-कुलपति का चुनाव आर्डिनेंस द्वारा स्थगित किये जाने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन—। (अनुज्ञा नहीं दी गई)। अं० ६, पृ० १९५, १९६।

आगरा विश्वविद्यालय के उप-कुलपति का चुनाव आर्डिनेंस द्वारा स्थगित किये जाने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन—की सूचना। (विचार स्थगित

किया गया।) अं० ५, पृ० १४५, १४६।

इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कोर्ट के लिये दो सदस्यों के चुनाव का—। स्वीकृत हुआ। अं० ४, पृ० १३६, १३७।

—कि काशी के घाटों के सम्बन्ध में शीघ्र कार्य आरम्भ किया जाय। (वापस लिया गया)। अं० २, पृ० ५३, ५४-६०, ६१।

प्रेम चन्द्र शर्मा, श्री—

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारों के ऋण कम करने का विधेयक। अं० ३, पृ० ८८।

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश फायर सर्विस (संशोधन) विधेयक। अं० ४, पृ० १३६।

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक। अं० ५, पृ० १८४, १८५। अं० ६, पृ० २३५।

संकल्प कि उत्तर प्रदेश में अनायालयों तथा विधवा आश्रमों का प्रबन्ध सरकार अपने हाथ में ले ले। अं० २, पृ० २३।

‘ब’

बद्री प्रसाद कवकड़, श्री—

आगरा यूनिवर्सिटी (अनुपूरक) विधेयक, १९५२। अं० ८, पृ० ३३५, ३३६।

उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक १९५२। अं० ७, पृ० ३०२, ३०३, ३०४।

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारों के ऋण कम करने का विधेयक। अं० ३, पृ० ७६, ८०।

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक। अं० ५, पृ० १७०, १७१-१७२, १७३। अं० ६, पृ० २२३।

बंशीधर शुक्ल, श्री—

आगरा यूनीवर्सिटी (अनुपूरक)
विधेयक १९५२। अं० ८, पृ०
३५७।

संकल्प कि प्रदेश में माध्यमिक
कक्षाओं में सैनिक शिक्षा अनि-
वार्य कर दी जाय। अं० २,
पृ० ४६, ४७।

‘म’

मान पाल गुप्त, श्री—

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारों
के ऋण कम करने का विधेयक। अं०
३, पृ० ८१, ८२।

मुकुट बिहारी लाल, प्रोफेसर—

सदन का कार्यक्रम। अं० १, पृ० ११।

मोहन लाल गौतम, श्री—

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश म्युनि-
सिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक—
(पुरःस्थापित किया)। अं० ३,
पृ० ११२। अं० ५, पृ०
१४६, १४७-१४९, १५०, १६४,
१७९, १८०, १८१, १८७।
अं० ६, पृ० १९७-२००, २०१,
२०२, २०३, २०६, २०९, २१०,
२१६, २१७, २१८, २२३, २२४,
२२६, २२७, २२८, २३१, २३२,
२३३, २३४, २३८, २३९, २४०,
२४१, २४३, २४४, २४५, २४८,
२५०, २५१, २५२, २५३।
अं० ७, पृ० २६७, २६६,
२७०, २७१, २७२, २७३,
२७५, २७६, २७८, २८४, २८६,
३०६, ३११, ३१५, ३१८, ३१६।

संकल्प कि उत्तर प्रदेश में अनायालयों
तथा विधवा आश्रमों का प्रबन्ध
सरकार अपने हाथ में ले ले। अं०
२, पृ० २३, २४।

‘र’

राजा राम शास्त्री, श्री—

आगरा यूनिवर्सिटी (अनुपूरक) विधेयक,
१९५२। अं० ८, पृ० ३२९, ३३०-
३३२, ३३३।

आगरा विश्वविद्यालय के उप-कुलपति
का चुनाव आर्डिनेंस द्वारा स्थगित
किये जाने के सम्बन्ध में कार्य-
स्थगन प्रस्ताव। (प्रस्तुत किया)
अं० ६, पृ० १९५, १९६।

आगरा विश्वविद्यालय के उप-कुलपति
का चुनाव आर्डिनेंस द्वारा स्थगित
किये जाने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन
प्रस्ताव की सूचना। अं० ५, पृ०
१४५, १४६।

उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन)
विधेयक: १९५२। अं० ७, पृ०
२६७ २७१, २७२, २७३, २७४,
२७५, २७६, २८२, २९३, २९४,
२९८, ३१७।

प्रस्ताव कि काशी के घाटों के सम्बन्ध
में शीघ्र कार्य आरम्भ किया जाय।
अं० २, पृ० ५६, ५७, ६०।

सदन का कार्यक्रम। अं० १, पृ० ११।
अं० ४, पृ० १३७। अं० ६, पृ०
२५५।

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारों
के ऋण कम करने का विधेयक। अं०
३, पृ० ७३, ७५, ७६-७७-७८।

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश विप्लो
कर (संशोधन), विधेयक। अं० ४,
पृ० १२६, १३०, १३१।

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश म्युनि-
सिपैलिटी (संशोधन) विधेयक। अं०
५, पृ० १५०, १५१, १५२, १५३,
१५५, १५६।

अं० ६, पृ० २०२, २०३, २०४,
२०६, २०७, २२१, २२२, २२३,
२२९, २३०, २३५, २३६, २३७,
२३८, २३९, २४४, २४७, २४८,
२४९, २५०, २५२।

संकल्प कि प्रदेश में माध्यमिक कक्षाओं
में सैनिक शिक्षा अनिवार्य कर दी
जाय। अं० २, पृ० ३२, ३३-३४,
३५।

राम नन्दन सिंह, श्री—
देखिये ‘प्रश्नोत्तर’।

राम लगन सिंह, श्री—

सन १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश म्यु-
निसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक।
अं० ६, पृ० २०१, २०२, २०३।

हर्लिंग—

It is quite within the compe-
tence of the House to accept
the one part of the amend-
ment and to reject the
other. अं० ७, पृ० २७२।

It is within the competence of
the Chair to put any
amendment in the manner
it thinks best. If necessary,
the Chair can divide the
amendment before putting
it before the House. अं० ७,
पृ० २७२।

the member incharge moves
that the Bill be taken into
consideration, any member
may move an ammendment
that the Bill be referred to
a Select Committee or a
Joint Select Committee. अं०
५, पृ० १५२।

A thing cannot be taken up
when it is not on the agen-
da and anything of any kind
cannot be asked at any
time. अं० ४, पृ० ११७।

किसी आर्डिनेंस के सम्बन्ध में, जो सदन
में विचार के लिये उपस्थित है, अलग
मोशन भी मूव किया जा सकता है
और प्रस्ताव के पेश होते समय,
उस आर्डिनेंस पर बहस भी की जा
सकती है। अं० ६, पृ० १९६।

किसी खंड में संशोधन होने पर, उसी
संशोधन के सम्बन्ध में बोला जा
सकता है और उस समय पूरे खंड
पर वाद-विवाद नहीं किया जा सकता
है। हां, सदस्य उस खंड के विरुद्ध
वोट दे सकते हैं या तीसरे वाचन के
समय उस सम्बन्ध में अपने विचार
प्रकट कर सकते हैं। अं० ६, पृ०
२४४।

किसी नई संस्था को स्थापित करने के
सम्बन्ध में संशोधन प्रस्तुत करके
किसी विधेयक का स्कोप नहीं बढ़ाया
जा सकता है। अं० ६, पृ० ६०७।

किसी विधेयक द्वारा संविधान की अद-
हेलना होने पर न्यायालय में जाया
जा सकता है। अं० ४, पृ० १२३।

चेयरमैन के खड़े होने पर किसी अन्य
सदस्य को खड़ा नहीं होना चाहिये।
हर सदस्य को अपने संशोधन के पक्ष
में या विपक्ष में वोट देने का अधि-
कार है। अं० ६, पृ० २०४।

नियमों के अनुसार कार्य—स्थगन प्रस्ताव
कार्यवाही शुरू होने के आधा घंटा
पहले आना चाहिये। अं० ५, पृ०
१४५।

प्रश्न पूछने वाले सदस्यों को प्रश्नों के
उत्तर दिये जाने के समय सदन में
अवश्य उपस्थित रहना चाहिये।
अं० ६, पृ० १९५।

बिल का स्वरूप किसी संशोधन द्वारा
उचित होगा या अनुचित होगा,
इस बात का अवश्य ध्यान रखना
चाहिये और तभी संशोधन प्रस्तुत
करना चाहिये क्योंकि इस प्रकार
संशोधन करके आपत्ति उठाना अवै-
धानिक है। अं० ६, पृ० २०६।

विधान का प्रश्न उठाने समय भाषण
नहीं दिया जा सकता है। अं० ४,
पृ० १२२।

विधेयक में किसी संशोधन द्वारा नई
व्यवस्था का आयोजन नहीं किया जा
सकता, लेकिन यदि संशोधन का कोई
भाग विधेयक की सीमा के अन्तर्गत
हो, तो वह प्रस्तुत किया जा सकता
है। अं० ७, पृ० २७२।

सदस्य परस्पर प्रश्नोत्तर नहीं कर सकते
हैं, बल्कि अपने विचार अध्यक्ष के
सम्मुख रख सकते हैं। अं० ४, पृ०
१३५।

सदस्य सदन में परस्पर प्रश्नोत्तर नहीं
कर सकते हैं। अं० ४, पृ० १२७।

सदस्यों को अधिकार है कि जो विषय सदन में प्रस्तुत है, उस पर वे अपनी राय दे सकते हैं, मगर किसी पत्र के न होने के कारण कार्यवाही को नहीं रोक सकते हैं। अं० ४, पृ० १३५।

समाचार पत्रों में छपी हुई सूचनाओं के सम्बन्ध में सदन में प्रश्न नहीं किये जा सकते हैं। अल्प सूचक प्रश्नों के सम्बन्ध में सरकार को अधिकार है, वह चाहे उत्तर दे या न दे। प्रश्नों का उत्तर न मिलने पर कामरोकी प्रस्ताव रखा जा सकता है। अं० ४, पृ० १३७।

संशोधन प्रस्तुत करने के पश्चात् जब दुबारा कोई सदस्य जवाब दे देता है, तो पुनः वह उस पर नहीं बोल सकता है। अं० ६, पृ० २४४।

‘व’

ब्रज लाल वर्मन (हकीम), श्री—
देखिये ‘प्रश्नोत्तर’।

प्रस्ताव कि काशी के घाटों के सम्बन्ध में शीघ्र कार्य आरम्भ किया जाय।
अं० २, पृ० ५५, ५६।

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश म्यु-
निसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक।
अं० ५, पृ० १६९, १७०।

ब्रजेन्द्र स्वरूप, डाक्टर—

आगरा यूनीवर्सिटी (अनुपूरक) विधेयक,
१९५२। अं० ८, पृ० ३४१-३४४,
३४५।

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश म्यु-
निसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक।
अं० ५, पृ० १७३, १७४, १७५।

व्यक्तिगत प्रश्न

प्राचार्य विनोबा भावे—

उत्तर प्रदेश म—के भू-दान यज्ञ
म बी गई भूमि। अं० २, पृ० १४-
१६, १७।

विधेयक—

आगरा यूनिवर्सिटी (अनुपूरक) —,
१९५२ (पुरःस्थापित किया गया)।
अं० ६, पृ० २४४। (पारित हुआ)।

अं० ८, पृ० ३२२-३५७, ३५८।

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश
(अस्थायी) कंट्रोल ऑफ रेस्ट एण्ड
एविकेन (संशोधन) —,
(घोषणा की गई)। अं० १, पृ०
१०।

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश इले-
क्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्न ऑफ
कंट्रोल) (संशोधन) —, (घोषणा
की गई)। अं० १, पृ० ९।

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारों
के ऋण कम करने का—।
(मेज पर रखा गया) अं० १, पृ०
६। (पारित हुआ)। अं० ३, पृ०
६६, ६७-१११, ११२।

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश
(टेम्पोरेरी एकोमोडेशन) रिक्वाजी-
शन (संशोधन) —, (घोषणा
की गई)। अं० १, पृ० १०।

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश फायर
सर्विस (संशोधन) —,
(प्रस्तुत किया गया)। अं० १, पृ०
९। (पारित हुआ)। अं० ४, पृ०
१३३, १३४-१३५, १३६।

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश बिक्री
कर (संशोधन) —, (मेज
पर रखा गया)। अं० १, पृ० ९।
(पारित हुआ)। अं० ४, पृ० ११७,
११८-१३२, १३३।

सन् १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश
कन्ट्रोल आफ सप्लाइज (कन्टीन्यु-
एन्स आफ पावर्स) (संशोधन)
—, (घोषणा की गई)। अं० १,
पृ० १०।

विश्वनाथ, श्री—

उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन)
विधेयक, १९५२। अं० ७, पृ०
३०९, ३१०।

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश
जमींदारों के ऋण कम करने का
विधेयक। अं० ३, पृ० ८२, ८३।

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश
म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन)
विधेयक। अं० ५, पृ० १८५, १८६-
१८७।

संकल्प कि प्रदेश में माध्यमिक कक्षाओं
में सैनिक शिक्षा अनिवार्य कर दी
जाय। अं० २, पृ० ४२, ४३, ४४।

बीर भान भाटिया, डाक्टर—

संकल्प कि प्रदेश में माध्यमिक कक्षाओं
में सैनिक शिक्षा अनिवार्य कर दी
जाय। अं० २, पृ० ४७।

वेणी प्रसाद टन्डन, श्री—

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश जमीं-
दारों के ऋण कम करने का विधेयक।
अं० ३, पृ० ८३, ८४।

“श”

शान्ति स्वरूप अग्रवाल, श्री—

आगरा यूनिवर्सिटी (अनुपूरक) विधे-
यक, १९५२। अंक ८, पृ० ३३९-
३४०।

उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशो-
धन) विधेयक, १९५२। अं० ६,
पृ० २०६। अं० ७, पृ० ३१४।

श्याम सुन्दर लाल, श्री—

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश म्यु-
निसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक।
अं० ५, पृ० १७०।

शिवराजवती नेहरू, श्रीमती—

उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन)
विधेयक, १९५२। अं० ७, पृ० २९१,
२९२।

सदन का कार्यक्रम। अं० १, पृ० १२।

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश म्यु-
निसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक।
अं० ५, पृ० १७६, १७७।

संकल्प कि उत्तर प्रदेश में अनायालयों
तथा विधवा आश्रमों का प्रबन्ध सर-
कार अपने हाथ में ले ले। (प्रस्तुत
किया) अं० २, पृ० १६, २०, २१,
२४।

शिव सुमरन लाल जौहरी, श्री—
देखिये ‘प्रश्नोत्तर’।

“स”

सत्यप्रेमी उपनाम हरिप्रसाद, श्री—

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश म्यु-
निसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक।
अंक ६, पृ० २६६, २१०।

सभापति उपाध्याय, श्री—

उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशो-
धन) विधेयक। अं० ७, पृ० ३१४,
३१५।

प्रस्ताव कि काशी के घाटों के सम्बन्ध
में शीघ्र कार्य आरम्भ किया जाय।
(प्रस्तुत किया) अं० २, पृ० ५३,
५४, ६०।

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश
म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधे-
यक। अं० ५, पृ० १६६।

सरदार सन्तोष सिंह, श्री—

उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशो-
धन) विधेयक, १९५२। अं० ७,
पृ० २९१।

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश फायर
सर्विस (संशोधन) विधेयक। अं० ४,
पृ० १३५।

संकल्प कि प्रदेश में माध्यमिक कक्षाओं
में सैनिक शिक्षा अनिवार्य कर दी
जाय। अं० ३, पृ० ४१, ४२।

सत्रावसान—

-----। अं० ८, पृ० ३५८।

स्थानीय प्रश्न

आंबला—

तहसील —, जिला बरेली के कच्चे मार्ग। अं० ३, पृ० ६४।

काशी—

विलीन — राज्य क्षेत्र की ग्राम पंचायतों के रूपों की वापसी। अं० ४, पृ० ११४, ११५।

नैनीताल—

----- में बन्दूक के लाइसेंसदारों से जबर्दस्ती चन्दा वसूल किया जाना। अं० ६, पृ० १९२, १९३-१९४, १९५।

पीलीभीत—

एल० एच० आयुर्वेदिक कालेज, —। अं० ३, पृ० ६४, ६५, ६६।

फतेहपुर—

----- जिले में चोरियों और डकैतियों की संख्या। अं० ६, पृ० १६२।

बनारस—

महाराजा — का अपने राज्य का सर्वोच्च सत्ताधारी होना। अं० ५, पृ० १४४।

बांदा—

केन कैनल डिवीजन, — में हिसाब-किताब में देरी। अं० ५, पृ० १४२-१४३, १४४।

बरेली—

तहसील आंबला जिला — के कच्चे मार्ग। अं० ३, पृ० ६४।

बरेली कालेज, — में विभिन्न फीजों का लिया जाना। अं० ७, पृ० २५६, २५६।

— हल्द्वानी रोड पर गवर्नमेंट रोडवेज की बसें। अं० ६, पृ० १९०-१९१, १९२।

हल्द्वानी—

बरेली — रोड पर गवर्नमेंट रोडवेज की बसें। अं० ६, पृ० १९०-१९१, १९२।

संकल्प—

----- कि उत्तर प्रदेश में अनायालयों तथा विधवा आश्रमों का प्रबन्ध सरकार अपने हाथ में ले ले। (वापस लिया गया) अं० २, पृ० १९, २०-२४।

----- कि प्रदेश में माध्यमिक कक्षाओं में सैनिक शिक्षा अनिवार्य कर दी जाय (अस्वीकृत हुआ)। अं० २, पृ० २५-२२, ५३।

सेक्रेटरी, लेजिस्लेटिव कौंसिल—

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश (अस्थायी) कंट्रोल आफ रेस्ट एण्ड एविकेशन (संशोधन) विधेयक (घोषणा पढ़ी)। अं० १, पृ० १०।

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कंट्रोल) (संशोधन) विधेयक (घोषणा की गई)। अं० १, पृ० ६।

सन् १९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारों के ऋण कम करने का विधेयक। (मेज पर रखा)। अं० १, पृ० ६।

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी एकोमोडेशन) रिक्रूजिशन (संशोधन) विधेयक (घोषणा की गई)। अं० १, पृ० १०।

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन) विधेयक (मेज पर रखा)। अं० १, पृ० ९।

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ सप्लायज (कन्टीन्युएन्स आफ पावर्स) (संशोधन) विधेयक। (घोषणा की गई)। अं० १, पृ० १०।

‘ह’

हयातुल्ला अन्सारी, श्री—

उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक, १९५२। अं० ७, पृ० २६४, २६५-२६६, २६७।

संकल्प कि प्रदेश में माध्यमिक कक्षाओं में सैनिक शिक्षा अनिवार्य कर दी जाय। अं० २, पृ० ३६, ३७, ३८।

हर गोविन्द सिंह, श्री—

आगरा यूनिवर्सिटी (अनुपूरक) विधेयक,
१९५२। (विचार के लिये प्रस्तुत
किया) अं० ८, पृ० ३२२-३२६,
३२७, ३२८, ३३०, ३३१, ३३२,
३३३, ३३७, ३४१, ३४५, ३५१,
३५३, ३५४-३५६, ३५७।

आगरा यूनिवर्सिटी (पूरक) विधेयक,
१९५२ ई०। (पुरःस्थापित किया)।
अं० ६, पृ० २५४।

आगरा विश्वविद्यालय के उपकुलपति
का चुनाव आर्डिनेंस द्वारा स्थगित
किये जाने के सम्बन्ध में कार्य स्थगन
प्रस्ताव। अं० ६, पृ० १९६।

उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन)
विधेयक, १९५२। अं० ७, पृ०
२७२।

सदन का कार्यक्रम। अं० ६, पृ० २५४।

हाफिज मुहम्मद इब्राहीम, श्री—

आगरा विश्वविद्यालय के उप-कुलपति
का चुनाव आर्डिनेंस द्वारा स्थगित
किये जाने के सम्बन्ध में कार्य-
स्थगन प्रस्ताव। अं० ६, पृ०
१९५, १९६।

आगरा विश्वविद्यालय के उप-कुलपति
का चुनाव एक आर्डिनेंस द्वारा
स्थगित किये जाने के सम्बन्ध में
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना।
अं० ५, पृ० १४५।

इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कोर्ट के लिये
दो सदस्यों के चुनाव का प्रस्ताव।
(प्रस्तुत किया) अं० ४, पृ० १३६,
१३७।

प्रस्ताव कि काशी के घाटों के सम्बन्ध
में शीघ्र कार्य आरम्भ किया जाय।
अं० २, पृ० ५६, ६०।

सदन का कार्यक्रम

अं० १, पृ० १०, ११। अं० २,
पृ० ६१। अं० ४, पृ० १३७।

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश फायर
सर्विस (संशोधन) विधेयक। प्रस्तुत
किया। अं० १, पृ० ९।

(विचार के लिये प्रस्तुत किया।) अं०
४, पृ० १३३, १३४, १३५, १३६।

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश बिक्री
कर (संशोधन) विधेयक। (विचार
के लिये प्रस्तुत किया।) अं० ४, पृ०
११७, ११८-११९, १२०, १२२,
१२५, १२६, १३१, १३२, १३३।

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश म्यु-
निसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक।
अं० ५, पृ० १५१।

संकल्प कि प्रदेश में माध्यमिक कक्षाओं
में सैनिक शिक्षा अनिवार्य कर दी
जाय। अं० २, पृ० २७, २८, २९,
३१, ५०, ५१-५२, ५३।

